## भारत में राजकीय ट्यापार : आलोचनात्मक मूल्यांकन

### इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल् उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध



#### निर्देशक

#### प्रो० जी० सी० अग्रवाल

विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग निदेशक, मोतीलाल नेहरू रिसर्चं एण्ड विजनेस एडमिनिश्ट्रेशन पूर्व प्रति-कुलपित इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

शोध कर्ता

#### कृष्ण चन्द्र बर्मा

प्रवक्ता वाणिज्य राजकीय महाविद्यालय ओवरा, सोनभद्र

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

9994

आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरण में राज्य का एक मात्र कार्य जीवन,धन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना था जिसे वह केवल कानून की सरचना एवं उसके परिपालन द्वारा सुनिश्चित कर लेता था परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्धसे राजकीय उत्तरादायित्वों में तेजी से वृद्धि होने लगी । वर्तमान समय में राज्य आर्थिक प्रक्रिया का मूकदर्शक मात्र बनकर नहीं रह सकता बल्कि समाज के सभी पक्षों के सरक्षक, नियन्त्रक और अभिभावक के रूप में उसकी सिक्रिय भूमिका हो गयी है । आधुनिक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नागरिकों की गर्भकाल से अन्त्येष्ठि तक की देखभाल करे ।

हमारे देश की सरकार ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एव समाजवादी समाज की सरचना के पुनीत सकल्प को स्वीकार किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने वस्तुओं के उत्पादन एव वितरण में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी एव राजकीय नियन्त्रण के औचित्य को भी आत्मसात् किया है। सरकार उत्पादन एवं वितरण मे अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से तथा इस पर नियन्त्रण विभिन्न कानूनों के माध्यम से करती है। आज के बदलते आर्थिक एव भौतिकवादी युग मे 'उपभोक्ता' अर्थात् 'सम्पूर्ण जन समुदाय ' के हितों की रक्षा तथा उन्हें मूल्य पर उचित गुण की वस्तुए उपलब्ध कराने से न केवल उपभोक्ता बल्कि सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा। सरकार के इस पवित्र कर्तव्य से बढकर शायद ही कोई अन्य कर्तव्य होगा।

वर्तमान समय मे विश्व का आर्थिक परिदृश्य बडी तेजी से परिवर्तित हो रहा है । साम्यवादी गढ सोवियत संघ बिखर चुका है, विखण्डित सोवियत सघ चीन के साथ मुक्त बाजार व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहा है । पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी जैसे विपरीत दिशाई राज्यों का विलय हो चुका है । अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहे हैं । विश्व मे कई शिक्तशाली क्षेत्रीय व्यापार समूह गठित किये गये है । गैट व्यवस्था पुन परिभाषित की गयी है । विश्व की आर्थिक गितिविधियों मे हो रहे इन परिवर्तिनों से भारत भी अछूता नही रहा है । एक वर्ष मे भारतीय मुद्रा का दो बार अवमूल्यनिकया गया, बहुत सी वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबन्धित सूची से हटाया गया, रूपये को पूर्ण परिवर्तिनीय बनाया गया । विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे अधिनियमों में बहुत से महत्वपूर्ण सशोधन कर देश की औद्योगिक एव आयत-निर्यात नीति में आधार-भूत परिवर्तन किये गये है । आर्थिक परिवर्तन के इस दौर में भारत मे 'राजकीय व्यापार का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन' करना आवश्यक समझा गया। उदारीकृत व्यापार नीति के परिणाम स्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदलीं और इस बदलती प्राथमिकताओं के क्रम में भारत के राजकीय व्यापार को

भी अपनी नवीन रचनात्मक भूमिका निभानी है जिसके अनुसंधान में वह तत्पर है, यह इसिलिये भी और आवश्यक है कि वह जो भी भूमिका अपनाये उससे सामाजिक कल्याण का स्वरूप प्रतिविम्बित हो ।

इसी मूल भावना को लेकर प्रस्तुत शोध को पांच सर्गों मे बाटा गया है । प्रथम सर्ग मे राजकीय व्यापार की भूमिका, इसके औचित्य, आश्रय, परिभाषा, उद्देश्य स्वरूप एव क्षेत्र तथा इसके विभिन्न प्रारूपों पर प्रकाश डाला गया है । द्वितीय- सर्ग मे भारत मे राजकीय व्यापार के विकास क्रम को बताया गया है जिसमे इसके विकास को तीन काल क्रमों- प्राचीन, मध्य एव आधुनिक, मे बाट कर इसका अध्ययन किया गया है । तीसरे-सर्ग मे राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भों का विश्लेषण करते हुए उनका मूल्याकन किया गया है । इस उद्देश्य से इस सर्ग को पुन दो भागों मे बांटा गया है । प्रथम उपसर्ग, खाद्यान्नों मे राजकीय व्यापार जिसमे - राशिनेंग व्यवस्था, खरीदकार्य, सार्वजिनक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है । द्वितीय उपसर्ग- अन्य वस्तुओं मे राजकीय व्यापार के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, राजकीय व्यापार में संलग्न सार्वजिनक क्षेत्र के अन्य अभिकरणों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा कुछ स्वायत्तशासी संस्थाओं का विश्लेषण किया गया है । चतुर्थ-सर्ग राज्य द्वारा व्यापार का नियमन है । जिसमे उन विनियमनों की व्याख्या की गयी है जिनसे व्यापार पर राजकीय नियन्त्रण किया जाता है । पंचम और अन्तिम सर्ग मे राजकीय व्यापार मे प्रत्यक्ष भागीदारी वाले अभिकरणों एव व्यापार पर नियन्त्रण करने वाले विनियमों को लागू करने से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किये गये है ।

प्रस्तुत शोध प्रो0 जी0सी0 अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग एव निदेशक, मोतीलाल नेहरू रिसर्च एण्ड बिजनेस एडिमिनिस्ट्रिशन तथा पूर्व प्रति कुलपित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के सफल निर्देशन मे किया गया है । मै अपने परम् आदरणीय गुरूवर की वन्दना व स्तुति निम्न श्लोक से प्रारम्भ करता हूँ -

'गुर्रुब्रहमा गुर्रुविष्णु गुरुदेवोमहेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रहमतस्मै श्री गुस्वे नम ।'

मै अपने ब्रहमस्वरूप गुरू का हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपनी अनेक व्यस्तताओं व समस्याओं के पश्चात् अपना बहुमूल्य समय देकर इस शोध को अल्प समय मे अन्तिम स्वरूप प्रदान किया , बिना उनकी प्रेरणा , सहयोग व श्रुभाशीर्वाद के यह महानतम् कार्य सम्भव नहीं हो सकता था । मैं आपका जीवन पर्यन्त आभारी रहूँगा ।

इस शोध में बौद्धिक मार्गदर्शन का श्रेय हमारे वरिष्ठ एवं विद्वान मित्र डा० अजनी कुमार मालवीय , डी० लिट०, प्रवक्ता, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद एवं आपके परिवार को है। आपकी प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन से ही मैं गुरूवर की शरण में आ सका। आपने समय-असमय सदैव शोध कार्य में हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया है। मैं आपका एवं आपके पूरे परिवार का आजीवन ऋणी रहूँगा।

मै अपने पूज्य पिता जी एव माता जी का हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ । अपने अग्रज डा० आर०के० वर्मा, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , काशीपुर, नैनीताल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे शैक्षिक जीवन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । में अपने अग्रज श्री राम सुन्दर वर्मा व अपनी भाभियों का भी ऋणी हूँ । श्री हरिश्चन्द्र वर्मा, अनुज के प्रति भी मे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिसने इस शोध कार्य को गति प्रदान करने मे सहायता की है । मै अपने मित्र डा० आर०एस० वर्मा, न्यूरोसर्जरी विभाग, डा० राममनोहर लोहिया हास्पिटल, नई दिल्ली का भी आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने आंकडे व सूचनाए प्रदान करने में सहायता प्रदान की ।

राजकीय महाविद्यालय ओबरा मे विशेष रूप से प्राचार्य डा० एन० पाण्डेय , डा० योगेश्वर पाण्डेय, श्री जगधारी सिंह, डा० एन०एन० सिंह, डा० एस०पी० सिंह व समस्त मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमे समय- समय पर सहयोग व प्रेरणा प्रदान की । मै उन सभी व्यक्तियों व अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे सूचनाए संकलित करायी ।

मे अपनी पूज्यनीया भाभी श्रीमती रेनू मालवीया व अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी वर्मा एव श्री निमिष अग्रवाल के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्ता करता हूँ जिनसे मै सदैव प्रेरित होता रहा । मै इस शोध कार्य के टकक श्री एस0एन0 सिंह के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अल्प समय मे शोध टंकण का कार्य सम्पन्न किया ।

एक बार पुन<sup>•</sup> मै अपने आचार्य प्रो0 अग्रवाल के चरण-कमलों मे अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हैं जिन्होंने अपनी अनुपम अनुभृतियों एवं मनोरम प्रवृत्तियों द्वारा पल -पल मेरा मार्ग प्रशस्त किया ।

जून 1995

( कृष्ण चन्द्र वर्माः ) प्रवक्ता वाणिज्य राजकीय महाविद्यालय ओबरा (सोनभद्र)

#### विषय-सूची

		पृष्ठ सख्या
प्रथम-सर्ग	भारत में राजकीय व्यापार की भूमिका	1-21
	(क) औचित्य	3
	(ख) आशय	7
	(ग) परिभाषा	. 8
	(घ) विशेषताए	10
	(ड) उद्देश्य	11
	(च) स्वरूप एव क्षेत्र	18
द्वितीय-सर्ग	भारत में राजकीय व्यापार का विकास	22-40
	(क) प्राचीन काल	23
	(ख) मध्य काल	26
	(ग) आधुनिक काल	30
	1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय व्यापार	31
	2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजकीय व्यापार	34
तृतीय-सर्ग	राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ	41-204
	( 🛘 ) खाद्यान्नो में राजकीय व्यापार	42
	(क) राशनिग व्यवस्था	47
	अ प्रक्रिया	47
	ब लाभ	55 - 5
	स समस्याए एव सुझाव	57
	(ख) खरीद कार्य	59
	अ उद्देश्य	59
	ब विधि	60
	स खरीद के माध्यम	61 65
	द समस्याए एव सुझाव	
	(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली	66
	अ परिभाषा	67
	ब विशेषताए	68

			5
	स	अवधारणा	69
	द	उद्देश्य	70
	य	विकास	72
	र	वर्तमान स्थिति	78
	ल	समस्याए एव सुझाव	92
(घ)	भारती	य खाद्य निगम	102
	अ	परिचय	102
	ब	उद् देश्य	193
	स	कार्यात्मक प्रगति का मूल्याकन	104
	द	िनगम की अन्य गतिविधियो का मूल्याकन	134
	य	निगम की लाभदायकता का मूल्याकन	136
	र	कमियाँ	138
	ল	सुझाव	143
(इ)	भारतीय	<ul><li>केन्द्रीय भण्डारण निगम</li></ul>	147
	अ	परिचय	147
	ब	निगम की उपलब्धियाँ	148
	स	निगम की अन्य गतिविधियाँ	156
	द	निगम की समस्याए एव सुझाव	159
$(\Pi)$	अन्य व	स्तुओं में राजकीय व्यापार	
(क)	भारती	ाय राज्य व्यापार निगम	167
	अ	उद्देश्य	168
	ब	निगम का सगठन एव प्रबन्ध	170
	स₊	निगम का कार्य	172
	द	निगम का प्रमुख व्यापार क्षेत्र	175
	य	परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य का निगम पर प्रभाव	176

179

181

185

187

निगम की व्यापारिक स्थिति

निगम के कारोबार की विशिष्टताए

निगम की उपलब्धियो का मूल्यांकन

चीनी सकट-1994 में निगम की भूमिका

₹

ल

व

ष

				•
		श भा	रतीय राज्य व्यापार निगम का अनुषगी निगम	190
		ह निग	ाम की आलोचना	192
		क्ष सुझ	गाव	195
	(ख)	सार्वजनिक	क्षेत्र की अन्य एजेन्सियाँ	197
		अ भार	रतीय हस्तशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	197
		ब भार	रतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम लिमिटेड	198
		स भार	तीय काजू निगम लिमिटेड	198
		द भार	तीय परियोजना एव उपकरण निगम लिमिटेड	199
		य भार	तीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड	199
		र भार	तीय राज्य रसायन एव भेषज निगम लिमिटेड	200
	(ग)	उपभोक्ता र	तहकारी समितियाँ	200
	(ঘ)	कुछ स्वायत	त्तशासी सस्थाए	201
चतुर्था–सर्ग,	राज्य द्वारा	व्यापार का	नियमन	205-260
I	(क)	औद्योगिक(नि	वेकास एव नियमन) अधिनियम–1951	207
	(ख)	अग्रिम अनुब	न्ध(नियमन) अधिनियम-1952	216
	(ग)	खाद्य अपिम	श्रण निवारण अधिनियम-1954	221
	(ঘ)	आवश्यक व	स्तु अधिनियम-1955	222
	(ਵ)	प्रतिभूति अ	नुबन्ध(नियमन) अधिनियम-1956	224
	(च)	व्यापार एव	व्यापारिक चिह्न अधिनियम-1958	230
	(छ)	एकाधिकार	एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम-1969	231
	(ज)	पैकेज्ड वस्त्	तु नियमन आदेश-1975	242
	(झ)	बाट एवं मा	ाप-मान अधिनियम-1976	244
	(ञ)	उपभोक्ता स	रक्षण अधिनियम-1986	246
	(ਟ)	भारतीय प्रति	तेभूति एव विनिमय बोर्ड अध्यादेश-1992	254
पंचम -सर्ग	समस्याए	एवं सुझाव		260 <b>- 2</b> 93
	-	समस्याए		263
	****	सुझाव		27 6
		संदर्भिका		294

## तालिका~सूची

तालिका-संख्या	विवरण	पृष्ठ-सख्या
1	सरकार द्वारा निर्धारित खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य	61
2	खाद्यान्नो की सरकारी खरीद	62
3	भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी खरीद	64
4	भारत मे उचित मूल्य की दुकाने	79
5	उचित मूल्य के दुकानो के वितरण की स्थिति	84
6	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आविण्टत मात्रा	85
7	नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न राज्यो/	
	केन्द्र शासित प्रदेशो मे खोली गयी दुकाने	87
8	खुली बिक्री एव लेवी चीनी का आवण्टन	88
9	निजी कम्पनियो द्वारा किया गया चीनी आयात	91
10	सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी	98
11	निगम द्वारा मूल्यात्मक अधिप्राप्ति की स्थिति	105
12	रबी-फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि	106
13	निगम द्वारा अधिप्राप्ति की कुल मात्रा	107
14.	राज्यवार गेहूँ की खरीद की स्थिति	107
15	कुछ प्रमुख राज्यो में चावल की अधिप्राप्ति का निर्धारित मूल्य	109
16	चावल की अधिप्राप्ति में कुछ प्रमुख राज्यों का योगदान	110
17.	धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एव अधिप्राप्ति मात्रा	111
18	निगम द्वारा अधिप्राप्त चीनी की मात्रा एव मूल्य	112
19.	चीनी की अधिप्राप्ति का राज्यवार विवरण	112
20	मोटे अनाज एव अन्य उत्तपादो की अधिप्राप्तियाँ	113
21	निगम द्वारा की गयी मदवार बिक्री	114
22	खाद्यान्नों का राज्यवार वितरण	116
23	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी खाद्यान्नो की मात्रा	117
24	सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य	118
25	आई टी डी पी /नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विशेष सहायतित निर्गम मूल्य	119

तालिका- संख्या	विवरण	पृष्ठ-सख्या
26	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत बिक्री	120
27	पोषाहार कार्यक्रम एव जवाहर रोजगार योजना के अधीन बिक्री	121
28	वर्ष 1992-93 मे आयातित खाद्यान्नो की 31 मार्च-1993 तक प्राप्त मात्रा	124
29	निगम द्वारा खाद्यान्नो के निर्यात की स्थिति	125
30	सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भण्डारण सीमा	127
31	निगम की कुल भण्डार क्षमता	128
32	केन्द्रीय पूल मे भण्डारो की स्थिति	129
33	भण्डारण क्षमता के उपयोग की स्थिति	130
34	राज्यवार खाद्यान्न भण्डारण की स्थिति	131
35	खाद्यान्न तथा चीनी की परिचालित मात्रा का विवरण	132
36.	चीनी मूल्य समानीकरण कोष हेतु वसूली, भुगतान एव सम्पूर्ण घाटे की स्थिति	134
37	निगम के लाभ हानि खाते को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मदो का विवरण	137
38	मार्गस्थ तथा भण्डारण कमियाँ	139
39	लेवी चीनी एव आयातित चीनी के कार्यकारी परिणाम	140
40	निगम के भण्डारगृहो की सख्या एव उनकी क्षमता का विवरण	149
41.	भण्डारगृहो की जमाकर्तावार उपयोग की स्थिति	150
42	निगम का विगत वर्षों का वित्तीय निष्पादन	152
43.	केन्द्रीय भण्डारण निगम की लाभदायकता एव लाभाश	153
44.	राज्य भण्डारण निगमो की प्रगति एवं इनसे प्राप्त आय	155
45	गुणवत्ता नियन्त्रण एव परिरक्षण के लागू किये गये उपाय एव उनकी प्रगति	157
46.	राज्य व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति	180
47	विगत वर्षों मे निगम के कारोबार की विशिष्टताए	182
48	सरणीबद्ध एव असरणीबद्ध व्यापार की स्थिति	184
49.	विदेशी व्यापार मे राज्य व्यापार निगम का योगदान	187
50	भारतीय चाय व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति	191

# प्रथम-सर्ग भारत में राजकीय व्यापार की भूमिका

#### प्रथम-सर्ग भारत में राजकीय व्यापार की भूमिका

वर्तमान समय में लोकतान्त्रिक समाजवादी सरकार की स्थापना विश्व के अधिकाश देशों में हो चुकी है। सरकार एक सस्था है जिसके पीछे जन अनुज्ञा, जन समर्थन एव जनशक्ति होती है। इसका कार्य अपने नागरिकों की रक्षा करना तथा उनका विकास करना होता है। इस पवित्र एव महानतम उद्देश्य व दायित्व की पूर्ति के लिए राज्य का वह प्रत्येक कार्य करने का कर्तव्य होता है जो जनहित की परिधि में आता हो। हमारे देश की सरकार ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एव समाजवादी समाज की सरचना के पुनीत कर्तव्य का वृत लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने व्यापारिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप के औचिन्छ को भी आत्मसात् किया है। हमारी सरकार व्यापारिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए जिन नीतियों का अनुसरण करती है वे उसे भारतीय सविधान द्वारा प्रवत्त है। बदलते आर्थिक परिवेश में व्यापार की महत्ता दिन-पृतिदिन बढती जा रही है। सरकार ने व्यापार की क्रियाओं में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप किया है। सरकार व्यापारिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते समय सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ता सरक्षण से प्रेरित एव मार्गदर्शित होती है। आज के विपणन युग में "उपभोक्ता" या "जन समुदाय" के हितों की रक्षा व उन्हें उचित मूल्य पर उचित वस्तुए उपलब्ध कराने से न केवल उपभोक्ता का बल्क देश का आर्थिक विकास भी सम्भव हो स्केगा।

आधुनिक परिवेश में ससार के लगभग सभी देशों की सरकारे किसी न किसी रूप में या तो व्यापार की स्थापना, संचालन, विकास व विस्तार में भाग लेती हैं, या व्यापार के अविद्या कियाओं पर विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से नियमन और नियन्त्रण करती हैं। सरकारों को अपने दायित्व की पूर्ति हेतु व्यापारिक क्रियाओं में भाग लेना अथवा उन पर हस्तक्षेप करना अनिवार्य सा हो गया है। यह अवश्य है कि हस्तक्षेप और नियन्त्रण की विशाएँ तथा तकनीक बदलती रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक सरकार समस्याओं को अपनी दृष्टि से देखती हैं। इस प्रकार सरकार देश मे राजनीतिक एवं आर्थिक संस्कृति का पोषण करती हैं और साथ ही अपने नागरिकों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने के लिए व्यापारिक क्षेत्र का नियमन और नियन्त्रण भी करती हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार चाहे वह समाजवादी हो या पूँजीवादी अथवा साम्यवादी, राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत व्यापारिक क्रियाओं पर नियन्त्रण कमाधिक रूप में करती ही है। इस नियन्त्रण से विश्व के हर राष्ट्र में एक नया आर्थिक दर्शन विकसित हो रहा है।

समाज के भौतिक, प्रौद्योगिक और सास्कृतिक आधारों में परिवर्तन के साथ-साथ आर्थिक अवस्थाओं में भी परिवर्तन आया है। विस्तृत प्रौद्योगिकी परिवर्तन, विश्व बाजार का विकास, विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में होने वाला वृहत् औद्योगीकरण तथा नये-नये उत्पादनों की सख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यापारिक गतिविधियों में कुछ राजकीय हस्तक्षेप नितान्त आवश्यक है। प्रत्येक उपभोक्ता स्वभावत उचित मूल्य पर अच्छी से अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान मे व्यापारी वर्ग द्वारा की जाने वाली जमाखोरी कालाबाजारी तथा वस्तु की अनियमित पूर्ति के परिणाम स्वरूप, मूल्यों में होने वाली वृद्धि उपभोक्ता वर्ग के कष्ट का कारण बनती है। इस तरह व्यापार व्यवस्था में लगे निजी विक्रेता स्थिति का दुरुपयोग कर उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण करने लगते है। कल्याणकारी राज्य में सरकार कायह दायित्व है कि वह जनसाधारण को सुरक्षा व न्याय दिलाने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की भी उचित व्यवस्था करे।

#### (क) औचित्य --

वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र अपने को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। वह अपने आर्थिक विकास की गित को तीव्रतम रखते हुए पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से बचना भी चाहता है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन एव वितरण को सरक्षण प्रदान करते हुए उसके विकास एव विस्तार हेतु शान्तिपूर्ण तथा नियमित व्यवस्था बनाये रखना उसके लिए अपरिहार्य हो गया है। समाज में व्याप्त मुनाफाखोरी, जमाखोरी एव मिलावट जैसी कुरीतियों को दूर करने तथा अधिक से अधिक जनकल्याण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का स्वय उत्पादन एव वितरण—क्रियाओं में शामिल होना आवश्यक हो गया है। राजकीय व्यापार का औचित्य निम्न तथ्यों से और भी स्पष्ट हो जाता है—

- 1 नियोजित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किसी भी देश के योजनाबद्ध विकास में राज्य द्वारा किया गया व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विकास की इस प्रक्रिया में समस्त महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को आपस में सगठिस व समन्वित किया जाता है। इस परिस्थित में यह युक्तिसगत न होगा कि व्यापार को अनिश्चितता व उच्चावचन के सहारे छोड दिया जाय।
- 2 निजी व्यापारियों के शोषण से जनता को बचाने के लिए —योजनाबद्ध विकास को अपनाने वाले देशों की इच्छा यह नहीं होती कि वे पूर्ण रूप से व्यक्तिगत एजेन्सियों के माध्यम से व्यापार को सम्पादित होने दे। देश के शासक व्यापार में राजकीय हस्तक्षेप को उचित समझते हैं, जिससे छोटे—छोटे व्यापारियों द्वारा उत्पन्न की गई विभिन्न समस्याओं से बचा जा सके और साथ ही सरकार अपने द्वारा किये गये वायदों को ईमानदारी से पूरा कर सके। राजकीय ध्यापार में राज्य निधीरित योजनानुसार अधिकाश व्यापारिक क्रियाओं का सचालन करता है। वह निजी व्यापार करने वाले देशों से भी समझौता करने में सक्षम होता है, ताकि निजी व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले शोषण से जनता को बचाया जा सके।
- 3 राजकीय व्यापार एजेन्सी की अधिक सगठनात्मक शक्ति एव उसके अधिक वित्तीय ससाधन विकसित देशों के राजकीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शक्तिशाली निर्यात गृह और देश-विदेश से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विभिन्न कार्यालय स्थापित किये गये

है। वे सम्बन्धित उद्योग और सम्बन्धित सरकार के वाणिज्यिक कार्यालय से अखण्ड व्यवहार बनाये रखते है तािक कुछ कठिनाइयो और अस्थायी हािनयों को सहन करते हुए भी अपने व्यापार में निरन्तरता बनाये रख सके।

भारत मे भी निर्यात सम्बर्धन हेतु सरकार ने निजी व्यापारियों को निर्यात-गृह की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सहायता प्रदान की है तािक अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात हेतु नया बाजार खोजा जा सके। यद्यपि निर्यात गृहों की स्थापना से इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है लेकिन अभी यह उदीयमान अवस्था में ही है जो कि विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता कर पाने में सक्षम नहीं हैं। नया बाजार बनाने के लिए उन्हें न केवल अपने घरेलू उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करनी पडती है बल्कि उन विदेशी पूर्तिकर्ताओं से भी कडी प्रतिस्पर्धा करनी पडती है बल्कि उन विदेशी पूर्तिकर्ताओं से भी कडी प्रतिस्पर्धा करनी पडती है जिनके पास एक शिवतशाली उत्पाद होता है और जिन्हें उनकी सरकारे भी सहायता प्रदान करती है। इन परिस्थितियों में राजकीय सचिवालय या वाणिज्यिक सलाहकार या अन्य नियामक सस्थाए जैसे -निर्यात सम्बर्धन परिषद द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता और सहयोग पर्याप्त नहीं होता है। अत विदेशी व्यापार के समझौतों और सौदों को निष्पादित करने वाली राजकीय व्यापार एजेन्सी का गठन अपरिहार्य हो जाता है जिसके पास शिक्तशाली सगठनात्मक शिक्त और पर्याप्त वित्तीय ससाधन हो तािक निर्धारित कार्यक्रम को कार्यरूप प्रदान कर सके।

- 4 <u>दिपक्षीय समझौतो एव आर्थिक नीतियो को लागू करने के लिए</u> यदि व्यापार निजी क्षेत्र के हाथ में होता है तो सरकार को द्विपक्षीय समझौतों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड सकता है। व्यापार में राजकीय प्रवेश से सरकार को इन समझौतों को ससम्मान पूरा करने में मदद मिलती है। राजकीय व्यापार, व्यापार के अतिरिक्त भी सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण एव उपयोगी उपकरण होता है। उदाहरण के लिए सरकार राजकीय व्यापार, राष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी सुविधाओं का विकास करने के लिए उन्हें सरक्षण प्रदान करने का निर्देश दे सकती है।
- 5 निजी व्यापारियों के समक्ष प्रतियोगितात्मक वातावरण बनाने हेतू यदि देश के निर्यातकर्ता विदेश के निर्यात अनुबन्धों को समय से पूरा नहीं कर पाते या आयातक द्वारा वाछित गुणवत्ता की वस्तुए उत्पादित कर प्रेषित नहीं कर पाते अथवा निजी व्यापारियों में स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होती जिससे कि वे प्रेरणा लेकर, सौदेवाजी करके निर्यात अनुबन्धों को प्राप्त करे, तो ऐसी दशा में निजी व्यापारी विदेशी आयातकों का शोषण करने लगते हैं। इस स्थिति का निवारण राजकीय व्यापार के माध्यम से निजी व्यापारियों के समक्ष प्रतियोगितात्मक वातावरण बना कर किया जा सकता है ताकि विदेश में देश के वस्तुओं की गुणवत्ता एव निर्यात अनुबन्धों के समय पर पूरा करने की तत्परता सम्बन्धी छिंव अच्छी बनी रहे।
  - 6 निर्यात सम्बर्द्धन हेतु राजकीय व्यापार आवश्यक है राजकीय व्यापार निर्यात सम्बर्द्धन मे

महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। विशेषरूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के निर्यातकों का अनुचित व्यापार व्यवहार देश की निर्यातक ख्याति को बनाने में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। राजकीय व्यापार निजी क्षेत्र के निर्यातकों के सम्मुख विकल्प प्रस्तुत कर अनुचित व्यापार व्यवहार को समाप्त कर देश की निर्यातक ख्याति में स्थायित्व ला सकताहै। निजी क्षेत्र के निर्यातकों की प्रवृत्ति परम्परागत बाजारों को निर्यात करने पर ही केन्द्रित रहती है। क्योंकि नये बाजार की खोज में अतिरिक्त विनियोग और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए निजी निर्यातक नये बाजार की खोज का प्रयास ही नहीं करते। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के निर्यातकों को एक भय यह भी होता है कि कुछ व्यापारियों द्वारा नये बाजार की खोज में किये गये व्यय एव उठायी गयी परेशानियों के परिणामस्वरूप यदि नये बाजार तैयार कर भी लिये जाए तो अन्य व्यापारी भी इस नये बाजार में अपना उत्पाद पहुँचाकर हिस्सा बँटा लेते हैं। सरकारे सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्वीकार की जाती है अत उन्हें इस प्रकार का भय नहीं होता। इसके अतिरिक्त सरकार अपने वृहत् ससाधनों के माध्यम से नये बाजार की खोज एव नये निर्यात स्रोतों का पता लगाने में निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक धन का व्यय कर सकती है।

7 <u>बढी मात्रा में खरीददारी के अनुबन्ध करना</u> बडी मात्रा में खरीददारी छोटी—छोटी मात्रा में खरीददारी की तुलना में मितव्ययी होती है। राजकीय व्यापार मध्यस्थों को इस कार्य से हटाकर उनके कमीशन राश्चि से कस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि पर रोक लगा सकता है। यद्यपि बडी मात्रा में खरीददारी के कई जोखिम भी रहते हैं। भावी मूल्यों के अनुमान में कोई भी तुटि होने पर देश का बहुत बडा नुकसान भी हो सकता है। प्रतियोगितात्मक व्यवस्था में तेजडिये की गलती से होने वाली हानि को मन्दिं में द्वारा कम प्रभावी बना दिया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि राजकीय अनुमान व्यक्तिगत रूप से निजी व्यापारियों के अनुमान से अधिक सही होगा। सरकार अपने वृहत् ससाधनों द्वारा विभिन्न कस्तुओं की माग एव पूर्ति के विषय में अधिक | सही सूचनाए इकट्ठा कर सकती है। यह प्रवृत्ति के आधार पर भावी मूल्य का अनुमान लगाने वाले विश्लेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकती है। बडी मात्रा में खरीददारी के अनुबन्ध निर्धारित मूल्यों पर पूर्ति को सुनिश्चित करते हैं एव राष्ट्र की योजना को सफल बनाने में सहायता करते हैं। इसके अभाव में आयातित वस्तुओं के मूल्य एव मात्रा में उच्चावचन होने के कारण योजना के निर्धारित लक्ष्यों तक नहीं पहुँचा जा सकता। बडी मात्रा में खरीददारी का अनुबन्ध निर्धारक के लिए भी लाभदायक होता है। एक निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति के विषय में निर्यातक आश्वस्त होकर आगे के उत्पादन योजना की रूप-रेखा तैयार कर सकते हैं। बडी मात्रा में खरीददारी के अनुबन्ध कर लिये जाने से आयातक आयात की वित्त व्यवस्था की समस्या से भी बच जाता है।

8 सरकार को विश्व एकाधिकारी का लाभ - सरकार जिस वस्तु की विश्व मे एक मात्र निर्माता

है, राजकीय व्यापार की दशा में वह इसका प्रयोग एकाधिकारी शक्ति का लाभ उठाने में कर सकती है। सरकार उपभोक्ता से उस वस्तु का वह अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकती है जिसको उपभोक्ता देने को तैयार हो। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न बाजारों की माँग एवं पूर्ति की विभिन्न शर्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न मूल्य भी प्राप्त कर सकती है। विभिन्न देशों के व्यापार एवं विनिमय प्रतिबन्धों में असमानता के कारण ही मूल्य स्तर में भी असमानता आ जाती है। इससे मूल्यान्तर का क्षेत्र और बढ जाता है जिसका प्रयोग करते रहने पर विश्व बाजार के बँटने की सम्भावनाए भी बढ जाती है। अत राजकीय व्यापार अपनी इच्छानुसार इन तत्वों पर नियन्त्रण करता है।

- 9 क्रेता एकाधिकारी की दशा में लाभ यदि देश किसी वस्तु का विश्व बाजार में एक मात्र वास्तिविक और बड़ा क्रेता है तो वह अपनी एकाधिकारी शिक्त का प्रयोग करते हुए सबसे सस्ती दर पर आयात भी कर सकता है। निजी आयातको द्वारा वस्तु के कीमत की बार—बार पूछ—ताछ किये जाने से नियातक को वस्तु की माँग की वास्तिविक स्थिति का पता चल सकता है। जिससे निर्यातक वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देता है और इस प्रकार व्यापारिक सम्बन्ध भी खराब हो जाते है। ऐसी गतिविधि निर्यातक देश के हितो के भी विरुद्ध होती है। मूल्यों के बढ जाने के बाद इस बात की सम्भावना रहती है कि अनुमानित माँग में भी कमी हो जाय। मूल्यों को निर्यातक द्वारा बढ़ा देने के बाद भी सम्भावना रहती है कि आयातक किसी दूसरे म्रोत से उस वस्तु को प्राप्त करने का अनुबन्ध करे। इससे निर्यातक देश के पास अतिरिक्त पूर्ति की वस्तुए बेकार हो सकती है। अगर राजकीय व्यापार के माध्यम से केन्द्रित रूप में माँग के पूर्ति हेतु पूछ—ताछ विदेशी पूर्तिकर्ता से की जाय तो यह मूल्य और माँग दोनों दृष्टि से अच्छा होगा तथा दोनों ही पक्षों के लिए उचित भी होगा।
- 10 भुगतान शेष को सन्तुलित करने के लिए जहाँ कुछ देशों के साथ व्यापार शेष अनुकूल नहीं है वहाँ राजकीय व्यापार के माध्यम से भुगतान शेष को सतुलित किया जा सकता है। राजकीय व्यापार अभिकरण मूल्यों के यथावत् बने रहने की दशा में भी उन देशों से आयात व्यापार को बढ़ा सकता है जिनकी मुद्रा प्राप्त करना सरल है क्योंकि उन देशों के साथ हमारा व्यापार सन्तुलन अनुकूल है। 'हार्ड करेन्सी' अर्थात् कठिन मुद्रा वाले देश, जिनके साथ हमारा व्यापार सतुलन प्रतिकूल है, से आयात व्यापार को घटाया या बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसी तरह से हार्ड करेन्सी वाले देशों को राजकीय व्यापार एजेन्सी अपना निर्यात बढ़ा सकती है तथा सरल मुद्रा वाले देशों को निर्यात में कमी कर सकती है। निजी व्यापारियों के लिए किसी देश की मुद्रा और भुगतान संतुलन के आधार पर निर्णय लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना लाभदायक आयात एव निर्यात। अत राजकीय व्यापार देश के भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाये रखने की दृष्टि से भी आवश्यक है।

11 सावर्जनिक राजस्व की प्राप्ति का स्रोत — कुछ व्यक्ति राजकीय व्यापार को इसलिए अधिक अच्छा कहते हैं कि इससे सार्वजनिक राजस्व की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से विकासशील देशों की आर्थिक मामलों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका के निर्वहन के लिए वित्तीय आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है। सरकार घरेलू एव विदेशी मूल्य की असमानता को समाप्त करने के लिए कुछ वस्तुओं पर आयात और निर्यात प्रतिबन्ध लागू करके विदेशी व्यापार के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ कमा सकती है। कुछ व्यापारियों को और अधिक सम्पन्न बनाने के बजाय सरकार इस तरह से प्राप्त अप्रत्याशित लाभ का प्रयोग सामान्य जनता के हित के लिए कर सकती है।

#### (ख) आशय -

"राज्य" शब्द का प्रयोग सामान्य तौर पर दो अर्थों मे किया जाता है— प्रथम एक सामाजिक सगठन के रूप मे, तथा द्वितीय सत्ता के सगठन के रूप मे। प्रथम अर्थ मे राज्य ऐसे समाज का द्योतक है जो एक निश्चित क्षेत्र मे बसा हुआ हो और राजनीतिक दृष्टि से सगठित हो, अर्थात् जिसमे "मूल्यों का अधिकारिक आवटन " करने वाली सत्ता विकसित कर ली गयी हो। दूसरे अर्थ मे राज्य उस सस्था या सत्ता का द्योतक है जो "मूल्यों का अधिकारिक आवटन" करती है और व्यक्तियों तथा समूहों की मॉंगों और मतभेदों का समाधान करती है।

राज्य का आधुनिक आशय इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि"राज्य मनुष्य के उस समुदाय का नाम है जो सख्या में चाहे अधिक हो या कम, पर जो किसी निश्चित भू—खण्ड पर स्थायी रूप से बसा हो, जो किसी भी बाहरी शक्ति से मुक्त हो और जिसमें एक सगठित सरकार हो, राज्य के सारे नागरिक जिसके आदेशों के पालन के अभ्यासी हो। 2

इस प्रकार महान राजनीतिक विचारको के अनुसार राज्य के पास जनसख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार एव सप्रभुता होनी चाहिए। <sup>3</sup> जनसख्या और भू-भाग का कोई आकार निश्चित नही है, लेकिन फिर भी यह इतना अवश्य हो कि जीवन के विविध पक्षो की देख-भाल सुचारु रूप से की जा सके। सरकार की स्थित कम्पनी के सचालक की तरह होती है। जैसे सचालक कम्पनी की ओर से कार्य करते है, वैसे ही

<sup>1</sup> राजनीति के सिद्धान्त की रुपरेखा-गाबा, ओ०पी०, नेशनल पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली-1987, पृष्ठ स0 32

<sup>2</sup> राजनीति के सिद्वान्त- जैन, एम पी , आर्थर गिल्ड पब्लिकेशस, दिल्ली-1988, पृष्ठ संख्या 05

<sup>3</sup> राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त- जैन, पुखराज, साहित्य भवन आगरा-1983, पृष्ठ संख्या 76

सरंकार(गवर्नमेट), राज्य(स्टेट) की ओर से कार्य करती है क्योंकि राज्य का कोई भौतिक अस्तित्व न होने के कारण वह स्वय कुछ नहीं कर सकता। सप्रभुता, 'राज्य' की एक ऐसी शक्ति होती है, जिसके बल पर वह अपने भू-भाग में अपनी आज्ञाओं और कानूनोंका पालन कराता, तथा बाहर के राज्यों के साथ एकइकाई के रूप में किसी तरह का लेन-देन, मैं त्री या युद्ध कर सके।

"व्यापार' का आशय पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं या सेवाओं का आदान- प्रदान करना है। जब एक व्यक्ति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी वस्तु या सेवाओं का विक्रय मुद्रा या वस्तु के बदले में करता है तो ऐसी क्रिया को व्यापार की सज्ञा दी जाती है। व्यापार व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अग है जिसका मूलाधार लाभ है। इसीलिए व्यापार में वे क्रियाए शामिल नहीं की जाती जिसमें लाभ निहित न हो।

इस प्रकार सामान्य अर्थों में राजकीय व्यापार का सिम्मिलित आशय ऐसे व्यापार से हैं जो कि राज्य के द्वारा सचालित किया जाता है। इस व्यापार में लाभ सफलता का मापक तो हो सकता है लेकिन आधार नहीं। राजकीय व्यापार का आधार जनहित होता है। इसमें लाभ की भावना का निहित होना अनिवार्य नहीं है।

#### (ग) परिभाषा -

राजकीय व्यापार को समय-समय पर विभिन्न विद्वानोने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ इस प्रकार है-

"सकुचित अर्थ मे राजकीय व्यापार का तात्पर्य राज्य द्वारा किये गये आयात व निर्यात से है, अथवा ऐसी एजेन्सियो से है जो कि राज्य द्वारा नियन्त्रित हो तथा व्यावसायिक क्रय-विक्रय हेतु वस्तुओ को खरीदे व बेचे।" <sup>4</sup>

"विस्तृत अर्थ मे राजकीय व्यापार का आशय है सरकार की ओर से विदेशों से वस्तुओं की खरीद तथा आधिक्य वाली वस्तुओं का सरकार के आदेशानुसार विक्रय करना।"<sup>5</sup>

उपर्युक्त परिभाषाओं पर यदि एक साथ ध्यान दिया जाय तो भी यह सम्पूर्ण नहीं होगी क्योंकि ये परिभाषाएं फेवल राज्य के विदेशी व्यापार में योगदान पर प्रकाश डालती है, जबिक देश की सीमा के अन्दर सरकार द्वारा किया जाने वाला क्रय-विक्रय भी राजकीय व्यापार की परिधि में आता है।

<sup>4</sup> रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन स्टेट ट्रेडिंग, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया- नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या05

<sup>5</sup> वर्किंग ऑफ स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया-गुप्ता, के आर , एस चॉद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 03

जिस रामय राज्य वस्तुओ और सेवाओ का उत्पादन या वितरण या **दोनो** क्रियाए करने लगता है तो ऐसी क्रियाओ को राजकीय व्यापार कहते है। ' <sup>6</sup>

यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है क्योंकि उत्पादन को व्यापार में तब तक शामिल नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विक्रय के लिए न हों साथ ही व्यापार के लिए वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन के माध्यम से ही प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि वस्तु या सेवाएँ राज्य द्वारा खरीद कर बेची जाती है तो भी इसे राजकीय व्यापार ही कहा जायेगा।

। । ''राजकीय व्यापार देश के विदेशी व्यापार में सीधे या एजेन्ट के रूप में भाग लेता है। इसमें वे सारी क्रियाएं आती है जो कि सरकार के द्वारा आयात व निर्यात के पूर्ण करने में सम्पादित की जाती है। '7

"राजकीय व्यापार का आशय ऐसे व्यापार से है जिसमे कुछ निर्धारित वस्तुओ की खरीद एव बिक्री बाजार मूल्य का नियन्त्रण करने तथा उत्पादक और उपभोक्ता दोनो के हितो की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है।" 8

उक्त परिभाषा में उत्पादन कार्य को ध्यान में नहीं रखा गया है जबिक राज्य द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करके यदि उसकी बिक्री की जाती है तो इसे भी राजकीय व्यापार कहते हैं। इसमें राजकीय व्यापार के कार्य-क्षेत्र पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसा व्यापार आन्तरिक होगा कि बाह्य अथवा दोनो।

"राजकीय व्यापार दो प्रकार का होता है— पूर्ण राजकीय व्यापार और आशिक राजकीय व्यापार। राज्य के स्वामित्व अथवा उसकी प्रायोजक एजेन्सी के द्वारा खाद्यान्नों की खरीद एवं बिक्री को पूर्ण राजकीय व्यापार कहते हैं। यह पूर्ण नियन्त्रण और राशनिंग की मान्यता पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में यह खुली बाजार व्यवस्था पर रोक लगाता है। इसमें कोई भी निजी व्यापारी अपनी ओर से अपने लाभ के लिए खाद्यान्नों की खरीद एवं बिक्री में भाग नहीं ले सकता। आशिक राजकीय व्यापार में निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्र के व्यापारिक संगठन खुले बाजार में स्थापित होते हैं।" 9

<sup>6</sup> विपणन, विक्रयकला एव विज्ञापन-जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा -3, पृष्ठ सख्या 156

एकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एण्ड फॉरईस्ट-स्टेट ट्रेडिंग इन कन्ट्रीज ऑफ इस्कैफ रीजन जिनेवा-1964 पृष्ठ संख्या 04

<sup>8</sup> कमीशन एण्ड कॉम्पिटिशन फोर्म, आई-76ए, लक्ष्मीनगर दिल्ली, नवम्बर-1992

<sup>9</sup> मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया-गुप्ता, ए पी , वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स-बम्बई पृष्ठ संख्या-235

उपर्युक्त परिभाषा में राजकीय व्यापार के अधिकाश पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह परिभाषा इतनी विस्तृत होते हुए भी पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें भी उत्पादन के द्वारा वस्तुओं की बिक्री को परिभाषा में स्थान नहीं दिया गया है। इसमें केवल खाद्यान्नों को लिया गया है जबिक राज्य किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकता है। इसके अतिरिक्त राजकीय व्यापार की सीमा भी परिभाषा से स्पष्ट नहीं है।

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के अवलोकन के पश्चात हम राजकीय व्यापार को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं –

"जब राज्य स्वय या अपने द्वारा नियन्त्रित एजेन्सियों के माध्यम से उपभोक्ता व उत्पादक दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन व वितरण या दोनों क्रियाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करता है तो इसे राजकीय व्यापार कहते हैं।"

#### (घ) विशेषताए -

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम राजकीय व्यापार की निम्न विशेषताए प्रस्तुत करते हैं –

- राजकीय व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओ या सेवाओ का उत्पादन या वितरण या दोनो क्रियाए
   की जाती है।
  - राजकीय व्यापार आन्तरिक पा विदेशी दोनो तरह का हो सकता है।
  - राजकीय व्यापार मे जनहित प्रथम स्थान पर तथा लाभ द्वितीय स्थान पर आता है।
- देश मे वस्तुओ का अभाव होने की दशा मे राज्य विदेशों से उनको आयात करता है तािक मूल्यों में उच्चावचन न हो।
- राजकीय व्यापार मे विभिन्न देशों से वस्तुओं का क्रय-विक्रय समझौते के आधार पर किया
   जाता है।
- यह व्यापारिक क्रिया केन्द्र सरकार, राज्य सरकारे या स्थानीय सत्ताओ द्वारा पृथक -पृथक व सयुक्त रूप से सम्पादित की जाती है।
- राजकीय व्यापार के माध्यम से, जब देश में किसी वस्तु का आधिक्य हो जाता है तो उसका निर्यात कर, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की जाती है।
- राजकीय व्यापार सरकार द्वारा या उनके द्वारा स्थापित एजेन्सियो के माध्यम से सचालित
   किया जाता है।

- जब राजकीय व्यापार विभिन्स एजेन्सियो द्वारा किया जाता है तो भी इन एजेन्सियो पर सरकार का पूर्णनियन्त्रण रहता है।
- राजकीय व्यापार के अन्तर्गत सरकार उन समस्त विपणन क्रियाओ को सचालित करती है जो
   कि वस्तुओ और सेवाओ के उत्पादन एव वितरण में सहायक होती है।
  - राजकीय व्यापार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान रखा जाता है।

#### (इ ) उद्देश्य -

गरीब और अर्द्धविकसित देशों में क्षेत्रीय असमानताए धनी देशों की अपेक्षा अधिक रहती है तथा धनी देशों में क्षेत्रीय असमानताए कम होती जा रही है जबिक गरीब देशों में इनका विस्तार हो रहा है। इस मान्यता का आधार यह धारणा है कि यदि स्वतन्त्र व्यापार नीति को अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से असमानताओं के दायरे बढते जायेंगे और येअसमानताए बड़े आकार में दिखने लगेंगी। " 10

राजकीय व्यापार का मूल उद्देश्य उन वस्तुओं के व्यापार की समस्याओं का समाधान करना है जिस वस्तु के व्यापार में निजी क्षेत्र के व्यापारिक ससाधन पर्याप्त न हो। यह उन देशों के साथ व्यापार समझौता करता है जिन देशों में विदेशी व्यापार केवल सरकार के द्वारा किया जाता है क्योंकि ऐसे देश निजी व्यापारियों से विदेशी व्यापार के अनुबन्ध करने में कतराते हैं।

पूँजीवादी व्यवस्था से पहले ऐसा माना जाता था कि सरकार को व्यापार में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यवसायों को उन्मुक्त रूप से छोड़ दिया जायेगा तो शायद उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे तथा व्यवसाय अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अधिक आसानी से कर सकेंगे।परन्तु यह अनुभव किया गया कि देश की व्यावसायिक सरचना इतनी व्यवस्थित नहीं हो पायी कि उसे बिना राजकीय सहारे के निर्बाध गित से आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाय जिससे कि वह विकास की अवस्था को प्राप्त कर सके।पूँजीवाद अपने साथ गुणों से अधिक दोषों को लाया और इन्हीं दोषों के कारण व्यावसायिक क्रियाओं में राज्य को अपनी सिक्रिय भूमिका निभाने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत में राजकीय व्यापार का उद्देश्य निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है ——

1 समाजवादी विचारधारा —जुलाई—1954 में तत्कालीन सरकार ने समाजवादी विचारधारा का संकल्प लिया और दिसम्बर—1954 में ही ससद में इस बात को रखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसायों का विस्तार किया जायेगा। समाजवादी समाज के दर्शन और उनके व्यापक सिद्धान्तों ने इस विचारधारा की नयी दिशा प्रदान की। सरकार को अग्राकित क्षेत्रों का सम्पूर्ण दायित्व सीपा गया —

<sup>10</sup> व्यवसाय, समाज और सरकार -उपाध्याय, शर्मा एव सुधा, रमेश बुक डिपो, जयपुर-1988-89, पृष्ठ सख्या 157

- उत्पादन के साधनो सामाजिक लक्ष्यो तथा अर्थव्यवस्था के सन्तुलन पर सरकार द्वारा पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय।
- विद्युत, परिवहन आदि आधारभूत सरचना से सम्बन्धित वृहतस्तरीय योजनाओ को सरकार द्वारा
   शुरू करना एव उनका सुचारु सचालन करना।
- उत्पादन और श्रम के लिए प्रमाप का निर्धारण करते हुए सरकार एकाधिकारी औद्योगिक गतिविधियो पर कठोर नियन्त्रण लगाये, और

सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उसके मौलिक एव वृहत् पहलुओ के सन्दर्भ में स्वय को नियोजित करे।

- 2 योजनाबद्ध विकास की संकल्पना स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास को अपनाते हुए देश की सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया एवं उसी क्रम में प्रथम योजना 1951 से प्रारम्भ हुई। विकास की यह सतत् प्रक्रिया अभी तक चलती आ रही है। किसी भी देश में नियोजित अर्थव्यवस्था स्वीकार कर लेने के बाद राजकीय सिक्रयता एवं अर्थव्यवस्था पर उसका नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यापार को भविष्य की अनिश्चितताओं एवं उच्चावचनों पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। विकास की इस प्रक्रिया में व्यापार एवं उद्योग का केवल नियमन ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि आर्थिक क्रियाओं में सिक्रिय हिस्सेदारी योजनाबद्ध विकास की एक आवश्यकता मानी जाती है।
- 3 सिवधान की दृढ मान्यताओं की पूर्ति हेतु भारतीय सिवधान में सभी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की सुदृढ व्यवस्था का दायित्व सरकार को सौपा गया है। इसके लिए मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों को सिवधान में केवल शामिल ही नहीं किया गया है बल्कि इसे महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। सबैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा तथा जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय मिल सके। इसलिए सरकार को देश के व्यापार एवं वाणिज्य में सिक्रिय हिस्सा लेकर उन्हें नियन्त्रित करना सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
- 4 संतुलित आर्थिक विकास हेतू देश के सर्वागीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त किया जाय। निजी क्षेत्र के व्यापारी अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान उन्ही क्षेत्रों में स्थापित करना चाहते हैं जहाँ कि उन्हें स्वत एक विकसित बाजार मिल जाय तथा जहाँ पर सभी वाणिज्यिक ससाधन पहले से उपलब्ध हो। पिछडे क्षेत्र के उपभोक्ताओं की निजी क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा उपेक्षा की जाती है।

राजधानी से बहुत दूर स्थित क्षेत्रो तथा सीमावर्ती क्षेत्रो मे बसे उपभोक्ताओं के लिए आधारभूत वस्तुएँ भी उपलब्ध नहीं हो पाती जहाँ कि ग्राहक कम होने की वजह अथवा अन्य असुविधाओं के कारण निजी व्यापारी वितरण में पर्याप्त सहयोग नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने स्वय के हित को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निजी व्यापारियों पर नियन्त्रण रखने के लिए तथा देश के सतुलित विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका के निष्पादन हेतु राज्य का उत्पादन एव वितरण दोनों में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक हो जाता है। यदि राज्य व्यापार में इस प्रकार की सिक्रिय भूमिका न निभाता तो न केवल आर्थिक सन्तुलन बनाये रखना कठिन होता बल्कि यह इतना अधिक असतुलित हो जाता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

- 5 सार्वजिनक उपयोगी सेवाओं में निरन्तरता बनाये रखने हेतु राजकीय व्यापार की आवश्यकता सम्पूर्ण विश्व और वहाँ के निवासियों के जीवन में कुछ ऐसी सेवाएँ होती है जिनका निर्बाध रूप से सदैव उपलब्ध होना आवश्यक होता है। निजी क्षेत्र के निहित स्वार्थों और गतिरोधात्मक व्यवहार के कारण इन सार्वजिनक सेवाओं में सूक्ष्म गितरोध भी राष्ट्रीय जीवन के लिए असुविधाजनक होता है। सार्वजिनक उपयोगी सेवाओं में प्रमुखत डाक, तार, रेलवे एव यातायात, सुरक्षा उपक्रम , जल, विद्युत, गैस, बैक, बीमा, समुद्री परिवहन आदि आते हैं। अत इनमें निरन्तरता बनाये रखने के लिए राजकीय भागीदारी आवश्यक है।
- 6 दितीय औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिये जाने के कारण राजकीय व्यापार की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में घोषित द्वितीय औद्योगिक नीति आज भी औद्योगिक विकास का आधार मानी जाती है। इसमें सरकार को राजकीय उपक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण में राजकीय उपक्रमों के प्रयासों को महत्वपूर्ण समझा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किये गये उत्पादन का समाज में उचित प्रकार से वितरण किये बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। उचित वितरण निजी इकाइयों के माध्यम से हो पाना आसान नहीं होता है इसलिए राजकीय व्यापार की भागीदारी 1956 में तय की गयी औद्योगिक नीति के अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति का अपरिहार्य माध्यम है।
- 7 विकास की प्राथमिकताओं एवं संस्थापना सम्बन्धी निर्णयों का क्रियान्वयन —उद्योगों एवं विपणन संस्थाओं की स्थापना मनमाने तथा अव्यवस्थित ढंग से नहीं की जा सकती। किसी संस्था को कब, कहाँ और किस ढंग से स्थापित किया जाय, यह सरचनात्मक निर्णय सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था द्वारा ठीक—ठीक नहीं लिया जा सकता। उपक्रमों के उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्णय भी सरकार के द्वारा या उसकी देख—रेख में ही किया जाना चाहिए। देश के लोगों के रहन—सहन, जीवन—स्तर में सुधार, उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि तथा देश वासियों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार का सिक्रिय योगदान आवश्यक है।

- 8 अधिक जोखिम एवं कम लाभ वाली क्स्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में राजकीय सहयोग भारी एवं आधारभूत व्यापार जिनकी स्थापना और सचालन में काफी जोखिम रहता है निजी क्षेत्र द्वारा अधिक उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं। कुछ ऐसे व्यापार क्षेत्र जैसे— पेट्रोलियम और गैस, जिनकी स्थापना और उत्पादन प्रारम्भ होने के बीच की अविध काफी अधिक होती है और प्रारम्भिक वर्षों में लाभ के स्थान पर हानि होने की सम्भावना भी अधिक होती है लेकिन ऐसे उद्योग एवं उत्पादन देश के लिए अत्यन्त उपयोगी होते हैं। केवल इसिलए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण न कियाजाय कि उनकी लागत बहुत अधिक है या लाभ की सम्भावनाए बहुत कम है, विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसिलए सरकार का ऐसी वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना आवश्यक हो जाता है।
- 9 <u>आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए राजकीय व्यापार</u> डाँ० हजारी के अनुसार," आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण से पूँजी में एकाधिकार प्राप्त करने से हैं। धन के असमान वितरण से पूँजीवाद पनपता है और उपभोक्ताओं का शोषण होता है। निजी उद्योगपित एवं व्यापारी एकाधिकारी शिक्त के द्वारा अनुचित मूल्य वृद्धि, कच्चे माल के उत्पादकों का शोषण, वस्तु की किस्म में गिरावट, माल की कृत्रिम कमी आदि दोषों को जन्म देते हैं। अत इन सभी प्रकार की गितिविधियों को समाप्त करने के लिए सरकार का व्यापार में भाग लेना आवश्यक है।" 11
- 10 देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए आर्थिक अस्थिरता का व्यापार के विकास पर बुरा असर पड़ता है। तेजी अथवा मन्दी काल में व्यापारिक असुरक्षा पैदा हो जाती है। अधिक तेजी की दशा में मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है। मन्दी की स्थिति में माँग के गिर जाने के कारण उत्पादन में कमी हो जाती है तथा उद्योगों के बन्द हो जाने की स्थिति बन जाती है। अत सरकार व्यापार में स्वय भाग लेकर तेजी—मन्दी, माँग, उत्पादन, विनियोग, पूर्ति एव मूल्य आदि तत्वो पर नियन्त्रण करती है। इससे देश में आर्थिक स्थिरता आने लगती है।
- 11 <u>अकुशल निजी इकाइयो पर रोक लगाने के लिए</u> जब निजी इकाईयाँ अकुशल और रूग्ण हो जाती है तो वे राष्ट्र के ससाधनो का सदुपयोग न कर पाकर उन्हें बर्बाद करने लगती है। सरकार ऐसी इकाईयों की गूँजी , प्रबन्ध या सम्पूर्ण ससाधनों में भाग लेकर या अशदान करके उनमें अपेक्षित सुधार सम्भव बनाती है।
- 12 <u>एक आदर्श विनियोजक</u> निजी क्षेत्र के व्यापार व उद्योग मे कार्य की दशाए व अन्य सुविधाए पर्याप्त नहीं होती इसलिए अधिकाश पूँजी-श्रम विवाद निजी क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं। राज्य व्यापार एव उद्योग को अपने स्वामित्व एव प्रबन्ध में सचालित करके कर्मचारी एव उपभोक्ता दोनों के हितों को पूराकर

<sup>11</sup> व्यवसाय, समाज और सरकार-उपाध्याय, शर्मा एव सुधा, रमेश बुक डिपो, जयपुर-1988-89, पृष्ठ सख्या 167

सकता है। इस प्रकार सरकार द्वारा अपने उद्योगों को आदर्श उद्योग और अपने व्यापार को एक आदर्श व्यापार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी राजकीय व्यापार किया जाता है साथ ही इसे रोजगार वृद्धि का एक साधन भी माना जा सकता है।

- 13 स्थानीय मॉग की उचित एव स्थिर मूल्य पर पूर्ति निजी व्यापारी लाभ की भावना से प्रेरित होकर व्यापारिक क्रियाए करते हैं, फलस्वरूप वे ऐसी वस्तुओं के निर्यात का अनुबन्ध कर सकते हैं जिनकी उपलब्धता अपने देश की उपभोग्य आवश्यकता से कम हैं, जिसका परिणाम होगा कि देश के उपभोक्ता उस वस्तु के प्रयोग से वचित रह जायेगे।ऐसी कमी का प्रभाव उस वस्तु के आन्तरिक मूल्य पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। अत देश के उपभोक्ताओं को अपने ही देश मे तैयार की गयी वस्तु का मूल्य लागत से बहुत अधिक चुकाना पड़ेगा।राजकीय व्यापार के माध्यम से इस समस्या का निराकरण हो सकता है। राज्य अपनी एजेन्सी के माध्यम से देश मे उस वस्तु के कुल उत्पादन एव कुल मॉग का सही अनुमान लगाकर तद्नुसार निर्यात अनुबन्धों को स्वीकार करेगी।
- 14 <u>अनुकूल मूल्य पर आयात एव निर्यात</u> एक राज्य की सौदेबाजी की शक्ति निजी क्षेत्र के व्यापारी से कई गुना अधिक होती है, अर्थात् वह एकाधिकारी की स्थित में रहता है। ऐसी दशा में वह निजी व्यापारी की तुलना में आयात के सस्ते एव निर्यात के महेंगे अनुबन्ध प्राप्त कर सकता है फलस्वरूप देश के उत्पादकों को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य तथा उपभोक्ताओं को उपभोग सामग्री न्यूनतम मूल्य पर मिल सकती है।
- 15 <u>अभिप्रेरणा के माध्यम से क्स्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना</u> सरकार मूल्यों और अन्य अभिप्रेरणाओं से कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। वह अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने उत्पादकों को न केवल अच्छा मूल्य दिला सकती है बल्कि उत्पादन को बढाने के लिए कच्चे माल की पूर्ति को सुनिश्चित करके, लगातार ईधन उपलब्ध कराकर तथा अबाध उत्पादन प्रक्रिया जारी रखने हेतु मुद्रा में राज—सहायता प्रदान कर उत्पादकों को उत्पादन बढाने हेतु अभिप्रेरित भी कर सकती है।
- 16 <u>घरेलू मूल्य को स्थायित्व प्रदान करना</u> विशिष्ट उत्पादों के घरेलू मूल्यों को उन उत्पादों के उत्पादन और विपणन को नियन्त्रित करके सरकार स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि वह एक सप्रभुता सम्पन्न सस्था होती है। वह किसी वस्तु के उत्पादन को बढाने और किसी वस्तु के उत्पादन कम करने व रोकने का आदेश जारी कर सकती है। क्योंकि सरकार निजी व्यापारी की तुलना में माँग का सही अनुमान लगा सकती है अत तद्नुसार उत्पादन का आदेश देकर वस्तु के मूल्य को स्थायित्व प्रदान कर सकती है। यदि वस्तु की प्रकृति

इस प्रकार की है कि उसका उत्पादन आसानी से घटाना—बढाना सम्भव नहीं होता है तो सरकार ऐसी वस्तुओं के वितरण को अपने हाथ में लेकर या उस पर अपनी एजेन्सी के माध्यम से नियन्त्रण करके वस्तु के घरेलू मूल्य में स्थायित्व ला सकती है।

- 17 निर्यात योग्य आधिक्य को बेचना सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय ससाधन होते हैं जिससे वह अपने उत्पादों के लिए निर्यात बाजारों की खोज कर सकती है और यदि ऐसा बाजार पहले से उपलब्ध नहीं है तो नया बाजार बना भी सकती है। ऐसे निर्यात बाजार उपलब्ध हो जाने से देश मैं निजी आवश्यकता से हुआ अधिक उत्पादन उचित मूल्य पर निर्यात किया जा सकता है। इस प्रकार देश में पड़ा अतिरिक्त उत्पादन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक नया स्रोत बन जायेगा।
- 18 अधिक मात्रा में सौदों के निष्पादन से लाभ सरकार केन्द्रीकृत रूप में वस्तुओं की माँग एव पूर्ति का सही अनुमान लगाकर आयात-निर्यात के बड़े अनुबन्ध करती है। बड़ी मात्रा में आयात अनुबन्ध करने से वस्तु की कीमत कम चुकानी पड़ती है साथ ही ऐसी वस्तु पर परिवहन की लागत, अच्छी पैकिंग, परिवहन का अधिक सुरक्षित साधन, विभिन्न प्रकार के स्थायी कमीशनों एवं दलाली पर होने वाले खर्च की प्रति वस्तु लागत कम हो जाती है। इस प्रकार बड़ी मात्रा में आयात करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और यदि निजी क्षेत्र के व्यापारी छोटी-छोटी मात्रा में आयात करते हैं तो अन्तत उपभोक्ता इन लाभों से वचित रह जाता है। इसी प्रकार निर्यात के छोटे-छोटे अनुबन्धों में निर्यातित वस्तु का उचित मूल्य नहीं मिल पाता क्योंकि आयातक की विभिन्न प्रकार की बचते न हो पाने से वह वस्तु का अधिक मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होता है। इस प्रकार बड़ी मात्रा में सौदों के निष्पादन से होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए राजकीय व्यापार किया जाता है क्योंकि निजी व्यापारी अधिक बड़ी मात्रा में सौदों का निष्पादन करने की स्थिति में नहीं होता है।
- 19 विदेशी सहायता वाली वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की पूँजीगत एव कल्याणकारी वस्तुओं या सेवाओं के आयात पर वित्तीय सहायता, प्राय विकसित देशों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थानों के द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सस्थाएं अथवा देश निजी व्यापारियों से सम्पर्क करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि निजी व्यापारी द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के आयात में अन्य कई जटिलताए होती है जिनका निराकरण संरकार द्वारा ही आसानी से किया जा सकता है।
- 20 <u>क्यापारिक समझौतों के क्रियान्वयन को सुगम बनाना</u> दो देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध आपसी समझौतों पर निर्भर करते है। इन समझौतों में कुछ शर्ते लगायी जाती है और कुछ स्वीकार की जाती है।

निजी व्यापारी इन शर्तों को अपने हित की पूर्ति होने तक पालन करते है और जब उनके हित की पूर्ति नहीं होती तो वे शर्तों को तोड़ने लगते हैं, इससे दो देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध कटु हो जाते हैं। ऐसे समझौते लागू करवाने में सरकार की विश्वसनीयता अधिक होती है तथा ये समझौते सरकार को ही प्रस्तावित भी किये जाते हैं। अत राजकीय व्यापार के माध्यम से इन समझौतों के पूर्ण सम्मान की आशा की जा सकती है।

- 21 <u>अनिवासियों के नियन्त्रण से व्यापार को मुक्त कराने हेतू</u> जब सरकार व्यापार को गैर निवासी के नियन्त्रण से मुक्त कराना चाहती है तो उस व्यापार में वह स्वय हस्तक्षेप करती है। गैर निवासी व्यापारी लाभ कमाकर अपने देश को प्रेषित करते रहते हैं परिणाम स्वरूप उनके द्वारा देश के व्यापारिक हितों एव नागरिकों को हानि पहुँचाने के सम्भावना अधिक रहती है। सरकार उस वस्तु विशेष के व्यापार का अधिग्रहण कर स्वय अपने हाथ में ले सकती है।
- 22 कोषागार की आय बढाने के लिए आज की सरकारों को अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए बडी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। राजकीय व्यपार के माध्यम से वस्तुओं के क्रय-विक्रय द्वारा, प्रशुल्क एवं विभिन्न तरह के कर लगाकर सरकार अपनी आय को बढाने के लिए भी व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती है। निजी व्यापारी व्यापार से अर्जित की गयी आय का स्वय के लिए प्रयोग करते हैं जबिक सरकार विकास की प्राथमिकताओं को तय करते हुए अधिकतम आवश्यक मदो पर इस धन को व्यय करती है।
- 23 <u>उचित नियन्त्रण के लिए</u> व्यापारिक गतिविधियो पर उचित नियन्त्रण के लिए, अनैतिक व्यापार—व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए, आर्थिक नीति के अनुसार व्यापारिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, निजी क्षेत्र के व्यापारियों के समक्ष प्रतियोगितात्मक भूमिका प्रस्तुत करने के लिए सरकार व्यापार में हस्तक्षेप करती है। ताकि माँग, पूर्ति, मूल्य मजदूरी, आय एव सेवा सभी तत्वो पर नियन्त्रण कर सभी में सामञ्जस्य स्थापित करते हुए देश का तीव्रतम विकास किया जा सके।
- 24 असामान्य स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका देश में कोई असामान्य परिस्थिति जैसे—बाढ, अकाल, भूकम्प, महामारी आदि के आ जाने से वितरण व्यवस्था अस्त—व्यस्त हो जाती है, क्योंकि इन घटनाओं से वस्तु की माँग एव पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। यदि ऐसी दशा में व्यापार राज्य के द्वारा सचालित किया जाता रहता है तो माँग एव पूर्ति—व्यवस्था पर सरकार नियन्त्रण कर सभी को समान सुविधाए उपलब्ध करा करके समाज को सन्तुष्ट कर सकती है।
  - 25 राजकीय व्यापार के अन्य उद्देश्य इसके अन्य उद्देश्य निम्नलिखित है —— अनिवासियों को देश के राजकीय व्यापार में अवसर प्रदान करना,

- राष्ट्रीय प्रार्थामकताओं के अनुसार देश में किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार को विकसित करना
- देश को आत्मनिर्भर बनाना,
- मिश्रित अर्थव्यवस्था के उददेश्यो को प्राप्त कर ॥,
- उपभोक्ता को सरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन कार्य को बढावा देना,
- विदेशी तकनीकी सेवाओ का लाभ प्राप्त करना,
- स्वदेशी उद्योगो को सरक्षण प्रदान करना,
- पूँजी एव श्रम को गतिशील बनाना,
- प्रौद्योगिकी का लाभ जन सामान्य तक पहुँचाना।

कुछ देशो जैसे— म्यानमार(बर्मा) और इण्डोनेशिया मे राजकीय व्यापार न केवल आयात- निर्यात बिल्क उनकी राष्ट्रीय नीतियो को घरेलू क्षेत्र मे लागू करने मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबिक श्रीलका, भारत, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान तथा फिलीपीन्स मे राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय व्यापार खाद्यान्नो मे किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय व्यापार विभिन्न वस्तुओ की पूर्ति को सुनिष्टिचत करने मे तथा उनके देशी एव विदेशी मूल्य को उत्पादन एव विपणन पर नियन्त्रण करके स्थिरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। यहाँ का राजकीय व्यापार विदेश से बडी मात्रा मे खरीद का लाभ भी प्राप्त करता है।

बर्मा, श्रीलका, फिलीपीन्स तथा इण्डोनेशिया मे विदेशी व्यापारियो पर नियन्त्रण के उद देश्य से वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है। बर्मा, चीन, भारत तथा धाईलैण्ड ने राजकीय व्यापार का प्रयोग निर्यात बाजार को बढाने के उद्देश्य से किया है ताकि निर्यात योग्य आधिक्य वस्तुओं से सौदेकारी की शक्ति के आधार पर अच्छे मूल्य प्राप्त किये जा सके। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड मे राजकीय व्यापार का प्रमुख उद्देश्य निर्यात योग्य वस्तुओं से उचित मूल्य की प्राप्ति है। कम्बोडिया, नेपाल तथा वियतनाम मे राजकीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य विदेशी वित्त सहायता कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करना है।

#### (च) स्वरूप एव क्षेत्र -

एक देश रो दूसरे देश के राजकीय व्यापार के स्वरूप एव क्षेत्र में भिन्नता होती ही है यहाँ तक कि, एक ही देश के विभिन्न वस्तुओं के राजकीय व्यापार के स्वरूप एव क्षेत्रों में भी भिन्नता पायी जाती है। कुछ वस्तुओं की दशा में राज्य की भागीदारी उस वस्तु के उत्पादन से आरम्भ होकर अन्तिम उपभोक्ता तक चलती रहती है। जबिक कुछ वस्तुओं में राज्य की भागीदारी उनके निर्यात प्रतिबन्धों तक ही सीमित होती है। कुछ वस्तुओं में राज्य की भागीदारी उन वस्तुओं के खरीदकार्य एव निर्यात दोनों में होती है जबिक कुछ में राज्य उत्पादन, खरीद और निर्यात में भी पत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता बिल्क वह इन व्यवहारों का निष्पादन करने के लिए विभिन्न सिद्धान्तों को बनाकर अपने प्रतिनिधियों को

लगाता है। कुछ देशों में राजकीय व्यापार सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का एक अग होता है। ऐसे देशों में राज्य उत्पादन से लेकर आन्तिरक खरीद कार्य उसका देश में वितरण विदेश को निर्यात तथा वहाँ से आयात, समस्त हार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

निर्यात की तरह आयात के स्वरूप एव क्षेत्र मे भी विभिन्नता पायी जाती है। कुछ देशों में आयात के साथ—साथ वितरण का कार्य भी सरकार के हाथ में होता है तो कुछ में केवल आयात सरकार के द्वारा किया जाता है तथा उसका वितरण निजी व्यापारियों पर छोड़ दिया जाता है। कुछ दशाओं में आयात और वितरण दोनों कार्य निजी एजेण्टों के हाथ में होता है और राज्य केवल इन पर नियन्त्रण का कार्य करता है। कुछ देशों में वस्तुओं की पूर्ति उचित मूल्य पर बनाये ररवने के लिए देश के आन्तरिक पूर्ति कर्ता सघों के माध्यम से वस्तुओं का आयात कर घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार राजकीय व्यापार के स्वरूप और क्षेत्र को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है —

- 1 स्वतन्त्र व्यापार स्वरूप पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में राजकीय व्यापार का स्वतन्त्र स्वरूप प्रचलन में हैं। इस स्वरूप का समर्थक इगलैण्ड रहा है। इस प्रारूप के समर्थकों की मान्यता है कि व्यापारिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए और व्यापार का सचालन माँग और पूर्ति की स्वतन्त्र शक्तियों के द्वारा होना चाहिए। आयात-निर्यात प्रतिबन्धित नहीं होना चाहिए। राज्य का कार्य देश की आन्तरिक एव बाह्य सुरक्षा,शान्ति एव न्याय तक सीमित होनी चाहिए। वास्तव में कोई भी राष्ट्र इस स्वरूप को पूर्णरूप से अपनाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका उत्तरोत्तर बढती जा रही है। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युग में व्यापार पर कुछ नियन्त्रण करना आवश्यक हो गया है। तथापि राजकीय व्यापार के इस स्वरूप में व्यापार अभी भी काफी सीमा तक कडे राजकीय नियमन से बचा हुआ है।
- 2 <u>वाणिज्य वादी स्वरूप</u> यह स्वरूप काफी समय(सत्रहवी शताब्दी) से चला आ रहा है। यूरोपीय महाद्वीप में अनेव्द राष्ट्र विशेषकर फ़ास इसे आज तक अपनाये हुए है। जापान में भी यह स्वरूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साम्यवादी रूस का व्यापारिक स्वरूप भी इसके काफी निकट है। इस स्वरूप की कुछ विशेषताए निम्नवत् हैं –
- इस स्वरूप में नियात सम्बर्धन पर विशेष बल दिया जाता है। निर्यात ही इस अर्थव्यवस्था के विकास एव समृद्धि का मापदण्ड होता है।
  - व्यापारिक विवाद पारस्परिक सहयोग एव सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से निपटाये जाते है।
  - - इस स्वरूप के अन्तर्गत राजनैतिक प्रभुसत्ता एव व्यापार व्यवस्था सहविस्तृत मानी जाती है।
    - इस स्वरूप मे विश्व बाजार मे अपनी स्थिति सुदृढ बनाये रखने के लिए व्यापार व्यवस्था

एव राजनीतिक प्रभुसत्ता को स्थापित और सगठित करने पर बल दिया जाता है।

- इसमे राज्य का प्रमुख कर्तव्य राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना होता है।
- इस व्यापारिक स्वरूप मे राज्य उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ, मॉॅंगो, रुचियो, फैशनो एव सस्कृति को ध्यान मे रख कर वस्तुओं का उत्पादन करवाने की व्यवस्था करता है जिससे कि उपभोक्ताओं को अधिकतम सन्तुष्टि मिल सके।
- 3 सिवधान वादी स्वरूप देश के व्यापार को नियन्त्रित करने का यह स्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका की उन्नीसवी शताब्दी की देन है। यह स्वरूप स्वतन्त्र व्यापार नीति मे विश्वास नही रखता। इस स्वरूप मे राज्य व्यापारियों के प्रति सदैव सशकित रहता है। इसकी विशेषताए निम्नवत है—
  - यह स्वरूप व्यापारिक गतिविधियों के लिए राजनैतिक नैतिकता की सीमाए निश्चित करता है।
- यह स्वतन्त्र व्यापार नीति मे विश्वास नही रखता है। इसकी मान्यता है कि सरकार व्यापार व्यवस्था से अलग नही रह सकती।
- यह स्वरूप एण्टीट्रस्ट कानूनो, विनिमय करने वाली एजेन्सियो तथा आपराधिक अभियोगो का प्रयोग करता है। अर्थात् इसके अन्तर्गत सरकार व्यापार को कानून के द्वारा विनियमित और नियन्त्रित करती है।
- यह स्वरूप व्यापारियों के प्रति सदैव सशिकत रहता है क्योंकि इसकी मान्यता है कि व्यापारी
   वर्ग सरकार के साथ सहयोग नहीं करते।
- यह स्वरूप वाणिज्य एव उद्योग मन्त्रालय अथवा सरकार के अन्य विभागो द्वारा तय की गयी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य भी करता है।

भारत में सरकारे सिवधान के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। भारतीय सिवधान के सातवी अनुसूची के तीनो सूचियों (सघ, राज्य एवं समवर्ती सूची) में व्यापार सम्बन्धी उपबन्ध दिये गये हैं जिसमें सभी सरकारों को व्यापार करने की स्वतन्त्रता है। विदेशी व्यापार के व्यवस्था का दायित्व केन्द्र सरकार का है। सिवधान में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर, व्यापार वाणिज्य और समागम की व्यवस्था भाग–13 के अनुच्छेद 301 से 307 के अधीन दी गयी है। <sup>12</sup> इसमें दिये गये विनियमों का अनुपालन सभी सरकारों का दायित्व है।

<sup>12</sup> भारत का सविधान- विधि एव न्याय मन्त्रालय, भारत सरकार-1988, पृष्ठ संख्या 152-159

राजकीय व्यापार के वाणिज्य वादी एव सिवधान वादी स्वरूप राजनीतिक अथवा प्रशासिनक सिद्धान्त के बौद्धिक स्वरूप है। वे "क्या होना चाहिए" के मानक है जबिक वास्तविकता सदैव आदर्श तक नहीं पहुँच पाती। इस प्रकार स्पष्ट है कि दौनो प्रकार के स्वरूप सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। वाणिज्य वादी स्वरूप में व्यापार—सरकार सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे हैं तथा व्यापार पर सरकार की पकड फिसल रही है। सिवधान वादी स्वरूप में व्यापार—आय सरकार के हाथ में जाती रहती है। वास्तव में यह दौनो स्वरूप नवीन व्यापारिक समस्याओं को हल करने में अधिक सक्षम नहीं है। अत एक नये व्यापारिक स्वरूप की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

- 4 <u>नवीन व्यापार स्वरूप</u> आज विश्व का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सास्कृतिक, शैक्षणिक एव तकनीकी वातावरण दिन—प्रतिदिन बदल रहा है। इस बदलते परिवेश मे व्यापार—सरकार सम्बन्धों को निर्धारित कर, विभिन्न समस्याओं का निवारण कर सकने वाले एक नये व्यापार स्वरूप की आवश्यकता है। यद्यपि व्यापार का कोई भी नया स्वरूप दीर्घकाल की देन होता है। फिर भी एक नया स्वरूप जो कि अभी अज्ञात है, से हम कुछ विशिष्ट बातों की अपेक्षा रखते है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राजकीय व्यापार के नवीन स्वरूप में निम्न बातों का समावेश आवश्यक है—
- कोई भी आर्थिक सगठन तभी अच्छी प्रकार काम कर सकता है जब उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता एवं जवाबदेहिता प्रदान की जाय। ऐसी स्वायत्तता गतिशील अर्थव्यवस्था, कुशल एव प्रभावी प्रबन्ध तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती है। अत नया व्यापारिक स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्याप्त विकेन्द्रीयकरण हो एव जो अधिक केन्द्रीयकृत नियन्त्रण में विश्वास न रखता हो। नया स्वरूप ऐसा भी होना चाहिए कि सरकार अपने सरल कानूनों से ही व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण कर सके।
- आज का व्यवसायी विभिन्न शोध, अनुसधान एव प्रशिक्षण के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्व और नैतिक आचरण के महत्व को समझने लगा है। फिर भी व्यापार लोक प्रशासन की विषय वस्तु बनता जा रहा है। अत नया स्वरूप ऐसा हो जो सक्रिय, स्वस्थ एव सुदृढ लोकतन्त्रीय सरकारों का जन्म दे सके जो कि आश्वासन में नहीं बल्कि कर्तव्य में विश्वास रखती हो।
- -नये व्यापार स्वरूप मे मिश्रित व्यापार व्यवस्था को ही और ऊँचा स्थान प्रदान करता होगा। आज यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि न केवल राजकीय और न केवल निजी व्यापार जन साधारण की जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम है। अत इसमें मिश्रित व्यापार होना चाहिए जिसमें दोनों एक दूसरे के पूरक एव सहयोगी की भावना से काम करे।
- नवीन स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो बहुराष्ट्रो की विश्व व्यापार व्यवस्था एव राष्ट्र तथा
   राष्ट्रीय सरकारो की प्रभुसत्ता के सहअस्तित्व को स्वीकार करते हुए इनकैमध्य समन्वय स्थापित कर सके ।

## द्वितीय-सर्ग द्वितीय-सर्ग भारत में राजकीयव्यापार का विकास

#### द्वितीय-सर्ग

#### भारत मे राजकीय व्यापार का विकास

भारत में राजकीय व्यापार के विकास को निम्न तीन काल-क्रमों में बॉटा जा सकता है-

- (क) प्राचीन काल,
- (ख) मध्य काल,
- (ग) आधुनिक काल,

#### (क) प्राचीन काल मे राजकीय व्यापार का विकास

प्रागैतिहासिक मे लोग काल मूल्य, न्यूनतम मजदूरी आदि बातो को कितना महत्व देते थे, इसका प्रमाण हम्मूराबी के कोड मे मिलता है जिसमे दर्जियो तथा अन्य कामो को करने वालो की मजदूरी निश्चित थी। नावो और बकरियो मे किराये की दरो तथा बस्तुओं के मूल्यो का निर्धारण किया जाता था। 1 प्राचीन काल मे राज्य का व्यापार मे यह सहयोग अप्र-त्यक्ष रूप सेहोता था कि, यदि दो साम्राज्यों के बीच सम्बन्ध मधुर होते थे तो विदेशी एव देशी व्यापार हो पाता था अन्यथा नहीं। इस काल मे व्यापार के लिए विनिमय की दरो, बटहरो और नापो का नियमित करना आवश्यक था। मुहरो का प्रयोग सम्भवत कपडो की गाठो पर लगाने मे किया जाता था लोथल से इस सस्कृति में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात समुद्र द्वारा किया जाता था। इस काल के निर्यात के व्यापार के सम्बन्ध मे इतिहासकारों का मत है कि मेसोपोटामिया(ईराक) मे इन्द्रगोप के मनके, सीपी और हड्डी की जड़ी हुई वस्तुए जो मिली है, भारत से लायी जाती थी। भारत का हडप्पा सस्कृति केकाल मे सुमेर, एलम और टाइलोस से व्यापार होता था। सिन्धुघाटी के क्षेत्र से पश्चिमी एशिया के सूती कपडे भेजे जाते थे। 2 उस समय सोना मैसूर की खानो से, चाँदी अफगानिस्तान से तथा ताँबा ब्लूचिस्तान से आयात किया जाता था। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि इस काल में व्यापार केवल अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं था।

वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मूलत कृषि एव पशुपालन पर आधारित होते हुए भी व्यापार एव वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थी। अधिकतर व्यापार वस्तु-विनिमय द्वारा होता था। परन्तु निष्क जो आरम्भ में सोने का हार था, का प्रयोग सिक्के के रूप में होने लगा था।<sup>3</sup>

- 1 आर्थिक विचारो का इतिहास-हजेला, टी एन ,शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी-आगरा, पृष्ठ संख्या 10
- 2 प्राचीन भारत का आर्थिक एव सामाजिक इतिहास-ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड नई दिल्ली, पृ०स० 100
- 3 प्राचीन भारत का इतिहास-श्रीवास्तव, के सी , यूनाइटेड बुक डिपो-इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या 58

पूर्वमौर्य से मौर्योत्तर काल के समकालीन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक व्यापार के विकास मे लिखा है कि यातायात एव सवादवाहन साधनों को उन्नत करने की जिम्मेदारी राज्य की थी। व्यापारिक सुविधाओं के लिए भण्डार गृहों तथा विश्राम-गृहों के निर्माण की जिम्मेदारी भी राज्य की ही थी। उन दिनों भारत में स्वतन्त्र व्यापार की प्रथा प्रचलित थी। व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। इससे जो आय होती थी उस पर राज्य का अधिकार होता था।व्यापार को विकसित करने के लिए राज्य कानून बनाता था। कौटिल्य ने कुछ वस्तुओं को निर्मित करने और विभागीय एजेन्सी द्वारा उनका विक्रय करने की सलाह राज्य को दी थी।

इस काल में कल्याणकारी राज्य सम्बन्धी विचार का पूर्ण उद्भव हो चुका था। भुखमरी से हर नागरिक की रक्षा के लिए राज्य प्रशासन भोजन का निर्धारण एव वितरण करता था। प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि राज्य वित्तीय सौदो, भार तथा मापो, आवश्यक उद्योगों के नियमन तथा वस्तुओं की मिलावट को रोकने के लिए कानून बनाता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य संचालन के तीन सिद्धान्त होने चाहिए, प्रथम— राज्य को ऐसे उद्योगों में भाग लेना चाहिए जो राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाने में प्रत्यक्ष रुप से सहायक सिद्ध हो। सोना, चाँदी, हीरा, लोहा तथा अन्य धातुए राज्य के अधिकार में होनी चाहिए। दूसरे कृषि, सूत, कर्ताई तथा बुनाई, पशुपालन, दस्तकारी इत्यादि को व्यक्तियों के अधिकार में छोड़ना चाहिए और उनको स्वामित्व का अधिकार देना चाहिए। अन्त में राज्य का कर्तव्य है कि वह देखे कि उत्पादन, वितरण तथा उपभोग सम्बन्धी क्रियाओं का सचालन कुशलता पूर्वक तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो।

मौर्यकाल मे व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण था। प्रजा के हित के लिए व्यापारियों को आदेश था कि पुराना माल शासनाधिकारी की आज्ञा के बिना न तो बेचा जा सकता था और न ही बन्धक रखा जा सकता था। माप और तौल का प्रति चौथे माह पर राज्य कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण होता था कम तौलने वाले को दण्ड दिया जाता था। लाभ की दर निश्चित थी। देशी वस्तुओं पर 4 प्रतिशत और आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था। बिक्री कर न देने वालों के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान था।

मौर्यात्तर काल मे व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण न था। फिर भी जो व्यापारी राज्य के नियमों का पालन नहीं करते थे उन्हें दण्ड दिया जाता था। मनु ने लिखा है कि यदि कोई व्यापारी ऐसी किसी वस्तु का निर्यात करे जिस पर राज्य का एकाधिकार हो तो राजा को उसकी पूरी सम्पत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। राजा को व्यापारी तथा खरीददार दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उसे वस्तु की खरीद, उसको रखने तथा लाने में जो खर्च लगा हो इन सभी का हिसाब लगाकर व्यापारी की लागत का हिसाब लगाना चाहिए। राजा को हर पन्द्रह दिन पर वस्तुओं के मूल्य सूची का नियन्त्रण करना चाहिए कि व्यापारी नापने

<sup>4</sup> आर्थिक विचारों का इतिहास -हजेला, टी एन , शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी-आगरा, पृष्ठ स0 515-519

और तौलने के ठीक बाट और पैमाने प्रयोग में ला रहे हैं। राजा को व्यापारी के लाभ पर 5 प्रतिशत कर लगाना चाहिए न कि लागत पर। <sup>5</sup>

गुप्तकाल में भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केन्द्र हो गया था। जब कोई व्यापारी माल लेकर अपने देश में लौटा हो और आते ही उसकी मृत्यु हो जाय तो राजा उसके उत्तराधिकारी को उसका माल दे देता था किन्तु यदि 10 वर्ष तक उस माल का कोई दावेदार न आये तो राजा स्वय उसका उपभोग कर सकता था। नारद और वृहस्पित ने विक्रेता तथा क्रेता दोनों के हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम दिये हैं। नारद के अनुसार यदि क्रेता क्स्तु को खरीदनें के बाद यह समझे कि उसने उस वस्तु का मृल्य अधिक दे दिया है तो उस वस्तु को बिना उसके प्रयोग किये लौटा सकता था और अपना पूरा मृल्य वापस ले सकता था। यह वापसी का कार्य यदि खरीद के दिन से अगले दिन किया जाय तो उसे खरीद के मृल्य से 1/30 भाग कम मृल्य मिलता था। तीसरे दिन लौटाने पर 1/15 भाग और उसके बाद दुकानदार वस्तु लौटाने के लिए बाध्य नहीं होता था। वृहस्पित ने लिखा है कि यदि वस्तु के दोष को बताये बिना कोई व्यापारी किसी वस्तु को बेचता था तो खरीददार को उसे उस वस्तु के मृल्य का दूना लौटाना पडता था और उसे सरकार को वस्तु के बेचता था तो खरीददार को उसे उस वस्तु के मृल्य का दूना लौटाना पडता था और उसे सरकार को वस्तु के मृल्य के बराबर जुर्माना देना पडता था। इस प्रकार इन नियमों से स्पष्ट है कि उस समय बाजार का नियन्त्रण सुव्यवस्थित नियमों के अन्तर्गत राज्य द्वारा होता था, और कोई व्यापारी मनमानी नहीं कर सकता था।

मौर्यकाल में वस्तुओं के मूल्य सरकार द्वारा तय किये जाते थे किन्तु गुप्तकाल का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि इस काल में भी वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु बेच दे जिसका वह स्वामी नहीं है तो ऐसी बिक्री मान्य नहीं थी। वस्तुओं का मूल्य माँग पर निर्भर करता था। इस प्रकार श्रीलका और चीन के सार्थ विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात व्यापार, कम्बोडिया को केवल हीरा, चन्दन और केसर का निर्यात, अरब से अच्छे घोडों का आयात होता था। इसके अलावा रोम, ईरान, तथा ईथियोपिया से भी व्यापार होता था।

गुप्तोत्तर काल में भी राज्य व्यापार में सहयोग करता था किन्तु इस काल में कुछ विशिष्ट व्यापारियों के प्रति राज्य के असन्तोष का उल्लेख मिलता है।गाहडवाल शासको ने मुसलमान व्यापारियों को रोकने के लिए 'तुरुष्क दण्ड' नाम का कर वसूल किया अर्थात् अपने देश के मूल निवासियों के व्यापार संरक्षण की भावना गुप्तोत्तर काल के शासकों में ही उत्पन्न हो गयी थी। भारतीय नरेशों विशेषकर बगाल

<sup>5.</sup> भारत का आर्थिक एव सामाजिक इतिहास-ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न, लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ स0 107

<sup>6</sup> प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास-ओम प्रकाश, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड-नई दिल्ली, पृष्ठ स0 121

के पाल और सेन तथा दक्षिण के पल्लव और चोल राजाओ ने चीन सम्राट के राज दरबार में अपने राजदूतों को भेजने का ताँता बाँधकर चीन के साथ व्यापार बढाने की चेष्टा की। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन भारतीय शासकों में भी अपनी प्रजा को उनके उपभोग हेतु उन वस्तुओं को उपलब्ध कराने की लालसा रहती थी जो कि भारतवर्ष में आसानी से तैयार नहीं की जा सकती थी।

#### (ख) मध्य काल मे राजकीय व्यापार का विकास -

राजकीय व्यापार के इतिहास में सल्तनतकालीन अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियन्त्रण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजार नियन्त्रण के पीछे उसका उद्देश्य राजनीति से प्रेरित हो सकता था, क्योंकि उसकी लगातार विजयो और मगोल आक्रमणो ने उसके लिए एक विशाल सेना रखना अनिवार्य कर दिया था। राज्य के कर्मचारियो तथा सैनिको और दीवानी प्रशासन पर अत्यधिक व्यय होता था। व्यय इतना अधिक धा कि उपज का 50 प्रतिशत कर लगाकर, विभिन्न प्रकार के अन्य कर लगाकर और सोने—चाँदी के पेय पात्रो को सिक्के मे परिवर्तित करके भी राज्य की आवश्यकताए केवल 5–6 वर्षों तक ही पूरी हो पाती। यह तो कहना कठिन है कि अलाउद्दीन के आर्थिक—सुधार केवल सेना को ही ध्यान मे रख कर किये गये थे क्योंकि आर्थिक नीतियो को विजय—दौड के समाप्त होने के बाद भी चालू रखा गया था।

वह एक विस्तृत गुन्तचर प्रणाली पर भरोसा रखता था और अनुचित व्यापार प्रणाली में सहभागी व्यक्तियों को दण्ड देने में कोई छूट नहीं देता था। उसका प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम (जाब्ता) सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित करने से सम्बन्धित था। उसने गेहूँ, जौ, धान, चना, दाल, चीनी, तेल और नमक इत्यादि वस्तुओं की मूल्य सूची जारी की थी जिसमें कोई भी वृद्धि नहीं की जा सकती थी। गल्ला मन्डी के भाव की स्थिरता उसके राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जब तक जीवित रहा इन मूल्यों में तिनक भी वृद्धि नहीं हुई, हाँ कीमते कम व नीची अवश्य कर दी गयी थी।

कीमते निश्चित करके सुल्तान ने अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किये। यहाँ से जनता व दुकानदार अन्न आदि खरीद सकते थे। अनाज बाजार मे दो प्रकार के व्यापारी थे, प्रथम— वे जिनकी दिल्ली में स्थायी दुकाने थी तथा द्वितीय—काफिले वाले व्यापारी,जो नगर मे अनाज लाते

<sup>7.</sup> मध्यकालीन भारत-प्रो0 सतीशचन्द्र, एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 66

<sup>8</sup> मध्यकालीन भारत-वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ स० 21 4

<sup>9</sup> मध्यकालीन भारत- शर्मा, एल पी , लक्ष्मी नारायण अग्रवाल-आगरा-3, पृष्ठ सख्या- 96

<sup>10</sup> भारत का वृहत् इतिहास-मजूमदार, राय चौधरी एव दत्त, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड-मद्रास, पृष्ठ स0 33

थे और उसे दुकानदारो और जनता को बेचते थे।अलाउद्दीन के नवीन आदेशो के परिणामस्वरूप व्यापारियों को मुनाफाखोरी का अवसर नहीं मिलता था। उत्पादन मूल्य उत्पादकों के लागत से बहुत अधिक नहीं होता था। इससे उत्पादकों को उनकी लागत का उचित मूल्य भी मिलता था और व्यापारियों को अधिक मुनाफाखोरी का अवसर भी नहीं मिलता था। उन्हें बाजार के शहना(बाजार—अधीक्षक) के पास अपने नाम दर्ज कराने पड़ते थे। सामान्य समय में इन व्यापारियों ने बाजारों में पूरा अनाज लाने के करारनामों पर सामूहिक और व्यक्तिगत हस्ताक्षर किये। इस काल में सरकारी गोदाम छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि बाजार में अनाज मुक्त रूप से उपलब्ध था।

खिलजी ने घुमक्कड व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें आसानी से अनाज उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाये। दोआब और दिल्ली के आस-पास के प्रदेशों के समस्त वण्डाधिकारियों तथा राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सुल्तान को इस आशय का लिखित करार दे कि वे कृषकों को उनकी उपज का 50 प्रतिशत भू-राजस्व उपज में ही वसूल करेगे। इस प्रकार सारा उपलब्ध अनाज बाजार में आता था। उसे भण्डारगृहों में रखा जाता था। सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर पूर्ण रोक लगा दी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तन का सामना करने के लिए राजकीय अन्त भण्डार बनाये। 11 इनसे अनाज केवल आपात्कालीन स्थित में ही निकाला जाता था। वर्षा की कमी या अन्य किसी कारण से यदि फसल नष्ट हो जाय या यातायात के किसी सकट के कारण राजधानी में अनाज न आ पाये तो इन गोदामों में से अनाज निकालकर घुमक्कड व्यापारियों को अनाज मण्डी में बेचने के लिए दिया जाता था।

ऐसे भी प्रमाण मिलते है कि अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। नगर के सम्पन्न व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। यह व्यवस्था केवल अकाल के समय लागू थी। अनुकूल मौसमों में लोग इच्छानुसार अनाज खरीद सकते थे। इस प्रकार राशन की पद्धित अलाउद्दीनकी नईसूझ थी लेकिन राशन कार्ड आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति बाजार जाता था उसे निर्धारित मात्रा में अनाज दे दिया जाता था।

सराय ए अदल (अर्थात् — न्याय का स्थान), निर्मित वस्तुओ तथा बाहर के प्रदेशो, अधीनस्थ राज्यो तथा विदेशो से आने वाले माल का सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। 2 यहाँ पर आने वाली वस्तुएँ थी — कपड़ा, शक्कर, जडी — बूटी, मेवा और दीपक जलाने का तेल। सुल्तान का आदेश था कि

-

<sup>11</sup> मध्यकालीन भारत-वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यात्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय-पृष्ठ स0 2 17

<sup>12</sup> भारत का वृहत् इतिहास-मजूमदार, राय चौधरी एव दत्त, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, मद्रास, पृष्ठ स0 34

प्रत्येक वस्तु जो व्यापारी खरीदे, भले ही उनका मूल्य एक टके से 10 हजार टके तक हो, बदायूँ द्वार के निकट स्थित इस बाजार मे अवश्य लायी जाय। जो इस नियम का उल्लंघन करता था उसकी वस्तुए जब्त करने के साथ ही उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। बरनी ने रेशमी व सूती कपड़ो की एक लम्बी सूची दी है जिनकी कीमते निश्चित कर दी गयी थी। कपड़े की कीमतो के निर्धारण से व्यापारी दिल्ली मे माल बेचने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि उनको अधिक लाभ नहीं होता था। 13

अलाउद्दीन ने दिल्ली में व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को, चाहे व हिन्दू हो या मुसलमान, दीवान—ए— रियासत (वाणिज्य मन्त्रालय) में अपना नाम दर्ज कराने का आदेश दिया। उसे एक ऐसे करारनामें पर हस्ताक्षर भी करने पड़ते थे कि वे निश्चित मात्रा में माल नगर में लायेंगे तथा उसे नियन्त्रित दरों पर बेचेंगे। सुल्तान ने राजकीय कोष से मुल्तानी व्यापारियों को धन अग्रिम रूप में दिया जिससे कि वे अन्यत्र माल खरीद कर नियन्त्रित दरों पर सराय—ए—अदल में बेच सके। इब्नबतूता के अनुसार सुल्तान ने व्यापारिक माल पर समस्त कर समाप्त कर दिये, व्यापारियों को अग्रिम धन दिया और कहा, "इस धन से बैल और भेड़े खरीदों और उन्हें बेचों, उनसे जो धन प्राप्त होगा वह कोषागार में चुका देना चाहिए और बेचने के उपलक्ष्य में तुम्हें भत्ता मिलेगा।" इससे प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति व्यापारी नहीं बिल्क शासन के एजेण्ट थे। उन्हें बाहर से माल खरीदकर दिल्ली में बेचने के लिए अग्रिम धन दिया जाता था और वे इस कार्य के लिए पारिश्रमिक पाते थे।

अगला अधिनियम परवाना नवीस(परिमट देने वाले अधिकारी) की नियुक्ति एव अधिकार से सम्बन्धित था। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि बहुमूल्य वस्त्र जैसे-कजमाबरी, सुनहरी जरी, देविगिर रेशम तब तक नहीं बेचे जा सकते थे जब तक कि परवाना नवीस लेने वाले अमीरो, मालिको अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परिचय पत्र से वह सन्तुष्ट न हो तथा उनकी आय के आधार पर परिमट न दे।

घोडो, दासो और मवेशियो के बाजार पर निम्न चार नियम लागू होते थे-

- किस्म के अनुसार मूल्य का निश्चय,
- व्यापारियो और पूँजीपितयो का बिहिष्कार।
- दलालो पर कठिन नियन्त्रण और,
- सुल्तान द्वारा नियमित जॉंच पडताल । <sup>14</sup>

कीमतो को कम बनाये रखने के लिए अलाउद्दीन ने घोड़ों के दलालों और मध्यस्थों से कठोरता का व्यवहार किया। उन दिनों के दलाल और मध्यस्थ इतने उद्दण्ड थे कि वे क्रेसा और विक्रेता दोनों से प्रत्येक लेन-देन में कमीशन लेते थे। खिलजी ने दुष्ट दलालों को समाप्त करने के लिए आजीवन

<sup>13</sup> मध्यकालीन भारत-शर्मा, एल0पी0, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा-3, पृष्ठ संख्या- 98

<sup>14</sup> मध्यकालीन भारत-वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, विल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ स0 220

कारावास तक का दण्ड दिया। जब कुछ समय बाद मूल्य स्थिर हो गये तो दलालों को सुल्तान द्वारा निश्चित दरों पर क्रय-विक्रय की अनुमित दे दी गयी। घोडों के मूल्यों पर नियन्त्रण हेतु वह स्वयं दलालों को दो मास के अन्तराल पर बुलवा कर कठोर एव विस्तृत जानकारी प्राप्त करता था।

बड़े बाजारों के अतिरिक्त अन्य छोटी वस्तुओं के मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित किये गये थे। मिठाई, सब्जी, कघी चप्पल, जूते, मौजे, कटोरी, सूई, सुपारी, पान, गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि सामान्य बाजार में बिकने वाली प्रत्येक वस्तु की मूल्य सूची बनायी गयी थी। राज्य द्वारा स्वीकृत सूची वाणिज्य मन्त्रालय को दे दी जाती थी। दिल्ली के बाजारों के महानिरीक्षक विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजारों के 'शहना' नियुक्त करते थे जो बाजार में मूल्य सूची लागू कराते थे। 'नाजिर याकूब'(नाप-तौल अधिकारी) की कठोर देखभाल के बावजूद भी व्यापारी ग्राहकों को छलते थे, खोंटे बाट रखते थे तथा अच्छी किस्म की वस्तुओं को अलग रखते थे। परिणामत अलाउद दीन अपने छोटे गुलाम लडकों को कुछ जीतल (मुद्रा) देकर भिन्न-भिन्न वस्तुए खरीदने को भेजता था। याकूब इन लडकों द्वारा लाये गये सामान की जाँच करता था। यदि कोई दुकानदार कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही माँस काट लिया जाता था। इस कड़े नियन्त्रण का प्रभाव यह पड़ा कि बाजार व्यवस्थित हो गया तथा कीमते स्थिर हो गयी।

खिलजी की बाजार व्यवस्था से किसान, कारीगर एव व्यापारी खुश नहीं थे। किसान को अपनी उपज का आधा भाग कर, कुछ अन्य कर तथा बची उपज को सरकारी व्यापारियों को निश्चित मूल्य पर बेचना पडता था। कारीगर एव व्यापारियों का लाभ भी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था। ऐसी स्थिति में व्यापार तथा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से उसके बाजार नियन्त्रण की महत्ता एव व्यापार में राजकीय हस्तक्षेप के सराहनीय उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता। उसका उद्देश्य था कि दैनिक आवश्यकताओं व सामान्य खाद्य पदार्थों के मूल्यों को इतना गिरा दिया जाय कि प्रत्येक सैनिक और आम व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके। वह अपने उद्देश्य में पूर्णत सफल रहा।

मुगलकाल मे थोक व्यापारियो(सेठ या वोहरा) दुकानदारों, सर्राफों व साहूकारों और गुमाशतों एवं दलालों के अलग—अलग व्यावसायिक समूह बन गये थे। सतीशचन्द्र के मतानुसार विपणन के क्षेत्र में तीव्र प्रतियोगिता थी। 15 बर्नियर ने ऐसे व्यापारियों का उल्लेख किया है जिनके पास 80 लाख रुपये तक की सम्पत्ति थी और जिनका व्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनी से कम नहीं था।बिरजी, वोहरा तथा कासी वीरन्ना का कुछ वस्तुओं पर एकाधिकार था और कुछ व्यापारियों में इसी प्रकार के एकाधिकार प्राप्त करने की उच्च आकाक्षाए भी थी लेकिन मुगल शासकों का ऐसे व्यापारियों पर भी कोई नियन्त्रण नहीं था।

<sup>15</sup> मध्यकालीन भारत-शर्मा, एल०पी०, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा-3, पृष्ठ सख्या 490

17वी शताब्दी के उत्तरार्व्ह में दूर के बाजारों के लिए अधिकाशत ददनी (अर्थात—अग्रिम सिवदा) के आधार पर माल खरीदा जाने लगा। तथापि बड़ी पूँजी वाला बड़ा शहजादा व्यापारी स्वय व्यापारियों से माल खरीद लेता था तथा अग्रिम सिवदा के बिना पूरा बाजार स्वय समेट लेता था। फिर भी सरकार व्यापारियों पर यदा—कदा ही हस्तक्षेप करती थी बशर्ते कि बन्दरगाहों पर शान्ति बनी रहे तथा सरकारी राजस्व सुचारु रूप से एकत्रित किया जाता रहे। इस प्रकार भारतीय विदेश व्यापारी को न तो अपने राज्य का सरक्षण मिला हुआ था और न ही सरकार का उसे कोई डर था। व्यापारी वर्ग इस काल में तीव्र प्रतियोगिता वाले वातावरण में रहा किन्तु उसने प्रतियोगिता सम्बन्धी सामाजिक सीमाओं को स्वीकार किया।

मुगल काल मे शासन की व्यापारिक नीति व उचित नियन्त्रण के अभाव में उत्पादक व उपभोक्ता आपस में एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते थे। जिसका लाभ शासक वर्ग को प्राप्त होता था। वस्तुओं का उत्पादन समाज की आवश्यकतानुसार न होकर, अमीर वर्ग या शासक वर्ग की इच्छा पर होता था। उपभोक्ता वर्ग कई भागों में विभक्त था जिससे उनमें कोई सगठन नहीं बन पा रहा था। अमीर लोग धन लोलुपता एव विलासिता के शिकजे में बुरी तरह जकड़ गये थे।

आरम्भ में अग्रेजों ने मुगल दरबार में उपस्थित होकर कुछ छोटी-छोटी सुविधाए प्राप्त की और धीरे-धीरे मुगल बादशाहों की आज्ञा से व्यापार करना आरम्भ किया। देश की राजनीतिक दुर्व्यवस्था को देखते हुए अग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आयी। मुगल शाही सेना व मराठों तथा अन्य दकनी राज्यों के बीच दीर्घकालीन युद्धों, बगाल में सुबेदारों की निर्बलता, मालाबार में समुद्री डाकुओं के उपद्रव और इनसे प्रतिरक्षा की आवश्यकता आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने इस व्यापारिक कम्पनी को एक राजनीतिक शक्ति बनने का अवसर दिया। वर्ष 1969 में बम्बई के गवर्नर जेराल्ड औंगियर ने कोर्ट आफ डायरेक्टर्स को लिखा था कि 'अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तसवार लेकर अपने व्यापार का प्रबन्ध करे। इस प्रकार जो प्रक्रिया भारतीय मसालों को प्राप्त करने के लिए प्रतिगालियों द्वारा आरम्भ हुई थी वह पूरे देश को अग्रेजी उपनिवेश बनाने तक जारी रही।

# (ग) आधुनिक काल में राजकीय व्यापार का विकास

आधुनिक काल में भारत में राजकीय व्यापार के विकास का सुविधापूर्वक विश्लेषण करने के लिए हम इसके सम्पूर्ण विकास-क्रम को दो भागो में बॉट सकते हैं-

<sup>16</sup> मध्यकालीन भारत-भाग दो-वर्मा, हरिश्चन्द्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय; पृष्ठ सख्या 432

- 1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय व्यापार,
- 2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजकीय व्यापार ।
- 1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय व्यापार प्रारम्भ मे भारतीय शासको ने ही यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों के कर से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों को भारत में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और बाद में इन कम्पनियों ने भारत की व्यापारिक नीतियों को अपने हाथ में लेकर भारतीय व्यापार और उसके उपभोक्ता को अनदेखा करते हुए अपने हित में व्यापारिक नियमों का संशोधन किया। वर्ष 1600 से लेकर 1757 तक भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भूमिका एक व्यापारिक निगम की थी। वह भारत में बाहर से बहुमूल्य वस्तुए तथा धातुए लाती थी और उनका विनिमय कपड़ों, मसालों आदि भारतीय वस्तुओं से करती थीं, और तब उन्हें बाहर ले जाकर बेचती थीं। उसकी आय मुख्य रूप से भारतीय वस्तुओं को विदेशों में बेचने से होती थीं। इस प्रकार कम्पनी ने तैयार भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाया और उसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया। अन्य कारणों के साथ एक कारण यह भी था जिससे भारतीय शासकों ने भारत में कम्पनी के कारखानों की स्थापना को न केवल बर्वाशत किया बल्क प्रोत्साहन भी दिया।

प्रारम्भ से ही ब्रिटिश कपडा निर्माता ब्रिटेन में भारतीय कपडो की लोकप्रियता से जलते थें। एकाएक पहनावें के फैशनों में परिवर्तन हो गया और हल्के सूती कपडों ने अग्रेजों के मोटे ऊनी कपडों की जगह लेना आरम्भ कर दी। ब्रिटिश निर्माताओं ने इगलैण्ड में भारतीय वस्तओं की बिक्री को नियन्त्रित करने और उस पर पाबन्दी लगाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डाला। 1720 तक कानून पास कर इगलैण्ड में रंगे हुए सूती कपडे पहनने व इस्तेमाल करने की मनाही कर दी गई। इसके अलावा सादे कपडे पर भारी आयात शुल्क लगा दिया गया।हालैण्ड को छोडकर अन्य योरोपीय देशों में भी भारतीय कपडे केआयात पर मनाही कर दी गयी या भारी आयात शुल्क लगा दिया गया, लेकिन फिर भी भारतीय रेशम व सूती कपडे अठारहवी शताब्दी के मध्य तक विदेशों में जमें रहे। 17

कम्पनी को मुगल बादशाह से 1717 में एक शाही फरमान(राजकीय आज्ञापत्र) मिला जिसके फलस्वरूप उसे बहुमूल्य विशेषाधिकार मिल गया। कम्पनी को बिना टैक्स दिये बगाल में अपने मालो का आयात-निर्यात करने की आज्ञा दे दी गई। उसे माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए दस्तक (पास) जारी करने का अधिकार दे दिया गया।

<sup>17</sup> आधुनिक भारत-विपिन चन्द्र,एन सी ई आर टी ,नई दिल्ली-पृष्ठ सख्या-76

<sup>18</sup> आधुनिक भारत का इतिहास- शुक्ला, राम लखन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या—60

ब्रिटिश विनिर्माता ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पूर्वी व्यापार पर उसके एकाधिकार और भारत के राजस्व एव निर्यात व्यापार के नियन्त्रण के माध्यम से भारत के शोषण के तरीकों को अपने सपनों के साकार होने के मार्ग में बाधा समझते थे। उन्होंने 1793 और 1813 के बीच कम्पनी और उसके व्यापारिक विशेषाधिकारों के खिलाफ एक शक्तिशाली अभियान छेडा। अन्ततोगत्वा 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय व्यापार पर उसके एकाधिकार को समाप्त करने में सफल हो गये।

भारत सरकार ने मुक्त व्यापार या ब्रिटिश वस्तुओं के बेरोक—टोक प्रवेश की नीति को अपनाया। विदेशी शासकों ने न केवल भारतीय व्यापारिक हितों की रक्षा नहीं की बल्कि विदेशी वस्तुओं के मुक्त प्रवेश के लिए भारत के दरवाजे भी खोल दिए परिणामस्वरूप केवल ब्रिटिश कपडे का आयात जो 1813 में एक लाख दस हजार पौण्ड मूल्य का था। 1856 में तिरसठ लाख पौण्ड मूल्य का हो गया। 1840 की संसदीय जाँच समिति में बताया गया कि भारत आने वाले ब्रिटिश सूती और रेशमी सामानो पर जहाँ 3 5 प्रतिशत, उनी सामानो पर 2 प्रतिशत कर लगता था वही ब्रिटेन में भारत से आने वाले सूती कपडे पर 10 प्रतिशत, रेशमी कपडे पर 20प्रतिशत कर लगाया जाता था। ऐसे निषेधात्मक आयात शुल्कों और मशीन उद्योगों के फलस्वरूप, विदेशों को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं में तेजी से कमी हुई। 19

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अग्रेजो के शासनकाल में उनकी दमन व शोषण नीति के परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार की दशा अत्यन्त दयनीय थी। आवश्यक वस्तुओं का सर्वथा अभाव था। नैसर्गिक प्रकोपों से सुरक्षा का उपाय न किये जाने के कारण भारतीयों को खाद्यान्नों के लिए तरसना पड़ता था। शासन की ओर से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व वितरण की कोई भी समुचित व्यवस्था न थी, बिल्क इसके विपरीत 1770 में बगाल के भयकर अकाल के कारण वस्तुओं के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गयी कि जनता के पास इतना धन नहीं था कि वे वस्तु को खरीद सके। इसके बावजूद भी सरकार ने कड़ाई के साथ लगान वसूल किया। 1876-77 में जब अकाल पड़ा हुआ था तो ब्रिटिश सरकार लाभ कमाने के लिए यूरोप को गेहूँ का निर्यात कर रही थी। ब्रिटिश काल में आम भारतीयों के लिए उत्पादन व वितरण के प्रति पूर्ण उपेक्षा की नीति को अपनाया गया था जबिक नैतिक मूल्यों के आधार पर जनता को सुरक्षा एव न्याय दिलाने के साथ-साथ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित ढंग से आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराना सरकार का राजकीय एव मानवीय दायित्व होता है।

बीसवी शताब्दी के दूसरे दशक में प्रथम विश्वयुद्ध के कारण वस्तुओं के अभावों की पूर्ति और मूल्य वृद्धि पर नियत्रण करने के लिए भारत में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी। 1929-30 की व्यापक

<sup>19</sup> आधुनिक भारत का इतिहास—शुक्ला, आर एल , हिन्दी माध्यम, कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ संख्या— 56

आर्थिक मन्दी का प्रभाव काफी समय तक बना रहा। लोगों की क्रय शक्ति काफी कम हो गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व निर्धनता अधिक होने के कारण माँग कम रहती थी जिससे वस्तुओं की कमी का आभास नहीं हो पाता था। उपभोक्ता अभावों में भी गुजारा कर लेते थे। फलस्वरूप जमाखोरी और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। परन्तु बाद में प्राकृतिक कमी और उपभोक्ता की मनोवृत्ति के कारण व्यापार व्यवस्था अस्त—व्यस्त हो गयी। उत्पादक व व्यवसायी वर्ग आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को रोक कर कीमतों को बढाने में सहयोग कर रहे थे। इस समय उपभोग्य सामग्री के मूल्य में वृद्धि असमान रूप से हो रही थी।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् दो महत्वपूर्ण घटनाओं के परिणामस्वरूप राजकीय व्यापार का विकास हुआ और प्रत्येक देश की सरकार ने इस ओर अपना ध्यान दिया। प्रथम, सोवियत सघ ने 22 अक्टूबर, 1918 को एक अधिनियम पारित किया जिससे कि विदेशी व्यापार पर राज्य सरकार का एकाधिकार हो गया तथा द्वितीय कारण, 1929 की विश्व व्यापी महान आर्थिक मन्दी जो मुख्यतया कृषि उत्पादों में हुई, जिससे बेकारी बढी, विश्व का व्यापार सन्तुलन असन्तुलित हो गया और पूँजी की गतिशीलता में गरावट आयी इन सभी घटनाओं के कारण विदेशी व्यापार पर पर्याप्त नियन्त्रण करना पडा। द्वितीय विश्वयुद्ध ने भी राजकीय व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, उस समय मूल्य बढ रहे थे तथा उत्पादन सीमित था। अत सरकार ने खाद्यान्न, चीनी, कपडे व गैस का वितरण अपने हाथ में ले लिया, जो राशनिंग के नाम से जाना जाता है। युद्धोत्तर अविध में समाजवाद और नियोजन के उद्भव ने भी विश्व— व्यापार में सरकारी सहभागिता में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक ऐसा अभिकरण स्थापित करने का विचार सरकार के सम्मुख आया जो कि विदेशी व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और साथ ही परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप समय—समय पर वह अभिकरण अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करके अपने कार्यों का निष्पादन करें 20 युद्ध के समय भारतीय व्यावसायिक समुदाय ने स्वय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार हेतु एक अभिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया क्योंकि भारतीय व्यापारी विदेशी शासकों के कपटपूर्ण एव सौतेले व्यवहार से डरते थे। वे भारत में भारतीयों को न केवल भारतीय व्यापार से विचत करते थे अपितु व्यापार के लाभों से विचत करते थे। यहाँ तक कि वे भारतीयों को व्यावसायिक मामलों में अधिकार प्राप्त व्यापार के लाभों नहीं करने देते थे। यहाँ तक कि वे भारतीयों को व्यावसायिक मामलों में अधिकार प्राप्त व्यापारी अपने कार्यों को उचित ढग से कर पाने में अक्षम है। इसलिए सरकार वहाँ पर अपना एक राजकीय व्यापारिक अभिकरण स्थापित करें जहाँ पहले निजी व्यापारी व्यापार करते थे लेकिन अब उस व्यापार को करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। इस प्रकार स्थापित किया गया अभिकरण देश के आयात—निर्यात व्यापार का और अधिक विकास करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परन्तु भारत की तात्कालिक परिस्थिति जिसमें नीचे मूल्यों पर निर्यात हेतु बडी मात्रा में की जाने वाली खरीददारी, कुछ सीमित मदो में ही स्वतन्त्र व्यापार 20 राजकीय व्यापार पर गठित कमेटी का प्रतिवेदन, नई दिल्ली—1950, पूष्ठ सख्या 2—4

की सुविधा, देश मे राजनैतिक उथल-पुथल और अन्य अनेक कारणो से भारतीय व्यावसायिक समुदाय द्वारा विदेशी व्यापार हेतु राजकीय अभिकरण की स्थापना के सुझाव पर अमल नही किया जा सका।

(2) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजकीय व्यापार — 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक जीवन से मुक्ति मिलने के बाद भारत में नीति निर्माणकों को इस विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक सोचने और लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन करने का अवसर मिला। 1947 के उत्तरार्ध्ध और 1948 के पूर्वार्ध्ध में ही इस विषय पर पुन विचार किया गया। विचार—विमर्श से यह तथ्य प्रकाश में आया कि—भारत वर्ष में मूल्यों में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, भारत द्वारा विदेशों से आयातित खाद्यान्न के लिए बहुत ऊँचा मूल्य चुकाया जा रहा है साथ ही ये मूल्य भेदभाव पूर्ण है। और यदि सरकार निर्यात व्यापार को निजी क्षेत्र के लिए छोड देगी तो उनके द्वारा न केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर बहुत अधिक लाभ कमाया जायेगा बिल्क उनके स्वार्थमरक व्यापारिक व्यवहारों का भार विदेशी बाजार को उठाना पडेगा। सरकार ने मामले का विधिवत् परीक्षण किया और निर्णय लिया कि कपडा, मैंग्नीज, तिलहन और वनस्पित तेल के देश के आन्तरिक और निर्यात गूल्य के अन्तर को समाप्त करने के लिए निर्यात कर लगाया जाय।

मार्च 1948 में श्री आर0सीं0 गोयनका ने यह मामला केन्द्रीय विधायिका में कटौती प्रस्ताव के खप में उठाते हुए कहा कि सरकार को खाद्यान्नों के आन्तरिक और विदेशी मूल्य के बीच भारी अन्तर तथा बहुत अधिक लाभ की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या सरकार इस अन्तर को कम करने तथा लाभ को नियन्त्रित करने के लिए राजकीय संसाधनों से कोई निगम स्थापित करेगी? इसके उत्तर में तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री मा सी एच भाभा ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

मार्च 1949 में मा के सी नियोगी जो कि उस समय वाणिज्य मन्त्री थे, ने अपने विभाग की अनुदान माँगों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में इस माँग का अध्ययन किया है और सरकार कुछ वस्तुओं के व्यापार में राजकीय व्यापार का सहारा लेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सभी दृष्टिकोगी से राजकीय व्यापार राजकीय निगम के माध्यम से करने के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है। विभिन्न परीक्षणों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कुछ विशिष्ट वस्तुओं का कुछ विशिष्ट देशों के साथ व्यापार राजकीय सगठन के माध्यम से सम्भव है। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि ससद के कुछ सदस्यों की एक समिति इस मामले पर सुझाव देने हेतु जल्द से जल्द गठित की जाय।

समिति ने विचार किया कि कुछ निश्चित मामले मे द्विपक्षीय समझौता इस बात की पुष्टि करता है कि व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की कितनी आवश्यकता है। अप्रैल 1949 मे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के 21 वर्किंग आफ स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया, गुप्ता, के आर , एस चाँव एण्ड क प्रा लि , नई दिल्ली, पृष्ठ स0 45 समक्ष वाणिज्य मन्त्री ो सूती कपडे के पश्चिमी देशां को नियात व्यापार के अधिग्रहण हेतु एक निगम की स्थापना का प्रस्ताव विचारार्थ रखा। लेकिन यह प्रस्ताव अनुचित लाभ को समाप्त करने वाला न होकर मात्र विदेशी बाजार को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से रखा गया था, भले ही इसके क्रियान्वयन में हॉनि हो। जिसका परिणाग यह हुआ कि इस प्रकार का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

अक्टूबर 1949 में भारत सरकार ने इसका अध्ययन करने के लिये ससद सदस्य डा0 पजाब रांव शामराव देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो इस बात का पता लगायेगी कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की दिशा को देखते हुए राजकीय स्वामित्व में अथवा राजकीय प्रयोजन में किसी भी क्षेत्र के विदेशी व्यापार का सचालन करने के लिए किसी सगठन को स्थापित करना लाभप्रद होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसे सगठन की सरचना, उसका विस्तार तथा उसके कार्य का क्षेत्र क्या होना चाहिए?

समिति ने केन्द्र तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के कुछ कर्मचारी प्रतिनिधियों तथा निजी व्यापार संघों के प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण दराविषय पर जानने के लिए एक प्रश्नावली जारी की। समिति ने कांग्रेस पार्टी के कुछ ससद सदस्य सर्व श्री आर पी गोयनका, एम एल सक्सेना, वी पी झुनझूवाला, देशबन्धु गुप्ता और एम ए अय्यगर द्वारा तैयार किये गये सुझाव पत्र को भी उचित महत्व देते हुए राजकीय व्यापार मे आने वाली रामस्याओं और जोखिमों का अध्ययन किया। समिति ने गहन विचार—विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष अगस्त—1950 में प्रस्तुत की। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्य व्यापार निगम की स्थापना एक बहुत ही लाभदायक कदम होगा। उसके सुझाव इस प्रकार थे—

- सरकार को राज्य व्यापार के क्रिया कलापो, जैसे उर्वरक, खाद्यान्न, लोहा व कोयला के आयातों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए।
- पूर्वी अफ्रीका से सूती कपड़ों के आयात को बढावा देना चाहिए तथा अपने देश के
   लघु उद्योगों के उत्पादों और कटपीस सूती कपड़े के निर्यात को भी बढावा देना चाहिए।
- सरकार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निजी आयतको और निर्यातको की ओर
   से विदेशों में एकाधिकार स्थापित करने के लिए समझौतों का आयोजन करना चाहिए।

देश की आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1953 में एक तीन सदस्यीय सिमिति का गठन उक्त सुझावों पर पुनर्विचार के लिए किया गया। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिमिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि राज्य व्यापार निगम को रिपोर्ट में बतायी गयी वस्तुओं के आयात—निर्यात का सचालन का अधिकार नहीं देना चाहिए। सिमिति ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि राज्य

व्यापार निगम को अस्तित्व में लाने पर सरकार अपनी आर्थिक एवं व्यापारिक नीति के अलावा अन्य नीतियों को समाज पर धोपने के एक अस्त्र के रूप में इसका प्रयोग कर सकती है। फिर भी यदि ऐसा राज्य व्यापार निगम गठित ही करना है तो इसका कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया जाना चाहिए।

उस समय तक सरकार विदेशी व्यापार से सम्बन्धित अपनी आर्थिक नीतियों को कार्यरूप प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से आयात-निर्यात नियन्त्रण अधिनियम तथा प्रशुल्क(टैरिफ) अधिनियम पर निर्भर थी। ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि ये नियन्त्रात्मक शक्तियाँ कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का निराकरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुख्य रूप से केन्द्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने तथा उराका विस्तार करने में कठिनाई अनुभव की जा रही थी। ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के व्यापारी विदेश व्यापार के विकास में बाधक बन रहे थे क्योंकि वे एक व्यापार सगठन के अनुशरण में कार्य करते थे साथ ही उनमें स्वयं के अनुभव एव आपसी समझ का अभाव था।

इस सगस्या का निराकरण करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों में बड़े पैमाने पर व्यापार प्रतिनिधियों को व्यवस्थित किया गया। ये व्यक्ति अपने देश में आयात-निर्यात सगठन के सरक्षक के रूप में कम-अधिक एक स्थानीय अभिकर्ता की भाँति कार्य करते थे। इन्हें निजी पार्टियों के साथ अनुबन्ध करने में कठिनाई का अनुभव होता था। सरकार स्वाभाविक रूप से उचित आयात या निर्यात का अनुमोदन करने में हिचिकिचाती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार प्रतिनिधि स्वयं भारतीय व्यापारियों से अनुबन्ध करने लगे। इन परिस्थितियों में न चाहते हुए भी कुछ स्थापित फर्मों ने व्यापार के सचालन में भाग लिया। परिणामस्वरूप व्यक्तिगत व्यापारियों ने क्रय-विक्रय समझौतों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के आधार पर करना शुरू कर दिया और अनुबन्धों को एकाधिकार के आधार प्राप्त करने के लिए अलाभकारी व्यापारिक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाने लगा।

इस प्रकार एक व्यापारिक सगठन की आवश्यकता व्यापारियों के आपसी विवादों का निरीक्षण करने तथा निपटाने के लिए अनुभव की जाने लगी। साम्यवादी देशों की विदेशी व्यापार एजेन्सियों ने निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करने के लिए अपने निरीक्षक नियुक्त किये। लेकिन ये साम्यवादी देश इस प्रकार की निरीक्षण प्रक्रिया 'पूर्ति एव प्रबन्ध महानिदेशक' द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में करने में सक्षम नहीं थे। इसके अतिरिक्त निजी भारतीय पार्टियों के द्वारा किसी विशिष्ट वस्तु के आयात के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन कर निर्णय पर पहुँचना कठिन होता था क्योंकि वस्तुओं की उपयोगिता एवं प्रमाप में भिन्नता होती थी। इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं का निवारण, तथा भारतीय व्यापारियों और एकाधिकारी विदेशी व्यापार सगठनों के बीच सामञ्जस्य स्थापित करने का एक मात्र विकल्प राजकीय व्यापार अभिकरण की स्थापना था।

इसके अलाया अन्य कई कारणों ने राजकीय व्यापार के विषय में सरकार को सोचने के लिए बाध्य किया। कुछ अपरिहार्य वस्तुओं के आयात की मात्रा के निर्धारण के औजार के रूप में स्थानीय उत्पादन कम हो जाने की दशा में माँग के बढ़ने तथा माँग और पूर्ति में समानता बनाये रखकर मूल्यों को स्थिर करने के लिए राजकीय व्यापार आवश्यक हो गया। कच्चे सिल्क के आयात को इच्छित दिशा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से निजी व्यापारी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मात्रा में चीन से आयात करे तािक कच्चे सिल्क की कमी के कारण हैण्डलूम बुनकरों को अत्यधिक मूल्य का भुगतान न करना पड़े। इसी तरह की कठिनाई सोडा भस्म कािस्टिक सोडा और सोडियम बाई कार्बोनेट के मामले में भी हो रही थी।

सोड़ा भस्म के आयात के लिए मन्त्रालय द्वारा दो वितरको को नामित किया गया जो कि मन्त्रालय द्वारा चयनित सस्ते स्रोतो से परिमाण टेण्डर के आधार पर छ महीने की आवश्यकता के लिए स्वेच्छा से खरीदवारी करने को सहमत थे। सरकार द्वारा कास्टिक सोड़ा और सोडियम बाइकार्बोनेट को आयात करने का लाइसेन्स तुलनात्मक कोटेशन मूल्य के आधार पर उन आयातको को दिया गया जो कि विशिष्ट प्रतिबन्धो के अधीन एक निश्चित समय के अन्दर एक निश्चित न्यूनतम लाभ मात्रा पर आयात हेतु सहमत थे। सोड़ा भस्म के आयात व्यवस्था की इस आधार पर आलोचना की गयी कि छोटे आयातको की उपेक्षा करते हुए केवल दो फर्मों को इसकी अनुमति देना अनुचित है। इस बात का अनुभव किया गया कि सोड़ा भस्म जैसी वस्तुओं को आयात करने के सम्बन्ध मे राजकीय नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सगठनों को एकाधिकार या अर्द्धएकाधिकार दिया जाना चाहिए।

आयात के लिए राजकीय एजेन्सी की स्थापना से सरकार कीमत को नियन्त्रित करके, उसमें स्थिरता लाकर, बाजार में वस्तु की पूर्ति को नियन्त्रित करके, उत्पादक एवं उपभोक्ता के हितों को पूरा कर सकती है। ऐसा भी आरोप लगा कि केन्द्रीय नियोजित देशों में कुछ व्यक्तियों को विदेशी व्यापार व्यवहार में भाग लेने की अनुमति उनकी व्यापारिक क्रियाओं के आधार पर न देकर उनकी राजनैतिक सहानुभूति के आधार पर वी जाती है। साम्यादी देशों को यह भी भय था कि व्यापार का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह यह देश के वृहत् हित में था कि ऐसे व्यापार व्यवहार केवल राजकीय स्तर पर किये जाँय।

आयात की जारी रखने के लिए बडी मात्रा में धन एवं निर्मात के विस्तार एवं गतिशीलता की आवश्यकता थी। निर्मात में वृद्धि के लिए बड़ा बाजार अपरम्परागत वस्तुओं जैसे—हस्तिशिल्प, चप्पल तथा लघु उद्योग के अन्य उत्पादों के लिए उपलब्ध था। लघु उद्योग का उत्पादन बहुत अधिक इकाइयों के द्वारा किया जाता था लेकिन वे इकाइयाँ बहुत विस्तृत क्षेत्र में बिखरी हुई थी जिनमें न केवल वित्त की कमी थी बल्कि

इकाइयों को उनके विस्तृत बाजार का भी ज्ञान नहीं था। स्थापित निर्यातकों ने भी ऐसी वस्तुओं के नियोत में वृद्धि के रिए कोई रुचि नहीं ली। इसलिए इस क्षेत्र में भी राजकीय व्यापार की आवश्यकता महसूस की गयी।

लौह खनिज तथा मैग्नीज के निर्यात में भी कठिनाई अनुभव की गयी। निजी जहाजरानी में लंगे भारतीय, एकाधिकार प्राप्त करने के लिए विदेशी खरीददारों से अनुबन्ध करने में आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहें थे जिसके परिणागरवरूप उन्हें कम मूल्य पर सेवाए देकर विदेशी विनिमय की हानि उठानी पड रही थी। निजी निर्यातकों को असफलता से प्रतिष्ठित अनुबन्ध एवं देश की विदेशी छिंब खराब हो रही थी। खनिज उद्योग में दीर्घकाल में अच्छी शर्तों पर व्यापारिक अनुबन्ध प्राप्त करने, उत्पादन तथा रोजगार बढने की पूरी सम्भावना थी। आयातित सीमेन्ट की कीमत देश में उत्पादित सीमेन्ट से बहुत अधिक थी। यही स्थित इस्पात की भी थी। इस प्रकार देश में उत्पादित वस्तु की कीमत और आयातित कीमत के अन्तर को समाप्त करने के लिए, आयात व्यापार पर निगरानी करने एवं आयातित वस्तु का आन्तरिक वितरण करने के लिए राजकीय व्यापार अपरिहार्य हो गया।

यद्यपि राजकीय व्यापार को कार्यरूप प्रवान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था फिर भी प्रथम लोक सभा मे 26 अगस्त तथा 9 सितम्बर-1955 को एक सदस्य ने कुछ प्रमुख वस्तुओं के निर्यात को सरकार के अधीन करने का प्रस्ताव बहस के लिए प्रस्तुत किया। बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने राजकीय व्यापार के पक्ष में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वहस के सम्बन्ध में तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री ने 9 सितम्बर- 1955 को कहा कि 'हम लगातार इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और अगर यह प्रतीत होता है कि हमारी नियामक शक्तियाँ और वित्तीय उपाय किसी भी मामले में अपर्याप्त है, या व्यापार की प्रक्रिया में परिवर्तन सरकार एव जनता के हित में है, तो ऐसी सकारात्मक कार्यवाही करने में हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि राजकीय व्यापार सगठन स्थापित करना आवश्यक ही है तो इससे पहले दो बातों की जाँच जरूरी है, प्रथम- क्या हम वह सुविधा राजकीय व्यापार को दे सकेंगे जो कि व्यापार में भाग लेने वाले अन्य देशों की सरकारे उन्हें देती है? द्वितीय-क्या स्थापित राजकीय व्यापार सगठन निजी व्यापारिक सगठन द्वारा उत्पन्न समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करेगा?

उपर्युक्त सभी वाद-विवाद के बाद राज्य व्यापार निगम की स्थापना का प्रश्न मन्त्रिमण्डल ने नवम्बर-1955 में स्वीकार कर लिया। भारतीय राज्य व्यापार निगम(प्राइवेट)लिमिटेड, 18 मई, 1956को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक संयुक्त पूँजी कम्पनी के रूप में पजीकृत हुआ। अप्रैल-1959 से 'प्राइवेट' शब्द निगम के नाम से हटा दिया गया।

<sup>22</sup> इस्टीमेंट कमेटी,रिपोर्ट आन दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया,निव डेलही~1960,पृष्ठ स0 1-2

जून- 1962 में दूसरा राजकीय सगठन-भारतीय हस्तिशिल्प निगम लिमिटेड स्थापित किया गया जिसके सम्पूर्ण 12 लाख रुपये के अशो को राज्य व्यापार निगम ने खरीदा। यह राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्था के रूप में था जिराके सचालक मण्डल के गठन का अधिकार राज्य व्यापार निगम को था। अक्टूबर, 1962 में राज्य व्यापार निगम के एक भाग- हैण्डलूम निर्यात सगठन को एक सहायक निगम के रूप में हस्तान्तिरत कर नया नामकरण- भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड किया गया। यह कार्यवाही हस्तिशिल्प एव हथकरघा उत्पाद के निर्यात सम्बर्धन एव दोनों में बेहतर सहयोग को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से की गई।

व्यापार में हो रही तीव्र वृद्धि, राज्य व्यापार निगम की अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका, वीर्घकालीन योजना के क्रियान्वयन में अव्यवस्था होने की सम्भावना तथा आयात - निर्यात सम्वर्द्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राज्य व्यापार निगम को दो पृथक निगम भारतीय खिनज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के रूप में विभाजित कर दिया। नया निगम 1 अक्टूबर – 1963 को अस्तित्व में आया। इस गिगम ने खिनज एवं धातु व्यापार से सम्बन्धित सभी सम्पत्ति एवं दायित्व भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से 1 अक्टूबर – 1963 को ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायता के लिए 1970 में भारतीय चाय व्यापार निगम तथा काजू निगम की स्थापना अलग से की गयी। इसकी सहायक कम्पनी के ही रूप में अप्रैल 1971 में भारतीय परियोजना उपकरण निगम, जनवरी – 1976 में भारतीय राज्य रसायन एवं भैषज निगम तथा फरवरी – 1976 में केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम अस्तित्व में आये।

भारत सरकार ने खाद्यान्नों के बढते मूल्य की समस्या का समाधान करने के लिए यद्यपि 1943 में ही प्रथम खाद्य मीति तैयार की एव प्रथम मूल्य नियन्त्रण सम्मेलन आयोजित किया तथा सर्व प्रथम 1944 में केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों द्वारा केवल गेहूँ एव चावल के लिए राशनिग व्यवस्था आरम्भ की। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद खाद्य सामग्री खरीद समिति–1950 के अधीन उस खाद्य नीति को अपनाया जा सके जिसमें खाद्यान्नों के एकाधिकारी खरीद एव राशनिग व्यवस्था पर बल दिया गया। वर्ष 1957–58 में अमेरिका से पी एल 480 के अन्तर्गत आयातिक गेहूँ और चावल का वितरण उचित मूल्य की दुकानो द्वारा किया गया परन्तु 1962 के भारत—चीन युद्ध एव 1965 के भारत—पाक युद्ध के बाद मूल्य वृद्धि एव पूर्ति के अभाव से बचने के लिए उचित मूल्य के दुकाने तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डार, केन्द्र— प्रायोजित योजनान्तर्गत बडी तेजी से खोले गये। इसी बीच खाद्यान्नों की माँग, पूर्ति एव मूल्य को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए खाद्य निगम अधिनियम—1964 के अधीन भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गयी जिसने अपना कार्य जनवरी 1965 से प्रारम्भ किया। 23 वर्ष 1967—68 में खाद्यान्नों के वितरण हेतु स्थापित 'उचित मूल्य की दुकान

विपणन, विक्रय-कला एव विज्ञापन-जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-157

योजना' का नाम बदल कर 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया।

वर्ष 1970 में गामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निगम ने ग्रामीण उपभोक्ता योजना आरम्भ की। इसके अतिरिक्त सार्वर्जाक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 1978 के राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रस्ताव तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नागरिक एवं आपूर्ति मिन्त्रयों के विचार-विमर्श के बाद 1 जुलाई-1979 से 'सार्वजिनक उत्पादन एवं वितरण योजना' लागू की गयी जिसमें वितरण के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वसूली, भण्डारण परिवहन एवं वितरण की प्रक्रिया को शामिल किया गया। अगस्त 1986 में पूर्व प्रधानमन्त्री स्व श्री राजीव गांधी द्वारा पुनर्सशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत् वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ, कारगर एवं प्रभावी बनाने का सकल्प लिया गया। हमारे वर्तमान प्रधानमन्त्री ने 1 जनवरी, 1992 से ग्रामीण, दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को और अधिक सिक्रय एवं रचनात्मक बनाने की दृष्टि से नवीनीकृत सार्वजिनक वितरण प्रणाली की घोषणा की है, जिसका निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। 24

दूसरी और राजकीय व्यापार के विभिन्न अभिकरणों की पारस्परिक सरचना में भी हाल के वर्षों में कई विकासात्मक परिवर्तन किये गये। भारतीय राज्य व्यापार निगम 17 मई, 1990 को 'भारतीय व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड'(बी बी आई एल ) का अनुषगी बना दिया गया। यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक सूत्रधारी कम्पनी थी जिसमे चार सहायक कम्पनियो— भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज एव धातु व्यापार निगम, परियोजना एव उपकरण निगम तथा मसाले व्यापार निगम को रखा गया था। परन्तु बी ब्री आई एल को समाप्त करते हुए 26 मार्च, 1991 को भारतीय राज्य व्यापार निगम के सारे अश राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दिये गये। इस प्रकार 31 मार्च, 1991 को पहले की तरह राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनियों में भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय काजू निगम, भारतीय चाय व्यापार निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम शामिल थे। इसी तिथि को भारतीय काजू निगम को भारतीय राज्य व्यापार निगम में समामेलित कर दिया गया। 13 मई 1991 को भारतीय राज्य व्यापार निगम से इसकी अनुषगी कम्पनियों — भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम और परियोजना एव उपकरण निगम को अलग कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय राज्य व्यापार निगम को कवल एक अनुषगी—भारतीय चाय व्यापार निगम है। 25

<sup>24</sup> नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली, 29 अगस्त-1994, पृष्ठ सख्या- 7

<sup>25</sup> वार्षिक प्रतिवेदन- 1990-91 तथा 91-92, दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड-नई दिल्ली

# तृतीय-सर्ग राजकीयव्यापार के आधार स्तम्भ

## तृतीय-रार्ग

### राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ

वर्तगान समय में राज्य का कार्य केवल आन्तारिक शान्ति एवं बाह्य सुरक्षा स्थापित करना ही नहीं, बल्कि उन सभी जनतान्त्रिक कार्यों को भी सम्पन्न करना है, जिनसे सम्पूर्ण समाज के कल्याण में वृद्धि होती हो। इसीलिए आधुनिक समय में राज्यों को लोक-कल्याणकारी राज्य की सज्ञा दी गई है। प्रत्येक लोक-कल्याणकारी राज्य से यह आशा की जाती है कि वह प्रमुखता से राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में सहयोग दे। राष्ट्र अपनी आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल तो बनायें ही साथ ही साथ देश की जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति भी पूर्णतया सचेष्ठ हो। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ लगभग एक तिहाई जनसख्या गरीबी रेखा थे, नीचे जीवन-यापन कर रही हो वहाँ जमाखोरी, मुनाफाखोरी, उपभोक्ता- ग्रोषण एवं दैनिक उपभोग की वस्तुओं के श्रृटिपूर्ण वितरण से उत्पन्न मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओं का होना और भी कष्टकर है। आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि सदैव जन असन्तोष का कारण बनती है और अनेक आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं को जन्म देती है। इसी परिप्रकृप में भारत में स्वतन्त्र व्यापार के साथ-साथ राजकीय व्यापार की भी अपनी सार्थकता है। यह राजकीय व्यापार विभिन्न कार्य-व्यवस्थाओं के तहत् समाज को अपनी सेवाए प्रदान कर उपभोवताओं को अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। वस्तुओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन्ही कार्य एवं व्यवस्थाओं के आधार पर राजकीय व्यापार को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—

- (1) खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार,
- (II)अन्य वस्तुओ मे राजकीय व्यापार ।

# (1) खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार

'खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार' दो शब्दों से मिलकर बना है खाद्यान्न और राजकीय व्यापार। 'खाद्यान्न' से अर्थ उस अन्न से हैं जो मानव के खाने के काम में आता है, जैसे— गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का वालें इत्यादि। 'राजकीय व्यापार' से अर्थ सरकार द्वारा व्यापारिक क्रियाए करने से है। इसमें राज्य द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना या वितरण करना या दोनों क्रियाए आती है। इस प्रकार, खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार से अर्थ राज्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन या वितरण अथवा तोनों क्रियाए करने से लगाया जाता है।

भारत में खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार की आवश्यकता द्वितीय महायुद्ध के काल में प्रतीत हुई थी, उस समय खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ रहे थे तथा खाद्यान्न का उत्पादन सीमित था। अत सरकार ने खाद्यान्न, चीनी, कपडे आदि का वितरण अपने हाथ में ले लिया जो 'राशिंग के नाम से भी जाना जाता है।
| अपनी रिपोर्ट में खाद्यान्नों के व्यापार के सरलीकरण की आवश्यकता पर
बल दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1949 में फेन्द्र सरकार ने डा पजाबराव देशमुख की अध्यक्षता में राजकीय व्यापार के औचित्य की जाँच के लिए एक समिति नियुक्ति की जिसने अपो प्रतिवेदन में राजकीय व्यापार को वालू रखने तथा उसी उददेश्य की पूर्ति हेतु राजकीय व्यापार निगम की स्थापना की सिफारिश की। बाद में 1957 में खाद्यान्न जाँच रामिति ने सरकार द्वारा खाद्यान्नों के क्रय विकय पर बल दिया। इस समिति के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता थे।

अत केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 1965 को खाद्यान्न के न्यायपूर्ण वितरण कर एव उनके मूल्यों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। 1969 में काग्रेस पार्टी ने अपने वार्षिक अधिवेशन में खाद्यान्नों के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पारित किया और अक्टूबर 1972 में इस निर्णय को फिर दोहराया गया। इसके बाद 24 फरवरी 1973 को दिल्ली में मुख्य मिन्त्रियों का एक सम्मालन आयोजित किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। वर्तमान में सरकार द्वारा खाद्यान्नों में व्यापार करने की नीति है जिसके अन्तर्गत सरकार खाद्यान्नों की सरकारी खरीद करती है तथा बाद में उस खाद्यान्न को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचती है।

खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार का उद्देश्य — खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार करने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है—

- खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार का प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य खाद्यान्नो पर प्रभावकारी सरकारी
   नियन्त्रण रखना है जिससे कि खाद्यान्नो के मूल्य मे स्थिरता बनी रहे।
- खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ताओ को विशेषत दुर्बलवर्ग के उपभोक्ताओ को इस बात का आश्वासन देना है कि खाद्यान्न उनको निश्चित मूल्य पर मिलते रहेगे।
- तीसरा उद्देश्य किसानो को उनके उत्पादन का लाभदायक मूल्य प्रदान करना है जिससे कि उन्हें उत्पादन वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके और वे अधिकाधिक उपज सरकारी एजेन्सियों को बेच सके।
- चौथा उद्देश्य अनावश्यक मध्यस्थो को समाप्त कर बिक्री की लागत को कम करना तथा खाद्यान्नों के विक्रय व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।

- ग्वाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लागा राजकीय व्यापार का अन्तिम महत्वपूर्ण उद देश्य है। <u>रागान्नों में राजकीय व्यापार के लाभ</u> — खाद्यान्नों में गजकीय व्यापार के निम्न लाभ है-
- 1 र<u>गद्यान्नों के मूल्यों पर नियन्त्रण -</u> रााद्यान्नों के मूल्यों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृश्चि हुई है जिसके परिणामस्चरूप खाद्यान्नों का मूल्य सूचकाक बढ़ गया है ऐसी रिथित में उचित है कि खाद्यान्न में राजकीय व्यापार कर मूल्यों को नियन्त्रित किया जाय।
- 2 उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्त कराना खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार इसिलए भें महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापारिक वर्ग उपभोक्ताओं का बड़ा शोषण करता है। वह वस्तुओं का सग्रह कर कृति कमी पैदा कर देता है और फिर उस स्थिति से लाभ उठाने के लिए मूल्यों में वृद्धि कर देता है। अत या उचित है कि खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार किया जाय। इससे मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी औं जनसाधारण को खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते रहेगे।
- 3 खाद्यान्त के मूल्यों का प्रभाव खाद्यान्त के मूल्यों का प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर प पड़ता है। यदि खाद्यान्तों के मूल्य बढ़ते हैं तो सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ता है। इसके विपरीत खाद्यान्त के मूल्य गिरते हैं तो सामान्य मूल्य स्तर भी गिरता है। अत यदि खाद्यान्तों के मूल्यों पर सरकारी नियन्त्रण रहता है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है।
- 4 <u>विश्वव्यापी खाद्यान्न समस्या</u> याद्य पदार्थों की कमीकेवल भारत में ही नहीं है बल्कि या तो एक विश्वव्यापी समस्या है, ऐसी दशा में खाद्यान्नों का आयात भी कम हो जाने की सम्भावना है। इसलिए खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार होना परम आवश्यक है।
- 5 कृषि विपणन के दोषों का निवारण खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार होने से कृषि विपण में जो दोष है, उनका निराकरण स्वत हो जाने की पूरी सम्भावना रहती है, क्योंकि राजकीय व्यापार होने रं कृषि पवार्थों का क्रय सरकार द्वारा किया जायेगा। सरकार उन गलत तरीकों को नहीं अपनायेगी जिसे व्यापार्र वर्ग अपनाता है। इससे कृषकों को लाभ होगा। उनको अपने उत्पादन का उचित लाभ मिल सकेगा तथ अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।
- 6 किरान एव उपभोक्ता दोनों के लिए लाभकारी खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार किसा-एव उपभोक्ता दोनों के लिए लाभकारी है। इससे किसान को अपनी उत्पत्ति का उचित मूल्य मिल जात है तथा उपभोक्ता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते है। अत दोनों अपने रहन—सहन का स्थायी स्त-बंनाये रख सकतें है।

खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की हानियाँ —खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार से निम्न हानियाँ है— 1 बेरोजगारी की समस्या को बढाने मे सहायक — देश मे लगभग 7 हजार मण्डियाँ है जह कृषि पदार्थी का क्रय-विकय होता है। जिनमें 3 ! लाख थोक दुकाने हैं। इन दुकानों में 11 6 लाख व्यक्ति साझेदार है, 7 7 लाख व्यक्ति मुनीम है, 10 3 लाख व्यक्ति गजदूर या पल्लेदार है व 2 लाख व्यक्ति दलाल है। यदि खाद्यान्नों का पूर्ण राजकीय व्यापार होने लगता है तो ये सभी व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगे जिससे देश की वर्तमान बेरोजगारी की समस्या और अधिक विषम बन जायेगी।

- 2 <u>प्रशासिनक अकुशलता में वृद्धि</u> कुछ लोगों को मानना है कि खाद्यान्नों के व्यापार को सरकारी हाथ में तोना समस्या का सही निराकरण नहीं है। सरकारी विभागों में पहले से ही प्रशासिनक अकुशलता है। भ्रष्टाचार व बेईमानी चरमसीमा पर है, इससे तो चोर बाजारी एव मुनाफाखोरी और बढ जायेगी जो कर्मचारियों की छत्रछाया में पनपेगी।
- 3 राजकीय व्यापार की ऊँची लागत यदि सरकार खाद्यान्नो में व्यापार करती है तो इससे लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि मितव्ययिता न बरते जाने के कारण सरकारी क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्रों की तुलना में अधिक लागत आती है। इसके अतिरिक्त सरकार को अरबो रुपयं की व्यवस्था भी करनी होती है जिसके लिए हीनार्थ—प्रबन्धन की विधि को अपनाया जाता है। इसमें देश में मृल्य वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है जा देश के हित में नहीं है।
- 4 व्यापारिक फसलो की वृद्धि अधिकाश भारतीय कृषक अशिक्षित है। अत वे सरकारी झंझट से दूर रहना चाहते हैं। यदि खाद्यान्तों में पूर्ण राजकीय व्यापार आरम्भ किया जाता है, तो हो सकता है कि वे खाद्यान्तों के उत्पादन को छोड़ कर गैर—खाद्यान्त फसलों के उत्पादन में लग जाये। इससे खाद्यान्त का उत्पादन गिर सकता है और एक गम्भीर सगस्या उत्पन्त हो राकती है।
- 5 मूल्य वृद्धि एव पूर्ति में व्यवधान का उत्तरदायी केवल व्यापारी ही नही कुछ समस्याए ऐसी है जिसे राजकीय व्यापार भी सगाप्त नहीं कर पायेगा। इसिलए खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार के विपक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि मूल्य वृद्धि एव पूर्ति के तिए अकेला व्यापारी ही उत्तरदायी नहीं है बल्कि अन्य कारण भी उत्तरदायी है जैसे— प्राकृतिक प्रकोप(बाढ आना, सूखा पडना और अत्यधिक वर्षा होना इत्यादि) सरकारी नीति ,कृषक द्वारा उत्पत्ति को रोक कर रख लेना, आदि। ये घटक खाद्यान्नों का व्यापार सरकार के द्वारा किये जाने पर भी समाप्त नहीं होंगे।
- 6 खाद्यान्नों के उत्पादन में एकाधिकारी प्रवृत्ति का न होना खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ भी नहीं है। इसका उत्पादन तो पूरे देश में फैले हुए किसानों द्वारा किया जाता है। अत इसका समाजवादी समाज की स्थापना से कोर्न सम्बन्ध नहीं है तथा न ही एकाधिकार से लडने का ही प्रधन है।

<sup>1.</sup> भारत की आर्थिक रामस्याए-मामोरिया एव जैन, साहित्य भवन आगरा-1994, पूष्ट सख्या 245

- 7 रामाज को परेशानी खाधान हो गं गज कीय त्यापार होने से समाज को परेशा है तोती है स्पोकि कालाबाजारी बढ़ती है। उपभोक्ताओं को सरकारी दुकानों से खाद्यान्नों के क्रय करने में घण्टों लगते हैं और जैसी वस्तु होती है, वैसी ही लेगी पड़ती है चाह उसकी गुणवत्ता अच्छी हो या बुरी।
- 8 <u>अन्य</u> खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार कुछ अन्य दोषो के कारण भी अनावश्यक पतीत होता है, जैसे— राजकीय व्यापार मे यह भी राम्भावना हो सकती है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल ईमानदारी से कार्य न करे और वे खाद्यान्नो के मूल्य निर्धारण वितरण व सरकारी खरीक में स्वार्थ को ध्यान भे रखकर ही निर्णय ले।

खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में जो दोष ऊपर नताये गये है उनमें से अधिकाण अस्तित्व विहीन है जिन्हे राजकीय व्यापार में दक्षता कुशलता और कर्तव्यनिष्ठा के विकास द्वारा काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। इसके दोष, लाभों की तुलना में गण्य है अत खाद्यान्तों में राजकीय व्यापार जन-कल्याण के एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है।

सरकार खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार के लिए सर्व प्रथम खाद्यान्नों का क्रय करती है और आवश्यकता पड़ने पर आयात भी करती है। क्रय करने की पद्धित को सरकारी खरीद कहते हैं। रारकार देश के कृषकों से ,उन्हें उचित मूल्य की अदायगी करके बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का क्रय करती है तथा उसका स्टाक रखती है, अपने स्टाक को बनाये रखने के लिए यदि आवश्यकता हुई तो सरकार खाद्यान्नों का आयात भी करती है जिससे कि देश के प्रत्येक उपभोक्ता को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुए सही समय एव उचित मूल्य पर प्राप्त हो जायै। सरकार खाद्यान्नों का वितरण कुछ निर्धारित दुकानों पर निर्धारित मूल्यों में करती है तो इसी को राशांनग कहते हैं।<sup>2</sup>

सरकार का यह परम व पुनीत कर्तव्य है कि वह देश के विभिन्न भागों में वहाँ की उत्पादन क्षमता के आधार पर खाद्यान्नों के सन्दर्भ में मूल्य नीति घोषित करे। वह प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों की उत्पादकता एवं उपभोग की पद्धित या माँग और पूर्ति के आधार पर खाद्यान्नों के मूल्य नीति की घोषणा करती है। रारकार का यह कर्तव्य है कि वह खाद्यान्नों की पर्याप्त व्यवस्था एवं भण्डारण करें इसके लिए सरकार पूर्व निर्धारित मूल्यों पर कृषकों से खाद्यान्नों का नकद क्रय करती है। इस प्रकार भारत के किसानों से अनाज की उपज क्रय करके बफर स्टाक बनाने से एक तरफ किसानों को बिचौलियों की लूट से बचाया जा सकता है, दूसरी ओर किसानों के हाथ में कुछ क्रयशक्ति आ जाती है जिससे अपनी जीविका ठीक दृग से चलाने के अलावा वे अपनी खेती के लिए आवश्यक सामग्री खरीद सकते हैं और साहूकारों से अपनी

युरक्षा कर सकते है। खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार को अग्राकित शीर्षको के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है-

<sup>2</sup> विपणन, विक्रय-कला एव विज्ञापन-जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या 157

- (क) राशनिग व्यवस्था,
- (ख) रत्ररीद-कार्य,
- (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
- (घ) भारतीय खाद्य निगम ओर
- (इ) केन्द्रीय भण्डारण निगम ।
- (क) राशनिग व्यवस्था -

राशिनग व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार द्वारा खाद्यान्नों का वितरण कुछ निर्धारित वुकानों में निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है। हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए कृत सकला है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार उचित मृल्य पर अच्छी वस्तुए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।ऐसा राशिनग व्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता है। जब सरकार प्रत्येक वस्तु का वितरण अपनी एजेन्सी के माध्यम से कराती है तो जनता को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए पाप्त होती है तथा समाज के कमजोर व दुर्बल व्यक्तियों का शोषण पूंजीपति व व्यवसायी नहीं कर पाते। राशिनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुए समान या असमान किस्म रूप रंग, आकार और उपयोगिता की हो सकती है। प्राय दैनिक उपभोग की वस्तुओं के वितरण हेतु राशिनंग व्यवस्था को अपनाया जाता है। कुछ वस्तुए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक होती है तो कुछ केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी वस्तुओं के लिए एक ही राशिनंग व्यवस्था अपनाकर कोई भी सरकार अपने उद्देशयों को नहीं प्राप्त नहीं कर पायेगी।

(अ) <u>राशनिग व्यवस्था की प्रक्रिया</u> - राशनिग व्यवस्था लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है-

1 राशनिंग व्यवस्था का चयन —राशनिंग दो प्रकार से हो सकती है— विशेष राशनिंग एवं वर्ग राशनिंग। एक वस्तु की राशनिंग के लिए दोनों में से किसी एक राशनिंग व्यवस्था का चयन करना होता है। विशेष राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होता है। ऐसी राशनिंग व्यवस्था उसी वस्तु के सम्बन्ध में सफल हो सकती है जिस वस्तु विशेष के रूप, रंग, आकार एवं किस्म में समानता हो। जबिंक वर्ग राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं के चयन करने का समान अवसर प्राप्त होता है। जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता होती है यदि वह वस्तु अनुपलब्ध है तो उसकी प्रतिस्थापित या स्थानापन्न वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। इस राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओं के चयन में पर्याप्त लोच रहती है तथा दो या दो से अधिक वस्तुए एक साथ राशनिंग व्यवस्था में चलती रहती हैं। रागन की पूरी मात्रा निश्चित कर दी जाती है, परन्तु उपभोक्ता को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता रहती है कि भे इन वस्तुओं को जिस प्रकार से चाहे, क्रय कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों

- (क) राशनिग व्यवस्था
- (ख) रारीद-कार्य
- (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाती,
- (घ) भारतीय खाद्य निगम ओर
- (३) केन्द्रीय भण्डारण निगम ।
- (क) राशनिग व्यवस्था -

राशिष व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार द्वारा खाद्यान्नो का वितरण कुछ निर्धारित दुकानों में निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है। हगारी सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए कृत संकल्प है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।ऐसा राशिनग व्यवस्था के गाध्यम से ही किया जा सकता है। जब सरकार प्रत्येक वस्तु का वितरण अपनी एजेन्सी के माध्यम से कराती है तो जनता को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुए प्राप्त होती है तथा समाज के कमजोर व दुबेल व्यक्तियों का शोषण पूँजीपित व व्यवसायी नहीं कर पाते। राशिनिग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुए समान या असमान किस्म, रूप रगं, आकार और उपयोगिता की हो सकती है। प्राय दैनिक उपभोग की वम्तुओं के वितरण हेतु राशिनग व्यवस्था को अपनाया जाता है। कुछ वस्तुए समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक होती है, तो कुछ केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी वस्तुओं के लिए एक ही राशिनिग व्यवस्था अपनाकर कोई भी सरकार अपने उद्देशयों को नहीं प्राप्त नहीं कर पायेगी।

- (अ) <u>राशनिग व्यवस्था की प्रक्रिया</u> राशनिग व्यवस्था लागू करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है-
- 1 राशनिंग व्यवस्था का चयन —राशनिंग दो प्रकार से हो सकती है— विशेष राशनिंग एवं वर्ग राशनिंग। एक वस्तु की राशनिंग के लिए दोनों में से किसी एक राशनिंग व्यवस्था का चयन करना होता है। विशेष राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति उस वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होता है। एसी राशनिंग व्यवस्था उसी वस्तु के सम्बन्ध में सफल हो सकती है जिस वस्तु विशेष के रूप, रंग, आकार एवं किस्म में रामानता हो। जबिक वर्ग राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोनताओं को अपनी वस्तुओं के चयन करने का समान अवसर प्राप्त होता है। जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता होती है यदि वह वस्तु अनुपलब्ध है तो उसकी प्रतिस्थापित या स्थानापन्न वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। इस राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओं के चयन में पर्याप्त लोच रहती है तथा दो या दो से अधिक वस्तुए एक साथ राशनिंग व्यवस्था में चलती रहती है। राशन की पूरी मात्रा निश्चित कर दी जाती है, परन्तु उपभोक्ता को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता रहती है कि वे इन वस्तुओं को जिस प्रकार से चाहे, क्रय कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों

को छोड़ कर कोई भी उपभोवता एक अधिकतम गात्रा से अधिक राशन क्रिया निश्चित कर सकता। इसमें एक खाद्य सामग्री का दूसरी खाद्य सामग्री से आसानी से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इस व्यवस्था में एक बिन्दु व्यवस्था के अत्तर्गत विभिन्न वस्तुओं की गात्रा एक व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में निश्चित कर दी जाती है। यह प्रणाली उसी नस्तु के सम्बन्ध में उपयुक्त होती है कहाँ कि विभिन्न प्रकार के गणों में भी विभिन्न की मात्रा एक ही वर्ग के अत्तर्गत रहती है, इसिलाए उपभोवता को वस्तुओं के चुनाव में स्वतन्त्रता रहती है जैसे-कपड़ा, इसमें एक तस्तु के टोते हुए भी विभिन्न प्रकार की मात्रा ए। गुण होते दैं, जैसे-तौिराया लुगी पैट शर्ट इत्यादि और इसके विभिन्न स्वरूप भी होते हैं। इसके अन्तर्गत जिस वस्तु की पूर्ति की स्थिति अच्छी होती है, उस वस्तु की कीमत कम होती है, यदि कोई वस्तु दुलर्भ है या जिसकी पूर्ति अभावग्रस्त है तो उसके पूल्य निश्चित रूप से अधिक होगे।

यदि कोई वस्तु किसी विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक है तो वह प्राथमिकता के आधार पर उन्हें उपलब्ध करायी जाती है। जैसे-मिट्टी के तेल के सन्दर्भ में युद्ध के समय मिट्टी का तेल उन गृह स्वामियों को नहीं दिया जायेगा जिनके पास बिजली है क्योंकि इस समय मिट्टी के तेल का अभाव हो जाता है। अन विलासिता की आवश्यकता में इसका उपभोग देश के साथ विश्वामघात के सगान है, क्योंकि मिट्टी का तेल उस घर के लिए नितान्त आवश्यक है जहाँ पर बिजली नहीं है। समाज के कमजोर व निर्धन वर्ग द्वारा इसका उपयोग करना ठीक है तथा उत्पादन की कुछ ऐसी इकाईयाँ भी होती है जहाँ पर इसका उपयोग उत्पादन के लिए भी होता है।

- 2 प्रशासिनक केन्द्रीयकरण राशनिग व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है कि राशिनग व्यवस्था से सम्बन्धित जितने भी अधिकारी है, उन सबका केन्द्रीयकरण हो। प्रत्येक राशन का विभाजन कर दिया जाता है। विभिन्न राशनों की मात्रा के अनुसार पूरे शहर या क्षेत्र में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। रेलवे विभाग अपने कर्मचारियों को राशिनग के अन्तर्गत वस्तुए उचित मूल्य पर प्रदान कराता है। इस सम्बन्ध में सभी दुकानों के दुकानदारों को पूर्व निश्चित मात्रा बतायी जाती है कि इतनी मात्रा निर्गमित की जानी है।
- 3 <u>क्षेत्रीय राशनिग कार्यालयों की स्थापना</u> खाद्य पदार्थों की आवश्यकता एक आवश्यक आवश्यक वांच्य पदार्थों के और कोई भी व्यक्ति खाद्यान्नों के बिना जीयित नहीं रह सकता। इन परिस्थितियों में जब खाद्य पदार्थों के नियन्त्रण या राशनिंग की व्यवस्था की जाती है तो उपभोक्ता को राशनिग अधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क करना पड़ता है। जब व्यक्ति को आवश्यकता का अनुमान होता है तो वह उस वस्तु को पाने का प्रयास करता है और इसके लिए उसे अधिकारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क करना पड़ता है। साथ ही राशन कार्ड बनवाने या परिवार में नये सदस्य के आगमन पर युनिट में वृद्धि करवाने, निवास स्थान में परिवर्तन हो जाने

पर उरामे सशोधन करवाने राशन कार्ड राो जाने पर तथा गणन कार्ड बनवाने के लिए या गशनिण के सम्बन्ध में कोई णिकायत करने के सम्बन्ध में उसे राणिनग अधिकारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क करना पड़ना है। इसलिए इन क्षेत्रीय कार्या के लिए क्षेत्रीय राशिंग कार्यालय विभिन्न क्षेत्रों में होना नितान्त आवश्यक होता है। यदि क्षेत्रीय कार्यालय वार्य-धारक की पहुँच के बात्र रियत दें तो उसको अपनी समस्याओं के समाधान रेतु काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।

यह लोक हित एव प्रशासन दोनों की दृष्टि से उपयोगी होगा कि शहर को पाँच या छ भागों में बाँट विया जाय और प्रत्येक क्षेत्र में एक कार्यालय खोटा दिया जाय, गहाँ एक अधिकारी नियुक्त हो। इस्र कार्यालय का उदयेश्य उस क्षेत्र के निवासियों व व्यक्तियों की समस्याओं को देखना तथा उसको यथासम्भव हर्ग करने का प्रयास करना है। इसलिए राशनिंग अधिकारी का केन्द्रीयकरण व प्रशासनिक अधिकारी का विकन्दीयकरण उपशोक्ता व लोकहित दोनों दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

4 राशिनग व्यवस्था का पचार एव प्रसार — गशिनग व्यवस्था के सफल सचालन के तिए आवश्यक है कि इराका प्रचार व प्रसार सरकार बहुत ही विवेक न बृद्धिमानी से करे। इस तथ्य में इन्कार नहीं किया जा सकता कि बिना प्रचार व प्रसार के राशिनग व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। खाद्यान्तों के सम्बन्ध में यह जानना अत्यन्त आवश्यक होता है कि इसके विषय में सरकार की ग्या राय है? उसकी नीतियाँ क्या है? तथा उसकी कार्य—प्रगित कितनी है? प्रत्येक भारतीय अफवाहों में अधिक विश्वास रखते है और उसे प्रशारान के परिज्ञान में लाना भी नहीं चाहते। इसलिए सापेक्षिक रूप में यह अधिक आवश्यक हो जाता है कि सरकार विवेकपूर्ण प्रचार करके उपभोक्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे क्योंकि बिना उपभोक्ता की सहायता प्राप्त किये, सरकार राशिनग व्यवस्था को सफल नहीं बना सकती। राशिनग तकनीक एव इससे सम्बन्धित अध्यादेशों को लागू करने से पहले इसका प्रचार—प्रसार आवश्यक होता है। इस प्रकार का अनुभव सरकार ने बम्बई में ऐसा प्रचार करके किया था कि गलत राशन कार्ड का होना एक अपराध है। जो लोग बम्बई छोडकर चले गये हैं, वे अपने राशन कार्ड का निरस्तीकरण करा ले, अन्यथा उन्हे दण्ड दिया जायेगा। इस प्रकार का प्रचार करने पर प्रतिदिन औमत रूप से साठ हजार राशन यूनिट निरस्तीकरण के लिए आवेदित की गयी।

भारत में अज्ञान और अशिक्षा के कारण सरकारी गजट में जो सूचनाए प्रकाशित की जाती है, उसके द्वारा हुआ प्रचार कार्य छोटे स्तर पर होता है क्योंकि गजट अधिकाश व्यक्तियों की पहुँच से बाहर होता है। बहुत से शहरों या स्थानों पर सरकार अपने आदेश नगाडों या ड्रम पिटवाकर बताती है। जनता को यह सुनाया जाता है कि रारकार का आदेश अमुक है और इसे सभी व्यक्तियों को मानना है। अवहेलना की

<sup>3</sup> प्राइस कंद्रोल एण्ड राशनिग-भागर्व, आर एन , किताबिस्तान, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या - 60

दशा में अगुक दण्ड वं। व्यवस्था है।सामान्तया कोई भी व्यक्ति कानून व नियम का उल्लंघन करना उचित नहीं समझेगा। यद्यपि इस सन्दर्भ में यह भी प्रचलित है कि 'कानून की अज्ञानता निर्वेषिता को सिद्ध करने का पर्याप्त आधार नहीं है।' अर्थात् कानून के न जानने पर उससे बचा नहीं जा सकता।

सरकार को गशनिंग व्यवस्था का पत्तार एवं प्रगार एक योजनाब है तरीके से करना होगा ताकि जनता खाद्यान्नों की महत्ता और उससे समबिधत गमग्या को भलीभोंति सगदा सके। इस विषय में जानकारी देने के लिए इस जन गग्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस पकार के अधिकारी का कर्तव्य यह होगा कि वह प्रेम एवं जनता की सहानुभूति प्राप्त करें और इंगके गाध्याग थे। सरकार की नीतियों को सामान्य जनता तंक पहुँचाये। यह विधि वहाँ अधिक उपयोगी होगी जहाँ साक्षरता की दर ऊँची है। प्रचार व पसार के लिए लाउडरपीकर लगी गाडियों को विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में भेजा जाता है जहाँ पर कम शिक्षित व्यक्ति होते हैं। वे इस विषय पर अपने आख्यानो एवं व्याख्यानों को प्रसारित कर जनता को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों। एवं कार्यकमों को सिनेमा तथा पत्र-पत्रिकाओं में भी विज्ञापित किया जाता है। जहाँ जिस प्रकार से सम्भव होता है वहाँ उसी प्रकार में लोगों में राशनिंग के प्रति उत्साह पैदा किया जाता है। बम्बई में सरकार ने खाद्य नियन्त्रण व गशनिंग पर 20 मिनट की एक फिल्म बनायी थी जिसे वहाँ के स्थानीय सिनेमाघरों में दिखाया जाता था। परिस्टरों, चित्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से भी राशनिंग व्यवस्था का प्रचार एवं प्रसार किया जाता था। परिस्टरों, चित्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से भी राशनिंग व्यवस्था का प्रचार एवं प्रसार किया जाता था।

5 <u>गणनाकार्य एव सूचनाओं का एकत्रीकरण</u> राशिनग व्यवस्था लागू करने से पहले इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि कितने व्यक्ति राशिनग व्यवस्था के अन्तर्गत आयेगे। इसके लिए गणन-क्रिया आवश्यक है। राशिनग अधिकारी को गणना अधिकारी नियुक्त करने तथा उन्हें विभिन्न सूचनाए एकत्रित करने का आदेश देने सम्बन्धी अधिकार होना चाहिए। उच्चाधिकारियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे जहाँ चाहें, जिस धर में चाहें, प्रवेश कर सकते हैं तथा झूठी सूचना बताने वाले गणक को पदच्युत कर सकते हैं। सभी घरों की सख्या अिकत होनी चाहिए जिससे गलत या झूठी सख्या देने वाले घरों की पहचान की जा सके। पहले की जनगणनाओं में इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी है। जनगणना करते समय इस प्रकार की सूचनाओं के एकत्रीकरण का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। पूर्व की जनगणनाओं में गणक किसी न किसी व्यवसाय में लगे थे, इस कारण उनका व्यक्तिगत हित इरा कार्य में नहीं था, वे अपने इच्छानुसार ही कार्य करते थे। परन्तु वर्तमान समय में कुछ अवधि के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा इस कार्य का सम्पादन कराया जाता है।

<sup>4</sup> प्राइस कट्रोल एण्ड राशनिग-भार्गव, आर एन , किताबिस्तान इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या 69

गणकों के कार्य की निगरानी हेतु पर्यवन के एवं राज्या के पर्य वेशकों की निगुक्त भी को जाति चाहिए। यदि कुछ व्यक्ति निरक्षर है तो रार्शानग अधिकारी दारा गाँगी गगी नाहित सूचना की प्रविष्टि का कार्य गणक स्वय करेगे। गणन—कार्य को सरल बनाने के लिए यदि पत्येक मुहल्ले में मुहल्ला समिति का गठन करके उसके प्रधान को यह कार्य सौपा जाय तो गणन कार्य में होने वाली धोखा-धडी तथा असामयिक या झुठे गणन कार्य से छुटकारा मिल सकता है।

यदि किसी ऐसे वस्तु या वस्तुओं के राम्बन्ध में राशनिंग व्यवस्था लागू की जाती है जो कि जानवरों के खाने के काम में आ सकती है तो इसके लिए कितने और किस पकार क जानवर है, उनकी भी गणना करनी होगी। इन सब जानवरों के लिए अलग से राशन काई निर्मित करने चाहिए तथा साथ ही साथ उसकी गात्रा भी निश्चित कर देनी चाहिए। यह गणना कार्य एक निश्चित समय में सभी वर्षों को लेते हुए किया जाना चाहिए जिससे कि वास्तविक सख्या का पता लगाया जा सके। इसलिए राशनिंग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि गणना कार्य में एकत्र की गई सूचनाए वृहत् पैमाने पर एकत्र की जाये। जिससे भविष्य में होने वाली रामस्त आकस्मिकताओं की पूर्ति की जा सके। गणनाकार्य में उचित शुद्धता रहे इसलिए पहले से ही शुद्धता स्तर के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिये जाने चाहिए। पूर्ण गणना कार्य कराये बिना राशनिंग व्यवस्था लागू करना बहुत बड़ी भूल होगी।

6 राशनकार्ड या कूपन का चयन — राशनिग वस्तुओं को क्रय करने के लिए राशन कार्ड या कूपना, राशनिग अधिकारी जो उचित समझे एक अहस्तन्तरणीय पत्र के रूप में जारी कर सकते हैं। कूपन के निर्गमन की दगा में कूपन वस्तु प्राप्त करते समय देना होगा। राशनकार्ड वस्तु प्राप्त करते समय आवश्यक प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत करना होगा। कूपन प्रति सप्ताह या प्रतिमाह वस्तु प्राप्तकर्ता को बनवाना पडेगा जिसके लिए आपूर्ति कार्यालय में समय का अपव्यय होगा। कूपन जारी किया जाय अथवा राशन कार्ड यह खाद्यान्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा। खाद्यान्न के सम्बन्ध में कूपन व्यवस्था से प्रशासनिक व्यय में वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी असुविधा होगी। प्रत्येक खाद्यान्न के लिए अलग—अलग कूपन का निर्गमन करना, कूपन प्रणाली को और भी अनुपयोगी बना देगा। मिट्टी का तेल खाद्यान्न ईधन, चीनी आदि वस्तुए जिनकी पूर्ति नियमित रूप से वितरण के लिए होती है के लिए कूपन की अपेक्षा राशन कार्ड जारी करने से समय व धन दोनों की बचत होगी। यदि वस्तु की प्रकृति ऐसी है जिसकी पूर्ति अनिश्चित रहती है तथा जिसके वितरण की स्थिति असामयिक होती है उसके सम्बन्ध में कूपन का निर्गमन कर पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा के अनुसार कूपन का निर्गमन स्वेच्छा से या प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जायेगा। कूपन निर्गमन की प्राथमिकता मुहल्ला या क्षेत्रवार निर्धारित कि जा सकती है।

7 <u>पशनकार्ड</u> जारी करना — राशनकार्ड का निर्गमन व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा दोनो प्रकार से किया जा सकता है। परिवार को राशनकार्ड जारी करने के पक्ष मे यह तर्क दिया जाता है कि इस विधि में कागज की बचत होती है। व्यक्तिगत राशनकार्ड निर्गमित करने पर उस राशनकार्ड का लेखा—जोखा रखने में भी परेशानी होती है। जबिक पारिवारिक राशनकार्ड के निर्गमन की दशा में इस परेशानी से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि सम्पूर्ण परिवार के लिए एक राशनकार्ड जारी किया जाता है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह है कि जब परिवार के कुछ व्यक्ति बाहर घूमने या नौकरी करने चले जाते हैं तो उस परिवार द्वारा सम्पूर्ण राशन प्राप्त कर लिया जाता है जो कि अनुचित है। इस प्रकार के अपराधों का पता लगाना अत्यन्त आवश्यक होता है, परन्तु व्यवहारिक रूप से इसका पता लगाना कठिन है। पारिवारिक राशन कार्ड के सम्बन्ध में एक समस्या यह भी है कि वयस्क लड़की शादी के बाद अपने घर चली जाती है और उसका नाम ससुराल के सदस्यों में शामिल हो जाता है, किन्तु अधिकाशत लड़की के मायके में उसकी एक यूनिट को घटवाया नहीं जाता। परिणामस्वरूप उसके नाम से दो स्थानों पर राशन या खाद्य पदार्थ उठाया जाता है। व्यवहारिक रूप में राशनिंग अधिकारी के लिए यह एक कठिन कार्य है कि वह सिद्ध कर सके कि उस समय वह व्यक्ति जिसका कि राशन प्राप्त किया जा चुका है, बाहर था।

व्यक्तिगत राशनकार्ड जारी किये जाने की दशा में यह कार्य कठिन होता है कि व्यक्ति बाहर गया हो और उसका राशन कोई दूसरा व्यक्ति आकर प्राप्त कर ले। ऐसी अनुपस्थित अपने आप सिद्ध हो जायेगी और राशनिग अधिकारी राशनकार्ड के सम्बन्ध में की गयी बेईमानी पर रोक लगा सकते हैं। व्यक्तिगत राशनकार्ड की व्यवस्था इस दृष्टि से भी उचित होती है क्योंकि पारिवारिक राशनकार्ड की दशा में परिवार का मुखिया अपने राशनकार्ड का नवीनीकरण कराने में उस दशा में अनावश्यक विलम्ब करता है जबिक उसके परिवार के कुछ सदस्य बाहर चले गये होते हैं। बम्बई के राशनिग अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर पारिवारिक राशनकार्ड के बजाय व्यक्तिगत राशनकार्ड को अधिक उपयोगी बताते हैं। इस प्रकार यह विभिन्न तत्वो पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का राशनकार्ड जारी करना उचित होगा, क्योंकि दोनो पद्धितयों के अपने—अपने गुण—दोष है और इन गुणो और दोषों की जानकारी राशनिग अधिकारियों को होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब राशनिग प्रणाली प्रचलन में आयी तो अधिकारियों ने पारिवारिक राशनकार्ड निर्गमित करना आरम्भ कर दिया जबिक उन्हें भी इस व्यवस्था के गुण—दोषों की पूर्ण जानकारी नहीं थी।

जलपान—गृह, होटल, धर्मशाला और लॉज इत्यादि सामूहिक खाद्य स्थानो के लिए राशनकार्ड जारी करते समय बहुत सी बातो का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी सस्थाओ के लिए राशनकार्ड की आवश्यकता का निर्धारण करने मे, वहाँ आने वाले व्यक्तियो की सख्या, प्रयोग किये जाने वाले ईधन की मात्रा

<sup>5</sup> प्राइस कट्रोल एण्ड राशनिग-भार्गन, आर एन , किताबिस्तान, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या-65

प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा, कार्य करने वाले नौकर, दिया जाने वाला किराया, भुगतान किया जाने वाला आयकर इन सबके आधार पर उसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। मात्रा का निर्धारण बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बाद में इसमें वृद्धि की गुजाइश भी रहनी चाहिए। आकिस्मिक या अस्थायी रूप से आने वाले अतिथियों के एक प्रार्थना पत्र पर कार्ड निर्गमित किया जा सकता है।

8 <u>राशिनिग कस्तुओं की आपूर्ति</u> व्यक्स्था — राशिनिग अधिकारी को यह निश्चित करना होगा कि किस-किस समय राशिनिग वस्तुओं की पूर्ति की जायेगी। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि निर्धन व्यक्ति एक ही दिन में अपने पूरे माह के उपभोग हेतु राशन क्रय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता कि वे अपनी निर्धारित मात्रा का क्रय एक निश्चित समय पर ही कर सके। अत राशिनिग वस्तुओं की पूर्ति एक लम्बी अवधि तक बनाये रखे जानी चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति भी अपनी सुविधानुसार खरीदकार्य कर सके। यदि साप्ताहिक आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को उठाया जाता है तो श्रमिक व निर्धन व्यक्तियों को अपना राशन उठाने में आसानी होगी। कार्ड—धारकों को यह सुविधा प्राप्त होनी चाहिए कि वे सप्ताह में किसी भी दिन जाकर अपनी राशन की मात्रा उठा ले। राशनकार्ड का निर्गमित हो जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो जाता है कि सरकार राशन की उचित मात्रा की पूर्ति के लिए जागरूक है तथा उपभोक्ता इससे आश्वस्त हो जाता है और वितरण के प्रथम दिन ही दुकानो पर भीड नहीं लगाता। इससे प्रत्येक श्रमिक व मजदूर को अपने कार्य घण्टो को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सभी व्यक्तियों को राशन की दुकान पर पहुँचते ही वस्तुए प्राप्त हो जायेगी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा इसकी पूर्ति के सम्बन्ध में नहीं होगी। अत सप्ताह में किसी भी दिन दुकान से उपभोक्ताओं को राशन की पूर्ति करने व वितरण करने का प्रावधान होना चाहिए न कि किसी विशिष्ट दिन।

इस सम्बन्ध मे राशनिग अधिकारियों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि राशनिग वस्तुओं की सूची मे आवश्यक वृद्धि समय-समय पर की जाती रहे जिससे कि अन्य वस्तुओं पर उसका उचित प्रभाव पडे। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जब एक खाद्य-वस्तु पर राशनिग व्यवस्था लगायी जाती है तो अन्य खाद्यान्नों का मूल्य अपने आप बढने लगता है।इसलिए उस दशा में आवश्यक हो जाता है कि जिस वस्तु पर राशनिग व्यवस्था नहीं लगायी गई है, उस पर भी वितरण के सम्बन्ध में कुछ नियन्त्रण लगाने चाहिए।

9 राशन की दुकानों का चयन — राशन की दुकानों का चयन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राशन की दुकानों का निर्धारण करने के लिए अधिकारियों को एक योजनाबद्ध रूप में कार्य करना होगा। सामान्यतया राशन की दुकाने भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करती है इसलिए दुकानों का निर्धारण करने समय मुहल्ला खाद्य सलाहकार समिति का गठन कर उसका निर्देशन प्राप्त करना

11/1

चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो ये सिमितियाँ उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखते हुए ऐसी दुकानों का चयन करेगी जिससे उपभोक्ताओं को वस्तु क्रय करने के लिए अपने आवास से अधिक दूर न जाना पड़े। दुकानों की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि फुटकर व्यापारियों मर नियन्त्रण किया जा सके। इसके लिए सरकार को स्वय तो राशन की दुकाने खोलनी ही चाहिए साथ ही साथ ऐसी दुकानों का लाइसेन्स अन्य व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में इस प्रकार का लाइसेन्स दिये जाने में पचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम-प्रधानों से भी विचार विमर्श किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी दुकानों का लाइसेन्स देते समय सहकारिता को भी प्राथमिकता दी जाती है। इसके संचालन में लड़ाई में मारे गये सैनिकों के परिवार के सदस्य,स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी, लड़ाई में घायल परिवार के सदस्य तथा विकलाग व्यक्ति, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी,ग्रीन कार्ड धारक और अन्य स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने देश या परिवार या समाज का लाभ नहीं सोचते, केवल अपना व्यक्तिगत हित देखते हैं और हममें आपसी कल्याण के भावना की कमी हैं। सरकार भी लोगों के मस्तिष्क में व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर देश हित की भावना जागृत नहीं कर पाती। इसलिए व्यक्ति नैतिक रूप से सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं देते। परिणामस्वरूप सरकार खाद्य समस्या से प्रभावकारी ढग से निपटने के लिए कृत सकल्प होते हुए भी आधिक्य वाले क्षेत्री से खाद्यानाों को निकालने में सफल नहीं हो पाती। किसान फसल खरांब हो जाने पर, वर्षा की अनियमितता अथवां बाढ़ आ जाने पर, महामारी व बीमारी के कारण सदैव अनिश्चितता का जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसी दशा में वे भविष्य के लिए खाद्यान्नों को सचित करते हैं जिससे खाद्य समस्या और भी बढ़ जाती है।

उपभोक्ता की पसंन्द पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण भी राशनिंग व्यवस्था की आलोचना की जाती है। उपभोक्ता को राशनिंग व्यवस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तु पर ही निर्भर करना पड़ता है। उसे स्वेच्छा से वस्तुओं के चयन की सुविधा नहीं रहती। एक उपभोक्ता जो अपनी वर्ष भर की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्न खरीदना चाहता है उसे भी राशनिंग व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न की थोडी-थोडी मात्रा खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रत्येक स्थित युद्ध के दिनों में अपनी वर्ष भर की खाद्यान्न आवश्यकता का भण्डारण कर लेना साहता है तािक उसे वर्ष भर में खाद्यान्न के लिए परेशान न होना पड़े और उसके आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। कभी-कभी धनवान व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुए खरीदने में हतोत्साहित करते हैं। धनवानों की इस स्वतन्त्रता को सामाजिक गा राजनैतिक किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें एक वर्ग के द्वारा वूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। यद्यपि वर्ग राशनिंग के माध्यम से ऐसी समस्याओं को कम किया जा सकता है।

- (ब) <u>राशिनग व्यवस्था के लाभ</u> राशिनग व्यवस्था का प्रयोग अलग–अलग समय में अलग–अलग स्वरूप में होता रहा है। कभी इसका प्रयोग वर्ग राशिनग के रूप में किया गया तो कभी आशिक राशिनग के रूप में। इसी कारण अधिकाश राज्यों में इसका विरोध भी होता रहा है। प्रणाली की जटिलता, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ और नागरिक प्रशासकीय व्ययों में होती असमान वृद्धि आदि इस व्यवस्था के विरोध का आधार रहे हैं। वास्तव में राशिनग व्यवस्था के विभिन्न लाभों के कारण ही हम अर्थव्यवस्था के प्रारिभक सिद्धान्तों को जानने के बाद खुले हृदय से इस व्यवस्था का स्वागत करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ग्रंशिनगं व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—
- 1 असामाजिक और अमैतिक जमाखोरी पर रोक राशनिंग के माध्यम से असामाजिक व अमैतिक रूप से ध्यापारियों व उत्पादको द्वारा की गयी जमाखोरी पर प्रतिबन्ध लगता है तथा वे जमाखोरी नहीं कर पाते, क्योंकि रारकार द्वारा निजी व्यापारियों के लिए वस्तुओं के अधिकतम स्टाक की मात्रा निर्धारित कर वी जाती है और खाद्यान्तों की कृषकों से सीधी खरीद कर लेने से इनके लिए खाद्यान्तों की खरीद हेतु मात्रा भी कम बचती है। सामान्य जनता को राशनिंग दुकानों से खाद्यान्त उपलब्ध करा दिये जाने के परिणामस्थकप इनका स्टाक कभी—कभी गोदामों में पड़ा ही रह जाता है। इस प्रकार खाद्यान्तों की पूर्ति और उसके वितरण के सम्बन्ध में सरकार की हो रही आलोचना समाप्त हो जाती है।
- 2. रोजगार में वृद्धि इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे देश मे अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा इसकी व्यवस्था एक अलग मत्रालय द्वारा सम्पन्न की जाती है। प्रत्येक जिले मे जिला पूर्ति अधिकारी और उसके अधीनस्थ विभिन्न स्तर के कर्मचारियो तथा विभिन्न दुकानो की स्थापना एव सचालन हेतु बड़ी सख्या मे व्यक्तियो को कार्य पर लगाया जाता है।
- 3 अनावश्यक उपभोग पर प्रतिबन्ध जब राशनिंग के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण होने लंगता है तो इसके अनावश्यक उपभोग पर स्वत प्रतिबन्ध लग जाता है। युद्ध के समय राशनिंग व्यवस्था की सागू करके खाद्यान्नों के अनावश्यक उपभोग को कम किया जा सकता है। इस प्रकार एक और तो जम साधारण का मैतिक स्तर ऊँचा होता है, लोगों में देश भिक्त की भावना जागृत होती है वे खाद्यान्नों का उपभोग कम करके देश के प्रति वफादारी का परिचय देते हैं, दूसरी और जनता द्वारा उपभोग की कमी से हीने वाली बचत का उपभोग अन्यत्र किया जा सकता है।
- 4. समय का सदुपयोग राशनिंग व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक मुहल्ले में स्थापित दुकानी पर हमें माम्बाही वस्तु अपने निकटतम दुकान से प्राप्त हो जाती है और 'पक्ति-व्यापार' समाप्त हो

जाता है। व्यक्तियों के लम्बी-लम्बी कतारों में नष्ट हो जाने वाले समय की बचत होती है। पिक्तियों में खंडे होने वाले श्रिमिकों के जो श्रम घण्टों की हाँनि होती है, उस पर रोक लगायी जा सकती है। बचाये गये श्रम घण्टों का उपयोग श्रिमिक देश के उत्पादन कार्यों में कर सकते हैं जिससे कि देश का उत्पादन बढता है और आर्थिक विकास होता है।

11

- 5 <u>काले बाजार की कमी में सहायक</u> राशनिंग व्यवस्था काले बाजार के अवसर को कम करती है क्योंकि इससे वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण हो जाता है। जब सभी व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार वस्तुओं की पूर्ति उचित समय, स्थान और मूल्य पर होगी, तो कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को काले बाजार से अधिक मूल्य पर क्रय नहीं करेगा। इस प्रकार काले बाजार के अवसरों में अपने आप कमी आती है।
- 6 प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य में सहायता राशनिग व्यवस्था के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी भविष्य में खाद्यान्नों की माँग का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर आकंतित माँग की पूर्ति हेतू वे माँग के अनुरूप पर्याप्त भण्डार की व्यवस्था कर सकते हैं।
- 7 खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने में सहायक राशनिग व्यवस्था प्रत्येक परिवार में हो रही खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने में सहायक होती है। खाद्यान्नों का सम्पूर्ण रूप से उचित प्रयोग हो सके इसके लिए राशन की मात्रा प्रति इकाई की दर से निर्धारित की जाती है। राशनिग के आधार पर जब एक निर्धारित मात्रा ही एक व्यक्ति को प्राप्त होगी तो वह उतनी ही मात्रा क्रय करेगा जितनी उसके लिए आवश्यक होगी क्योंकि अतिरिक्त मात्रा प्राप्त ही नही होगी तो बर्बादी का प्रश्न ही नही उठता। साथ ही यदि किसी परिवार में दूध, मांस, फल का उपयोग अधिक होने से खाद्यान्न का उपयोग कम होता है तो उसके मस्तिष्क मैं भी खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने की भावना जागृत होगी और इस प्रकार हर एक व्यक्ति खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने का प्रयास करेगा।
- 8 सरकार पर विश्वास राशनिग व्यवस्था के माध्यम से सरकार अकाल पड जाने पर, युद्ध के समय, या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा जैसे— भूकम्प आदि, के आ जाने पर अपने रखे गये अतिरिक्त भण्डार में से खाद्यान्म की एक निश्चित मात्रा राशनिग के माध्यम से वितरित करती रहती है। इस प्रभार देश की सामान्य जनता को ऐसी अनिश्चित घटनाओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है, और उसकी निष्ठा सरकार में और षढ जाती है।
- 9 सामाजिक कुरीतियो पर नियन्त्रण राशनिंग के द्वारा रूढिवादी, परम्परागत, धार्मिक व सामाजिक उत्सवों पर रोक लगायी जा सकती है। जब राशन की निर्धारित मात्रा से अधिक राशन प्राप्त नहीं होगा, तो समारोहो या सांस्कृतिक उत्सवो पर गाँव वालो को भोजन कहाँ से खिलाया जा सकेगा। इस कारण आम जनता इसमें बचत करेगी। बचत से पूँजी निर्माण होगा और पूँजी का प्रयोग देश को और अधिक समृद्ध करेंगी में सहायम होगा।

- (स) राष्ठित व्यवस्था की समस्याए एव सुझाव कोई भी व्यवस्था बहुत अच्छी होते हुए भी कुछ न कुछ दोष पूर्ण अवश्य होती है। व्यवस्था मे रहने वाली किमयो के आधार पर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और यह प्रयास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो दीर्घकाल मे किसी व्यवस्था को परिष्कृत तो कर सकती है परन्तु दोष-रहित नही। पूर्ण सत्यता की इसी सीमा के अन्तर्गत राष्ठिति व्यवस्था की भी कुछ समस्याए और उनको दूर करने के सुझाव निम्नलिखित है-
  - 1 खाद्यान्तो की अनियमित पूर्ति —इस व्यवस्था का सबसे बडा दोष खाद्यान्तो की अनियमित पूर्ति है। उपभोक्ता को एक लम्बी अविध तक लाइनो में खडे होकर खाद्यान्न प्राप्त करना पडता है क्योंकि राशनिंग दुकानें माह में केवल कुछ दिन खुलकर पूरे माह बन्द ही रहती है, जिससे दुकानों के खुलाने पर भीड इकट्ठा हो जाती है।

वास्तव मे यह दोष राशनिंग प्रणाली का नहीं है। इसलिए हमें राशनिंग प्रणाली का विरोध न करके राशनिंग के प्रबन्ध, भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था का विरोध करना चाहिए। यदि राशनिंग व्यवस्था को व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाय, साथ ही अधिकारी वर्ग दुकानों को सप्ताह में कम सै कम तीन दिन खुलवाने की व्यवस्था करने का सकल्प ले तो इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

2 <u>रुचि के अनुसार खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता</u> प्रत्येक व्यक्ति या परिवार अपने खाद्यान्न का चयन अपनी रुचि के अनुसार करता है। हमारे देश में पारिवारिक विविधिता के कारण खाद्यान्न के प्रकार उसके उपभोग की मात्रा में पर्याप्त अन्तर होता है। यदि समाज परम्परागत और रूढिवादी है तो वह खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार की अपेक्षा करता है। राशनिंग के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सम्मुख्य करना एक कठिन कार्य है, जैसे— बगाली गेहूँ का कम तथा चावल का उपभोग अधिक करते हैं। जबकि पंजाबी चावल का कम तथा गेहूँ का उपभोग अधिक करते हैं।

इस समस्या का निराकरण राशनिग वस्तुओं की सख्या में वृद्धि करके किया जा सकता है। दुकानीं में कई प्रकार की वस्तुए उपलब्ध कराकर अधिकाश उपभोक्ताओं की रूचि के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है।

3 <u>आंकड़ों की अनुपलब्धता</u> — यदि राशनिग व्यवस्था नये शिरे से लागू करना हो तो इस बात का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन है कि किसी खाद्यान्न की राशनिग के लिए खाद्यान्न का कितना स्माक राधाने की आवश्यकता होगी। सामान्य व शान्ति के समय व्यक्ति कितने खाद्यान्न का उपभोग करता है इसी आधार पर भविष्य के लिए आवश्यक खाद्यान्न की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

वास्तव में जिन व्यक्तियों के माध्यम से राशनिग व्यवस्था सम्पन्न करायी जानी है उनको इस मान्ना का अनुमान लगाने का कार्य सौप कर आवश्यक खाद्यान्न की यथोचित मात्रा का अनुमान बिना अतिरिक्त व्यक्त के सम्लात से जगामा जा सकता है। 4 जनसंख्या की निरक्षरता एव अज्ञानता — अधिकाश भारतीय जनता की अशिक्षा एव अज्ञानता के कारण वह राशनिंग व्यवस्था का विरोध करती है। जनता सरकार की नीतियों का विरोध करते करते सरकार का ही विरोध करना आरम्भ कर देती है। ऐसे व्यक्ति यह विचार भी व्यक्त करते हैं कि यदि राशनिंग व्यवस्था न होती तो वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का क्रय कर पाते।

इस रामस्या के निवारण हेतु आवश्यक है कि राशनिग व्यवस्था लागू करने से पूर्व इसके कारणो एव प्रभावो तथा राशनिग प्रक्रिया का विधिवत् प्रचार एव प्रसार किया जाय ताकि इस व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता की भान्तियो से निजात् पाया जा सके।

5 <u>राशन की मात्रा के निर्धारण में कठिनाई</u> — इस बात का निर्धारण करना भी एक कठिन कार्य है कि एक व्यक्ति अथवा परिवार को राशन की कितनी मात्रा प्रदान की जाय, क्या इस सम्बन्ध में किसी अधिकतम अथवा न्यूनतम मात्रा को निश्चित किया जाय अथवा नहीं ?

जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग का विभाजन और राशन की मात्रा का निर्धारण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए, विभिन्न स्तरो पर होना चाहिए। इस कार्य के लिए पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है। विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वेक्षण कर लेने के बाद ही उनके दैनिक उपभोग की मात्रा के अनुसार कुल आवश्यक खाद्यान्न का अनुमान लगाकर राशन की नियमित पूर्ति की जा सकती है।

6 सुकानदारो द्वारा बेईमानी — राशन की दुकानो पर काम करने वाले व्यक्ति न तो ईमानदारी पूर्वक विक्रय का कार्य करते हैं और न ही उपभोक्ताओं की भावनाओं का ही आदर करते हैं। वे अपने लाभ को बढ़ाने के लिए नैतिक और अनैतिक हर तरह के कार्य कर सकते हैं। ये वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर काला बाजारी को प्रोत्साहित करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्थाए साथ—साथ चलती रहती है जिसका दुष्परिणाम उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है।

यह दोष भी राशनिग व्यवस्था का नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता की है। यदि समाज का हर व्यक्ति उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति सजग हो तथा कर्मचारियों ह्यारा मैतिकता के साथ अपने उत्तरदायित्वोंका निर्वहन किया जाय तो ये समस्या स्वत समाप्त हो जायेगी।

7 खाद्यान्नों का केन्द्रीयकरण -राशनिंग व्यवस्था में खाद्यान्नों को उत्पादकों से खरीदकर एकत्रित किया जाता है जिससे खाद्यान्न एक निश्चित क्षेत्र में केन्द्रित हो जाता है इसके अतिरिक्त राशन की वुकाने भी कुछ असुविधाओं से बचने के लिए केन्द्रीकृत हो जाती है।

खाद्य दुकानों को शहर के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए जिससे कि हर क्षेत्र के व्यक्ति राशन खरीद सकें। इसके लिए खाद्यान्नों के बाजारों का विकेन्द्रीकरण भी होना चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओं को रोशन खरीदनें में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

B: <u>खाधामीं के प्रतिस्थापन की सुविधा महीं:-</u> राप्रातिंग ब्यवस्था के विषय में कहा जाता है

कि 'यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, न कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस खाद्य को उपभोग के स्वाद से सन्तुष्ट होने के लिए। '

इसके लिए आवश्यक है कि एक खाद्यान्न का प्रतिस्थापन करने वाले दूसरे खाद्यान्न का भी राशिनिग व्यवस्था की जाय, जैसे – चावल के स्थान पर कोदो अथवा गेहूँ के स्थान पर बाजरा। इससे एक वस्तु की अनापूर्ति की दशा मे दूसरी वस्तु से उपभोक्ताओं को सन्तुष्ट किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति गेहूँ के स्थान पर बाजरे का उपभोग करना चाहता है तो उसे बाजरे की पूर्ति की जा सकती है।

# (ख) खरीद-कार्य -

उपभोक्ता के लिए खाद्यान्नों को खरीदते और एकत्रित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनके उत्पादको अर्थात् कृषकों को उनकी लगायी पूँजी पर उचित लाभ प्राप्त हो। खाद्यान्नों की खरीददारी में उपभोक्ता के हितों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता होते हुए भी हम अपने इन ससाधनों का अत्युत्तम प्रयोग कर उत्पादन वृद्धि में सफल नहीं हो पाते, परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार की स्थिति बढ़ती ही जाती है। देश का विकास हमने योजनाबद्ध तरीके से करने का निभ्चय किया है, ऐसे समय में खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार की सफलता बहुत हद तक उचित व समन्वित खाद्यान्नों की खरीद नीति पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यापार का क्षेत्र कितना विस्तृत है, उसकी क्षमता कितनी है, तथा कितनी मात्रा में वस्तुओं को एकत्रित किया जा सकता है। जितनी मात्रा में खाद्यान्नों को एकत्रीकरण हो पाता है खाद्यान्नों की उतनी मात्रा ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है। यदि सरकार खाद्य-पदाथों की आपूर्ति उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहती है तो उसे खरीद—नीति सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना होगा। खरीद—कार्य राशनिग व्यवस्था की जीवन—वाहिनी है, बिना इसके राशनिग व्यवस्था चल ही नहीं सकती।

- (अ) उद्देश्य -आवश्यक वस्तुओं के न्यायोचित वितरण के लिए यह आवश्यक है कि उचित खरीद नीति अपनायी जाय। खरीद-नीति के साथ-साथ पर्याप्त भण्डारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उपयुक्त खरीद-नीति व भण्डारण की व्यवस्था से मूल्य वृद्धि के स्तर में कमी करने और मूल्यों को स्थायित्व प्रदोन करने मैं मदद मिलती है। खरीद कार्य के प्रमुख उद्देश्य निम्न है-
- 1 <u>उत्पादको को न्यायोचित प्रतिफल प्रदान करना</u> खरीद कार्य का मुख्य उद्देश्य जहाँ एक और उपभोक्ता। के लिए सस्ती दर पर खाद्यान्न खरीदना है वही दूसरी ओर कृषक को उसके उत्पादन का न्यायोचित प्रतिफल प्रदान करना है। वे जितनी भी पूँजी इस उत्पादन कार्य मे लगायें उनको उचित लाभ

प्राप्त हो जिससे कि वे पुन इस कार्य में सलग्न रहे और उत्पादन करे। जब सरकार द्वारा उनको उचित प्रतिफल प्रदान किया जायेगा और वे आर्थिक उत्पादन के लिए प्रयत्नशील रहेगे, तब उन वस्तुओं का अभाव नहीं होगा और उत्पादन प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी।

- 2 <u>पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखना</u> खरीदकार्य का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है खाद्यान्न का पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखना। ऐसा बफर स्टाक बन जाने की दशा में यदि किसी प्राकृतिक आपवा अग्वा अन्य किसी कारण से उत्पादन कार्य बाधित होता है तो क्स्तुओं के अभाव की दशा में उपभोक्ता को वस्तुओं की पूर्ति बनाये रखी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ उत्पादक भी अत्यधिक उत्पादन की दशा में होने वाली आशंका से प्रभावित न होकर अतिरिक्त उत्पादन का प्रयास सदैव जारी रखेंगे क्योंकि प्रत्येक दशा में उनके उत्पादन का पर्याप्त मूल्य मिलता रहेगा।
- 3 उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना खरीदकार्य के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद करके उसका भण्डारण कर लिया जाता है जिससे अभाव की दशा में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जा सके तथा व्यापारी वर्ग गरीब उपभोक्ताओं का शोषण न कर सके। पर्याप्त खरीद करके सरकार मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करती है। वह वस्तुओं की माँग एव पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करके मूल्यों में वृद्धि को रोक्ती है। इसके फलस्वरूप निम्न आयवर्ग के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है जो कि राशनिग व्यवस्था का मूल आधार है।
- (बं) विधि खरीदकार्य इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसे सारे देश पर लागू किया जा सके। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम ऐसा एक मात्र अभिकर्ता है जो कि इस कार्य को सम्पादित करता है। सरकार खरीद मूल्यों की घोषणा करके उत्पादकों से उनका उत्पादन क्रय करती है। सरकार द्वारा खाद्यान्नों का निर्धारित किया जाने वाला मूल्य खाद्यान्न के गुणों के अनुसार होता है। निर्धारित मूल्यों में सरकार समय—समय पर परिवर्तन भी करती रहती है। खरीद की विधि का निर्धारण वहाँ की स्थानीय द्यांओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सरकार प्रत्येक राज्य में वहाँ की उत्पादन क्षमता के आधार पर खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य की घोषणा अपनी मूल्य नीति के तहत् करती है। वास्तव में खाद्यान्नों की यह मूल्य नीति विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है क्योंकि प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों की उत्पादन क्षमता दूसरे राज्यों की तुलना में भिन्न रहती है तथा इसके साथ ही साथ खाद्यान्नों की गुणवत्ता में भी अन्तर रहता है। इस प्रकार जब राज्यों में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न की आवश्यकतानुसार खरीद नहीं हो पाती अथवा खाद्यान्न का उत्पादन आवश्यकतानुसार नहीं हो पाता तो सरकार खाद्यान्नों की आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक मांत्रा में खाद्यान्नों का आयात भी करती है जिससे उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की कमी का सामना न करना पढ़े तथा उसकी नियमित पूर्ति बनाये रखी जा सके। सरकार किसानों पर लेवी लगा कर भी खाद्यान्नों का

क्रयं करती है जिसमे विभिन्न उत्पादन क्षमता वाले किसानों को खाद्यान्न की विभिन्न मात्रा निश्चित रूप से सरकार को बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। इस लेवी का मूल्य स्वय सरकार द्वारा निर्धारित एव समय— समय पर परिवर्तित किया जाता रहता है। मूल्य निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कृषकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिल सके। निम्न तालिका में सरकार द्वारा कुछ खाद्यान्नों के समय—समय पर निर्धारित किये गये मूल्य दर्शाये गये हैं—

तालिका सख्या 1 सरकार द्वारा निर्घारित खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति कुन्तल)

खाद्यान्न	1983-84	1988-89	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
गेहूँ	151	173	275	330	350	360
जौ	122	135	210	269	275	_
चना	235	290	500	600	640	670
सरसो	335	430	670	760	810	830
गन्ना	13 5	19 5	26 0	27 0	32 5	36 1
धान(सामान्य)	132	160	230	270	310	340
सूत	400	500	695	800	900	1000
जूट	185	250	375	400	425	450

म्रोत- 1 इण्डियन इकोनमी-अग्रवाल, डी सी , साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-274

2 सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल- अप्रैल1995, क्रॉनिकल पब्लिकेशस, प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ स0 70

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक खाद्यान्न एव वस्तु के सरकारी खरीद मूल्य में वर्ष 1983-84 से लगातार वृद्धि हो रही है वर्ष-1994-95 में निर्धारित खरीद मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें जूट के मूल्यों में 11 1 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि तथा सरसों के मूल्य में 2 4 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि की गई है जबिक 1983-84 से 1988-89 के बीच में खरीद मूल्य में वृद्धि का विस्तार 2 1 प्रतिशत से 7 0 प्रतिशत के बीच रहा। यद्यपि मूल्यों में वृद्धि का कारण मुद्रा स्फीति भी है परन्तु निर्धारित किये गये मूल्य किसानों को फसलों के उगाने के लिए पर्याप्त रूप में प्रोत्साहित करते हैं।

(स) खरीद के माध्यम — खरीद कार्य के लिए देश में कई प्रकार के माध्यम बनाये गये हैं जिससे इस कार्य को बिना किसी असुविधा के सम्पन्न किया जा सके और खाद्यान्नों की कमी का अनुभवं भी न हो। इस प्रकार खाद्यान्नों के खरीद कार्य हेतु निम्नलिखित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है-

1 राज्य सरकार एव उनकी एजेन्सियो के माध्यम से खरीद कार्य — जहाँ पर भारतीय खाद्य निगम अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक नहीं कर पाता, वहाँ पर राज्य सरकार की एजेन्सियो द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया जाता है। खरीद कार्य के लिए अलग—अलग राज्यों में अलग—अलग विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद से कृषि मूल्यों में स्थिरता आती है। वर्ष 1988—89 खरीद मौसम से चावल और गेहूँ जैसी मुख्य फसलों की सरकारी खरीद का विवरण निम्नवत् है—

तालिका संख्या 2 खाद्यान्नो की सरकारी खरीद

(लाख टनो मे)

फसल	1988-89	1989-90		1991-92 अनतिम		1993-94 अनतिम
चावल	77 29	118 67	126 76	102 47	130 41	-
गेहूँ	65 81	89 42	110 65	77 52	63 80	128 33

नौट नामल की खरीद मात्रा में 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक की अवधि एवं गेहूँ की खरीद मात्रा में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में खरीदी गयी मात्रा को शामिल किया गया है। स्रोत, भारत—1993, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 438

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि खाद्यान्तों के खरीद में सरकारी एजेन्सियों व राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चावल की सरकारी खरीद में वर्ष 1991-92 को छोड़कर लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1988-89 में चावल की खरीद मात्र 77 29 लाख टन ही थी जो वर्ष 1992-93 में बढ़कर 130 41 लाख टन तक पहुँच गयी है। गेहूँ की सरकारी खरीद भी पिछले 6 वर्षों में लगभग दो गुना हो गई। यदि सम्पूर्ण रूप से देखा जाय तो गेहूँ की खरीद वर्ष 1988-89 में 65 81 लाख टन थी जो वर्ष 1993-94 में बढ़ कर 128 33 लाख टन हो गयी। परन्तु वर्ष विशेष की तुलना यदि उसके गत वर्ष की खरीद से की जाय तो स्पष्ट होता है कि गेहूँ की खरीद में पर्याप्त उच्चावचन होता है।

सरकार तथा उसकी एजेन्सियो द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विदेशो से भी खाद्यान्नो का आयात किया जाता है। सरकार को खाद्यान्नो का आयात इसलिए अधिक करना पड़ता है क्योंकि लगभग आधे किसान अपनी उपज बड़ी एव नियमित मण्डियो मे बेचने के बजाय अब भी गाँव के छोटे बाजारो मे उन साहूकारों के माध्यम से बेचते हैं जिनसे उन्होंने फसल के लिए ऋण लिया है। सरकार द्वितीय महायुद्ध के काल से ही खाद्यान्नों का आयात कर रही है। इन खाद्यान्नों में गेहूँ, चावल के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्न

भी होते हैं लेकिन उनकी मात्रा कम ही होती है। 1951 से लेकर 1977 तक की अवधि में लगभग 3 हजार लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया। वर्ष 1978,1979,1980 में खाद्यान्नों की स्थिति देश में ही अच्छी होने के कारण आयात नहीं किया गया। लेकिन बफर स्टाक कम हो जाने के कारण 1981 में पुन खाद्यान्नों का आयात किया गया। <sup>6</sup> वर्ष 1989–90 में खाद्यान्न भण्डारण हेतु 5 23 लाख टन चावल का आयात किया गया जिसमें 1 04लाख टन चावल थाईलैण्ड से तथा 4 19 लाख टन वियतनाम से आयात किया गया वर्ष 92–93 के दौरान सरकार ने 29 9 लाख टन गेहूँ 2 15 लाख टन चावल के आयात का अनुबन्ध किया। <sup>7</sup>

2 <u>भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद कार्य</u> भारतीय खाद्य निगम राशनिग व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद, उसका बफर स्टाक तथा भण्डार की व्यवस्था करने हेतु एक मात्र सस्था है जो वस्तुओं की खरीद समस्त देश में करती है और सरकार के आदेशानुसार उसको वितरण के लिए उपलब्ध करांती है। किसान अपने उत्पाद को स्थायी अथवा अस्थायी बाजार या मडियो में लाते है। यदि बाजार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाये जाते हैं तो वहाँ उनके उत्पाद की जाँच की जाती है। जाँच करने के उपरान्त खाद्यान्नों को उनके गुणो के आधार पर मूल्यांकित कर बिक्री हेतु कृषकों को आमन्त्रित किया जाता है। यदि उत्पाद उचित औसत किस्म के अन्तर्गत नहीं आया तो निर्धारित मूल्य में कुछ कटौती करने के बाद भुगतान किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद का व्यवस्थापन रबी एवं खरीफ की फसलों के तैयार होने के पहले ही आरम्भ कर दिया जाता है। रबी की फसल के सन्दर्भ निगम के क्षेत्रीय प्रवन्धकों को जनवरी माह में ही बुलाकर कुल उत्पादन का अनुमान लगाने का कार्य सौपा जाता है तािक इस बात का पता चल सके कि आवश्यकतानुसार खाद्याग्न निर्धारित मूल्य पर खरीद हेतु उपलब्ध हो सकेगा अर्थवा मही। खरीद—कार्य—योजना विभिन्न क्षेत्रीय आधारों पर फरवरी या मार्च के प्रारम्भ में प्राप्त हो जाती है तथा इस सम्बन्ध में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रवन्धकों के मध्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रवन्धन हेतु पर्याप्त वित्त कोष, कर्मचारी, मशीने एवं भण्डारण क्षमता उपलब्ध करायी जाती है। प्रत्येक माह अधिकारियों की बैठक में एक फेन्द्र से दूसरे खरीद केन्द्र को आवश्यकतानुसार इनका समायोजन कार्य चलता रहता है।

खरीदकार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भारतीय खाद्य निगम उस राज्य की भाषा में समाचार पश्र—पश्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करता है और इसके साथ ही साथ वह रेडियो और टेलीविजन पर भी विज्ञापन करता है। इसके अतिरिक्त वह पोस्टर बनवा कर विभिन्न स्थलों पर चिपकवाता है और उसका

<sup>6</sup> भारत की आर्थिक समस्याए-मामोरिया एव जैन, साहित्य भवन, आगरा-1995, पृष्ठ सख्या 176

<sup>7.</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या 439

वितरण भी करता है, कि सरकार द्वारा समर्थित मूल्य की घोषणा कर दी गई है। ऐसे प्रचार एव प्रसार का उद्देश्य होता है कि किसान इन मूल्यो एव खरीददारी के नियमों के विषय में भलीभौति अवगत हो जाय। इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम मण्डियो तथा राज्य सरकार के अन्य क्रय—केन्द्रों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। किसानों को अपना उत्पाद अधिक दूर न ले जाना पड़े इसके लिए यह ध्यान रखा जाता है कि क्रय केन्द्रों की स्थापना इस प्रकार की जाय कि कृषकों को को 5 से 8 कि0मी0 से अधिक दूर तक अनाज न ढोना पड़े। यदि कृषकों की सुविधानुसार नियमित मण्डियों नहीं है तो ऐसी दशा में अस्थायी क्रय केन्द्र खीलकर खरीद कार्य किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम सरकार की मूल्य समर्थित नीति के अन्तर्गत ही खरीद कार्य करता है न कि किसी एकाधिकारी सस्था के रूप मे। इसके द्वारा खरीदी हुई मात्रा का अवलोकन निम्न तालिका से किया जा सकता है—

तालिका सख्या -3 भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी खरीद

वर्ष	मात्रा(लाख टनो मे)	मूल्य(करोड रु० मे)
1976-77	174 67	2545 28
1978-79	148 44	2199 64
1980-81	132 67	2633 39
1988-89	175 6	4936 47
1989-90	210 7	6712 13
1990-91	235 2	8207 32
1991-92	194 0	7635 86
1992-93	225 7	10549 78

मौत म्वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1976-77 की तुलना में वर्ष 1992-93 में मात्रात्मक खरीद में तो मात्र 29 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मूल्यात्मक खरीद में लगभग 314 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मात्रा की तुलना में मूल्यात्मक खरीद लगभग 11 गुना बढी हैं।

3 सहकारी सिमितियों द्वारा खरीद कार्य - संहकारी सिमितियों के माध्यम से भी खाद्यान्नों की खरीद का कार्य किया जाता है। ऐसी सिमितियों उन दुर्गम स्थानो पर खरीद का कार्य करती

है जहाँ भारतीय खाद्य निगम और सरकारी एजेन्सियाँ नहीं है। किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य उनके उत्पादन स्थल पर ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक गाँव में सहकारी समितियाँ अवश्य होती है जिसमें उनको परिवहन व बाजार की असुविधा से छुटकारा प्राप्त हो जाता है।

- (द) समस्याएं एव सुझाव खरीद कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पडता है। यह जरूरी नहीं है कि खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा खरीद केन्द्र पर आये ही। इसिलए खरीदकार्य से सम्बन्धित नीति का निर्धारण करते समय सरकार को कृषि मूल्य आयोग की सस्तुतियों पर बल देना चाहिए और इस सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार आपस में सम्बन्धित विकास क्रिम के अनुकूप ही कार्य करे तथा उसके लक्ष्यों को निर्धारित करे। इस सम्बन्ध में निम्न समस्याओं का सामना करना पड सकता है—
- 1 खाद्यान्नों का आधिक्य की दशा में होना खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि और उसका आधिक्य की दशा में होना, एक गम्भीर समस्या है क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन में जिस अनुपात में वृद्धि होती हैं उसी अनुपात में जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप माँग और पूर्ति में सन्तुलन या कंभी—कंभी पूर्ति में कमी की स्थिति ही बनी रहती है। जब खाद्यान्नों में वृद्धि नहीं होगी तो उसकी खरीदवारी और एकत्रीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, साथ ही राशनिंग व्यवस्था के कार्य में भी बाधा उत्पनन हो जायेगी।

वास्तव में खाद्यान्नों के उत्पादन की बढी हुई मात्रा का काफी हिस्सा बढी हुई जनसंख्या के भरण-पोषण में लग जाता है परन्तु फिर भी खाद्यान्न उत्पादन उत्पादकों की आवश्यकता से बहुत अधिक होता है। यदि ऐसी आशका हो कि खरीद का कार्य निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा तो किसानों पर न्यूनतम खेंची निर्धारित करके इस आशका से मुक्ति पायी जा सकती है परन्तु लेवी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसानों के उत्पादन प्रेरणा में वृद्धि हो, जैसे— खरीदे गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान लेवी की चीनी से अथवा सस्ते कपड़े से अथवा सस्ती उर्वरक या किसानों के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं में ही किया जाय। ऐसी दशा में किसान लेवी को भार न समझ कर खरीद केन्द्रों पर अनाज की बिक्री क्रिरमा अपना कर्तव्य समझेंगे और उत्साह पूर्वक सरकार की राशनिग व्यवस्था में अपना सहयोग देगे।

2 मण्डारण की समस्या — खरीद कार्य के सन्दर्भ मे एक समस्या यह भी आती है कि जितनी भी मान्ना में खाद्यान्नों का एकत्रीकरण या खरीददारी किया जाये, उसको सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको निर्गमित करने हेतु पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था होनी अनिवार्य है जिससे आवश्यकता पड़ने पर या आधिक्य की अवस्था में खाद्यान्नों के अभाव से बचने के लिए भण्डारण कर लिया जाये। पर्याप्त और उचित भण्डारण व्यवस्था के न होने की दशा में खाद्यान्नों का काफी भाग नुकसान भी हो जाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय खाद्य निगम को अपने गोदामो की सख्या बढानी चाहिए फिर भी यदि खाद्यान्नो की आधिक्य मात्रा के एकत्रीकरण हेतु पर्याप्त स्थान प्राप्त नहीं होता तो किराये के गोदामी का पर्याप्त सख्या में प्रयोग इस प्रयोजन के लिए करना चाहिए।

3 समन्वय का अभाव —खरीद के कार्य में एक समस्या यह भी है कि केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियों में आपस में समन्वय तथा भारतीय खाद्य निगम के विभागों तथा केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों मैं आपस में समन्वय का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप दोनों की नीतियों के स्पष्ट रूप से घोषित न होने के कारण नीतियों में एक लक्ष्य नहीं होता और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती।

वास्तव मे यह दोष व्यवस्था का है न कि खरीद कार्य का। इस समस्या से निबटने के लिए यह आवश्यक है कि निगम के अधिकारियो तथा राज्य एव केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागो के अधिकारियों को शामिल करते हुए जिस समय खरीद कार्य चल रहा होता है पाक्षिक बैठक तथा अन्य दशाओं में मासिक बैठके करते रहना चाहिए, ऐसी बैठकों में समस्याग्रस्त मुद्दो पर आपसी विचार—विमर्श द्वारा आपसी समन्वय स्थापित किया जा सकेगा तथा लक्ष्यों और नीतियों में एकरूपता स्थापित की जा सकेगी।

4 सांख्यिकीय आकडो की अनुपलब्धता — सांख्यिकीय आकड़ो की अनुपलब्धता के कारण अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। यदि खरीद कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सम्पन्न करना हो तो इसमे भी असुविधा होती है क्योंकि गलत अनुमान लगाने से वित्त व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था आदि का सदुपयोग नहीं हो पायेगा।

राजकीय प्रशासन को खरीद कार्य के लिए सस्थानात्मक एव सगठनात्मक ढाँचे की नियुक्ति के विषय में, राज्य, जिला एव खरीद केन्द्र की इकाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में, खरीद कार्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा विभिन्न स्तर पर निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में विशेष साबधानी बरती जानी चाहिए। जिलास्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करते समय आकडों की अपर्याप्तता एवं अनुपंत्रबर्धता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही साथ जो आकडे उपलब्ध है उनमें शुद्धता का सतर क्या है इसे भी ध्यान में रखा जाय। यदि ऐसा करने के बाद स्वेच्छा एवं लेवी से खरीद हेतु पर्याप्त वित्त उपलब्ध रहता है तो खरीद कार्य राजकीय व्यापार का एक नियमित एव स्थायी उपकरण बन सकता है।

## (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली-

1

प्रत्येक सरकार को जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसको आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना उसका दायित्व होता है। सामान्य विसर्ण धार्मिक्यों के अन्तर्गत उत्पादक से उपभोक्ता के बीच मध्यस्थता की एक लम्बी जजीर होती है, जिसके फ्रिक्किंप वस्तुओं की कीमते अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ये मध्यस्थ अपनी विमियोजित पूँजी खा अक्का प्रतिकाल अपनी मेताओं और सोविम का पुरस्कार तथा बढ़े हुए अन्य खर्च वस्तु के मूलवी मे

जोडकर प्राप्त कर लेता है। अन्त में इसका भार उपभोक्ता को ही वहन करना पडता है। उत्पादक से उपभोक्ता तंक वस्तुए पहुँचने में मध्यस्थों की सख्या कम से कम होने पर मूल्यों पर नियन्त्रण के साथ ही साथ उनकी शुद्धता और नियमित पूर्ति सम्भव है। इस कारण से मध्यस्थों पर अकुश होना आवश्यक है। सार्वजिनक वितरण प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकार उपभोक्ताओ विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को उनकी दैनिक आवश्यकताओ की वस्तुओं को उचित मूल्य उचित स्थान, उचित िकस्म तथा उचित समय पर उपलब्ध कराती है। स्वार्थपूर्ण भावना से निहित व्यापारी वर्ग द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण की सम्मावना की सार्वजिनक वितरण प्रणाली द्वारा ही समाप्त िकया जा सकता है। सार्वजिनक वितरण प्रणाली विशुद्ध रूप से एक सामाजिक वितरण व्यवस्था है जो सरकार के पूर्ण नियन्त्रण एव मार्ग दर्शन में चलती है। इसमें उत्पादक से लेकर उद्योगपित, किसान से लेकर मजदूर, फेरीवाले से लेकर सुपर बाजार तक शामिल है। इस माध्यम से व्यवसाय की विभिन्न कुरीतियाँ, जैसे—चोर बाजारी, वस्तुओं का सग्रह करके अभाव पैदा कर देना, मूल्यों में वृद्धि का अनापेक्षित प्रयास करना इत्यादि, को समाप्त कर मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया जाता है, जिससे कि वस्तुए कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जा सके। इसमें वस्तुओं में हो राष्टी मिलावट को भी नियन्त्रित किया जाता है जिससे कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर वस्तुओं के उपयोग से प्रतिकृत प्रभाव न पडे। इसके साथ ही साथ यदि देश का उत्पादन आन्तरिक उपभोग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो विदेशों से वस्तुओं का आयात करना भी शामिल है जिससे कि पर्याप्त स्थान का जीर अभावों की दशा में वस्तुओं का आयात करना भी शामिल है जिससे कि पर्याप्त स्थान की शोर अभावों की दशा में वस्तुण उपभोक्ताओं को उचित रूप से उपलब्ध करायी जा सके।

(अ) <u>परिभाषा</u> — सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिभाषा विभिन्न विद्वानो ने अपने—अपने ढग से दी है जिनमे से कुछ निम्नवत् है—

'भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह फुटकर व्यवस्था है जो राज्य के निरीक्षण एव मार्ग दर्शन में चलती है। 8

'सार्वजिनक वितरण प्रणाली वितरण के क्षेत्र में समाज के कमजोर और निर्धन वर्ग के उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार दैनिक उपभोग की वस्तुएं उचित मूल्य एव उचित समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। ' 9

<sup>8.</sup> पश्चितक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम-ढोलिकया एव खुराना, आक्सफोर्ड एण्ड आई बी एच , पब्लिशिंग कम्पनी, मई दिल्ली-1979, पृष्ठ संख्या- 35

<sup>9</sup> योजना-31मार्च 1987, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-22

''सार्यजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक वस्तुओं का वितरण सरकार द्वारा नियन्त्रित उचित मूल्य की वुकानों के माध्यम से किया जाता है।"<sup>10</sup>

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ' सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं को उनके गुणवत्ता के आधार पर उचित मूल्य एवं उचित समय तथा उचित मात्रा में उपभोक्ता तक पहुँचाने की वह प्रक्रिया है जिस पर सरकार का नियन्त्रण रहता है।

- (ब) <u>विशेषताएँ</u> —उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निम्न विशेषताए प्रकट होती है—
- <u>आवश्यक क्स्तुओं से सम्बन्धित</u> सार्वजिनक वितरण प्रणाली केवल आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति से सम्बन्धित वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करती है। यह आरामदायक या विलासिता की वस्तुओं से सम्बन्धित नहीं है। सार्वजिनक वितरण प्रणाली में कार, स्कूटर, टेलीविजन इत्यादि वस्तुओं का वितरण नहीं आता। वर्तमान समय में यह प्रणाली 6 महत्वपूर्ण वस्तुओं के वितरण में लगी है— गेहूँ, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल व कोयला। कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कुछ अन्य वस्तुओं यथा—साबुन नमक, चाय, दालों व कापियों के वितरण की व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत की है।
- 2 <u>उचित समय तथा उचित मूल्य</u> इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह भी है कि सभी उपभोक्ताओं को वस्तुओं की पूर्ति उचित समय एव उचित मूल्य पर की जायेगी। उचित समय का आशय है कि वस्तुओं की आवश्यकता जब होगी तब वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायेगा, ऐसा न होगा कि आवश्यकता पर वस्तुएं उपलब्ध न रहे तथा आवश्यकता न होने पर उपलब्ध हो। उचित मूल्य का आशय है कि जितना मूल्य उपभोक्ता आसानी से दे सके और उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि अत्यधिक किंचे मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध करायी जायेगी तो इस प्रणाली का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पायेगा।
- 3 अन्तिम उपभोनता के प्रतिसमर्पित इसका सम्बन्ध उस व्यक्ति से नही होता है जो वस्तु को खरीदकर पुन विक्रय करे। इसका सम्बन्ध उत्पादक से सीधा उपभोनता का होता है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को वस्तु की पूर्ति करायी जाती है, वही इसका उपभोग भी करते है।
- 4 सार्वजनिक हित —यह प्रणाली समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती, बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे व धनी हो अथवा निर्धन सभी को इस अध्यास्था से लाभ होता है। सरकार इस प्रकार का कोई भी बन्धन नहीं रखती जिससे कि यह प्रणाली केवल निर्धन वर्ग पर लागू हो। ऐसी व्यवस्था सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर की जाती है।
- 5 वितरण व्यवस्था यह प्रणाली वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित है न कि उत्पादन 10 इंकिंग इकोननी आजात, ही सी , साहित्र अन्त आग्रा-1884, मुख्य संख्या 277

से। जितना उत्पादन होता है उसी के अनुरूप उसका वितरण किया जाता है। उत्पादन से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। इसका पूर्ण सम्बन्ध वितरण व्यवस्था से ही है।

- 6 सरकारी नियन्त्रण सार्वजिनक वितरण प्रणाली सरकार के नियन्त्रण में कार्य करती है। केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सत्ता सभी का इस प्रणाली से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। यदि इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी वस्तु की पूर्ति अपर्याप्त है तो उसके आयात की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है।
- (स) अवधारणा बस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक हैं सही वस्तुओं का उचित मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना। यह कार्य उपर्युक्त वितरण व्यवस्था के बिना असम्भव है। भारत में अभी भी अनिवार्य वस्तुओं के अभाव की समस्या रहती है क्योंकि भारत अभी तक आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में आत्मिनिर्भर नहीं बन पाया है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थों द्वारा जमाखोरी की प्रवृत्ति अपनाकर वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु सार्वजिक वितरण प्रणाली का समय—समय पर प्रयोग किया गया है। 11 क्योंकि महँगाई की अधिक मार गरीब उपभोक्ता पर पडती है, इसलिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुलभ बनाकर उनके मूल्यों पर नियन्त्रण करना अनिवार्य हो जाता है। वास्तव में सन्तोषजनक वितरण प्रणाली सरकार की मजदूरी, आय व मूल्यनीति का एक अग होती है। इसका आशय है कि मजदूरी व वेतन का निर्धारण काफी हद तक मूल्य स्तर से प्रभावित होता है।

हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना मे कृत सकल्प है जिसके लिए आवश्यक है कि प्रात्येक बस्तु का न्यायपूर्ण वितरण हो। यह भी आवश्यक है कि वितरण व्यवस्था मे लगी सम्पूर्ण इकाइयों पर पर्याप्त नियन्त्रण रखा जाय जिससे कि ये इकाइयों व्यवस्था का दुरुपयोग न कर सके। यह तभी सम्भव है जब हम वितरण व्यवस्था के सभी कार्यों का सम्पादन ठीक ढंग से करे तथा इस व्यवस्था को जन सहयोग मिलता रहे। यदि जम सहयोग न होगा तो लोगो मे जागरूकता नहीं होगी और यदि लोगो मे जागरूकता नहीं है तो कोई भी प्रणाली सफल नहीं हो सकती । इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार में वितरण के क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया जिससे कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण हो तथा वुर्बल वर्ग के उपभोक्ता का कल्याण हो सके।

111

इस प्रणाली में सरकार अपना सहयोग देती है, साथ ही साथ इसमें किसान से लेकर प्रद्योगपति तक, प्रत्येक उत्पादक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने की और फेरी

<sup>11</sup> इंग्डियन जर्नल आफ मार्केटिंग-अक्टूबर-नवम्बर, 1981, एसोसियेटेड मैनेजमेण्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली

वाले से लेकर सुपरवाइजर तक सभी वितरको को नैतिकता के आधार पर उचित वितरण की व्यवस्था करनी होती है। यदि इन उपर्युक्त वर्गों मे से कोई वर्ग अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढग से निष्पादित नहीं करता तो सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था विफल हो जाती है। इसलिए इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी का सहयोग प्राप्त होता रहे, तभी यह सफल हो सकती है।

- (द) उद्देश्य →प्रारम्भ में इसका उद्देश्य जनता को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुए केवल उपलब्ध कराना मात्र था, क्योंकि अभाव की दशा में वस्तुए उपलब्ध कराना ही महत्वपूर्ण था। वर्तमान समय में आवाश्यक वस्तुओं का अभाव तथा मूल्य वृद्धि की समस्या साथ—साथ है। ऐसी दशा में निर्वल व मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की वस्तुए प्राप्त करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करमा पड़ता है। सामान्यतया वस्तुओं की पूर्ति एव उनके मूल्य, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, किन्तु अनेक दशाओं में पर्याप्त उत्पादन के उपरान्त भी वितरण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उपभोक्ताओं को वस्तुए उपलब्ध नहीं हो पाती और यदि उपलब्ध होती भी है तो ऊँचे मूल्य पर। अत समाज के सभी वर्गों के लिए समानता के आधार पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है।
- 1 उपमोक्ताओं के कल्याण हेतु सुविधा प्रदान करना निर्धन व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि सही स्थान व उचित मूल्य पर कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समाज में धनी एव निर्धन प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता होते हैं, लेकिन भोजन की आवश्यकता सभी को हौती है। भोजन के अतिरिक्त भी व्यक्ति की कुछ और दैनिक आवश्यकताए होती हैं। इन सभी दैनिक उपभोग की वस्तुओं को समाज के कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराना जिससे वह व्यापारी वर्ग के द्वारा किये गये कृत्रिम अभावों के परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि से प्रभावित न हो। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उचित समय पर ही वस्तुए प्राप्त करागी जाय ऐसा न होकिजब किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव की जाय तो वस्तु की प्राप्ति न हो सके। वस्तु की समय से प्राप्ति के साथ ही उसे उचित किस्म का भी होना चाहिए। इस प्रकार उपभोक्ताओं के अधिकतम कल्याण की भावना से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम एव प्रादुर्भाव हुआ।
- 2 निर्धनता दूर करने का प्रमुख शस्त्र गरीबी की मान्य परिभाषा— भारतीय योजना आयोग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गाँव में 2400 कैलोरीज प्रतिदिन व शहर में 2100 कैलोरीज प्रतिदिन नहीं मिलता तो उसे गरीब माना जायेगा। भारत में आज भी कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग भोजन में अपनी दैनिक कैलोरीज को पूरा करने में असमर्थ है। विशेषज्ञ समिति के अनुसार

तो यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो मे 39 1 तथा शहरी क्षेत्रो मे 40 1 है। <sup>12</sup>ऐसे मे सार्वजितक वितरण प्रणाली इन गरीब एव असहाय उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब बाजार में वस्तु विशेष की पूर्ति कम हो जाती है तो उचित मूल्य की दुकानो पर दबाव बढ जाता है। फलस्वरूप मनुष्य की क्षुधा तृष्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की उपलब्धता इन्ही उपभोक्ता सहकारी भण्डारो एव उचित मूल्य की दुकानो द्वारा सम्भव हो पाती है।

- 3 मूल्य नियन्त्रण का प्रभावी माध्यम वैसे तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की समस्या देश में स्वतन्त्रता के बाद से ही रही है, परन्तु विगत 7-8 वर्षों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि जिस तीव्रता से हुई है, उससे देश के निम्न मध्यम एव निम्न आय वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गई है। निरन्तर अपनायी गई घाटे की अर्थव्यवस्था, चोर बाजारी मुनाफाखोरी, जमाखोरी एव उपलब्ध वस्तुओं के विषमतापूर्ण वितरण ने मूल्य वृद्धि को ऊँचा उठाने में भरपूर सहयोग दिया है। ऐसी स्थिति में नि सन्देह एक सशक्त एव देश व्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य वृद्धि पर अकुश लगाकर मूल्यों में स्थायित्व लाने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। अत सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु अपनी मौद्रिक एव राजकोषीय नीतियों के साथ-साथ यदि वितरण प्रणाली में सुधार लाए तो निश्चित रूप से यह प्रणाली मूल्य नियन्त्रण में सहायक सिद्ध हो सकती है।
- 4 उपभोक्ता सरक्षण का वैद्यानिक उपाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता सरक्षण के लिए एक सरचनात्मक आधारभूत माध्यम है, जो उपभोक्ता वस्तुओं के समुचित वितरण के लिए व्यावहारिक आधार निर्मित करती है। चूँिक उपभोक्ता सरक्षण एक सामाजिक आन्दोलन है जिसका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य के मामले में उपभोक्ता के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना है। अत सरकार ने उपभोक्ता—सरक्षण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम, बाट एव माप अधिनियम तथा उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम आदि बनाये हैं। इसी क्रम में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उचित वितरण, मूल्य नियन्त्रण तथा सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अपनी वैधानिकता को स्पष्टत सिद्ध कर चुकी है।
- 5 व्यवसायों की कुरीतियों का अन्त करना जब समाज में कृत्रिम अभाव पैदा करके, उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण करके व्यवसायी वर्ग अत्यधिक लाभ कमाने का प्रयास करने लगते हैं तो उस दशा में सार्वजिनक वितरण प्रणाली वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति बनाये रखने का प्रयास करती है। उसके इस प्रयास से मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि नहीं होने पाती जब मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती तो व्यवसायी वर्ग स्वत ऐसी व्यापारिक कुरीतियों को त्यागने के लिए विवश हो जाता है। सरकार रावजिनक वितरण प्रणाली के

<sup>12</sup> भारतीय अर्थशास्त्र-मामोनिया एव जैन, साहित्य भवन आगग-1995, गृष्ठ सम्बा ३३

माध्यम से पूर्ति को नियमित करने का प्रयास करती है दूसरी ओर व्यावसायिक कुरीतियो को समाप्त करने हेतु कठोर अधिनियम भी पारित किया जाता है।

- 6 उत्पादक -उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध सार्वजिनक वितरण प्रणाली का उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना होता है। प्रत्येक मध्यस्थ चाहे वह थोक विक्रेता, आढितया, कमीशन एजेन्ट, अथवा फुटकर विक्रेता कुछ भी हो अपनी लगायी गयी पूँजी का कुछ न कुछ अवश्य लाभ चाहता है और वह अपनी पूँजी का लाभ अपने द्वारा बेची गई वस्तु मे सिम्मिलित कर लेता है। परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ जाते है। सार्वजिनक वितरण प्रणाली इन विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों का उन्मूलन करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध कराने में सफल होती है।
- 7 <u>रोजगार के अवसर प्रदान करना</u> रोजगार के अवसर में वृद्धि करना भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि यह एक जन वितरण प्रणाली है जो लाखो व्यक्तियों के सहयोग से क्रियान्वित की जाती है। राशनिंग व्यवस्था, खरीद कार्य, वितरण व्यवस्था, भण्डारण व्यवस्था आदि कार्यों के सम्पादन में लगे व्यक्ति भारत की बेरोजगारी की समस्या में कमी करते हैं।
- 8 <u>क्स्तुओं की नियमित पूर्ति बनाये रखना</u> देश में बाढ अकाल, महामारी, भूकम्प या युद्ध की स्थिति में अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है तथा वस्तुओं का अभाव हो जाता है। ऐसी दशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति बनाये रखने के लिए न केवल विदेशों से वस्तुओं का आयात करना पडता है बल्कि उसका पर्याप्त भण्डार भी अपने यहाँ रखना पडता है। अपने देश में भी वस्तुए धूप या वर्षा में नष्ट न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाती है।
  - (य) विकास सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रमिक विकास निम्नवत् है-
- 1 प्राचीन काल में सार्वजिनक वितरण व्यवस्था वर्तमान समय में वितरण प्रणाली वितरण की एक महत्वपूर्ण विधा है, यद्यपि प्राचीन काल में इसका इतना महत्व नहीं था। पुराणों में वितरण के सन्दर्भ में स्पष्ट सकेत मिलता है। समुद्र—मथन के समय सुरों और असुरों ने मिलकर समुद्र—मथन किया था और गर्भ से जो वस्तुए प्राप्त हुई थी उनका वितरण देवताओं और दानवों के मध्य किया गया था। यद्यपि वितरण का वह स्वरूप आज के वितरण स्वरूप से भिन्न था फिर भी उस समय भी वितरण की स्थिति दृष्टिगोचर होती थी। <sup>13</sup> वस्तु वितरण व्यवस्था के लिए सार्वजिनक वितरण प्रणाली का जन्म हुआ और मानव विकास के साथ इसका क्रमिक विकास होता रहा। विकास के प्रारम्भिक चरण में मानव की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण वितरण की समस्या का कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि उत्पादक ही उस समय उपभोक्ता था। पारिवारिक व्यवस्था अपनाने के साथ—साथ मनुष्य ने कृषि कार्य करना आरम्भ किया।

<sup>13</sup> व्याख्यान-विपणन की आधुनिक विचारधारा-23 मार्च, 1987, अग्रवाल, जी सी

उस समय प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की फसल ही पैदा करता था और आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की अदला—बदली करता था। वस्तु विनिमय प्रथा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य प्रारम्भ से ही आवश्यक वस्तुओं के प्रति सचेत रहा है। पशुपालन व कृषि के बाद व्यापार-वाणिज्य उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाओं का चरणबद्ध विकास हुआ। बाद में भारतीय समाज वर्णों के आधार पर विभक्त हो गया। तृतीय समूह में आने वाले वैश्य वर्ग को पशुपालन कृषि वाणिज्य आदि कार्यों का दायित्व सौपा गया। वैदिक काल की समाप्ति के बाद नागरिक जीवन का विकास हुआ। श्रेणी समूहों ने व्यक्तिगत कार्य व्यवस्था का स्थान ग्रहण किया। वाणिज्य की उत्पत्ति नगरों के साथ हुई। सामान्य वस्तुओं का व्यापार ग्रामों एव नगरों में दुकानों या फेरीवालों के माध्यम से होता था।परिवहन साधनों की कमी के कारण वस्तुओं का वितरण एक कठिन कार्य था।

1

कौटिल्य ने वस्तुओं के क्रय-विक्रय में सदैव ही उचित मूल्यों पर बल दिया। धार्मिक उपदेशों में वस्तु के भाव में अत्यधिक वृद्धि की आलोचना की गयी। इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय में उचित मूल्य तथा उचित लाभ ने तत्कालीन शासन नीति के उददेश्यों के अन्तर्गत प्रमुख स्थान ग्रहण किया। कौटिल्य ने सरकार के वाणिज्य एव व्यवसाय-नियन्त्रण पर ही जोर दिया। वे व्यापारियों को सदैव सन्देह की दृष्टि से देखते थे। व्यापारी अनुचित लाभ कमा कर आय वृद्धि कमाने का प्रयास करते थे इसलिए बहुत सी वस्तुओं के व्यापार एव उत्पादन पर राज्य का अधिकार होता था। प्रजा को कम मूल्य पर अधिकाधिक वस्तुएं प्राप्त हो, राज्य सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील था। कौटिल्य का सुझाव था कि सभी कारखाने राजा अपनी तरफ से खोले जिसमें कारीगरों व मजदूरों को समुचित रोजगार मिल सके। यदि कोई व्यापारी बिना राजाज्ञा के किसी वस्तु का व्यापार करता था तो उसके माल को जब्त कर लिया जाता था। उस समय वितरण व्यवस्था पर पर्याप्त नियन्त्रण इसे सुव्यवस्थित करने के लिए लगाये गये थे।

इस प्रकार हमे वितरण व्यवस्था तथा राज्य द्वारा लगाये गये अकुशो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रतिविम्ब दिखायी देता है। प्राचीन काल में वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित किमयों को दूर करने के लिए कई प्रकार का नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, जैसे—वस्तु की गुणवत्ता पर नियन्त्रण, नाप—तौल पर नियन्त्रण, कमाये जाने वाले लाभ एव मूल्य पर नियन्त्रण, वस्तु की माँग एवं पूर्ति पर नियन्त्रण, जमाखोरी एव सट्टेबाजी पर नियन्त्रण, धोखाधडी एव छल—कपट पर नियन्त्रण इत्यादि इस प्रकार प्राचीन काल की वितरण व्यवस्था में भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाता था।

2 <u>मुगलकाल में सार्वजनिक वितरण-व्यवस्था</u> — देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन का प्रभाव व्यापार एव वाणिज्य पर भी पडा। सल्तनतकालीन अलाउद्दीन खिलजी की मौद्रिक एव बाजार व्यवस्था वाणिज्यक इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। मुगलकाल में व्यापारियों को राज्य

के अधिकारियो एव कर्मचारियो का भय सदैव बना रहता था इसीलिए ये व्यापारियो से मनमानी लगान वसूलते रहते थे। कभी-कभी व्यापारियो को अपना माल लागत से कम मूल्य पर बडे-बडे सूबेदारो को बेचना पड़ता था। इस समय की व्यापारिक नीति पर उचित नियन्त्रण के अभाव मे उपभोक्ता और उत्पादक एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे जिसका लाभ शासक वर्ग को मिलता था। वस्तु का उत्पादन समाज की आवश्यकतानुसार न होकर कुछ विशिष्ट व्यक्तियो की इच्छा पर निर्भर करता था। उपभोक्ता कई वर्गों मे विभक्त और असगठित था। उस समय व्यक्तियो की आवश्यकताए सीमित थी तथा वस्तुए सस्ती भी थीं और आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध भी हो जाया करती थी इसलिए वस्तुओ के अभाव का अनुभव नहीं होता था।

3 औपनिवेशिक काल में सार्वजिनक वितरण व्यवस्था — इस काल में भारतीय लोगो की स्थिति अग्रेजो की दमन एव शोषण की नीति के कारण बड़ी दयनीय थी। प्राकृतिक प्रकोपो से सुरक्षा का प्रबन्ध न किये जाने के कारण उन्हें खाद्यान्नों के लिए तरसना पड़ता था। वस्तुओं के उत्पादन एव वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आवश्यक वस्तुओं का सर्वथा अभाव रहता था। 1770 में बगाल के भयकर अकाल के कारण वस्तुओं के मूल्यों में इतनी वृद्धि हो गयी कि जनता को आवश्यक वस्तुए खरीदने में भी बहुत किठनाई हुई। फिर भी ब्रिटिश सरकार अपने लाभ के लिए उत्पादन एव वितरण की नीति को तय कर रही थी और उसे भारतीय लोगों के हित की चिन्ता नहीं रहती थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण वस्तुओं के मूल्य एव पूर्ति की समस्या से निबटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। 1929—30 की आर्थिक मन्दी का प्रभाव द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तक रहा। धीरे-धीरे प्राकृतिक कमी एव उपभोक्ता की मनोवृत्ति के कारण वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने लगी। उत्पादक और व्यवसायी वर्ग आवश्यक चस्तुओं की पूर्ति को जमा करके वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने में सहयोग करने लगे। मूल्यों में वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और निर्धन लोगों पर पड़ रहा था, वे भूखों मरने लगे।

भारतीय इतिहास में 1943 के बगाल अकाल में पहली बार सरकार ने खाद्यान्नों के मूल्य को नियन्त्रित करने का प्रयास किया परन्तु अकाल के कारण प्रयास में सफलता न मिल सकी। इसके बाद सरकार ने खाद्यान्नों के व्यापार में हस्तक्षेप न करके केवल निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का फैसला किया। जब जापान ने युद्ध घोषित किया तो उस समय बगाल सरकार खाद्य सामग्री की मात्रा बढाने में लगी थी। सरकार ने घोषणा की कि आम जनता अपने—अपने घरों में दो महीने की खाद्य सामग्री सुरक्षित रखे। सरकार की इस घोषणा के परिणामस्वरूप लोग छ –छ महीने की खाद्य सामग्री अपने यहाँ सुरक्षित रखने लगे। फलस्वरूप सरकार की मूल्य एवं पूर्ति योजना पूर्णत विफल हो गयी। सरकार के स्थान पर आम जनता स्वय खाद्य समस्या के निवारण हेतु प्रयास करने लगी। यह एक

ऐसी दुखद स्थिति थी जिसका आमन्त्रण सरकार ने स्वय दिया था। इस प्रकार वितरण व्यवस्था पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गयी।

बगाल की जनता को खाद्यान्न की पुन आपूर्ति हेतु सरकार ने 'डेनियल नीति' लागू की। इसके अन्तर्गत गेहूँ के वैधानिक मूल्य की घोषणा की गई। गेहूँ उत्पादक राज्यों से बडी मात्रा में गेहूँ क्रय करके जमा किया गया। इसका परिणाम गेहूँ के सामान्य अभाव के रूप में सामने आया। चौथे मूल्य नियन्त्रण सम्मेलन में पजाब सरकार के प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मूल्य नियन्त्रक न रहे तो खाद्यान्नों के आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। उस समय के मूल्य नियन्त्रण योजना को परिणाम खाद्यान्नों का पूर्ति के बाहर हो जाना रहा। बगाल सरकार ने उसी गलती की पुनरावृत्ति करते हुए जून 1942 में चावल के वैधानिक मूल्य की घोषणा की। 9 जुलाई 1942 से प्रभावी इस आदेश में चावल का अधिकतम मूल्य घोषित किया गया। घोषित मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम होने तथा उसमें लोचहीनता के कारण सरकार पुन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पायी। 'डेनियल नीति' लागू करने से सरकार अपने उद्देश्यों में सफल हुई। जब व्यापारी वर्ग जमाखोरी की प्रवृत्ति अपनाकर अपने मूल्यों को बढाने लगते थे तो सरकार अपने द्वारा रखे गये स्टाक से खाद्यान्न की आपूर्ति बाजार में बढा देती थी और पुन मूल्य अपने स्थान पर आ जाता था। सरकार ने 1942 में ही एक ऐसी खरीद एजेन्सी स्थापित करने का विचार व्यक्त किया जो आधिक्य की मात्रा में उत्पादित फसलों का क्रय करके उसका वितरण शहरी क्षेत्रों में करती। परन्तु इस विचार को कार्यरूप प्रदान करने में इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि उस समय खाद्यान्नों के अभाव की समस्या में कुछ कमी आ गई थी।

जब पुन जमाखोर व्यापारियों ने खरीद-दारी प्रारम्भ की, पूर्ति अव्यवस्थित हुई तथा मूल्यों में वृद्धि होने लगी तो सर्वप्रथमः। राजशाही मण्डल में 22 दिसम्बर, 1942 से खरीद कार्य प्रारम्भ हुआ। प्रथम लक्ष्य 7 4 टन खाद्यान्न की खरीद का रखा गया। प्रत्येक जिले के जिला— अधिकारी द्वारा खरीद कार्य निर्धारित किया गया। परन्तु अधिकारियों द्वारा धीमी खरीद के कारण इस योजना को समाप्त करना पड़ा। सरकार ने इस समय सारा नियन्त्रण वापस ले लिया। उसने पूर्ति व्यवस्था को सही रखने के लिए विज्ञाप्ति जारी की कि 'धान एव चावल के सम्बन्ध में कोई वैधानिक मूल्य नहीं होगा।' सरकार ने समझा कि लोगों के द्वारा असामान्य लाभ कमाना ही मूल्य नियन्त्रण की किमयों है।

दूसरे विश्वयुद्ध की शुरुआत से ही आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान गया। भारत सरकार ने सर्वप्रथम—1939 में बम्बई में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य पुरुष वृकान की स्थापना की। भारत में 1943 के बगाल अकाल से उत्पन्न खाद्य समस्या का निराकरण

न हो सकने के कारण सरकार खाद्यान्नों के मूल्य को नियन्त्रित न कर पायी। पुन मूल्य वृद्धि आरम्भ हो गयी। इस समस्या के समाधान हेतु प्रथम खाद्य नीति समिति की घोषणा की गयी और, प्रथम मूल्य नियन्त्रण सम्मेलन 1943 में की गयी सिफारिशों के आधार पर ही खाद्यान्न के वितरण हेतु सर्वप्रथम 1944 में केन्द्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों द्वारा केवल गेहूँ और चावल के लिए राशनिंग व्यवस्था आरम्भ की गई।

ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में अस्थायी रूप से सार्वजिनक वितरण व्यवस्था को अपनाया। इस सम्बन्ध में भारत में भी ब्रिटिश शासन ने खाद्यान्न के अभाव की दशा में उसके उत्पादन, वितरण एवं व्यापार में हस्तक्षेप की स्पष्ट नीति को स्वीकार किया। यहाँ अगस्त— 1947 में 5 4 करोड लोग स्थायी रूप से ग्रामिन व्यवस्था के अन्तर्गत थे तथा 9 करोड लोग सार्वजिनक वितरण व्यवस्था के अन्य रूपों में शामिल थे। बाढ, अकाल, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकीपों से निपटने के लिए सार्वजिनक वितरण व्यवस्था का सहार्ग, राशिनिंग के रूप में, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भी लिया जाता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हीने के ठीक बाद ही भारतीय रक्षा अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत सरकार ने मूल्यों को नियन्त्रित करने तथा वितरण को नियमित करने का प्रयास शुरू कर दिया। अधिक अन्त उपजाओ' आन्दोलन—1941 से ही चल चुंका था। सरकार किसी भी दशा में सभी लोगों को, किसी भी मूल्य पर आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए कृत सकल्प थी। सरकार अपनी कर से होने वाली आय को बढाने की भी इच्छुक थी जो व्यापारियों द्वारा अधिक लाभ कमाये जाने की दशा में ही सम्भव था। इस प्रकार सरकार व्यापारियों तथा उपभौक्ताओं दोनों के हितों में सामजस्य स्थापित करना चाहती थी।

संभी विकासशील देशों का आर्थिक अनुभव इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि मूल्यों में स्थिरता तथा उसमें वृद्धि का एक निर्धारित क्रम उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। सोवियत सघ का टूट कर विखरना तथा रूस जैसे समृद्ध राज्य में आर्थिक ज्वार—भाटे का आना इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारत में आवश्यकताओं को वेखते हुए एक विवेकपूर्ण एव नियन्त्रित कृषि मूल्य नीति का होना अपरिहार्य हो गया जिसमें कृषि उपजो का मूल्य निर्धारित कर कृषि उत्पाद एव बाजार मूल्य में समन्वय स्थापित किया जा सके प्रमाण ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों में पूर्ति को सन्तुलित किया जा सके। यहाँ उपभोक्ता के हित में खाद्य सामग्री के मूल्यों को निश्चित करना, उसी तरह आवश्यक हो गया जिस तरह कृषकों के लिए कृषि उपजो के न्यूनंतम मूल्य का निर्धारण।

4 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली — स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में विकास की नियोजित नीति को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा प्रसार बढा और खाद्य सामग्री की कीमते भी आसमान छूने लगी। जुलाई 1948 में पुन नियन्त्रित प्रणाली अपनायी गयी जिससे

खाद्य सामग्री के मूल्य कुछ समय के लिए स्थिर हो गये थे परन्तु मूल्यों में स्थायित्व अधिक समय तक न रहा। वर्ष 1949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन तथा 1950 में कोरिया—युद्ध के कारण खाद्य—सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हुई। इस प्रकार खाद्यान्नों के मूल्य में और आगे वृद्धि के मुख्य कारक—1951 की प्राकृतिक आपदा, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, कोरिया—युद्ध तथा भविष्य में अकाल पड़ने की आशकाए रहीं। स्वृतम्त्रता से पूर्व केवल युद्धकाल को छोड़ कर न तो कभी कोई मूल्य नीति तय की गई और न ही किसी वस्तु पर नियन्त्रण लगाया गया।द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व राशनिग व्यवस्था की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् खाद्य सामग्री खरीद समिति–1950 के अधीन 'खाद्य नीति' को अपनायां गया जिसमे एकाधिकारी खरीद एवं राशनिंग व्यवस्था पर बल दिया गया। यह व्यवस्था खीद्यान्नों की उचित पूर्ति बनाये रखने के लिए की गयी थी। प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादम में पर्याप्त वृद्धि हुई, फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण के सम्बन्ध में जो भी सम्भव था, किया गया। वर्ष 1955–56 में आवश्यक वस्तुओं की कमी पुन अनुभव की गई जिससे मूल्यों में पुन वृद्धि होने लगी। समस्या के निराकरण हेतु सरकार ने 1957 में मूल्यों में हुई वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए एक खाद्य समिति का गठन श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया।उत्पादन बढ़ने के बावजूद मूल्यों में वृद्धि होने के कारणों तथा असामयिक रूप से जमाखोरी बढ़ जाने के कारणों का पता लगाना भी समिति के प्रमुख कार्यों में शामिल था। समिति ने सुझाव दिया कि यदि सरकार मूल्यों में स्थायित्व लाना चाहती है तो उसे व्यापार पर पूर्ण सामाजिक नियन्त्रण करना होगा। थोक व्यापारी के मूल्य बढ़ाने पर फुटकर व्यापारी भी मूल्य बढ़ाने के लिए बाध्य होता है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि खाद्य सामग्री का बजट बनाकर इसका पर्याप्त स्टाक रखना भी खाद्यान्तों के मूल्यों के स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सरकार ने समिति के सुझावों के अनुपालन में गेहूँ एव चावल के पर्याप्त स्टाक बनाने के लिए अमेरिका से पी एल 480 समझौता आयात हेतु किया। इस प्रकार सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद खाद्यान्तों के वितरण में मुख्यतया निम्न कारणों से हस्तक्षेप शुरू किया–

- -- भारत की एक तिहाई आबादी का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना,
- -- आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होना,
- -- प्राकृतिक आपदा से उत्पादन कुप्रभावित होना,
- -- भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भर होना,
- -- कृषि उत्पादन मे क्षेत्रीय विषमता का विद्यमान होना,
- भारतीय कृषि की उत्पादकता मे कमी होना,

- -- व्यापारियों का अनैतिक व्यापारिक क्रियाओं में लिप्त होना और,
- - खाद्यान्नो की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करना ।

स्नतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने खाद्यान्नों के नियमित पूर्ति को बनाए रखने तथा उपभोवताओं के सरक्षण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित मूल्य की दुकानों एव राशनिंग के द्वारा अपनाया। जिसके तहत् राज्यों में खाद्यान्न हस्तान्तरण को सुगम बनाते हुए खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद एवं भण्डारण की व्यवस्था की गयी।

(र) वर्तमान स्थित न्वर्ष 1957-58 में अमेरिका से पी एल 480 के अन्तर्गत आयातित गेहूँ एवं चावल का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया गया। 1962 के भारत-चीन युद्ध एवं 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकाने और उपभीवता सहकारी भण्डार भी केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बहुत तेजी से खोले गये तािक युद्ध जनित प्रभावों को दूर करके आवश्यक वस्तुओं की नियमित पूर्ति बनाये रखी जा सके। इसी बीच 1965 में मुख्य मिन्त्रियों के सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि खाद्य सामग्री का अभाव अभी थोड़े समय तक और मामा रहेगा, और इस अभाव की पूर्ति हमारा उत्पादन नहीं कर पायेगा क्योंकि उत्पादन कम था एव प्राकृतिक आपदाए अधिक। सरकार ने इस सम्बन्ध में विवेकपूर्ण कार्य करते हुए इस सम्मेलन में दो तथ्यों पर बल दिया-

प्रथम— उपभोक्ताओं का अधिकतम कल्याण — उपभोक्ताओं के कष्ट को कम करने के लिए उनकों सभी आवश्यक वस्तुए एक निश्चित समय एवं स्थान पर उचित मूल्यों में उपलब्ध कराना चाहिए। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए तथा उसकी सन्तुष्टि को अधिकतम करने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए।

ब्रितीय-मूल्यों में समरूपता लाना — सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि सारे देश में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में एकरूपता लायी जाय। सरकार द्वारा उन विशिष्ट वस्तुओं को बिशिष्ट मूल्य पर सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से उपलब्ध करायी जाय, जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं का शौषण किये जाने की सम्भावना हो।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1965 में एक जॉंच सिमित सार्वजिनक वितरण की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नियुक्त की। हमारे देश में किसी वर्ष खाद्यान्न की प्रचुरता रहती है तो किसी वर्ष कमी। यह क्रम चक्रीय रूप में चलता रहता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ऐसी प्रणाली अपनायी जाय जिसमें हम मानसून की दशाओं पर निर्भर न रहकर अपने आप में निर्भर हो जाय। अत यह आवश्यक था कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य नीति में खार्यान्नों का पर्याप्त बफर स्टाक और खरीददारी हो। इसी

उददश्य स को लेकर जनवरी 1965 में 'भारतीय खाद्य निगम' की स्थापना की गई जिसे अनाज की खरीद सग्रह, परिवहन एव समुचित वितरण व्यवस्था का कार्य सौपा गया। उपभोक्ता को सीधे खाद्यान्न प्रदान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण कराया जानं लगा। वर्ष 1967-68 में उचित मूल्य की दुकान योजना का नाम बदल कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया। समय के विकास क्रम के साथ खाद्यान्नों का उत्पादन एवं जनसंख्या दानों में वृद्धि होती रही परिणामस्वरूप वितरण व्यवस्था को और व्यापक एवं चुस्त करना आवश्यक हो गया। प्रत्येक वर्ष बफर स्टाक की मात्रा बढ़ती ही जानी चाहिए, तभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख उददेश्यों -सही समय पर, सही मूल्य में एवं सही किस्म की वस्तुए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में सफल हो सकते हैं। देश में सम्पूर्ण उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक सा हो गया कि उचित मूल्य के दुकानों की सख्या में वृद्धि की जाय। तालिका सख्या-4 में भारत में उचित मूल्य के दुकानों की सख्या में क्रमबद्ध वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है-

तालिका सख्या -4 भारत मे उचित मूल्य की दुकाने

वर्ष(31 मार्च )	कुल सख्या	अच्छादित जनसंख्या (करोड मे)
1957	37,591	_
1971	1,21,032	29 94
1972	1,65,081	41 17
1973	2,00,655	43 53
1974	2,21,724	44 14
1975	2 40,210	46 94
1976	2,36,196	56 59
1977	2,38,622	58 91
1978	2 41,255	60 14
1983	2 97,000	65 60
1984	3,02,000	67 3
1985	2,83,646	-
1989	3 54लाख	<del>-</del>
1990	3 61 "	
1991	3 99 "	
1992	4 12 " (अनुमानित)	73 0
5 दिस0 1994(नयीनीकृत सार्	वे प्र ) 14,008	16 0

मृति 1 योजना तथा भारत 1991-93, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 2 नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली, 4 फरवरी 1995

तालिका सख्या 4 से स्पष्ट हे कि 1957 में इस योजना के अन्तर्गत केवल 37 591 । वुकाने ही थी जो 1971 में बढकर 1 लाख 21 हजार से अधिक हो गयी जिसमे 29 94 करोड व्यक्तियो को अपने कार्यक्षेत्र मे शामिल किया। 26 जून, 1975 को देश की तत्कालीन स्व प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने देश मे आपात् काल की घोषणा कर दी और इसी घोषणा के साथ ही साथ 20सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घीषणा भी की जिसके परिणामस्वरूप इसके विकास मे आश्चर्यजनक तेजी आयी। इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अग समस्त उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानो पर वस्तूए उपलब्ध कराना भी था। इस प्रकार 1978 में इनकी संख्या बढकर 2,41,255 हो गई जो 60 14 करोड जनसंख्या को आच्छादित करती थी। 1965 से 75 के बीच दुकानो की सख्या दो गुनी से अधिक बढी परन्तु 1965 मे प्रति लाख जनसंख्या पर 23 दुकाने थी तथा 1975 में 39 दुकाने। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति लाख जनसंख्या पर दुकानो की उपलब्धता को उस अनुपात में नहीं बढाया जा सका। देश में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या में वृद्धि के बाद भी वितरण कार्य में कमी आयी। 1965 में इन दुकानों के माध्यम से औसत रूप में लगभग 92 लाख दन खाद्यान्न का वितरण हो रहा था जो 1975 में घटकर 48 लाख टन रह गया यद्यपि 1983 मे पुन थोडी बढकर 62 लाख टन हो गया। वर्तमान समय मे उचित मूल्य की 4 लाख से अधिक दुकाने देश की लगभग तीन-चौथाई जनता को अपनी सेवाए प्रदान कर रहीं है। 1 जनवरी 1992 से घोषित नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत10,580 अतिरिक्त दुकाने खोलमें के लक्ष्य के बदले 15 दिसम्बर, 1994 तक 14008 उचित मूल्य की दुकाने खोली गयी जिनसे लगभ्ग 16 करोड अतिरिक्त लोगो को इसका लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

सार्वजिमक वितरण प्रणाली द्वारा जनकल्याण मे वृद्धि हेतु किये गये योगदान एव उनका व्यवस्थापन निन्नवत् है-

1 जनता दुकानें — भारत सरकार ने 1977-78 में समाज के निर्बल वर्ग को आवश्यक वस्सूएं उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से जनता दुकाने सचालित करने की एक विशेष योजना प्रसारित की। तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मत्री श्री मोहन धारिया ने जनता दुकानों के क्रिया-कलापों को बताते हुए जून-1979 में 1000 जनता दुकानों को मिलन बस्तियों में स्थापित करने का निर्णय लिया। इन जनता दुकानों के प्रमुख उद्वेश्य निम्न थे-

🛪 जनता दुकाने गदी एव मलिन बस्तियो मे खोली जायेगी जो गरीब लोगो को उनकी

आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

- \* सरकार शिक्षित बेरोजगार नवयुवको को इस योजना को चलाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सके।
- \* सुपर बाजारो की तरह ये दुकाने ग्रामीण व अर्द्ध विकसित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकार की सहायता करेगी।
- \* योजनान्तर्गत प्रत्येक व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले व्यक्ति को 2000रु० की प्रारम्भिक पूँजी अमुदान के रूप मे दी जायेगी जिससे कि उनको इन दुकानो को चलाने मे कोई कठिनाई न हो।
- 2 सार्वजनिक उत्पादन एव वितरण योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे आवश्यक यस्तुओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने मार्च, 1978 मे प्रस्ताव किया कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रणाली का और विस्तार एव सुदृढीकरण किया जाय। जनवरी 1979 मे आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन मे इस योजना का सर्वसम्मित से स्वागत किया गया और इस पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। योजना को अन्तिम रूप देने तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए राज्यों और केन्द्र भासित प्रवेशों के नागरिक एवं आपूर्ति मन्त्रियों ने विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त 1 जुलाई 1979 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उत्पादन व वितरण योजना इस विश्वास के साथ लागू की गयी कि देश भर के उपभोक्ताओं विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर स्थायी रूप से उपलब्ध होती रहे। इसे स्थायी एव व्यापक रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सार्वजिनक उत्पादन व वितरण योजना आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन व वितरण की समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु आरम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वसूली, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की प्रक्रिया भी सिम्मिलित थी। इस योजना के द्वारा व्यापार के आधार पर उत्पादन व वितरण से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया गया। योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य एव आपूर्ति मन्त्रालय के साथ-साथ कृषि, उद्योग, रेलवे, इस्पात व खान मन्त्रालय से सहयोग प्रदान कर नी गयी थी।

उद्देश्य — उत्पादन व वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाये रखना, व्यापारियों की कुरीतियों को समाप्त करना, उत्पादित वस्तुओं की वसूली, परिवहन तथा वितरण में समम्बंग स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुए उपलब्ध कराना, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण कराना और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना था। इस प्रकार यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संशोधित एवं परिमार्जित रूप में थी। इसका विशेष ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उचित मूल्य

की दुकाने खोलकर कमजोर वर्ग के लोगो को वस्तुए उपलब्ध कराने की ओर लगा था।

<u>प्रमुख तत्व</u> उत्पादन व वितरण योजना के तहत् सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त एवं प्रभावपूर्ण बनाने एव इसको सफलता पूर्वक लागू करने के लिए निम्न व्यवस्थाए की गयी-

- 1 योजनान्तर्गत आच्छादित जनसख्या की दृष्टि से प्रत्येक 2000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गाव या गावो के समूह के लिए एक उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की योजना बनायी गई, किन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर ही एक दुकान खोली जा सकेगी। इस हिसाब से 3 5 लाख उचित मूल्य दुकानों की आवश्यकता होगी। योजना के प्रारम्भ में देश में 2 4 लाख दुकाने निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में कार्यरत् थी, जिनकी संख्या 1981 में बढकर 2 9 लाख हो गयी।
- 2 इस योजना की शुरुआत 13 वस्तुओ- गेहूँ, चावल, मोटा अनाज, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कपड़ा माचिस, नहाने व धोने का साबुन, चाय, कॉफी और विद्यार्थियों के लिए कापियों से की गयी। अन्य वस्तुओं को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भी शामिल किया जा सकता था। वस्तुओं की संख्या राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है, परन्तु सभी वस्तुए देश भर में एक ही मुल्य पर बैची जायेगी।
- 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- 4 वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिए चयनित वस्तुओं की वसूली और उसका पर्माप्त भड़ारण आवश्यक है। इसके लिए राज्यों में भण्डारण एव वितरण केन्द्र बनाने की व्यवस्था है। मूल्य स्थिर बनायें रिखनें के लिए बफर स्टाक के अतिरिक्त जहाँ जरूरी हो, एजेन्सियों के द्वारा आयात भी किये जा सकते हैं।
  - 5 सार्वजिनक वितरण प्रणाली में निजी, सार्वजिनक व सहकारी क्षेत्र सिम्मिलित है।
- 6 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व वितरण में लोगों का सिक्रिय सहयोग प्राप्त करने हैंतु उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।
- 7 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि तथा उत्पादन पर निरन्तर नियन्त्रण बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को सचार व्यवस्था बनाये रखना अत्यन्त ही आवश्यक है जिससे कि समय रहते सुधीरात्मक कार्यवाही की जा सके।
- 8 वितरण प्रणाली के निरीक्षणः व समायोजन के लिए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उच्च अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित की जायेगी।
- 9 योजनान्तर्गत शामिल वस्तुओं को स्थानीय आधार पर उत्पादित कराये जाने का प्रावधान किया गंगा। वितरण के लिए अन्य वस्तुएं केन्द्र सरकार के सहयोग से लेवी के रूप में वसूली जायेगी।

- 10 उचित मूल्य की दुकानों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी किन्तु सार्वजनिक वितरण के लिए वस्तुओं के भण्डारण हेतु धन सुलभ कराया जायेगा। युवा बेरोजगार व्यवसायी को दुकान खौलने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 11 दुकानों के सुचारू संचालन के लिए स्थानीय आधार पर राशनकार्ड धारकों को चौकसी समितियाँ बनाने की व्यवस्था की गयी।
- 12 राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण इन दुकानों के माध्यम से करायेगी। राज्य सरकारे वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए संचलं दुकानों की भी व्यवस्था कर सकती है।

अगस्त-1986 मे पूर्व प्रधानमत्री स्व0 श्री राजीव गाँधी द्वारा पुनर्सशोधित 20सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोक्ता सरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, कारगर एव प्रभावी बनाने का सकल्प लिया गया।

3 सगठन, प्रबन्ध एव वितरण व्यवस्था — वर्तमान समय मे 4 लाख से अधिक दुकानो के माध्यम से प्रति वर्ष 180 लाख टन खाद्यान्न 43 लाख टन लेवी चीनी एव 83 लाख टन मिट्टी का तेल वितरित करमे वाली कवाचित् विश्व की सबसे बंडी वितरण प्रणाली हैं। 14 यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली छठवे वशक से शासकीय नीति का एक महत्वपूर्ण अग बनी हुई है जिसमे मुद्रा स्फीति मे वृद्धि एव उसके प्रभाव की कम करने का प्रयास किया जाता रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सगठन एव प्रबन्ध मे केन्द्र एव राज्य वोनो सरकारों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनाजो की खरीद, कभी की स्थित मे विदेशों से आयात, मूल्य निर्धारण और विभिन्न राज्यों और सधीय राज्यों का हिस्सा तय किया जाता है, जबिक राज्यों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सचालन सम्बन्धित राज्य सरकार का विधिन्न हैं। इस प्रकार इस प्रणाली को सफल बनाने की केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सयुक्त जिम्मेंदारी हैं। इस प्रणाली के काम—काज की नियमित समीक्षा की जाती है, और राज्य सरकारों से विचार—विमर्श के बाद सुधारात्मक उपयों को लागू किया जाता है। केन्द्र मे इस प्रणाली की समीक्षा एक संलोहकार परिषद समय—समय पर करती है। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता सलाहकार सिमितियाँ णिला, ब्लाक और तालुका स्तर पर उचित दर दुकानों के काम—काज को देखती है।

खाद्य तेल के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा मिट्टी के तेल के लिए पेट्रोलियम उद्योग के सरकारी-सगठन खरीद, भण्डारण एव आपूर्ति की व्यवस्था करते है। महीने के प्रारम्भ मे प्रत्येक राज्य में आपूर्ति द्वारा वस्तुओं को प्रदाय केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है तािक जिलाधीश द्वारा अनुमोदन प्राप्त दुकानीं में राश्चन कार्ड के माध्यम से उपभोकताओं को वस्तुए वितरित कर सके। केन्द्र सरकार ने 14 नवभारत ट्राइम्स- नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1995

सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 6 महत्वपूर्ण क्स्तुओ की आपूर्ति का दायित्व लिया है ये है— गेहूँ चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिटटी का तेल एव कोयला। कुछ राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कुछ अन्य क्स्तुओ यथा— साबुन, नमक, चाय दाले, कापियों के वितरण की व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत की है। जैसे पिचिमी बगाल और तमिलनाडु राज्य ने उचित दर की दुकानों में नमक चाय, कॉफी, माचिस, दाल नहाने का साबुन कापियों, साइकिल के टायर— ट्यूब आदि भी शामिल किये गेये है।

विगत 10 वर्षों में उचित मूल्य के दुकानों की सख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मार्च 1984 में जहाँ इनकी संख्या केवल 3 2 लाख थी पाँच वर्षबाद मार्च-89 में बढ़ कर 3 54लाख और वर्तमान समय में लगभग सवा 4 लाख हो चुकी है। 31 मार्च, 1991 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल दुकानों की स्थिति निम्न तालिका में दिखायी गई है-

तालिका सख्या 5 उचित मूल्य दुकानो के वितरण की स्थिति

(31 मार्च, 1991)

विवरण	ग्रामीण क्षेत्र	। । शहरी क्षेत्र	योग
सहकारी क्षेत्र मे ।	68,053	21,621	89,674
अस्य क्षेत्र मे	2,37,446	72,618	3,10,064
युलं विक्रय केन्द्र	3,05,499	94,239	3,99,738

स्रोत प्रतियोगिता वर्पण अक्टूबर-1993, उपकार प्रकाशन, बीमानगर, आगरा-2, पृष्ठ सख्या-345

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग 76 प्रतिशत दुकाने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। कुल दुकानी में 22 43 प्रतिशत दुकाने सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित है। अलग-थलग पडे दुर्गम इलाको, विशेषरूप से जन जोतीय इलाको में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने राज्यो/केन्द्र भ्रांसित प्रवैशों को वाहन खरीवने के लिए 596 लाख रुपये वर्ष 1992-93 में स्वीकृत किये गये है। जबकि वर्ष 1989-90 एव 90-91 में यह धनराशि क्रमश 245 6 लाख, तथा 144 5 लाख रुपये ही थी। 16

खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण वर्ष भर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव जारी रहता है। वर्ष 1989 में जनवरी से नवम्बर तक सार्वजनिक वितरण

<sup>15</sup> नवभारत टाइम्स- नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1994, पृष्ठ सख्या-7

<sup>16.</sup> भारत-संम्बन्धित वर्ष, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई विक्ली,

प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, पौष्टिक आहार कार्यक्रम आदि के मीध्यम से 75 88 लाख टन चावल, 80 04 लाख टन गेहूँ आवण्टित किया गया। इससे पहले इसी अविध मे 86 05लाख टन चावल तथा 84 38 लाख टन गेहूँ इन कार्यक्रमों के तहत् आवण्टित किया गया था। इस प्रकार गेहूँ एव चावल का आवण्टन वर्ष 1988 की तुलना मे कम किया जा सका। वर्ष 1990-91 में गेहूँ एवं चावल का कुल आवण्टन(सार्वजिनक वितरण प्रणाली तथा पौष्टिकता कार्यक्रम आदि हेतु) क्रमश 95 96और 97 94 लाख टन था जबिक उससे पिछले वर्ष यह आवण्टन मात्र 85 26 और 95 47 लाख टन था। वर्ष 1991-92 में गेहूँ और चावल का कुल आवण्टन क्रमश 105 70 तथा 114 23 लाख टन रहा। केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजिनक वितरण हेतु गेहूँ, चावल एव खाद्य तेल की आवण्टित मात्रा निम्न सालिका में अकित की गयी है-

तालिका संख्या 6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आविण्टत मात्रा (लाख टनो में)

वस्तुए	वर्ष 1989-90	वर्ष 1990-91	वर्ष 1991-92
गैहूँ	85 26	95 96	105 70
चायल	95 47	97 99	114 23
खाद्य तेल	3 91	6 52	1 20

मोतं भारत-सम्बन्धित वर्ष, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति खण्ड, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, मई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गेहूँ के आवण्टन मे पिछले वर्ष की तुलना मे वर्ष 1990-91 में 12 5 प्रतिशत तथा 1991-92 मे 10 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबिक चावल की आविण्टत मात्रा मे अधिक उच्चावचित वृद्धि होती है। चावल के आवण्टन मे 2 64 प्रतिशत वृद्धि वर्ष 1990-91 में तथा 16 57 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 1991-92 मे हुई है।

खाद्य तेलों की आपूर्ति में कमी को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्ष 1989 मैं जनवरी से नवम्बर की अवधि के लिए खाद्य तेलों का आयात घटाकर 3 65 लाख टन किया गया जबकि वर्ष 1988 में इसी अवधि में 9 79 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था। ये कमी 62 6 प्रतिशत की रही। मूँगफली के तेलों में मूल्य वृद्धि के कारण 1 लाखटन पामोलीन का आयात करना पड़ा जिसमें अधिकांश मात्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा गया। गुजरात में वर्ष देर से हों के कारण देशी खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी आने और इनकी बढ़ती हुई माँग को देखते हुए वर्ष

1990 के दौरान 6 5 लाख टन आयातित खाद्य तेल आविण्टत किये गये जबिक 1989 में इसी अविध के लिए 3 91 लाख टन खाद्य तेल आविण्टत किया गया। इस प्रकार इसमें 66 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रवेशों द्वारा आवण्टन से उठाया गया हिस्सा 5 21 लाख टन रहा जबिक पिछले वर्ष 1989 के दौरान 3 27 लाख टन ही था। विवेशी मुद्रा की समस्या के कारण वर्ष 1991 में ज्यादा खाद्य तेलों को आयात नहीं किया जा सका। इसीलिए आवण्टन में भी कमी की गई। 1990 में जहाँ 6 52 लाख टन आयोजित खाद्य तेल आविण्टत किया गया था वहीं 1991 में मात्र 1 20 लाख टन खाद्य तेल ही आविण्टत किया जा सका। इस प्रकार खाद्य तेलों के आवण्टन में आलोच्य वर्षी में पर्याप्त उच्चावचन रहा।वर्ष 1990-91 का आवण्टन पूर्व वर्ष की तुलना में 66 75 प्रतिशत बढ़ गया जांबिक अगले ही वर्ष में इसमें 81 59 प्रतिशत की कमी आ गयी।

4 <u>नवीनीकृत सार्वजिनक वितरण प्रणाली</u> — सार्वजिनक वितरण प्रणाली का लाभ दूरदराज के गावों, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्र मे रहने वाले गरीबो तक पहुँचाने के लिए वर्ष 1992 में एक नयी प्रोजना भ्रांक की गयी जिसेनवीनीकृत सार्वजिनक वितरण प्रणाली(रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) का नाम दिया गया है। इस नयी सार्वजिनक वितरण प्रणाली की शुरूआत प्रधानमत्री पी वी नरसिंह राव ने 1 जनवरी, 1992 को राजस्थान के अभावग्रस्त रेगिस्तानी जिले बाडमेर से की। इस व्यवस्था का उद्देश्य देश के सुदूर क्षेत्र के गांवो में रहने वाली गरीब जनता को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावकारी बनाना है।

मयी सार्वजिनक वितरण प्रणाली देश के 1775 विकास खण्डों के लिए शुरू की गयी है। शुरूआत के समय 1700 खण्डों को चुना गया था, बाद मे यह सख्या बढ़ाकर 1775 कर दी गयी। जिन विकास खण्डों की इस व्यवस्था के अन्तर्गत पहचान की गयी है वे जनजाति बहुल राज्यों व पर्वतीय क्षेत्रों में है और जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम(डी पी ए पी ) समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम(आई टी डी पी ) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम(डी डी पी ) चल रहे हैं। इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है।

नयी सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देश की आबादी के पाचवे हिस्से, लगभग 16 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके तहत् 10580 अतिरिक्त उचित दर की दुकाने खोलने का लक्ष्य निर्मारित किया गया था। इस लक्ष्य के मुकाबले, 15 दिसम्बर, 1994 तक 14008 उचित मूल्य की दुकाने खोली जो चुकी थी। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित 2675898 नये राशनकार्ड के लक्ष्य के मुकाबले, 3523,737 नये राशन कार्ड बनाये जा चुके है। गरीबी के लिए बनायी गयी इस योजना का अपात्र व्यक्ति अनुचित लाभ न उठाने लगे, इसके लिए राशन कार्डों की भारी पैमान पर छानबीन की गई।

नवीनीकृत सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अनतर्गत 1 जनवरी 1992 के बाद खोली गई उचित दर की दुंकानो की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार सूची निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है-

तालिका संख्या 7
नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न राज्यो/केन्द्र शासित प्रदेशों में खोली गयी दुकाने
(15 दिसम्बर, 1994)

क्र स	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दुकामे	क्र स	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	दुकाने
1	महाराष्ट्र	3395	15	मिजोरम	99
2.	विद्यार	2469	16	मणिपुर	74
3	मध्य प्रदेश	1276	17	प0 बगाल	69
4	<b>कर्नाट</b> क	1155	18	केरल	51
5	उत्तर प्रदेश	1141	19	त्रिपुरा	32
6	उड़ीसा	1138	20	नागालैण्ड	24
7	राजस्थान	1079	21	तमिलनाडु	19
8	हरियाणा	432	22	अण्डमान निकोवार द्वी स	18
9	असम	385	23	दादर एव नगर हवेली	11
10	आन्ध्र प्रवेश	362	24	हिमाचल प्रदेश	8
11	गुजरात	276	25	सिक्किम	2
12	असणाचल प्रवेश	263	26	लक्षद्वीप	2
13	जेम्मू कश्मीर	123	27	दीव	1
14	मेघालय	104		महायोग	14,008

मोतं नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1995

उपर्युक्त अवरोही क्रम मे प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र राज्य मे सर्वाधिक 24.2 प्रतिषात नयी दुकाने खोली गयी है। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 83 प्रतिशत दुकाने प्रथम 7 राज्यों में खोली गयी है, जिनकी कुल संख्या 11653 है। इस प्रकार शेष 17 प्रतिशत दुकाने 75 प्रतिशत राज्यों में खोली गयी।

सुवूर क्षेत्रों, पर्वतीय, आदिवासी तथा पिछडे इलाको के लिए प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव भी विशेष घोषणा के तहत् शुरू किये गये इस कार्यक्रम का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिले और इम क्षेत्रों को वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को काले बाजार में न पहुचाया जा सके, यह सुनिश्चित भारने के लिए उपभोक्ता के द्वार पर ही इन वस्तुओं के आपूर्ति की भी व्यवस्था की गयी है। अब तक इस घर-घर आपूर्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत, 54426 उचित दर की दुकाने शुरू की जा चुकी में 1746 50 लाख रुपये व्यय हुए है। इसके लिए केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

5 चीनी सकट-1994 - चीनी के मूल्यो पर नियन्त्रण और उसे उचित दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं। इसके लिए खुली बिक्री और लेवी की चीनी का कोटा बढाया गया। सितम्बर 1989 में दोनो तरह की चीनी के लिए चीनी का आवण्टन 8 82 लाख टन था जबिक अक्टूबर 1989 में बढाकर इसे 10 32 लाख टन कर दिया गया। अक्टूबर 1988 में लेवी चीनी तथा खुली चीनी का कोटा 9 17 लाख टन था। स्वदेशी चीनी की बाजार में उपलब्धता बढाने के लिए करीब 3 लाख टन चीनी के आयात का सौदा किया गया। चीनी का आयात देश में चीनी के उत्पादन में कमी की दशा में किया जाता है।

चीनी संकट पर प्रकाश डालने से पूर्व खुली बिक्री चीनी एव लेवी चीनी के आवण्टन एव खंपत का अवलोकन आवश्यक है जिसे निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका संख्या 8 खुली बिक्री एवं लेवी चीनी का आवण्टन

( मात्रा- लाख टनो में)

अवधि		आविष	टत	मात्रा	अवधि		र	वपत की मात्रा
अक्टूबर—	1988	9	17		अक्टूबर	से	सितम्बर-1980-81	50 0
14	1989	10	32		11	**	" 1983-84	76 0
ď	1990	10	07		11	11	" 1987-88	93 3
f)	1991	10	57		11	11	" 1990-91	107 2
अप्रैल-	1994)खुली -∫	5	60		ff	**	1991-92	115 0
मई -	1994≬बिक्री ≬	4	75					

स्रोतं भारत- सम्बन्धित वर्ष, सूचना एव प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1988 से लगातार चीनी के आवण्टन मे वृद्धि होती रही, परन्तु अप्रैल, 94 मे इसमे चीनी के कुल उत्पादन मे कमी हो जाने तथा उस कमी को प्राक्ररने के लिए समय से आधात की व्यवस्था न किये जा सकने के कारण मई-1994 मे केवल 4 75 लाख टन चीनी ही खुली बिक्री हेतु आवण्टित की जा सकी। चीनी की खपत घटती हुई दर से बढ रही है। अत बढी हुई खपत की पूर्ति हेतु खुली बिक्री एव लेवी की चीनी का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए था और कोटा बढ़ामें के लिए चीनी के कुल उत्पादन मे वृद्धि की जानी चाहिए थी। यदि उत्पादन मे वृद्धि सम्भव महीं बी ली बीनी की निवित्त आपूर्ति बनावे रखने के लिए चीनी का आवात समय से किया जाना चाहिए

था।

रांसद मे विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीनी आयात-मामले पर'काम रोंकों प्रस्तान" जून-1994 में प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकारी महकमों की अक्षमता और मिन्त्रयों तथा नौकरशाहों के बीच अहम के टकराव से हुए घाल-मेल के कारण ऊँची कीमतों पर चीनी का आयात किया गया और देश के खजाने को 650 करोड़ रूपये की चपत लगी। मार्च-1994 के प्रारम्भ में सरकार ने चीनी के शुल्क मुक्त आयात हेतु इसे खुलें सामान्य लाइसेन्सं(ओं जी एल ) के तहत लाने का निर्णय लिया, फिर भी राजधानी की खुदरा दुकानों में जून-1994 के पहले सप्ताह में चीनी की कीमत 18 रुपये प्रति किलों से भी अधिक हो गयी जबिक वर्ष जून-1993 में यह 12 50 रुपये की दर से बिक रही थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सकट के सकेत 1991-92 में ही मिलने लगे थे उस वर्ष भारत ने अतिरिक्त चीनी का उतपादन किया था। चीनी की खपत् 115 लाख टन थी जबिक उत्पादन 132 77 लाख टन हुआ जिससे कीमतों में भारी कमी आयी। भारत ने जब चीनी का निर्यात किया तो वहाँ भी कीमतों में भारी कमी आयी। परिणामस्वरूप भारतीय चीनी उद्योग में नकदी की भारी कमी हो गई जिससे किसामों को गन्ने के मूल्य का भुगतान समयसे नहीं किया जा सका और अगले गन्ना सत्र में किसानों ने गन्ने की जगह दूसरी फसलो पर जोर दिया।

वूसरी ओर केन्द्र सरकार ने जून-1993 में चीनी मिलों के शीरा बेचने पर लगे कीमत एवं वितरण सम्बन्ध नियन्त्रणों को उठाने का आदेश पारित किया जिससे शीरे की कीमत लगभग 15 गुना बढ गई। शीरा महँगा होने से अवैध शराब कम्पनियों ने गुंड का प्रयोग शुरू कर दिया और वे उसकी अधिक भीमतें दैने लगी। बदलें में गुंड बनाने वाली इकाईयाँ गन्ना किसानों को 10 से 15 रुपये प्रति कुन्तल की घर से (विशिष्ट रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में) अधिक भुगतान करने लगी। जनवरी-1994 में स्थिति और भी बिगड़ गई। खाद्य मन्त्रालय ने उत्तर प्रदेश, पजाब और हरियाणा की सरकारों को इस सन्दर्भ में पत्र लिखा जहाँ सबसे अधिक गन्ना गुंड उत्पादकों के पास जा रहा था। माननीय श्री मुलायम सिंह ने 24 जनवरी-94 को गुंड के भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश दिया। लेकिन किसानों के विरोध के बाद 8 परवरी-1994 को यह आदेश रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप लगभग 80 लाख टन गन्ना गुंड उत्पादकों के पास चला गया और चीनी का उत्पादन 8 लाख टन घट गया।

फरवरी 1994 के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा में दावा किया गया कि देश की प्राप्त भी का पर्याप्त भण्डार है, फिर भी 15 मार्च, 1994 को चीनी को आयात में खुले 17 इंग्डिंग दुंडे- 30 जून, 1994, कमाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या- 50

लाइसेन्स में रखने की घोषणा की गई। बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी की कीमत 75 पैसे प्रति किलो बढाकर जब 9 रुपये 5 पैसे प्रति किलो की गई तो उस समय खुले बाजार में चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रतिकिलो पहुँच चुका था। 3 सितंम्बर-1993 को राज्य चीनी सचिवो की बैठक में वर्ष 1993-94 में चीनी के 106 लाख टन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया। योजना आयोग का अनुमान था कि अगले वर्ष में चीनी की खपत 120 लाख टन हो गायेगी। अत 15 लाख टन चीनी के आयात की व्यवस्था की जाय। यह एक उचित कदम होता क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त विदेश मुद्रा भंडार भी था। परन्तु आयात अनुबन्धों को पूरा करने में विलम्ब हुआ। प्रारम्भ में खाद्य मंत्री का विचार था कि पिछले साल के मुकाबले हम नवम्बर-दिसम्बर में अधिक चीनी का उत्पादन कर रहे थे। ऐसी दशा में आयात का अन्तिम निर्णय ले लेना जल्दीबाजी होती। इस बीच 15 दिसम्बर-93 से 8 मार्च, 1994 के बीच मन्त्रि मण्डल की मूल्य सम्बन्धी समिति (सी पी ) की बैठक छ बार स्थिगत हुई और जब 8 मार्च को बैठक हुई तब तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 337 डालर प्रति टन पहुँच गयी। 19

भारत सरकार के लिए चीनी आयात करने वाला सस्थान भारतीय राज्य व्यापार निगम है। क्योंकि निजी क्षेत्र के व्यापारियों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी खरीदने की खुली छूट दी गई थी, इसलिए निगम की मील नोल की शिक्त कमजोर पड गयी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे चीनी की कीमते बढ़ने लगी। चीनी की आपूर्ति तथा कीमतो पर नियन्त्रण के मसले पर भिन्न-भिन्न मन्त्रालयों में सवादहीनता की स्थित बनी हुई थी। वित्त, वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एव खाद्य मन्त्रालयों की संयुक्त जिम्मेदारी थी कि वे इसके प्रिते सर्तर्क रहें। आयात का काम वाणिज्य मन्त्रालय का है तथा सरकारी वितरण का काम खाद्य मन्त्रालय का। चूँकि आयात करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरण करने में सब्सिडी का मसला भी अहम् हो जाता है। इसलिए वित्त मन्त्रालय की भूमिका भी वहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण थी। बहुत दिनो तक तो यही नहीं तय हो पाया कि सब्सिडी का भार वाणिज्य मन्त्रालय वहन करेगा या खाद्य मन्त्रालय। निजी क्षेत्र में भरीसा रखने बाला वित्त मन्त्रालय निश्चन्त था कि व्यापारी इतना आयात करेगे कि आपूर्ति की कोई समस्या महीँ रह जायेगी।

जब सी सी पी की 8 मार्च-1994 की बैठक में वित्त मन्त्री ने दोहराया कि वे आयात पर सिक्सिडी मही देगे तो मन्त्रिमण्डलीय सिमिति ने चीनी को खुले लाइसेन्स के तहत लाने का फैसला किया

18 नवंभीरत टाइंम्स- नई दिल्ली, 6 जून, 1994, पृष्ठ सख्या-7

<sup>19</sup> इंग्डिया दुःहै-30 जून, 1994 कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-49

और इस तरह निजी क्षेत्र को भी शुल्क मुक्त चीनी आयात करने की अनुमित मिल गयी। अधिसूचना जारी होने के बाद 7 जून-94 से पूर्व जिन निजी कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी आयात का सौदा किया उन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 9 निजी कम्पनियो द्वारा किया गया चीनी आयात

क्रम सं	कम्पनी का नाम		मात्रा( टनो मे)
1	भारतीय चीनी मिल सघ(इसमा)		92,000
2	ग्रेट ईस्टर्न शिपिग कम्पनी		2,00,000
3	एशिया शुगर्स कम्पनी		1 10 000
4	एस्सार गुजरात		77,000
5	अन्य कम्पनिया		2,15,000
		योग	6,94,000

म्रोत इण्डिया हुडे, 30 जून, 1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या – 52

इस प्रकार निजी कम्पनियो द्वारा 7 जून, 1994 तक कुल 6 94 लाख टन चीनी आयात का सीदा पूरा हो चुका था। यद्यपि तब तक राज्य व्यापार निगम और भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम नै भी 6 26 लाख टन चीनी के आयात का अनुबन्ध पूरा कर लिया था लेकिन इससे पूर्व ये दोनो संस्थाएं दुविधा में थी कि यदि सारी आयातित चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी की जायेगी तो उन्हें भारी धादा होगा क्योंकि आयातित चीनी की कीमत 13 10 रु० प्रति किलो होगी जबकि उचित दर की दुकामों भर इसे उस समय रुपये 7 10 प्रति किलो की दर से जारी किया जाता। इससे पूर्व भारतीय खाद्य निगम को भी आयात सौद मे शामिल करने का विचारिकया गया था परन्तु जब भारतीय खाद्य निगम में 16 मई—1994 को खाद्य मंत्री की इजाजत के बिना टेण्डर जारी किये गये तो खाद्य मंत्री ने अपनी धिदेश यात्रा से वापस आकर 19 मई—94 को यह टेण्डर इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि 1989 के ऐसे ही तथाक्रियत घोटाले के विषय मे लोक लेखा समिति ने ने खाद्य मन्त्रालय की आलोचना की थी जिसकी रिपीर्ट में कहा गया था कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मन्त्रालय चीनी आयात न करे और यह अधिकार राज्य व्यापार निगम तथा भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम को दिया गया। इसमे यह भी कहा गया कि किसी अपंजीकृत कम्पनी को भी चीनी आयात की अनुमित न दी जाय। यद्यपि उसी दिन राज्य व्यापार निगम ने 385 डालर प्रतिदिन की दर से पहले सौदे को अन्तिम रूप दिया और इसके बाद

के सौंदे 400 डालर प्रति टन की कीमत से कुद अधिक पर किये गये जिससे कुल 150 करोड रुपये का तुकसान हुआ।

ऐसा सकट दुबारा उत्पन्न न हो इसके लिए राकट के समय प्रयोग के लिए सरकार के पास 20 लाख तम चीनी का भण्डार वैज्ञानिक ढग से सरक्षित होना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे सकटो के समय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों यथा-वित्त मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा नागरिक एव खाद्य आपूर्ति मन्त्रालय में सवादहीनता की स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। चीनी का उत्पादन बढाने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि गन्ने का उत्पादन बढाने पर सरकार जोर दै। इसके लिए गन्ना उत्पादकों को नये उन्नितिशील बीज, न्यूनतम कीमतों पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए। गन्ने की वैज्ञानिक खेती का उत्पादकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। चीनी की कीमते राजनैतिक वंबावों रो मुक्त हो इसके लिए इस उद्योग को भी उदारीकरण की मुक्त हवा का झोका चाहिए। देशी बाजार में प्रतिस्पर्धा ही चीनी उद्योग की उन किमयों को दूर सकती है, जिसके कारण इसकी उत्पादन जांगत अधिक हो जाती है। इससे गन्ना उत्पादक किसानों का भी भला होगा। उन्हें गन्ने की उचित कीमत मिलेगी तथा समर्थन मूल्य बढाने के लिए वे सरकार के दरवाजे बार-बार खटखटाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इससे उपभोक्ता को चीनी की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि से राहत तो मिलेगी ही साथ ही हम अम्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफ के साथ निर्यात करने देसपने भी सजो सकते हैं।

(ल) समस्याए एव सुझाव -भारत में सार्वजिनक वितरण प्रणाली जहाँ मूल्य नियन्त्रण एव उपभोक्ता-संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम है, वही यह गरीबी से लड़ने का एक प्रमुख हिथयार भी है परम्तु व्यावहारिक धरातल पर आज भी इस प्रणाली में अनेक ऐसी किमयाँ एवं दोष हैं जिसके चलते देश के विभिन्न क्षेत्रों में यह आम उपभोक्ताओं को अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पा रही है। अन्य कल्याणकारी व्यवस्थाओं के समान सार्वजिनक वितरण प्रणाली भी भ्रष्टाचार के चगुल में फसी हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि। ग्रामीण समाज की क्रय-शिक्त सरकार के तमाम सर्वक्षण एवं आकड़ों से भिन्न है जिससे बचारे अत्पद्ध, अर्द्धनान कृषक एवं मजदूर, उचित समय पर सार्वजिनक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध करायें गयें सामग्रियों को खरीवने से विचत हो जाते हैं। साथ ही गावों में इस प्रणाली के सचालक कुछ दश्म लीगी की तो सामग्रियों उपलब्ध करा देते हैं, मगर निम्न आय वाले कमजोर व्यक्तियों को यह भी ज्ञात महीं है कि प्रित इकाई कितनी चीनी, गेहूँ, मिट्टी का तेल आदि मिलने का प्रावधान है। इसका परिणाम यह हीता है कि जिन्हें राहत पहुँचाने के लिए इसकी परिकल्पना की गई, वे गौण हो जाते हैं और अधिकारी— ध्यापारी मालामाल होते जाते हैं। इसकी मुख्य समस्याएं तथा उनका निराकरण अग्राकित है—

1 प्रणाली का नगरो तक ही सीमित होना — वर्तमान सार्वजिनक वितरण प्रणाली मूलभूत रूप से शहर आधारित व्यवस्था है क्योंकि शहरी लोग आधुनिक तन्त्र के अग है और अधिक शोर मचा सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार इस पद्धित से 31 से 41 प्रतिशत लाभ शहरी व्यक्तियों को तथा 8 से 19 प्रतिशत लाभ ग्रामीण व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। 20 ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकाने कम अथवा नहीं के बराबर हैं। इस ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों को वस्तूए पहुँचाने में भी कठिनाई होती है।

आज आर्थिक नीतियों के परिवर्तन के सन्दर्भ में देश में तेजी से मुक्त बाजार व्यवस्था लागू की जा रही है और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना और उसे मजबूत बनाकर आवश्यक वस्तुए सुलभ कराना लोगों को काफी राहत प्रदान करेगा। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस दिशा में एक सराह्मीय प्रयास के रूप में सफल हो रही है।

2 गांवों मे वितरण न होना — ग्रामीण क्षेत्रों के निकट जो कस्बे हैं, उनमें खुले बाजार में खाद्यान्न साधारणतया मिलते ही रहते है। यद्यपि इनके लिए कई बार अधिक मूल्य देना पडता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने नियन्त्रित मूल्य पर वस्तुओं को दिलवाने का प्रबन्ध कर रखा है लेकिन जिन लोगों के नाम गांव का कोटा है, वे शायद ही कस्बे से गांव में ले जाकर उन्हें वितरित करते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि वे अधिक मूल्य पर खाद्यान्नों शहर में ही बेच देते हैं। खरीद और बिक्री का मूल्यान्तर उनका लाभ बन जाता है।

इस समस्या का निराकरण सार्वजिनक वितरण व्यवस्था का कार्य ग्राम-प्रधान तथा ग्राम सभा के सदस्यों की सीपकर किया जा सकता है। ग्राम प्रधान की सहमित से कोटेदार नियुक्त किये जाने हेऐसे कोटेदार ग्राम-वासियों को अधिकतम् सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगे। ऐसी दशा में क्त्तुओं की उचित मूल्य पर बिक्री को सुनिष्टिचत किया जा सकेगा।

3 दरिद्रों को सहायता पहुँचाने वाला दावा खोखला — सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा विरिद्रों को रहित पहुँचाने का दावा कितना खोखला है, यह इससे स्पष्ट होता है कि सस्ते गल्ले की वितरित मान्ना और दरिद्रों की संख्या में कोई अनुपातिक सम्बन्ध नहीं है। 1992-93 में उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश जिनकी सख्या देश की कुल जनसंख्या का 34 3 प्रतिशत है, और जहाँ देश की कुल दिद्राता रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वालों का 42 2 प्रतिशत निवास करता है, को देश में कुल वितरित सस्तै अन्त का केवल 13 7 प्रतिशत ही आविण्टत किया गया था। जबिक दिल्ली, केरल और

<sup>20</sup> कमीशन एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम-नवम्बर-1992, आई-76ए, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, पृष्ठ सख्या-24

आन्ध्र परेष, जिनकी आबादी देश की आबादी का केवल 11 4 प्रतिशत और जहाँ देश के गरीबो में केंग्ल 10 5 प्रतिशत ही निवास करते हैं, कुल वितरित सस्ते खाद्यान्न का 28 7 प्रतिशत आविण्टत किया गया था। सार्वजिनक वितरण प्रणाली दिख्रों के प्रति कितनी उदासीन है यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि बिहार राज्य को, जिसकी आबादी देश की आबादी का का 10 24 प्रतिशत है और जहाँ देश के 14 5 प्रतिशत दिख्र निवास करते हैं, देश में कुल वितरित सस्ते खाद्यान्न का केवल 4 0 प्रतिशत दिया गया था, जबिक दिल्ली नगर को जिसकी आबादी देश की कुल आबादी की पूरे एक प्रतिशत भी नहीं है और जहाँ दिख्रों की सख्या भी सबसे कम है, कुल सस्ते अन्न का 5 3 प्रतिशत बाँटा गया था। 21 देश में जितने अन्म की खपत हो रही है उसके आठवे भागसे अधिक सार्वजिनक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित नहीं हौता। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान सार्वजिनक वितरण प्रणाली से देश की आठवी आबादी ही, अर्थात लगभग 11 25 करोड लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं।

इस समस्या की वैकल्पिक व्यवस्था यह हो सकती है कि देश के अति दिरद्रों की पहचान की जाय और उन्हें सीधे नकदी या कूपनो द्वारा आर्थिक सहायता दी जाय, जिससे वे अपना पेट भरने के लिए ख़ुले बाजार सै अन्न खरीद सकें। क्योंकि दिर्द्रों की सहायता पूरे राष्ट्र की कीमत पर (अर्थात् सरकारी खंजाने सें) की जानी चाहिए न कि केवल किसानों की कीमत पर, जिनमें अधिकाश स्वय दिरद्र है। लगभग सभी देशों ने पुराना रास्ता'अनाज के मूल्य को गिराकर रखों का परित्याग कर, नया रास्ता' गरीबों की पृष्टभान करों का मार्ग अपनाया है। इस मार्ग पर चलने से कई लाभ है, जैसे— सहायता उन्हें ही मिलेगी, जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है और कम धन से अधिक दिद्रों को सहायता मिल सकेगी। खाद्यान क्यापार पर लगे सभी प्रतिबन्ध इटने से भ्रष्टाचार कम होगा और किसानों को भी खुले बाजार का अवसर प्राप्त होगा जिससे उन्हें अच्छे मूल्य भी मिल सकेगे। श्रीलका सरकार ने गरीबों की पहचान कर उन्हें सीधे सहायता देने का मार्ग अपनाकर अपने खाद्य अनुदान की राशि को एक—तिहाई करने में संक्लता प्राप्त की है। इसका दूसरा विकल्प यह है कि ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्नाभ न विद्या जाय जिनकी वार्षिक आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। इस प्रतिबन्ध को लागू करके भी, केवल वास्तविक लाभ पाने योग्य व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली वर्तमान सुविधा को और अधिक बढ़ायों जा सकेगा।

4 कम पूर्ति की दशा मे उचित मूल्य की दुकानो पर दबाव बढ़ जाना — जब वस्तुओ की आपूर्ति कम होती है तो इन दुकानो पर उपभोक्ता का दबाव बढ़ जाता है ओर सामान देने में घण्टो लग

<sup>21</sup> संबंधारते टाइम्स-नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1994

जाते है। किन्तु जब खुले बाजारों में भी वस्तुए मिलती रहती है तो बहुत बड़ी सख्या में उपभोक्ता खुलें बाजार से ही अपनी आवश्यकताए पूरी करने लगते है। इससे इन दुकानों को अपना खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है।

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिन वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था की जाती है उनकी देश में उत्पादन एवं खपत की सही—सही मात्रा का अनुमान लगाया जाय। सही प्राक्कलन हेतु आवश्यक है कि इसके लिए दो या दो से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाय। उत्पादन ओर खपत के सही प्राक्कलन से दोनों समस्याओं का निराकरण हो जायेगा अर्थात् त तो दुकानों पर उपभौकताओं का अधिक दबाव बढेगा और न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का खर्च न चलनें की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि प्रारम्भिक अनुमान से उत्पादन खपत से कम है तो उसके आयात की समय रहते व्यवस्था कर ली जायेगी और यदि उत्पादन खपत से अधिक है तो आर्थिक्य मात्रा का निर्यात कर विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकेगा।

5 <u>अन्य वस्तुओं को बेचे जाने की अनुमति न देना</u> उचित मूल्यों की दुकानों से बिकने घाली वस्तुओं की संख्या में और अधिक वस्तुओं को इच्छानुसार जोड देना सरल कार्य नहीं होता क्योंकि इन पुकानों पर बिकने वाली वस्तुओं को सरकार को स्टाक रखने की आवश्यकता होती है। बिना स्टाक रखे राशन प्रणाली नहीं चलायी जा सकती।

वास्तव मे जिन वस्तुओं के वितरण मे उचित प्रतियोगिता है तथा जिनके वितरण मे उपभोक्ताओं का किसी तरह से शोषण नहीं हो रहा है उस वस्तु को सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाना आवश्यक नहीं होता। अत जिन वस्तुओं के वितरण मे उपभोक्ता का शोषण किये जाने की सम्भावना हो उसके उत्पादन एवं खपत का पूर्वानुमान करना अनिवार्य हो जाता है। पूर्वानुमान के पश्चात् उस वस्तु के स्टॉक देशी अथवा विदेशी खरीद के माध्यम से बनाये जा सकते हैं और उस वस्तु को सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जा सकता। है।

6 सरकारी तन्त्र में भ्रष्टता — भ्रष्टता की जितनी शिकायते निजी व्यापारियों के सम्बन्ध में की जाती हैं, वे सब शिकायते सरकारी तन्त्र के दुकानदारों में पनप रही हैं, वितरण हेतु प्राप्त खाद्याम्नों एवं वस्तुओं को फुटकर व्यापारियों को बेच देना, चीनी में पानी डालकर वजन बढाना, खाद्यान्नों मैं अपिमिश्रण, नाप व तौल ठीक –ठीक न करना, दुकानों को प्राय बन्द रखने की समस्या लगभग 80 प्रतिश्रीत दुकानों में पायी जाती है।

इस वोष का निवारण प्रधानमत्री पी वी नरसिंह राव के उस कथन से होता है जो उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तानी जिला बाडमेर में नई व्यवस्था का शुभारम्भ करते हुए दिया था कि ' केन्द्र सरकार ने लोगों के तिए यह योजना तो प्रदान कर दी है परन्तु इसकी सफलता एवं विफलता का दायित्व राज्य सरकार और स्थानीय लोगों का है।" 22 वास्तव में वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय लोग एवं उच्चस्तरीय प्रशासन दोनों के सहयोग से सरकारी तन्त्र के भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों की एक आकिस्मक जाँच दल द्वारा समय—समय पर जाँच करवायी जाय तथा दोषी दुकानदारों को कठोर से कठोर सजा दी जाय साथ साथ ही दुकानों की जाँच का अधिकार तथा प्रशासकीय जाँच में सहयोग हेतु मुहल्ला या ग्राम—जाँच समितियाँ बनायी जानी चाहिए ताकि वितरण व्यवस्था की निचले स्तर पर भी जाँच की जा सके और इस तथ्य से सन्तुष्टि प्राप्त की जा सके कि वस्तुओं का वितरण वांछित व्यक्तियों को ही किया जा रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जागरूक बनाया जाना चाहिए जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ठ रहे साथ ही दुकानों की कार्य प्रणाली में रचनात्मक सुधार भी किया जाना चाहिए।

7 <u>अच्छी किस्म की वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई</u> जब खुले बाजार में वस्तुए मिलती है तों लोग खुलें बाजार को ही पसन्द करते हैं, वे राशन की दुकान से वस्तुए नहीं खरीदना चाहते क्योंकि खुलें बाजार में वस्तु की किस्म का चुनाव करने का अवसर प्राप्त होता है जो राशन की दुकानो पर नहीं होता है।

वास्तव में यदि अच्छी किस्म की वस्तुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाये तो समाण को वस्तुओं का चयन करने की आवश्यकता ही न पड़े क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की अच्छी किस्म की ही प्राप्त करना चाहता है चाहे वह उपभोक्ता अमीर हो अथवा गरीब। अत इस समस्या का निवान उचित दर की दुकानों में अच्छी किस्म की वस्तुए उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।

8 अफसरशाही का दोष — सरकारी तन्त्र में अफसरशाही अधिक चलती है। इसलिए ऐसा तम्त्र हमीशा 'टाँप हैवी' बन जाता है, उन अफसरो एवं कर्मचारियों का वेतन भी वितरित वस्तुओं की लागत में शामिल किया जाता है इसलिए' उचित दर पर'नाम रहते हुए भी उपभोक्ता को वस्तु 'अनुचित दर' पर ही मिलती है।

सम्चाई यह है कि सरकार द्वारा जनता के हित के लिए सचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों में ' न लाभ न हानि' के सिद्धान्त का अनुपालन किया जाता है, इतना ही नहीं कभी—कभी तो ऐसी गतिविधियों सरकार द्वारा हाँनि उठाकर भी जारी रखी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु भी 1993-94 में 3000 करोंड रुपये की राज्य सहायताका प्रावधान किया गया था। दूसरी और निजी व्यापारी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास निरन्तर जारी रखते है।

<sup>22</sup> वामीशान एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम-नवम्बर-1992, आई-76ए, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, पृष्ठ संख्या-24

इस प्रकार अधिकारियो एव कर्मचारियो का वेतन वस्तुओ की लागत मे जोडने तथा राज-सहायता का समायोजन करने के बाद भी उपभोक्ता फायदे में ही रहता है।

11

9 ग्रीब वर्ग की उपेक्षा — एक सुनियोजित, सुदृढ, सक्षम और स्वस्थ वितरण प्रणाली के बिना कमजोर वर्गो के उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। वितरण व्यवस्था से सम्बद्ध लोग अपनी अपनी परिस्थिति का लाभ उठाकर, मूल्य वृद्धि, मिलावट, कम माप तौल, फर्जी राशन कार्ड, दुकानों का प्राय बन्द रखना, गरीब कार्ड धारकों को घुडकना और लौटा देना आदि अनैतिक उपायों से अधिकतम लाभ कमाते है।

कमजोर वर्ग को इस प्रणाली से अनुकूल लाभ पहुँचे, इसके लिए सर्वप्रथम फर्जी राशन कार्डों एव जाली यूनिटो को रद्द करना अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह एक प्रभावी एवं वण्डनीय अभियान चलाये, तभी जरूरतमन्द लोगों के हितों को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए गरीब जनता को इस प्रणाली के प्रति पूर्णत जागरूक बनाने की भी जरूरत है कि उन्हें कितनी मात्रा में किस वर पर, किस समय वस्तुओं की आपूर्ति मिलनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब वर्ग के प्रति पूर्णतया न्यायसंगत बनाने के लिए आवश्यक है कि इस प्रणाली के दायरे से उच्च आय वर्ग के लोगों को बाहर किया जाय तभी निम्न वर्ग के लोगों की पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती हैं।

10 <u>डीलर द्वारा दुकानों को ठेके पर दिया जाना</u> बहुत सी उचित दर की दुकानों केडीलर अपनी सुकाने व्यापारियों को ठेके पर दे दते हैं जिससे एक और मध्यस्थ आ जाने के कारण उपभौक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। ठेकेदार को इस प्रणाली की मूल भावना से कुछ लेना—देना नहीं होता है। वह तो अधिक से अधिक लाभ कमाने का उपाय दूढता है उचित दर की दुकानों से सामान की चोरी इसी का परिणाम होती है<sup>23</sup>

सार्वजिनक वितरण प्रणाली को इन बुराइयों से मुक्त करके कारगर बनाने के लिए इस सम्पूर्ण ध्यवस्था पर प्रभावी नियन्त्रण आवश्यक है। इसके लिए उचित दरमेदुकानों का सतर्कता सिमितियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। जिला प्रखण्ड एवं तालुका स्तर पर उपभोक्ता सलाहकार सिमितियों को और अधिक चुस्त-वुरुस्त किया जाना चाहिए।

11 वितरित की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में वृद्धि — पिछले वर्षों मे राश्चन की दुकानों से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य मे समय—समय पर बहुत अधिक वृद्धि होती रही है। गेहूँ की कीमत फरंबरी-94 में 427 रुपये प्रति कुन्तल थी जबकि बाजार में राशन की तुलना में बढिया किस्म

<sup>23</sup> घोजभा = 15 जून, 1992, ह्याना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नर्द विस्ती

का गेहूँ 4 से 4 50 रुपये प्रति किलो उपलब्ध था। यही स्थिति चावल की भी है। चीनी की कीमत पिछले बजट से पहले फरवरी—94 मे 75 पैसे प्रति किलो बढ़ाकर 9 रु 5 पैसे कर दी गई। ऐसी परिस्थिति मे जनता का विश्वास सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे घटता है साथ ही उसके पारिवारिक बजट मे समायोजन की कठिनाई भी होती है।

वास्तव में उचित दर की दुकानों पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का कारण सब्सिडी का कम होना है। वितरित की जाने वाली वस्तु के प्राप्य मूल्य और उसके खरीद एवं भण्डारण की कुल लागत में होने वाले अन्तर का समायोजन सब्सिडी से किया जाता है। इस समय खाद्य निगम के गेहूँ की लागत 542 रु प्रति कुन्तल है जिसमें 330 रु खरीद मूल्य और 212 रु रख-रखाव का खर्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि गेहूँ का उत्पादन करने वाले किसानों को दिये जाने वाले प्रत्येक 3 रुपये के साथ 2 रु निगम को दिये जाते हैं। इस स्थिति में गेहूँ को 407 रुपये प्रति कुन्तल के बढ़े दामों पर बेचने के बावजूद खाद्य निगम को 135 रुपये प्रति कुन्तल की हानि होती है जो सब्सिडी के रूप में सरकार से प्राप्त की जाती है। पिछले दशकों में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में वृद्धि को निम्न तालिका में देखा जा सकता है—

तालिका संख्या 10 सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी जाने वाली सब्सिडी

বৰ্ষ	करोड रुपये
1970-71	71
1980-81	650
1990-91	2450
1993–94	3000(प्रावधानित) 6000(अनुमानित)

म्रोत नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली,21 अप्रैल,1994,पृष्ठ सख्या-6

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वितरण प्रणाली के लिए खाद्य निगम को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में लगातार वृद्धि हो रही है। यह सब्सिडी जो 1970-71 में केवल 71 करोड़ रुपये थीं जो बढ़तै-बढ़िते वर्ष 1990-91 में 2450 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी। वर्ष 1993-94 के बजट में इस सब्सिडी के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था परन्तु वास्तव में दी जाने वाली सब्सिडी का अनुमान 6000 करोड़ रुपये अर्थात् बजटीय घाटे से का डेढ गुना है। सरकार का स्पष्टीकरण है कि पिछले वर्ष अनाज के खरीद मूल्यों में की गई वृद्धि के कारण सब्सिडी का खर्च बढ़ क

गया है। वास्तव मे यदि गरीब उपभोक्ताओं को प्रणाली का लाभ अनिवार्यत दिलाना है तथा उसके पारिवारिक बंजट मे स्थिरता लानी है तो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।

- 12 कुछ अन्य सुझाव सार्वजिनक वितरण प्रणाली की आलोचना उपर्युक्त विन्दुओ पर की जाती है( यद्यपि इन सबका उचित निदान सम्भव है) फिर भी सार्वजिनक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने का एक अपरिहार्य माध्यम है। यह आम निरीह, गरीब एव शोषित उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर वस्तुऔं को उपलब्ध कराने का एक मात्र सहारा है। अत वर्तमान समय में जहाँ एक ओर इसके समसागियक एव प्रासंगिक महत्व को देखते हुए इसके अस्तित्व को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है, वही दूसरी ओर इस प्रणाली के उद्देश्यपरक लाभों को, मध्यम एव निम्नवर्ग को प्रदान करने हेतु उसमें निम्नलिखित सुझाव भी लागू करने की आवश्यकता है—
- 1 एक दुकानदार को आविष्टत जनसंख्या व कार्डो की संख्या बढायी जाय। वस्तुओं की कोटा में वृद्धि की जाय जिससे प्रत्येक दुकान आर्थिक दृष्टि से लाभदायी बन सके। ऐसी दुकानों, जिनकी संख्या कम है, का एकीकरण किया जाए या इन्हें सहकारी भण्डारों को सौपा जाय।
- 2 इस प्रणाली का उपयोग उन क्षेत्रों में न किया जाय जहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अभी भारत में ऐसे असख्य गाव है जहाँ न तो पक्की सड़के हैं और न गोदाम। यहाँ तक कि इन गावों की दुर्दशा से परिचित होने के लिए यहाँ कोई अधिकारी अभी तक नहीं गया है। ऐसे क्षेत्रों में सर्व-प्रथम सड़क परिवहन जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के बाद ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जानी चीहिए ताकि पर्याप्त निरीक्षण एवं वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
- 3 मई दुकानों के खोले जाने में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। प्रावधान है कि कम से कम 2 हजार की आबादी पर या 3 किलोमीटर की दूरी पर एक उचित मूल्य की खुदरा आपूर्ति की सुकान हो। किन्तु कही पर तो यह 5 हजार की आबादी पर भी नहीं है और कही पर एक हजार की आबादी वर भी नहीं है और कही पर एक हजार की आबादी ही ऐसी दुकानों की स्थापना के लिए पर्याप्त मान ली गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश में यह स्थित सामान्य बन गयी है। 24
- 4 विद्यमान सामाजिक परिवेश में स्वार्थ की जड़े काफी गहरी हो चुकी है, उसको उखाड़ पेंकिना मिताम्त आवश्यक है इसके लिए लोगों में देश भक्ति एवं नैतिकता की भावना जागृत करनी चाहिए।
- 5 शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाय तथा जनता को जनसंख्या वृद्धि से

<sup>24</sup> नवभारत टाइम्स-गई विल्ली, 28 अगस्त 1994, पृष्ठ सख्या-7

होने वाली हानियों से मली-भाँति अवगत कराया जाये, जिससे कि व सीमित परिवार रख सके।

- 6 सनकार को उचित मूल्य के दुकानदारों की आय में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि प्र गरान कार्य के निम्मिरित न हो।
- 7 अवत म्द्रा की दक्ताना पर उपलब्ध वस्तुओं को होते होते उन्ना के पैकेटो में जिस पर भारतीय मानक रास्थान की मुहर लगी हो, उपलब्ध कराना चाहिए। इससे वस्तुओं की किस्म में अपने आप शुद्धता रहेगी तथा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण भी कम माप-तौल के सम्बन्ध में न हो सकेगा।
- श्व सरकार को राशनकार्डों के हस्तान्तरण करने वाले दोनो पक्षकारों को दण्डित कर इस पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए।
  - 9 कार्ज की जॉच करते रामय प्रवसन व विवाह को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- 10 रिचंत मूल्य की दुकानों के लिए तस्तु जिला मुख्यालय से दुकानदार की दकान पर **डी** वस्तुओं की आपूर्ति की जानी चाहिए जिससे दुकानदारों को कम आपूर्ति अथवा प्राप्ति दर के विषय में मनमाना बहाना करने का अवसर न मिल सके।
- 11 प्रणाली के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में महिलाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
- 12 गागीण क्षेत्रों में अधिक दुकाने खोलने के लिए सरकार द्वारा नवयुवकों को पीरत दिया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों को रोजगार भी पाप्त होगा। साथ ही साथ गामीण जेन के उपभोक्ताओं को वस्तुए भी सुगमता से उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- 13 मरकार को दुकानदारो द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिये जाने वाले चन्दो पर रोक लेगाना चाहिए जिससे कि इनके दैनिक कार्य प्रणाली में राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द हो सके।
- 14 बाजार मूल्य व उचित मूल्य की दुकानो की वस्तुओ का सम मूल्य होने पर सरकार को किसी न किसी रूप में इन दुकानदारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण मन्दी के दिनों में कर सके।
- 15 पुकानदारों का कमीशन बिक्री के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाना चाहिए तथा यह प्रतिशत सभी नस्तु के लिए समान नेना चाहिए।
- 16 शरकार को उचित दर की दुकाने सप्ताह में कम से कम 5 दिन खुला होना सुनिश्चित करना चाहिए।

यद्यपि उपरोक्त सभी सुझाव तभी सम्भव है जब लोगों की नीयत साफ हो।

समाज के सभी वर्गों को समान रूप से जागरूक होना होगा और अपने अन्दर क्रिक्य बोध एव ाधिन्य बोध जागृत करना होगा। इस योजना के पुनरूद्धार के समय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त आश्रका भी सही है। कि सारकार अनेक करयाणकारी योजनाओं को कि इरादों के साथ शुरू करती है परन्तु बीच में होने गली गडबडियों के कारण जास्तिवक पात्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस योजना की सफलता और असफताता सरसार है के करना पर विभिन्न करती है।

सरकार के कड़े कदमों के अधीन 19 फरवरी-1995 को केन्द्र सरकार ने राशन की ट्यानों पर होने वाली अनिगमितताओं व काला बाजारी को रोकने के लिए देश के सभी जिलों में नियन्त्रण कक्ष खोलने का निर्देश सभी राज्यों को दिया गया है क्योंकि इन दुकानों की अनिगमितताओं के कई मामले नागरिक आपूर्ति मन्नाराय के परिज्ञान में लाये गये थे जिनमें अधिकाश शिकायते गामीण क्षेत्रों से राम्बन्धिन थी। इन नियन्त्रण कक्षा में उपभोक्ता सार्वजिनक वितरण प्रणाली के सामानों की अनुपलब्धता और राशन के दुकानदारों की अनिगमितता जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से आग्रह किया है कि वह देश के सभी आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को विभिन्न क्षेत्रों में खुले बाजार और राशन की दुकानों से मिलने वाली आवंश्यक वस्तुओं के मूल्य और उसकी मात्रा के सम्बन्ध में सूचनाए प्रसारित करने का निर्देश दे। इसके साथ ही राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा जिला नियन्त्रण कक्षों के गठन का व्यापक प्रयार करे ताकि आम जनता को उसकी जानकारी हो सके। 25

सारकार ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर भी निगरानी समितियों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इन समितियों का गठन इसके लाभार्थियों के बीच के लोगों द्वारा किया जाता है। इनमें महिलाओं उपभोक्ता आयोजन के सिक्रिय कार्यकर्ताओं तथा प्रबन्धकों को पूरी भागीदारी दी गयी है। अब तक 80 प्रतिशत से भी अधिक लिक्ष्यित पंचायतों में ऐसी ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है। कुछ राज्यों में इन समितियों का गठन पंचायत स्तर पर, तो कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर दुकान के क्षेत्र स्तर पर किया गया है।

यद्यपि इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने अपनी ओर से मूल्य नियन्त्रण की विशा में अनेक ठोस कदम उठाये हैं, लेकिन सत्ता के बिचौलियों ने सरकारी नीतियों में छिद्रान्वेषण कर व्यापारी वर्ग के हित-साधन करने का मार्ग पूर्ववत् खोज लिया इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली इतनी प्रभावीं न हो सकी, फिर भी भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में यह प्रणाली जहाँ सामाजिक

<sup>25</sup> दैनिक जागरण- वारणसी, 20 फरवरी, 1995

आर्थिक न्याय प्रदान करने वाली योजना के रूप में स्थापित हुई, वहीं यह आम उपभोक्ताओं के अधिकारों एव हितों की रक्षा करने के साथ -साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक आधार स्तम्भ भी बन चुकी है अत लोकतन्त्र के अन्तर्गत लोक विश्वास को जीतने के लिए इस प्रणाली को एक नये रूप में सगठित करने की आवश्यकता है तभी इस प्रणाली में व्याप्त पूर्व-प्रस्तुत किमयों एव दोषों को दूर करके कमजोर एव निबर्ल-वर्ग के लोगों को वाछित लाभ प्रदान किया जा सकता है।

#### (घ) भारतीय खाद्य निगम -

(अ)परिचय → भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम—1964 के अधीन की गयी जिसने अपना कार्य 1 जनवरी, 1965से प्रारम्भ किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य कुछ निश्चित क्षेत्रों में निजी व्यापारियों की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना और उत्पादक एव उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करना था। यह निगम भारत सरकार की एक प्रमुख एजेन्सी के रूप में स्थापित किया गया जो खाद्यान्नों के आयात, खरीद, भण्डारण एव वितरण को सचालित करे तथा भारत की राष्ट्रीय खाद्य नीति का अनुपालन भी करे। भारतीय खाद्य निगम उर्वरकों के आयात, भण्डारण एव वितरण के साथ ही साथ लेवी चीनी की खरीद भण्डारण एव वितरण का कार्य भी करता है।

निगम का प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमे एक अध्यक्ष, निदेशक मण्डल और एक कार्यकारी समिति होती है। इसके निदेशक मण्डल में वर्ष 1992-93 में 11 सदस्य तथा कार्यकारी समिति में 8 सदस्य थे। इसके अतिरिक्त सचिव भी होता है। निगम में प्रबन्ध निदेशक के अधीन 9 कार्यकारी निदेशक अपने-अपने कार्यक्षेत्र क्रमश वाणिज्य, आन्तरिक लेखा परीक्षक, वित्त, भण्डारण और बिक्री, इजीनियरिंग, यातायात, सर्तकता, सामान्य तथा कार्मिक सेवाओं में अपना-अपना सहयोग प्रदान करते हैं। निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में हैं। निगम की कार्यक्यक्स्था-5 आचिलक कार्यालयों, 19 क्षेत्रीय कार्यालयों 3 सयुक्त प्रबन्धक बन्दरगाह कार्यालयों, 3 उपक्षेत्रीय कार्यालयों तथा 160 जिला कार्यालयों के माध्यम से सम्पन्न होती है।

खाद्य निगम अधिनियम 1964 की धारा-5 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूँजी 31 मार्च 1981 को केवल 45 करोड़ रूपये थी जो वर्तमान समय में बढ़ कर 100 करोड़ रूपये हो गयी है। निगम की भारत सरकार द्वारा अभिदत्त पूँजी 31 मार्च 1972 को केवल 7637 94 लाख -रूपये थी जो मार्च-1981 में बढ़ कर25044 85 लाख रूपये हो गयी। मार्च 1993 में निगम की अभिदत्त पूँजी 95097 88 लाख रूपये तक पहुँच गयी।

<sup>26</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

- (ब) उद्देश्य -- भारतीय खाद्य निगम की स्थापना समाज के कमजोर व निर्धन वर्ग को आवश्यक वस्तुए या खाद्यान्नो को उचित मूल्यो पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी, जिससे कि व्यापारियो द्वारा उपभोक्ताओ का शोषण न किया जा सके। निगम को भारत सरकार की खाद्य नीति के मुख्य लक्ष्यो को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौपा गया है, ये लक्ष्य है-
  - प्रभावी मूल्य समर्थन के द्वारा किसानो के हितो की रक्षा करना,
- सार्वजिनक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के लिए राज-सहायता मूल्यों पर पूरे देश
   मे एक समान दर पर खाद्यान्नों का वितरण करना,
- राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिचालनात्मक और सुरक्षित भण्डार का
   सन्तोषजनक स्तर बनाये रखना।

खाद्यनीति के उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के निम्न उद्देश्य वर्गीकृत किये जा सकते हैं—

- 1 किसानों से उनके उत्पादन आधिक्य को खरीदना भारतीय खाद्य निगम का प्राथमिक उद्देश्य किसानों से उनका उत्पाद उचित मूल्य पर अथवा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य । पर खरीदना है। खरीद कार्य के सम्बन्ध में निगम को इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न होने पाये। इस कार्य के लिए देश की समस्त सरकारी, सहकारी व स्वतन्त्र मण्डियों में भारतीय खाद्य निगम के विभाग कार्यरत है।
- 2 उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध कराना निगम का द्वितीय उद्देश्य देश के निर्धन तथा कमजोर उपभोक्ताओं को वस्तु ए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। उसके लिए वह अपने गोदामों में एकत्रित खाद्यान्न भण्डार से उचित समय पर उचित मात्रा में खाद्यान्नों का निर्गमन करता है जिससे कि वस्तुओं की कीमते असमान रूप से न बढने पाये। खाद्यान्नों का उचित मूल्य पर ही वितरण किया जाय इसके लिए सरकार कभी—कभी राज सहायता के रूप में भण्डारण एव परिवहन लागत को समायोजित करने हेतु वित्त भी प्रदान करती है।
- 3 मूल्यों की विभिन्नता को समाप्त करना भारतीय खाद्य निगम इस बात की भी सदैव चेष्ठा करता है कि सम्पूर्ण भारत में एक वस्तु के मूल्य में समानता रहे जिससे किसी भी राज्य के उपभोक्ता में असन्तोष न पनपने पाये। इसके अतिरिक्त मौसमी या चक्रीय प्रभावों तथा प्राकृतिक आपदाओं की दशा में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों के मूल्यों में विभिन्नता न आये। निगम का उद्देश्य यह रहता है कि मौसम, या विभिन्न राज्यों में उत्पादन के स्तर पर जो विभिन्नताए उत्पन्न होती है उनको समाप्त करना जिससे कि सारे देश के मूल्यों में समानता बनाये रखी जा सके।

4 पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित भण्डार बनाये रखना — भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य यह भी है कि नह गेश वे आर्तारक उत्पादन के आधिक्य को र्यरीदकर तथा आधिक्य न होने की दशा में देश की आवश्यकता को ध्यान म रखते हुए वस्तुओं का आयात करके आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त सुरक्षित भण्डार बनाये रखे जिससे कि पाकृतिक विपत्तियों या दैवी-आपदाओं से उपभोक्ता व देश के नागरिकों की रक्षा की जा सके तथा इसके साथ ही साथ कमजोर वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुए उपलब्ध करायी जा सके।

भारतीय खाद्य निगम अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाए सम्पादित करता है। निगम अपनी क्रियाओं के सम्पादन में केन्द्र एवं राज्य सरकार के अभिकरणों, सहकारी सस्थाओं एवं कुछ संसाधनात्मक इकाईयों का सहयोग लेता है। यद्यपि निगम ने अपने स्वयं के संसाधनों को विकसित करने का प्रयास किया है, परन्तु कमजोर और निर्धन उपभोक्ताओं की आधारभूत खाद्यान्न आवश्यकता की न्यूनतम व्यय पर पूर्ति का पुनीत कर्तव्य निभाने में वह भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा निजी आयात—निर्यात अभिकरणों से भी कभी—कभी सहयोग प्राप्त करता है।

# (सं) कार्यात्मक प्रगति का मूल्याकन -

भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों तथा कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्यों में एकंक्पता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाए करता है। उसकी समस्त क्रियाए द्विपक्षीय हितों पर निर्भर करती है। जहाँ वह एक और उपभोक्ता को कम मूल्य पर उचित मात्रा में उचित समय पर वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, वही दूसरी ओर वह उत्पादकों को भी उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्रवान कारने का वह सत्त् प्रयास करता रहता है तािक उत्पादकों को अधिकतम उत्पादन की अभिप्रेरणा भी मिलती रहे। इसके लिए वह खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उसके दुलाई की व्यवस्था, भण्डारण एवं रख-रखाद, धस्तुओं की गुणवस्ता पर नियन्त्रण एवं उचित समय पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की भण्डार से निकासी तथा बिक्री जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों के साथ ही साथ वह उपभोक्ता जागरूकता जैसे, सामाजिक चेतना कार्यक्रम में भी अपनी सिक्रय भूमिका निभाता है। निगम के प्रमुख कार्य तथा उनकी वर्तमान स्थित निम्नवत् है—

1 <u>अधिप्राप्ति एवं खरीद</u> — वर्तमान समय में निगम केन्द्रीय पूल के लिए गेहूँ, धान, चावल और मीटे भागाणों की अधिप्राप्ति का कार्य मुख्यत राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों के सहयोग से करता है। धान, गेहूँ सधा मीटे अनाजों की अधिप्राप्ति मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत की जाती है। चावल की अधिप्राप्ति राज्य सरकारों द्वारा जारी लेवी आदेशों के अनुसार की जाती है। भारत सरकार ने पुन इस बात को वोहराया है कि उचित एव औसत गुणवत्ता वाले वे सभी अनाज जो कि उत्पादको द्वारा खरीद मूल्य पर बेचन के लिए प्रस्तृत किये जाये तो उन्हें पूर्णरूपेण खरीदा जाय। चावल धान एव मोटे अनाज के अधिपाप्ति की विधि का विधारण राज्य रारकारे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर करती है। मूल्य समर्थन नीति के अतिरिक्त अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकारे मिल मालिको एव व्यापारियों पर लेवी और उत्पादको पर श्रेणीकृत लेवी लगाती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पजाब, राजस्थान, तिमलनाडु, पिश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में धान और चावल की खरीद न केवल न्यूमतम समर्थन गूल्य पर, बल्कि मिल मालिको और व्यापारियों पर लेवी लगाकर भी की जाती है। भारतीय खाद्य निगम धान एवं चावल की अधिप्राप्ति बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उडीसा से तथा गेहूँ की अधिप्राप्ति गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उडीसा से नहीं करता है। इन राज्यों में सम्पूर्ण अधिप्राप्ति राज्य सरकार और उसकी एजेन्सियों के माध्यम से की जाती है। अन्य राज्यों में एक विस्तृत अधिप्राप्ति एजेन्सी के रूप मे भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार की खरीद एजेन्सियों के साथ-साथ खरीद कार्य सम्पन्न करता है। गत वर्षों में विभिन्न खाद्यान्तों की कुल मूल्यात्मक अधिप्राप्ति मी स्थिति निग्मवत् है-

तालिका संख्या <del>-</del> 11 निगम द्वारा मुल्यात्मक अधिप्राप्ति की स्थिति

منعن بنسن فينت شنع الم	्र वर्ष	खरीद(लाख रुपयो मे)	वार्षिक वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
	1981-82	3,43,427 48	_
	1983-84	4,20,389 96	11 73
	1985-86	5,38,620 07	22 69
	1987-88	4,88,867 75	(-) 14 79
	1988-89	4,93,647 14	97
	1989-90	6,71,212 64	39 97
	1990-91	8,20,732 06	22 28
	1991-92	7,63,586 97	(-) 6 96
	1092-03	10,54,977 73	38 16

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदम- भारतीय खाद्य निगम, बारखम्बा लेन, नई दिल्ली पृष्ठ सख्या-26 उपर्युक्त बालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम के पिछले बारह वर्षों के इतिहास

<sup>27</sup> वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

में वर्ष 1987-88 एवं वर्ष 1991-92 में कुल अधिप्राप्ति मूल्य में कमी ही आयी है। सबसे अधिक कमी वर्ष 1987-88 में रही जो कि 14 79 प्रतिशत थी। यद्यपि उसके अगले वर्ष में भी खरीद में केवल 97 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पार्यी है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि उसके अगले वर्ष 1988-89 में निगम ने अपनी कुल अधिप्राप्ति को गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक 39 97 प्रतिशत की वृद्धि अकित करायी। लगभग इसी प्रकारका सम्बन्ध वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 की वार्षिक खरीद वृद्धि में भी है। वर्ष 1991-92 की खरीद में 6 96 प्रतिशत की कमी आयी परन्तु वर्ष 1992-93 में इसमें 38 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्मरणीय है कि खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार द्वारा उत्पादन लागतों में वृद्धि को देखते हुए प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है यदि इस वृद्धि का कुल मूल्यात्मक खरीद की वार्षिक वृद्धि में समायोजनं किया जाय तो कुलमूल्यात्मक—खरीद वृद्धि काफी कम हो जायेगी। निम्न तालिका में रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वार्षिक वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका सख्या --12
रबी-फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि

खाद्यानन	1989-90	1990-91	वार्षिक वृद्धि	1993-94	1994-95	वार्षिक वृद्धि
गेहूँ	183	200	9 3%	350	360	2 9%
जौ	145	160	10 3%	275	285	3 6%
चेना	325	370	13 8%	640	670	4 7%
सरसौ	460	510	10 9%	810	830	2 5%

म्रोत. 1 इंग्डियन इकोनमी-अग्रवाल डी सी , साहित्य भवन, आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-274

2 प्रतियौगिता दर्पण-जनवरी, 1995, उपकार प्रकाशन, बीमानगर, आगरा-2, पृष्ठ सख्या-868

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 मे 1989-90 की तुलना मे वार्षिक वृद्धि तर वर्ष 1994-95 मे पूर्व वर्ष की तुलना मे वृद्धि दर से कम रही है। फिर भी समर्थन मूल्यों मे होने वाली प्रत्येक वृद्धि निगम की कुल मूल्यात्मक खरीद की वृद्धि मे आनुपातिक प्रभाव डालती है। अत खाद्यान्नों के कुल अधिप्राप्ति क्षा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत पाँच वर्षों मे खाद्यान्नों/वस्तुओं की कुल अधिप्राप्ति मात्रा को अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका संख्या 13 मे दर्शाया गया है। परम्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त किये जाने वाले खाद्यान्नों का अलग-अलग विश्लेषण अधिक समीचीन होगा जो कि इस प्रकार है-

1 गेहूँ की खरीद - तालिका सख्या 13 में दर्शायी गयी गेहूँ की अधिप्राप्ति को सन्तोषजनक

तालिका संख्या <del>-13</del> निगम द्वारा अधिप्राप्ति की कुल मात्रा

( दस लाख टनो में)

	वर्ष	गेहूँ	चावल	चीनी
, [	<b>1988-</b> 89	8 72	7 64	1 20
	1989 -90	8 58	11 05	1 44
	<b>1990-</b> 91	10 34	12 00	1 18
	1991 -92	8 61	9 56	1 23
	1902-93	9 58	11 73	1 26

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्ष 1990-91 की तुलना में गेहूँ की अधिप्राप्ति 1991-92 में 16 7 प्रतिशत कम हो गयी है। यद्यपि वर्ष 1992-93 में इससे पूर्व के वर्ष की तुलना में 9 7 लाख टन गेहूँ की खरीद में यृद्धि हुई परन्तु फिर भी यह वर्ष 1990-91 की तुलना में 7 6 लाख टन कम ही है। वर्ष 1990-91 में 102 2 लाख टन गेहूँ की खरीद की गई थी इसमें असम्बद्ध वैगनों से सम्बन्धित खरीद 1 2 लाख टन की यी। वर्ष 1990-91 की शुद्ध गेहूँ की अधिप्राप्ति में वर्ष 1989-90 की तुलना में 17 6 लाख टन की वृद्धि हुई। कुल अधिपाप्ति में से भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 29 10 प्रतिशत की अधिप्राप्ति की। शेष मात्रा की खरीद राज्य सरकारों शौर उनकी एजेन्सियों द्वारा की गई। राज्य सरकारों/ एजेन्सियों द्वारा जो भण्डार खरीदें गये उसे भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न चरणों में प्राप्त किये। निगम की वर्ष 1992-93 की खरीद में बृद्धि वर 11.3 प्रतिशत है। गेहूँ की राज्यवार खरीद की स्थित को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

### तालिका संख्या 14 राज्यवार गेहूँ की खरीद की स्थिति

(मात्रा टनो मे)

	ويست ويست ويسره ويست وينون وينهم والمناه والمناه والمناه والمناه والمائم والمائد المأول ويا		(साता दर्गा स)
क्रमं संख्या	राज्य	वर्ष 1990-91	वर्ष 1992-93
1	2	3	4
1	पजाब	62,58,955	47,40,014
2	हरियाणा	22,45,436	14,34,307
3	उत्तर प्रदेश	15,75,708	4,88,067
4	राजस्थान	1,34,929	22,291
5.	हिमाचल प्रवेश	1,065	_

1	2	3	4
6	मध्य प्रदेश	42	141
7	उनीसा	5	-
8	बिहार	an-	57
9	पांधे चमी बगाल		26
	महायोग	102, 16, 140	66,84,903

स्रोतं वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गेहूँ की खरीद में सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्य क्रमश पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश एव राजस्थान है। यद्यपि गेहूँ की अधिप्रान्ति मात्रा को बढाने के लिए सरकार ने वर्ष 1992-93 में प्रोत्साहन स्वरूप बोनस की घोषणा की थी परन्तु फिर भी कुल अधिप्राप्ति कम रही। गेहूँ की अधिप्राप्ति में कमी के कारण निम्नवत् है-

\* गेहूँ का बाजार भाव, सरकार द्वारा निश्चित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य एव प्रोत्साहन स्वंक्ष्प दिये जाने वाले बोनस दोनो को मिलाकर भी अधिक था जिससे किसानो को खरीद केन्द्र पर गेहूँ बेचनै से हानि हो रही थी।

\* किसानों ने भण्डारों को रोक लिया जिससे खुले बाजार में गेहूँ की आवक कम रही। इससे भी बाजार मूल्य उँचे बने रहे। इसके अतिरिक्त किसानों ने बाजार के बाहर भी अपने भण्डारोंको बेचा।

\* निजी व्यापारियों ने भी बडी मात्रा में अधिप्राप्ति की जिसके फलस्वरूप सरकारी खरीद केन्द्रों पर गैहूँ कंम पहुँचा ।

सम्भवत भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान वर्ष मे उक्त कारणो को ध्यान मे रखते हुए ही खरीव-कार्यक्रम बनाया है। इसके परिणामस्वरूप निगम तथा सरकारी एजेन्सियो ने तेजी से गेहूँ की अधिप्राप्ति को कार्य करते हुए 30 जून-1994 तक 118 37 लाख टन का स्तर प्राप्त कर लिया है, जो कि पिछले धर्ष हरी अवधि के दौरान अधिप्राप्त 127 52 लाख टन की मात्रा से धोड़ा सा कम है। कुल 124 34 लाख टन की बाजारआवक के 95 प्रतिशत भाग की अधिप्राप्ति की गयी, कुल अधिप्राप्ति मे भारतीय खाद्य निगम की हिस्सेवारी 25प्रतिशत रही। 28

2 चावल की खरीद — चावल की अधिप्राप्ति राज्य सरकारो द्वारा मिलो(चावल के उत्पादन) पर लेबी लगाकर की जाती है। लेवी का प्रतिशत अलग—अलग राज्यों में अलग—अलग होता है तथा उसका निर्धारण, भारत सरकार के परामर्श से राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार लेवी का प्रतिशत

<sup>28</sup> फूड क्षौर्प-जुलाई-सितम्बर, 1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग होता है, उसी प्रकार लेवी भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग किस्मों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। निम्नतालिका में कुछ प्रमुख राज्यों में चावल की अधिप्राप्ति का मूल्य दिखाया गया है-

तालिका संख्या 15 कुछ प्रमुख राज्यों में चावल की अधिप्राप्ति का निर्घारित मूल्य

andres severa coldide delete			वर्ष 199	90-91	वर्ष 1	992-93	
राज्य व	का नाम 	कामन	फाइन	सुपरफाइन	कामन	फाइन	सुपरफाइन
1 प	नाब	347 25	374 30	393 80	463 10	493 35	514 10
2 हरिय	गणा	347 25	374 55	394 10	463 45	494 00	514 45
3 उत	त्तर प्रवेश	327 65	342 75	365 90	441 30	456 50	482 35
4 आ	न्ध्र प्रवेश	330 70	345 90	369 25	<b>454 1</b> 5	469 90	485 65
5 मध	य प्रवेश	338 55	354 30	370 05	448 85	464 40	479 95
6 उई	गेसा	345 05	361 10	377 15	462 75	478 80	494 90
7 परि	रेचमी बंगाल	323 15	341 55	356 70	433 80	453 33	468 50
8 क	र्नाटक	322 20	337 15	352 10	432 45	447 45	462 40

म्रोतं वार्षिक प्रतिवेदन- 1990-91 एव 1992-93, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चावल अधिप्राप्ति का सर्वाधिक मूल्य दोनों वर्षों में सभी किस्मों हेतु हरियाणा राज्य के लिए तय किया गया है। द्वितीय स्थान पर पजाब तथा तृतीय स्थान पर उड़ीसा का निर्धारित मूल्य आता है। चतुर्थ स्थान वर्ष 1990-91 में मध्य प्रदेश का तथा वर्ष 1992-93 में आन्ध्र प्रदेश का आता है। श्रेणीवार मूल्यों में वर्षवार कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। कामन फाइन और सुपर्रफाइन मूल्यों के बीच जो अन्तर अलग-अलग राज्यों का है, उस अन्तर को प्राय समान ही रखा जाता है। वास्तव में इस मूल्यं का निर्धारण अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग जलवायु एव उत्पादन लागत की ध्याम में रखकर किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति की कुल मात्रा जो तालिका सख्या 13 में दर्शायी गयी है, में चावल की खरीद-मात्रा भी बहुत सन्तोषजनक नहीं रही है। यद्यपि वर्ष 1988-89 की सुला में वर्ष 1989-90 में 34 1 लाख टन की वृद्धि हुई जो 44 6 प्रतिशत रही, परन्तु अगले वर्ष अधिप्राप्ति में कैंबल 9 5 लाख देन ही नाम-मात्र की वृद्धि हुई। आगामी सभी वर्षों में चावल की अधिप्राप्ति इससे कम ही रही। यद्यपि वर्ष 1992-93 में चावल की कुल अधिप्राप्ति पुन बढ़कर 117 3 लाख टन हो गंगी। चावल की इस अधिप्राप्ति में कुछ गमुख राज्यों के योगदान को अग्राकित तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या -16 चावल की अधिप्राप्ति में कुछ प्रमुख राज्यों का योगदान

(मात्रा सौ टनो मे)

<u>'</u>	वर्ष 199	90-91	वर्ष 1992	-93
ज्य	<b>खारी</b> व	मिलिग के बाद प्राप्ति	खारी द	मिलिग के बाद प्राप्ति
पंजाब	27,410	17 614	38,961	10,365
आन्ध्रं प्रवेश	34 211	123	30,462	22
उत्तरं प्रवेश	13,226	9	11,768	_
हरियाणा	9,422	829	8,830	401
मध्य प्रवेश	5,589	1	6,234	-
उडीसा	2,552	gants.	3,509	_
कर्नाटक	1,574	-	1,093	~
पविचमी बगाल	1,132		1,751	custo

स्रोत वार्षिक प्रतिबैदन भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका अधिप्राप्ति के अवरोही कम में व्यवस्थित है। गेहूँ की तरह चावल की अधिप्राप्ति में भी पंजाब का ही योगदान सर्वीधिक रहता है। यद्यपि सीधी खरीद में आन्ध्र प्रदेश का सहयोग भी उल्लेखनीय है परन्तु मिलिंग के बाद चावल की प्राप्ति में पंजाब का योगदान 90 प्रतिशत से अधिक ही रहता है। चावल की अधिप्राप्ति विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्षों में हुई उपज, खपत एव समर्थन मूल्य तथा निगम की भण्डारण आवश्येकता के अनुसार घटती—बढती रहती है। उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त राजस्थान, असम, दिल्ली, मेहीराष्ट्र और तेमिलनाडु भी अधिप्राप्ति में सहयोग करते हैं, परन्तु इनका सहयोग महाराष्ट्र को छोड़कर 50,000 टन से कम ही रहता है। भारतीय खाद्य निगम की चावल— अधिप्राप्त की नवीनतम स्थिति का अवलोकन किया जाय तो खरीफ विपणन मौसम 1993—94 के दौरान चावल अधिप्राप्ति 140 87 लाख टम तक पहुँच गयी जो कि आज तक की सर्वाधिक मात्रा है, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 129 27 लाख हम चावल की अधिप्राप्ति हुई थी।

3. धाम की खरीद — निगम धान की अधिप्राप्ति भी मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत ही करता है, परिन्तु बड़ी मींगा मे धान की अधिप्राप्ति से उसके भण्डारण एवं मिलिंग में कई समस्याए आती हैं। इसलिए धान की खरीद निगम द्वारा बंडे पैमाने पर नहीं की जाती। चावल की तरह धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग—अलग राज्यों में भिन्न—भिन्न न होकर एक राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। परन्तु चावल की ही तरह धान का श्रेणीयन भी कामन, फाइन और सुपरफाइन तीन श्रेणियों में विभाजित कर न्यूनतम

मूल्य की घोषणा की जाती है। निम्न तालिका में गत वर्षों में धान का घोषित समर्थन मूल्य तथा अधिप्राप्ति की मात्रा दर्शायी गई है—

तालिका संख्या 17 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अधिप्राप्ति मात्रा

	मूल्यप्रति कुन्तल (रुपये मे)			मात्रा(दस हजार टेमो मे)	
वर्ष 	कामन	फाइन	सुपर फाइन		
1989-90	185	195	205	143	
1990-91	205	215	225	339	
1991-92	230	240	250	159	
1992-93	270	280	290	163	

मोतं वार्षिक प्रतिवैदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि धान के अधिप्राप्ति मूल्य मे श्रेणीवार 10 रुपये प्रति कुन्तल की दर से अन्तर रखा जाता है। यही अन्तर पूर्ववर्ती वर्षों में भी रहा है। धान के समर्थन मूल्यों में वृद्धि बंदती हुई दर से हो रही है। वर्ष 1990-91 में समर्थन मूल्य 20रु0, वर्ष 1991-92 में 25 रु0 तथा 1992-93 में 40 रु0 प्रति कुन्तल की दर से वृद्धि हुई। गेहूँ की तरह ही धान की अधिप्राप्ति मैं भी केवल कुंछ राज्यों का योगदान रहता है। पजाब, हरियाणा एव आन्ध्र प्रदेश ही मुख्य रूप से धान के अधिप्राप्ति में प्रमुख सहयोग कर्ता राज्य है और इसमें भी पजाब का भाग 90 प्रतिशत से अधिक रहता है। यद्यपि अशिक योगदान, तमिलनाडु, असम, उडीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी रहता है।

4 चीनी की अधिप्राप्ति — भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी के मूल्यो पर नियन्त्रण हेतु चीनी की अधिप्राप्ति वीनी मिलो पर लेवी लगाकर की जाती है। वर्तमान आदेशो के अनुसार चीनी मिले अपने कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत लेवी के रूप में बेचने के लिए बाध्य होती हैं तथा 60 प्रतिशत चीनी उन्हें खुले बाजार में बेचने की लिए छूट दी जाती है। चीनी के उत्पादन को बढावा देने के लिए त्यौद्यारों के दौरान किये गये उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग खुले बाजार में बेचने की छूट प्रदान की गयी हैं। निगम पहले की तरह वर्तमान समग्र में भी 12 राज्यों तथा 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में चीनी के वितरण हेतु चीनी की अधिप्राप्ति करता है। किसानों की गन्ना उत्पादन में रुचि को बढाने के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा घौषित किया जाता है। राज्य सरकार अपने—अपने राज्यों में अलग—अलग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती हैं, परन्तु ये मूल्य केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं हो सकते। इसी प्रकार राज्य की चीनों मिले राज्य सरकार घोषित गन्ना मूल्य से कम पर किसानों को गन्ना बेचने के लिए 19 किसानों के गन्ना बेचने के लिए 19 किसानों को गन्ना बेचने के लिए 19 किसानों को गन्ना बेचने के लिए 19 किसानों की गन्ना की गन्ना बेचने के लिए 19 किसानों की गन्ना वेसान वित्र की गन्ना वेसान व

बाध्य नहीं कर सकती। उनके द्वारा सरकार द्वारा घोषित मूल्य से अधिक मूल्य दिया जा सकता है। निम्नतालिका मे भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी की गत वर्षों कं। खरीदी गयी मात्रा एवं चुकता मूल्य दर्शाया गया है—

तालिका संख्या 18 निगम द्वारा अधिप्राप्त चीनी की मात्रा एवं मूल्य

वर्ष	मात्रा (दस लाख टनो में)	मूल्य(करोड रूपये मे)
1989 -90	1 44	832 80
1990-91	1 18	648 58
1991-92	1 23	717 21
1992-03	1 26	799 82

म्रोतं, वार्षिक प्रतिवेषन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई विल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 में वर्ष 1989-90 की तुलना में कंस खरीद की गई। पुन इसके बाद के वर्षों में खरीद की मात्रा में 50,000 टन तथा 30,000 टन की चृद्धि हुई। यही स्थिति कुल मूल्यात्मक अधिप्राप्ति में भी है। वर्ष 1991-92 की खरीद की मात्रात्मक वृद्धि दर की तुलना यदि वर्ष 1990-91 की मात्रा से की जाय तो यह वृद्धि 4 24 प्रतिशत है, परम्तु यदि इन्ही अधियों की खरीद की मूल्यात्मक तुलना करे तो मूल्यात्मक वृद्धि 10 58 प्रतिशत आती है। इसी प्रकार वर्ष 1992-93 में 91-92 की तुलना में मात्रा वृद्धि दर 2 44 प्रतिशत एव मूल्यात्मक वृद्धि दर 11.52 प्रतिशत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मात्रात्मक वृद्धि की तुलना में मूल्यात्मक वृद्धि की दर प्रत्येक वर्ष अधिक रहती है। इसका कारण खरीद मूल्य में लगातार वृद्धि होते रहना है। निगम द्वारा की गयी चीनी की अधिप्राप्ति का क्षेत्रवार सहयोग निम्न तालिका में अंकित किया गया है-

तालिका संख्या 19 चीनी की अधिप्राप्ति का राज्यवार विवरण

(मात्रा टनो मे)

राज्य	वर्ष 1990-91	वर्ष 1992-93
a nama anna agana namangangkatkanga kanga panga sama bana sama sama sama sama sama nama sama nama n	2	3
1 महाराष्ट्र	6,63,056	7,40,040
2 उत्तर प्रवेश	3,36,052	3,55,868
3. विद्यार	1,47,165	1,13,225
4. उड़ीसा	6,894	11,642
<b>5</b> तेमिलनाडु	3,589	9,036 क्रमश
	1 1 महाराष्ट्र 2 पंत्तर प्रवेश 3. बिहार 4. वंड्रीसा	1 2 1 महाराष्ट्र 6,63,056 2 उंत्तर प्रवेश 3,36,052 3. बिहार 1,47,165 4. उंड़ीसा 6,894

1			3
h	हरियाणा	4,337	3,265
7	असम	2,820	3,265
8	पश्चिमी बगाल	456	701
g	उत्तरी पूर्वी सीमान्त	प्रदेश 2,429	
<b>‡</b> 0	असम्बद्ध वैगन	15,123	24 268
و المنت بعلمة مائلة مدين معلق ينيون والله فعلم موجه موجو اللها ليون.	महायोग	11,81,921	12, 59, 863

स्रोत वार्षिक प्रतिवेतन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र का चीनी के कुल अधिप्राप्ति में सर्वाधिक योगदान रहता है जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष 55 प्रतिशत से अधिक भाग की प्रतिपूर्ति करता है। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है जो कुल अधिप्राप्ति का लगभग 28 प्रतिशत योगदान करता है। तृतीय स्थान बिहार का है जो वर्ष 1990-91 में 12 5 प्रतिशत तथा 1992-93 में 8 9 प्रतिशत का योगदान करता है। इस प्रकार ये तीनों राज्य कुल चीनी अधिप्राप्ति में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। वर्ष 1990-91 में तो इन तीमों राज्यों का योगदान 95 प्रतिशत है।

5 गोटे अनाज एव अन्य अधिप्राप्तियों — भारतीय खाद्य निगम गेहूँ, चावल, धान तथा चीनी के अतिरिक्त कुछ मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का एव चना तथा चना उत्पाद, दाले, जौ मूँगफली का गूदा, मैदा, पटसन तथा अन्य लघु उत्पाद जिसमें कुछ खाद्य उत्पाद तथा कुछ प्रक्रिया इकाइयों के लिए आवश्यक उत्पाद शामिल किये जाते हैं, की भी खरीद का कार्य करता है। मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा तथा मक्का क्या उत्पादन हरित क्रान्ति सें, और विशेष रूप से पिछले दशक में कम हो गया है, अत निगम द्वारा इसकी खरीदवारी भी कम हो गयी है। पिछले दशकों में इनकी खरीद मात्रा अधिक रहती थी। निम्न तालिका में मोटे अनाज तथा अन्य उत्पादों की खरीदी गई मात्रा को दर्शाया गया है—

तालिका संख्या -20 मोटे अनाज एव अन्य उत्पादो की अधिप्राप्तियाँ

(मात्रा टनों मे)

खाद्यान्न	प्रमुख राज्य	1980-81	1990-91	1992-93
चंगी	राजस्थान एवं हरियाणा	24,565		
वालैं	उ०प्र0 तथा मध्य प्रदेश	19,547	206	-
जी	विल्ली एव हरियाणा	6,627		***
ज्ञार	आन्ध्र प्रदेश एव राज0	7,677	808	4292
सबका	पूर्वोत्तर राज्य	119	000	721/21
लधुउत्पाव	आ प्र एवं तमिलनाडु	62	6271	2303
	चनी वा <b>णै</b> जी ज्यार सम्बन्ध	चनी राजस्थान एवं हरियाणा वाण उ०प्र० तथा मध्य प्रवेश जी विल्ली एव हरियाणा ज्यार आन्ध्र प्रवेश एव राज० मनका पूर्योत्तर राज्य	चनी राजस्थान एवं हरियाणा 24,565 वालें उ०प्र० तथा मध्य प्रदेश 19,547 जी विल्ली एव हरियाणा 6,627 जार आन्ध्र प्रदेश एव राज० 7,677 मनका पूर्वोत्तर राज्य 119	चनी राजस्थान एवं हरियाणा 24,565 वालें उ0प्र0 तथा मध्य प्रदेश 19,547 206 जी विल्ली एव हरियाणा 6,627 ज्ञार आन्ध्र प्रदेश एव राज0 7,677 808 मध्या पूर्योत्तर राज्य 119

तालिका सख्या 20 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम अब मैदा, बाजरा और मूँगफली का गूदा नहीं खरीदता है। तालिका में दिखाये गये अन्य लघु उत्पाद मिलिंग के बाद अधिप्राप्ति में शामिल किये जाते हैं। निगम जहाँ वर्ष 1980-81 में चना दाले और जौ की कुल खरीददारी 50 739 टन की करता था वर्ष 1990-91 में यह मात्रा घट कर 206 टन ही रह गयी और वर्ष 1992-93 में तो इन्हें बिल्कुल ही नहीं खरीदा गया। बाजरे की खरीददारी आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1979-80 में 56 84 टन की गयी थी परन्तु गोटे अनाजों में अब उसका अलग प्रतिनिधित्य समाप्त हो चुका है। वर्ष 1980-81 की मोटे अनाजों की सयुक्त गात्रा 7,796 टन की तुलना में वर्ष 1990-91 में केवल 10 4 प्रतिशत तथा 1992-93 में केवल 55 1 प्रतिशत मात्रा का क्रय किया गया। अन्य लघु उत्पादों में लगभग 5 राज्यों से अधिप्राप्ति की जाती है जिसका मात्रात्मक अवरोही क्रम इस प्रकार है- आन्ध्र प्रदेश तिमलनाहु, पजाब हिरियाणा और उत्तर प्रदेश।

2 बिकी एवं वितरण — आम जनता के कल्याण कार्य में जितना महत्व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली अधिपाप्ति का है, उसरों कही अधिक महत्व खाद्यान्नों का उचित समय पर, उचित मूल्य पर, उचित गात्रा में, उचित व्यक्ति अथया संस्था को उसकी बिक्री करना होता है। निगम द्वारा जो खाद्यान्न अधिप्राप्ति किये जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो खाद्यान्न आयातित किये जाते हैं, उनकी बिक्री अवथा वितरण का कार्य भी सुव्यवस्थित ढग से किया जाता है। बिना सुव्यवस्थित बिक्री के खरीदी गयी मात्रा का औचित्य सिद्ध मही होता। अधिप्राप्ति अथवा आयातित मात्रा की बिक्री का कार्य निगम विभिन्न माध्यमों से सम्मन्न करता है। निगम के बिक्री तथा वितरण कार्य की स्थित का विश्लेषण निम्न शीर्षकों के अधीन सुविधा पूर्वक किया जा सकता है—

1 <u>मदवार बिक्री</u> — निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं की, बिक्री को वर्षवार निम्न तालिका में दर्शीया गया है -

	तालि	का	सख्य	T 21	
निगम	द्वारा	की	गयी	गदवार	बिक्री

(दस लाख टनो मे)

 मवें	198	88-89	198	39-90	1990	)-91	199	1-92	199	92-93
 गेहूँ	8	95	7	73	8	89	10	79	8	05
चावलं	8	51	7	64	8	12	10	58	9	90
चीनी	1	29	1	30	1	23	1	25	1	21
उर्वरक	0	03	0	08	0	03	0	02	0	01
अन्य	0	01	0	01	0	01	0	01		-
चुत्रा मात्रा	18	79	16	76	18	28	22	65	19	17
कुल मूल्य (लाख क मे)	4752	35	4526	86	5492	24	7354	23	7487	19

अपर्गृत्त गिति का के अवलोक न से रपष्ट है कि लगभग सभी खाद्यान्नो/वस्तुओं की बिकी माना में, समय के साथ साथ उच्चावचन होता रहा है। वर्ष 1988-99 की गेहूँ की बिक्रीत मात्रा की तुलना यिव वर्ष 1992-93 की बिक्री से की जाय तो यह 5 तर्ष बाद 9 लाख टन कम ही हुई है जबिक वर्ष 1991-92 में गेहूँ सबसे अधिक, लगभग 107 9 लाख टन बेचा गया। समीक्षात्मक 5 वर्षों में सबसे कम गेहूँ की बिक्री 7/3 लाख टन वर्ष 1989-90 में रही। वर्ष 1992-93 में गेहूँ की आयातित एव देशा अधिपाप्ति दोनों की रार्वाधिक मात्रा 11 18 लाख टन महाराष्ट्र को बेची गयी जबिक दूसरा एव तीसरा स्थान रामस्यान एव पश्चिमी बगाल का रहा। इस विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि जो राज्य गेहूँ की अधिक्रामित्रा करते या बहुत कम करते हैं, उनकों गेहूँ की अधिक मात्रा आवाण्टित की जाती है साथ ही अधिक मात्रा उन्ही राज्यों को दी जाती है जहाँ गेहूँ की उपज कम होती है।

चावल की बिक्रीत मात्रा वर्ष 1988-89 की तुलना वर्ष 1992-93 में 13 9 लाख टन बढी है परन्तु फिर भी यह मात्रा वर्ष 1991-92 से 6 8 लाख टन कम है। समीक्षात्मक वर्षों में गेहूँ की तरह चावल की बिक्री भी वर्ष 1989-90 में सबसे कम केवल 76 4 लाख टन ही है। वर्ष 1992-93 में देशी अधिप्राप्ति से उपलब्ध चावल एव कुल चावल की सर्वाधिक बिक्री 18 92 लाख टन आन्ध्र प्रदेश को की गई। दूसरे स्थान पर केरल तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आन्ध्र प्रदेश चावल की अधिप्राप्ति में सहयोग करने वाला दूसरा बडा राज्य है और उसको ही सर्वाधिक चावल की बिक्री भी की गयी है। आयातित चावल की सर्वाधिक मात्रा वर्ष 1992-93 में कर्नाटक को 14,162 टम आविधित की गयी है।

तालिका संख्या 21 में चीनी की बिक्री को देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1988-89 तथा 89-90 की कुल बिक्रीत मात्रा में कोई विशेष अन्तर नहीं है, परन्तु बाद के तीनो वर्षों में बेची गयी चीनी की मात्राएं पहलें वर्षों की तुलना में कम है। वर्ष 1992-93 में चीनी की मात्रा तो समीक्षात्मक पाँचो वर्षों में सबसे कम केवल 12 1 लाख टन है। वर्ष 1992-93 में सर्वाधिक देशी चीनी का आवण्टन बिहार, पश्चिमी बगाल और उडीसा को किया गया जो क्रमश 4 29, 3 04 और 1 60 लाख टन था। सर्वाधिक आयातित चीनी का आवण्टन 1,224 टन मध्य प्रदेश को किया गया जो कि कुल आयातित चीनी का 53 प्रतिभात था। जबकि मध्य प्रदेश से चीनी की कोई अधिप्राप्ति नहीं होती।

भारतीय खाद्य निगम नियत प्रासंगिक खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत यूरिया(46 प्रतिशत नाइट्रोंजन) तथा डी ए पी अर्वरक की बिक्री भी करता है। वर्ष 1989-90 में वर्ष 92-93 की तुलना में 8 गुनी उर्वरकों की बिक्री की गयी। अन्य वस्तुओं में मैदा, चना उत्पाद, मूँगफली का गूदा जो

ज्वार, बाजरा, मक्का तथा अन्य खाद्य उत्पाद आते हैं जिनकी बिक्री/वितरण निगम सम्पन्न करता है परन्तु इसकी मात्रा नगण्य ही है। वर्ष 1992-93 में तो अन्य किसी भी वस्तु की बिक्री निगम द्वारा नहीं की गयी।

े खा गिल्ला की राज्यवार बिक्री - निगम राष्ट्रान्लों को उन राज्यों से अधिप्राप्त करता है जहाँ कि ने कम लागत में अधिक मात्रा में उत्पादित किये जाते हैं तथा उन राज्यों में उनकी बिक्री करता है, जहाँ वे या तोअपनी पाकृतिक विविधता के कारण उत्पादित ही नहीं किये जा सकते, अथवा उनके उत्पादन की लागत अधिक आती है। निगम विभिन्न खाद्यान्लों की बिक्री व्यवस्था सम्पूर्ण राष्ट्र को 24 क्षेत्रों में बॉटकर स्निष्टित्तत करता है। यद्यपि यह क्षेत्रीय विभाजन अधिकाश मामलों में राज्य की सीमाओं से ही निर्देशित होता है, परन्तु कुछ बन्दरगाहों को अतग क्षेत्र बनाया गया है तथा कुछ छोटे पूर्वोत्तर राज्यों को एक ही क्षेत्र में मिला दिया गया है। समस्त खाद्यान्लों जिसमें गेहूँ, चावल, धान, चीनी, दाले, मोटे अनाज तथा अन्य लघु उत्पाद आते है, की वर्ष 1990-91 तथा 1992-93 में की गयी राज्यवार बिक्री को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका सख्या 22 खाद्यान्नो का राज्यवार वितरण

(मात्रा सौ टनो मे)

क्रम सं	राज्य		वर्ष 1990-91	वर्ष 1992-93
1	महाराष्ट्र		1,983	1,908
}	पंश्चिमी बंगाल		1,886	1,576
3	केरल		1,853	2,086
ļ	आन्ध्र प्रदेश		1,677	2,039
5	तमिलनाडु		1,220	1 044
5	गुजरात		1,046	943
	विक्ली		1,018	1,028
	कर्मादक		996	1,080
	विश्वार		974	1,214
Q	उत्तर प्रवेश		907	949
	अन्य		4,694	5,293
		योग	18,254	19,160

म्रोतः वार्षिकं प्रतिवेदन -भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 में खाद्यान्नों की बिक्री में प्रथम, द्वितीय एव सृतीय स्थान रखने वाले राज्य क्रमश महाराष्ट्र, पश्चिमी बगाल और केरल रहे जबकि वर्ष 1992-93 में सर्वाधिक खाद्यान्नों की बिकी करने वाले राज्य क्रमण केरल आन्ध्र पदेश एवं गहाराष्ट्र है। इस प्रकार वर्ष 1990-91 में केरल तीसरे और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था जबिक वर्ष 1992-93 में केरल प्रथम एवं महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। स्पष्ट है कि खाद्यान्नों की बिक्री राज्यों की आवश्यकतानुसार घटती -बढ़ती रहती है। रााद्यान्नों की कुल बिक्री वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1992-93 में 906 सौं टा अधिक रही। तालिका से यह भी रपष्ट है कि दिल्ली को बेची गयी मात्रा में इन दो वर्षों के अन्तराल में सबसे कम उच्चावचन केवल 1000 टन खाद्यान्नों को वृद्धि के रूप में रहा।

- 3 <u>खाद्यान्तों की माध्यमवार बिक्री</u> भारतीय खाद्य निगम जिन वस्तुओं का विक्रय अथवा वितरण करता है वे विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ता तक पहुँचती है। निगम की माध्यमवार/योजनावार बिक्री निम्न प्रकार है -
- 3 1 शार्थ जिए वितरण प्रणाली निगम इसके माध्यम में अपनी अधिकाश बिक्री सम्पन्न करता है। विभिन्न राज्य सरकारो और सघ शासितो पदेशों को खाद्यान्न का माप्तिक आवण्टन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है तािक वे पूरे राज्य में उचित दर की दुकानों के माध्यम से उसका वितरण कर सकें। वर्ष 1992 से पूर्व पश्चिमी बगाल के कुछ जिलों तथा केरल में भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के एणेण्ट के रूप में वितरण कार्य कर रहा थीं। 1 अगस्त 1992 से पश्चिमी बगाल में खुदरा वितरण कार्य राज्य मरकार को सुपूर्व कर दिया गया। 6 निगम सम्पूर्ण देश में फैले अपने भण्डारण केन्द्रों में परिचालम, सभाल और भण्डारण कार्यों के दौरान आने वाली विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं को बावंजूद प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार बनाये रखता है। उत्तर—पूर्वी क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों सिहत दूर—दराज के क्षेत्रों, भीतरी इलाकों और जम्मू कश्मीर के उपद्रय ग्रस्त इलाकों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त भण्डार उपलब्ध कराकर नियमित पूर्ति सुनिश्चित करता है। विगत वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् जारी किये गये खाद्यान्नों की मात्रा को निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

तालिका संख्या 23 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी खाद्यान्नों की मात्रा

(दस लाख टनो मे)

खाद्यान्न/वग्तु	वर्ष 1990-91	वर्ष 91-92	वर्ष 92-93
1 गेह्रॅ	6 28	8 13	6 08
2 चावल	6 65	8 82	7 51
3 चीनी	1 19	1 25	1 21

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नमीक्षात्मक तीनो वर्षों मे 1991-92 मे गेहूँ, चावल तथा

<sup>30</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-1992-93, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-20

चीनी तीनो वस्तुओं की जारी की गयी मात्राए सर्वाधिक है। यद्यपि चावल एव चीनी की मात्रा वर्ष 1990-91 की तुलाना में 1992-93 में क्रमश 12 9 तथा 1 7 प्रतिशत बढ़ी है। ये मात्राए अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न मूल्यो पर जारी की जाती है। निम्न तालिका में वर्ष 1992-93 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हैतु निर्गित केन्द्रीय निर्गम मूल्य दशार्ये गये है-

तालिका राख्या 24 राार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(मूल्य रुपये प्रति कुन्तल)

乘	म स निर्गम अविधि	गेहूँ	चावल कागन	चावल फाइन	चावल सुपर फाइन	चीनी
1	दि 215 3 88 से 30 4 90	204	-	****	*	_
2	दि 1 5 90 से 27 12 91	234		-	-	Shares.
3	दि 25 । 89 से 24 6 90		244	304	325	Name .
4	दि 25 6 90 से 17 12 91	-	289	349	370	-
, <b>5</b>	दि 28 12 91से 10 1 93	280	377	437	458	-
6	वि 11 1 93 के बाद	330	437	497	518	
7	वि 22 1 92 से 16 2 93	-		***	-	690
8	दि 17 2 93 के बाद	-	-	-		830
-	and the first the tests which with the set of the form on the same was the set of the set	-				

म्रोतः वार्षिक प्रतिवदेन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

खंपर्युंक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पहले गेहूँ और चावल के मूल्यों में परिवर्तन अलग—अलग तिर्धियों को किया जाता था, परन्तु अब दोनो खाद्यान्नों के मूल्यों में परिवर्तन एक साथ ही किया जाता है। केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में परिवर्तन खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति लागत ढुलाई, भण्डारण तथा खाद्यान्नों के खुले बाजार में मूल्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन लागतों में से खाद्यान्नों पर सरकार से प्राप्त होने वाली सिन्सडी को हटाया जाता है। 27 दिसम्बर 1990 से पूर्व मूल्यों में जो सशीधन हुए उसमें गहुँ के मूल्य में 30 रुपये पित कुन्तल तथा चायल के सभी किस्मों में 45 रुपये प्रति कुन्तल की दर से वृद्धि की गयी। इसी प्रकार दिनोंकार 1 93 से गेहूँ के निर्गम मूल्यों में 50 रुपये तथा चायल के तीनों किस्मों के मूल्य में 60 रुपये प्रति कुन्तल की दर से वृद्धि की गयी। चायल के विभिन्स किस्मों में मूल्य परिवर्तन की दर समान ही रखी गयी है। चीनी के मूल्यों में एक वर्ष के अन्तराल में 140 रुपये प्रति कुन्तल की तुलनात्मक रूप में सर्वाधिक वृद्धि की गयी।

3 2 समन्यित आदिवासी विकास परियोजना/नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री - विसम्बर -1985 से शुरू की गयी इस योजना के अन्तर्गत समन्वित जनजातीय विकास परियोजना (आई टी डी पी )के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों और जनजाति बहुल राज्यों में लोगों को खाद्यान्न विशेष जनजातीय परियोजना गले सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे - नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, लक्षतिप, वादरा और नगर हवेली तथा असम के करबी अगलौंग और उत्तरी कछार के पहाडी जिलों को लाभ मिटा रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को गेहूँ और नावल की आपूर्ति निशेष रियायती दरों पर की जाती है। 31

ये जनजातीय क्षेत्र प्रधानमन्त्री द्वारा आरम्भ की गयी नई सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रणाली का उददेश्य न केवल इन इलाको के निर्धन लोगों को, बल्कि सूखा ग्रस्त व रेगिस्तानी सथा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों तक सार्वजिनक वितरण प्रणाली का लाभ पहुँचाना है। नई वितरण प्रणाली क अन्तर्गत लगभग 1700 चुने हुए क्षेत्रों/ खण्डों में वितरण के लिए 1 जून-1992 से खाद्यान्नों को विशेष अन्तर्ग समर्थित दरों पर जारी किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में गत वर्षों में समन्यित आदिगासी विकास परियोजना/नवीनीकृत सार्वजिनक वितरण प्रणाली के लिए विशेष अनुदान प्राप्त निर्गम मूल्य विये जा रहे हैं-

तालिका संख्या 25 आई टी डी पी /नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विशेष सहायतित निर्गम मूल्य ( मूल्य रूपये प्रति कुन्तल )

<b>弗 ゼ</b>	निर्गाम अवधि	गेहूँ	चावल कामन	चावल फाइन	चावल सुपर फाइन
1	वि 26 6 89 से 30 4 90	154	شده هشده میشد. منتب	order driver makes trickens december they was a second	ayya distan uluya ushak sakapatahin kalipatahin yang saka saka
2	वि 1 5 90 से 27 12 91	184		~~	
3	वि 25 1 89 से 24 6 90		194	254	275
4	वि. 25 6 90 से 27 12 91	-	239	299	320
5	वे 28 12 91 से 10 1 93	230	327	387	408
б (	वे. 11 1 93 के बाव	280	387	447	468

म्रोत वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि समन्वित आविवासी परियोजना के लिए निर्गम मूल्य के निर्धारण एव परिवर्तन में उसी नीति का अनुसरण किया जाता है जिसका कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य में, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत की जाने वाली बिक्री के मूल्य स्वितरण प्रणाली के अधीन की जाने वाली बिक्री के मूल्य से इसलिए कम होते है क्योंकि केन्द्र सरकार इस पी विशेष राज- सहायता प्रवान करती है। इसके परिणामस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत किये

<sup>31</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-439

जाने नारों मेहूँ ए। नावन की राभी किस्सों के विक्री मूल्य में 50 रुपये पित कुन्तल की दर से विशेष रिगायत है जाती है। आई टी डी पी के लिए विशेष सहार्यातन निर्गम मूल्य में 25 पैसे प्रति किलोग्राम की वर से राज्य रारकारों को यातायात और वितरण की लागत पूरी करने के लिए कीमत में जीड़ने के लिए विये जाते हैं। इस प्रकार 11 जनवरी 1993 में में रूपये > 90+ 25= 3 05 प्रति किलोग्राम तथा सामान्य किस्म का चावल रुपये 3 87 । 25 ±1 12 प्रांग किलोग्राम की दर से रियायती कीमत पर आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत की गई बिक्री को निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 26 समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत बिक्री (दम लाख टनो मे)

खाद्यान्न	वर्ष 1990-91	1991- 92	1992-93
गेहूँ	0 81	0 83	1 53
चावल	1 24	1 36	1 97

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत वितरण की जाने वाली मात्राए लगातार बढ़ रही है। अभी तो यह वितरण योजना देश के केवल 1700 ब्लाको में चल रही है, परन्तु हमीरे प्रधानमम्त्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1994 को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए इस मवीमीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 200 और ब्लाको में लागू करने की घोषणा की है। इस नयी सार्वजनिक गितरण प्रणाली का सचालन नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलो व सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय कर रहा है और खाद्य मन्त्रालय इसके परिचालन पर नजर रखता है।

3 3 पोषाहार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विक्री — हाल के वर्षों में रारकार के गिमिन्न विभाग ने पौष्टिक आहार के बारे में कुछ ऐरो तथ्यों का पता लगया है जिनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध लोगों के पौष्टिक आहार के स्तर से हैं और खाद्य विभाग के पौष्टिक आहार कार्यक्रमी का सम्बन्ध इसमें सुधार लाने से। इसके लिए ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय क्षेत्रों में पोषाहार के बारे में जानकारी देने के लिए 34 चलती—फिरती भोजन और पोषाहार प्रसार इकाईयों गठित की गई है। मन्त्रालय में कम खर्च वाले तैयार पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे—विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ इत्यादि को विकसित और उत्पादित करने की कार्य योजनाये शुरू की है, जिनका पयोग भोजन देने के लिए कार्यक्रमों और साधमहीन धर्ग के लोगों की पोषाहार जरूरतों को पूरा करने में किया जाता है। इसके लिए भारतीय खाद्य मिगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों पर खाद्यान्त उपलब्ध कराता है।

्सी पकार केन्द्र सरकार ने 28 अपैल 1089 से गागीण 1 में के 1 गए ए। नयो राजगार योजना " जागहर रोजगार योजना" के नाम से शुरू की है जिसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। इस योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व पचायतों को दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेसा से मीचे जीवन यापन करने वाल व्यक्तियों विशेष रूप से स्त्रियों तथा अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजानि के कागगारों की उनकी गजदूरी के बदले सस्ती दर पर खाद्यान्न वितरित किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत गितरित खाद्यान्नों का मूल्य भी सार्वजनिक वितरण पणाली के अधीन विनरित किये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य के बराबर होता है। वर्ष 1992–93 के लिए इस योजनान्तर्गत 2,556 करोड़ रुपये आविष्ठत कराकर 77 83 करोड़ श्रमदिवस के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया। भारतीय खाद्य निगम हारा इन दोनी योजनाओं के अधीन की गयी बिक्री की मात्रा को निम्न तालिका में परसूत किया गया है।

तालिका संख्या ~27 पोषाहार कार्यक्रम एव जवाहर रोजगार योजना के अधीन बिक्री (माना 10 लाख टनो मे)

-	Fight strong before determine the region of the party of the strong strong strong of the strong stro	a aliana manan talima, garan fahan shann salima amind orona, mulm slatiar matas serier serier serier	and the same same same same same same same sam
	योजना /खाद्यान्नं	वर्ष 1990-91	1092-93
Motor middle sphills where makes glass 600p can	पोषाहार कार्यक्रम–		
	। गेहूँ	0 04	0 55
	2 चायल	<b>भू</b> न्य	शून्य
	जयाहर रोजगार योजना-		
	L गेहूँ	नगण्य	1 73
	2 चावल	0 03	1 47
	योग	0 07	3 75
other styletic real play with pagent abbress	makes after some grades stated detailed before stated author orders also and allow strongs and author to a		

ग्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली उपर्युक्त तालिका से रपष्ट है कि पोषाहार कार्यक्रग तथा जवाहर रोजगार योजना दोनो के अभीन निगम ने अपनी बिक्री एक वर्ष के अन्तराल मे अलग-अलग क्रमश 13 एव 106 गुना बढा दी है।

3 4 खुली तथा सविदा बिक्री — भारतीय खाद्य निगम गेहूँ एव चावल के भण्डार की सुविधाजनक स्थिति एव पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए कभी—कभी खुली बिक्री का वर्ग्य भी करता है। जैसे धर्म— 1990 के आखिरी तिमाही में गेहूँ की सविदा बिक्री की गयी। मूल्यों में स्फीति की प्रवृत्ति को 32 भारतीय अर्थशास्त्र—मामोरिया एव जैन, साहित्य भवन आगरा—1995, पुण्ठ संख्या—39

रोकने के लिए देश गर में रोजर पतोर मिली ने उत्पादकों न्यापारिम भपर बामा आहि को भान सरकार धारी निर्धारित मृत्यों पर स्तुली बिक्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निरी की जाती है। यदि सार्यान्नों की स्तुली बिक्री को विभाग थालोंकन किया जाय तो जून 1991 मा सम्म निमातों के संस्कृत निमम ने खुली बिक्री के माध्यम से 4 06 लाख टा मेहूँ एन () 18 तास टा एका की बिक्री की। विन्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान मेहूँ, नावल दोनों के स्तुला बामार मृत्यों पर एसात्रण स्रमा व तिए उपाय स्वरूप भारतीय साद्य । एम ने स्तुली बिक्री की योजना के अन्तर्ग मेहूँ औं भावत है। कार एम मानों की बिक्री की।

गैर्ट ।। चावल की कीमतों के आंतरित राने गाजार में भिम्नों की तीमतों को उचित स्तर पर बनाय रखने के किए गारतीय खाद्य निगम कि बाजार के नीम की भी की माना भी जारी करता है। उपभोषताओं का उचित वर पर चीनी प्राप्त तो सके इसके लिए गुणि विकी और नीम चीनी का कोटा बढ़ाया जाता रहता है। इन्ही उपायों के गन्तर्गत खुली बिक्री और लेवी चीनी की गाना अगस्त 1991 से मार्च 1993 तक के लिए राज्य और कन्द्रशासित प्रदेशों हेतु 5 पतिशत की दर से बढ़ायी गयी। इसके अलावा सम्यों ओर केन्द्रशासित प्रदेशों को 1992 में उनके आवण्टा के अनुपात से एक नास्त दन अतिरिक्त लेवी चीनी वी गयी।

3 5 मुरक्षा विभाग को बिक्री — भारतीय खाद्य निगम भारत राग्कार द्वारा जारी आवण्टन आवेशों के अनुसार सुरक्षा विभाग को भी सार्वजनिक वितरण पणाली के मृत्य पर खाद्यान्नों का वितरण करता है। सुरक्षा विभाग में कार्यरत् व्यक्तियों को भी यूर-दराज के इता को में राट कर अपनी सेवाए प्रवान करनी होती है। अत उन्हें भी निगम द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है इसमें सुरक्षा सैवाओ, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को यह सुविधा प्रवान की जाती है। इन सेवाओ में निगम ने वर्ष 1990-91 में () , जारा उन खाद्यान्न( गेहूँ 0 09 साख दन और चावला 14 लाख दन) जारी किया। वर्ष 1992-93 में इस किया केन्द्रीय अवाय हत कुल 3 25 लाख हन खाद्यान्न जिसमें 1 24 लाख दन गेहूँ और 2 01 लाख दन चावत का आवण्टन किया गया।

3 6 प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत बिक्री - इस योजना के शन्तर्गत मुख्य रूप से यूरिया तथा डी ए पी एव कुछ अन्य उर्वरको की बिक्री की जाती है। यह बिक्री वास्तविक प्रासिंगक खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना एवं नियत प्रासिंगक खर्चा की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत की जाती है। वर्ष 1990-91 मैं इन दोनो योजनाओं के अन्तर्गत कुल 26,940 टन उर्वरक तथा 1992-93 मे 13,143

<sup>33</sup> फूड कोर्प- जुलाई-सितम्बर-1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन नई दिल्ली, पृष्ठ राख्या-()4

तम उर्वरक का निक्रम किया गया। वर्ष 1050 00 00-01 01 01 वर्ष 02-03 में कमण 12 98, 3 61 180 एउ 2 16 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरकों की बिकी की गयी। वर्ष 1902-05 में सर्वाधिक उर्वरक डी ए पी 6256 टन बेची गयी। यद्यपि वर्तमान समय में भारतीय खाद्य निगम दस योजना के अन्तर्गत देश के 15 क्षेत्रों में बिकी का कार्य कर रहा है परन्त पंजाब 17नार पंदेश वरियाणा और महाराष्ट्र में में रूप योजना के अन्तर्गत रहा है परन्त पंजाब 17नार पंदेश वरियाणा

3 7 जित्रण की नवीनतम स्थिति – जून, 1994 को समाप्त तिमाही के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्नों की राहज उपलब्धता को बनाये रखने के परिणामस्वरूप सभी योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों का उतान नीचा रहा। फिर भी भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर-पूर्वी अचल तथा जम्मू और कश्मीर में विभागों में वृद्धि करने के प्रयास में कोई शिथिलता नहीं बरती। अप्रैल से जून-1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुली बिक्री के अन्तर्गत खाद्यान्नों का कुल उठान 32 92 लाख टन था। इसमें खुली बिक्री के लिए 4 06 लाख टन गेहूँ के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण पणाली के तहत् जारी 10 14 लाख टन गेहूँ शामिल है। 1 जून 1994 से रबी फसल की शुक्त आत तथा नो गहूँ के अणडार की आवक के कारण खाद्यान्नों का उठान नीचा रहा 34

3 अपात निर्यात — आज विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हैं। 7 500 से भी अधिक वस्तुए लगभग 190 देशों को निर्यात की जाती हैं और 6000 से अधिक वस्तुए 140 देशों से आयात की जाती हैं। 35 भारतीय खाद्य निगम अपने द्विपक्षीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं बिक्री के साथ—साथ उनके आयात -निर्यात का कार्य भी करता है। यदि खाद्यान्नों की देशी अधिप्राप्ति से खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा नहीं हो पाती तो उसे गाँग एवं पूर्ति में सन्तुलन बनाये रखने के लिए, खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए तथा निगम की विभिन्न बिक्री योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों की उचित मात्रा जारी करने के लिए खाद्यान्नों का आयात करना पडता है। इसी प्रकार यदि देश में इनका उचित भण्डार सुविधाजनक स्थिति में हैं और इनकी पर्याप्त उपलब्धता बने रहने की पूरी सम्भावना है तो विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु तथा उत्पादकों में उत्पादन की अभिप्रेरणा बनाये रखने हेतु, विदेशी सहायता कार्यक्रम के रूप में अथवा अन्य उद्वेश्यों से खाद्यान्नों के निर्यात कार्य भी भारतीय खाद्य निगम सम्पन्न करता है।

1 आयात - वर्ष 1989-90 के दौरान उत्पादन अधिप्राप्ति के स्तर मे गिरावट आने तथा

<sup>34</sup> फूड कोर्प ज्लाई रिातम्बर, 1991, भारतीय खाद्य निगम बाराखम्बा लेन नई दिल्ली

<sup>35</sup> भारत-1993,सूनना एव प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पूष्ठ सख्या-541

अपने चावल भण्डारण की स्थित को देखते हुए निगम ने कुल 5 23 लाख टन चावल का आयात किया। इस आयात में 1 04 लाख टन चावल थाईलैण्ड से तथा 4 19 लाख टन वियतनाम से आयातित किया गया। वर्ष 1990-91 के दौरान किसी खाद्यान्न का आयात नहीं किया गया क्योंकि खाद्यान्नों के भण्डारण की स्थिति सन्तोषजनक थी। केवल ऋण की अदायगी के रूप में वियतनाम से 0 045 मिलियन टन चावल प्राप्त किया गया जो कि वर्ष 1980 में वियतनाम सरकार ने लिया था। वर्ष 1992-93 के दौरान भी उत्पादन अधिप्राप्ति में कमी के कारण भारत सरकार ने 29 90 लाख टन गेहूँ के आयात के लिए आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के साथ अनुबन्ध किया। इसी प्रकार 2 15 लाख टन चावल के आयात के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया गया। गेहूँ चावल दोनों का आयात माँग और पूर्ति के सन्तुलन को ठीक करने, खुले बाजार में मूल्यों को नियन्त्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति को बनाये रखने के लिए किये गये। इन अनुबन्धों के अधीन जो खाद्यान्न 31 मार्च, 1993 तक बन्दरगाहों पर पहुँच गये थे उनकी मात्रा को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका संख्या 28 वर्ष 1992-93 में आयातित खाद्यान्नों की 31 मार्च-93 तक प्राप्त मात्रा -(लाख टनों में)

 फ्र स	निर्यातक देश		खाद्यान्न	प्राप्त मात्रा
1	कनाडा		गेहूँ	10 27
2	आस्ट्रेलिया		गेहूँ	8 74
3	अमेरिका		गेहूँ	6 88
	*	योग		25 89
4	वियतनाम(वाणिज्यिक खरीद)		चावल	0 72
5	वियतनाम(वियतनाम सरकार द्वारा		चावल	0 28
	ऋण अदायगी पर देय ब्याज)	योग		1 00

म्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-1993, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-24

इस प्रकार से स्पष्ट है कि 31 मार्च, 1993 तक गेहूँ की मात्रा 4 01 लाख टन तथा चावल 1 15 लाख टन प्राप्त नहीं हो पाया था।

वर्ष 1990-91 तथा 1992-93 में खाद्य निगम द्वारा चीनी का आयात नहीं किया गया, परन्तु 1993-94 में चीनी की खपत एवं लेवी चीनी की अधिप्राप्ति की कमी को देखते हुए 13 मई, 1994 को मन्त्रिमण्डलीय सचिवों की बैठक में खाद्य सचिव को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चीनी ...

आयात करने का निर्देश मिला था जिसके अन्तर्गत निगम ने 16 मई 1994 को 700 करोड़ रूपये के चीनी के आयात हेतु गिविदा जारी की थी परन्तु 19 मई को अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने से कुछ ही घण्टे पहले खाद्य मन्त्री द्वारा इस निविदा को इसिलाए रव्द कर दिया गया क्योंकि वर्ष 1989 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयात की गयी चीनी के तथाकथित घोटाले की जाँच हेतु नियुक्त लोक लेखा समिति ने अपने पितिनेदन में रिपर्नारंश की थी कि भारतीय खाद्य निगम एव खाद्य मन्त्रालय चीनी का आयात न करे। यह कार्य भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम का है। अत वर्ष 1994 में चीनी की कमी के बानजूद निगम द्वारा चीनी का आयात नहीं किया गया। 36

2 निर्यात - वर्ष 1989-90 मे भारतीय खाद्य निगम ने अपने गेहूँ के भण्डारण की उचित स्थित कों देखते हुए 12000 टन गेहूँ का निर्यात वियतनाम को किया। इसी प्रकार वर्ष 1990-91 के वौरान निर्मम ने सोवियत संघ को उपहार के रूप मे 10,000 टन चावल का निर्यात भी किया। इसके अतिरिनंत 10 लाख टन गेहूँ बीरो मे भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम को निर्यात हैतु विया जाना था जिसकी सुपूर्दगी उन्हे की गयी। इसी वर्ष मे 575 टन खाद्य सामग्री जिसमे 383 टन चावल तथा 36 टन आयातित चीनी शामिल थी, जिसका मूल्य 56 56 लाख रुपये था राहत सामग्री के रूप मे जोर्डन को निर्यात की गयी। निगम द्वारा वर्ष 1991-92 मे एव 92-93 मे निर्यात किये गये खाद्यानमीं की मात्रा को निम्म तालिका मे दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 29 निगम द्वारा खाद्यान्नों के निर्यात की स्थिति

( लाख टनो मे)

Martin part of the filter again gives also also make an area. As a constraint annue and district and a				
वर्ष	खाद्यान्न	उपहार/सहायता	वाणिज्यिक	कुल
1991-92	गेहूँ		7 26	7 26
	चावल	0 17	0 31	0 48
1992-93	गेहूँ	-	0 12	0 12
(31दिसम्बर, 92 तक)	चावल	0 03	0 19	0 22

भीत भारत-1993, सूचेमा एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-439

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1991-92 में कुल 7 74 लाख टन खाद्यान्न तथा 1992 93 में 0 33 लाख टन खाद्यान्न दिसम्बर, 1992 तक निर्यात किया गया था। इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम अपने भण्डारण एव देश की खाद्यान्न स्थिति को देखते हुए खाद्यान्नों के निर्यात करने

<sup>36</sup> इपिश्रया दुडे-30 जून, 1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-49

अथवा न करने का निर्णय लेता है। वर्ष 1992-93 में विभिन्न देशों को किये गये निर्यात का विवरण निम्नवत् है-

11

\* पडोरी। वेशो के साथ मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए निगम ने नेपाल को गेहूँ के निर्यात का अनुबन्ध किया। पर अनुबन्ध खाद्य मन्त्रालय की ओर से 'नेपाल फूड कारपोरेशन के साथ रूपये 2800 प्रति टन की दर से 10 000 रन गेहूँ की बिक्री के लिए किया गया। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत नेपाल फूड कारपोरेशन में गेहूँ की 10,714 टन मात्रा की सुपुर्दगी प्राप्त की। इस अनुबन्ध में पिछले अनुबन्ध की बकाया मात्रा 930 टन भी शामिल है।

\* वर्ष के दौरान नेपाल फूड कारपोरेशन को रूपये 5840 प्रति टन की दर से सुपर फाइन चावल की 12,969 टन मात्रा की भी बिक्री की गयी।

\* समीक्षात्मक वर्ष मे क्यूबा को चावल का निर्यात किया गया। यह निर्यात अस्थिगित भुगतान के आधार पर किया गया। इसमे 10,068 टन सुपरफाइन चावल भेजा गया।

\* इस वर्ष में निगम ने सोवियत सघ को भी चावल को निर्यात किया। यह निर्यात भारत सरकार की ओर से राहत सहायता के रूप में किया गया। इस निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को सुंपरफाइन चावल की 3000 टन की मात्रा सुंपर की गयी।

\* विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से उपहार के रूप मे प्राप्त 20,266 टन गेहूँ की सभाल का काम भी मिगम ने किया।

इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो के आयात-निर्यात मे भारत सरकार की ओर से स्वय भाग लेकार इस कार्य को सम्पादित करने के साथ ही साथ वह राजकीय व्यापार मे सलग्न अन्य इकाइयो/ एजेन्सियों का सहयोग भी करता है।

- 4 भागंडार और भण्डारण भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नो के सुरक्षित भण्डार को बनाये रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह खाद्यान्न उत्पादन के समय खाद्यान्नो की खरीद भार उसे अपने भण्डार में सुरक्षित रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर समय—समय पर उसे उपभोक्ताओं के लिए मिमिन योजनाओं के अधीन भण्डार गृहों से विभिन्न राज्य सरकारों को निर्गत करता है। वह खाद्यान्नों के समय उपयोगिता में वृद्धि का कार्य निम्न प्रकार से करता है—
- 1 न्यूनतम भण्डार की सीमा को बनाये रखने में सहयोग भारत सरकार ने अपनी खाद्य मीति के तहत् खाद्याग्नों के एक निश्चित न्यूनतम भण्डार की सीमा वर्ष के विभिन्न तिथियों के लिए निर्भारित की है। इस न्यूनतम भण्डार सीमा को अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत किया गया है—

तालिका सख्या 30 सरकार द्वारा निर्घारित न्यूनतम भण्डार सीमा

(लाख टनो मे)

तिथि	गेहूँ	चावल	योग
1 अप्रैल	3 7	10 8	14 5
1 जुलाई	13 1	9 2	22 3
1 अक्तूबर	10 6	6 0	16 6
1 जनारी	7 7	7 7	15 4

म्रीत भारत -1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-438

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि खाद्यान्नों को न्यूनतम भण्डार एक सुविचारित नीति के तक्त किया गया है। 1अप्रैल को गेहूँ का न्यूनतम भण्डार 3 7 लाख टन निर्धारित है। जो कि अन्य सभी सीमाओं में भी न्यूनतम है, को इसलिए न्यूनतम रखा गया है कि क्योंकि मई में गेहूँ की नगी फसल आ जाती है। इसी पकार चावल की न्यूनतम भण्डारण सीमा 1 अक्टूबर को न्यूनतम रखी गयी है क्योंकि नवम्बर में धान की नयी फसल आने लगती है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल को जब गेहूँ का न्यूनतम भण्डार सबसे कम है उसी तिथि को चावल की न्यूनतम भण्डार सीमा सबसे अधिक है जबिक सम्पूर्ण भण्डार भी इसी तिथि को न्यूनतम रखा गया है। परन्तु तालिका में दी गयी खाद्यान्नों की ये मात्राएं न्यूनतम है।अत सवैव एक निर्धारित समय पर उस समय के लिए निर्धारित न्यूनतम भण्डार सीमा से भण्डार में रखा हुआ खाद्यान्नों कम नहीं होना चाहिए।निगम इन्हीं न्यूनतम मात्राओं को ध्यान में रखकर खरीद कार्य हैंतु समयबद्ध कार्यक्रम एवं लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा खाद्यान्नों के भण्डारण की मात्रा खाधा नीति द्वारा निर्धारित सीमा से सवैव अधिक बनाये रखने में सहयोग करता है।

2 <u>भण्डारण क्षमता</u> सार्वजनिक क्षेत्र की तीन एजेन्सियों विशाल पैमाने पर भण्डारण और भण्डारणार सुविधा उपलब्ध कराने में लगी है, ये है— भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और 16 राज्यों के राज्य भण्डारण निगम। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख एजेन्सी है। खाद्य निगम की कुल भण्डारण क्षमता उसके स्वयं के गोदामों तथा किराये के गौदामों से प्राप्त होती है। यह निगम सरकारों और निजी सस्थाओं जैसे अन्य स्रोतों से भी भण्डारण सुविधाए किराए पर लेता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं राज्य भण्डारण निगमों का मुख्य कार्य उपयुक्त स्थानों पर गोदाम लेना, बनाना तथा उनका कृषि उत्पादों, उर्वरको तथा कुछ अन्य सामानों के लिए प्रयोग करना है। सहकारी समितियों भी खलिहान एवं मण्डी स्तर पर गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराती है। भारतीय खांध निगम के अपने तथा किराये पर लिये गये गोदामों की भण्डारण क्षमता को अग्रीकित तालिका

तालिका संख्या 31 निगम की कुल भण्डारण क्षमता

(दस लाख टनो मे)

वर्ष/प्रकार	<b>4</b>	- अपनी		राष	 न्द्रीय/ न्य नेन्सिया	केर्न्द्र राज्य भण्ड निग	7 81	कृषि	पुनर्वित्त (स निगम	योग		महाय	ोग
1989-90	ढकी	11	94	0	52	2	19	2	94	5	65	17	59
	कैप	1	07					1	01	1	01	2	08
Author person minister seem belayage supelys	योग 	13	01	0	52	2	19	3	95	6	66	19	67
1990-91	ढकी	12	00	0	61	3	73	3	26	7	60	19	60
	कैप	1 (	04		_			1	47	1	47	2	51
	यौग	13 (	04	0	61	3	73	4	73	9	07	22	11
1991-94	इकी	11 9	94	0	62	2	69	3	02	6	33	18	27
	कैप	1 :	13	-	•	-	-		52	0	52	1	67
	योग	13 (	07	0	62	2	69	3	54	6	85	19	92
1992-93	ढकी	12 :	17	0	69	2	46	2	69	5	84	18	01
	कैप	1 :	11	-man			-		34		34	1	45
	योग	13 2	28	0	69	2	46	3	03	6	18	19	46
अगस्त-1994	ढकी											17	38
parties assess viceste como coposis bajdar dishar sejan	कैप		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		-						4	08
Manufacture annual review places (stabil) Spenny stability	योग			-								21	38

म्रोत वार्षिक प्रतिवेदन भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेम, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगम की अपनी तथा किराये की कुल भण्डार क्षमता वर्ष 1990-91 में सर्वाधिक रही। वर्ष 1992-93 में 1989-90 की तुलना में इसकी भण्डारण क्षमता 2 3 लाख टन बढ़ी है। समीक्षात्मक वर्षों में निगम की कुल भण्डारण क्षमता 21 8 लाख टन बढ़ी है। समीक्षात्मक वर्षों में निगम की कुल भण्डारण क्षमता 21 8 लाख टन बढ़ में स्पष्ट है कि भग्रतीय खांद्य निगम कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से सर्वाधिक किराये की भण्डार क्षमता प्राप्त करता

है। इसके बाद फेन्द्रीय एव राज्य भण्डारागार निगम तथा अन्त में केन्द्रीय एव राज्य की अन्य एजेन्सियों का स्थान आता है। निगम की अपनी भण्डार क्षमता उसकी कुल भण्डार क्षमता का 65 से 70 प्रतिशत तक है। यह औसतन अपनी कुल भण्डार क्षमता का 10 5 प्रतिशत भाग कैप भण्डार के रूप में व्यवस्थित करता है। फैप भण्डार की व्यवस्था या तो निगम स्वय करता है अथवा वह इसे कृषि पुनर्वित्न विकास निगम के माध्यम से पान्त करता है।

भारतीय द्याद्य निगम की स्वय की भण्डार क्षमता को बढाने के लिए अभी हाल में ही खाद्य राज्य मंत्री शी बी एस पाटिल सेसानुर ने कर्नाटक के हुबली जिले में 30 000 टन भण्डारण क्षमता बालें गोंवाम का शुभारम्भ किया। यह भण्डारण क्षमता जिले में खाद्य निगम की पहले से उपलब्ध 10 000 टम भण्डारण क्षमता के अतिरिक्त होगी। 37 इसी क्रम में खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए वी गोकाक ने जुलाई—1994 म उत्तरी कर्नाटक में स्थित बेल्लारी में 10,000 टन क्षमता वाले डिपोका उद्घाटन किया। इसकें अलावा 50,000 टन क्षमता वाले एक अन्य डिपो का निमार्ण भी शीघ्र पूरा होने वाला है। 38

3 भण्डारण की स्थिति — भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए भण्डारों को अपने पास रखता है। ये भण्डार निगम के सुपूर्व किये जाने तक राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों के पास भी रहते हैं। इन भण्डारों को सार्वजिनक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के लिए किये जाने वाले मासिक आवण्डान के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों को जारी किया जाता है। निगम का यह प्रयास हमेशा रहता है कि पूरे वैश में भण्डारों को उपलब्ध रखा जाय। विगत वर्षों में प्रत्येक 31 मार्च को केन्द्रीय पूल में भण्डारण की स्थिति को निम्न तालिका में वर्शीया गया है—

तालिका स**ख्या** 32 केन्द्रीय पूल मे भण्डारो की स्थिति

(दस लाख टनो मे)

वर्ष	गेहूँ	चावल	योग
198990	3 32	7 22	10 54
1990-91	5 38	10 76	16 14
1991-92	2 10	9 08	11 18
1992-93	3 13	10 02	13 15
जून−1994	17 71	14 79	<b>32</b> 50
जुलाई- 1994	16 97	12 73	29 70
अगस्त -1994	16 22	11 92	28 14

<sup>37</sup> पूड कॉर्प-जुलाई से सितम्बर-1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-5

<sup>38</sup> पूर्व कोर्प-अक्टूबर से दिसम्बर-1994, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली, पृष्ठ स0-5

तालिका सख्या 32 से स्पष्ट है कि वर्ष 1900-91 में केन्द्रीय पूल के भण्डार में चावल एवं गेहूँ मोनों की मात्राए समीक्षात्मक चारो वर्षों में सर्वाधिक रही हैं। भरपूर फसल के कारण वर्ष 1990-91 में खांधान्नों की भारी अधिप्रान्ति की गयी, परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के भण्डार की स्थिति में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 1991-97 में गेहूँ एव चावल के भण्डारण में क्रमश 22 8 एवं 6 8 लाख टन की कमी आयी। परन्तु वर्ष 1907 03 में पुन दोनों खाद्यान्नों के भण्डारण में क्रमश 49 1 तथा 10 4 लाख टन की वृद्धि के परिणामस्वरूप गेहूँ एवं चावल दोनों के भण्डारण में संयुक्त रूप से 17 6 प्रतिशत की वृद्धि वर्ज की गयी। गत वर्षों में लगातार भारी मात्रा में अधिप्राप्ति होने से भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के पास दिनोंक 1 6 94 को भण्डारों का स्तर 327 लाख टन था जो कि आज तक का सर्वोच्च स्तर है। पिंछला रिकार्ड दिनोंका 1 7 85 का 286 7 लाख टन था।

4 भण्डारण क्षमता के उपयोग की स्थित – वर्ष 1770 में पड़े अकाल के समय बिहार के लिए अमाज "कोठार" का कार्य करने हेतु सर्वप्रथम कैंप्टन जॉन गार्सिटन द्वारा बनवायी गयी 29 मीटर ऊँची इगारत के रूप में भारत में शुरू किया गया खाद्यान्न भण्डारण कार्य, अब बहुत प्रगति कर चुका है। आज पर्यम्परागत गोदामों में वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण, मशीनीकृत साइलों और खुले एवं ढके हुए भण्डारण में सुधार, ऐसी उपलब्धियों हैं, जो हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा प्रणाली में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। भारतीं खाद्य निगम के पास 31 जुलाई-1994 तक 216 6 लाख टन की भण्डार क्षमता थी इसके अतिरिक्त 30 4 लाख टम का कैंप भण्डार भी उपलब्ध था। इस प्रकार निगम की कुल भण्डार क्षमता 256 लाख हम थी। गत वर्षों में उपलब्ध भण्डार क्षमता के उपयोग की स्थित की निम्न तालिका में वर्शाया गयी है-

तालिका संख्या 33

	भण्डारण क्षर	ाता के उपयोग की स्थिति	(प्रतिशत मे		
मुर्ष	प्रकार	स्तर	31 मार्च को उपयोग स्थिति		
1989-90	ढकी	35 से 54	52		
	कैप ,	3 से 30	30		
1990-91	<u>कैप ,</u> ढकी	. 55 से 73	68		
	केप	26 से 77	41		
1991-92	ढकी	50ं से 70	60		
	कैप	31से 57	31		
1992-93	<u></u> ढकी	42 से 65	65		
	कैप	17 से 51	17		

मीतं वार्षिक प्रतिवेवन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

यद्यपि भण्डार स्थलों का उपयोग अधिप्राप्ति तथा उठान के आधार पर अलग-अलग समय अलग-अलग होता है और भारत सरकार द्वारा 31मार्च या 1 अप्रैल को ही वर्ष में न्यूनतम सुरक्षित भण्डार की न्यूनतम सीमा भी निर्धारित की गयी है। तालिका सख्या 33 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1992-93 मैं ढकी भण्डार क्षमता का प्रयोग वर्ष के दौरान सर्वाधिक 65 प्रतिषात का रहा है। यद्यपि 1989-90 मैं भी वर्ष के अन्त में ढकी भण्डार क्षमता के अधिकतम उपयोग स्तर से केवल 2 प्रतिशत ही कम रहा है। वर्ष 1989-90 में कैप भण्डार क्षमता का सर्वोच्च स्तर भी वर्ष के अन्त में उपयोग में लाया जा रहा था। वर्ष 1990-91 में ढकी एवं कैप दौनों भण्डारण क्षमताओं का प्रयोग स्तर समीक्षात्मक चारों वर्षों में रार्वाधिक रहा है, जो क्रमश 55 से 73 एवं 26 से 77 प्रतिशत है। तालिका सख्या 33 से यह भी स्मष्ट है कि कैप भण्डारण की तुलना में ढकी भण्डारण क्षमता का अधिक प्रयोग किया जाता है।

5 राज्यवार खाद्यान्न भण्डारण — खाद्यान्न भण्डारण में सहयोग करने वाले राज्यों की प्राथमिकता खाद्यान्न उत्पादन एवं उसकी अधिप्राप्ति में सहयोग करने वाले राज्यों के क्रम में ही है। निगम देशी तथा कैप दोनों भण्डारण क्षमताएं किराये पर भी प्राप्त करता है, परन्तु उत्तरी अंचल, उत्तर पूर्वी सीमान्त अंचल तथा पूर्वी अंचल में कैप भण्डारण क्षमताएं किराये पर लेने की न तो विशेष आवश्यकता महत्ती हैं और मही उसे प्राप्त किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमान्त अंचल तथा पूर्वी अंचल में निगम स्वयं अपनी भी कैप भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं करता। वहाँ केवल हकी भण्डारण क्षमता का उपयोग किया जाता है। निम्न तीलिका में खाद्यान्त भण्डारण में सहयोग करने वाले प्रमुख राज्यों को अकित किया गया है-

	तालिका	सख्या	34	
राज्यवार	खाद्यान्न	अपहार्ष	की	स्थिति

(दस इजार टनो मे)

41_ m		वर्ष1990-91				वर्ष <b>1</b> 992-93						
(क्य	अप	नी	कर्ष	र्क	3	ल	अप	नी	किरा	की	<u>कुर</u>	<u> </u>
र्पजार्थ	247	9	299	7	547	6	249	4	245	9	495	
उत्लर प्रवेश	159	5	110	4	269	9	164	9	62	9	227	8
गन्ध्र प्रवैधा	98	6	136	5	235	1	108	0	69	7	177	7
रियाणा	108	4	50	9	159	3	107	8	32	2	140	0
हाराष्ट्र	117	7	35	0	152	7	123	7	27	4	151	1
ध्य प्रवेश	86	6	48	1	134	7	80	2	25	1	105	3
जरात	36	2	39	4	75	6	36	7	32	6	69	

मौत गार्मिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उल्लेखींग है कि निगम खाद्यान्नों को किराये पर रखने की सुविधा केन्द्र एवं राज्य सरकार की एंजेन्सियों, केन्द्रीय एवं राज्य भण्डारागार निगम एवं कृषि पुनर्वित्त विकास निगम तथा निजी पार्टियों से प्राप्त करता है। तालिका संख्या 34 से स्पष्ट है कि समीक्षात्मक वर्षों में जो खाद्यान्न भण्डारित किये गये उनका सर्वाधक मात्रात्मक क्रम समान रहा है परन्तु चतुर्थ स्थान पर वर्ष 1992–93 में महाराष्ट्र की भण्डारित मात्रा आती है क्योंकि तुलनात्मक रूप में हरियाणा की मात्रा वर्ष 1990–91 में महाराष्ट्र से अधिक रही। यद्यपि निगम के सभी 24 क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षित रखे जाते हैं परन्तु प्रमुख भूगिका अदा करने वाले तालिका सख्या 34 में अकित केवल 8 राज्य ही है।

5 खुलाई कार्य उपभोकता के प्रति अपने दायित्वो का निर्वहन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम खाद्यानों की भारी मात्रा में दुलाई का कार्य करता है। खपत वाले विभिन्न राज्यों में भण्डार उपलब्ध कराने के लिए उत्पादक क्षेत्रों से भण्डार निकालने हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख एजेन्सी के रूप में यह निगम लगातार बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, खर्नरक, चीनी तथा अन्य वस्तुओं की दुलाई सम्पूर्ण देश में रेल अथवा सड़क के माध्यम से करता है। मंद्यिप सर्वधिक मात्रा रेल के माध्यम से ही स्थानान्तरित की जाती है। कुछ जरूरतमन्द राज्यों में विश्रीष क्षम से असम, पूर्वोत्तर राज्यों एव पूर्वी तथा केन्द्रीय राज्यों में उत्तरी क्षेत्र के राज्य मुख्य रूप से पंजाब, हिर्गणा और उत्तर प्रदेश से खाद्यान्नों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं को जारी करने हेतूं प्रेषित किया जाता है। मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे मामूली आधिक्य वाले राज्यों में भी चावल के परिचालन का कार्य किया जाता है। परिचालन की सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजना के कारण गत धर्म में खाद्यान्नों तथा चीनी के दुलाई की बढ़ती मात्रा को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गयी है।

तालिका संख्या. 35 खाद्यान्म तथा चीनी की परिचालित मात्रा का विवरण (दस लाख टनो मे)

1 1991-92	1992-93
4	5
3 9 97	8 94
1 4 69	4 02
6 2 35	2 07
7 93	71
0 -	1 38
4 17 94	17 12
4	17 94

1	2	3	1	5
योग लाया गया	15 00	16 64	17 '94	17 12
मिलो मे(लेवी चीनी)और बन्दरगाहो से(आयातित चीनी)	1 42	1 17	1 23	1 25
रेल मार्ग द्वारा कुल दुलाई	16 42	17 81	19 17	18 37
अन्य परिचालन-				
सडक मार्ग से मुख्यत पजाब, हरियाणा, उ०प्रंठ, म०प्रंठ, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, असम उ पू सीमान्त क्षेत्र और बन्दरगाहो से	0 76	0 64	0 71	1 75
निकटयर्ती राज्यो और नदी मार्ग से परिचा	21	0 03	0 01	0 03
महायोग	17 39	18 48	19 89	20 15

## स्रोत वाभिन्न प्रतिवेदम-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका में मध्य प्रदेश से खाद्यान्नों के परिचालन को वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में अन्य राज्यों से खाद्यान्न परिचालन में शामिल किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि केवल 1989-90 में 91 7 प्रतिशत बुलाई का कार्य रेलो द्वारा किया गया जबकि बाद के वर्षों में यह 96 प्रतिशत से अधिक रहा। केवल वर्ष 1992-93 में खाद्यान्नों की रेलो द्वारा दुलाई में कभी आने से रेलो द्वारा की गयी कुल दुलाई लगभग 4 प्रतिशत कम हो गयी है। निगम द्वारा की गयी समीक्षात्मक चारो वर्षों की दुलाई की कुल मान्ना लगातार बदती रही है जो क्रमश लगभग 11, 14 तथा 2 6 लाख टन प्रतिवर्ष बढी है। असम में करीमगज तथा पाण्डु एव कुछ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को कलकत्ता से अनाज पहुँचाने के लिए नदीं मार्ग का प्रयोग भी किया जाता है।

6 गुणवत्ता नियन्त्रण — खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय का भण्डारण और अनुसन्धान प्रभाग खाँखाम्म की खरीद के सम्बन्ध में एक जैसे मानदण्ड बनाने तथा इसके आयात निर्यात के तकनीकी पहलुओं के बारे में नीति सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए उत्तरदायी है। यह भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों को खाद्यान्न संरक्षण और गुणवत्ता के बारे में परामर्श देता है। इसके लिए केम्प्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, देशी तथा आयातित खाद्यान्न ओर उससे तैयार उत्पादों के नमूनों का विश्लेषण फरती है।

भारतीय खाद्य निगम देश भर मे फैली अपनी गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओ के माध्यम से अधिप्राप्त किये गये भण्डारो को गांरी होने तक उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने तथा परिरक्षण का कार्म करता है। खाद्यान्नों के भण्डारों का परिरक्षण उन्हें स्वस्थ एवं अच्छी दशा में बनाये रखने की कार्य निगम द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी गुणवत्ता नियन्त्रण अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। खाद्यान्नों के भण्डारों को अच्छी दशा में बनांगे रखने के लिए परिरक्षण हेतु रोग निरोध एवं उपचारणात्मक उपाय किये जाते हैं। निगम के पास वर्ष 1981 में ही 138 गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाए विभिन्न जिलों क्षेत्रों एवं मुख्यालयों पर स्थापित की गयी थी। खाद्यान्नों के नियमित रासायनिक विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में रासायनिक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गयी है। ये प्रयोगशालाएं उर्वरको सहित समस्त खाद्यान्नों के रासायनिक परिक्षण हेतु आवश्यक समस्त उपकरणों में सुसज्जित है। इन प्रयोगशालाओं में कार्यरत् व्यक्तियों को विश्लेष इत् से प्रिशिक्षत भी किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त शिकायती पत्रों को इन्हीं प्रयोगशालाओं में जाँम के आधार पर निस्तारित किया जात है।

### (द) निगम की अन्य गतिविधियो का मूल्यांकन -

1 चीनी मूल्य समानीकरण कोष -चीनी के मूल्यों में समानता बनाये रखने के लिए निगम भारत सरकार की आर से चीनी मूल्य समानीकरण कोष को बनाये रखता है। कम लागत वाले राज्यों में लेंबी चीनी के वितरण से होने वाली बचत की राशि इस कोष में जमा की जाती है। इसी कोष से अधिक लागत वाले राज्यों की हानि को भी पूरा किया जाता है। गत वर्षों में 31 मार्च, 1990, 91 92 तथा 1993 को इसमें क्रमण 60 77, 30 15, 250 06 तथा 363 40 करोड़ रुपये का कोष रेखा गया। इस प्रकार इस कोष में वर्ष 1990-91 में वर्ष 1989-90 की तुलना में 30 62 करोड़ रुपये की कमी आयी परन्तु उसके बाद ये कोष अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है और वर्ष 1992-93 में यह पूर्व वर्ष की तुलना में 113 34 करोड़ रुपये अधिक रहा। विगत वर्षों में कम लागत वाले राज्यों इस कोष हेतु वसूली एव ऊँची लागत वाले राज्यों को किये गये भुगतान निम्न तालिका में विखान में है-

तालिका स् चीनी मूल्य समानीकरण कोष हेतु वसूली,	तंख्या ३६ <b>भुगतान एवं स</b> म्प	पूर्ण घाटे की	स्थिति (करोः	डरूमे)
विवरण	वर्ष 1989-90	90-91	91-92	92-93
1 रिज्यू सरकारो/संघ शासित प्रदेशों से आधिक्य तथा निगम मूल्यों के अन्तर की वसूली	30 78	1 11	1 74	16 57
2 राज्य सरकारो/संघ शासित प्रदेशों को घाट की प्रतिगूर्ति	21 74	91 52	78 69	60 45
3 निगम को इस कार्य हेतु लेवी चीनी मे घाटा	101 67	146 79	120 89	68 90
4 निग्म को इस कार्य हेतु आयातित चीनी मे घाट	ग 42 33	9 22	1 80	1 12
5 निगम को इस कार्य में सम्पूर्ण घाटा	144 00	156 01	122 69	70 02

तालिका सर्या 36 के अवताकन से स्पष्ट है कि चीनी समानीकरण कोष की आवश्यक मात्रा के अनुसार ६राके वसूली एव भुगतान मे उच्चावचन होता रहा है। कम लागत वाले राज्यों से आधिक्य एवं निर्गम मूल्य के अन्तर से वसूली में तुलनात्मक रूप में अधिक उच्चावचन हुआ है जबिक ऊँची लागत वाले राज्यों को किये गये भुगतान में तुलनात्मक रूप में स्थिरता रही है। यद्यपि वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1992-93 में वसूली की राशि में 46 16 प्रतिशत की कमी तथा ऊँची लागत वाले राज्यों को किये गये भुगतान में 178 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

भारतीय खाघ निगम 12 राज्यो तथा 3 सघ शासित प्रदेशो— असम अरुणाचल प्रदेश, अडमान निकोबार शीप समूह बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप समूह मेघालय, मिजोरम, उडीसा, सिक्किम, पिश्चमी बगाल, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड मे लेवी चीनी के वितरण का कार्य करता है। इन राज्यों और सघ शासित प्रदेशों में चीनी की कमी को चीनी मूल्य समानीकरण कोष से पूरा किया जाता है। निगम को इसके कार्य हेतु वर्ष 1989–90 में 101 67 करोड रुपये का घाटा हुआ यह घाटा वर्ष 1990-91 में बढ़कर 146 79 करोड रुपये हो गया, परन्तु बाद के वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर कमी हुयी है और यह वर्ष 92–93 में 68 9 करोड रुपये तक कम हुआ है। निगम चीनी मूल्य समानीकरण कोष हेतु आयातित चीनी को उपयोग भी करता है। आयातित चीनी की सभाल से सम्बनिधत घाटे की मात्रा इस चीनी के उपयोग की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि सम्पूर्ण घाटे का अवलोकन किया जाय तो समीक्षात्मक चार वर्षों में इसमे पर्याप्त उच्चावचन रहा है। परन्तु 1989-90 की तुलना में 1992–93 में सम्मूर्ण घाटा 73 98 करोड रुपये घटा हुआ है जी 51 4 प्रतिशत कम है।

2 पंपभोक्ता जागक् कता कार्यक्रम - सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे भारतीय खाद्य निगम की भूमिका के भार में उपभोक्ताओं के बीच जागरू कता पैदा करने का कार्य जन सम्पर्क प्रभाग की कार्य सूची में संबंधिक स्थान पर है। यह कार्य गैर सरकारी उपभोक्ता सगठनो के सक्रिय सहयोग से किया जाता है, तािक उपभोक्ताओं को भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली एवं उनके अधिकारों से अवगत कराया जा सके। इस सम्बन्ध में रोचक कार्यशालाए आयोजित की जाती है। इसमें निगम के विभिन्न हिंपुओं से खाधान्त जारी करने के बाद अपनायी जाने वाली वितरण प्रणाली के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है। उन्हें निगम की वैज्ञानिक भण्डारण पद्धतियों और गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के प्रत्येक पहलू के भारे में जानकारी दी जाती है। इस कार्य हेतु व्यापक जन सम्पर्क किया जाता है। इसके लिए एक जन सम्पर्क नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार किया गया है जिसके माध्यम से निगम अपने कर्मन्तियों तथा व्यापक जनता के साथ दो स्तरों पर सूचनाओं के आदान—प्रदान का कार्य कर सके। उपभौक्ताओं को जागरूक करने हेतु निगम द्वारा कभी—कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

3 क्म्प्यूसीकरण एव मानवसंसाधन विकास - नेशनल इन्फार्मिक सेटर (एन आई सी ) के साथ सहगित ज्ञापन के निष्पादित हो जाने से सम्पूर्ण देश मे फैले विभिन्न जिला कार्यालयों तक भारतीय खाद्य निगम की सीधी पहुँच हो गयी है। निगम मुख्यालय, 5 आचिलक कार्यालयों, तथा 14 क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित आकड़ों के राग्रहण, मिलान और भण्डारण आदि से सम्बन्ध तथ्यपूर्ण सूचनाओं को निगम के कर्मचारियों द्वारा एन आई सी के सैटलाइट के माध्यम से सुवृद्ध संचार सुविधा हेतु अपने कम्यूटर नेटवर्क को और कुशल बनाया गया है। इसके सहयोग से पजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं। निगम अपने केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान तथा आचिलिक प्रशिक्षण सस्थानों में अपने अधिकारियों ओर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कक्षाए चलाने के साथ-साथ अपने विश्वठ कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न सस्थानों की सेवाओं का उपयोग करता है।

## (य) निगम की लाभदायकता का मूल्यांकन -

भारतीय खाघ निगम की लाभवायकता के मूल्याकन हैं। निगम के लाभ-हानि की स्थित को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मवो का विवरण अग्रपृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका सख्या 37 में दिया गया है। इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम के विगत 20 वर्षों के इतिहास में प्रथम बार वर्ष 1986—87 में हानि हुई जो 127 लाख रुपये की थीं। इससे पूर्व उसे वर्ष 1985—86 तक लगातार लाभ ही रहा था। यद्यपि इसमें पर्याप्त उच्चावचन रहा परन्तु फिर भी वर्ष 1984—85 का लाभ सर्वाधिक 261 लांख रुपये था।इसके बाव निगम को लगातार हानि हो रही है और वर्ष 1989—90 में यह अपनी चरम सीमा 1141 लाख रुपये तक पहुँच गयी थी। यद्यपि बाव के वर्ष में इसमें कमी आयी तथा वर्ष 1992—93 में निगम को पुन एक बार लगभग 164 लाख रुपये का लाभ हुआ।

उल्लेखनीय है कि निगम की बिक्री गत 20 वर्षों में 9 गुना तथा उपभोक्ता सहायता राशि लगभग 50 गुना बढ चुकी है। यदि कुल प्राप्तियों की तुलना की जाय तो इस अवधि में लगभग 13 गुना बढ़ी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस अनुपात में कुल उपभोक्ता सहायता राशि में वृद्धि की गयी उसकी आधी माना में भी बिक्री और कुल प्राप्ति को नहीं बढाया जा सका। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम का सकल लाभ गत 20 वर्षों में 20 गुना बढ़ा है परन्तु भाड़ा, सभाल व्यय, व्याज इत्यादि में तुलनात्मक रूप से अधिक बृद्धि हो जाने के कारण निगम को एक लम्बे समय से घाटे का सामना करना पड़ रहा है। घाटे

तालिका संख्या 37 निगम के लाभ हानि को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मदो का विवरण

(लाख रुपये मे)

					(419 (199 4)
विवरण	1992-93	1991-92	1990-91	1986-87	1971-72
बिक्री	7,48,719	7,35 423	5,49,224	5,20 236	81,051
उपभोक्ता संहायता राशि	3,88,974	3 63,713	2,86,276	2 26,996	7,806
कुल प्राप्ति	11,37,693	10,99,136	8,35,500	7,47,232	88,857
घटाया-निक्रय लागत	8,77,880	8,55,765	6,31,578	5,65 581	75,862
सकल लोभ	2,59,813	2,43 371	2,03,922	1,81,651	12,995
व्यय-भाडा	64,657	69 689	67,537	57 748	3,464
संभील व्यय	24,780	25,821	20,093	19,874	939
कर्मचारी पारि	58,317	36,386	34,762	17,180	2,031
ब्याज	90,857	89,817	62,968	65,059	4,126
मूल्य हास	3,589	3 793	3,371	2,174	284
अन्य	17,725	18,535	15,986	19,743	2,039
योग	2,59,925	2,44,043	2,04,717	1,81,778	12,883
कर से पूर्व लाभ/हानि	(-) 112	(-) 672	(-) 795	(-) 127	112
कर-व्यवस्था	paine	208	136		81
कर संमायोजन	276	_	-	editir	<u>(-) 10</u>
निवलं लाभ/मा नि	164	(-) 880	(-) 931	(-) 127	21

मौतं वार्षिकं प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

के मुख्य कारणो में गेहूँ, धान एव चावल की अधिप्राप्ति लागत मे वृद्धि तथा वितरण लागतो मे वृद्धि हो जाना भी है। येवि व्ययो मे हो रही वृद्धि की तुलनात्मक स्थितिका अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि कर्मचारी पारिश्रमिक ग सर्वाधिक वृद्धि 28 गुना रही है। जबिक अन्य व्ययो मे सभाल व्यय, ब्याज, भाडा मूक्य हास में वृद्धि वर्ष 1971–72 की तुलना मे वर्ष 92–93 मे क्रमश 26 गुना, 22 गुना, 18 6 गुना एवं 12 6 गुना हुई। इस प्रकार कुल व्यय 20 गुना बढा। अत निगम की लाभदायकता को सन्तोषजनक नहीं कहा जो सकता। इस परिस्थिति मे निगम को अपने सभी व्ययो को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। यदि हम धर्ष 1989–90 से वर्ष 1992–93 तक के प्रति कर्मचारी कारोबार पर वृष्टि डाले तो स्पष्ट होता है कि इसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए प्रति कर्मचारी कारोबार क्रमश 545,610,620 तथा 627 कुन्तल तक बढा, फिर भी वर्ष 92–93 मे निगम ने अपनी लाभदायकता को घनात्मक स्थिति मे पहुँचाकर एक सम्तोषजनक स्थिति प्रदान की है। यद्यपि इस लाभ मे गत वर्ष के कर के समायोजन का महत्वपूर्ण यौगवान है।

#### (र) कमियाँ -

लगभग 30 वर्षों पूर्व भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन खाद्य मन्त्री ने कहा था कि ' मेरा यह निगम सिद्ध करके विखलायेगा कि किसी निजी व्यापारी के मुनाफे की तुलना में कम मुनाफे पर खाद्यान्न का वितरण सम्भव है। ' इन तीस वर्षों में निगम ने यदि कुछ सिद्ध करके दिखाया है तो यह कि उसकी क्षुधा में निरन्तर वृद्धि हो रही है और उसकी उपगोगिता बढने के बजाय घरी है। <sup>39</sup> इस तथ्य का प्रमाण निगम के निम्न कमियों में वृष्टिगोचर होता है -

- 1 निगम के नियोजित पूँजी की तुलना में कुल कारोबार की स्थित सन्तोषजनक नहीं कुल कारोबार मैं निगम द्वारा की गयी कुल खरीद एवं बिक्री को शामिल किया जाता है। निगम का कुल कारोबार वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक लगभग स्थिर सा रहा जो 1986-87 में 10,939 5 करोड एवं 1989-90 में 11,239 99 करोड रूपये का था। 1989-90 में नियोजित पूँजी से इसके कुल कारोबार का अनुपत 3 1 का रहा जो घटकर 1990-91, 91-92 एवं 92-93 में 2 1 हो गया। निजी स्वामित्व के संस्थाओं मैं यह अनुपात 6 1 के ऊपर ही रहता है। इस प्रकार निगम के कुल कारोबार की स्थित को सन्तोषजनक नहीं कहाजा सकता।
- 2 निगम में निरंत्तर घाटे की स्थित भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1986-87 से निरन्तर घाटे का साम ना करना पड़ रहा था। घाटे के कई कारण रहे हैं, जैसे—मार्गस्थ हानियों में वृद्धि, पर्याप्त खरीव क्या ने ही पाना, गोवामी में सग्रहीत स्कन्ध की उचित देखभाल न हो पाना, माल की चोरी एवं नष्ट ही जामा, क्यमैंचारियों द्वारा स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर सही ढंग से अपने उत्तरवायित्वों का निर्वहन न करमा और किसानों का निगम के खरीद केन्द्रों पर अपनी उपज को बेचने में उत्साह म होना इत्यादि। यद्यपि निगम को दी जाने वाली उपभोक्ता सहायता राशि में पिछले 20 वर्षों में 50 गुनी वृद्धि की गयी परन्तु बिक्री केवल 9 2 गुना बढी व्ययों में सर्वाधिक वृद्धि कर्मचारी पारिश्रमिक में 28 गुना हुई। वर्तमान समय में गेहूँ की लागत 542 रुपये प्रति कुन्तल आती है। इस गेहूँ को 330 रुपये प्रति कुन्तल की दर से खरीदा जाता है। इसे 407 रुपये प्रति कुन्तल की दर पर बेचने के बाद भी खाद्य निगम को 135 रुपये प्रति कुन्तल की दर से होने वर से होने होती है।
- 3 मार्गस्थ हानियाँ एवं भण्डारण में कमी बहुत अधिक बडी मात्रा में खाद्यान्न की सभाल के समय अमिको द्वारा लोहे के हुको का प्रयोग करने से बोरो से खाद्यान्न निकलने, खाद्यान्न के परिचालन के समय वामी कै विखरने तथा निकासी आदि के समय खाद्यान्नो की छीजन और लम्बी अविध के भण्डारण

<sup>39</sup> नवभारत टाइम्स- नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1994

कै दौरान सबसे अधिक कमी खाद्यान्नों के सूखने के कारण होती है। इन कमियों से निगम को अत्यधिक उठानी पड़ती है। पिछरों वर्षों में मार्गस्थ हानियों एवं भण्डारण की कमी से होनी वाली हानि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

तालिका संख्या 38 मार्गस्थ तथा भण्डारण कमियाँ

वर्ष	मात्रा (दस लाख टनो मे)	मूल्य (करोड रुपये मे)	खरीद एव बिक्री के सन्दर्भ में कमी का प्रतिशत
1987-88	0 70	169 84	1 72
1988-89	0 42	113 90	1 25
1989-90	0 30	87 89	0 85
1990-91	0 46	155 98	1 17
1991 92	0 50	219 70	1 49
<b>1992</b> -93	0 50	223 33	1 28
मार्गस्थ कमी	0 35	149 73	1 65
भण्डारण कभी	0 15	73 60	0 38
योंग	0 50	223 33	1 28

म्नौत यार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

नोट उपर्युक्त तालिका में वर्ष 1992-93 की कुल मार्गस्थ कमी का प्रतिशत(1 65) की गणना खाद्य मिंगम द्वारा परिचालित कुल मात्रा एव भण्डारण कमी की गणना कुल जारी मात्रा पर की गयी है।

सालिका राख्या 38 के अवलोकन से रपष्ट होता है कि मात्रात्मक निरपेक्ष हानि की सर्वाधिक मात्रा वर्ष 1987-88 में 7 लाख टन की रही जिसका मूल्य 169 8 करोड़ रुपये था। मूल्यात्मक निरपेक्षा हानि संबंध अधिक 1992-93 में ही रही है। परन्तु यदि सापेक्षिक तुलना समीक्षात्मक छ वर्षों की, की जाय तौ प्रकट होता है कि खरीद एव बिक्री के सन्दर्भ में सर्वाधिक कमी वर्ष 1987-88 में 1 72 प्रतिशत रही जबकि सबसे कम हानि वर्ष 1989-90 में 85 प्रतिशत रही। वर्ष 1992-93 के दौरान हुई इस प्रकार की हानि से स्पष्ट होता है कि मार्गस्थ कमी भण्डारण कमी के लगभग दो गुने के बराबर होती है।

4 उपभोक्ता सहायताराशि में वृद्धि के बावजूद हानि — भारत सरकार समय-समय पर अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्य निर्धारित करती है। निगम खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति, भण्डारण, वितरण और परिचालन पर जी सम्पूर्ण क्य्य करता है वह खाद्यान्नो के निर्गम मूल्य से पूरा नहीं होता। लागत और निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति उपभोक्ता राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा की जाती है। सुरक्षित भण्डार बनाये

रखने का व्ययं भी भारत सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। गत् बीस वर्षों में उपभोक्ता सहायता एवं अन्य प्राप्तियों में लगभग 50 गुना वृद्धि की जाती है परन्तु फिर भी निगम का वित्तीय परिणाम निवल घाटे में जा रहा है।

5 लेवी चीनी एवं आयातित चीनी में घाटा — भारतीय खाद्य निगम को 12 राज्यों तथा तीन केंन्द्र शासित प्रदेशों में लेवी चीनी के संभाल का कार्य सौपा गया है। जब लेवी चीनी की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण हेतु पर्याप्त नहीं होती तो आयातित चीनी का भी प्रयोग वितरण हेतु किया जाता है। निगम को लेवी चीनी एवं आयातित चीनी दोनों के संभाल एवं वितरण में लगातार घाटा हो रहा है जिसे निम्म तालिका में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका संख्या 39 लेवी चीनी एव आयातित चीनी के कार्यकारी परिणाम

क्रस	विवरण	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
i	लेंबी चीनी के संभाल (बिक्री पर)प्रति कुन्तल व	98 25 त्र्यय	98 36	118 10	137 07
2	आयातित चीनी की संभाल(बिक्री) पर प्रति कुन्तल व्यय	167 48	172 36	53 96	457 76
3	कुल घाटा(करोड़ रु मे)	144 00	156 01	122 69	70 02

म्रोत, यार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि लेवी चीनी के संभाल(बिक्री) पर व्यय में प्रतिकृत्तलं उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यह वर्ष 1989-90 में रुपये 98 25 प्रति कृत्तल से बढ़कर 1992-93 में रुपये 137 07 प्रति कृत्तल पहुँच गया है। इसी प्रकार आयातित चीनी की सभाल लागत भी बढ़ी है। यहापि निगम द्वारा लेवी चीनी एवं आयातित चीनी के वितरण में मितव्ययिता बरती जा रही है जिससे कुल घाटे मैं कमी के प्रयास को सफलता मिली है। परन्तु फिर भी यह घाटा 1992-93 में 70 02 करोड़ रुपये का रहा, जो कि कम नहीं है।

6 निगग की भण्डारण लागत में वृद्धि — भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण लागत दिन—प्रतिदिन बंदती जा रहीं है। लागत में वृद्धि के प्रमुख कारणों में क्यांज दर में वृद्धि हो जाना, बड़ी मात्रा में खरीद के मारणों अधिक क्यांज, भण्डारण क्षमता का पूर्ण प्रयोग न होना तथा कभी—कभी भण्डारित वस्तु का क्षमांपेक्षित दीर्घकाल तक भण्डारगृह में पड़े रहना भी है। इन कारणों से संग्रहीत वस्तु की उपयोगिता मैं कगी के साथ—साथ उसकी भण्डारण लागत बढ़ती चली जाती है।

- 1 शासकीय निर्णयों में विलम्ब एवं विभिन्न मन्त्रालयों में तालमेल का अभाव आर्थिक मामलों में सही समय पर सही निर्णय लेना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। विलम्ब से लिये गये निर्णय की कोई उपयोगिता महीं होती। खाद्य निगम में आज भी अधिकारों के केन्द्रीयकरण की स्थित प्रतीत होती है। विभागीय अधिकारियों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव पाया जाता है। तभी तो खाद्य सचिव मीनी के आयात का तेण्डर निर्गत करते हैं तो खाद्य मन्त्री द्वारा उसे रद्द कर विया जाता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है जो कि वर्तमान समय में अलग—अलग मन्त्रालय के रूप में कार्य कर रहे हैं साथ ही साथ खाद्यान्नों के खरीद एवं वितरण से सम्बन्धित विभिन्न मामलें कृषि, बित्त एवं वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बद्ध होते हैं।विभिन्न मन्त्रालयों में ताल—मेल न होने के कारण कभी-कभी अलग—अलग मन्त्रालयअलग—अलगराग अलापते हैं,परिणामस्वरूप समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को असुविधा का साममा करना पडता है। वर्ष 1994 का चीनी सकट इस तालमेल के अभाव का एक ज्वलन्त उदाहरण है।
- 8 कृषि दशाओं में विभिन्नता के कारण निगम के कार्यों में अवरोध कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे वेश में उसके उत्पाद में काफी विभिन्नता रहती है। कही पर कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता है तथा कहीं पर बहुत कम। कृषि उत्पादन मानसून की दशा व प्रकृति पर आधारित होता है। बुरे समय में बाज़ार कैं। साध—साथ सरकारी या निगम के खरीद केन्द्रों पर पर्याप्त उपज नहीं पहुँचती जबिक इसी अविध में सार्थजिनिक वितरण प्रणाली पर भी जनता का दबाव बढता है। निगम के कार्य में कठिनाई उत्पादन, यातायात एवं परिवहन के साधन की कमी के कारण भी उत्पन्न होती है। कम उत्पादन तथा आवश्यकतानुसार परिवहन, संचार एवं राग्रहण के साधनों की अनुपलब्धता की दशा में निगम को अपने कार्यों के सुचार सचालन में कठिनाई का ज्ञामना करना पडता है।
- 9 समय व स्थान सुपूर्वगी की समस्या भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के व्यापार में एक मात्र एजेन्सी के रूप में काम करता है तथा केन्द्रीय गोवामों के अनुरूप सम्पूर्ण देश में उचित समय व उचित स्थान पर वस्तुओं को उपलब्ध कराता है जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग के हित में उसकी उपादेयता सिद्ध हो सके। निगम वस्तुओं की सुपूर्वगी, उचित समय व उचित स्थान पर करने के लिए वचनबद्ध होता है परन्तु कभी—कभी स्थानीय समस्याओं जैसे— श्रीमक समस्या, रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता आदि के कारण यह कार्य सम्भव महीं हो पाता जिससे उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। इन समस्याओं के कारण निगम को पूर्विमिनीरित प्रक्रिया एवं गाध्यम में परिवर्तन करना पडता है ताकि समयानुसार कार्यों को पूरा किया जा सके। इसहै निगम के व्यय अमार्थिक इप से बढ जाते है।

वंस्तुओं को उचित संगय एवं उचित स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए निगम को अन्य विभागो एवं निगमीं कै ऊपर आश्रित होना पड़ता है, जैसे— बन्दरगह, रेलवे, राज्य प्रशासन, केन्द्रीय भण्डारण निगम। इनके ऊपर भारतीय खाद्य निगम का किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता जिससे कि वह खाद्य निगम की सहायता से ही अपना कार्य चला सके।

- 10 किस्म की विभिन्नता से उत्पन्न संमस्याए केन्द्रीय भण्डारो व गोदामो मे एकत्रित किये गये खाद्यान्नो की किस्म गैं विभिन्नता होती है। विभिन्नता के कारण रोग्रहण का समय, स्थान, प्रमाप एव सग्रहण की विधि में विभिन्नता होती है, जब उन्हें केन्द्रीकृत रूप मे एकत्रित किया जाता है तो खाद्यान्नो की श्रेणीवार एकरूपता भी नही आ सकती। उपभोक्ता का मनोविज्ञान होता है कि वह अच्छी किस्म व एक ही प्रकार की किस्म की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार प्रमुख समस्या यह है कि निगम सबको खाद्यान्न की पूर्ति तो करा सकता है परन्तु सबको सन्तुष्ट नहीं कर सकता।
- 11 वजन या तौल से सम्बन्धित समस्याए अनाज की अधिप्राप्ति एव निकासी दोनो समयो पर तौल से सम्बन्धित समस्याए उत्पन्न होती है।अधिकांश किसानो का आरोप होता है कि खाद्यान्नो की खरीद तौल वास्तविक तौल मे अधिक की जा रही है इसके साथ ही उनका आरोप यह भी होता है कि उनकी विक्रीत वस्तु को उचित श्रेणी का नहीं माना गया है जिससे उनको कम मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। क्योंकि निगम को बड़ी मात्रा में खरीद एवं विक्रय करना होता है जिसमें प्रत्येक बोरे की तौल असुविधा जनक होती है। 10 बोरो की तौल के औसत के अनुसार निकासी का कार्य किया जाता है। इससे तौल में पूर्ण एकक्षिपता आना असम्भव हो जाती है।
- 12 <u>कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की वृद्धि एवं क्षभिप्रेरणा का अभाव</u> कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के मामलीं की रहस्योद्धाटन समाचार पत्रों में प्राय प्रकाशित होता रहता है। एक ऐसा ही समाचार नवभारत टाइम्स्(मेर्ड क्रिक्ली) के 23 जनवरी 1994 के अक में प्रकाशित हुआ जिसमें गेहूँ एवं चावल से लंदे 900 द्रकों के लांपता होने की बात कही गयी है। कागजों पर इन ट्रकों की रवानगी दर्ज की गयी है पर माल कहाँ उतार लिया गया इसे बताने को कोई तैयार नहीं, जिसका मूल्य लगभग सवा तीन करोड़ रुपये है।

अनाज से भरे ये द्रक एक दिन में लापता नहीं हुए। लापता होने का यह सिलसिला करीब एक हैंद्र साल से जारी था, अनुमान है कि अधिसख्यक द्रकों को जम्मू—श्रीनगर मार्ग पर कहीं अपहरण कर लिया गया। बहुतेर ट्रक बीच से ही अपहरण कर लिये गये ऐसी घटनाओं को आतकवाद के नाम पर रफा—दफा कर दिया गया। कुछ ऐसी घटनाए भी जानकारी में आयी है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की साठ—गाठ से बहुतेर ट्रक राज्य सरकार के गोदामों में तो पहुँच जाते हैं, मगर आमद दर्ज नहीं होती। भारतीय खाद्य निगम का अनाज जम्मू तक रेल मार्ग से जाता है। आगे की सप्लाई ट्रकों से की जाती है। जम्मू से आगे इनका कथित अपहरण कर लिया जाता है। खाद्य निगम के कर्मचारियों का जबाव होता है— हमने तो माल रवाना कर दिया। हमारे रिजस्टर में रवानगी दर्ज है, आगे हम क्या करें? गोदामों में हजारों टन गल्ला सड जाता है।

लाखों टन गेहूँ और चावल को "सी"और "डी" श्रेणी का घोषित कर दिया जाता है तािक उसे औने—पोने, गिद्दी के भाय गीलाग िम्या जा सके। वे गोवाम जिसमे नया स्टॉक रखना होता है फटे—पुराने बोरो, सडी गली तिरपाला और लकड़ी के टूटेफूटे ब्रेकटों से भरा रहता है। कई—कई वर्ष तक बोरे पलटे नहीं जाते, दवाइयों का छिड़ काव तो दूर की बात है। पैसे की ताकत पर "सी" और "डी" श्रेणी के अनाज को "ए" और "बी" श्रेणी का बना दिया जाता है। वजन अधिक करने के लिए मिट्टी और रोडी मिलायी जाती है। चावल में नमीं 17—18 प्रतिशत तक ही मान्य है पर पैसा उसे 25 प्रतिशत तक खीच देता है। बाद में वही चावल सुख़ कर तीन—चौथाई रह जाता है। इस प्रकार निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा, कर्त व्यक्ति एवं ईमानवारी पर सन्देह व्यक्त किया जाता है और वे अपने कार्य के प्रति अभिप्रेरित नहीं होते।

#### (लं) सुझाव -

प्रो० भगवती ने खाद्य निगम की आलोचना करते हुए अपने अध्ययन में इसके विघटन का सुझाव दिया है और राज्य के समाजवादी सकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प के रूप में निर्धन परिवारों में पूष्ट स्टाम्प बॉटने की एक योजना का सुझाव भी दिया है जिससे उन्हें आवश्यक क्स्तुए खरीदने में कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। यह सुझाव अमेरिका में निर्धन परिवारों को दिये जाने वाले कूपन के समान है। 40 मेरे विचार से निगम के विघटन की कोई आवश्यकता नहीं है केवल कुछ सुझावों का अनुपालन कर निगम को पुन देश की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है जिससे यह निगम उदारीकरण एवं वैश्विकीकरण को पूरा लाभ उठा सकता है। निगम की कमियों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं—

\* यद्यपि भारतीय खांद्य निगम की स्थापना सामाजिक कल्याण में वृद्धि के उद्देश्य से की गई थी परम्तुं धर्तमाम प्रतियोगिता एवं खुलेपन के युग में इस अपने विकास एवं विस्तार हेतु संसाधन प्राप्त करने तथा समाज का अपनी सेवाए प्रदान करने में निरम्तरता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि निगम भी व्यापारिक सिद्धान्ती के अनुसार सेवा के साथ—साथ कुछ लाभ प्राप्ति की भावना से अपने कार्यों का निष्पादन करें।

\* भारतीय निजी कम्पनियाँ अपनी विनियोजित पूँजी पर 15 से 20 प्रतिशत का प्रत्याय प्राप्त कर लेती है। ऐसी स्थित मे भारतीय खाद्य निगम को 6-7 प्रतिशन की न्यूनतम प्रत्याय दर के लक्ष्य को ध्याम मे रखनार निक्री मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए साथ ही साथ इसके विभिन्न व्ययों पर मिश्निया भी किया जाना चाहिए। निगम का कर्मचारी पारिश्रमिक पर व्यय सबसे अधिक बढ़ा है। इन व्ययों में क्रमी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृह्ति योजना को और आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे दीर्घ काल मैं स्थापना क्रमण को कम किया जा सके तथा प्रति कर्मचारी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। यद्यपि इस

An महाशीरत टाइम्स - नई दिल्ली. 21 अप्रैल 1994

उपायं से त्रात्कालिक व्ययं बढ़ेगे, परन्तु निगम की दीर्घकालीन लाभदायकता को बढ़ाया जा सकेगा।

- \* निगम की मार्गस्थ हानि एवं भण्डारण-कमी से होने वाली हानि को नियन्त्रित किया जाना चीहिए। भण्डारण एव परिचालन के समय हानि एक ऐसा विषय है जिस पर राबसे अधिक चर्चा कीजाती है। वार तथ् में इस पर अभिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि निगम ने अत्यधिक रख-रखाव और विविध प्रकार के जिटिल कार्यों के बीच भी निगम ने इन हानियों को नियन्त्रित करने के कई उपाय किये हैं, जिन्हें अनदेखा मही किया जा सकता, किन्तु इन्हें क्रमाश और कम करने के लिए निम्न अच्छे उपायों के अनुपालन की अपेक्षा है-
- -- मार्गस्थ हानियों को कम करने तथा खाद्यान्नों की परिवहन लागत को न्यूनतम रखने हेतु आवश्यक हैं कि यथाराम्भव सीमाओं तक रेल-परिवहन का उपयोग किया जाय।
- -- मारा की छीजन को रोकने अथवा कम करने के लिए **बोरो** को **लादने** एव उतारने में मशीमों का उ<sup>1</sup>।योग किया जाय।
  - -- हुको के प्रयोग को केवल विशेष परिस्थिति मे ही अनुमति दी जाय।
- -- मार्गस्थ हानियों को नियन्त्रित करने के लिए निगम को अधिप्राप्ति के समय विनिर्देशनो को कड़ाई से लागू करना चाहिए तथा बोरों की सिलाई केवल मशीन से की जानी चाहिए।
- -- निगम के खाद्यान्न गोदामों से खाद्यान्न निर्गमन हेतु फीफो विधि का ही प्रयोग करना चाहिए जिसमें पहुंचों प्राप्त खाद्यान्नों का पहले निर्गमन किये जाने से खाद्यान्नों को सडने-गलने से होने वाली हानि से अचीमा जो सकैगा।
- -- भण्डारण प्रबन्ध इस तरह से किया जाय कि कैप भण्डारण के अन्तर्गत केवल मोटे अनाजो को छोइकर भावल एव गेहूँ जैसे खाद्यान्नों को न रखना पड़े।
- -- खाद्य निगम द्वारा विये जाने वाले व्यय विवरणो को यथावत् स्वीकार न किया जाय बल्कि स्वीकृत मामनौ के आधार पर निगम के वास्तविक व्ययो का अनुमान लगाया जाय।
- -- ट्रकों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले खाद्यान्नों के पहुँच को सुनिश्चित किया जाय तथा आतंक्षवादी, सर्राई एव दुर्गम क्षेत्रों में अनाज की आवा-जाही के लिए ट्रकों के साथ-साथ सुरक्षा गार्डों को भी रखा जाय और ट्रकों को केवल काफिलों में ही चलने की अनुमित दी जाय।
- \* किसानों को सरकारी खरीद केन्द्रों पर अपनी उपनों को बेचने के लिए प्रीत्साहित करने हेतु सरकारी खरीब मूल्यों की मोषणा उस फसल की बुआई के समय ही कर देनी चाहिए। इससे कृषक अपनी फसलें सरकारी खरीद केन्द्रों पर बेचने की योजनानुसार कार्य करेंगे। उपनों के न्यूनतम मूल्यों के निर्धारण में सरकारी पाणी पर कृषि उपनों की आने वाली लागतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा किसी भी लागत की अनुमान के आधार पर मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

\* कृषि उत्पादको को उनकी उपज का समृचित मूल्य प्रवान करने, के साथ ही साथ खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि जो खाद्यान्न खरीदा जा रहा है वह निर्धारित कोटे एव गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इस प्रकार निगम का लक्ष्य ' गुणवत्ता वाले अनाजो की अधिकाधिक खरीद' होना चाहिए, क्षवल मात्रा-लक्ष्यप्राप्तकरने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। इस कार्य में अधिकारियों को " आप ऐसा करे" के स्थान पर "आओ हम सब मिलकर ऐसा करे" पर जोर देना चाहिए। खरीद के समय मान्य सीमा की नमी को ही स्वीकार किया जाय जैसे चावल के सन्दर्भ में अधिकतम 17-18 प्रतिशत। इससे भण्डारण में सूखने से होने वाली अत्यधिक हानि को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

\* निगम के अपने गोदाम तथा अन्य खाद्यान्न— गोदाम जी मिंगम किराये पर प्राप्त करता है, का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का स्कन्ध,स्थन्ध-बही के अनुसार न होना, खाद्यान्नों का सड़ या गल जाना, बोरों एवं तिरपालों का सड़ जाना, दबाह्यों का छिड़काव समय से न हो पाना इत्यादि समस्याओं का निदान भौतिक सत्यापन एव उसकी दिपीर्ट के अनुसार कार्यवाही करके किया जा सकता है।

यह तर्क कि— माल गोदांमों में सालों साल भरा पड़ा रहता है जिसकी भौतिक सत्यापन लागत है। बहुत अधिक आयेगी, तर्कहीन लगता है क्योंकि खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हो रही हानि सत्यापन लागत से सदैव अधिक ही होगी। भण्डार कार्य में लगे कर्मचारियों को सर्तक एवं सावधान करने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन हेतु डिपुओं का निर्धारण लाटरी निकालकर किया जाये। इससे देश के केवल कुछ डिपों का भौतिक सत्यापन कर गोदामों में हो रही। खाद्यान्न क्षति को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण गोदामों पर खाद्यान्न लेखा पुस्तकों के अनुसार ही बना रहें तथा निकासी एवं प्राप्ति के कार्यों की अधिक सुरक्षा सुनिष्चित करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल्ल तैनात किया जाना चाहिए।

- \* निगम अब भी अपना लगभग एक तिहाई कारोबार किराये के गोदामों में सम्पन्न करता है। इन गोदामों का भारी किराया तो उसे चुकाना पड़ता ही है साथ है। इन गोदामों की क्षमता एव उपयोगिता सन्तोषजनक नहीं होती। अत खाद्य निगम को अगनी भण्डारण क्षमता में बृद्धि करनी चाहिए।
- \* शासकीय निर्णयों में विलम्ब एवं सरकार के विभिन्त मन्त्रालयों में तालमेल के अभाव का दोष भारतीय खाद्य निर्णम का स्वयं का नहीं है परन्तु फिर भी हुन्ते निर्णम को बहुत अधिक हानि होती है। यह व्यवस्था का दोष है। इस दोष के निवारण के लिए आविष्रमक है कि राजनीतिक पदाधिकारियों तथा विभागीय अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरवायित्व की स्पष्ट व्याख्या की जाय। निर्णय के अधिकार को यथा सम्भव उत्तरवायित्व के साथ विकेन्द्रित किया जाय ताकि संगय एवं परिस्थित के अनुरूप सही

\* कृषि उत्पादकों को उनकी उपज का समृचित मूल्य प्रवान करने के साथ ही साथ खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि जो खाद्यान्न खरीदा जा रहा है वह निधारित कोटे एवं गुणवत्ता गाला होना चाहिए। इस प्रकार निगम का लक्ष्य ' गुणवत्ता वाले अनाजों की अधिकाधिक खरीद' होना चाहिए, केवल मात्रा लक्ष्यप्राप्तकरने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। इस कार्य में अधिकारियों को " आप ऐसा करे" के स्थान पर "आओ हम सब मिलकर ऐसा करे" पर जोर देना चाहिए। खरीद के समय मान्य सीमा की नमी को ही स्वीकार किया जाय जैसे चावल के सन्दर्भ में अधिकतम 17–18 प्रतिशत। इससे भण्डारण में सुखने से होने वाली अत्यधिक हानि को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

\* निगम के अपने गोदाम तथा अन्य खाद्यान्न गोदाम जी निगम किरायें पर प्राप्त करता है, का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का स्कन्धं,स्वन्धं बही के अनुसार न होना, खाद्यान्नों का सड़ या गल जाना, बोरो एव तिरपालों का सड़ जाना, दवाद्दयों का छिड़काव समय से न हो पाना इत्यादि समस्याओं का निदान भौतिक सत्यापन एव उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करके किया जा सकता है।

यह तर्क कि – माल गोदामो में सालो साल भरा पड़ा रहता है जिसकी भौतिक सत्यापन लागत ही बहुत अधिक आयेगी, तर्कहीन लगता है क्योंकि खाद्यान्नों के सम्मन्ध में हो रही हानि सत्यापन लागत से सदैव अधिक ही होगी। भण्डार कार्य में लगे कर्मचारियों को सर्तक एव सावधान करने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन हेतु डिपुओं का निर्धारण लाटरी निकालकर किया जाये। इससे देश के केवल कुछ डिपों का भौतिक सत्यापन कर गोदामों में हो रही खाणान्न क्षेति को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण गोदामों पर खाद्यान्न लेखा पुस्तकों के अनुसार ही बना रहे तथा निकासी एव प्राप्ति के कार्यों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीयं औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया जाना चाहिए।

\* निगम अब भी अपना लगभग एक तिहाई कारोबार किराये के गोदामों में सम्पन्न करता है। इन गोदामों का भारी किराया तो उसे चुकाना पड़ता ही है सीध ही इन गोदामों की क्षमता एवं उपयोगिता सन्तोषजनक नहीं होती। अत खाद्य निगम को अपनी भण्डारण क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए।

\* शासकीय निर्णयों में विलम्ब एवं सरकार के विभिन्न गन्त्रालयों में तालंगेल के अभाव का वोष भारतीय खाद्य निर्णम का स्वयं का नहीं है परन्तु फिर भी इससे निर्णम को बहुत अधिक हानि होती है। यह व्यवस्था का वौष है। इस वोष के निवारण के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक पदाधिकारियों तथा विभागीय अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरबायित्व की स्पष्ट ब्यांख्या की जाय। निर्णम के अधिकार को यथा सम्भव उत्तरवायित्व के साथ विकेन्द्रित किया जाय ताकि समय एवं परिस्थिति के अनुरूप सही

समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

\* निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, विन्त वाणिजय एव कृषि मन्त्रालयों से सम्बन्धित अधिकारियों के श्रीच समन्वय तथा सचार की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन, आवश्यकता, खरीद एव निर्गमन आदि के सम्बन्ध में वास्तविक अनुमानों पर आधारित निर्णय लिया जा सके।

\* निगम के अधिकारियो एवं कर्मचारियों में स्वयं की प्रेरणा से कार्य सम्पादन की इच्छा जागृत करने के लिए अभिप्ररेण के नवीनतम साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारी पूरी निष्ठा, कार्यक्षमता एवं ईमानवारी रो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे इसके लिए उन्हें यह बात समझायी जानी चाहिए कि मिगम के हितों में कर्मचारी का हित भी विद्यमान एवं सुरक्षित हैं। इसके लिए निगम के लगभग 65,000 कर्मचारियों को कार्यात्मक एवं आद्यात्मिक वीनों प्रकार का प्रशिक्षण विया जाना चाहिए।यह प्रशिक्षण विश्वमें चरणों में प्रा किया जा सकता है। निगम के कर्मचारियों में मनोबल बनाये रखने के लिए निगम के उद्देशयों एगं लक्ष्यों की जानकारी इसके कर्मचारियों, साथ—साथ निगम से सम्बन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं, जैसै कि—राज्य सरकारों, चावल और गेहूँ के मिल मालिकों के मंच(फोरम), शहरों के गैर सरकारी संगठनों, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों, बैकों, रेलवें, गोदाम मालिकों, नीति निर्धारकों, प्रेस आदि से परस्पर सम्पर्क स्थापित कर, दी जाय।

\* ससद की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सम्बन्धी स्थायी समिति ने दिसम्बर-1994 में प्रस्तुत अपनी रिपीर्ट में भारतीय खाद्य निगम की आलोचना करते हुए निम्न अतिरिक्त सिफारिशे प्रस्तुत की है $-^{41}$ 

- समिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गौदामीं में चांबल उतारने के काम में लगे ठेकेंदार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, अत इस कार्य में भ्रष्टाचार कों समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर निगम स्वय दैनिक मजदूरी पर नियुक्त श्रमिकों से इस कार्य को पूरा कराये।
- --- समिति की सिफारिश है कि धान की खरीद पर लगने वाले करों में एकरूपता लाने के लिए राज्यीं को राजी किया जाय क्योंकि इस समय लेवी धान के खरीद मुल्यों में कोई समानता नहीं है।
- समिति ने यह सिफारिश भी की है कि चूँिक किसानों के पास अनाज के भण्डारण की पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम या किसी अन्य एजेन्सी को खरीद केन्द्रों के निकट किसानों की मामूली किराये पर अनाज के भण्डार के लिए स्थान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि किसान जब चाहें अपनी अनाज बेच सके।

<sup>--</sup> समिति ने खाद्य मन्त्रालय के इस तर्क को मार्मजूर कर दिया कि खुले बाजार मे गेहूँ

के अधिक मूल्य मिलने तथा किसानो द्वारा अपनी मर्जी से अनाज बेचे जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद कम हो पाती है। समिति ने कहा कि निगम के क्रय केन्द्रों के काम-काज पर कड़ी निगरानी रखी जाय। इस इस बात पर आश्चर्य किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3-4 महीने बाद बोरियों की खरीद के लिए आदेश दिये जाने के कारण राज्य में गेहूँ की समय पर खरीद वर्ष 1991-92 में नहीं हो पायी।

— समिति ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी दिया है कि भारतीय खाद्य निगम छोटे चक्की मालिंकों को भी कम दरों पर गेहूँ की सप्लाई करे, क्योंकि शहरों में कमजोर तबकों के लोग राशन कार्ड के अभाव में इन्ही आटा चिक्कियों से आटा खरीदते हैं। निगम इस समय आटा मिलों और डबल रोटी निर्माताओं को कम दरों पर गेहूँ बेचता है, जबिक ये आटा मिले खुले बाजार में ऊँचे मूल्यों पर आटा वेचकर लाभ कमाती है।

इस प्रकार यदि भारतीय खाद्य निगम को मानव जाति की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने वाले एक महान सगठन की भूमिका का निर्वाह वास्तव मे करना है तो उपर्युक्त सुझावो पर भली-भाँति विचार-विमर्श करके इन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में आर्थिक उन्नित की एक नयी लहर चल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उदारीकरण एव वैश्विकीकरण के इस नये आर्थिक दौर मे भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। ऐसी स्थिति मे निगम को भी उपलब्ध व्यापारिक सुअवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उपर्युक्त सुझावों का अनुपालन कर भारत की अग्रणी सामाजिक एव आर्थिक कल्याण की सस्था के रूप मे भारतीय खाद्य निगम अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करा सकता है।

# (इ) केन्द्रीय भण्डारण निगम -

(अ) परिचय — केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना वर्ष 1957 में की गयी थी। वर्तमान समय में इस निगम का सचालन वेजर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 के अधीन कियों जा रहा है। इसकी स्थापना का मुख्य उव्देशय खाद्यान्नों, उर्वरकों, लघु वनोत्पादों तथा कुछ अन्य ठोंस एव तरल वस्तुओं की राष्ट्र स्तर पर उचित एव पर्याप्त पूर्ति हेतु भण्डारण की व्यवस्था करना तथा देश के राज्य भण्डारण निगमों का मार्ग-वर्धन करना है। यह निगम भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदीं गई मात्राओं तथा भारतीय राज्य ब्यापार निगम, भारतीय खिनज एव धातु व्यापार निगम तथा भारतीय जूट निगम एव आयात करने वाली मुख एजेंन्सियों के द्वारा आयातित वस्तुओं के भण्डारण संभाल का कार्य करता है। यह निजी क्षेत्र, सहकारी सीमितियोंतथा किसानों के आधिक्य खाद्यान्नों के भण्डारण के साथ ही खाद्यान्नों की खरीद में भी छोटे इसरे पर योगदान करता है। इसके लिए अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डारण निगम भण्डारित वस्तुओं के

गुणवत्ता की सुरक्षा हैतु रोगरोधी उपचार एव प्रद्यमन की व्यवस्था भी करता है। यह किसान विस्तार सेवा योजना एवं कीटनाशक विस्तार सेवा योजना जैसी सेवाए तथा विकसित एव आधुनिक भण्डार गृहों की डिजाइनिंग एवं निर्माण के सम्बन्ध में अनुसधान एवं विकास का कार्य भी सम्पन्न करता है। इस प्रकार यह निगम भारतीय खाद्य गीति के अनुर प राजकीय व्यापार में लगे विभिन्न अभिकरणों को अपना सहयोग प्रदान करती है।

निगम का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। जिसमे एक अध्यक्ष तथा 9 निदेशक हींते हैं। निगम की अधिकृत पूंजी 1000 रुपये वाले 10 लाख अशो में विभाजित है। 31 मार्च 1993 कों निगम की कल अभिवत्त पूंजी 7452 5 लाख रुपये थी जो 1000रुपये के 7,45,250 अंशो में विभक्त थी। निगम के आधे से अधिक अश केन्द्र सरकार के पास है जबकि अन्य अशो में क्रमश भारतीय स्टेट बैंक के पास 1,74,729 अंश, अन्य अनुसूचित बैंकों के पास 1,42,052 अश, भारतीय जीवन बीमा मिगम सहित अन्य बीमा कम्पनियों के पास 51,454 अश, सहकारी समितियों के पास 2,689 अंश, कृषि स्टिपाद का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पास 71 अंश एव कृषि उत्पाद आदि का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पास 71 अंश एव कृषि उत्पाद आदि का व्यापार करने वाली कम्पनियों के पास 5 अश थे। वेअर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम की धारा 5(1) के अनुमारणे में निगम के अशों पर मूलधन लौटाने तथा अंशो के जारी करने के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मारित वार्षिक लाभांश की अदायगी करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा गारण्टी प्रदान की गयी है। 42 निगम ने राज्य भण्डारण निगमों के 50 प्रतिशत समता अंशों में स्वयं निवेश किया है तथा पजाब राज्य भण्डारण निगमों के साथ उसका संयुक्त उद्यम भी चल रहा है।

- (ब) निगम की उपलब्धियाँ केन्द्रीय भण्डारण निगम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को उमकी आवश्यकतानुसीर वस्तुओं के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए देश को भण्डारण की महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध करों में अपनी भूमिका का सफलता पूर्वक निर्वहन कर रहा है। इसकी कार्यात्मक प्रगति का मूल्यांकन इसं प्रकार है—
- 1 निगम का व्यवसाय हाल के वर्षों में निगम को नये आर्थिक वातावरण में कार्य करने के साथ—साथ सरकार के आर्थिक उचारीकरण कार्यक्रम एवं ढाँचागत परिवर्तनों से उत्पन्न प्रभावों को सहना पड़ा है। उचारीकरण की नीति से बाँण्डेड वेअर हाउसिंग की गतिविधियों में बहुत कमी आयी है। क्योंकि भारतीय ग्रांका व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा भारतीय जूट निगम और आयात करने वांकी अन्य एजेन्सियों का कारोबार कम हो गया। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों की खरीद में कमी धाने से निगम के भण्डारण गृहों के उपयोग पर प्रभाव पड़ा।

यद्यपि पिछले वर्षों में निगम के भण्डारगृष्टों की सख्या और उसकी भण्डारण क्षमता मे लगातार

वृद्धि हुई है जिसे निम्न तालिका मे प्रस्तुत किया गया है-

तालिका संख्या 40 निगम के भण्डार गृहों की संख्या एवं उनकी क्षमता का विवरण

( 31 मार्च को)

tamo ataya uzu- zar	घेवरण	वर्ष 1989-90	1990-01	1991-92	1992-93
1	कैन्द्रीय भण्डार गृहो की संख्या	483	498	490	465
2	उनकी भण्डारण क्षमता (लाख मी टनों मे)	65 16	67 77	67 19	66 58
	क निर्मित/अपनी	45 68	47 22	47 75	48 51
	ख किराये की	17 68	17 55	16 53	15 90
	गं खुरी	1 80	3 00	2 91	2 18
3	औसत/उपलब्ध क्षमता	64 38	66 56	67 65	66 65
4	प्रयुक्त क्षमता	49 75	52 16	49 63	44 65
5	प्रयुक्त क्षमता(प्रतिशत मे)	77	78	73	67
б	वस्तुवार(सप्रतिशत) उपयोग की स्थि	यति—			
	(क) खाद्यान्न		27 66	21 72	21 74
	, ,		(51)	(49)	(45)
	(ख) उर्वरक		6 8	5 96	7 91
			(13)	(13)	(17)
	(ग) अन्य		19 28	17 20	18 46
			(36)	(38)	(38)

म्रीतः वार्षित प्रतिवेदन- केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल/एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भण्डार गृहों की सर्वाधिक संख्या वर्ष 1990-91 में 498 थीं इस वर्ष में 20 नये भण्डार गृह खोले गये जबिक 5 को अपना कारोबार परिचालन तथा अन्य कारणों से बन्द कारमा पड़ा। वर्ष 1991-92 में 6 भण्डारगृहों तथा 1992-93 में गत वर्ष की तुलना में 27 भण्डारगृहों की कमी हो गयी। भण्डारगृहों की संख्या में होने वाली वृद्धि एवं कमी के अनुरूप ही उनकी भण्डारण क्षमता में भी वृद्धि एवं कमी हुयी है। निगम भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराने के लिए किराये पर भी भण्डारण क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन उसकी अपनी क्षमता कुल भण्डारण क्षमता की 70 प्रतिशत से अधिक ही रहती है। वह औसतम 25 प्रतिशत क्षमता किराये पर लेता है।

निगम की औसत भण्डारण क्षमता 1992-93 की तुलना में 1 लाख मी टन कम हो गयी है।

न केवल मण्डारण क्षमता में कमी हुई है बल्कि वर्ष 90-91 से लगातार भण्डारण की उपयोग में लायी गयी क्षमता भी कम हो रही है। यह वर्ष 1991-92 तथा 92-93 में अपने गत वर्षों में प्रयोग में लायी गयी क्षमता से क्रमश 5 लणा 6 प्रतिशत कम है। क्षमता उपयोग में गिरावट का मुख्य कारण कस्टम बीण्डेड कारीबार में कमी होना था क्योंकि आयात में गिरावट और सीमा शुल्क अधिनियम में किये गये परिवर्तन कस्टम वॉण्डेड भण्डारगृहों के क्षेत्र में हतोत्साही सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों, जूट की खरीम में कमी एवं राज्य व्यापार निगम एवं खनिज तथा धातुव्यापार निगम इत्यादि द्वारा आयात बन्द किये जाने से भण्डारण क्षमता के औरत उपयोग पर प्रतिकृत प्रभाव पडा।

तालिका रोयह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम अपने भण्डार गृहों में अपनी भण्डारण क्षमता का लगभग आधा भाग खाद्यान्नों के भण्डारण में प्रयुक्त करता है। निगम द्वारा भण्डारित वस्तुओं में पहलीबार वर्ष 1990-91 में अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्नों का भण्डारण 50 प्रतिशत से अधिक रहा। उर्वरकों के भण्डारण में वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में अन्य वस्तुओं की तुलना में बराबर क्षमता ही प्रयोग में लायी गयी परन्तु कुल भण्डारण में वर्ष 91-92 में मात्रात्मक रूप में 0 84 मीठटन की कमी रही। वर्ष 1992-93 में उर्वरकों के भण्डारण कारोबार में वृद्धि हुई और पिछले वर्ष 9 96 लाख मी. टन की सुलना में यह कारोबार बढ़ कर 7 91लाख मी टन हो गया।

निगम अन्य वस्तुओं मे तेन्तु पत्ता, आलू, रसायन,रूईगांठ, कॉपर कॉयल्स, टेलीविजन पिक्चर द्यू बं आदि वस्तुओं का भण्डारण भी करता है। इन वस्तुओं के भण्डारण हेतु वह अपनी कुल भण्डारण भीमंता का लगभग एक तिहाई से अधिक भाग उपलब्ध कराता है। निगम नये कारोबार के क्षेत्र मे मध्य प्रदेश से मुख्यत तेन्दु पत्ते के भण्डारण की ओर आकर्षित हुआ है।

कैन्द्रीय भण्डारगृहों का जमाकर्तावार उपयोग अग्राकित तालिका मे प्रवर्शित किया गया है-

भण्डारगृहों की जमाकर्तावार उपयोग की स्थित

तालिका सख्याः 41

(31 मार्च को प्रतिशत में)

and later and	जमाकर्ता	वर्ष 1987	1988	1989	1990	1991
1	सरका। द्वारा प्रायोजित संस्थाए	71	64	59	56	65
2.	सरकार	5	5	6	13	07
3.	<b>निजी</b>	24	31	35	31	28
	योग	100	100	100	100	100

नींद्रः निजी ज़िमाकतीओ में सहकारिताएं, व्यापारी एवं किसान शामिल है।

मीतं वार्षिक प्रतिवर्देन-केम्ब्रीय भण्डारण निगम,सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया,हौजखास, नई दिल्ली

न केवल भण्डारण क्षमता में कमी हुई है बल्कि नर्ष 90-91 से लगातार भण्डारण की उपयोग में लायी गयी क्षमता भी कम हो रही है। यह वर्ष 1991-92 तथा 92-93 में अपने गत वर्षों में प्रयोग में लायी गयी क्षमता में क्रमश 5 तथा 0 प्रतिशत कम है। क्षमता उपयोग में गिरावट का मुख्य कारण कस्टम बाण्डेड कारोबार में कगी होना था क्योंकि आयात में गिरावट और सीमा शुल्क अधिनियम में किये गये परिवर्तन कस्टम वॉण्डेड भण्डारगृहों के क्षेत्र में हतोत्साही सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त खाद्यान्तो, जूट की खरीद में कमी एवं राज्य व्यापार निगम एवं खनिज तथा धातुव्यापार निगम इत्यादि द्वारा आयात बन्द किये जाने से भण्डारण क्षमता के औसत उपयोग पर प्रतिकृत प्रभाव पडा।

प्राणिका सेयह भी स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम अपने भण्डार गृहों में अपनी भण्डारण क्षेमता का लगभग आधा भाग खाद्यान्नों के भण्डारण में प्रयुक्त करता है। निगम द्वारा भण्डारित वस्तुओं में पहलीबार वर्ष 1990-91 में अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्नों का भण्डारण 50 प्रतिशत से अधिक रहा। उर्वरकों के भण्डारण में वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में अन्य वस्तुओं की तुलना में बराबर क्षेमता ही प्रयोग में लायी गयी परन्तु कुल भण्डारण में वर्ष 91-92 में मात्रात्मक रूप में 0 84 मीठटन की कमी रही। वर्ष 1992-93 में उर्वरकों के भण्डारण कारोबार में वृद्धि हुई और पिछले वर्ष 9 96 लाख मी. टन की तुलना में यह कारोबार बढ़ कर 7 91लाख मी टन हो गया।

निगम अन्य वस्तुओं में तेन्दु पत्ता, आलू, रसायन, र्रूडगाठ, कॉपर कॉयल्स, टेलीविजन पिक्चर ट्यूबं आदि वस्तुओं का भण्डारण भी करता है। इन वस्तुओं के भण्डारण हेतु वह अपनी कुल भण्डारण क्षमतों का लगभग एक तिहाई से अधिक भाग उपलब्ध कराता है। निगम मये कारोबार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मुख्यत तेन्दु पत्ते के भण्डारण की ओर आकर्षित हुआ है।

केन्द्रीय भण्डारगृहों का जमाकर्तावार उपयोग अग्राकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है-

तालिका संख्या 41 भण्डारगृहो की जमाकर्तावार उपयोग की स्थित

	मण्डारमूखा यम अमायरामिर अनुवार यम रियारी					को प्रतिशत
	जमाकर्ता	वर्ष 1987	1988	1989	1990	1991
1	सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं	71	64	59	56	65
2,	सरकार	5	5	6	13	07
3	निजी	24	31	35	31	28
	योग	100	100	100	100	100

मीद निजी जमाकर्ताओं में सहकारिताए, व्यापारी एवं किसान शामिल है।

बौद्यं वार्षिकं प्रतिवदेन-केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

इस प्रकार स्पष्ट है कि तीनो प्रकार के जमाकर्ताओं के द्वारा भण्डारगृहों का प्रयोग प्रतिवर्ष घटता-बंढती रहा है। इसमें परिवर्तन इस प्रकार हुआ है जिससे किसी प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। परन्तु इतना अनश्य ही कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा प्रायोजित सस्थाओं के इन भण्डार गृहों में केमी तथा सन्दार एवं निजी जमाकर्ताओं द्वारा समीक्षात्मक 5 वर्षों में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।

- 2 पिंन्सिक बॉण्डेड भण्डार-गृहों की स्थिति पिंन्सिक बॉण्डेड भण्डारगृहों के क्षेत्र में निगम वर्ष 1990-91 तक लगातार अच्छी प्रगित करता रहा है। इस वर्ष के दौरान ऐसे 15 नए भण्डारगृह खोले गये। मार्च-1991 को निगम 9 43 लाख टन क्षमता के 178 पिंन्सिक बॉण्डेड भण्डार गृह चला रहा था। निगम द्वारा चलाये जा रहे ये भण्डारगृह रसायनो, इलैक्ट्रोनिक्स, आटोमोबाईल्स, टैक्सटाइल्स, मशीनी-औजारों आदि के लिए भण्डार सुविधाए उपलब्ध कराकर व्यापार एवं उद्योग-क्षेत्र की आवश्यकताए पूरी कर रहे हैं। सामान्य वायुमण्डलीय परिस्थितियों में भण्डारण करने के अतिरिक्त इस निगम द्वारा संवेदनशील वस्सुओं का नियन्त्रित तापमान में और तरल पदार्थों का टैकों में भण्डारण भी किया जाता है।
- 31 मार्च 1992 को निगम 8 81 लाख क्षमता के 169 पब्लिक बॉण्डेड भण्डारगृहों को चला रहा था। इन सींगा शुल्क द्वारा नियन्त्रित भण्डारगृहों ने विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में आयातकों के आवश्यकताओं की पूर्ति की। ऐकिन आयात में गिरावट एवं विशेष रूप से सीमा शुल्क अधिनियम में सशोधन जैसे— बॉण्ड अविध तीन माह से घटाकर एक माह करने, बॉण्डिंग से पहले निर्धारित सीमा शुल्क के शेष 50 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान भी जरूरी करने से निगम को बॉण्डेड भण्डारगृहों के उपयोग के क्षेत्र में भारी धक्का लगा। इत्तं परिवर्तनों ने बाण्डेड भण्डारगृहों के व्यापार को हतोत्साहित किया। सीमा शुल्क नियन्त्रित व्यापार के क्षेत्र में क्षमता उपयोग में कमी के कारण निगम केआवर्त में अत्यधिक कमी आयी। जिसके परिणामस्वरूप, लाभ पर भी इसका प्रतिकृत प्रभाव पडा। वर्ष 1992—93 में नियन्त्रित कारोबार में गिरावट आने के कारण 2.4 लाख मी टन क्षमता का कारोबार घट गया लेकिन सामान्य एवं औद्योगिक भण्डारगृहों के उपयोग को बढ़ाकर संगभग 1 4 लाख मी टन की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करके इस कमी को पूरा कर लिया गया।
- केटेनर दुलाई स्टेशनों की प्रगति यह निगम देश में कटेनर दुलाई स्टेशनों की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के मामले में एक अग्रणी संस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्ष 1990-91 में निगम में पुणे, अहमदाबाद तथा हैदराबाद में तीन नये कंटेनर स्टेशन स्थापित किये। इस प्रकार इस धर्ष में मिगम द्वारा चलायें जा रहे कटेनर दुलाई स्टेशनों की संख्या बढ़ कर 8 हो गयी। वर्ष 1991-92 में विस्तान्वकम, मद्रास में एक नये कटेनर दुलाई स्टेशन की स्थापना की गयी। इस प्रकार निगम के पास अब कैटेनर दुलाई स्टेशनों की संख्या बढ़ कर 9 हों गयीं है। एक अन्य स्टेशन पजाब राज्य भण्डारण

निगम के साथ सयुक्त उराम के रूप में लुधियाना में कार्य कर रहा था। निगम ने वर्ष 1991-92 के दौरान 114 हज़ार फंटेनर की संभाल की। जबकि इसके पूर्व के वर्ष में सभाल किये गये कटेनरों की सख्या 74,929 थी। इस प्रकार इसमें 53 पितशत की वृद्धि हुई। कटेनरों के सभाल कार्य में प्रमुख वृद्धि जवाहर लील मेहरूपोर्ट एवं कालम्बोली में हुई।

वर्ष 1992-93 मे 1 44 लाख कटेनर की संभाल की गई। जबिक पिछले वर्ष इनकी सख्या 1 14 लाख थीं। निर्माम के वर्तमान अध्यक्ष श्री के एस रेड्डी ने बताया है कि निगम ने वर्ष 93-94 के दौरान कुल 48 अरब 30 करोंड रूपये मूल्य की वस्तुओं का संचालन अपने 12 कटेनर ढुलाई स्टेशनों के माध्यम से की। निर्मात कटेनरों के सचालन में निगम ने 18 प्रतिशत की वृद्धि की है।श्री रेड्डी ने यह भी बताया कि इन कंटेनर ढुलाई स्टेशनों पर कुल 80 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है।निकट भविष्य मे इसी तरह के और 5 कटेनर ढुलाई स्टेशनों की स्थापना करने की योजना है। इन पर 30 करोड़ रूपये निवेश किये जाने का अनुमान है। निगम ने सूरत, काण्डला, उदयपुर, नासिक, माधवरम (मद्रास) तथा कोटा में कंटेनर ढुलाई स्टेशन स्थापित करने के लिए केन्द्र की अन्तर मन्त्रालय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। 43

4. <u>निगम का वित्तीय निष्पादन</u> केन्द्रीय भण्डारण निगम के गत वर्षों के वित्तीय निष्पादन को निम्न तार्शिकों में प्रस्तृत किया गया है-

तालिका संख्या 42 निगम का विगत वर्षों का वित्तीय निष्पादन (करोड रुपये मे)

क्र सं	विव्रण	वर्ष 1989	90	1990-9	91	1991-	-92	1992-	-93
<b>1</b> '.	संबंश ब्लॉक	107 49	)	215	58	241	89	263	38
2	कार्मशील पूँजी	70 34	1	91	67	102	94		
3	निवेधा	39 51	L	43	57	45	92	-	
4	निमौणित पूँजी	274 43	}	312	70	345	86	351	84
Б	संकल प्राप्तियाँ	105 84	1	117	46	121	86	111	11
b	मरिमीलन खर्चे	65 36	<u>;</u>	73	99	79	85	88	22
7	मिष्ल लाभ	40 48	}	43	47	42	09	22	89
8	प्रति कर्मचारी प्राप्तियाँ(रुपये मे)	1,08,545	5	1,18,	181	1,21,	965	1,12,0	000
ġ	प्रति कर्मचारी सभाली गयी भंगता (टर्नों गे)	668			682		672	-	_

बीति: बार्षिक प्रतिवेदन-केम्ब्रीय भण्डारण मिगम,सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

<sup>43</sup> नवभीरत टाइम्स-नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994.

तालिका सख्यां 43 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगम की रथायी सम्पत्ति, कार्यशील पूँजी, निवेश तथा निगोजित पूँजी में समयानुसार लगातार वृद्धि हो रही है जिसे भण्डारण निगम के विस्तार की वृष्टि से एक शुभ सकेत कहा जा सकता है। यदि इन मदों की वर्ष 1089-00 की तुलना वर्ष 1991-42 की मदों से की जाय तो रपष्ट होता है कि इस अवधि में कार्यशील पूँजी में सर्वाधिक वृद्धि 45 प्रतिशत की हुई। इसके बाद नियोजित पूँजी 26 प्रतिशत बढ़ी, स्थायी सम्पत्ति में 22 5 प्रतिशत तथा निवेश में सबसे कम 16 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मिगम की सकल प्राप्तियाँ निगम के इतिहास में वर्ष 1991-92 में सर्वाधिक रही है जबिक निवल लीभ वर्ष 1990-91 में ही सर्वाधिक रहा। यदि वर्षवार प्राप्तियों में वृद्धि दर का अवलोकन किया जीय तो यह राबसे अधिक 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-01 में 10 98 पतिशत की दर से बढी है। गिर्व सीमा शुरक नियन्त्रित व्यापारों में गिरावट न आयी होती तो वर्ष 1991-92 में सकल प्राप्तियों में वृद्धि और अधिक होने की सम्भावना थी। निगम की सकल प्राप्तियों में वर्ष 1999-93 में 10 83 करोड़ रूपये की कंमी हो गयी। कारोबार में गिरावट आने से प्राप्तियों में गिरावट आना स्वाभाविक था। यदि प्रति कर्मचारी प्राप्तियों एवं उनके द्वारा सभाली गयी क्षमता की विश्लेषण किया जाय तो प्रति कर्मचारी प्राप्तियों वर्ष 91 प्रे में सर्वाधिक 1,71,965 रूपये थी जबिक इस वर्ष उनके द्वारा संभाली गयी भण्डारण क्षमता गत वर्ष की तुलना में 10 टन कम रही। वर्ष 1992-93 में प्रति कर्मचारी प्राप्तियों पूर्व वर्ष की तुलना 9,965रूपये प्रति कर्मचारी कम हो गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों ने भी अपनी कार्य क्षमता की पूर्ण उपयोग नहीं किया है।

411

5 निगम की लाभदायकता एवं लाभाश — हाल के वर्षों मे निगम की प्राप्तियों में कमी तथा ह्यायों में शृद्धि के फलस्वरूप उसकी लाभदायकता में कमी आयी है। इसके लाभदायकता एवं लाभाश के विश्लेषण हैंतू एवं उससे सम्बन्धित अन्य तथ्यों को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है—

तालिका संख्या 43

	केन्द्रीय भण्डारण	निगम की लाभ	वायकता एवं	लाभांश का वि	वेवरण (ल	ख रुपये मे)
-	विवरण	1986 -87	1987-88	1990-91	1991-92	1992-93
1	मिवल लाभ	2699	3622	4347	4209	2289
2	नियोजित पूँजी पर लाभ(%मे)	14 99	17 43	13 90	12 17	6 5
3	आंवर्स पर लाभ(% मे)	40 43	43 55	37 00	34 50	20 60
4.	लोभाश	358	358	476	850	476
5.	स्रामांश दर(%मे)	5	5	7	12 5	7
6.	प्रारक्षण में हस्तान्तरित	gdaydy. Dawn arthur sudan move media yapan anada yapan mada yapan mada yapan mada yapan mada yapan mada yapan mada yapa	empe e epiles deliti vilps deliti tipop sons, eneg	3827	3317	486

तालिका गरूया 43 में दर्शाये गये निवल लाभ की समीक्षा की जाय तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 के बीच निवल लाभों में जिस पकार आश्चर्यजनक रूप में वृद्धि हुयी थी उसी प्रकार यह वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में आश्चर्यजनक रूप से घटा भी है। नियोजित पूँजी पर लीभ वर्ष 1987-88 में 17 43 प्रतिशत के उच्चतम शिखर पर पहुँचकर बाव के वर्षों में इसमें निरन्तर कमी होतें-होते यह 6 5 प्रतिशत के चिन्तागनक अवस्था में पहुँच गया है। इसी प्रकार आवर्त पर लाभ की वृष्टि से समीक्षात्मक वर्षों में सबसे अच्छा वर्ष 1987-88 तथा सबसे खराब वर्ष 1992-93 रहा है।

जहाँ तक लाभाश का प्रश्न है तो 'वेशर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम—1962' की धारा—5 (1) के प्रांतधानों के अधीन निगम के अंश मूलधन की वापसी तथा न्यूनतम लाभाश के भुगतान के लिए केन्द्र संस्कार द्वारा गारण्टीबन्द्र है। 31 40 करोड रुपये के मृल्य के पहले 7 निर्गमों के अशो पर न्यूनतम लाभाश की दर 3 5 प्रतिशत है जबिक शेष अशो पर न्यूनतम लाभाश 5 5 प्रतिशत है। पहले सात निर्गमों गर्र लाभाश की दर वर्ष 1986—87 में पहली बार बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गयी थी। इसके बाद 1988—89 में लाभाश की दर 5 5 प्रतिशत अर्थात् शेष निर्गमों के समान ही कर दी गई थी। सभी 15 निर्गमों के लिए वर्ष 1989—90 के लिए लाभांश की दर बढ़ाकर 6 प्रतिशतकी गयी थी वर्ष 1990—91 में लाभांश की दर बढ़ाकर 7 प्रतिशत की गयी और कुल 4 76 करोड रुपये लाभाश के रूप में अशधारियों की वितरित किये गये।

वर्ष 1991-92 में निगम के निदेशकों ने लाभाश की दर में सहर्ष वृद्धि कर 12 5 प्रतिशत कर विया और 8 50 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में वितरित किये। परन्तु लाभों की कमी के कारण निगम की लाभाश दर वर्ष 1992-93 में पुन पूर्व के स्तर तक कम करनी पड़ी जो प्रदत्त पूँजी पर 7 प्रतिशत तथा निवल लाभी का लगभग 20 8 प्रतिशत है। ऐसा रिपोर्टाधीन वर्ष में निगम को प्रतिकूल परिस्थितियों का सागना करने के कारण करना पड़ा। लाभाश तर में 5 प्रतिशत की कमी एक ओर की गयी तो दूसरी ओर प्रारक्षण की धनराश को भी पूर्व वर्ष की तुलना में 28 31 करोड़ रुपये कम करना पड़ा।

6 राज्य भण्डारण निगमों में निवेश एवं लाभांश की स्थिति — निगम में देश के 16 राज्य भण्डारण निगमों की 50 प्रतिशत समता अंश पूँजी में विनियोजन भी कर रखा है। इसने पंजाब राज्य भण्डारण निगम में सबसे अधिक 4 लाख अश खरीद कर 4 करोड़ रुपये का विनियोजन किया है। यह निगम में भण्डारण निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य कर रहा है। यद्यपि केन्द्रीय भण्डारण निगम के माथ्य प्रदेश भण्डारण निगम के 17,020 अतिरिक्त समता अंशों को वर्ष 1992—93 में खरीद कर इस निगम में भी अपनी पूँजी को 4 करोड़ रुपये तक पहुँचा विया है। अन्य राज्य भण्डारण निगमों में 31 मार्च, 93 की निगम ने जी अश खरीद रखे थे उनमें प्रमुखत तिमलनाड़ के 3,80,500, उत्तर प्रदेश के

3,73,260 आन्ध्र प्रवेश के 3,30,703 महाराष्ट्र के 3,14,800 तथा पश्चिमी बगाल के 3 09 700 अंश थे। इन राभी अंशो का अंकित मूल्य 100 रुपये हैं। इन राज्य भण्डारण िगमो की प्रगति तथा इनसे प्राप्ता औय को जिन्न तारिका में दर्शाया गया है—

नालिका संख्या 44 राज्य भण्डार निगमों की प्रगति एवं इनसे प्राप्त आय

4000 Option 80000	चिव्रण	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-0
1	संख्या( ३१ मार्च को)	1324	1331	1 343	1350
2	भण्डारण क्षमता(लाख मी टन मे)	90 00	93 54	91 05	92 03
	क- स्विनिर्मित	64 53	65 98	67 46	69 38
	ख– किराये पर	24 27	25 81	22 01	21 36
	ग- खुले प्लिथ	1 20	1 75	1 58	1 29
3	केन्द्रीय भण्डार निगम का अशो में मिवेण लागत पर(करोड रु में)	34 80	37 77	40 25	42 02
4	प्राप्त लाभांश(करोड रुपये मे)	1 23	48	1 66	1 06
5	मिवैषा पर आय का प्रतिशत	3 53	1 27	1 12	2 52

म्रोतं वार्षिक पतिवेदन-केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनरा एरिया, हौजखास, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य भण्डारण निगमों के भण्डारगृहों की राख्या लगातार बढ़ती रही है और 1992-93 में यह 1350 हो गयी है। इस प्रकार निगम भण्डारगृहों की सख्यात्मक बृष्टि से वृद्धि कर रहा है, परन्तु यदि निगम की भण्डारण क्षमता पर दृष्टि डाली जाय तो स्पष्ट होता है कि इन निगमों की कुल भण्डारण क्षमता 1991-92 में 87-88 से कुछ कम ही थी। वर्ष 1987-88 में केन्द्रीय भण्डारण निगम के भण्डारगृहों की सख्या 1306 और उनकी भण्डारण क्षमता 90.60 लाख मीं टम थी। निगम की भण्डारण क्षमता प्रति वर्ष घटती बढ़ती रही है परन्तु उनके अपने भण्डारगृहों की क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है। निगम सार्वजनिक निर्माण विभाग से भण्डारण क्षमता किराये पर प्राप्त करता है और उसकी कुल भण्डारण क्षमता में उच्चावचन किराये के भण्डारण क्षमता एव खुले ज्लिंथ भण्डारण के कारण ही रहा है। राज्य भण्डारण निगम के लिए यह एक सुखद स्थिति है कि उसकी स्थिती मिंत भण्धारण क्षमता लगातार बढ़ रही है जबकि किराये की एव खुले ज्लिंथ की भण्डारण क्षमता लगातार कह रही है जबकि किराये की एव खुले ज्लिंथ की भण्डारण क्षमता ने जा रही है।

वर्ष 1990-91 में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा एव तमिलनाडु के राज्य भण्डारण निर्मम विभिन्न कारणों जैसे- लेखी को अन्तिम रूप न दिया जाना, लेखा परीक्षकों की देरी से नियुक्ति के कारण अपनी वार्षिक बैठके न कर सके। मेघालय के अतिरिक्त सभी राज्य भण्डारण

निगमों की, जिनकी वार्षिक साधारण सभा वर्ष 1990-91 के दौरा। हुई ने ताम दर्शाया एवं सात राज्य भण्डारण निगमों ने लाभाशं 0 5 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक घोषित किया जिससे केन्द्रीय भण्डारण निगम को पिछंदों वर्ष 123 50 लाख रुपये के राशि की तुलना में इस वर्ष 47 53 लाख रुपये लाभाश प्राप्त हुआ। इस वर्ष में कुछ राज्य भण्डारण निगमों द्वारा मुख्य रूप से वार्षिक साधारण सभा न करने के कारण केन्द्रीय भण्डारण निगम के लाभाश राशि में गिरायट आयी। राज्य भण्डारण निगमों के लाभ में गिरायट व्यापार राम्बन्धी एवं पाउनिक आपदाओं जैसे- बाद एयं सुरग्ना इत्यादि के कारण आयी।

नर्ष 1992 असे 13 राज्य भण्डारण निगमों ने अपनी वार्षिक साधारण बैठके की। इनमें से मेघालग तथा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम ने हानि दिखायी तथा लाभाश घोषित नहीं किया। पजाब राज्य भण्डारण निगम ने यद्यपि लाभ होने की सूचना दी फिर भी लाभाश घोषित नहीं किया। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्मींटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बगाल वार्षिक साधारण बैठकों के सम्बन्ध में संवैधानिक अपेक्षाए पूरी नहीं कर पाये। केन्द्रीय खाद्य सचिव ने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस मामले को उठाया भी। निगम ने राज्य भण्डारण निगमों की पूँजी में वर्ष 1992–93 में 176 36 लाख रूपयें की और निवेश किया फलस्वरूप सम्पूर्ण निवेश 31 मार्च-1993 को बढ़ कर 4201 57 लाख रूपये हो गया। इस वर्ष में केन्द्रीय भण्डारण निगम ने इस निवेश पर कुल 105 76 लाख रूपये का लाभांश अर्थित किया।

# (स) निगम की अन्य गतिविधियाँ -

केन्द्रीय भण्डारण निगम की अन्य गतिविधियाँ निम्नवत् है-

1 निर्माण कार्यक्रम — भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के बीच 29 फरंबरी 1980 को हुए त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत, केन्द्रीय भण्डारण निगम, भारतीय खाद्य निगम की और सं गोदामों का निर्माण करेगा जिसके लिए प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 1 1 ऋण समता के अनुपात पर पूरा वित्त दिया जायेगा एव केन्द्रीय भण्डारण निगम भारत संस्कार को निर्धारित एण की ब्याज सिक्त किश्तों के भुगतान के लिए भारतीय खाद्य निगम की देयता को यहन करेगा। 15 वर्ष पश्चात् रेलवे साइडिंग तथा अन्य सुविधाओं सिहत इन गोदामों का पूर्ण स्वामित्व केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा पहले ही चुकायी गर्यी राशियों को घटाकर द्वासित मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम से भण्डारण निगम के पास पहुँच जायेगा। इसी नीति के तहत् केन्द्रीय भण्डार निगम ने वर्ष 1990—91, 91—92 तथा 92—93 में क्रमशं 0 76, 1 27 तथा 0 81 लाख टन क्षमता के भण्डारगृहों का निर्माण 15 96, 23 44 तथा 21 76 करोड रुपये की लागत से पूरा किया।

निगम ने संरम्थाओ और सरकारी निकायों की ओर से जमा कार्यों के रूप में विभिन्न प्रकार के भण्डारगृहीं पूर्व अन्य ढाँचों के डिजाइनिंग तथा निर्माण कार्य को अपने हाथ में लिया है। इसकी विशेषज्ञता

का लाभं दो सहकारी संस्थाओं अर्थात् गन सी सी एफ तथा सुपर बाजार ने उठाया है। एन सी सी एफ में नागप्र कें समीन हीगना में अपने पिसर का निर्माण कार्य केन्द्रीय भण्डारण निगम को सौपा। सुपर बाजार, मई विल्ली ो पालम में सुपर बाजार बिल्डिंग के निर्माण का कार्य केन्द्रीय निगम को सौपा है। निगम आई जी एस आई हापुड के लिए स्टाफ क्वार्टर एवं अन्य आधारभूत इमारतों का भी निर्माण कर रहा है। निगम के पर्तमान अध्यक्ष श्री के एस रेड्डी ने बताया है कि निगम वेश में 50 से 100 टन क्षमता बार्ष कई और कोल्ड स्टोरेज भी खोलेगा। इस सन्दर्भ में व्यापार योजना बनाई जा रही है। 44

2 गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण — पिछले वर्षों में निगम ने अपने भण्डारगृहों में स्टॉक के गुणवत्ता नियंन्त्रण एवं परिरक्षण के ऊँचें मानक स्थापित करने में अच्छा नाम कमाया है। निगम भण्डारगृह सुविधाओं के प्रयोगकर्ताओं को गुणवत्ता का आश्वासन तथा ग्राहकों को सन्तुष्टि प्रवान करता है। भण्डारगृह में रखें गये गाल की बाजार में कीमत के अनुसार गुणवत्ता बनाये रखने के लिए भण्डारण प्रक्रिया सहिताओं को पूरी तरह लागू किया गया है। इस दिशा में किये गये उपायो तथा उनकी प्रगति को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है—

तांलिका सख्या 45 गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण के लागू किये गये उपाय एव उनकी प्रगति

क्रं सं	विवरण	वर्ष	1990-91	1991-92	<b>19</b> 92-92
1	ममूमी की सख्या जिनका विश्लेषण				
	एवं ग्रैंड निर्धारण किया गया		70,028	72,050	68,834
2	स्टाँक जिनका रोग रोधी उपचार हु	आ(मिलियन बोरे)	552 06	512 65	401 39
3	स्टॉक जिसका प्रधूमन किया गया	****	58 26	63 83	42 49
4.	संगरोध प्रधूमन	1111	4 46	3 48	5 71
5	प्रधूमित किया गया भण्डार स्थान	(क्यूबिक मीटर)	4440	26,000	5,601
6	भण्डारण क्षतियाँ	(प्रतिशत मे)	0 35	51	43

म्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, होजखास, नई दिल्ली

इस प्रकार निगम भण्डारित वस्तु मे उचित गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण एव ग्रेड निर्धारण करता है। यह विभिन्न कीटनाशक दवाओं से स्टॉक का रोग रोधी उपचार तथा प्रधूमी का कार्य भी करता है, जिससे भण्डारण अविध में वस्तुओं के गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न और भण्डारण की क्षित को न्यूनतम किया जा सके। निगम ने खाद्यान्तों में होने वाली भण्डारण भितियों पर नियम्ब्रण रखा है। प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 1992-93 में पिछले वर्ष की

<sup>44</sup> मवभीरत टाइम्स-नई विल्ली, 30 सितम्बर, 1994

भण्डारणं क्षिति 51 पतिशत की तुलना में 43 प्रतिशत ही रह गई। यह िगम की वैज्ञानिक परिरक्षण में प्रिप्त की ग्रंथी सफलता का द्योतक है।

इसके अतिरिक्त निगम ने भण्डारगृहों में वस्तुओं की सुरक्षित सभाल एव भण्डारण के लिए भण्डारण प्रृक्तिया सिहताएं तैयार की है। वर्ष 1991-92 में 10 और नयी वस्तुओं के लिए, जो कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक वस्तुए है, की भण्डार प्रक्रिया सिहताए बनायी गयी। इस प्रकार मार्च 1992 तक 229 वस्तुओं के लिए भण्डारण प्रक्रिया सेहिताए तैयार की जा चुकी थी।

3 किसान एवं कीटनाप्रक विस्तार सेवा योजना - किसानो को वैज्ञानिक भण्डारमृहों के लोभों सै अवगत कराने, भण्डार मृहों की रसीदों को गिरवी रखकर ऋण लेने में उनकी सहायता करने तथा उनके अपने गोदामों में स्टॉक के परिरक्षण के उपायों के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए निगम ने वर्ष 1977 - 78 में किसान विस्तार सेवा योजना प्रारम्भ की थी। निगम द्वारा किसानों के लाभ के लिए इस प्रीत्साहम यौजना पर धन पूरी तरह से अपने ससाधनों द्वारा लगाया जा रहा है। वर्ष 1990 - 91 के दौरान इस योजमां के अधीन 10 नये केन्द्र शामिल किये गये। इन केन्द्रों के साथ किसान विस्तार सेवा योजना का कार्य 185 भण्डार गृहों के माध्यम सेसम्पन्न हुआ। इस वर्ष में निगम के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा 5442 गौवीं का दौरा किया गया और 90,087 किसानों को फसल के बाद होने वाली क्षतियों को कम करने एवं वैज्ञानिक भण्डारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिक्षित किया गया। इन दौरों के दौरान तकनीकी कर्मचारियों द्वारा 510 प्रदर्शन भी किये गये जिनके द्वारा 27354 बोरों तथा 8679 वर्ग मीटर खाली स्थान का निर्मेधात्मक उपचार किया गया एव इसके अतिरिक्त 2,771बोरों को प्रधूमित किया गया। सम्पर्क स्थापित कंगे के परिणामस्वरूप कृषकों ने भण्डारगृहों में कृषि उत्पाद के 1 28,405 बोरे भी वर्ष 1990 - 91 में जमा करवाए।

वर्ष 1992-93 में पिछले वर्ष के 196 भण्डारगृहों की तुलना में 200 भण्डारगृहों के माध्यम से इस योजना को चलाया गया। योजना के अधीन 5019 गावों का दौरा किया गया तथा 1,01,613 किसानों को शिक्षित किया गया। इस आदान-प्रदान के कारण कृषक समुदाय ने कृषि उत्पाद के 2 08 शिख बोरे विभिन्न भण्डार गृहों में जमा कराये। कीटनाशक विस्तार सेवा योजना के अधीन निगम अपने ग्रीहकों को उनके भण्डारण स्थानों पर ही कीटनाशक सेवाए उपलब्ध कराता है। इस योजना के अधीन कर्ष 1992-93 में निगम ने पिछले वर्ष की 33 244 लाख रुपये की आय की तुलना में इस वर्ष 42 21 शिख रुपये अर्जित किये।

4 <u>अनुसंघान एवं विकास कार्य</u> निगम द्वारा विकसित की गई आधुनिक भण्डारगृहो की डिजाइतिंग एवं निर्माण में विशेषज्ञता को एन सी सी एफ एव सुपर बाजार को उनके काम्पलेक्सो के

निर्माण एवं डिजाइनिंग हेतु उपलब्ध करयाया गगा। बांण्डेड भण्डारगृहों के परिचालन में महसूस की गई परिचालन समस्याओं एवं अडसनों के निराकरण के लिए निगम का अनुसन्धान एन विकास विभाग अपने बांण्डेड भण्डारगृहों में एक समान पद्धित विकासित कर रहा है। भण्डारगृहों में वांन्कुलर ट्रैफिक में तीव्रता की सगस्या एवं परिसर के अन्दर तथा बाहर भीड—भाड को कम करने की सगस्या का अध्ययन कर विकासित पद्धितियों को भली—भाँति अपनाया जा रहा है तािक ट्रैफिक के आने जाने में बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिस्कित निगम ने गृड के भण्डारण की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए परिवेशी तापमान के अन्तर्गत गृंह भण्डारण की तकनीक के विकास के अध्ययन का कार्य हाथ में तिया है। निगम द्वारा देश में शीत भण्डारण कमता का बढाने के उद्देश्य से कुछ केन्द्रों का सर्वेक्षण किया गया है एवं व्यापारिक सम्भावनाओं का पता भी लगाया जा रहा है।

5 गेहूँ की खरीव — केन्द्रीय भण्डारण निगम ने छोटे पैमाने पर वर्ष 1992-93 से गेहूँ की खरीव भी शुंक की है। उसने गेहूँ खरीव का कार्य अभी केवल तीन राज्यों— तत्तर प्रदेश, बिहार एव राजस्थान में ही किया है। यद्यपि इससे निगम की आय में कोई विशेष योगवान नहीं मिला तथापि इससे भविष्य मैं और कारोबार बढने की सम्भावना है।

# (द) निगम की समस्याएं एव सुझाव -

विगत वर्षों से भिगम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुं। भारत के राजकीय व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिक्य के रूप में उपलब्ध मेंस्तुओं की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को उसकी आवश्यकता एवं उपभोग के समय तक सुरक्षित रखंना और म केवल सुरक्षित रखना बल्कि उसके लिए कम से कम लागत पर अधिकतम सुविधाए प्रदान करना किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए एक सराहनीय प्रयास है। निगम वस्तुओं को अपनी भण्डारगृहों में रखकर उनकी समय उपयोगिता में वृद्धि का पुनीत कर्तव्य पूरा करता है। इससे राजकीय व्यापार में लंगी अन्य एजेन्सियों जैसे—भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार मिगम आदि के साथ—साथ सरकार की प्रायोजित संस्थाए, सहकारी समितियों तथा सामान्य कृषकों को अपने आवश्यकता के अतिरिक्त खाद्यान्ना तथा अन्य वस्तुओं के भण्डारण की सुविधा प्राप्त होती है। परन्तु अन्य राजकीय अभिकरणों की तरह ही यह निगम भी समस्याओं से रहिन नहीं है। निगम की समस्याएं एवं तत्सम्बन्धी सुझावं निम्नवत् है—

\* निगंग की भण्डारण क्षमता में वृद्धि के बावजूद प्रयुक्त क्षमता में कगी — यदि निगम की स्विनिर्मित भण्डारण क्षमता का अवलोकन किया जाय तो इसमें गत वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी कुल भण्डारण क्षमता में उच्चावचन का प्रमुख कारण किराये पर प्राप्त की गयी भण्डारण क्षमता मे

उच्चावनन है। रवनिर्मित भण्डारण क्षमता में की गयी वृद्धि इसिलए अनार्थिक प्रतीत हो रही है क्योंकि निगम मी प्रयुक्त भण्डारण क्षमता कम हो रही है।प्रयुक्त क्षमता में कमी वर्ष 1991-92 के दौरान 5 प्रतिशत मधा 1992 93 के दौरान पून 6 प्रतिशत की कमी हुयी है जिसे उचित रही कहा जा सकता।

यह नो रान्तोष का विषय है कि निगम किराये पर पाप्त करने वाली भण्डार क्षमता में कमी करके अपनी रविनिर्मित भण्डारण क्षमता को बढ़ाने में लगा है परन्तु अपार पूर्णी निवेश से स्विनिर्मित भण्डारण क्षमता अथवा किराये पर प्राप्त की जाने वाली भण्डारण क्षमता यदि अपयुक्त रूप में खाली पड़ी रहती है तो यह निगम को हानि पहुँचाने का माध्यम बनती है। इसलिए निगम को चाहिए कि वह स्विनिर्मित भण्डार क्षमता को बढ़ाने का कार्य निरन्तर जारी रखे तथा अपने रांसाधनों का विस्तार करे, किन्तु किराये पर प्राप्त की जाने वाली भण्डारण क्षमता माँग अथवा आवश्यकता के अनुरूप ही प्राप्त की जाय। इसरी किराये के रूप में चुकाये जाने वाली धनराशि की बचत की जा सोजी तथा ऐसे भण्डारगृहों का अन्य अपने रांसाधनों हो सकेगा।

\* प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव समाली गयी क्षमता में कमी — निगम के वित्तीय मिष्पादम में सम्बन्धित समको के अवलोकन से रपष्ट होता है कि वर्ष 1992-93 में प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव प्रति कर्मचारी वर्ष के दौरान सभाली गयी क्षमता दोनों में अधिक कमी आयी है। इसका कारण मिगम की सकल प्राप्ति में कमी होना है क्योंकि कर्मचारियों की सख्या गत वर्षों में बहुत अधिक घटी-बढी नहीं है। सकल प्राप्ति में कमी का कारण अधिकारीगण आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप राजकीय व्यापार में लगी एजेन्सियों द्वारा किये गये कारोबार में कमी को बताते हैं। परन्तु निगम के निजी जमाकर्ताओं की संख्या में भी गिरावट आयी है जबिक सीमा शुल्क नियन्त्रणों में कमी करने अथवा हटाने से निजी जमाकर्ताओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी। इसका एक कारण यह भी हो शकता है कि निगम निजी जमाकर्ताओं के साथ उत्ति यवहार एवं उचिन गुणवत्ता बनाये ग्याने का वाछनीय प्रयास न कर पा रहा हो।

अत निगम की अपनी सकल प्राप्तियों को बढाने का प्रयास करना होगा क्योंकि प्रति कर्मचारी संभाली गयी क्षमता एव सकल प्राप्ति तथा निगम के कर्मचारियो पर व्यय, कर्मचारियो की सख्या से प्रत्यक्षता। जुडे हुए हैं। इसलिए कर्मचारियो की सख्या पर नियन्त्रण भी आवश्यक है। निगम को उसकी सकल प्राप्ति मे आयी कमी के कारणो की गहन जाँच करानी चाहिए और उस पर नियन्त्रण करना चाहिए।

\*मण्डारगृहीं से आय मे कमी — वर्ष 1990—91 से निगम की आय लगातार कम होती जा रही है जंबों कि निगम के प्राप्ति के अन्य साधन जैसे— ऋण एव अग्रिम पर ब्याज, पोर्टफोलियो योजना के अन्सर्गित वैंकों मे जमा पर ब्याज, एजेंक्सी कमीशन, महाराष्ट्र सरकार की ओर से संभाल प्रचालनो से

आय, पंजाब राज्य भण्डार निगम के सयुक्त उद्यम रो उत्पन्न भाग तथा अन्य आयो में लगातार वृद्धि होती रही हैं।अर्त निगम के लिए यह एक चिन्ता का विषय है।

निगम के भण्डारगृहों रो होने वाली आय को बढ़ाना होगा और इसमें वृद्धि तभी होगी जब निगम अपनी भण्डारण क्षमता का पूरा—पूरा उपयोग तथे। भण्डारण क्षमता का पूरा—पूरा उपयोग तभी हो सकेगा जब समस्त कर्मवारी भी अपनी पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करते हुए भण्डारगृहों को आधुनिक तकनीकों से सुसम्जित करने में अपना योगदान करें और जमाकर्ताओं को हर सम्भव सुविधा प्रदान करें। इसके लिए निगम को भण्डारित की जाने वाली वस्तुओं में होने वाली गुणात्मक एवं मात्रात्मक क्षिति को भी न्यूनतम करना होगा।

\* िगग के स्थापना व्यय एवं परिचालन व्यय इत्यादि अनियन्त्रित - केन्द्रीय भण्डार निगम अपने स्थापना व्यय एवं परिचालन व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं रख पा रहा है। स्थापना व्यय में वृद्धि का कारण ग्रेच्युटी, बोनस एवं सन्दिग्धं ऋणों के लिए अधिक धन का प्रावधान करना आदि जैसे कारण रहे हैं। जबकि परिचालन व्यय में वृद्धि का कारण कर्गचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि यात्रा शस्तों में वृद्धि, मजदूरी एवं रखं-रखाव के व्ययों में वृद्धि के अतिरिक्त किराया दर और कर छपाई एवं रोखंग सामग्री के व्यय इत्यादि में बड़ी तेजी से हो रही वृद्धि है।

वास्तव मे इन व्ययों में वृद्धि को रोका तो जा ही नहीं सकता, हाँ, इनकी वृद्धि दर में कमी अवश्य की जा सकती है और वह एक ऐसी दीर्घकालीन गीति के तहत् जिसमें प्रारम्भ में व्ययों के बढ़ने की भी सम्भावना है। निगम को इन व्ययों में नियन्त्रण हेतु स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण की योजना लागू करना भिष्टिए इससे अनावश्यक कर्मचारियों की भीड में कमी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कार्य को देखते हुए यदि कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक ही है तो नव-नियुक्त कर्मचारी अधिक कार्यक्षमीतों के साथ ही कम बेतन पर अपनी सेवाए प्रदान करेगा, जो कि किसी भी बेतनमान की प्रारम्भिक अवस्था में होंने के कारण बेतन भत्तों पर होने वाले व्यय में कमी जायी जा सकेगी।

परिचालन व्ययं में कमी लाने हेतु प्रशिक्षित जन शक्ति, नवीनतम तकनीक पर आधारित मशीनें हाथा विवेकीकरण पर आधारित भण्डारण प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है। भण्डारगृहों में उपलब्ध स्टाक भी संगणना हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करना आवश्यक है।

\* राज्य भण्डार निगमों में किये गये निवेश से सन्सोषजनक उपार्जन नहीं — केन्द्रीय भण्डारण मिंगमं, रिज्य भण्डारण मिंगमं की 50 प्रतिशत समता अंश पूँजी में विनियोजन करता है। राज्य भण्डारण निगमों में लंगातार अपनी संख्या एवं स्विनिर्मित भण्डार क्षमता वोनों में वृद्धि की है। लेकिन केन्द्रीय भण्डारण निगम को हैन निगमों में किये गये समता पूँजी निवेश के प्रतिफल के सन्दर्भ में लाभाश का प्रतिशत वर्ष 1989-90 में 1992-93 के बीच क्रमश 3 53, 1 27, 4 12 तथा 2 52 रहा। लाभाश की ये

वरे समग्र पूँगी निनंग को वेखते हुए बहुत कम है। यहापि राज्य भण्डारण निगम () 5 प्रतिशत से लेकर , प्रतिशत तक लाभाश घोषित करते हैं परन्तु कई निगमो द्वारा समय से अपनी वार्षिक बैठके न करने साथ ही कई निगमो में लाभ होने पर भी लाभाग घोषित न करने तथा कुछ निगमों के कारोबार में हानि होने से भी केन्द्रीय भण्डारण निगम को उसके निवेश पर पर्याप्त उपार्जन नहीं हो पाता। फलस्वरूप इससे केन्द्रीग भण्डारण निगम का लाभ पभावित होता है। तर्ष 1992-93 में मेघालय तथा उत्तर प्रदेश के निगम हानि पर चल रहे थे। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल राजस्थान उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बगाल के राज्य भण्डारण निगम अपनी वार्षिक साधारण सभा की सवैधानिक व्यवस्था पूरी नहीं कर सके जिसमें लामाश की घोषणा नहीं हो पायी।

अत सभी राज्य भण्डारण निगमों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय से स्पष्ट एउ कि निर्वेश, समय से वार्षिक साधरण सभाए करने के सम्बन्ध में दिये जाने चाहिए इससे केन्द्रीय भण्डारण निगम को मिलने वाले लाभाश में स्थिरता आयंगी। राज्य भण्डारण निगमों को भी उन सुझावों का अनुपालन करना चाहिए जो कि कन्द्रीय भण्डारण निगम की आय बढाने के सम्बन्ध में दिश गये हैं। राज्य भण्डारण निगम राज्य की स्थानीय परिस्थित , आवश्यकता एवं विभिन्नता से अधिक परिचित होते हैं।अत उन्हें अपने निगम की रोवाएं राज्य की निजी एवं सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित कर न्यूनतम लागत में अधिकतम मात्रा में प्रवान करनी चाहिए।

\* निगम के लाभवायकता एव लाभांश में और सुधार की आवश्यकता — निगम की लाभवायकता एव लाभांश, वर्ष 1990—91 तक सन्तोषजनक रहा है इसमे एक स्थिर गति से वृद्धि होती आ रहीं थाँ परन्तु इसके बाव के वर्ष 1991—92 तथा विशेष रूप से 1992—93 में इसमें काफी कमी आ गयी और नियोजित पूँजी पर प्रत्याय 12 2 से पटककर 6 5 में आ गया। वास्तव में इस वर्ष का कारोबार कुछ ती व्यापारिक वंशाओं तथा कुछ प्राकृतिक आपवाओं जैसे— बाढ एवं सूखा इत्यादि से प्रभावित रहा जिसके कारण लाभ की दर में इतनी अधिक कमी आयी। इसी प्रकार से लाभांश भी एक स्थिर गति से धीरे—धीरे बंद्रकर वर्ष 1991—92 में 12 5 प्रतिशत पर पहुँच गया था जो 1992—93 में पुन 7 प्रतिशत की वर भी बनाये रखने के लिए निगम ने गत वर्ष की तुला में इस वर्ष 3317 लाख रुपये के स्थान पर केवल 486 लाख रुपये ही प्रारक्षित किये।

निगम को अपना लाभ एव लाभाश दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके लिए उसे निम्न प्रयास करने चाहिए-

-- निगम को अपने साभान्य व्ययो पर नियन्त्रण करना चाहिए तथा परम्परागत क्षेत्रो के कारोबार मैं वृद्धि करनी चाहिए साथ ही साथ अपरम्परागत क्षेत्रो में भी अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए।

- -- फलो एन सब्जियों के भण्डारण व्यवस्था में पृद्धि करने हेतु गार अधिक कोल्ड स्नोरंज बनाये जाने चाहिए ताकि किसानों को आलू तथा अन्य सब्जियाँ रखने की सुविधा पाप्त हा सके।
- --- कटेनर ढुलाई स्टेशनो रो निगम को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावना है अत इनकी संख्या को जो वर्तमान में 12 है, से बढाकर 20 तक कर देना चाहिए। मुख्य रूप से सूरत काण्डली, उंवयपुर, नारिक तथा कोटा जहाँ के लिए कटेनर ढुलाई रटेशन स्थापित करने का अनुमोदन मन्त्रालय द्वारा मिल चुका है, उनकी स्थापना में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।
- -- निगम ने गेहूँ की खरीद का कार्य जो छोरे पैमाने पर शुरू किया है उसमे और वृद्धि की जानी चाहिए साथ ही साथ अन्य खाद्यान्नों की खरीद एवं भण्डारण तथा न्युल बाजार में कीमनों में चृद्धि की दशागे निजी व्यापारियों को ही भण्डारित मात्रा का निर्गमन कर निगम अपने लाभों को और अधिक बढ़ाने में सफल हो सकता है।

यद्यपि निगग ने उपर्युक्त उपायों को लागू करने का प्रयास भी किया है जिससे रामाप्त वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान निगम ने अपने कारोबार व लाभ में शानदार वृद्धि की है। इस अवधि में निगम में 124 करोड़ रुपये का कारोबार करके 29 8 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है तथा बढ़े हुए लाभ पर निगम में 9 पित्रशत लाभांश देने की घोषणा की है। 45 परन्तु इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवध्यकता है।

- \* गण्डारित वस्तुओं के गुणवत्ता नियन्त्रण एव परिरक्षण में पर्याप्त रुचि नहीं निगम के अधिकारी धवं कर्मचारी भण्डारित वस्तुओं के गुणवत्ता नियन्त्रण एवं परिरक्षण में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं। इसी कार्रण से निगम के भण्डारण क्षतियाँ बढ़ी है यदि प्रतिशत के रूप में देखें तो वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में ये क्षतियाँ क्रमश 0 35, 0 51 तथा 0 43 प्रतिशत रही। यद्यपि ये भण्डारण क्षंतियाँ भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण एवं गार्गस्थ क्षतियों रो कम है किन्तु फिर भी इन्हें निम्म प्रयस्थि से और कम किया जाना चाहिए—
- -- माल की छीजन को गेंकने अथवा कम करने के लिए बोरो को लादने एव उतारने में मशीनों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो हुको का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए।
- --- निगम द्वारा कैप भण्डारण क्षमता का प्रयोग केवल अपरिहार्य **दशाओं** में किया जाना चाहिए।
- -- नमूनो के विश्लेषण एवं वस्तुओं के ग्रेड निर्धारण में आ रही गख्यात्मक कमी से निगम को बंचना चाहिए।

<sup>48</sup> नवभारत टाइम्स-मई विक्ली, 30 सितम्बर, 1994

-- मण्डारित वस्तुओं के रोग रोधी उपचार, स्टाक का प्रधूमन और भण्डार स्थान के प्रधूमन में गत वर्षों में जो कमी आयी है उसे दूर किया जाना चाहिए जिससे मण्डारण में में रही शितियों में कमी की जा सके।

1

- निगम को और अधिक वरत्ओं के सम्बन्ध में भण्डारण प्रक्रिया सहिता निर्धारण कर ॥ चाहिंग जो मार्च 1000 तक केवल 220 वरत्ओं के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी थी। भण्डारण प्रक्रिया सहिता का न केवल निर्धारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका कडाई में अनुपालन भी आवश्यक है।
- भण्डारण क्षतियों को नियम्त्रित करने के लिए आवश्यक है कि स्टॉक मूल्याका एवं नियम्त्रण की नवीन विधियाँ उपयोग में लायी जाये ताकि क्षण—प्रतिक्षण स्टॉक में रखी गई वस्तुओं की बिना उनका भौतिक सत्यापन किये जानकारी की जा सके और समय—समय पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था भी की गानी चाहिए।

2स प्रकार उपर्युक्त उपायो को अपनाकर भण्डादण क्षितियो को न्यूनतम किया जा सकता है।

\* किसानो द्वारा भण्डारगृहों का प्रयोग बहुत कम - केन्द्रीय भण्डारण निगम अथवा राज्य भण्डारण निगम के भण्डार गृहों का प्रयोग किसानों के द्वारा वाछित मात्रा में नहीं िक्तया जा रहा है जबिक उन्हीं के द्वारा उत्पादित खाद्यान्न अथवा फल, फूल एव सब्जियाँ विभिन्न मध्यस्थों के द्वारा खरीद कर भण्डारित की जाती है और भण्डारण की सुविधा का लाभ उठाया जाता है। फलस्वरूप कृषकों को उनकी उपजे को पीर्यान्त मूल्य नहीं मिल पाता।

इस समस्या के निराकरण हेतु किसान एवं कीटनाशक विस्तार सेवा योजना को और अधिक बंडे पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए तथा किसानो को वैज्ञानिक भण्डार विधियों से अवगत कराया जाना चाहिए सीथ ही इन विधियों का प्रदर्शन कर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। यदि उन्हें निगम द्वारा अपनी भी श्वारण प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा तो किसान स्वत अपने आधिक्यों को भण्डारगृहों में रखने के लिए तत्पर होंगे और भण्डारण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

\* <u>शासकीय अभिकरणों की अन्य समस्याएं</u> — जिस प्रकार भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम या सार्यजनिक वितरण प्रणाली जैसी व्यवस्थाओं में कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, नौकरशाही, क्यार्य में अभिग्नेरणा का अभाव, नैतिकता के पतन, अधिकारों के केन्द्रीयकरण, विभागों एवं अधिकारियों में तालमेल क्या अभाव, कार्य के प्रति अरुचि इत्यादि में समस्याए व्याक्त है, उसी प्रकार की समस्याए केन्द्रीय भण्डारण मिर्गम में भी दृष्टिनगोचर होती है।

इन समस्याओं के निदान हेतु कर्मचारियों में कार्य के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय अभिप्रेरणा की विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कर्मचारियों में अतिरिक्त कार्य क्षमता के सूजन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्थी समय-रागय पर की जानी वाहिए। विदेश भण्डार प्रक्रिया रो भी निगम के कर्मचारियों को अवगत कराया जीना चाहिए। कर्मचारियों में कार्य के प्रति निष्ठा ईमानवारी एवं स्वयं की प्रेरणा जागृत कर के लिए अध्यात्मिक प्रिप्रिक्षण जैसे—योग, ध्यान, तैतिक प्रिप्रिक्षण शिविरों का आयोजन समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में चलाया जाना चाहिए। विभिन्न मामलों पर शीघ्र निर्णयन हेत् अधिकारों एवं उत्तरदायित्चों का साथ—साथ विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। विभागों एवं अधिकारियों में ताल-मेल बनाये रखने के लिए त्यरित संचार व्यवस्था एवं समय—रामग पर विभागीय और अन्तर्विभागीय बैठके आयोजित करते रहना चाहिए। जिससे नवीन गतिविधियों एवं भविष्य में आने वाली समस्याओं पर खुले वातावरण में विचार विमर्श कर नीतियों का निर्धरण किया जा सके।

इस प्रकार निगम उपर्युक्त दिग गये सुझावों का अनुपालन कर अपने विकास एवं विस्तार की महत्त्वांकाँकी योजनाओं को पूरा कर सकने में सक्षम हो सकेगा तथा राजकीय व्यापार में लगे अन्य अभिकरणों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन और अच्छे ढग रो कर सकेगा। नि सन्देह केन्द्रीय भण्डारणें निगम देश के उद्धरीकरण एवं वैश्विकीकरण के नये आर्थिक वातावरण का पूरा लाभ उठाते हुए राजकीय न्यापार के आधार स्तम्भ के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

खाद्यान्तो मे राजकीय व्यापार की सफलता का मूल्याकन — खाद्यान्तो मे राजकीय व्यापार यद्यपि मूर्ण कप से सफल नहीं रहा है और इसको आशिक सफलता ही गित पायी है, लेकिन इसमें कोई वी रोय नहीं कि राजकीय व्यापार के निम्न प्रयास सराहनीय है—

- इसमे खाद्याम्मों में मूल्य वृद्धि को रोकने में काफी योगवान किया है।
- खाद्यांन्नी की पूर्ति कम होने की दशा में भी जनता को खाद्यांन्न उपलब्ध कराये गये हैं चोहें भीरी मात्रा में आयात ही क्यों न करना पड़ा हो।
- खाद्यान्नीं में राजकीय व्यापार से कृषक व उपभोक्ता दोनों लाभान्वित हुए है। समर्थित मूल्य मीति ने किसानो को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे जनता को भी खाद्यान्न एंचित मूल्य पर मिलते रहे है।
  - व्यापारी वर्ग कृत्रिम रूप से कमी पैदा करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। परन्तु खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार में कुछ कमियाँ भी है जो कि निम्नवत् है-
- सरकारी कर्मचारी उचित ईमानवारी का परिचय नहीं देते हैं जिनके परिणामस्वरूप सरकार को हानि व उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। वे खाद्यान्न क्रय करते समय तौल में हैरा-फेरी करते हैं एवं निम्म गुणवत्ता के खाद्यान्म भी खरीद लेते हैं।
  - साद्य निगम व सरकार के वितरण व भण्डारण व्यय बहुत ऊँचे होते है जिससे सरकार

व्यवस्था समय-समय पर की जानी वाहिए। निर्वेश भण्डार प्रक्रिया से मी निगम के कर्मचारियों को अवगत कराया जाना चाहिए। कर्मनारियों में कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी एवं स्वयं की प्रेरणा जागृत करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण, जैसे-योग, ध्यान, नैतिक पशिक्षण शिविरों का आयोजन समयबद्ध कार्यकम के रूप में चलाया जाना चाहिए। विभिन्न मामलों पर शीघ्र निर्णयन हेतु अधिकारों एवं उत्तरदायित्यों का साथ-साथ विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। विभागों एवं अधिकारियों में ताल मेल बनाये रखने के लिए स्वरित सेवार व्यवस्था एवं समय-रामय पर विभागीय और अन्तर्विभागीय बैठके आयोजित करते रहना चाहिए जिससे नवीन गतिविधियों एवं भविष्य में आने वाली समस्याओं पर खुले वातावरण में विचार विमर्श कर नीतियों का निर्धारण किया जा सके।

इस प्रकार निगम उपर्युक्त विये गये सुझावो का अनुपालन कर अपने विकास एव विस्तार की महत्वाकाँकी योजनाओं को पूरा कर सकने में सक्षम हो सकेगा तथा राजकीय व्यापार में लगे अन्य अभिकारणों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन और अच्छे ढग रो कर मकेगा। नि सन्देह केन्द्रीय भण्डारणं निगम देश के उदारीकरण एव वैश्विकीकरण के नये आर्थिक वातावरण का पूरा लाभ उठाते हुए राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ के रूप में अपनी अग्रणी भूगिका निभा सकेगा।

खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार की सफलता का मूल्याकन — खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार यद्यपि पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा है और इसको आंशिक सफलता ही मिल पायी है, लेकिन इसमें कोई वौ एांग नहीं कि राजकीय व्यापार के निम्न प्रयास सराहनीय है—

- इसमे खाद्यान्तो मे मूल्य वृद्धि को रोकने मे काफी योगदान किया है।
- खाद्यांन्नी की पूर्ति कम होंने की दशा में भी जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराये गये है चाहें भारी माना में आयात ही क्यों न करना पड़ा हो।
- खाद्यानों में राजकीय न्यापार से कृषक व उपभोक्ता वोनों लाभान्वित हुए है। समर्थित मूल्य नीति ने किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे जनता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलते रहे है।
  - व्यापारी वर्गं, कृत्रिम रूप से कमी पैवा करने मे पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। परन्तु खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार में कुछ कमियों भी हैं जो कि निम्नवत् है-
- सरकारी कर्मचारी उचित ईमानवारी का परिचय नहीं वेते हैं जिनके परिणामस्वरूप सरकार की हानि व उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। वे खाद्यान्न क्रय करते समय तौल में हैरा-फेरी करते हैं एवं निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न भी खरीव लेते हैं।
  - खारा निगम व सरकार के वितरण व भण्डारण व्यय बहुत ऊँचे होते है जिससे सरकार

को अरबीं रुपये की हानि होती है।

खा गा नो अचित मूल्य पर नेचने में सरकार को आर्थिक सहायना अर्थात सब्सिडी देश पड़ती है जो किमान समय में क हजार करोज रुपये तक पर्हें न न्हीं है।

प्रे 1र्ष भर उचित मूल्य के दक्ता है। उपभौक्ता को परेशानी होती है और कभी कभी तो घण्टो लाइन में खड़े रहना पड़ता है।

सरकारी अधिकारियों व व्यापारियों की गाठ गाठ से उचित मृल्य की द्कानों पर खाद्यान्नों की पूर्ति में देरी कर दी जाती है जिससे बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जाते हैं और समाज के प्रत्नेक वर्ग को खाद्यान्नों के ऊँचे गुल्य देने पड़ते हैं।

जीनत मुल्य के दुका।। की संख्या बहुत कम है।

बान्त से खाद्यान्न खुले आसमान के नीचे पड़े रत्ते हैं जिससे उन ही गुणवत्ता कम टो जाती है।

अत खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार को सुदृढ एव प्रभावकारी बना ने के लिए कुछ सुझाव निम्नवत् हैं

- 🛦 सरकार व खाद्य निगम को अपने व्ययो मे कमी करनी चाहिए।
- \* सरकारी अधिकारियो द्वारा उचित ईमानदारी का परिचय देकर पृरी तौल करानी चाहिए।
  तथा निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्न ही क्रय करना चाहिए।
- ४ उचित मूल्य के दुकानो पर पूरे वर्ष भर खाद्यान्न उपलब्ध होना नाहिए जिससे उपभोक्ता को कंभी भी खाद्यान्न खरीदने की छूट हो और उसको घण्टो लाइन में व्यक्तित न करना पडे। वर्ष भर खाद्यांक्त उपलब्ध होने से खुले बाजार में भी खाद्यान्तों में मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी।
- \* उचित मूल्य पर बेचने के लिए जो सहायना सरकार देती है उसके उपयोग पर नियंन्त्रण होनां चाहिए। इससे लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की राज्य सहायता की धनराशि की बचन होगी जिसंको अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है।

\*खाद्यान्नो में राजकीय व्यापार का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक जनसंख्या को खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिल सके। इसके लिए उचित मूल्य की दुकानो की संख्या भी बढायी जानी चाहिए।

\* सरकार द्वारा गोवामो और भण्डारो की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि खाद्यानीं की खले स्थानों में न रखना गडे और उसे खरांब होने से बचाया जा सके।

इस प्रकार खाद्यान्नो मे राजकीय व्यापार मे लगे हुए अभिकरणो की समस्याओ का निदान

प्रस्तत किये गय गुजाजा का अनुपालन कर किया जा सकता है और खाशा जो । भाँग पूर्ति मूल्य एउ गुणवत्ता इत्पादि के सम्बन्ध में उपभोक्ता को होने वाली समस्याओं से छुग्कारा विताया जा सकता है।

## (II) ग्रन्य वस्तुओं में राजकीय व्यापार

सरकार द्वारा खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में भी व्यापार किया जाता है। पारम्भ में तो इन पस्तुओं की सरूया बहुत कम थी लेकिन जैसे गैसे सरकार ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्माठ की बात सोची नैसे-वैसे त्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मरूया में वृद्धि हुई। भारत के आन्तरिक व निदेशी व्यापार को उचित रीति में चलाने के उददेग्य से भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गई। इसी रान्दर्भ में बाद में राज्य व्यापार निगम की सहायता के तिए विभिन्न सहायक संस्थाओं की भी स्थापना की गई। इस प्रकार अन्य वस्तुओं में राजकीय व्यापार को इस कार्य में लगी संस्थाओं के वृष्टिकोण से निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है

- (क) भारतीय राज्य व्यापारे निगम
- (ख) राजकीय व्यापार में संनारत सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेरिसयाँ
- (ग) रानकीय व्यापार एवं न्यभो स्ता सहकारी सीमीतयाँ और
- (ध) रानकीय व्यापार में स्यायत्त शासी संस्थाए।

# (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम -

भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना भारत में राजकीय इंग्रापार की पृष्ठभूमि है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान दा महत्वपूर्ण घटनाए घटी जिनके गारण प्रत्येक वैश्व की सरकार एक व्यवस्थित अभिकरण के माध्यम से वस्तुओं को स्वण खरीदने एवं बेचने की और सोचने के लिए बाध्य हुई। प्रथम, सोवियत सघ द्वारा बनाया गया वह अधिनियम जिससे विदेशी व्यापार पर सरकार का एकाधिकार हो गया तथा द्वितीय 1929 की विश्वव्यापी मन्त्री जिसका ऋणात्मक प्रभाव कृषि उत्पादी एवं रोजगार की स्थित पर बहुत अधिक पडा। द्वितीय महायुद्ध काल में यह आवश्यकता अनुभव की गंगी कि देश में विवेशी व्यापार हेतु एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए। इसका कारण यह था कि विवेश संस्थाएं सामान्यत देश की व्यापारिक नीति के विरुद्ध कार्य कर रही थी। एक स्वायत्त संस्था की स्थापान की विचार सर्वप्रथम' भारतीय व्यावसायिक संघ'द्वारा रखा गया, जो कि भारत में " यू के कामांशियल कारपोरेशन" की गतिविधियों से भयभीत था। यह कारपोरेशन भारतीयों को न केवल निर्यात के लोभों से इंधित कर देता था बल्कि कुछ देशों से व्यापारिक अनुबन्धों को भी प्राप्त नही करने देता था। उनका तर्क यह था कि युद्ध की असगान्य परिस्थित में यदि सामान्य व्यापारिक माध्यम कार्य नहीं कर

राकते तो सरकार को एक भारतीय एजेन्सा उन क्षेत्रा में व्यवसाय के लिए सापित करनी गहिए जिनमें निजी व्यापारी अपनी असमर्गता प्रकट करे भरन्त कई कारणों से इस सुझाव का अनुपालन जहीं शिक जा सका।

इस के पश्चात् वस्ताओं के राज कीय व्यापार का राग्गादा करने के लिए एक स्वायत्त गरंथा की स्थापना करने के तिए कई बार मिन्नन्तरीय समितियाँ सरावीय समितियाँ एवं उप समितियाँ गठित की गयी। जिनमें सर कार के कर्मचारियों, व्यापार प्रतिनिधियों और स्वयसेवी सस्थाओं के विचार लिए गए कि ऐसी संस्था की स्थापना उपयोगी होगी अथवा नहीं, यदि उपयोगी होगी तो ऐसे सगठन की सरचना विषय एवं कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए? पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । अन्ता नवम्नर-1955 में एक ऐसे राजकीय संगटन की स्थापना का पस्ताव स्वीकार कर लिया गया जो गज्य की ओर से वस्त्का के क्रय निक्रय में भाग ले और सरकार का सगाज के पित कर्तयों की पूर्ति में योगदान करे।एक सयक्त पूँजी कम्पनी के खप में मारतीय कम्पनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत भारतीय गज्य व्यापार निगम(पाइवेट) लिमिटेड, का पानकण 18 मई 1956 को हुआ। कम्पनी के नाम में से पाइवेट" शब्द 6 अपेल-1959 की हटा विया गया। वर्तमान समय में इसका नाम 'भारतीय राज्य व्यापार निगम' है। प्रारम्भ में इसकी पूर्वत्त पूँजी 1 करोड रुपये थी जो 1970 में बढकर 15 करोड रुपये हो गयी। वर्ष 1986-87 में इसकी प्रवत्त पूँजी को 15 करोड से बढाकर 30 करोड रुपये कर दिया गया। वर्तमान समय में इसकी प्रवत्त पूँजी को करोड रुपये ही है। वै

(अ) उद्वेष्य — भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना का उद्देश्य " उन वस्तुओ एव पवार्थों की भारत में आयात एव भारत रो निर्यात करना है जिनको कम्पनी निश्चित करे और वे सभी कार्य करना है जो इसके लिए सहायक हो। "47 निगम के ये उद्देश्य मूलक्ष्प में इसके पार्षद सीमानियम में दिये गये हैं। इस प्रकार कम्पनी द्वारा समय समय पर निश्चित की गयी वस्तुओं का आयात एव निर्यात अथवा सामान्य व्यापारिक क्रियाएं करना निगम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके सहायक उद्देश्यों में वस्तुओं के भासान-मिर्यात एवं सामान्य व्यापारिक क्रिया से सम्बन्धित समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अत देश अथवा विदेश में वस्तुओं का क्रंय विक्रय उसके यातायात की ब्यवस्था, व्यापार को बढाने के लिए वैषि एवं अल्पकालीन यौजनाएं बनाना, व्यापारिक क्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करना निगम के राहायक उद्देश्यों में शामिल होगा। कुछ आयातित वस्तुओं की गौंग एव पूर्ति में काफी अन्तर रहता है, अत निगम के माध्यम से सरकार इस मात का प्रयत्न करेगी कि ऐसी वस्तुओं की पूर्ति उचित

<sup>46</sup> वि इंकोमोमिक टाइम्स-नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1990

<sup>47</sup> बीपीर व्यवस्था शर्मा, टी आर एव जैन, एस सी ,साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या-120

मूल्य पर सभी व्यक्तियां को होती रहे। भोधाय की सभी वरता। का वियत त करके कुछ वास व्यक्त वस्तुआ का निर्यात किया गाय। सक्षेप में निगम के मुख्य उद्देश्य कि प्रकार रहे हैं

- । बड़ी गात्रा में पदार्थी का निर्यात सम्बद्धा एवं वि हास करना,
- । वर्तमान बाजारो को बिस्तुन करना एव नये बाजार बनाना
- उ भारत के निर्यात व्यापार के विधीकरण को नताना
- । राजकीय व्यापार करने वाल दशों के साथ त्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना,
- ५ भारी पदार्थों के आयात का भारणीबन्द्र करना,
- ठ देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए आवण्यक पदार्थों की अर-नायी गाँग । पूर्ति के अन्तर को कम करना,
- 7 व्यक्तिगत त्यापार की ऐसी परिस्थितियों में सहायता करना जहाँ उनको व्यापार करने में कठिनाई हो या उनमें भारी प्रतियोगिता हों,
- क्ष मूल्यों के स्थिर करने एनं वितरण हेतु आयात करने अथवा आगात और वितरण दोनों कार्य केन्द्रीय सरकार के आदेश पर करना.
- 9 आयात, निर्यात, आन्तरिक व्यापार या वितरण के सम्बन्ध में दिश गये केन्द्रीय सरकार के आवेशों की पालन करने के लिए विशेष प्रबन्ध करना,
- 10) केन्द्रीय सरकार द्वारा शीपे जाने पर उन पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य- सहायता एव सगीकरण भण्डार क्रियाए करना।

भारत सरकार द्वारा उदार व्यापार नीतियाँ बड़े पैमाने पर लागू की गयी है जिसके परिणांसस्विक्षंप निगम के उद्देश्यों को निग्न प्रकार से पुनर्सशोधित किया गया है

- \* प्रतियोगितात्मक विषव व्यापार क्षेत्र मे निगम को एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे पस्तुत करना।
  - \* निगम मे लगायी गयी पूँगी पर पर्याप्त प्रत्याय सुनिधिनत करना।
- \* शासकीय नीतियों को लागू करने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में काम करना।
- \* निगम को उत्तरवायित्व पूर्ण एव प्रबन्ध में भागदारी की व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर ग जो एक अच्छे जीवन यापन माध्यम के साथ साथ एक प्रभावशाजी कार्य संस्कृति को सुनिश्चित करे।
  - \* लघु एवं कुटीर क्षेत्र को आधारभूत सुविधाएं पदान करना जैसे- उनके लिए कच्चे माल

की आपूर्ति, उनके उत्पादन के विपणन आदि की सुविधाए प्रदान करना। <sup>48</sup>

#### (ब) निगम का सगठन एव प्रबन्ध -

भारतीय राज्य व्यापार निगम का प्रधान कार्यालय टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली में है। प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त वर्तमान समय में देश के भीतर 17 अन्य कार्यालय आगरा, अहमदाबाद, बेगलूर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, गांधीधाम(कादला पोर्ट) गोहाटी गुण्टूर, हैदराबाद, जालधर, लखनऊ, मद्रास, पटना, तूतीकोरन एव विशाखापट्टनम् में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त निगम के 8 कार्यालय विदेशों में स्थिति है जो न्यूर्याक, लन्दन, फ्रैंकफर्ट, मास्को, जिम्बाब्दे, हाककाग, सिगापुर और मेलबोर्न में रहकर निगम की सहायता कर रहे हैं। पिछले 39 वर्षों में निगम के कार्यों में काफी वृद्धि हुई है। अत इसके कार्यों में सहायता देने के लिए कई सहायक निगम भी गठित किये गये, जैसे—परियोजना एव उपकरण निगम, हस्तिशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय काजू निगम, राज्य रसायन एव भेषज निगम, भारतीय कुटीर उद्योग निगम, भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम और भारतीय चाय व्यापार निगम । हाल के वर्षों में भारतीय राज्य व्यापार निगम ओर इसकी सहायक कम्पनियों की स्थिति में कई फेर—बदल किया गया है, जो इस प्रकार है-

- 1 <u>भारत बिजिनेस इण्टरनेशनल लिमिटेड(बी बी आई एल)</u> भारतीय राज्य व्यापार निगम 17 मई 1990 को भारत व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड का अनुषगी निगम बना दिया गया। बी बी आई एल केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक सूत्रधारी कम्पनी थी जिसके अन्तर्गत निम्न चार सहायक कम्पनियो को रखा गया—
  - 1 भारतीय राज्य व्यापार निगम,
  - 2 भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम,
  - 3 भारतीय परियोजना एव उपकरण निगम, और
  - 4 भारतीय मसाले व्यापार निगम। <sup>49</sup>

सूत्रधारी कम्पनी— बी बी आई एल की पूँजी केन्द्र- सरकार, वित्तीय सस्थओ, जनता व कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की जानी थी। इसके अध्यक्ष श्री एस वी एस राघवन ने बताया कि आगे चलकर हिन्दुस्तान हीरा निगम एव हस्तिशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम भी इसके अन्तर्गत आ जायेगे। उनके अनुसार यह सूत्रधारी कम्पनी, सेवा सगठन होगा, न कि नियन्त्रित करने वाली सस्था। सभी सहायक कम्पनियों में अलग-अलग अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक (सी एम डी) होगे। बी बी आई एल का प्रबन्ध एक

<sup>48</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-1991-92, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली

<sup>49</sup> बाजार व्यवस्था-शर्मा, टी आर ,जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या -128

सचालक मण्डल द्वारा होगा जिसमे एक अध्यक्ष व दो पूर्ण कालिक कार्यकारी निदेशक होगे। सभी सहायक कम्पनियां के अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक इसके सचालक मण्डल के सदस्य होगे। यह कम्पनी भारतीय निर्माताओं को बढावा देगी। यह आयात निर्यात तथा सहायक कम्पनियों की व्यापार नीति में समन्वय करेगी तथा उत्पादन सुविधाओं को भी बढावा देगी। 50

परन्तु उपरोक्त गतिविधियां को कार्यरूप दिया जा पाता कि, सरकार ने बी बी आई एल को समाप्त कर देने का निर्णय लिया परिणास्वरूप मूल स्थिति में वापस आते हुए राज्य व्यापार निगम के सारे अश 26 मार्च, 1991 को राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दिये गये। <sup>51</sup> 31 मार्च 1991 को यथास्थिति भारतीय राज्य व्यापार निगम के निम्नलिखित अनुषगी थे-

- भारतीय हस्त शिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम,
- भारतीय काजू निगम,
- भारतीय चाय व्यापार निगम, और
- भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम।
- 2 <u>भारतीय काजू निगम का भारतीय राज्य व्यापार निगम में समामेलन</u> केन्द्र सरकार के पूर्व निश्चयानुसार 31 मार्च-1990 की यथास्थित को लेखा -परीक्षित लेखों के सन्दर्भ में बनाये रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के अन्तर्गत कम्पनी मामलों के विभाग द्वारा भारतीय काजू निगम का राज्य व्यापार निगम में समामेलन अधिसूचना जारी की जाने की औपचारिकताए वर्ष 1990-91 में ही पूरी कर ली गयी परन्तु समामेलन अधिसूचना सख्या-252, दिनौंक 21 अप्रैल,1992 को जारी की गयी जो 31 मार्च-1991 के अकेक्षित लेखों से प्रभावी हुआ। इस प्रकार 31 मार्च 1991 के भारतीय काजू निगम के सचय रुपये 14 61 करोड़ को राज्य व्यापार निगम के 31 मार्च-1992 के सचय में मिला दिया गया। वर्तमान समय में काजू व्यापार की गतिविधियों का सचालन करने के लिए अलग से काजू अनुभाग खोला गया है तथा इसकी शाखा को कोचीन में विकेन्द्रित किया गया है। भारतीय काजू निगम के कर्मचारियों को भारतीय राज्य व्यापार निगम में स्थानान्तरित करने में कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि उन्हें उनके सम्बन्धित सामान्य कैडर प्रदान कर दिये गये।
- 3 भारतीय राज्य व्यापार निगम से अनुषगी कम्पनियों का विलगन भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम और परियोजना एव उपकरण निगम 13 मई, 1991 को भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग हो गये। भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम में

<sup>50</sup> बाजार व्यवस्था-शर्मा, टी आर जैन , एस सी , साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या- 128

<sup>51</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-1990-91, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36 जनपथ, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-12

भारतीय राज्य व्यापार निगम के 7 5 करोड रुपये की सारी साझेदारी राष्ट्रपित (वस्त्र मत्रालय) को नकद भुगतान पर हस्तान्तरित कर दी गयी है। परिणामस्वरूप केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम जो कि हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम का अनुषगी था अब भारतीय राज्य व्यापार निगम का अनुषगी नहीं रहा। वर्ष 1990-91 के दौरान परियोजना एव उपकरण निगम भी राज्य व्यापार निगम से अलग हो गया जबिक परियोजना एव उपकरण निगम की रुपये 1 5 करोड की समग्र साझेदारी सरकार के निर्णय के अनुशरण में एक रुपये के प्रतीक मूल्य पर बी बी आई एल को हस्तान्तारित कर दी गई थी। परियोजना एव उपकरण निगम के अश अब सरकार द्वारा बी बी आई एल बन्द कर देने के निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपित को हस्तान्तरित कर दिये गये है। 52 इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय राज्य व्यापार निगम की केवल एक सहायक कम्पनी भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड रह गयी है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम के पार्षद सीमानियम के अनुसार इसका प्रबन्ध एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। सचालक मण्डल का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति समय—समय पर करते है। इसकी सख्या अधिकतम बारह और न्यूनतम चार होती है, किन्तु सचालक मण्डल की वास्तविक सख्या समय—समय पर घटती—बढ़ती रहती है। 1960 में इनकी कुल सख्या अध्यक्ष सहित 13 थी। 53 जबिक 1992—91 में यह सख्या 12 ही थी। वर्तमान सगठन-चार्ट के अनुसार निगम में एक अध्यक्ष एव प्रबन्ध निर्देशक होगे जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से अनुबन्ध के आधार पर कार्य कर रहे हैं। इनके अधीन पाँच और निदेशक जिसमें दो विपणन निदेशक, एक वित्त निदेशक, एक कार्मिक निदेशक तथा एक कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) के रूप में कार्य करते हैं। निगम में 7 मुख्य महाप्रबन्धक (सी जी एम ) तथा चार महाप्रबन्धक (जी एम) अलग—अलग अनुभागों के कार्यों का निष्पादन करते हैं। वर्ष 1992—93 में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2—ए) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों की कुल सख्या 50 अधिकारियों का मासिक वेतन 12,000रुपयें से अधिक है।

## (स) निगम का कार्य -

ानेगम का मुख्य कार्य विदेश व्यापार करना है। प्रारम्भ मे निगम ने सभी वस्तुओं का आयात—निर्यात किया लेकिन समय—समय पर अलग—अलग कार्यों के लिए अलग—अलग निगम बन जाने के कारण सम्बन्धित निगम का कार्य उनको सौप दिया गया। निगम विदेशों में भारतीय वस्तुओं के बाजारों एवं उनकी माँग की खोज करता है जिससे कि विदेशी व्यापार में वस्तुओं की माँग बनी

<sup>52</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36 जनपथ, नई दिल्ली

<sup>53</sup> सरकार, समाज एव विपणन-मालवीय, एच सी , किताब महल इलाहाबाद-1990, पृष्ठ सख्या-36

रहे। निगमका उददेश्य है कि जहाँ तक सम्भव हो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर होती रहे। इसके प्रमुख कार्य निम्नवत है-

- परम्परागत वस्तुओं के सन्दर्भ में नये—नये बाजारों का सृजन तथा अपरम्परागत वस्तुओं के बाजारों की खोज करना।
  - भारतीय वस्तुओं के विद्यमान बाजारों का विस्तार करना।
  - निर्यात के अवसरो का विविधीकरण।
  - एक निर्यात एव आयात एजेन्सी के रूप मे कार्य करना।
  - विनिमय व बाजार सिन्ध के अन्तर्गत एक व्यापारिक समझौता करना।
  - व्यावसायिक सघ के आधार पर निर्यात व आयात करना।
- एसे विदेशी वयापार को सम्पादित करना जो उद्योग, व्यापार एव समाज के लिए आवश्यक
  - मॉंग एव पूर्ति मे सन्तुलन बनाये रखना।
  - कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के आन्तरिक वितरण की व्यवस्था करना।
- मूल्य-समर्थित क्रियाविधि एव बफर स्टाक के उपायो को अपनाना जिससे कि मूल्यो को स्थायित्य प्रदान किया जा सके।
  - सरकारी नीतियो का लागू करवाने मे सहायता करना।
  - विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुओ का आयात एव निर्यात करना।

बदली हुयी आर्थिक नीतियों के अनुरूप निगम के कार्यों को पुन परिभाषित किया गया है, जिन्हें निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

- 1 <u>निर्यात -</u> भारतीय राज्य व्यापार निगम ने निर्यात सम्बन्धी कार्यों मे निम्न नये आयाम दिये है-
- \* निर्यात की माँग को पूरा करने के लिए उत्पादको को सहायता प्रदान करना जिससे वस्तुओं का उत्पादन माँग के अनुरूप हो सके तथा उत्पादन के मार्ग में आने वाली कठिनाई दूर हो सके, जैसे—कच्चे माल की सुरक्षा, ईधन की उपलब्धता, सचार सुविधाए इत्यादि की व्यवस्था करना।
- \* परम्परागत वस्तुओं के व्यापार को बढाना तथा विश्व में अपरम्परागत वस्तुओं का परिचय कराना जिससे कि भारत को निर्यात के सम्बन्ध में नये—नये बाजार प्राप्त हो सके।
  - \* नयी-नयी विधियो द्वारा एक नये प्रकार से निर्यात सम्वर्द्धन करना।
  - \* पूर्वी यूरोप के देशों में अपनी व्यापारिक योजनाए लागू करना।

- \* विशेष व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत कठिनाई से बिकने वाली वस्तुओं का निर्यात तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात के साथ अतिरिक्त निर्यात की सुविधा देना व उसको सगठित करना।
- \* उत्पादकता का पर्याप्त स्तर रखकर, स्थानीय उत्पादन का स्टाक बनाये रखने में सहायता देना जिससे कि मूल्यों को स्थिर रखा जा सके। ऐसा तभी सम्भव है जब किसी वस्तु की निर्यात सम्भावनाए बहुत अधिक हो, उत्पादन में स्थिरता हो, उत्पादन के लिए आवश्यक ससाधन पर्याप्त हो और स्थानीय उत्पादकों को भी इनकी पूर्ति उचित मूल्य पर उपलब्ध हो।
  - 2 आयात निगम अपने कार्य में निम्न नये-नये आयामों को शामिल करता है-
- \* देश के आर्थिक विकास में आवश्यक वस्तुओं का आयात करना इसमें पूँजीगत वस्तुए, औद्योगिक कच्चा माल और दुलर्भ वस्तुओं का आयात करना।
  - 🗴 उन वस्तुओं का आयात करना जिनकी देश में आवश्यकता है।
  - \* पूर्वी यूरोपियन देशो से विशेष समझौते के अन्तर्गत व्यापारिक योजना का लागू करना।
  - \* तेजडियो को खरीद की अच्छी सुविधा प्रदान कर वस्तुओ का आयात करना।
- \* वस्तुओं के मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करना तथा उनका वितरण उचित ढग से उचित मूल्य पर करना।
  - \* ऐसे देशों से वस्तूए आयात करना जहाँ व्यापार पर सरकार का एकाधिकार हो।
- \* सरकार द्वारा सूचीबद्ध आयातित वस्तुओं का आयात करना ताकि उद्योगों अथवा उपभोक्ताओं को वस्तुओं की आपूर्ति निश्चित मूल्य पर उचित समय एव उचित मात्रा में उपलब्ध करायी जा सके।
  - 3 निर्यात विकास कार्य निगम के नये निर्यात विकास कार्य निम्न है-
- \* अब प्रत्यक्ष निर्यातो(पृष्ठ दर-पृष्ठ सिवदा) के स्थान पर सीधे निर्यातो(खरीदना और बेचना) पर अधिक बल दिया जायेगा।
  - 🗴 पूर्ति के अधिक से अधिक सुनिश्चित/प्रतिबद्ध स्रोतो के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी।
- \* भारत में माल गोदाम व निरीक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा साथ ही विदेशों में किराये पर लिये गये माल गोदामों से बिक्री की योजना बनाना।
- \* निर्यात योग्य व्यापारी वस्तुओं के लिए आई एस ओ 9000 के अनुसार गुणवत्ता वायदा कार्यक्रम शुरू करना।
  - अन्य बातो के बराबर रहते हुए प्रति व्यापार को प्राथिमकता देना।

- \* देश के निर्माताओं को सगिठत करना तथा उन्हें तकनीकी एव वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे निर्यात होने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो सके।
  - \* निर्यातोन्मुखी सगठनो मे भाग लेना ।
  - \* विदेशी व्यापार, मेले एव प्रदर्शनियो का आयोजन करना।
  - \* विदेशों में अपने और नये कार्यालय स्थापित करना।
  - \* निर्यात सहायता योजना को कार्यरूप प्रदान करना।
  - \* गुण एव किस्म नियन्त्रण हेत् मशीनो का विकास करना।
- 4 लघु उद्योगों को निर्यात सहायता छोटे—छोटे लघु उद्योगों के निर्माताओं को उनकी वस्तुओं के बारे में विदेशों में प्रचार—प्रसार, आकर्षक पैकिंग, साख की सुविधा, परिवहन की सुविधा आदि प्रदान करना जिससे कि विभिन्न देशों में उनकी वस्तुओं का निर्यात हो सके।
- 5 <u>आन्तरिक व्यापार</u> कुछ निश्चित वस्तुओं के आन्तरिक व्यापार को अधिग्रहीत करना भी निगम के कार्यक्षेत्र में आता है। वस्तुओं की उचित मूल्य पर पूर्ति हेतु पर्याप्त बफर स्टाक बनाना तथा पूर्ति की स्थिरता के लिए कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद कार्य में सहायता करना तथा ऐसी वस्तुओं की विदेश में माँग उत्पन्न करना।
- 6 <u>व्यापार सम्वर्द्धन समझौता</u> ऐसे देशो मे अपने व्यापार प्रतिनिधियो एव अधिकारियो को भेजना जहाँ से अभी तक नाम-मात्र का ही आर्यात-निर्यात हो पाता है ताकि नये-नये व्यापारिक अनुबन्ध प्राप्त किये जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढाया जा सके।
- 7 <u>अन्य-निगमों में योगदान —</u> आयात-निर्यात हेतु अन्य गठित निगमों जैसे खनिज एवं धातु व्यापार निगम, हम्तिशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम, परियोजना एवं उपकरण निगम, काजू निगम आदि निगमों को समय-समय पर आर्थिक एवं कार्मिक सहायता भी प्रदान करता है। निगम ने आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, इण्डियन रेलवे फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया जैसी सस्थाओं में स्थायी विनियोग भी किया है।

# (द)निगम का प्रमुख व्यापार क्षेत्र-

भारतीय राज्य व्यापार निगम सार्वजिनक क्षेत्र के सुनहरे दिनों में प्रमुख आकर्षण था जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में सरकार की व्यापार भुजाओं के रूप में ऊँचाई को छू रहा था। यह लगातार निर्यात ओर आयात के नये बाजार की खोज में लगा रहा जिससे कि वह देश में बड़े राजकीय व्यापार गृह के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। निगम के व्यापार क्षेत्र को मुख्य रूप में निम्न चार भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है— आयात, निर्यात, स्वदेशी व्यापार एव भारतीय निर्यातको के लिए सेवाए-

- 1 आयात निगम उन वस्तुओं का आयात करता है जिनकी आवश्यकता देश के उत्पादको अथवा उपभोक्ताओं को पड़ती है, जो मुख्य रूप में इस प्रकार है— अखबारी कागज,रबर, वन्यउत्पाद खाद्य एवं वसा तेल रसायन, कृषि वस्तुए, जीवन रक्षक दवाए, थर्मीप्लास्टिक तथा अन्य ऐसी वस्तुए जिन्हें खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्रालय,भारत सरकार द्वारा किसी भी देश से आयात करने हेतु निर्देशित किया जाय।
- 2 निर्यात निगम द्वारा उन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है जो देश में या तो आवश्यकता से अधिक उत्पादित की जाती है अथवा विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु ऐसी वस्तुओं का निर्यात महत्वपूर्ण होता है। गत तीन वर्षों में निगम द्वारा अग्रवर्णित वस्तुओं का निर्यात किया गया दवाए, चीनी, अल्कोहल,शीरा, रसायन,अफीम, चमडे की वस्तुए,चपडा(लाह) इजीनियरिंग एव सरचना सामग्री, सीमेन्ट, सयुक्त उद्यम, सैनिकों की वस्तुए, वस्त्र तथा कपडा, जेम तथा ज्वेलरी, जूट, खेल का सामान, कृषि उत्पाद, सोयाबीन मील/खिलयाँ, कॉफी, चाय, अरडी का तेल, तम्बाकू, चावल, गेहूँ, विविध( जौ एव जई) खाद्य एव उपभोक्ता उत्पाद, ताजा एव प्रसस्कृत खाद्य, फल एव सिक्जियाँ( सूखे मेंवे सिहत) माँस और समुद्री उत्पाद तथा काजू।
- 3 स्वदेशी व्यापार निगम स्वदेशी व्यापार भी करता है जिसमे वह देश—विदेश से वस्तुओं का क्रय करके देश की सीमा में उनके विक्रय का कार्य सम्पन्न करता है। स्वदेशी व्यापार में आयातित कार, रसायनों में खुले सामान्य लाइसेन्स( ओ जी एल )की मदो का आयात, औषधि एव प्लास्टिक टिम्बर, दाले, फलियाँ/बीज ससाधन एवं तेल बिक्री को शामिल किया जाता है।
- 4 <u>भारतीय निर्यातको के लिए सेवाए</u> निगम आयात, निर्यात एव स्वदेशी व्यापार के साथ-साथ भारतीय निर्यातको को निम्न सेवाए भी प्रदान करता है-
- विपणन अवस्थापना अर्थात् विदेश मे वस्तुओं को बेचने के लिए आधारभूत सुविधाए प्रदान करना।
  - व्यापार मेलो व प्रदर्शनियो मे भाग लेना।
- आयातित मशीनरी व कच्ची सामग्री की आपूर्ति जिससे कि निर्यातोन्मुखी वस्तुओ का उत्पादन नियमित रूप से होता रहे। परख सुविधा अर्थात् निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की किस्म, गुणवत्ता, रूप, रग, आकार के शुद्धता की जाँच सुविधा।

निर्यातको को वित्तीय सहायता।

(य) परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य का निगम पर प्रभाव —वर्तमान समय मे विश्व एव भारतीय आर्थिक परिवेश बडी तेजी से बदल रहा है। विश्व के बहुत से देशों में आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का वातावरण बदल गया है। साम्यवादी समूह टूट चुका है, सोवियत सघ अनेक भागों में बँटकर राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर मुक्त बाजार व्यवस्था के लिए रास्ता साफ कर रहा है, साम्यवादी एवं पूँजीवादी, पूर्वी एवं पिश्चमी जर्मनी का विलय हुआ है, चीन में मुक्त बाजार—व्यवस्था का पक्ष स्वीकार किया गया है, लम्बे समय से चल रहे विभिन्न युद्धों ने विश्व आर्थिक चक्र परआश्चर्यजनक दबाव डाला है। सामान्य रूप से पूरे विश्व में एवं विशिष्ट रूप में अमेरिका में मन्दी का दौर चल रहा है। पूरे विश्व के व्यापार दर में 1 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की कमी वर्ष 1991—92 में ऑकी गयी है। <sup>55</sup>

हाल ही में विश्व के कई आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाये एवं प्रावधान परिवर्तित किये गये तथा कई शिक्तशालां क्षेत्रीय व्यापार समूह भी गठित किये गये, जैसे-व्यापार एवं तट कर सम्बन्धी सामान्य समझौता(गैट) यूरोपियन इकोनोमिक कमेटी( ई ई सी )नॉथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट(नाफ्टा) साउथ एशिया प्रीफ्रेन्शियल ट्रेडिंग एग्रीमेन्ट(सेप्टा), एशिया फ्री ट्रेड एरिया(आफ्टा) इत्यादि ने विश्व व्यापार पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। गैट की 1992–93 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व व्यापार में 1992 में पिछले पाँच वर्षों में पहली बार वृद्धि हुई है, इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति पुन सभली है, लैटिन अमेरिका को पुन आयात की शिक्त प्राप्त हुई है, विश्व व्यापार में 1992 में पुन 1991 की तुलना में 1 5 प्रतिशत मात्रात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 1993 में विकसित देशों की आर्थिक बृद्धि दर 2 प्रतिशत रही। इस बीच अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इस वर्ष में और अधिक आर्थिक सुधार की आशा व्यक्त की है। विश्व आर्थिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखकर भारतीय राज्य व्यापार निगम को अपनी भावी रणनीति तय करनी पडेगी।

विश्व में हो रहे आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। भारत के आर्थिक परिदृश्य में हाल ही में बहुत से परिवर्तन आये हैं। अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये का दो बार अवमूल्यन किया गया। अमरीकी डालर की तुलना में जुलाई—1991 में किया गया अवमूल्यन 23 7 प्रतिशत या जबिक मार्च—1991 के अन्त में यह 33 2 प्रतिशत था। बैकर्स एक्सेप्टेस स्कीम एण्ड सप्लायर्स क्रेडिट के अधीन अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण की वापसी के लिए अतिरिक्त लागत पर अवमूल्यन का प्रभाव रुपये 135 करोड़ का पड़ा। खाद्य तेलों तथा वसा अम्ल के लिए अतिरिक्त लागत की वसूली सरकार से की गयी एव अखबारी कागज के मामले में इसकी वसूली अशत उद्योग द्वारा देय अधिभार और अशत बजट सहायता द्वारा की गयी।

<sup>55</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-1991-92, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली,पृष्ठ स0-12

वर्ष 1991-92 मे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास मे कुछ सुस्ती रही क्योंकि वर्ष के दौरान एक तरफ कृषि का उत्पादन कम रहा और दूसरी तरफ औद्योगिक विकास दर मे भी कमी आयी। वर्ष 1991-92 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन भी कम हुआ। अगस्त-1991 मे मुद्रास्फीति की दर 16 7 प्रतिशत के शिखर पर पहुँच गयी जिससे भुगतान सन्तुलन बिगड गया। जुलाई-1991 मे विदेशी विनिमय दर मे समायोजन एव आयातित उत्पादक सामग्री की कमी के प्रभाव ने स्थायी उपभोक्ता क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित किया। वर्ष 1991-92 मे निर्यातोन्मुखी उद्योगों को सोवियत सघ एव अन्य पूर्वी यूरोप के बाजारों में माँग की कमी हो जाने के कारण औद्योगिक मन्दी का सामना करना पडा।

भुगतान असतुलन को ठीक करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न साहिसक कदम उठाये जिसकी शुरुआत जुलाई-1991 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन से हुई। आयात-निर्यात नीति में बहुत से परिवर्तन किये गये। अगस्त-91 में अनेक वस्तुओं को असरणीबद्ध घोषित किया गया, जहाँ तक भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यवहृत वस्तुओं का सम्बन्ध है तो चीनी, अल्कोहल, शीरा, अरडी का तेल का निर्यात तथा वसा अम्ल एव सोडियम बोरेट के आयात को अगस्त-1991 में असरणीबद्ध कर दिया गया है। राज्य व्यापार निगम के अन्तर्गत सरणीबद्ध मदो में अखबारी कागज एक ऐसी मद है जिसे 1 अप्रैल-1992 को असरणीबद्ध किया गया।

28 फरवरी, 1992 को सरकार द्वाराआयात एव निर्यात के मध्य सीघा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए रुपये की आशिक परिवर्तनशीलता की घोषणा की गई। निर्यातको को विदेशी मुद्रा खाता खोलने एव निर्यात मूल्य का 15 प्रतिशत इस खाते से प्राप्त करने की अनुमित दी गयी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा फेरा कानून(फारेन एक्सचेज रेग्युलेटिंग एक्ट) में भी सशोधन किया गया। 34 चुने हुए ऐसे उद्योग जिसमें कि उच्च तकनीक एव वृहत् विनियोग की आवश्यकता थी, में विदेशी विनियोग बढाने हेतु 51 प्रतिशत इक्विटी के भागीदारी की स्वत अनुमित मिल गयी। औद्योगिक नीति में क्रान्तिकारी परिर्वतन किया गया। आर्थिक वैश्विकीकरण में शामिल होने के लिए भारत ने एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम(एम आर टी पी एक्ट) से तमाम नियन्त्रणों को हटा लिया।

इन शासकीय निणर्यों के फलस्वरूप मुद्रा स्फीति की दर जो अगस्त 1991 में 16 7 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी एक वर्ष बाद अगस्त 1991 के मध्य में 8 33 प्रतिशत पर आ गयी। वर्ष 1992-93 के अन्त में यह 7 प्रतिशत तक आयी तथा 10 जुलाई 1993 को यह 5 4 प्रतिशत गिरी जो कि 1987 के बाद की सबसे कम मुद्रा स्फीति की दर अकित की गयी। विदेशी मुद्रा भण्डार 1 अरब डालर से बढकर 20 अरब डालर तक पहुँच चुका है। सम्पूर्ण रूप से आर्थिक विकास दर जो 1991-92 में 1 2 प्रतिशत कम हो गयी थी पुन 1992-93 में लगभग 4 प्रतिशत रही। 56 सरकार के साहसिक कदमों के

<sup>56</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-1992-93, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36 जनपथ, नई दिल्ली

परिणामस्वरूप निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है तथा व्यापार घाटे में कमी आयी है। वर्ष 1993-94 के प्रथम त्रैमास में निर्यात में (डालर के मूल्य में) 27 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गयी है। इन सबका प्रभाव राज्य व्यापार निगम पर भी पड़ा है।

उदारीकृत त्र्यापार नीति के परिणामस्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदली और सरकार की प्राथमिकताए बदलने और सरकार की प्राथमिकताए बदलने के कारण निगम को भी अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पडा। निगम अपनी स्थापना क समय से सरणीबद्ध वस्तुओं के व्यापार में व्यस्त था जिसमें वह एक तेजिंडिये की भूमिका निभा रहा था। खाद्य तेलों को छोडकर अनेक वस्तुओं को असरणीबद्ध कर देने के कारण निगम के सरणीबद्ध आयात निर्यात कारोबार में कमी की आशका के साथ—साथ इसके परिचालन लाभ में भी कमी की आशका थी।

इस स्थिति का सामना करने के लिए निगम ने असरणीबद्ध निर्यातो एव स्वदेशी व्यापार के लिए एक्जिम स्क्रिप्स पर असरणीबद्ध निर्यातो और आयातो को बढाने की योजना बनायी इसके साथ ही निगम ने अपने आप को प्रतियोगितात्मक विश्व व्यापार क्षेत्र मे एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्थान के रूप मे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। अब निगम अपनी लगायी गयी पूँजी पर उचित लाभ कमाने का भी प्रयास करेगा। यह सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीतियो को लागू करवाने मे सहायता भी करेगा। इस प्रकार निगम को आत्मपरीक्षण कर अपने वर्तमान स्वरूप को परिवर्द्धित एव परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उसे अब असरणीबद्ध वस्तुओ के निर्यात—आयात एव स्वदेशी व्यापार पर ही जोर देना है ताकि वह देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नेतृत्व कर सके।

## (र) निगम की व्यापारिक स्थिति -

आरम्भ में निगम अपनी समस्त व्यापारिक क्रियाए स्वय करता था लेकिन अक्टूबर-1963 में खनिज एवं धातु के व्यापार के लिए अलग से निगम बन जाने के कारण खनिज एवं धातुओं के निर्यात का कार्य उसे सौप दिया गया। इसके बाद समय-समय पर निगम के कार्यों को करने के लिए विभिन्न सहायक कम्पनियों एवं निगमों की स्थापना की गयी जो कि समय-समय पर राज्य व्यापार निगम से अलग भी होती रही और वर्तमान समय में तो इसका केवल एक अनुषगी सस्थान भारतीय चाय व्यापार निगम ही है। निगम न केवल निर्यात सम्बर्द्धन का कार्य करता है बल्कि वह विश्व की नयी-नयी अपरम्परागत वस्तुओं जैसे- डिस्पोजल सिरिज, चावल की भूसी, अच्छी किस्म के चावल फल एवं फूल, के सन्दर्भ में जानकारी भी प्रस्तुत करता है। इसकी व्यापारिक स्थिति में हो रही उत्तरात्तर प्रगति का अनुमान अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका संख्या 46 से लगाया जा सकता है-

तालिका संख्या 46 राज्य व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति

(करोड रुपये मे)

वर्ष	आयात	निर्यात	स्वदेशी व्यापार	कुल व्यापार	कर देने से पूर्व लाभ	कुल लाभ अनुपात(%मे'')
1969-70	150 2	55 1	5 40	210 7	16 24	7 7
1976-77	301 0	666 0	8 00	975 0	26 7	2 7
1980-81	1315 0	450 0	15 00	1780 0	_	
1981-82	1290 89	555-4	20 56	1866 85	71 45	3 9
1982-83	1188 23	630 47	13 44	1832 14	62 66	3 4
1983-84	1403 38	796 11	15 54	2215 03	59 83	2 7
1934-85	2119 00	719 56	26 97	2865 53	61 13	2 1
1985-86	2158 38	377 44	15 34	2551 16	61 66	2 4
1986-87	2179 27	542 12	13 88	2735 27	55 42	2 0
1987-88	3036 81	580 99	27 72	3645 52	51 97	1 4
1988-89	2044 92	529 51	19 56	2593 99	40 57	1 6
1989-90	1070 47	751 78	32 99	1855 24	36 78	2 0
1990-91	1332 00	369 00	55 00	1756 00	34 59	1 96
1991-92	610 00	625 00	80 00	1315 00	36 00	2 73
1992-93	324 00	551 00	138 00	1013 00	27 00	2 66

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन- भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1980-81 तक निगम द्वारा किये गये आयात में लगातार वृद्धि होती रही, इसके बाद आयात में पर्याप्त उच्चावचन रहा जबकि सर्वाधिक निर्यात वर्ष 1983-84 में 796 11 करोड़ रुपये का हुआ। वर्ष 1983-84 के बाद वर्ष 1990-91 में निगम का निर्यात सबसे कम केलव 369 करोड़ रुपये था। वर्ष 1989-90 एवं 90-91 में निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारण निम्नलिखित रहे-

- \* खाडी सकट(ईराक-कुवैत युद्ध) जिसके कारण अनेक मदो जैसे रसायनो, औषधियो, खिलयो, चावल, चमडे की बनी वस्तुओ आदि के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पडा।
- \* काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र से सीधे निर्यातो के कारण राज्य व्यापार निगम के द्वारा सरणीबद्ध --अरण्डी के तेल के रूप में भुगतान क्षेत्र को कम आयात ।
  - \* वर्ष के लिए निश्चित किया गया गेहूँ के निर्यात का लक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं किया जा सका

कि भारत के बन्दरगाहो पर बडे जहाजो मे लदान की सुविधा नही थी।

\* कॉफी के मामले में लक्षित निर्यात प्राप्त न करने का कारण यह रहा कि आई सी ओ कोटा न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में मदी रही। इसका यह भी कारण था कि नरमी में कॉफी के कुछ खास ग्रेड उपलब्ध नहीं थे, जिससे कुछ सविदाओं की पूर्ति नहीं हो सकी।

\* वर्ष के दौरान चावल का निर्यात कम रहा क्योंकि खाडी सहकारी परिषद ने पहले के समान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चावल खरीदने के बजाय सीधे ही निजी पार्टियों से खरीदना पसन्द किया।

\* सोवियत रूस तथा पूर्ववर्ती पूर्वी जर्मनी की खरीददारी पद्धित में परिवर्तन के कारण भी इन देशों को फुटवीयर के राज्य व्यापार निगम के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

स्वदेशी व्यापार में भी आयात की तरह प्रारम्भ से वर्ष 1981-83 तक लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1982-83 में यह घटकर 13 44 करोड़ रुपये हो गया जो वर्ष 1980-81 के बाद अब तक का सबसे कम स्वदेशी व्यापार रहा। वर्ष 1989-90 से वर्तमान समय तक इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राज्य व्यापार निगम के इतिहास में वर्ष 1987-88 में सर्वाधिक व्यापार रुपया 3645 52 करोड़ का हुआ परन्तु इस वर्ष के सर्वाधिक व्यापार के बावजूद निगम का कर के पूर्व लाभ 51 97 करोड़ रुपये ही रहा इस प्रकार निगम का इस वर्ष का निवल लाभ अनुपात(कर देने के पूर्व बिक्री के अनुपात में) 1 4 प्रतिशत रहा। यदि हम निगम के निवल लाभ अनुपात की ऐतिहासिक समीक्षा करे तो स्पष्ट होता है कि यह अनुपात इसी ऐतिहासिक वर्ष में सबसे कम है जिसमें कुल व्यापार सबसे अधिक। वर्ष 1969-70 में यह अनुपात सर्वाधिक 7 7 प्रतिशत था। निगम का मात्रात्मक लाभ वर्ष 1981-82 में सर्वाधिक रहा है जबिक इस वर्ष का निवल लाभ अनुपात 3 9 प्रतिशत था। वर्ष 1992-93 में निवल लाभ अनुपात 2 66 प्रतिशत था जिसे सन्तोषजनक कहा जा सकता है।

## (ल) निगम के कारोबार की विशिष्टताए -

गत वर्षों मे भारत और यहाँ तक कि विश्व के आर्थिक परिदृश्य मे बहुत से परिवर्तन हुए है। इसके साथ ही साथ निगम की सगठनात्मक सरचना भी बी बी आई एल के गठन, पुन इसके समापन, अनुषिगयों के विलगन एवं समामेलन के कारण प्रभावित हुई। इन परिवर्तनों का प्रभाव निगम की कार्य-प्रगति पर भी पड़ा है, जिसका अवलोकन अग्र पृष्ठ पर प्रस्तुत तालिका संख्या 47 से किया जाता सकता है-

तालिका सख्या 47 विगत वर्षों मे निगम के कारोबार की विशिष्टताए

(करोड रुपये मे)

	विवरण	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	निर्यात- असरणीबद्ध	262	173	292	542
	सरणीबद्ध	135	113	234	9
	दोहरा व्यापार(तटेतर सहित)	355	83	99	
	योग	752	369	625	551
2	आयात- असरणीबद्ध	25	23	11	39
	सरणीबद्ध	1045	1309	599	285
	योग	1070	1332	610	324
3	स्वदेशी-	33	55	80	138
	महायोग	1855	1756	1315	1013
4	वित्तीय-कर के पूर्व लाभ्य	36 78	34 59	36	27
	कर के लिए प्रावधान	5 07	11 46	11	8
	कर के बाद लाभ	31 71	23 13	25	19
5	विनियोजन—प्रस्तावित लाभाश	6 00	6 00	9 0	9 0
	आरक्षित राशि मे अन्तरण	26 69	17 75	<b>17</b> 0	10 0
	शुद्ध मूल्य	312 00	329 00	360 00	369 00

म्रात वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-91 के दौरान निर्यात 369 करोड़ रुपये के रहे जबिक इससे पूर्व वर्ष 1989-90 में यह 752 करोड़ रुपये का था। निर्यातों में कमी का प्रमुख कारण दोहरे व्यापार तथा असरणीबद्ध निर्यातों के अन्तर्गत कम निर्यात रहा, जो पिछले वर्ष क्रमश 341 करोड़ रुपये तथा 262 करोड़ रुपये के तुलना में वर्ष 1990-91 में केवल 83 करोड़ एवं 173 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 1990-91 में निर्यातों में कमी खाड़ी सकट, साम्यवादी सोवियत रूस एवं पूर्वी जर्मनी की खरीद विधि में परिर्वतन तथा कुछ वस्तुओं के असरणीबद्ध कर दिये जाने से विदेशी खरीददारों द्वारा निजी पार्टियों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के कारण भी रही।

वर्ष 1991-92 में निगम का निर्यात 369 करोड़ रुपये से बढ़कर 625 करोड़ रुपये हो गया और इस प्रकार निर्यात में एक वर्ष में ही 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। असरणीबद्ध वस्तुओं का निर्यात इस अविध में 173 करोड़ रुपये से बढ़कर 292 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार असरणी बद्ध वस्तुओं के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों, में सर्वोच्च वृद्धि दर 69 प्रतिशत दर्ज की गयी। असरणीबद्ध वस्तुओं में मुख्य रूप से सोयाबीन मील/खिलयों, गेहूँ, चाय, प्रसंस्कृत खाद्य, केमिकल और दवाए इत्यादि थी।

वर्ष 1991-92 में असरणीबद्ध निर्यात-क्षेत्र में निगम द्वारा की गयी प्रगति में कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है-

- \* सोयाबीन मील/खिलयों का निर्यात गत वर्ष 1990-91 की तुलना में 1991-92 में 20 करोड़ रुपये अधिक रही जो 21 करोड़ रुपये से बढ़ कर 41 करोड़ रुपये हो गया। निगम ने पहली बार इस वर्ष चावल की भूसी की खली रुपये 1 68 करोड़ का निर्यात किया।
  - \* इस वर्ष मे पहली बार गैर-बासमती चावल रुपये 6 05 करोड़ का निर्यात किया गया।
- \* निगम स्वीडिश बाजार में पहली बार प्रविष्ट हुआ और एक करोड रुपये का निर्यात आदेश प्राप्त करने में सफल रहा।
- \* निगम ने यूनाइटेड अरब अमीरात को निर्यात करने का एक दीर्घकालीन समझौता किया है जिसमें एक करोड़ रुपये की डिस्पोजल सिरिंज का निर्यात प्रति वर्ष करना है। निगम ने पहली बार हालैण्ड को 45 लाख रुपये की इफेड्रिन तथा 50 लाख रुपये की कोन्ट्रीमैक्सजॉल दवा की गोली, फ्रांस को 20 लाख रुपये की इण्डोशल्फान का निर्यात किया। उसे 64 लाख रुपये का फार्मूलेशन का आर्डर नाइजीरियन हैल्थ अथॉरिटी द्वारा प्राप्त हुआ है।

वर्तमान समय में निगम उदारीकृत व्यापारिक वातावरण में असरणीबद्ध वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रहा है। वर्ष 1992-93 के दौरान असरणीबद्ध वस्तुओं का निर्यात 38 6 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष का कुल निर्यात यद्यपि 1991-92 के 625 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 551 करोड़ रुपये रहा। सरणीबद्ध वस्तुओं का निर्यात 234 करोड़ रुपये से घटकर केवल 9 करोड़ रुपये रह जाने से कुल निर्यात प्रभावित हुआ। निगम लगातार सोयाबीन, चावल की भूसी, सरसो एव सूरजमुखी का तेल का निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। देश में ट्रकों की हड़ताल एव असामान्य परिस्थित के बावजूद वर्ष 1992-93 में कुल 34 करोड़ रुपये का निर्यात इन वस्तुओं से सम्बन्धित किया गया।

वर्ष 1990-91 के दौरान रुपये 1332 करोड का आयात कारोबार हुआ जो पिछले वर्ष के आयात से 262 करोड रुपये अधिक था, जिसका मुख्य कारण खाद्य तेलों के आयातों में बढी हुई मात्रा है। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी नीतियों एव दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सरणीबद्ध वस्तुओं का निर्यात निगम द्वारा किया जाता है। आयात का समय एव आयातित मात्रा का निर्धारण भी सरकार ही करती है। वर्ष 1991-92 में 90-91 की तुलना में आयात रुपया 1322 करोड से गिरकर 610 करोड रुपये रह गया। यह कमी मुख्य रूप से सरणीबद्ध खाद्य तेलों के आयात में कमी के कारण रही। वर्ष 1991-92 के दौरान 1 15 लाख मीट्रिक टन पामोलिन का विक्रय 217 करोड रुपये में किया गया जबिक वर्ष 1990-91 में 5 95 लाख मीट्रिक टन पामोलिन का विक्रय 836 करोड रुपये में किया गया

था। निगम का आयात आवर्त वर्ष 1992-93 में 46 9 प्रतिशत और कम हो गया। यह कमी अखबारी कागज के असरणीबद्ध िकयं जाने तथा खाद्य तेलों के आयात में कमी के कारण आयी 3 लाख टन खाद्य तेलों के आयात की मूल योजना के अनुक्रम में केवल 30,000 मी टन खाद्य तेलों का ही आयात किया गया क्योंकि तिलहन के स्वदेशी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

पिछले चार वर्षों में निगम ने स्वदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए चार गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज करायी है। वर्ष 1990-91 में स्वदेशी बिक्री में वृद्धि का मुख्य कारण सरकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिक्री तथा सोयाबीन के तेल की अधिक बिक्री रही। स्वदेशी व्यापार में वर्ष 1991-92 तथा 92-93 में निगम ने अपने गतवर्ष की तुलना में क्रमश 45 प्रतिशत तथा 72 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। स्वदेशी व्यापार में वृद्धि का मुख्य कारण निगम की तेल निकालने वाली अधिग्रहीत परियोजनाओं द्वारा तेल की अधिक बिक्री के साथ-साथ आयातित कारो एव प्राकृतिक रबर की अधिक बिक्री करना रहा है।

वर्ष 1992-93 में सरणीबद्ध व्यापार में कमी के बावजूद निगम अपने कुल व्यापार को हजार करोड़ रुपये के स्तर पर बनाये रखने में सफल रहा है यद्यपि वर्ष 1992-93 में कुल व्यापार 1315 करोड़ रुपये से घटकर रुपये 1013 करोड़ ही रह गया है। यह कमी मुख्य रूप से सरणीबद्ध व्यापार में कमी के कारण रही। वर्ष 1991-92 का सरणीबद्ध व्यापार 833 करोड़ रुपये का था जो अगले वर्ष गिरकर 294 करोड़ रुपये ही रह गया जबिक असरणीबद्ध व्यापार में वर्ष 1992-93 के दौरान 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निम्न तालिका में विगत वर्षों के सरणीबद्ध एवं असरणीबद्ध व्यापार की स्थित को प्रस्तुत किया गया है-

तालिका संख्या 48

सरणीबद्ध एवं असरणीबद्ध व्यापार की स्थिति

(करोड रुपये मे)

Mary Mark make to	विवरण	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	सरणीबद्ध व्यापार	1180	1422	833	294
2	असरणीबद्ध व्यापार (तटेतर तथा स्वदेशी सहित)	675	334	482	719
	योग	1855	1756	1315	1013

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरणीबद्ध व्यापार में वर्ष 1000-01 से लगातार कमी एव असरणीबद्ध व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। तालिका सख्या 47 मे यदि निगम के अर्जित लाभ का अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि 1992-93 मे वर्ष 1991-92 की तुलना मे 9 करोड़ रुपये की कमी रही है। लाभ मे कमी का कारण निगम के कुल आयात-निर्यात व्यापार मे कमी होना रहा है। यद्यपि इस अवधि मे स्वदेशी व्यापर बढ़ा है परन्तु वह लाभ को अधिक प्रभावित नहीं कर सका। कर के पूर्व लाभ को विक्रय के सन्दर्भ मे देखने पर यह स्पष्ट होता है कि गत चार वर्षों मे इसमे अधिक उच्चावचन नहीं है। वर्ष 1989-90 से 92-93 तक यह अनुपात क्रमश 2 0,2 0,2 8 एव 2 7 प्रतिशत रहा। वर्ष 1983-84 मे भी यह अनुपात 2 7 प्रतिशत ही था। निगम ने लाभाश की घोषणा मे पर्याप्त स्थिरता का ध्यान रखा है।वर्ष 1982-83 से 85-86 तक लाभाश की राशि रुपये 3 75 करोड़ 1986-87 से 1990-91 तक लाभाश 6 करोड़ रुपये तथा 1991-92 एव 92-93 मे रुपये 9 करोड़ लाभाश के रूप मे वितरित किये गये। वर्ष 1986-87 से 90-91 तक लाभाश की दर 20 प्रतिशत थी। वर्ष 1991-92 मे इसमे 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लाभाश दर को 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

### (व) चीनी सकट-1994 में निगम की भूमिका -

चीनी सकट 1994 को कम करने में राज्य व्यापार निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निगम सरकार के आदेश पर चीनी अथवा अन्य वस्तुओं का आयात करता है। उल्लेखनीय है कि चीनी का उत्पादन खपत से कम होगा, इसका सही—सही अनुमान समय पर नहीं लगाया जा सका था। भारतीय चीनी मिल सघ ने सरकार को भावी उत्पादन के विषय में सही आकड़े उपलब्ध नहीं कराये। 57 और जब इस बात का पता चला कि वर्तमान चीनी सत्र का उत्पादन पिछले वर्ष की खपत से कम है तो चीनी के आयात करने से सम्बन्धित प्रशासनिक आदेश देने में विलम्ब हुआ। फलस्वरूप चीनी की मात्रा बाजार में कम हो जाने से खुले बाजार में इसकी कीमत अनियन्त्रित हो गयी। कुछ व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकारी महकमों की अक्षमता और मन्त्रियों तथा नौकरशाहों के बीच अहम् के टकराव से हुए घालमेल के कारण उँची कीमतो पर चीनी का आयात किया गया और देश के खजाने को 650 करोड़ रुपये की चपत लगी। 58

वास्तव मे नवम्बर 1993 मे ही केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति मत्री द्वारा 10 लाख टन चीनी के आयात की सिफारिश की गयी थी। खाद्य सचिव ने भी चीनी के आयात का सुझाव दिया। परन्तु खाद्य मन्त्रालय का विचार था कि माँग पूरी करने के लिए चीनी का पर्याप्त उत्पादन होगा। 24 जनवरी, 1994 को खाद्य मन्त्री ने प्रधानमन्त्री कार्यालय को पत्र लिखकर चीनी आयात करने का निवेदन किया। मन्त्रिमण्डल की मूल्य सम्बन्धी समिति(सी सी पी) की बैठक कई बार स्थिगत होने के बाद जब 9 मार्च को हुयी तो

<sup>57</sup> अवर लीडर-इलाहाबाद, 30 मई, 1994

<sup>58</sup> इण्डिया दुडे- 30 जून, 1994, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या 48

तय हुआ कि चीनी को खुले सामान्य लाइसेन्स(ओ जी एल ) की सूची मे लाया जाय और राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम से चीनी के आयात के बारे मे फैसला करने को कहा जाय परन्तु वित्त मन्त्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को होने वाले घाटे को उठाने से इन्कार कर दिया क्योंकि आयातित चीनी की लागत रुपये 13 10 प्रतिकिलो होती जबिक विक्रय 7 10 रुपये प्रतिकिलो पर ही करना पडता, इसलिए राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम आयात का फैसला करने मे झिझकते रहे। जब राज्य व्यापार निगम ने चीनी मँगाने के लिए 13 मई, 1994 तक कोई अनुबन्ध नही किया, तब सचिवो की बैठक मे मन्त्रिमण्डलीय सचिव ने निर्देश दिया कि वे भारतीय खाद्य निगम से चीनी आयात करवाए। भारतीय खाद्य निगम ने 16 मई को निविदा जारी की, परन्तु इसे खाद्य मन्त्री द्वारा 19 मई को रव्द कर दिया गया और उसी दिन भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा 385 डालर प्रति टन की दर से चीनी मँगाने का पहला अनुबन्ध किया गया। आयात की कीमत नवम्बर—1993 की कीमत से 35 डालर प्रति टन अधिक थी। जब चीनी सकट का जायजा लेने के लिए 8 जून 1994 को प्रधानमन्त्री ने बैठक बुलायी तो वित्तमन्त्री भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी देने पर सहमत हुए, जिससे कि सस्ती दर की दुकानो पर चीनी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। पर इस बीच चीनी की कीमत खुले बाजार मे 18 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गयी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयात का निर्णय लेने मे विलम्ब तथा निर्णय केबाद आयात अनुबन्ध करने मे विलम्ब, चीनी सकट-1994 का आधार है। जब खाद्यमन्त्री से इण्डिया टुडे के प्रतिनिधि द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात मे विलम्ब का कारण पूछा गया तो उनका उत्तर था कि मन्त्रिमण्डलीय सचिव की जिम्मेदारी थी कि वे राज्य व्यापार निगम के चीनी आयात के सम्बन्ध मे, वाणिज्य सचिव को स्पष्ट निर्देश देते। यह काम तो उन्हे 8 अप्रैल की बैठक के बाद कुछ दिनों में ही कर लेना चाहिए था, जब यह फैसला हुआ कि राज्य व्यापार निगम और खनिज एव धातु व्यापार निगम सीवजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का आयात करेगे। वाणिज्य सचिव द्वारा वाणिज्य मन्त्रालय को पहला पत्र 5 मई-1994 को भेजा गया जिसमे राज्य व्यापार निगम से बाजार की कीमतो पर चीनी आयात करने की बात कही गयी। मगर तब सब्सिडी कौन देता?

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी की गयी निविदा को रद्द करने का कारण वर्ष 1989 के चीनी सकट पर, पी ए सी की रिपोर्ट थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मन्त्रालय चीनी का आयात न करे यह अधिकार राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एव धातु व्यापार निगम का है और किसी भी अपजीकृत कम्पनी को आयात सम्बन्धी निविदा भरने की अनुमति न दी जाय।

<sup>59</sup> इण्डिया टुडे, 30 जून-1994, कनाट प्लेस,नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-51

उदारीकरण के वर्तमान सन्दर्भों मे चीनी सकट— 1989 के पी ए सी की रिपोर्ट का अक्षरश अनुपालन बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। निजीकरण के दर्शन को बढावा देते हुए 15 मार्च—94 को निजी क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क मुक्त चीनी-आयात के दरवाजे खोल दिये गये। यद्यपि राज्य व्यापार निगम भारत सरकार के लिए चीनी आयात करने का एक उत्तरदायी सस्थान है परन्तु उसे समय पर स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए था। क्योंकि निजी पार्टियों भी आयात अनुबन्धों में लगी थी इसलिए निगम की विदेश से मोल—तोल शिक्त भी कमजोर पड गयी थी। चीनी की आपूर्ति तथा कीमतो पर नियन्त्रण हेतु सरकार को समय रहते वित्त, वाणिज्य तथा खाद्य मन्त्रालयों की एक सयुक्त समिति गठित किया गया होता, तथा इन विभागों के बीच सवादहीनता जैसी स्थित को समाप्त कर समस्या से निपटने का समय से प्रयास किया गया होता तो इस चीनी सकट को कम किया जा सकता था।

- (ष) <u>निगम की उपलब्धियों का मूल्याकन —</u> भारतीय राज्य व्यापार निगम की उपलब्धियों निम्नलिखित है--
- 1 देश के आयात—निर्यात व्यापार में योगदान विगत वर्षों में निगम ने देश के आयात—निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसका कुल व्यापार 1987—88 में 3645 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका था। बाद में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक उदारीकरण के मूल उद्देश्य— निजी आयातको तथा निर्यातको को विदेशी बाजार की प्रतिस्पर्धा में खंडे होने की योग्यता का विकास करने के लिए, व्यापार नीतियों में खुलापन लाया गया। इससे निगम का व्यापार हाल के वर्षों में कुछ कम हुआ है। परन्तु ऐसा नहीं है कि उदारीकरण से देश का कुल विदेशी व्यापार कुप्रभावित हुआ हो। राज्य व्यापार निगम के विदेशी व्यापार में योगदान को निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

तालिका संख्या 49 विदेशी व्यापार में राज्य व्यापार निगम का योगदान

(करोड रुपये मे)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल विदेशी व्यापार	निगम का कुल व्यापार	निगम का भाग प्रतिशत मे
1980-81	12,549	6,711	19,260	1,780	9 24
1985-86	20,452	10,895	31,347	2,551	8 13
1990-91	43,193	32,553	75,746	1,756	2 31
1992-93	62,923	53,351	1,16,274	1,013	0 87

म्रोत 1 इकोनोमिक सर्वे आफ इष्डिया -1992-93

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश के बढते हुए कुल विदेशी व्यापार मे निजी पार्टियो

<sup>2</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली

के शामिलहो जाने से निगम का योगदान कम हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव यह हुआ है कि निगम का सरणीबद्ध व्यापार कम तथा असरणीबद्ध व्यापार बढ रहा है। परन्तु समीक्षात्मक 12 वर्षों मे राज्य व्यापार निगम की विदेशी व्यापार मे भागीदारी 8 37 प्रतिशत घट गयी, यह एक चिन्ताजनक स्थिति है।

- 2 निर्यात एवं निर्यात उत्पादन को बढावा निगम ने निर्यात एवं निर्यात उत्पादन वो ने निर्यात एवं निर्यात उत्पादन वो ने ने निर्यात एवं निर्यात उत्पादन वोनों को बढाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। निगम का निर्यात इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 1983—84 तक लगातार बढता ही रहा है और यह 796 11करोड़ रुपये तक जा पहुँचा था। निगम ने चीनी एवं कृषिगत वस्तुओं के निर्यात तथा निर्यात योग्य चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन में अपना योगदान दिया है। 60 निगम उत्पादन को बढाने के लिए कच्चे माल,ईघन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करता है। वर्ष 1990—91 एवं 91—92 में निर्यातित वस्तुओं में सर्वाधिक चीनी का निर्यात किया गया जो क्रमश 99 19 एवं 242 5 करोड़ रुपये का था तथा वर्ष 1989—90 तथा 1992—93 में निर्यातित वस्तुओं में सर्वाधिक निर्यात कृषिगत वस्तुओं का रहा जो क्रमश 158 7 एवं 140 2 करोड़ रुपये का था। निगम रूस, जापान, कनाड़ा एवं सिगापुर आदि देशों में व्यापारिक मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहता है जिसके माध्यम से वह नयी—नयी वस्तुओं का परिचय कराकर निर्यात को प्रोत्साहित करता है। निगम मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से विश्व के उपभोक्ताओं को भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ज्ञान कराता है तथा उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है जिससे वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की जा सके।
- 3 <u>अपरम्परागत कस्तु एव बाजार की खोज</u> भारतीय राज्य व्यापार निगम प्रारम्भ में परम्परागत वस्तुओं का आयात-निर्यात करता था परन्तु बाद में उसने नयी—नयी वस्तुओं एव नये—नये बाजारों की खोज प्रारम्भ की। हाल के वर्षों में निगम ने अपरम्परागत वस्तुओं में प्रसस्कृत खाद्य, रसायन, दवाए, गैर बासमती चावल, चावल की भूसी, डिस्पोजल सिरिज, अमिटनीय स्याही, सुगन्ध प्रसाधन, पिपरमिण्ट, जूते, सिले सिलाये कपडे, प्याज, नमक, बीडी पत्ता, धर्मोप्लास्टिक्स, रगीन टेलीविजन का निर्यात, एव उपकरण, लकडी का गूदा— प्राकृतिक रबर, विटामिन'ए' पामीटेट, आदि वस्तुओं को आयात किया है।

निगम का व्यापार प्रारम्भ मे कुछ गिने चुने देशो के साथ होता था परन्तु आज उसका व्यापार सखदी अरब, ईरान, रूस, फास, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलका, यूगोस्लाविया, मोरक्को, डेनमार्क, जापान, जिबूती, मिश्र, यमन, इटली, नीदरलैण्ड, सोल्वेनिया, फिनलैण्ड, स्पेन, सिगापुर, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, कुवैत, कोरिया, पाकिस्तान, ताइवान, नाइजीरिया, कनाडा, ग्रीस, सीरिया, आस्ट्रेलिया,

<sup>60</sup> बाजार व्यवस्था-शर्मा, टी आर , जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या-127

बेल्जियम आदि देशों के साथआयात—निर्यात का व्यापार हो रहा है। विभिन्न वस्तुओं के सन्दर्भ में निगम विभिन्न प्रकार के बाजारों की खोज करता है जिससे कि वहाँ पर विशेष वस्तु का निर्यात किया जा सके जैसे— कॉफी के सम्बन्ध में जापान, कनाडा में जूते, नाइजीरिया में दवाए, अरब देशों को डिस्पोजल सिरिज आदि।

- 4 समर्थित मूल्य एव बफर स्टॉक की क्रियाओं में योगदान राज्य व्यापार निगम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि वह मूल्यों को स्थिर बनाये रखकर, वस्तु के स्टॉक को भी बनाये रखता है। इस क्रिया में वह सरकार द्वारा घोषित समर्थित मूल्य पर उत्पादकों से सीधे वस्तुओं को खरीदकर उन्हें विक्रय की चिन्ता से मुक्त कराता है तथा उन्हें शीघ्र भुगतान कर पुन उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। यह दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाये रखने में योगदान करता है। यह स्टॉक उस अविध में वस्तुओं की पूर्ति को नियमित करता है जबिक वस्तुओं का उत्पादन खपत से कम हुआ हो। विशेष रूप से निगम इस क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों के मूल्य में स्थायित्व प्रदान करता है जिससे कि जनसाधारण को आवश्यक वस्तुए उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके।
- 5 लघु एव कुटीर उद्योगों को सहायता राज्य व्यापार निगम लघु एव कुटीर उद्योगों को समस्त सुविधाए प्रदान करता है, यह उनके लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है। यथा उत्पादन में निरन्तरता के लिए कच्चे माल की व्यवस्था, उनके उत्पादों की गुणोत्तर प्रगति के लिए उच्च तकनीकी सहायता प्रदान करना, उत्पादों के विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात में सहायता प्रदान करना जिससे कि उनको किसी प्रकार की हानि न हो तथा उत्पादित वस्तुओं में पूँजी फसी न रह जाय। इस प्रकार राज्य व्यापार निगम लघु एव कुटीर उद्योगों को एक स्थायित्व प्रदान करने तथा उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- 6 स्वदेशी व्यापार में निगम का योगदान निगम स्वदेशी व्यापार में अपनी स्थापना के बाद से ही योगदान करता आ रहा है। जिसमें वह अपने देश में देश—विदेश से खरीदी गई वस्तुओं का विक्रय करता है। स्वदेशी व्यापार के अन्तर्गत निगम द्वारा वर्तमान समय में आयातित कारों से लेकर, केक जैसी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। निगम का स्वदेशी व्यापार उत्तरोत्तर बढता जा रहा है। वर्ष 1988—89 में यह व्यापार मात्र 19 56 करोड़ रुपये का था जो वर्ष 1992—93 में 138 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। वर्ष 1990—91 में 89—90 की तुलना में 33 करोड़ रुपये का अधिक स्वदेशी व्यापार हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1991—92 एवं 92—93 में इसमें क्रमश 45 तथा 72 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम ने अपनी बिक्री में यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक विक्रय, निगम द्वारा अधिग्रहीत तेल निकालने वाली परियोजनाओं द्वारा अधिक तेल के विक्रय

के साथ-साथ आयातित कारों के अधिक विक्रय द्वारा अर्जित की है। इसके अतिरिक्त निगम ने स्वदेशी व्यापार के अन्तर्गत प्राकृतिक रबर के देशी उत्पादको सेउत्साहवर्धक मूल्य पर 18420 मीट्रिक टन प्राकृतिक की खरीद 38 करोड रुपये में वर्ष 1991-92 में शासकीय निर्देशों के अधीन करोड रुपये का 5834 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबर निर्यात किया गया तथा निगम ने 565 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबर घरेलू बाजार के लिए 15 44 करोड रुपये में निर्गत किया। 61

7 उचित कार्मिक एव औद्योगिक सम्बन्ध — कम्पनी नियमावली —1975 तथा सशोधित नियमावली 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2-ए) के अन्तर्गत अपेक्षित प्रावधानानुसार निगम का कोई कर्मचारी किसी भी निदेशक से सम्बन्धित नहीं है, साथ ही निगम अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखता है। निगम के निदेशक प्रबन्धको एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित लगन के लिए अपनी प्रशसा अभिलेखित करते हैं। निगम ने 1 जून, 1989 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चालू की, जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते थे, जिन्होंने न्यूनतम10 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया हो या जिनकी आयु 40 वर्ष हो गयी हो।

वर्ष 1991-92 में सरणीबद्ध व्यापार में कमी को देखते हुए मानव शक्ति के आधिक्य में कमी लाने के लिए 553 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जिसके प्रतिफल में 10 7 करोड़ रुपये का भुगतान वर्ष के दौरान उन्हें किया गया तथा प्रबन्धकीय एवं अन्य व्ययों में बचत की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की संख्या को मार्च-1992 में 1962 के कर्मचारियों की संख्या के स्तर तक कम किया गया। निगम मानव संसाधन विकास की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्रबन्धको एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था समय-समय पर करता है। इस कार्य के लिए वह विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों की मदद लेता है, जैसे- इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, श्रीराम तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सेवा संस्थान तथा कम्यूटर अनुरक्षण निगम इत्यादि।

(श) भारतीय राज्य व्यापार निगम का अनुषगी निगम — राज्य व्यापार निगम के सगठन एव प्रबन्ध को मई-1990 में बी बी आई एल के अन्तर्गत लाया गया परन्तु मार्च-1991 में ही बी बी आई एल को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप मार्च-1991 में राज्य व्यापार निगम अपने पूर्व की स्थिति में आते हुए चार अनुषगी निगमो-भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम,भारतीय काजू निगम, भारतीय चाय व्यापार निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम पर नियन्त्रण करता था।बाद में भारतीय काजू निगम का राज्य व्यापार निगम में सिवलयन कर दिया गया तथा भारतीय चाय व्यापार निगम को छोडकर अन्य सभी अनुषगी निगमों को इससे विलग कर दिया गया। वर्तमान समय में राज्य व्यापार निगम का केवल एक

<sup>61</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-1991-92, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली।

अनुषगी निगम भारतीय चाय व्यापार निगम है।

भारतीय चाय व्यापार निगमकी स्थापना राज्य व्यापार निगम के अनुषगी निगम के रूप में वर्ष-1970 में की गयी थी। इसका प्रमुख कार्य पैकेटो में बन्द एवं खुली चाय का देश-विदेश में विक्रय करना है। यह निगम चाय के विपणन, उपभोग तथा चाय बागानों के प्रबन्धों में सहायता प्रदान करता है एवं चाय गोदामों का प्रबन्ध भी करता है। चाय व्यापार निगम के 100-100 रुपये के 11,14,193 समता अशों में राज्य व्यापार निगम ने 3 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वर्तमान समय में चाय व्यापार निगम की समता अश पूँजी 11 करोड़ 14 लाख रुपये तथा आरक्षित निधि 10 लाख रुपये हैं। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ऋण के माध्यम से भी वित्त प्राप्त किया जाता है जो 31 मार्च,92 को 16 करोड़ 11 लाख रुपये तक पहुँच चुका है।

भारतीय चाय व्यापार निगम की विगत चार वर्षों की व्यापारिक स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है--

तालिका सख्या 50 भारतीय चाय व्यापार निगम की व्यापारिक स्थिति

( लाख रुपये मे)

	विव	रण	वर्ष 1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	शुद्ध बिक्री	– निर्यात	2379	1746	3645	1699
		– स्वदेशी	882	1123	864	802
		योग	3261	2869	4509	2501
2	आय	– व्यापार लाभ	504	96	316	139
		– विविध आय	245	143	165	101
		योग	749	239	481	240
3	घटाया	–बधे खर्च, इास, ब्याज आवि	686	306	423	411
4	कर से पूर्व लाभ/हानि		63	(-) 67	58	(-) 171
5	व्यापार लाभ	तथा बिक्री अनुपात(%मे)	15 4	3 3	7 0	5 5

स्रोत वार्षिक प्रतिवेदन-भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम के निर्यात एव स्वदेशी बिक्री में उच्चावचन होता रहता है लेकिन उससे भी अधिक उच्चावचन उसके च्यापार लाभ में होता है। समीक्षात्मक 4 वर्षों में सर्वाधिक मात्रात्मक एव आनुपातिक दोनो लाभ वर्ष 1989-90 में रहा। इस वर्ष का कर से पूर्व लाभ रुपये 63 लाख तथा कुल लाभ अनुपात 15 4 प्रतिशत था। इस अवधि में बिक्री, व्यापार लाभ तथा इन दोनों के आपसी अनुपात वर्ष 1990-91 में सबसे कम रहा है। सम्भवत राजनीतिक अस्थिरता, उत्पादन क्षेत्र में आतकवादी गतिविधियों एव प्राकृतिक कारणों का प्रभाव चाय व्यापार पर पर्याप्त रूप से पड़ा है।

वर्तमान समय में निगम की कार्य प्रगित के असन्तोषजनक होने का एक कारण निगम द्वारा लिये गये ऋणों पर देय ब्याज का भारी बोझ भी है। निगम ने 31 मार्च-1990 तक 1,319 लाख रुपये के ऋण स्वीकार किये थे जो 31 मार्च-1992 तक बढ़कर 1,611 लाख रुपये हो गये। निगम पर स्थायी ब्याज के भुगतान का दायित्व बढ़ने तथा अन्य कारणों का प्रभाव निगम के वर्ष 1990-91लेखों में हानि के रूप में पड़ा तथा वर्ष- 1992-93 में 171 लाख रुपये की हानि की अस्थायी गणना की गयी है। ऐसी स्थिति में निगम को अपने सभी खर्चों में मितव्यियता बरतनी चाहिए। कर्मचारियों की अनावश्यक सख्या को घटाने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए उन्हें प्रिशिक्षित किया जाना चाहिए। सरकार को चाय के निर्यात पर सीमा शुल्क की छूट प्रदान करनी चाहिए तािक चाय व्यापार निगम की हािन को कम करते हुए लाभदायक स्थिति में लाया जा सके। क्योंकि निगम की गितिविधियों पर नियन्त्रण करने में अभी आसािनी होगी इसिलए शीघ्रातिशीघ्र निगम की समस्याओं के निवारण हेतु एक सिमिति की नियुक्ति कर इसके व्यापार को लाभदायक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रतियोगिता के युग में चाय व्यापार निगम को अपना लाभ बढ़ाने के अतिरिक्त जीवित रखने का कोई और विकल्प नहीं है।

- (ह) निगम की आलोचना भारतीय राज्य व्यापार निगम वस्तुओ मे राजकीय व्यापार का एक प्रमुख अग होते हुए भी, इसकी आलोचना निम्न आधारो पर की जाती है—
- राज्य व्यापार निगम का लाभ कुल बिक्री एव निगम के आकार की तुलना में काफी कम है। निजी व्यापारियों में कुल बिक्री एवं लाभ का अनुपात 8 से 10 प्रतिशत तक रहता है जबिक निगम का यह अनुपात पिछले 10 वर्षों में 2 से 3 प्रतिशत के बीच ही चल रहा है। निगम के अन्य व्ययों पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण वे अन्य निजी व्यापारिक संस्थानों की तुलना में बहुत अधिक है।
- निगम में अभी भी विकेन्द्रीयकरण की कमी अनुभव की जाती है जिसके कारण कोई भी निर्णय लेने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। राजनीतिक पदाधिकारियों एव नौकरशाहों के अहम् के टकराव का धातक परिणाम पूरे देश को भुगतना पडता है। आर्थिक गतिविधियों में सही समय पर सही निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण होता है जो राज्य व्यापार निगम की जटिल सगठनात्मक सरचना के कारण सम्भव नहीं हो पाता। अभी हाल के चीनी सकट के दौरान एक तो विलम्ब से विदेश से चीनी आयात का कार्य राज्य व्यापार निगम को सौपा गया, दूसरे आदेश के बाद भी विलम्ब से टेण्डर जारी किये गये तथा टेण्डर जारी करने के "

एक महीने बाद तक विदेशी एजेन्सियों से चीनी आयात का अनुबन्ध नहीं किया जा सका। देर से निर्णय लेना औरउसके कार्यान्वयन में उतना ही विलम्ब करना अधिकारों के केन्द्रीयकरण एवं विभागीय निष्क्रियता को स्पष्ट करता है।

- निगम के कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित मन्त्रालयों में प्राय तालमेल का अभाव सा देखने को मिलता है। निगम को कुछ अनुबन्धों को अन्तिम रूप प्रदान करने से पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय एवं वित्त मन्त्रालय से निर्देश प्राप्त करने पडते हैं। इन तीनो मन्त्रालयों में कभी-कभी निर्णयन एवं उनके कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं होती। मन्त्रालयों के दृष्टिकोण में भिन्नता होने के कारण निगम को अपना निर्यात कम मूल्य पर अथवा आयात अधिक मूल्य पर करने के लिए बाध्य होना पडता है।
- निगम के लगभग 80 प्रतिशत अधिकारी तथा बहुत से कर्मचारी भी अन्य सरकारी विभागों से निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हैं जिनमें व्यापारिक रीतिरिवाज एवं कार्य-कलापों के अनुभव का अभाव होता है जिसके कारण उनके निर्णय व्यापारिक नीति के अनुकूल नहीं होते। वे सरकारी तन्त्र के अनुरूप औपचारिकताओं से अभिप्रेरित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारी एवं कर्मचारी का भावनात्मक लगाव राज्य व्यापार निगम से उत्पन्न नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद अपने मूल विभाग को वापस होना रहता है।
- निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सत्यिनिष्ठा, एवं कार्य-सम्पन्नता की कमी पायी जाती है और इस कमी का मूल कारण उनमें अभिप्रेरणा के साथ-साथ प्रशिक्षण का भी अभाव होता है। प्रथमत तो वे स्वेच्छा से कार्य करना ही नहीं चाहते और यदि कार्य करना भी चाहे तो उनमें उचित कार्यक्षमता ही नहीं होती।
- जिन वस्तुओं में निगम को एकाधिकार प्राप्त है उनका वह अधिक मूल्य वसूल करता है। 62 परन्तु जहाँ उसे प्रतिस्पर्धा करनी होती है, वहाँ वह अपना व्यापार ठीक ढग से सचालित नहीं कर पाता। सरणीबद्ध व्यापार के सम्बन्ध में क्योंकि निगम का प्रतिस्पर्धी अन्य कोई नहीं होता जिसके परिणामस्वरूप वह समाज का शोषण कर राज्य के कल्याणकारी कर्तव्य से विमुख हो जाता है। दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धी व्यापार में निगम नौकरशाही एवं लालफीताशाही के कारण निजी व्यापार की प्रतिस्पर्धी में नहीं टिक पाता।
- निगम सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे अधिक मूल्य पर वस्तुओं को खरीदता है जबिक वे ही वस्तुए देशी व्यापारी कम मूल्य पर वहाँ से क्रय कर सकते हैं। अभी 19 मई-1994 से पूर्व निजी व्यापारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से चीनी आयात का अनुबन्ध 350 डालर प्रतिटन की दर से किया जबिक निगम ने उसी दिन 385 डालर प्रति टन की दर से आयात अनुबन्ध किया। 63 बाद में अर्थात् 7 जून,

<sup>62</sup> बाजार व्यवस्था-शर्मा एव जैन, साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या-128

<sup>63</sup> नवभारत टाइम्स- नई दिल्ली, 6 जून-1994

1994 को तो सरकारी एजेन्सी ने 407 से 415 डालर प्रतिटन की दरसे भी चीनी के आयात अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिया। 64 इससे स्पष्ट होता है कि निगम न्यूनतम मूल्यों पर आयात एव अधिकतम मूल्यों पर निर्यात में पर्याप्त रुचि नहीं लेता।

- गज्य व्यापार निगम के व्यय अन्य व्यापारिक सस्थाओं की तुलना में काफी अधिक है। निगम का स्थायां खर्च विगत वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गया है वर्ष 1989-90 में यह 3714 लाख रुपये था जो वर्ष 1991-92 में बढ़कर 4454 लाख रुपये हो गया है। इसमें स्थापना व्यय तथा ब्याज भुगतान के लिए चुकायी जाने वाली धनराशि का अधिक भाग है।
- भारतीय राज्य व्यापार निगम का विदेशी व्यापार मे योगदान घटता जा रहा है जो वर्ष 1980-81 में 9 24 प्रतिशत से क्रमश घटते हुए 1992-93 में केवल 0 87 प्रतिशत रह गया है। ऐसी स्थित में इतने बड़े राजकीय व्यापार सगठन के लिए यह एक चिन्ता का विषय है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि सरकार द्वारा सरणीबद्ध सूची को कम करने स निगम के सरणीबद्ध व्यापार में कमी आयी है, परन्तु उसने असरणीबद्ध वस्तुओं के व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाकर इस कमी को पूरा करने का उचित प्रयास नहीं किया।
- देश के उद्योग एव व्यापार से निगम का उचित पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में कमी के कारण देश में किसी वस्तु के वास्तविक/अनुमानित उत्पादन एव उसकी खपत की सही-सही जानकारी निगम को नहीं हो पाती और यदि समय रहते निगम को सही जानकारी नहीं हो पाती तो उचित समय पर वस्तु के आयात या निर्यात का निर्णय नहीं लिया जा सकता और जब तक सही समय पर आयात-निर्यात का निर्णय नहीं लिया जा सकेगा तब तक आयात का अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा तथा निर्यात का कम मूल्य प्राप्त होगा क्योंकि सही समय पर आयात-निर्यात का निर्णय न लिये जा सकने की दशा में निगम की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर पड जाती है।
- भारतीय राज्य व्यापार निगम पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि निगम के द्वारा सेवा मूल्य अधिक लिया जाता है तथा इसकी मूल्य नीतियाँ उचित नहीं है। ऐसी दशा में निगम राज्य की लोक कल्याणकारी विचारधारा से अलग होकर लाभ की भावना से प्रेरित एक निजी व्यापारिक सस्थान से अधिक कुछ और नहीं रह जाता जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कभी-कभी सेवा भावना को भूल सा जाता है।
- राज्य व्यापार निगम की एक मात्र अनुषगी सस्था भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ समन्वय का अभाव पाया जाता है तथा नीतियों में एकरूपता नहीं है, परिणामस्वरूप निर्णय लेने में कठिनाई होती है। चाय व्यापार निगम को वर्ष 1992-93 में कर से पूर्व 171 लाख रुपये की हानि होना, चिन्ता का विषय है।

<sup>64</sup> इण्डिया टुडे, 30 जून-1994, पृष्ठ सख्या-49

- इस प्रकार यदि समय रहते उपर्युक्त समस्याओ की ओर उचित ध्यान नही दिया गया तो राज्य व्यापार निगम वस्तुओ के राजकीय व्यापार का एक सज्ञात्मक आधार स्तम्भ मात्र बनकर रह जायेगा।
- (क्ष) सुझाव निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जो आलोचना की जाती है, उन्हें दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है-
- \* निगम को अपना लाभ बढाने के लिए व्यापारिक सिद्धान्तों का अनुपालन करना चाहिए। उसे अपनी विनियोजित पूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय दर 7-8 प्रतिशत निर्धारित कर देनी चाहिए और तद्नुसार अनुबन्धों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए। स्थापना व्यय तथा अन्य खर्चों में कटौती की जानी चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक कर्म चारियों को सेवानिवृत्ति देकर निगम के व्ययों को नियन्त्रित किया जा सके तथा लाभ की दर को बढाया जा सके।
- \* आर्थिक मामलो में सही समय पर सही निर्णय लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है ऐसी दशा में राज्य व्यापार निगम में अधिकारो एव उत्तरदायित्वो दोनों का और अधिक विकन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। राजनीतिक पदाधिकारियों के अधिकारों को सीमित कर, परिभाषित कर दिया जाना चाहिए तािक वे निगम के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न कर सके।
- \* निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालयों के बीच सवादद्दीनता जैसी स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए जब भी आवश्यकता समझी जाय तो मन्त्रिमण्डलीय सचिवों की समिति बनाकर अहम् मुद्दों पर विचारों का प्रत्यक्ष आदान—प्रदान किया जाना चाहिए ताकि किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके तथा उसका त्वरित कार्यान्वयन भी हो सके।
- \* निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो की नियुक्ति या तो अपनी स्वय की एक स्वच्छ समिति द्वारा अथवा किसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जानी चाहिए। केवल अपरिहार्य परिस्थिति मे ही अधिकारियो एव कर्मचारियो की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए वह भी या तो बहुत थोडे समय के लिए अर्थात् 1 वर्ष से कम अथवा 5 वर्ष से अधिक। इससे निगम अपरिहार्य परिस्थितियो से बच भी सकता है तथा यदि लम्बे समय तक नियुक्ति की जाती है तो कर्मचारी या अधिकारी की अनुभव से अर्जित कार्यक्षमता का उपयोग भी हो सकेगा।
- \* निगम पर विगत वर्षों मे विदेशी व्यापार मे भागीदारी की बहुत कमी, के आरोप का निराकरण, असरणीबद्ध वस्तुओं के व्यापार में योगदान करके बढाया जा सकता है। क्योंकि सरकार की उदारीकृत नीतियों के अधीन, न केवल सरकार द्वारा आयात अथवा निर्यात की जाने वाली क्त्तुओं की सख्या में बहुत कमी कर दी गयी है। अत अब निगम को देश के निजी व्यापारियों के समकक्ष अपनी

उपयोगिता को सिद्ध करते हुए प्रतियोगी विश्व बाजार में अपना स्थान बनाना है। अत उसे समाज की सेवा भावना के साथ-साथ अपने लाभ-हानि को भी ध्यान में रखकर अनुबन्ध स्वीकार करने चाहिए।

\* निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो में स्वेच्छा से कार्य करने की भावना जागृत करने के लिए प्रभावपूर्ण, वित्तीय एव अवित्तीय दोनो प्रकार के अभिप्रेरण साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे व्यक्ति समझ सके कि निगम के हित में उनका हित भी विद्यमान है। ऐसी दशा में वे पूर्ण निष्ठा,ईमानदारी एव पूरी कार्यक्षमता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

\* देश के उद्योग एव व्यापार से निगम को व्यावहारिक सम्बन्ध निरन्तर बनाये रखना चाहिए तािक वस्तुओं के उत्पादन एव खपत के सम्बन्ध में सही स्थिति की समय से जानकारी मिल सके। उत्पादन एव खपत के सही समय पर सही आकड़ों के आधार पर ही निगम के आयात—निर्यात में सौदेबाजी की शिक्त को बढावा मिलेगा तथा लाभदायक अनुबन्ध प्राप्त हो सकेगे।

\* निगम के अधिकारियो एव कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने का निगम का प्रयास सराहनीय रहा है परन्तु प्रशिक्षण के समय अन्तराल को और कम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की नयी—नयी विधियो का प्रयोग कर कर्मचारियो मे कार्य करने की क्षमता का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए।

\* निगम की अनुषगी संस्था भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ निगम को समन्वय बनाये रखना चाहिए। दोनो की नीतियों में एकरूपता एवं सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। चाय व्यापार निगम को हो रही हानि पर नियन्त्रण पाने के लिए व्ययों पर नियन्त्रण करते हुए उन सुझावों का अनुपालन करना चाहिए जो राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्र में चल रही आतंकवादी गतिविधियों से उत्पादन को निष्प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

\* कर्मचारियों की नियुक्ति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमें व्यापारिक क्षमता एव योग्यता विद्यमान हो। नियुक्ति के पूर्व उनकी व्यापारिक क्षमता एव योग्यता को नवीन विधियों से पर्याप्त परीक्षण करके ही नियुक्ति की जानी चाहिए।

\* निगम को यथार्थवादी व्यापारिक मूल्य-नीति अपनानी चाहिए। एकाधिकारी वस्तुओं के व्यापार में अधिक मूल्य लेने का आरोप सही प्रतीत नहीं होता फिर भी निगम को उचित सेवा मूल्य ही निर्धारित करना चाहिए। उसे प्रशासनिक सुविधा पर अधिक ध्यान न देकर ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।

\* निगम को नयी वस्तु एव नये बाजार की खोज पर अधिक धन खर्च करना चाहिए। वर्तमान समय में सरकार सरणीबद्ध वस्तुओं की सख्या में कमी करती जा रही है जिससे निगम को स्वय अपना व्यापार क्षेत्र एव व्यापार की वस्तु का चयन करना है। ऐसी दशा में वस्तु एव बाजार का नया क्षेत्र खोजना अपरिहार्य हो गया है। इस प्रकार यदि निगम उपर्युक्त सुझावो पर भली—भौति विचार कर इन्हें कार्यरूप प्रदान करें तो यह देश की सरकार एव जनसाधारण के लिए एक उपयोगी सस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा। वैसे यह समय सरणीबद्ध व्यापार में परिवर्तन का है जिसमें भारतीय राज्य व्यापार निगम को तेजी से सुधरते हुए विश्व आर्थिक वातावरण द्वारा प्रस्तुत आश्चर्यजनक व्यापारिक सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए। निगम कृषि वस्तुओं के आयात—निर्यात पर अधिक जोर देकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की भूमिका को निभाते हुए अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। आगामी बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के युग में निगम की नजर भविष्य पर है जहाँ यह निर्यात पर प्रमुख रूप से बल देते हुए उच्च प्रतियोगी विश्व व्यापार जगत में एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के रूप में उभरना चाहता है। निश्चित है कि निगम उदारीकरण की तरगो और भारत के बाहर निष्क्रिय उपक्रमों के ऊपर चढकर भारत को विश्व—व्यापार के नये मुकाबलें में अग्रभाग पर खडा करेगा।

## (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेन्सियाँ -

राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त देश के आयात—निर्यात व्यापार में राजकीय भागीदारी को बढावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अन्य कई एजेन्सियाँ भी स्थापित की गयी है जिनमें से प्रमुख निम्नवत् है—

(अ) <u>भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड</u> इस निगम की स्थापना जून, 1962 में भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप में की गयी थी, जिसकी प्रदत्त पूँजी, जो कि 12 लाख रुपये थी, को राज्य व्यापार निगम ने स्वय लिया था। अक्टूबर, 1962 में राज्य व्यापार निगम के एक भाग के रूप में स्थापित हथकरघा निर्यात सगठन को एक सहायक निगम बना दिया गया जिसे हथकरघा निर्यात निगम कहा जाता है। ऐसा कार्यों में समन्वय एवं सकेन्द्रण के उद्देश्य से किया गया था। निगम विकासशील देशों के साथ-साथ विकसित देशों जैसे- पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका एवं अन्य यूरोपियन देशों को हाथ से बने कपड़ों के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

इस निगम की समता पूँजी 31 मार्च-1991 को 750 लाख रुपये तथा ऋण पूँजी 1054 लाख रुपये थी। निगम की शुद्ध बिक्री वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में क्रमश 7900 लाख रुपये तथा 4820 लाख रुपये थी परन्तु कर के बाद वर्ष 1989-90 में तो निगम को 11 लाख रुपये का लाभ हुआ जबिक वर्ष 1991-92 में 254 लाख रुपये की हानि हुई। 65

13 मई 1991 को भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम को भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग कर दिया गया। इस निगम मे भारतीय राज्य व्यापार निगम के 7 5 करोड़ रुपये की सारी साझेदारी राष्ट्रपति(वस्त्र मन्त्रालय) को नकद भुगतान पर हस्तान्तिरत कर दी गयी है और अब यह निगम

<sup>65</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-560

स्वतन्त्र रूप से कर रहा है। 66

(ब) भारतीय खिनज एव धातु व्यापार निगम लिमिटेड — इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम के कार्यों को सुचारूप से चलाने के लिए इसे दो भागों में विभाजित कर वर्ष 1963 में की गयी। इसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रुपये तथा प्रार्थित पूँजी 2 करोड़ रुपये हैं। यह निगम खिनजों व धातु के विदेश व्यापार में अक्टूबर 1963 से महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इसे 17 मई, 1990 को भारत बिजनेस इण्टरनेशनल लिमिटेड (बी बी आई एल) की सहायक कम्पनी बना दिया गया। परन्तु 26 मार्च, 1991 को यह निगम पूर्व स्थिति में आ गया। अब लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रोम का निर्यात इस निगम के माध्यम से होता है। परन्तु 19 अगस्त, 1993 से कोयले के निर्यात का कार्य निगम से अलग कर दिया गया। इसी प्रकार 1991—92 के दौरान औद्योगिक कच्चा माल, अलौह धातुओ, उर्वरको तथा उर्वरको के निर्माण में काम आने वाली गधक और रॉक फास्फेट इत्यादि के आयात का कार्य भी निगम से अलग कर दिया गया है।

अब यह निगम निर्यात के क्षेत्र में अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इनमें कृषि पर आधारित उत्पादों, माँस और मछली, हीरे, जवाहरात, आभूषण और कुछ अन्य वस्तुए, जैसे— कपडा तथा चमडा और चमडे से निर्मित वस्तुए भी शामिल है। आयात करने के लिये यह निगम अलौह धातुओं , इस्पात के अलावा स्वर्ण, बिना तराशे हीरे और कीमती पत्थर इत्यादि पर ध्यान देगा। 1786 करोड रुपये के निर्यात, 6241 करोड रुपये के आयात और 88 करोड रुपये का घरेलू व्यापार वर्ष 1991—92 के दौरान किया गया।यदि समग्र रूप में देखा जाय तो निगम ने वर्ष 1991—92 के दौरान कुल 8115 करोड रुपये का व्यापार किया। हाल ही में निगम सिगापुर, बर्लिन(जर्मनी) न्यूयार्क(अमेरिका) और टोक्यो(जापन) में अपने विदेशी कार्यालय खोले हैं। वर्ष 1974 में स्थापित माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड, भारतीय धातु एव खनिज व्यापार निगम लिमिटेड की एक सहयोगी सस्था है। यह माइका के निर्यात का कार्य करती है। वर्ष 1992—93 के दौरान इस सस्था के द्वारा 5 लाख 81 हजार डालर का निर्यात किया गया।

- (स) <u>भारतीय काजू निगम लिमिटेड —</u> इस निगम की स्थापना 1970 में काजू एव कच्चे काजू के निर्यात को बढावा देने के लिए की गयी। यह निगम मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित करता है—
  - कच्चे काजू के आयात के नये-नये साधानो को खोजना।
  - काजू निर्यात को परम्परागत बाजार में बढाना तथा अपम्परागत बाजारो की खोज करना।
- देश से काजू की बनी वस्तुओ का निर्यात करने वाली सस्थाओ को काजू की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

<sup>66</sup> वार्षिक प्रतिवेदन-1990-91, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36-जनपथ, नई दिल्ली, पृष्ठ स0-63-65

इन्हीं कार्यों के निष्पादन हेतु निगम ने पेरिस और न्यूयार्क में अपने विदेशी कार्यालय भी खोले हैं, परन्तु इन्हें अभी तक आशातीत लाभ नहीं हुआ है। 31 मार्च, 1991 से भारतीय काजू निगम को भारतीय राज्य व्यापार निगम में समामेलित कर दिया गया है। काजू निगम के सचय रुपये 14 61 करोड़ को राज्य व्यापार निगम के सचय में 31मार्च-1992 को मिला दिया गया। वर्तमान समय में काजू व्यापार की गतिविधियों का सचालन करने के लिए अलग से काजू अनुभाग खोला गया है तथा इसकी शाखा को कोचीन में विकेन्द्रित कर दिया गया है। इसके समस्त कर्मचारियों को राज्य व्यापार निगम में उनके तात्कालिक कैंडर प्रदान कर दिये गये हैं। 31 मार्च, 1991 को निगम की समता पूँजी 150 लाख रुपये तथा ऋण पूँजी 1361 लाख रुपये थी। निगम की वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में शुद्ध बिक्री क्रमश 785 एव 962 लाख रुपये रही। इस प्रकार निगम को कर के बाद क्रमश 92 एव 142 लाख रुपये का लाभ हुआ। 67

(द) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड — इस निगम की स्थापना राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप में अप्रैल 1971 में की गयी। निगम का मुख्य उद्देश्य इजीनियरिंग उपकरणों तथा परियोजनाओं के निर्यात को बढावा देना था। रेलो, इजनो, भारती उपकरणों का निर्यात तथा सिविल निर्माण कार्य तथा निर्धारित अविध में परियोजनाओं का पूरा करना इस निगम की विशेषता है। निगम यह भी देखता है कि माल के निर्माताओं की प्रौद्योगिक क्षमता ठीक और समुचित है। यह निगम इस बात को सुनिश्चित करता है कि जिन कामों का ठेका लिया गया है वे उचित गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हो।

इस निगम को भी 17 मई, 1990 को बी बी आई एल की अनुषगी कम्पनी बना दिया गया था परन्तु 26 मार्च, 1991 को ही बी बी आई एल को समाप्त कर दिया गया। अत यह पुन अपनी मूल स्थिति मे वापस आ गया। वर्ष 1991-92 मे इस निगम ने 189 करोड़ रुपये का निर्यात और 4 करोड़ रुपये का आयात किये। निगम का इस वर्ष कुल कारोबार 193 करोड़ रुपये का रहा।

(य) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड — हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम की एक सहायक सस्था के रूप में 4 फरबरी—1976 को केन्द्रीय कुटीर उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई। निगम ने 1 अप्रैल—1976 से कुटीर उद्योग इम्पोरियम का कार्य भी अपने हाथों में ले लिया। निगम की समता पूँजी 31 मार्च—91 को 75 लाख रुपये, ऋण पूँजी 128 ला। रुपये तथा आरक्षित पूँजी 123 लाख रुपये थी। इस प्रकार 31 मार्च 1991 को इसकी पूँजी 326 लाख रुपये थी। इसका प्रमुख कार्य हस्तिशिल्प एव हथकरघा से तैयार कपड़ों का विक्रय करना है। इसके अतिरिक्त यह निगम कुटीर उद्योग के विकास में भी अहम् भूमिका अदा करता है। निगम की वर्ष 1989—90 तथा 90—91 की कुल बिक्री विवास प्रतिवेदन—1990—91, भारतीय राज्य व्यापार निगम, 36—जनपथ, नई दिल्ली—पृष्ठ सं0 63—65

क्रमश 1924 लाख रुपये तथा 2060 लाख रुपये थी। इन वर्षों मे निगम ने कर के बाद क्रमश 13 एव 88 लाख रुपये का लाभ कमाया। क्योंकि 13 मई, 1991 को इसकी सूत्रधारी कम्पनी भारतीय हस्तिशिल्प एव हथकरघा निर्यात निगम को उसके सूत्रधारी कम्पनी भारतीय राज्य व्यापार निगम से अलग कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कुटीर उद्योग निगम भी अब राज्य व्यापार निगम का अनुषगी नहीं रहा।

(र) भारतीय राज्य रसायन एव भेषज निगम लिमिटेड — भारतीय राज्य व्यापार निगम की सहायक कम्पनी के रूप में 1 जनवरी, 1976 को भारतीय राज्य रसायन एव भेषज निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी। दिसम्बर 1975 तक रसायन एव औषधियों से सम्बन्धित जो व्यापार राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता था इस निगम को सौप दिया गया। यह निगम केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अनुसार अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवाए प्रदान करता है। निगम उत्पादकों को कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर उत्पादन में सहायता करता है जिससे वितरण व्यवस्था एव मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सके।

### (ग) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ -

पिछले कुछ वर्षों से उपभोक्ता सहकारी समितियाँ राजकीय व्यापार के सहायक अगो के रूप मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनसाधारण, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को आवश्यक वस्तुए पहुँचाने मे ये समितियाँ महत्वपूर्ण माध्यम प्रमाणित हो रही है। निचले स्तर पर आत्मिनर्भर लोकतान्त्रिक सस्थाओं के रूप मे उपभोक्ता सहकारी समिति के विकास की राष्ट्रीय नीति बनायी गयी है। इन समितियों का प्रबन्ध व नियन्त्रण इनके सदस्य अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए करते है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सहकारिता आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये है।

आठवी पचवर्षीय योजना में उपभोक्ता आन्दोलन को अधिक सुदृढ करने का प्रस्ताव है जिससे वितरण में इनका कार्य क्षेत्र बढाया जा सके और क्षेत्रीय असन्तुलन कम हो जाय। सहकारिता आन्दोलन को खण्ड, तहसील एव क्षेत्र तक पहुँचाने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से उचित व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा दिन-प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण किया जाता है। इसमें वस्तुओं की उपलब्धता एव गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाती है। सुपर बाजार दिल्ली, अपना बाजार बम्बई, ट्रिपलिकेन शहरी उपभोक्ता स्टोर, मद्रास, थोक स्टोर, कलकत्ता, जनता बाजार कोल्हापुर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यर्ना बाजार, आजिनया बाजार, शेंद्रे जनता बाजार, रायगढ इसके आदर्श उदाहरण है।

मार्च, 1992 तक गावो मे 26,505 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला स्तर पर 605 केन्द्रीय/ जिला थोक उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, 30 राज्य स्तरीय उपभोक्ता सघ/राज्य विपणन तथा उपभोक्ता परिसघ और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसघ था। इनके शहरी क्षेत्रो मे 50,159 फुटकर बिक्री केन्द्र थे। अनुमान है कि शहरी सहकारी सस्थाओं ने 1992–93 में 3,300 करोड़ रुपये तक का कारोबार किया 68

राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र उपभोक्ता सहकारी सस्था राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसघ की स्थापना 1965 की में की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को बढावा देने के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान करना था। इस परिसघ के 108 सदस्य है।

सुपर बाजार सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली की स्थापना एक प्राथमिक भण्डार के रूप में 1966 में की गई। इसका उद्देश्य मूल्यों पर नियन्त्रण, उचित व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा दिल्ली राज्य में आम लोगों के दिन प्रतिदिन की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। यह सुपर बाजार पाँच क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों, 15 दवा बिक्री सिहत 148 शाखाओं, फल और सब्जी की गाडियों सिहत37 चलती—फिरती गाडियों के माध्यम से अपना काम काज चला रहा है। सुपर बाजार के कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुपर बाजार के पहले वर्ष में इसका कुल कारोबार 4 करोड रुपये का था जो वर्ष 1991—92 में बढ़कर 97 82 करोड रुपये हो गया। 31 मार्च 1992 तक सुपर बाजार की सदस्य सख्या 32,022 थी और चुकता पूँजी 152 02 लाख रुपये थीं, जिसमें सरकार का योगदान 128 70 लाख रुपये का था।

सरकार प्राथमिक सहकारी समितियों, बडी बहुउद्देश्यीय समितियों और किसान सेवा समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का आवण्टन करने के लिए मार्जिन की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है। आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 1 अप्रैल, 1992 से राज्यों को हस्तान्तरित की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 82,905 प्राथमिक सहकारी समितियों है। इनमें से लगभग आधी समितियों ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का आवण्टन करने में लगी हुई हैं।

## (घ) कुछ स्वायत्तशासी सस्थाए -

राजकीय व्यापार में सहयोग करने वाली कई स्वायत्त्तशासी सस्थाए भी है जो वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन कार्य करती है। ये सस्थाए मुख्यत निर्यात के विकास और

<sup>68</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-456

उसके सम्वर्द्धन का काम देखती है। इनमें से कुछ प्रमुख स्वायत्तशासी सस्थाए निम्नवत् है-

- 1 <u>अनुविहित वस्तु बोर्ड(परिषद)</u> भारत में वर्तमान समय में 5 अनुविहित वस्तु बोर्ड है जो चाय, कॉफी रबर, मसाले और तम्बाकू के उत्पादन, विकास एवं निर्यात के विषय में अपने—अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। कलकत्ता स्थित निर्यात निरीक्षण परिषद भी एक अविहित सस्था है, जो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म एवं गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखती है। निर्यात निरीक्षण परिषद जहाज पर लदान से पहले निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करती है।
- 2 <u>भारतीय विदेश व्यापार सस्थान</u> भारत के राजकीय व्यापार मे भारतीय विदेश व्यापार सस्थान-नई दिल्ली भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह एक पजीकृत सस्था है। यह सस्थान मुख्य रूप से निम्न कार्यों को निष्पादित करता है-
- \* राजकीय व्यापार में लगे कर्मचारियों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना।
  - \* विदेश व्यापार मे आने वाली समस्याओ पर अनुसधान के लिए व्यवस्था करना।
  - \* विपणन अनुसधान, क्षेत्र सर्वेक्षण, वस्तु सर्वेक्षण और बाजार सर्वेक्षण का आयोजन करना तथा,
- \* अनुसधान तथा बाजार अध्ययन से सम्बन्धित इसकी गतिविधियो से प्राप्त सूचना का प्रचार प्रसार करना।
- 3 <u>इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पैकेजिंग बम्बई</u> इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ बम्बई भी इसी प्रकार की एक स्वायत्तशासी सस्था है, जो 1966 में स्थापित एव पजीकृत हुयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य पैकिंग उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल के सम्बन्ध में अनुसधान करना, पैकिंग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना, अच्छी पैकिंग की आवश्यकता के लिए चेतना का विकास करना आदि है।
- 4 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे राजकीय व्यापार में सलग्न 11 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन तथा 8 निर्यात सम्वर्द्धन परिषदे वस्त्र मन्त्रालय के अधीन काम कर रही है। ये परिषदे कम्पनी अधिनियम के अधीन रिजस्टर्ड और लाभ न कमाने वाली सस्थाए है। ये सस्थाए सलाहकारी एव व्यापार सचालन दोनो प्रकार का काम करती है। निर्यात प्रयासों में ये फसल पैदा करने वालो, उत्पादको और निर्यातको का सिक्रिय सहयोग लेती है। ये परिषदे पजीकृत निर्यातको के लिए आयात—निर्यात नीति के अन्तर्गत पजीकरण प्राधिकारी का कार्य भी करती है। इन परिषदों का प्रमुख उद्देश्य निर्यात को बढावा देना तथा उसका विकास करना है।
  - 5 <u>निर्यात विकास प्राधिकरण –</u> कृषि जन्य तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण

फरवरी-1986 में गठित किया गया। यह प्राधिकरण कृषि जन्य पदार्थों के निर्यात के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करता है। विकास प्राधिकरण तैयार खाद्य पदार्थों को निर्धारित मूल्य पर बेचने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करता है। यह सस्था भी माल की गुणवत्ता एव किस्म पर नियन्त्रण रखने के लिए कारगर उपायों की व्यवस्था करती है।

6 <u>मारतीय निर्यात सगठन सघ</u> — भारतीय निर्यात सगठन सघ, नई दिल्ली विभिन्न निर्यात सम्बन्धी सगठनो और सस्थाओं की शीर्षस्थ सस्था है। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त घरानों को समन्वित सहायता देने के लिए प्रारम्भिक सेवा इकाई के रूप में तथा देश के परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में निर्यात के प्रयत्नों को बढावा देने के लिए एक केन्द्रीय समन्वय अभिकरण के रूप में भी कार्य करता है।

7 <u>भारतीय विवाचन परिषद —</u> भारतीय विवाचन परिषद, नई दिल्ली, सोसायटी पजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। यह व्यापारियो, विशेषकर उन व्यापारियो को जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सलग्न है के बीच वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के उपाय के रूप में मध्यस्थता को बढावा देती है।

- 8 <u>भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन सगठन</u> वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों को कार्य रूप प्रदान करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को मिलाकर भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन सगठन(इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन) स्थापित किया गया है इस सगठन की स्थापना 1 जनवरी 1992 को की गयी तथा इसका मुख्यालय प्रगित मैदान, दिल्ली में है। व्यापार सम्बर्द्धन के लिए यह सगठन राजकीय व्यापार एजेन्सी के रूप में समय—समय पर मेले एवं प्रदर्शनियों आयोजित करता है। यह व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाए उपलब्ध कराने का काम भी करता है।
- 9 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक अनुबन्धित सस्था के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन की स्थापना अगस्त-1972 में की गयी थी। यह सस्था समुद्र के विभिन्न उत्पादों के विकास और विशेष रूप से निर्यात को बढावा देने के लिए आवश्यक उपायों का कार्यान्वयन करता है।
- 10 केन्द्रीय सलाह कार परिषद व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाह कार परिषद में व्यापारिक एव वाणिज्यिक क्षेत्र में ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले विभिन्न सगठनों और व्यक्तियों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये है। यह परिषद सरकार को निम्न विषयों से सम्बन्धित मामलों पर अपने सुझाव देती हैं (अ) निर्यात और आयात नीति कार्यक्रम तय करना (ब) आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण का कार्यान्वयन करना (स) वाणिज्यिक सेवाओं का सगठन ओर विकास करना (द) निर्यात उत्पादन का सगठन और विस्तार करना।

<sup>69</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-560-62

- 11 <u>व्यापार परिषद —</u>केन्द्रीय वाणिजय मन्त्री की अध्यक्षता मे एक व्यापार परिषद की स्थापना की गयी है जो सरकार का निर्यात को बढावा देन एव आयात—नियन्त्रण के कार्यक्रमो और नीतियों को अपनाने के बारे में सलाह देता है।
- 12 <u>अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय</u> आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अधीन कार्यरत् आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण सगठन मुख्य रूप से सरकार की आयात व निर्यात नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। सरकार द्वारा 1992-97 की अविध के लिए घोषित नई निर्यात-आयात नीति को ध्यान में रखते हुए इस सगठन का नाम बदलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महानिदेशालय कर दिया गया है। यह सगठन लोहे, इस्पात तथा लौह मिश्रित धातुओं के आयात और निर्यात के लिए लाइसेन्स देने की प्यवस्था करता है।

इस प्रकार राजकीय व्यापार में सहयोग करने वाली अन्य एजेन्सियों अपने—अपने उद्देश्यों की विशिष्टता के अनुसार देश के व्यापारिक एव वाण्जियक उन्नित में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इन एजेन्सियों के कार्यों में आने वाली प्रमुख बाधाए वहीं हैं जो पूर्व वर्णित भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम एव राज्य व्यापार निगम की है। क्योंकि इन एजेन्सियों की स्थापना विभिन्न मन्त्रालयों एव सरकारी विभागों के अधीन की गयी है इसलिए इनके नीति निर्धारण, प्रशासन, कार्यान्वयन एव उपलब्धियों में आने वाली प्रमुख समस्याए अन्य सरकारी विभागों की तरह प्रशासनिक ही हैं जैसे—विभिन्न मन्त्रालयों एव विभागों में तालमेल न होना, राजनीतिक पदाधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों में इस्तक्षेप करना, निर्णय में विलम्ब, नौकरशाही, अधिकारों का केन्द्रीकरण, सम्बद्ध विभागों का असहयोग, कर्मचारियों में कार्य—प्रेरणां का अभाव इत्यादि है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए विभागों के प्रशासनिक सुधार की अपेक्षा है। विभिन्न मन्त्रालयों एव विभागों में समन्वय, राजनीतिक एव विभागीय अधिकारियों के अधिकार एव उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या अधिकारों एव उत्तरदायित्वों का साथ—साथ यथासम्भव विकेन्द्रीयकरण, विभिन्न प्रकार के नवीनतम तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण, वित्तीय एव अवित्तीय अभिप्रेरणा के साधनों का प्रयोग, प्रतिनियुक्तियों में कमी, नयी नियुक्तियों में व्यापारिक एव वाणिज्यिक योग्यता, कुशलता, अनुभव एव अभिरुचि को ही आधार बनाना इत्यादि उपायों के द्वारा कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यदि इनकी समस्याओं को दूर करने का सार्थक प्रयास, समय पर, पूरी निष्ठा के साथ किया गया तो नि सन्देह राजकीय व्यापार की ये एजेन्सियों बदलते हुए विश्व एव भारतीय आर्थिक परिदृश्य में अपनी उपादेयता सिद्ध कर सकेगी।

<sup>70</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-560-62

# चतुर्थ-सर्ग चतुर्थ-सर्ग ज्य द्वारा व्यापार का नियमन

### चतुर्थ-सर्ग

### राज्य द्वारा व्यापार का नियमन

राज्य द्वारा विपणन क्रियाओ एव गतिविधियो के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक भूमिका का सम्पादन अनेक वैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता है। राज्य के विधान या सविधान के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों से निर्मित सरकार को विभन्न क्षेत्रों में विधान बनाने सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अधिकार का प्रयोग सरकार के द्वारा उन विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक वैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए किया जाता है जो देशवासियों की आकाक्षाओं के रूप में देश के सविधान में परिलक्षित होती है।

भारतीय सिवधान मूल रूप से देश को समाजवादी समाज के रूप में स्थापित करने की जनभावना का उल्लेख करता है और इस दिशा में सामान्य नागरिको हेतु कुछ मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति—निदेशक सिद्धान्तों का अद्भुत समन्वय भारतीय सिवधान में दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक क्रियाओं में राजकीय हस्तक्षेप सम्बन्धी अधिकार की मात्रा और दिशा देश के विधान के अन्तर्गत ही निर्धारित होती है।

भारतीय सविधान के अन्तर्गत राज्य के लिए निर्धारित आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु देश की अर्थव्यवस्था के सचालन में व्यापक सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। इस तथ्य को सविधान में हुए अनेक महत्वपूर्ण संशोधनों ने और भी मजबूती प्रदान की है। भारतीय जनता ने देश को सम्प्रभुता—सम्पन्न समाजवादी, धर्मिनरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए संभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने के उद्देश्यों से सरकार ने सविधान के माध्यम से अनेक प्रभावशाली कदम उठाये हैं। भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में केन्द्र तथा राज्य सरकारे देश की प्रशासनिक एवं सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में विधान बनाने की अधिकारी है, अतएव भारतीय सविधान में केन्द्र एवं राज्य के कार्यों का वर्गीकरण किया गया है। सरकार की समाजवादी सकल्पना ने आर्थिक क्रियाओं में राजकीय हस्तक्षेप के संभी पहलुओ—नियन्त्रात्मक, प्रोत्साहनात्मक तथा भागीदारी के क्षेत्र में राज्य की भूमिका में निरन्तर वृद्धि की है।

समाजवादी समाज की स्थापना करने एव उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सरकार ने आर्थिक लाभ कमाने की होड को बढाया है जिसके परिणामस्वरूप वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भूल कर समाज का शोषण करना प्रारम्भ कर देते हैं। आधुनिक सरकारे इस शोषण प्रवृत्ति पर नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार का अधिकार विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर लेती है। भारत में इस प्रकार के बहुत से अधिनियम है जिनमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा की गयी है। ये प्रमुख अधिनियम अम्मिकित हैं

# (क) औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम-1951 -

वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति को तीन वर्ष तक कार्यान्वित करने के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के प्रारूप एव औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण को आवश्यक माना तथा पचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप आर्थिक विकास की दिशा प्रदान करने का निश्चय किया। इसको ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर, 1951 में औद्योगिक(विकास एव नियमन) अधिनियम–1951 बनाया। यह अधिनियम 8 मई, 1952 से लागू है। इसके अधीन अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना आवश्यक है। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान की जाँच कर सकती है एव ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें सरकार आवश्यक समझे। यदि किसी उपक्रम में अव्यवस्था एव कुप्रबन्ध जारी रहता है तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उसके प्रबन्ध व नियन्त्रण को अपने हाथ में ले ले। अधिनियम से सम्बन्धित प्रमुख बाते निम्नवत् है—

- (अ) अधिनियम के उद्देश्य इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों के विकास एव नियमन को देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारधाराओं के अनुरूप करना है। इसके द्वारा सरकार को देश में उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करने, बड़े एवं छोटे उद्योगों का एक साथ विकास करने तथा उद्योगों का पूरे देश में उचित क्षेत्रीय विकास करने तथा कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं—
- 1 देश में उद्योगों का विकास एवं विनियमन करना तथा सतुलित आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करना।
- 2 क्षेत्रीय सन्तुलन के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय असतुलन को कम करने तथा उद्योगों के विकास के लिए ऐसे प्रयत्न करना जिससे क्षेत्रीय सतुलन बनाये रखने में सहायता मिल सके।
- 3 देश मे आर्थिक सकेन्द्रण पर ध्यान रखना तथा अनुज्ञापत्र देते समय नियन्त्रणात्मक शक्तियो का उपयोग करना।
- 4 देश मे उपलब्ध एव सम्भावित साधनों के उपयोग के लिए विनियमात्मक साधनों का उपयोग करना। आवश्यक उपभोग एव साधनों के दुरुपयोग को रोकना।
- 5 बड़े उद्योगों की अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों से उत्पन्न सकट से लघु उद्योगों की रक्षा करना तथा लघु उद्योगों को भी विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- 6 योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के क्रमानुसार उपलब्ध साधनों का विभिन्न उद्योगों में उचित बॅटवारा करना तथा यह देखना कि प्राथमिकताओं के अनुसार उद्योगों का विकास किया जा रहा है।

7 नये उद्यमियों को नये उद्योगों की स्थापना में प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करना। इसका प्रमुख आशय औद्योगिक जगत में नवीन साहस को स्वीकार करना तथा मान्यता देना है।

- 8 अनार्थिक इकाइयो एव क्रियाओ की समीक्षा करना तथा इसके लिए उपचारात्मक साधन जुटाना।
- 9 उद्योगो द्वारा किये जाने वाले उत्पादन, वितरण एव मूल्य निर्धारण पर आवश्यकतानुसार विनियमन करना।
- 10 औद्योगिक क्रियाओं की पूर्ण जानकारी रखना तथा औद्योगिक प्रगति का लक्ष्यानुसार अवलोकन करना।
- 11 अनुसूचित उद्योगो में नीति-विचलन की स्थिति में जॉंच की व्यवस्था करना तथा सुधारात्मक उपायों का उपयोग करना।
  - 12 नवीन विधियो एव तकनीको के प्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- (ब) <u>अधिनियम का क्षेत्र</u> प्रारम्भ में यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोडकर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता था। सशोधन अधिनियम-1960 से अब यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर सिंहत सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। औद्योगिक(विकास एव नियमन) अधिनियम के प्रावधान उन समस्त उद्योगो पर लागू होते हैं जिनको अधिनियम की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अधिनियम की व्यवस्थाए ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयो पर लागू होती है जो कि अनुसूचित उद्योगो केअन्तर्गत वर्गीकृत करके प्रथम अनुसूची में सिम्मिलित उद्योगो से सम्बद्ध है। भले ही उनमें उत्पादन एक अथवा एक से अधिक कारखानों में किया जाता हो। व्यवहार में ऐसी समस्त उत्पादक इकाइयों इसके अन्तर्गत आ जाती है जिनमें यदि यान्त्रिक शक्ति का उपयोग न होता हो तो सौ या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो अथवा यदि उसमें यान्त्रिक शक्ति का उपयोग होता हो तो पचास या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो।

इस अधिनियम मे यह अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि समस्त अनुसूचित उद्योग सरकार से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाइसेन्स प्राप्त करे। इन अनुज्ञापत्रों में उद्योग के बारे में समस्त प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया जाता है जिससे कि औद्योगिक इकाई के बारे में पर्याप्त सूचना मिल सके। जैसे वह स्थान जहाँ उसकी स्थापना की जायेगी, उत्पत्ति वस्तुओं का नाम, कुल उत्पादन क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध आवश्यक तथ्य।

24 जुलाई, 1991 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति में केवल 18 प्रमुख उद्योगों को छोडकर अन्य सभी के लिए अनुज्ञापत्र व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी, चाहे उनमें कितनी ही पूँजी क्यों न लगायी जाय। 1 14 अप्रैल, 1993 से मोटरकार, खाले व चमडा तथा रेफ्रीजरेटर उद्योगों को अनुज्ञापत्र प्रणाली से

<sup>1</sup> भारतीय अर्थव्यवस्था-मामोरिया, सी बी ,साहित्य भवन आगरा-1995,पृष्ठ सख्या-214

मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब केवल 15 उद्योगों के लिए ही अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू है। <sup>2</sup> वर्तमान समय में उन उद्योगों की सूची निम्नवत् है जिन्हें अनुज्ञापत्र प्राप्त करना अनिवार्य है—

- 1 कोयला तथा लिग्नाइट
- 2 पेट्रोलियम(कच्चे तेल के अलावा) तथा इसके आसवन(डिस्टिलेशन) पदार्थ
- 3 एल्कोहल युक्त पेयो का आसवन एव इनके शराब बनाना
- 4 चीनी
- 5 पशु चर्बी तथा तेल
- 6 तम्बाकू के सिगार एव सिगरेटे तथा विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापन
- 7 एस्बेस्ट्स एव एस्बेस्ट्स पर आधारित उत्पाद
- 8 प्लाईवुड,डेकोरेटिव वीनियर्स तथा लकडी पर आधारित अन्य उत्पाद, जैसे कि मीडियम डेन्सिटी फायबर बोर्ड, ब्लौक बोर्ड
- 9 साभर चर्म एव रोएदार रगीन खाले
- 10 खोई पर आधारित एकको को छोडकर कागज तथा अखबारी कागज
- 11 इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण, सभी प्रकार के
- 12 डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिसो सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री
- 13 खतरनाक रसायन
- 14 औषध एव भेषज(औषध नीति के अनुसार)
- 15 मनोरजन हेतु इलेक्ट्रानिक्स(वी सी आर ,कलर टी वी ,सी डी प्लेयर्स, टेप रिकार्डस)<sup>3</sup>
- (स) अधिनियम के प्रावधानों में छूट अधिनियम की धारा 29(ब) के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह कुछ उद्योगों को इस अधिनियम के प्रावधानों एवं व्यवस्थाओं से छूट प्रदान कर सकती है। ऐसे छूट प्राप्त उद्योगों के विषय में पहले छूट की सीमा दस लाख रुपये थी जिसे बढाकर सन् 1964 में 25 लाख रुपये कर दिया गया। फरवरी—1970 में पुन बढाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया और वर्ष 1978 में इसे पुन बढाकर 3 करोड़ रुपये तथा अप्रैल 1983 में पाँच करोड़ रुपये कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि ऐसे छूट प्राप्त उद्योगों में यदि स्थायी सम्पत्तियों(भूमि, भवन, सयन्त्र आदि) में 5 करोड़ रुपये से अधिक के पूँजी निवेश का प्रस्ताव नहीं है, तो उन्हें इनके प्रावधानों से छूट प्राप्त होगी। किन्तुपहले से पजीकृत इकाइयों में यदि उनकी स्थायी सम्पत्तियों में 5 करोड़ या इससे अधिक का पूँजी निवेश है तो ऐसी छूट प्राप्त नहीं होगी। बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध अथवा विदेशी कम्पनियों से सम्बद्ध उत्पादक इकाइयों को भी छूट प्राप्त नहीं होगी।
  - (द) अधिनियम के प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों को अग्राकिततीन भागों में बॉटा जा सकता है—

<sup>2</sup> इकोनॉमिक सर्वे-1993-94,पृष्ठ संख्या- 93

<sup>3</sup> प्रतियागिता दर्पण-अतिरिक्ताक-1995, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा

- 1 <u>प्रतिबन्धात्मक प्रावधान —</u>इसके अन्तर्गत वे सभी प्रावधान आते है जिनके द्वारा उद्योगो की अवाछनीय प्रवृत्तियो पर रोक लगायी जाती है। ये प्रावधान निम्नलिखित है—
- 1 1 औद्योगिक प्रतिष्ठानों का रिजस्ट्रेशन तथा अनुज्ञापत्र अधिनियम की अनुसूची में जिन उद्योगों को रखा गया है, उनके सभी प्रतिष्ठानों का रिजस्ट्रेशन आवश्यक है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो अथवा सार्वजिनक क्षेत्र में। वर्तमान प्रतिष्ठान यदि विस्तार करना चाहे तो इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमित आवश्यक है। सरकार निजी अथवा सार्वजिनक क्षेत्र में स्थापित होने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापन करने के साथ—साथ उस पर आकार तथा स्थानीयकरण के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा सकती है। अनुज्ञापन दे देने के साथ ही केन्द्र सरकार को उसका संशोधन अथवा उसका निरसन करने का अधिकार रहता है। लाइसेन्स प्राप्त करने वाला यदि निर्धारिन समय के भीतर उद्योग स्थापित करने में असमर्थ रहता है या यदि उसने रिजस्ट्रेशन किसी झूठे आधार पर प्राप्त किया है, या उद्योग को भी रिजस्ट्रेशन से छूट प्रदान कर दी गई है तो अनुज्ञापत्र निरसन अथवा उसका संशोधन किया जा सकता है।

उद्योग (विकास एव नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगों के लिए अनुज्ञापन लेना आवश्यक है—

- 1 अधिनियम की अनुसूची में जिन उद्योगों का उल्लेख है, उनसे सम्बन्धित नवीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को यदि उसमें 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा उनकी स्थायी सम्पत्ति 5 करोड़ रूपये से अधिक की हो।
- 2 उपर्युक्त उद्योगो से सम्बन्धित विद्यमान प्रतिष्ठान यदि वह अपनी उत्पादन क्षमता को बढाना चाहे।
  - 3 विद्यमान उद्योग यदि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना चाहे।
  - 4 किसी विद्यमान औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपना स्थान परिवर्तित करना हो।
- 1 2 <u>अनुज्ञापन की प्रक्रिया</u> औद्योगिक प्रतिष्ठानो द्वारा अनुज्ञापन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रो की जाँच "डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्नीकल डेवेलपमेट " करता है। इस विभाग द्वारा उद्योगों की एक ऐसी सूची प्रकाशित की गयी है जिसमें उल्लिखित उद्योगों से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए आये हुए सभी आवेदन पत्र "अनुज्ञापन समिति" के पास भेजे बिना अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। अन्य उद्योगों से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर डायरेक्ट्रेट आफ टेक्नीकल डेवेलपमेट विचार करता है। भारत में उद्योगों का अनुज्ञापन प्रदान करने की व्यवस्था भारतीय उद्योगपितयों द्वारा निरन्तर आलोचना का विषय रही है। अत इस रीति को सरल बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए श्री स्वामीनाथन् की अध्यक्षता में एक सिमिति का गठन किया जिसने अनेक व्यवहारिक सुझाव देने के साथ—साथ इस बात पर जोर दिया कि अनुज्ञापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कम

समय में ही पूर्ण हो जानी चाहिए। सिमिति ने आधारभूत उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञापन के सम्बन्ध में विशेष विधि अपनाने की भी सिफारिश की। सरकार ने स्वामीनाथन् सिमिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। फलत अनुज्ञापन प्रणाली अब पहले की अपेक्षा सरल हो गयी है।

- 1 3 अनुसूचित उद्योगों की जाँच अधिनियम के अन्तर्गत सरकार का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठान विशेष के रिजिस्ट्रेशन अथवा उसे अनुज्ञापन प्रदान कर देने मात्र से पूरा नहीं होता। यदि किसी औद्योगिक इकाई का कार्यान्वयन असन्तोषजनक है, उत्पादन की किस्म खराब है, उत्पादन समुचित मात्रा में नहीं हो रहा है या उत्पादित माल की लागत एवं कीमत अनावश्यक रूप से अधिक है तो केन्द्रीय सरकार को उस प्रतिष्ठान की जाँच करने का अधिकार है। जाँच की अविध से सरकार प्रतिष्ठान विशेष को अन्तरिम निर्देश भी दे सकती है। जाँच द्वारा यदि सिद्ध होता है कि दोष औद्योगिक इकाई का ही है, तो केन्द्रीय सरकार उत्पादन की मात्रा, किस्म, कीमत उसके वितरण के सम्बन्ध में उचित निर्देश दे सकती है।
- 1 4 <u>अनुज्ञापन का निरस्तीकरण</u> किसी भी औद्योगिक इकाई का अनुज्ञापन केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 10(अ) के अन्तर्गत निरस्त कर सकती है। मिथ्यावर्णन के आधार पर प्राप्त किया जाने वाला अनुज्ञापन अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 2 सुधारात्मक प्रावधान इस अधिनियम मे दी गई व्यवस्थाओं का प्रयोजन उद्योगों में व्याप्त दोषों का उपचार करके उनमें सुधार लाकर अनुकूल दशाओं का निर्माण करना है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं—
- 2 1 सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रबन्ध एव नियन्त्रण की व्यवस्था(धारा—18) यह प्रावधान किया गया है कि निम्न दशाओं में केन्द्रीय सरकार किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण अपने हाथों में ले सकती है—
- 1 यदि कोई औद्योगिक इकाई सरकार द्वारा उसकी सचालन व्यवस्था के सुधार के लिए किये गये निर्देशों का परिपालन करने में विफल रहती है, अथवा
- 2 यदि किसी इकाई का प्रबन्ध उस उद्योग के हितों के विरुद्ध अथवा जनहित के विरुद्ध किया जा रहा है।

यदि सरकार जाँच करवाने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि निर्देशों की अवहेलना की जा रही है तो सरकार उस इकाई का प्रत्यक्ष प्रबन्ध व नियन्त्रण अपने हाथ में ले सकती है। किन्तु बिना औपचारिक जाँच के भी यदि प्रत्यक्षत केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो जाती है कि कोई उपक्रम सरकारी निर्देशों की अवहेलना कर रहा है अथवा उसका सचालन जनहित अथवा उद्योग के विरुद्ध किया जा रहा है तो उसका प्रबन्ध अपने हाथों में ले सकती है। ऐसा प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण सरकार द्वारा प्रथमत 5 वर्षों

तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है किन्तु बाद में ससद की अनुमित से इस अविध को दस वर्षी तक बढाया जा सकता है।

- 2 2 पूर्ति एव वितरण व्यवस्था तथा मूल्यो पर नियन्त्रण-धारा-18(जी) सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह एक विज्ञापित आदेश द्वारा अनुसूचित उद्योगो द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए समुचित पूर्ति एव वितरण तथा उनके उचित मूल्यो पर विक्रय की नियन्त्रण व्यवस्था कर सकती है। वितरण अथवा मूल्य नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था समान प्रकार की बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए भी की जायेगी। इस प्रकार की व्यवस्थाओं द्वारा निम्नलिखित प्रकार की दशाए सुनिश्चित की जा सकती है—
  - 1 किसी वस्तु के क्रय-विक्रय के लिए उसका मूल्य निर्घारित किया जा सकता है।
- 2 किसी वस्तु के वितरण को नियमित करने के प्रयोजन से लाइसेन्स अथवा 'परिमट' की व्यवस्था।
- 3 किसी उत्पादक अथवा सग्रहकर्ता को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह अपने माल को पूर्णत अथवा अशत किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या सस्था को ही बेचे।
  - 4 किसी वस्तु की बिक्री को पूर्णत बन्द किये जाने का आदेश दिया सकता है।
- 5 सम्बन्धित वस्तु के विषय में अन्य व्यापारिक एव वित्तीय व्यवहारों को नियमित किये जाने के आदेश दिये जा सकते हैं।

इन प्रावधानो के अन्तर्गत यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो न्यायलय मे ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।

- 3 <u>रचनात्मक प्रावधान</u> रचनात्मक व्यवस्थाओं के परिपालन के लिए ऐसे संस्थात्मक तन्त्र के निर्माण की आवश्यकता होती है जो सभी सम्बद्ध पक्षों को परस्पर विचार—विमर्श करने एव अपनी—अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सामान्य मच प्रदा कर सके। अत ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित संगठनो एव उपायों की आवश्यकता पड सकती है—
- 3 1 केन्द्रीय सलाहकार परिषद अनुसूचित उद्योगों के विकास एवं यिमन के विषय में तथा आवश्यकता पड़ने पर इस अधिनियम के प्रशासन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए और इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत तथ्यों एवं आकड़ों का सकलन तथा आवश्यक नियामवली का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। परिषद की सदस्यता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति चुने जाते हैं—
  - 1 अनुसूचित उद्योगों के औद्योगिक उपक्रमों के स्वामी।
  - 2 अनुसूचित उद्योगों के आद्योगिक उपक्रमों में सेवारत व्यक्ति।

- 3 अनुसूचित उद्योगो द्वारा उत्पादित या निर्मित वस्तुओ के उपभोक्ता।
- 4 प्रारम्भिक उत्पादनकर्ता सहित ऐसे अन्य वर्ग के व्यक्ति जिनका सलाहकार परिषद मे प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा उचित समझा जाय।
- 3 2 पुनरावलोकन उप-सिमिति यह सिमिति व्यवहार में केन्द्रीय सलाहकार परिषद की एक उप सिमिति के रूप में काम करती है। इस सिमिति का मुख्य कार्य उद्योगों को प्रदान किये गये अनुज्ञापत्रों के बारे में आवश्यक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके उनका पर्यवेक्षण करना है। यह उप सिमिति इस बात को देखती है कि समय-समय पर कितने लाइसेन्स प्राप्त किये गये, कितने लाइसेन्स अस्वीकृत किये गये, कितने लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये। यह सिमिति उन अनुज्ञापत्रों का भी पुनरावलोकन भी करती है जिन्हें सशोधित अथवा परिवर्तित किया गया है।
- 3 3 केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति यह केन्द्रीय सलाहकार परिषद का एक महत्वपूर्ण अग होती है जिसमें केन्द्रीय उद्योग मन्त्री पदेन अध्यक्ष होते है तथा 16 अन्य सदस्य होते है जिसके गठन का प्राथमिक उद्देश्य समय पर आवश्यकता होने पर किसी उद्योग की स्थिति के बारे मे पुनरावलोकन करना होता है।
- 3 4 विकास परिषदे अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों के विकास के लिए विकास परिषद की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। परिषद में सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा सम्बन्धित उद्योगों के उद्योगपितयों,श्रिमिकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य वर्गों के प्रतिनिधि रहते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध स्थापित होता है।

परिषदो का उद्देश्य -विकास परिषदो के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है-

- 1 पचवर्षीय योजना के समर्थन में देश के प्रयासो तथा साधनो को सुदृढ करना।
- 2 देश के समस्त कार्यों का सन्तुलित विकास करना।
- 3 समस्त महत्वपूर्ण, क्षेत्रो मे सामान्य अर्थनीतियो को बढावा देना आदि।

परिषदो का कार्य -विकास परिषदो के प्रमुख कार्य निम्नवत् है-

- 1 सम्बन्धित उद्योगो को तकनीकी सलाह देना,
- 2 केन्द्रीय सरकार के निर्णय तथा नीति से सम्बन्धित उद्योगो को परिचित कराना,
- अमिको के कार्य करने की दशाओ मे आवश्यक सुधार करना।
- 4 सम्बन्धित उद्योगो की जाँच करना तथा उनके सम्बन्ध मे केन्द्रीय सलाहकार परिषद की रिपोर्ट

<sup>4</sup> मरकेन्टाइल लॉ-शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-330

देना।

- 5 उद्योगो की अनार्थिक इकाइयो की कुशलता बढाना।
- 6 सम्बन्धित उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित करना, उत्पादन की योजनाओं में समन्वय स्थापित करना तथा उद्योगों की उन्नित के बारे में विचार करना।
  - 7 उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति में सहायता देना।
  - 8 हिसाब रखने की प्रणाली मे सुधार करना तथा उनको प्रमाणित करना।
- 9 उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में जाँच करना और उनसे सम्बन्धित छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योग धन्धों के विकास को प्रोत्साहित करना।
  - 10 औघोगिक मनोविज्ञान से सम्बन्धित विषयो की खोज करना।
  - 11 उपभोक्ता के लिए नियमित वस्तुओ तथा सेवाओ की खोज करना।
  - 12 वस्तुओ के प्रमापीकरण में सहायता देना।
  - 13 कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।
  - 14 उद्योगों के आकडे एकत्रित करना।
  - 15 उपभोक्ता के कल्याण के लिए विक्रय तथा वितरण की उचित प्रणाली व्यवहार मे लाना।
  - 16 उद्योग से निकले कर्मचारियो को प्रशिक्षण देकर अन्य जगह काम दिलाना।
- 17 सम्बन्धित उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबन्ध व विवेकीकरण के सिद्धान्तों को अपनाने के लिए उचित परामर्श देना।
- 3 5 <u>औद्योगिक पैनल</u> ऐसे उद्योगों में जहाँ विकास परिषद के गठन की आवश्यकता नहीं समझी जाती अथवा इसके गठन का कोई आचित्य नहीं होता वहाँ औद्योगिक पैनल नियुक्त किये जाते हैं। ऐसे पैनल में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ विशेषज्ञों को पैनल के सदस्य के रूप में नामाकन कर दिया जाता है। विशेषज्ञों के ये पैनल सम्बन्धित उद्योगों के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके उचित सुझाव देते हैं।
- 3 6 <u>आकडो का सकलन</u> अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार है किवह नियन्त्रित उद्योगों से उत्पादन आदि के सम्बन्ध में ऑकडे मॉग सकती है तािक अनुसूचित उद्योगों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस अधिनियम की धारा 30के अन्तर्गत वर्ष 1959-60 में सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों के लिए तथ्यों एव आकडों के सकलन के लिए नियमावली का निर्माण किया है जो अनुसूचित उद्योगों की भी सभी इकाइयों पर लागू होती है।
- 3 7 <u>कर की व्यवस्था</u> अनुसूचित उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुओ पर केन्द्रीय सरकार को 12, प्रतिशत कर लगाने का अधिकार होता है। कर की यह एकत्रित धनराशि विकास परिषद को सौप दी जाती

- है। जिसे निम्न कार्यों पर व्यय किया जाता है।
  - 1 प्रशासनिक व्ययो को पूरा करने के लिए।
  - 2 वस्तुओं की डिजाइन तथा किस्म में सुधार के लिए।
  - 3 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंघान में वृद्धि करने के लिए।
  - 4 तकनीकी तथा श्रमिको के प्रशिक्षण के लिए।
- (य) दण्ड का प्रावधान यदि कोई व्यक्ति अपने उपक्रम का पजीकरण नहीं कराता है या कोई नया उपक्रम लाइसेन्स नहीं लेता है या वस्तु के वितरण पूर्ति एव मूल्य सम्बन्धी दिये गये आदेशों का पालन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की सजा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनो दिये जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेश की अवहेलना करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिदिन तब तक जुर्माना किया जा सकता है जब तक कि वह आदेशों की पूर्ति न कर दे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्योगिक ( विकास एव नियमन) अधिनियम न केवल औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण अग है बल्कि इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के हाथों में यह एक प्रभावपूर्ण अस्त्र भी है। अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके राज्य हमारे देश के औद्योगिक विकास को उचित एव नई दिशा प्रदान कर सकता है तथा इस प्रकार निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योगों को राष्ट्र की व्यापक सामाजिक आर्थिक नीति के अनुरूप सचालित किये जाने के लिए विवश भी कर सकता है।

- (र) <u>अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्याकन</u> अधिनियम के प्रावधानो के सम्बन्ध में प्राय निम्नलिखित आलोचनाए की जाती है—
- 1 <u>आवश्यकता से अधिक सरकारी मियन्त्रण</u> अधिनियम की व्यवस्थाए अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण को बढावा देती है जिससे कि निजी क्षेत्र के उद्यमों का पर्याप्त विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। फलत , देश के औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किन्तु आर्थिक नियोजन तथा नियन्त्रण आज के युग में आवश्यक है। नियन्त्रण के अभाव में नियोजन सफल नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र का विकास, स्पष्ट रूप से तीव्र हुआ है।
- 2 निषेधात्मक कदम इस अधिनियम के प्रावधान सविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता अथवा व्यवसाय एव रोजगार की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। जबिक वस्तुस्थिति यह नही है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगीकरण की समस्याओं को दूर करना तथा सामान्य जनता के कल्याण में वृद्धि करना है।अत यदि सामान्य आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता कुछ सीमा तक प्रभावित होती है तो समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए ऐसा करना .

उपयुक्त ही होगा।

- 3 <u>राजकीय पूँजीवाद को प्रोत्साहन</u> यह कहा जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत, लोक उद्यमों को कुछ छूटे प्रदान की गई है जिससे राजकीय पूँजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसका परिणाम यह भी है कि आर्थिक ससाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। लेकिन देश के तीव्र आर्थिक विकास तथा सामाजिक आर्थिक जनकल्याण में वृद्धि के लिए लोक उद्यमों को प्रोत्साहन देना ही होगा। इससे आर्थिक शक्तियों के सकेन्द्रण को रोकने में भी मदद मिलेगी।
- ' बड़े औद्योगिक घरानो एव एकाधिकारो में वृद्धि कुछ लोग इस अधिनियम के प्रावधानो की आलोचना इस आधार पर भी करते है कि इसके अन्तर्गत लाइसेन्सनीति के दुरुपयोग की हर तरह से सम्भावना है। व्यवहार में, यह पाया गया है कि नये उद्यमियों को लाइसेन्स प्राप्त करने में जितनी अधिक कठिनाई होती है, पुराने तथा बड़े औद्योगिक घरानों को उतनी ही अधिक सुविधा मिलती है। फलस्वरूप देश में बड़े औद्योगिक घरानों तथा एकाधिकारों की स्थापना उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। इस प्रकार की आलोचना अपेक्षाकृत अधिक ठोस है तथा हजारी आयोग एवं दत्ता समिति ने इसआश्रय का समर्थन भी किया है।

उपर्युक्त आलोचनाओं के उपरान्त भी यह अधिनियम भारत के नियोजित आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों में जहाँ एक ओर सरकार को असीमित नियन्त्रण एव समुचित नियमन का अधिकार दिया है वही दूसरी ओर प्रादेशिक असन्तुलन तथा उद्योगों के असन्तुलित विकास को भी कम करने में सफलता प्राप्त की है। देश के सीमित आर्थिक ससाधनों के उचित तथा उपयुक्त उपयोग करने में इस अधिनियम का अपना एक अलग महत्व है। यह अधिनियम व्यावहारिक दृष्टि से, भारत के उद्योगों के लिए एक आदर्श आचार सिहता प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ देश के औद्योगिक नीति का कुशलता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का एक उचित माध्यम भी है।

## (ख) अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-1952 -

अग्रिम सौदो के नियमन के लिए अग्रिम अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम-1952 देश में लागू हैं। इसका उद्देश्य उन अग्रिम सौदो पर प्रतिबन्ध लगाना है जो जनहित के विरुद्ध है। भारत में अग्रिम व्यापार(भविष्य व्यापार) 19वी शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हो गया था , लेकिन उसके नियमन का कार्य व्यापारिक सघो द्वारा स्वय निधारित नियमों के द्वारा किया जाता था। सर्वप्रथम बम्बई राज्य में 1918 में रुई के व्यापार के नियमन हेतु सर गिलवर्ट बाइल्स की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसे रुई प्रसविदा समिति का नाम दिया गया, 1919 में इसके स्थान पर कॉटन प्रसविदा बोर्ड तथा बाम्बे काटन अनुबन्ध नियन्त्रण अधिनियम बनाया गया।

सविधान बन जाने पर स्कन्ध विनिमय व अग्रिम बाजार का विषय केन्द्र की सूची मे शामिल कर लिया नया। केन्द्रीय सरकार ने एक बिल फरवरी,1950 में बनाकर राज्य सरकारो, रिजर्व बैक आफ इण्डिया, चैम्बर आफ कामर्स व अन्य सम्बन्धित हितों को अपनी राय देने के लिए भेजा जिसके आधार पर जुलाई, 1950 में यह बिल एक विशेषज्ञ समिति को सौप दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष श्री ए डी श्रोफ थे। इस समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए एक विधेयक 19 दिसम्बर, 1950 में अस्थायी ससद को सुपुर्द कर दिया गया जिसने अपना प्रतिवेदन 9 अगस्त-1951 को प्रस्तुत कर दिया। यह विधेयक बाद में इस अस्थायी ससद के समक्ष विचारणार्थ न आ सका और ससद समाप्त हो गयी। अत 1952 में एक नया विधेयक प्रथम ससद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो अन्त में दिसम्बर 1952 में ससद द्वारा अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम के नाम से पारित कर दिया गया। इस विधान में यह व्यवस्था थी कि जिस समय किसी पदार्थ या स्थान पर यह विधान लागू होगा तो अन्य अधिनियम स्वत खण्डित हो जायेगे। इस अधिनियम में वर्ष 1953, 57 व 66 में सशोधन किये गये हैं। इस सशोधित अधिनियम में कुल 28 धाराये हैं। इस अधिनियम की प्रमुख बाते निम्नवत् हैं—

(अ) <u>अधिनियम का क्षेत्र एव उद्देश्य</u> प्रस्तुत अधिनियम ऐसे सभी तैयारी वायदे तथा भावी अनुबन्धो पर लागू होता है जो कि हस्तन्तरणीय प्रकृति के हो। अहस्तन्तरणीय तत्काल अनुबन्धो पर यह अधिनियम लागू नही होता है।

इस अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- 1 यह अधिनियम वस्तुओं के वैकल्पिक सौदो पर प्रतिबन्ध लगाता है।
- 2 सामान्यतया यह अधिनियम सुरक्षात्मक तथा भावी सौदो पर लागू होता है किन्तु हस्तन्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी अनुबन्धो को भी अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है। इस प्रकार यह हस्तन्तरणीय निश्चित सुपुर्दगी के अनुबन्धो पर रोक लगाता है।
- 3 यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित वस्तुओ तथा क्षेत्रों में अग्रिम अनुबन्धों के नियमन का अधिकार रखता है।

वर्ष 1960 मे इस अधिनियम मे सशोधन के निम्नलिखित उद्देश्य थे-

- 1 अग्रिम बाजार पर कडे प्रतिबन्ध लगाना,
- 2 अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने पर भारी संजा देने की व्यवस्था,
- 3 व्यापार सघ के कार्य करने के समय के अतिरिक्त समयो में व्यावहारों को रोकना, तथा
- 4 गत वर्षों मे अधिनियम के लागू होने के अनुभव मे सामने आयी कठिनाईयो को दूर करना तथा केन्द्रीय सरकार व अग्रिम बाजार आयोग को अग्रिम व्यवहारों के सम्बन्ध में नियन्त्रण के लिए अधिक अधिकार देना था।
- (ब) वस्तु या उपज विपिषयों को मान्यता इसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम विपिष आयोग की स्थापना 2 सितम्बर-1980 में की गई। इस अग्रिम विपिष आयोग की सिफारिश पर ही केन्द्रीय

सरकार किसी उपज विपणि को मान्यता प्रदान करती है। अधिनियमानुसार केवल मान्यता प्राप्त उपज विपणियो पर ही वायदे के सौदे किये जा सकते है।

- (स) केन्द्रीय सरकार का प्रशासन समिति में हस्तक्षेप केन्द्रीय सरकार को उपज विपणि के प्रशासन समिति में अधिक से अधिक 4 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त वह उपज विपणि को उसकी प्रशासन समिति में अधिक से अधिक तीन बाहरी प्रतिनिधियों को भी नियुक्त करने का आदेश दें सकती है।
- (द) केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार अग्रिम विपणि आयोग के माध्यम से किसी भी मान्यता प्राप्त उपज विपणियों के नियमों तथा उपनियमों में परिवर्तन कर सकती है, मान्यता वापस ले सकती है, प्रतिबन्ध लगा सकती है, कार्यों को करने से रोक सकती है तथा उसकी प्रशासन समिति को भग कर सकती है।
- (य) <u>वैकल्पिक व्यवहारो पर रोक</u> यह अधिनियम 'वैकल्पिक', डब्बा सौदो, कर्व ट्रेडिंग तथा सभी अवाछनीय व्यवहारो पर पूर्ण रूप से रोक लगाता है।
- (र) दण्ड का प्रावधान यदि कोई व्यक्ति अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है तो वह दण्ड का भागी होगा। जैसे विपणि आयोग को गलत सूचनाए भेजना, निर्धारित मात्रा से अधिक व्यवसाय करना आदि। प्रथम अपराध की दशा में , 4000रुपये तक का आर्थिक दण्ड अथवा एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनो प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं। अपराधों की पुनरावृत्ति पर और अधिक दण्ड दिये जाने का प्रावधान है।
- (ल) <u>उपज विपिष की क्रियाओ पर नियन्त्रण</u> प्रस्तुत अधिनियम उपज विपिषयो की क्रियाओ पर निम्न रूप में नियन्त्रण स्थापित करता है—
  - 1 अमान्यता प्राप्त उपज विपणियो को कार्य करने की अनुमति नही है।
  - 2 नाप-तौल तथा दलाली की प्रमापित दरे लागू कर दी गई है।
  - 3 माल की सुपूर्वगी एव भुगतान के सम्बन्ध में नियम बना दिये गये है।
- 4 नीलामी अथवा वास्तविक व्यवहारो द्वारा किये गये विक्रयो की चाहे जब जॉच की जा सकती है।
  - 5 आपसी विवादो का निपटारा पच निर्णय द्वारा करने की व्यवस्था की गई है।
  - 6 भावों में अत्यधिक उतार-चढाव को रोकने की व्यवस्था की गयी है।
- मार्जिन के रूप मे भारी धनराशि जमा करने की व्यवस्था है ताकि सट्टे की प्रवृत्ति को रोका जा सके।
  - 8 अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने पर अनेक प्रकार के दण्डो की व्यवस्था की गई है।

- 9 समाशोधन गृह की व्यवस्था की गई है।
- 10 वस्तुओं की श्रेणियों को निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।
- 11 बाजार के भावों को निश्चित करने का भी अधिकार है।
- (व) अग्रिम विपणि आयोग अग्रिम विपणि आयोग की स्थापना 22 सितम्बर 1953 को की गई। इस का मुख्य कार्यालय बम्बई में हैं। इस समय इस आयोग में एक सभापित और पूर्ण-कालिक सदस्य है। यह अधिनियम 26 जनवरी, 1955 को समाप्त होने को था, किन्तु 25 जनवरी, 1955 को इस अधिनियम के अधीन विज्ञप्ति नेकालकर उन पदार्थों के अग्रिम व्यापार पर रोक ज़ारी रखी गयी जो पूर्व के आवश्यक पूर्ति अधिनियम—1946 के अन्तर्गत अनुसूचित 33 पदार्थ थे।
- 1 <u>आयोग के कार्य</u> आयोग के कार्य सलाहकारी एव कार्यकारी दोनो तरह के होते है। यह केन्द्र सरकार को अधिनियम लागू करने के बारे में सलाह देता है। इसको मान्यता प्राप्त सघो को आदेश देने का अधिकार है। आयोग के प्रमुख कार्य निम्न है—<sup>5</sup>
- मान्यता-प्राप्त सघो को मान्यता देने, वापस लेने या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध के अन्तर्गत उठे किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।
- 2 अग्रिम विपणि का अवलोकन करते रहना व अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध मे उचित कार्यवाही करना।
  - 3 सूचनाओं को एकत्रित करना व प्रकाशित करना।
  - 4 विपणि बाजारों के संगठन व कार्यप्रणाली की उन्निति के बारे में सरकार को सिफारिश करना।
  - 5 किसी मान्यता-प्राप्त या पजीकृत सस्था की बही खातो व अन्य प्रपत्रो को देखना।
  - 6 उन कर्तव्यो को पूरा करना जो इस अधिनियम में दिये है या दिये जाए।
- 2 <u>आयोग के अधिकार</u> आयोग को सिविल प्रोसीजर अधिनियम 1908 के अन्तर्गत वे सभी अधिकार प्राप्त है जो एक अदालत को होते हैं। भारतीय दण्ड विधान की धारा 176 के अनुसार आयोग को किसी भी व्यक्ति को सूचना देने के लिए बाध्य करने का अधिकार है। जब कोई अपराध भारतीय दण्ड विधान की धारा 175,178,179,180 या 288 के अन्तर्गत आता है तो आयोग ऐसे अपराधों को किसी मजिस्ट्रेट को सौप सकता है। (धारा-4-ए)
  - 3 आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा सौपे गये अधिकार ये अधिकार निम्नवत् है—
  - 1 मान्यता प्राप्त सघो के सदस्यों की संख्या को सीमित या असीमित करना,
  - 2 सघो के नियमों में परिवर्तन करना,
  - 3 प्रत्येक सघ व उसके सदस्यों के लिए नक्शों की व्यवस्था करना,

<sup>5</sup> राज्य एव व्यवसाय-जगदीश प्रकाश, कक्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद-1991, पृ स 339

- 4 किसी सघ से उसके क्रिया-कलापो के बारे में स्पष्टीकरण मॉगना,
- 5 किसी सघ या सघ के सदस्यों की जाँच करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करना,
- 6 अधिनियम के नियमों में परिवर्तन करना या नये नियम बनाना,
- 7 किसी सघ के व्यापार को निलम्बित करना,
- 8 किसी पजीकृत सघ व उसके सदस्यों के लिए नक्शों की व्यवस्था करना।
- 4 <u>आयोग की क्रियाए</u> आयोग के प्रारम्भिक कुछ महीने स्थान, कर्मचारी व सगठन आदि की समस्याओं में व्यतीत हुए। आयोग ने सर्वप्रथम अधिनियम के नियम अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम के नाम से बनाये जिनकों केन्द्रीय सरकार ने जुलाई—1954 में स्वीकृति दे दी। आयोग ने अपना कार्य विभिन्न पदार्थों के बारे में सरकार को प्रतिवदेन देने से प्रारम्भ किया। इसने पहला प्रतिवदेन रूई के बारे में सरकार को दिया जिसे सरकार ने मान लिया। अत 30 अप्रैल—1954 को धारा 15 के अन्तर्गत, एक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसके अनुसार दि ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोशियेशन, बम्बई के नियमन का अधिकार बम्बई सरकार से हटकर आयोग के पास आ गया। तब से आयोग बराबर अग्रिम अनुबन्धों को नियमित कर रहा है। आयोग चुने हुए केन्दो एव मान्यता—प्राप्त संघों के माध्यम से भविष्य बाजार का नियमन करता है तथा विपणियों पर अत्यधिक मूल्य—वृद्धि तथा अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति होने पर इन्हें रोकने का प्रयत्न करता है।
- 5 अग्रिम विपणि आयोग के कार्यकारी खण्ड आयोग मे तीन कार्यकारी खण्ड है—वस्तु खण्ड, एनफोर्समेण्ट खण्ड एव प्रशासनिक खण्ड। इस समय 5 वस्तुओं मे अग्रिम व्यवहार धारा—15 के अन्तर्गत नियमित किये जाते हैं। ये वस्तुए हैं— पटसन एव टाट, अलसी, अरण्डी, काली मिर्च तथा हल्दी। वर्तमान समय मे देश मे 111 रिजस्टर्ड व 33 मान्यताप्राप्त सघ है। मान्यता—प्राप्त सघो मे ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन लिमिटेड बम्बई, ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेज लिमिटेड, कलकत्ता प्रमुख है। बहुत से सघ एक से अधिक पदार्थों के लिए मान्यता प्राप्त है। आयोग समय—समय पर मान्यता प्राप्त सघो के बारे मे अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। भारत वर्ष के प्रमुख वस्तु बाजार है— बम्बई कपास बाजार, बम्बई सर्राफा बाजार, बम्बई बिनौला बाजार, कलकत्ता जूट बाजार, कलकत्ता चाय बाजार, कलकत्ता चावल बाजार, हापुड गेहूँ बाजार, खुर्जा घी बाजार, दिल्ली उत्पादन बाजार।

आर्थिक उदारीकण के वर्तमान सन्दर्भों मे पुन उपज विपणि के कार्यों की समीक्षा करने तथा उसे प्रभावशाली बनाने के लिए एक सिमिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमे आर्थिक विशेषज्ञो, उपज विपणियों के सदस्यों एवं दलालों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे इस अधिनियम को बाजार एवं समाज के लिए अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाया जा सके।

## (ग) खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम-1954 -

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र मे व्याप्त बुराइयो को दूर करना तथा व्यापारियो व उत्पादको द्वारा खाद्य पदार्थों मे अपिमश्रण को रोकना एव जनता को शुद्ध खाद्य वस्तुए उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-

- (अ) कुछ वस्तुओं के बनाने व बेचने पर रोक धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो ऐसी वस्तु बनायेगा न बेचेगा, न सग्रह करेगा और न वितरित करेगा जो—(अ) कोई अपमिश्रित खाद्य पदार्थ हो, (ब) कोई धोखे वाली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ हो, (स) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री पर खाद्य अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई हो, (द) कोई अपमिश्रित वस्तु हो, (य) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री के लिए कोई लाइसेन्स लेना आवश्यक है।
- (ब) कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक धारा 5 के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगा दी गई है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति अग्रलिखित खाद्य पदार्थों का आयात नहीं करेगा— अपिमिश्रित खाद्य पदार्थ, कोई धोखे या नकली ब्राण्ड का खाद्य पदार्थ, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके आयात के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है, कोई खाद्य पदार्थ जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हो।
- (स) खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके खियार केन्द्रीय व राज्य सरकारे गजट में प्रकाशन के बाद खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है जिनकों यह अधिकार होगा कि वे किसी भी ऐसे विक्रेता या व्यक्तियों से जो वस्तु को दे रहा हो, नमूना ले सकते हैं। इस कार्य के लिए खाद्य निरीक्षक जहाँ देशी वस्तुए बन रही हो या सग्रह की गयी हो, या रखी गयी हो, देख सकता है और ऐसी वस्तुओं का नमूना वस्तु का सामान्य मूल्य देकर प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही वह पुस्तकों व किताबों को भी अपने अधिकार में ले सकता है। नमूना लेते समय उसकी मात्रा का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जो दूध के लिए 200 मिलीमीटर, घी व मक्खन 150 ग्राम, चाय 125 ग्राम आदि के बराबर होना चाहिए।
- (द) नमूने का विश्लेषण एवं मुकदमा खाद्य निरीक्षक द्वारा लिये गये नमूने को जन विश्लेषक को भेजा जायेगा जिसकी नियुक्ति केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। यह विश्लेषक निर्धारित फार्म पर अपनी रिपोर्ट देगा। यदि रिपोर्ट में वह पाता है कि वस्तु अपमिश्रित है तो उचित न्यायालय में मुकदमा द्वायर किया जायेगा। न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माना जो एक हजार रुपये कम नहीं होगा, किया जा सकता है। इसकी सजा को बढ़ाकर तीन वर्ष तक भी किया जा सकता है। कुछ मामलों में कम से कम तीन माह की सजा, जिसको 2 वर्ष तक भी किया जा सकता है तथा कम से कम 500 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जाय तो मुकदमें सरसरी तौर से भी सुने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को एक वर्ष तक की सजा देने का अधिकार होगा।

### (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 -

भारत सुरक्षा नियमो के अन्तर्गत सर्वप्रथम 1939 में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे जो 30 सितम्बर-1946 तक लागू रहे। इन प्रतिबन्धों को लागू रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से इनको जारी रखा और इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक पूर्ति(अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1946 ने ले लिया। इस अधिनियम का जीवन केवल 1 अप्रैल, 1947 तक सीमित था लेकिन समय-समय पर इसका कार्यकाल बढाया जाता रहा जो अन्त में 26 जनवरी, 1955 को समाप्त हो गया। लेकिन इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए फिर एक अध्यादेश जारी कर सरकार ने उन सभी अधिकारों को पुन प्राप्त कर लिया। इस अध्यादेश का स्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ने ले लिया। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1955 से लागू किया गया। प्रारम्भ में यह अधिनियम अस्थायी था और केवल दो वर्षों के लिए लागू किया गया था लेकिन बाद में इसको स्थायी बना दिया गया।

- (अ) अधिनियम का क्षेत्र एव उद्देश्य यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोडकर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है। इसकी धारा 3(1) में इसके उद्देश्य एवं नीतियों को दर्शाया गया है। इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की राय में यह जरूरी है कि किसी वस्तु की पूर्ति बनाये रखी जाय या बढायी जाय या समान वितरण करने के लिए उचित मूल्य पर वस्तुए उपलब्ध बनी रहे या भारत की सुरक्षा के लिए या सैनिक कार्यवाही को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करना आवश्यक है तो एक आदेश से ऐसी वस्तु के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण और उसके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा सकती है या उसका नियमन कर सकती है। इसमे समान वितरण और उचित मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जनहित में किसी वस्तु के उचित मूल्य पर समान वितरण की आवश्यकता है तो सरकार अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है।
- (ब) <u>आवश्यक क्स्तुए</u> वे वस्तुए जिनका प्रयोग मानव जीवन मे आवश्यक है, उनको इस अधिनियम मे वस्तुए बताया गया है। अधिनियम की धारा 2(ए) के अनुसार निम्न क्स्तुए इसके अन्तर्गत आती है-

1 जानवरों के खाने वाला चारा जिसमें खल व अन्य शामिल है, 2 कोयला, 3 सूती एवं ऊनी कपड़े, 4 खाद्य पदार्थ(तिलहन एवं तेल सिहत),5 कागज(न्यूजप्रिट एवं गत्ता सिहत), 6 लोहा एवं इस्पात(इसकी बनी हुई वस्तुओं सिहत), 7 पैट्रोलियम एवं इसके पदार्थ, 8 कच्ची रूई एवं बिनौले, 9 कच्चा जूट, 10 मोटर गाडियों के पुर्जे एवं अन्य सहायक सामान, 11 दवाइयाँ, 12 अन्य कोई वस्तु जिसकों केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है तो एक आदेश जारी कर उसकों भी आवश्यक वस्तु मान सकती है। भूतपूर्व नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक मन्त्री श्री ए के एटनी ने आर्थिक

सम्पादको के सम्मेलन में बताया है कि आवश्यक वस्तु कानून को अगले 5 वर्षों तक बढाने पर सभी राज्यों ने आम सहमित व्यक्त की है, जिसकी अविध इसी वर्ष समाप्त हो रही थी। उन्होंने बताया कि इस सूची में पहले 67 वस्तुए थी, परन्तु समीक्षा कर उसमें से 23 वस्तुए हटा दी गयी है। 6

आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सीमा से जुलाई 1994 मे 15 अन्य वस्तुओं को बाहर कर दिया गया। इससे पूर्व 8 वस्तुओं को दिसम्बर-1993 में बाहर किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम में केवल 44 वस्तुए रह गयी है। जिन 15 वस्तुओं को इस अधिनियम की व्यवस्था से मुक्त किया गया है वे है- अलौह धातुए तथा इनके उत्पाद, साबुन, माचिस, शुष्क सेल, लालटेन, बसो एव ट्रकों के टायर-ट्यूब, खिनज तेल, पावर थ्रेसर, प्राकृतिक गैस, पशु चालित गाडी के टायर ट्यूब। सरकारी सूत्रों के अनुसार इन वस्तुओं के सम्बन्ध में उपलब्धता तथा मूल्य सम्बन्धी अब कोई समस्या नहीं रह गयी है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन अब राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, यद्यपि पुन समीक्षा जारी है। 7

- (स) केन्द्रीय सरकार के अधिकार केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन, पूर्ति एव वितरण आदि के सम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न में से कोई भी आदेश पारित कर सकती है—
- 1 किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण को लाइसेन्स या परिमट या अन्य किसी प्रकार से नियमित करना।
  - 2 किसी भूमि पर खाद्य फसलो या अन्य प्रकार के फसलो की खेती करना।
  - 3 आवश्यक वस्तु के क्रय विक्रय का मूल्य निर्धारित कर उसका मूल्य नियन्त्रित करना।
- 4 किसी आवश्यक वस्तु का भण्डारण,परिवहन,वितरण, बिक्री प्राप्त करना, काम में लाना या उपभोग को लाइसेन्स, परिमट या अन्य प्रकार से नियमित करना।
  - 5 किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री को रोकने के लिए आदेश देना।
- 6 किसी भी व्यक्ति को आदेश देना कि वह अपना स्टॉक या उत्पादन या प्राप्ति या भावी उत्पादन पूरा या उसका कोई भाग केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार या इन सरकारों के पतिनिधियों को सौप दे।
- 7 जनिहत में खाद्य-पदार्थ या सूती वस्त्र से सम्बन्धित आर्थिक या वाणिज्यिक सौदे पर रोक लगाना या उनका नियमन करना।
- 8 नियमन करने के उद्देश्य से उपर्युक्त वर्णित किसी भी मद से सम्बन्धित सूचनाए या आकडे एकत्रित करना।

<sup>6</sup> दैनिक जागरण- वाराणसी, 23 सितम्बर, 1994

<sup>7</sup> प्रतियोगिता दर्पण- सितम्बर, 1944,स्वदेशी बीमा नगर,आगरा

- 9 किसी भी व्यक्ति की जो किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, पूर्ति या वितरण मे लगा हो, पुस्तके रखने एव उनका अवलोकन करने और सूचनाओं को देने के लिए कहना।<sup>8</sup>
- 10 किस भी मकान, जहाज, मोटर वाहन, जानवर की तलाशी लेना और उनको अपने अधिकार में लेना।
- (य) <u>दण्ड का प्रावधान</u> यदि कोई व्यक्ति पूर्व वर्णित(8 व 9) के सम्बन्ध में आदेशे की अवहेलना करता है तो उसको एक वर्ष तक की सजा एव जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों की अवहेलना करने पर कम से कम तीन माह की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा व जुर्माना भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति झूठे बयान या सूचनाए देता है तो उसे 5 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनो दण्ड दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के उल्लंधन में लगी कोई भी सम्पत्ति सरकार जब्त कर सकती है।
- (६) सरसरी तौर पर जॉन का अधिकार इस अधिनियम की धारा 12(ए) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी राय में ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि उत्पादन, पूर्ति या वितरण के हित में सरसरी तौर पर(समरी ट्रायल) आवश्यक है तो वह इस आश्रय की एक अधि सूचना जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति में इन अधिकारों का उपयोग एक प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा जिसको एक वर्ष तक की सजा देने का अधिकार होगा। लेकिन यदि न्यायाधीय यह समझते है कि मामला इस प्रकार का है कि दण्ड एक वर्ष से अधिक अवधि का है तो वे मामले को सुनकर ऐसा आदेश दे सकते है, तदुपरान्त किसी भी गवाह को सुनने या पुन सुनने के लिए नियमानुसार कार्य कर सकते है।

यदि न्यायाधीश सरसरी तौर पर किसी मामले की सुनवाई करके एक महीने से अधिक की सजा या दो हजार रुपये से अधिक जुर्माना या दोनो नहीं देते हैं तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।

## (ड) प्रतिभृति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-1956 -

गोरवाला कमेटी के सुझावो पर दिसम्बर, 1954 में प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) बिल प्रस्तुत किया गया। कमेटी ने कुछ बातो पर सरकार को अपनी इच्छानुसार कार्य करने का सुझाव दिया था, जिससे लोक सभा में नवम्बर, 1955 में बिल को ससद की सयुक्त समिति को सौपने का प्रस्ताव किया गया था तथा राज्य सभा ने दिसम्बर में इसका अनुमोदन किया। विभिन्न सशोधनों के पश्चात् 4 सितम्बर, 1956 को दोनो सदनो द्वारा पास किये गये बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर अधिनियम को स्थान मिल गया। इस प्रकार यह अधिनियम 20 फरवरी, 1957 से चलन में आया?

<sup>8</sup> विशम्भर दयाल, चन्द्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश, ए आई आर -1980

<sup>9</sup> व्यावसायिक सगठन प्रबन्ध एव प्रशासन—अग्रवाल, आर सी एव ए एन , नवयुग साहित्य सदन, आगरा, पृ स 6 34

इस अधिनियम की मुख्य बाते इस प्रकार है-

- (अ) अधिनियम का उद्देश्य इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नवत् है-
- 1 भारत में स्कन्ध विपणि के नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करना।
- 2 देश के विभिन्न स्कन्ध विपणियों के नियमों एव उपनियमों में पर्याप्त समरूपता प्रदान करना।
- 3 इनके निर्देशित एव स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करना।
- 4 विनियोजको के हितो की रक्षा करना।
- 5 स्कन्ध विपणि में होने वाले अनावश्यक सट्टेबाजी तथा अनुचित क्रियाकलापों को रोकना। 10
- (ब) अधिनियम का लागू होना अधिनियम हाजिर सौदो के अलावा अन्य सौदो पर भी लागू होता है। हाजिर सौदो का अर्थ ऐसे अनुबन्ध से हैं जिसके द्वारा प्रतिभूति तथा उसके मूल्य का भुगतान या तो उसी दिन हो जाय अथवा अनुबन्ध के दूसरे दिन। यदि मूल्य का भुगतान डाक द्वारा करना है तो उपर्युक्त समय का हिसाब लगाकर डाक वाले दिन का उचित समायोजन किया जायेगा। अन्य सभी अनुबन्ध 'भावी सुपुर्दगी के अनुबन्ध' कहलाते है। मुख्यतया अधिनियम के प्रावधान तुरन्त सुपुर्दगी वाले लेनदेनो को छोडकर अन्य समस्त लेन—देनो पर लागू होते है।
- (स) स्कन्ध विपणियों को मान्यता देना कोई भी स्कन्ध विपणि बिना केन्द्रीय सरकार की मान्यता के कार्य नहीं कर सकती है ओर न ही बिना उसकी अनुमित के स्थापित ही की जा सकती है। धारा—9 के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक विपणि को एक निर्दिष्ट प्रारूप पर केन्द्र सरकार को आवेदन देना पडता है।इस आवेदन पत्र के साथ उपनियमों की एक प्रतिलिपि भी देनी पडती है। केन्द्रीय सरकार आवश्यक जाँच पडताल के बाद, यदि सन्तुश्टि हो जाती है तो उस विपणि को मान्यता प्रदान कर सकती है। सरकार मान्यता प्रदान करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखती हैं—
  - 1 विपणि के नियम या उपनियम ऐसे है जिनसे विनियोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार होगा।
  - 2 विपणि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने के लिए तैयार है।
  - 3 विपणि मे केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व।
  - 4 सदस्यो की योग्यता, और
  - सदस्यो द्वारा हिसाब-िकताब रखना व उनका अकेक्षण।

केन्द्रीय सरकार मान्यता प्रदान करते समय उक्त बातो से सम्बन्धित अपनी शर्ते भी लगा सकती है। वर्तमान समय मे 16 स्कन्ध विपणियों केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसमे 8 को स्थायी तथा शेष 8 को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है। अस्थायी मान्यता, प्रथमत 5 वर्ष के लिए दी जाती है। इसके अतिरिक्त गगटोक(सिक्किम) राजकोट(गुजरात) तथा मेरठ(उ०प्र०) मे भी स्कन्ध विपणि की स्थापना

<sup>10</sup> राज्य एव व्यवसाय-जगदीश प्रकाश, कक्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद-1991,पृ स-322

विचाराधीन है। जिन स्थानो पर ऐसी विपणियाँ नहीं है वहाँ सेक्यूरिटी डीलर्स को अनुज्ञापत्र दिये जाते हैं जिन्हें निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य करना होता है। 11

- (द) सदस्यता नियम 8 के अनुसार निम्न व्यक्ति किसी विपणि के सदस्य नहीं हो सकते हैं -
- 1 जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है,
- 2 जो भारत के नागरिक नही है,
- 3 जो दिवालिया है या दिवालिया घोषित किये जा चुके है,
- 4 जिन्हाने अपने लेनदारों को पूरा धन नहीं चुकाया है,
- 5 जो बेईमानी या धोखा देही के लिए अदालत द्वारा सजा प्राप्त है,
- 6 जो प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यापार में या तो प्रधान है, या कर्माचारी है,
- 7 वे व्यक्ति जो किसी ऐसी सस्था से सम्बन्धित है जो प्रतिभूतियों में व्यापार करती है या वे ऐसी कम्पनी के सचालक, साझेदार या कर्मचारी है,
  - 8 ऐसे व्यक्ति जो किसी विपणि से निकाल दिये गये है अथवा जो दोषी करार दिये गये है,
- 9 जिनकी सदस्यता का प्रार्थना पत्र मन्जूर न किया गया हो और दुबारा प्रार्थना पत्र देने तक एक वर्ष का समय न समाप्त हुआ हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रार्थी को निम्न शर्तों में से एक शर्त को पूरा करना होगा-

- 1 उसने कम से कम दो वर्ष के लिए किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य किया हो, या
- 2 वह कम से कम दो वर्ष के लिए किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य करना स्वीकार करे और स्कन्ध विपणि मे अनुबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति के नाम करे, या
- 3 उसने अपने किसी निकट सम्बन्धी का स्थापित व्यापार उत्तराधिकार से प्राप्त किया हो। यदि प्रशासन समिति की राय मे प्रार्थी एक साधन सम्पन्न एव अनुभवी व्यक्ति है तो इस शर्त को पूरा करना आवश्यक न होगा।
- (य) सामयिक विवरण भेजना प्रत्येक मान्यता—प्राप्त स्कन्ध विपणि के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्रिया कलापो पर सामयिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार के पास समय—समय पर प्रस्तुत करता रहे। उसके साथ—साथ केन्द्रीय सरकार को भी अधिकार दिया गया है कि वह मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि अथवा सदस्यों से वह समस्त सूचनाए मॉग सकती है जो कि उनके क्रिया कलाप के सम्बन्ध में आवश्यक हो। धारा6 के अनुसार सरकार मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि या उसके सदस्यों के क्रियाकलापों के बारे में जॉच के लिए एक या दो जॉच अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इसी तरह धारा 7 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि के लिए आवश्यक है कि वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे जिसमें कि आवश्यक बातों का उल्लेख रहे।
  - (र) स्कन्ध विपणि को उपनियम बनाने का अधिकार धारा-9 के अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व

<sup>11</sup> निगमो का वित्तीय प्रबन्ध-कुल श्रेष्ठ, आर एस ,साहित्य भवन आगरा-1990,पृष्ठ सख्या-642

अनुमति लेकर मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि अनुबन्धो के नियमन एव नियन्त्रण के लिए उपनियम बना सकता है जो कि अन्य बातो के अतिरिक्त निम्न बातों से सम्बन्धि हो सकते हैं-

- 1 बाजारा के कार्य-दिवस एव व्यापार के समय का नियमन,
- 2 प्रतिभूतियो की सुपुर्दगी तथा उनका भुगतान,
- 3 अनुबन्धों के सामयिक समाधान के लिए समाशोधन की व्यवस्था तथा उनके शेष का प्रबन्ध,
- 4 समझौते की तिथि मे परिवर्तन अथवा स्थगित करना,
- 5 तरावनी व्यवसाय का नियमन,
- 6 बदला व्यवहार का नियमन अथवा निषिद्धकरण,
- 7 जॉबर अथवा दलालो के कार्यों का पृथक करना,
- 8 स्कन्ध विपणि मे प्रतिभूतियो का सूचीयन,
- 9 पच-निर्णय सिहत अन्य विवादो के समाधान के लिए व्यवस्था,
- 10 असामान्य परिस्थितियो मे अधिकारो का प्रयोग,
- 11 प्रतिभूतियो के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यो को निश्चित करने से सम्बन्धित अधिकार,
- 12 सदस्यो द्वारा अपने लिए किये गये व्यापार का नियमन तथा,
- 13 व्यक्तिगत सदस्यो की व्यवसाय की मात्रा को असामान्य परिस्थितियो मे सीमाबद्ध करना।
- (ल) हिसाब-किताब एव प्रलेखों का रख-रखाव धारा-14 के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि निम्न हिसाब-किताब एव प्रेलेख तैयार रखेगा ओर 5 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेगा-1 सदस्यों, प्रशासन समिति तथा अन्य कार्यकारिणी समितियों की सभाओं के लिए कार्यवाही-रजिस्टर, 2 सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें उनके पूरे नाम, पते एवं टेलीफोन नम्बर दिये हो, 3 अधिकृत लिपिकों का रजिस्टर, 4 अधिकृत सहायकों का रजिस्टर, 5 जमानती निक्षेपों का रजिस्टर, 6 सुरक्षा नियमों की पुस्तक, 7 खाता-बहियाँ, 8 रोजनामचे, 9 रोकड पुस्तक एवं बैंक पास बुक।

एक सदस्य को भी इसी प्रकार निम्न हिसाब-िकताब एव प्रलेख तैयार करने तथा सुरक्षित रखने पड़ेगे— 1 सौदाबही, 2 सदस्यों से अनुबन्धों की पुस्तके, 3 मुविक्कलों की खाता—पुस्तक, 4 मुविक्कलों को जारी किये गये अनुबन्ध फ्रों की प्रतियाँ, 5 सामान्य खाताबही, 6 रोजनामचे, 7 रोकड बही, 8 बैंक पास-बुक, 9 अनुबन्धों के लिए मुविक्कलों की लिखित सहमित, एवं 10 प्रलेखों का रिजस्टर, जिसमें प्राप्त एवं सुपुर्द की हुई प्रतिभूतियों का पूर्ण विवरण लिखा जाये।

- (व) केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण यद्यपि स्कन्ध विपणि अपने नियम तथा उपनियम बनाने के लिए स्वतन्त्र होते है, फिर भी इन पर नियन्त्रण के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को अनेक अधिकार दिये गये है, जैसे—
  - 1 मान्यताप्राप्त विपणि के नियमों में बिना सरकार की पूर्व अनुमित के परिवर्तन न होना(धारा-7अ)
- 2 विनिमय के कोई भी नये नियम व उपनियम बनाने के लिए बाध्य करना व उसके वर्तमान नियमों व उपनियमों में परिवर्तन करना(धारा-10)

- 3 किसी मान्यताप्राप्त विपणि की प्रबन्ध समिति को भग करना(धारा-11)
- 4 यदि व्यापार व जनिहत में आवश्यक हो तो किसी विपणि का व्यापार अधिक से अधिक 7 दिन के लिए बन्द करना(धारा-12)
  - 5 विशेष परिस्थिति में भावी अनुबन्धों के व्यापार को रोकना(धारा-16)
  - 6 इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाना(धारा-30)
  - 7 तत्काल सुपुर्दगी व्यवहारो को नियमित करना
  - 8 विपणि के कार्यों की जाँच करना
- 9 विपणि के सदस्यों को व्यवहारों का पूरा लेखा रखने के लिए बाध्य करना तथा उसकी जाँच चाटर्ड एकाउन्टेट से कराना आदि
- (ष) सूचीयन का नियमन प्रतिभूतियों के सूचीयन से विनियोजको एव कम्पनी के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ हैरा-फेरी के विरुद्ध सुरक्षा एव अप्रत्यक्ष नियन्त्रण के रूप में भी मूल्यवान होता है। धारा-21 के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार किसी सार्वजिनक कम्पनी के अशों को मान्यताप्राप्त विपणि पर सूचीयन कराना आवश्यक समझती है तो वह सूचीयन के लिए कम्पनी को बाध्य कर सकती है। धारा-22 के अनुसार सार्वजिनक कम्पनी को केन्द्रीय सरकार के पास अपील करने का अधिकार दिया गया है, यदि मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि ने उसके अशों, बाण्ड, ऋणपत्रों आदि के किये कोटेशन देने से इन्कार कर दिया है। सरकार अपील पर विपणि के निर्णय को उसी प्रकार रख सकती है, या परिवर्तित कर सकती है या मानने से इन्कार कर सकती है।
- (श) निरक हस्तान्तरण का नियमन निरक हस्तान्तरण को हतोत्साहित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रावधान किये गये हैं। धारा 27(क) के अनुसार किसी भी प्रतिभूति के पजीकृत अशधारी के लिए यह विधि सम्मत है कि वह इस पर देय लाभाश को अपने पास रखे चाहे भले ही उसके द्वारा प्रतिफल के लिए उसका हस्तान्तरण कर दिया गया है। यदि हस्तान्तरिती लाभाश प्राप्त करने के इच्छुक है तो उसे प्रतिभूति तथा अन्य प्रपत्र को लाभाशदायी होने के 15 दिन पूर्व ही अपने नाम से पजीकृत करने के लिए उपलब्ध कराना होगा।
- (ह) डीलर तथा दलालो का अनुज्ञापन धारा-17 के अनुसार ऐसा राज्य अथवा क्षेत्र जहाँ कि अधिनियम की धारा 13 लागू नही है, अर्थात् मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणि के कार्यक्षेत्र के बाहर के लिए सरकार यह अधिसूचना जारी कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभूतियों के डीलर के रूप में कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह सरकार से आवश्यक अनुज्ञापत्र नहीं ले लेता। धारा 30 के अनुसार केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों के डीलरों के अनुज्ञापन के सम्बन्ध में विस्तृत नियम बना सकती है। धारा-17 के अन्तर्गत दिये जाने वाले शुल्क तथा अनुज्ञापत्र की अविध क्या होगी, वे शर्तें कौन सी होगी जिनके

अन्तर्गत अनुज्ञापत्र दिया जायेगा, उस फार्म का प्रारूप क्या होगा जिनको प्रसिवदा करते समय प्रयोग करना आवश्यक होगा, अनुज्ञापित डीलर के द्वारा कौन से प्रपत्र रखे जायेगे तथा किस प्राधिकारी के पास सामियक प्रतिवेदन आदि किस प्रकार प्रस्तुत किये जायेगे तथा अनुज्ञापत्र किन परिस्थितियो मे रद्द किया जायेगा, ये सभी बाते बनाये जाने वाले नियम मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी।

- (क्ष) <u>अधिनियम की सफलताए</u> पिछले 28 वर्षों में सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके निम्नलिखित परिणाम सामने आये हैं—
- \* इस अधिनियम के अन्तर्गत एक शहर में एक ही विपणि को स्वीकृति प्राप्त होती है इसका प्रभाव यह हुआ कि विपणियों में प्रतियोगिता समाप्त हो गयी है और वर्तमान स्कन्ध बाजारों में अच्छी परिपाटी स्थापित होने लगी है और छोटे—छोटे असवैधानिक बाजार, जैसे कलकत्ता का 'कटनी' बाजार व बम्बई का 'ग्रे' बाजार समाप्त हो गये है।
- \* सदस्यता पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाने के कारण अब केवल प्रतिष्ठित व पर्याप्त धन वाले व्यक्ति ही विपणियों के सदस्य बन पाते हैं जिनसे उनके चूकदार(डिफाल्टर) होने की सम्भावनाए कम हो गयी है।
- \* सभी अनुबन्धों को लिखित रूप दे दिया गया है तथा साथ ही साथ सौदों का लेखा पाँच वर्ष तक रखना आवश्यक होने से झगडों की सम्भावनाए कम हो गयी है।
- \* सरकार द्वारा प्रत्येक विपणि की कार्यकारिणी समिति में कुछ व्यक्ति नामांकित किये जाते हैं जिनका कार्य विपणि की कार्यप्रणाली की देखभाल करते रहना है जिससे कोई असवैधानिक कार्य विपणि न कर सके।
- \* सरकार को विभिन्न प्रकार की सूचनाए मॉॅंगने व विपणि को भग करने का अधिकार होने के कारण अब विपणि अपनी सीमा में ही कार्य करती है।
- \* सरकार किसी भी कम्पनी को सूचीयन के लिए कह सकती है और उस कम्पनी को सूचीयन कराना होगा। सट्टे की रोकथाम के लिए सट्टे से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के सौदो को विपणि पर करने से, जनहित में सरकार रोक लगा सकती है। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब विपणियो पर सट्टेबाजी कुछ कम हो गयी है।

\*विपणि के नियमों को स्वीकार करते समय सरकार इस बात की चेष्ठा करती है कि दलाली क्रम में दी जाय, समाशोधन गृह स्थापित किया जाय, कार्य के घण्टे निश्चित हो, प्रसिवदे की शर्ते उचित हो, सदस्यों के व्यापार करनी की सीमा हो, प्रतिभूतियों के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य निश्चित हो, झगडों का निपटारा पचायत से हो आदि। इन सबका प्रभाव यह होता है कि विपणि की क्रियाए प्रमापित हो जाती है और मतभेद होने या धोखा खाने की सम्भावनाए कम हो जाती है।

- 🗴 अधिनियम ने सम्पूर्ण भारत के विपणियों के कार्य व विधियों में एकरूपता ला दी है।
- \* केन्द्रीय सरकार ने स्कन्ध विपणियों के मार्गदर्शन एवं आम हितों के मामलों पर समय-समय पर विचार-विमर्श करने के लिए मान्यताप्राप्त स्कन्ध विपणियों के अध्यक्षों की एक स्थायी समिति बना रखी है जिसका कार्य सरकार को समय-समय पर सुझाव देना है जिससे कि विपणि के कार्यों में एकरूपता लायी जा सके।

## (च) व्यापार एव व्यापारिक चिह्न अधिनियम-1958 -

भारत में ट्रेडमार्क के पजीकरण हेतु इस अधिनियम को पारित किया गया है। किसी भी निर्माता द्वारा अपनी वस्तु की पहचान एव उसका नाम याद रखने के लिए कोई चिह्न, नाम,शब्द, डिजायन या इनके सिम्मश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी वस्तु पर छाप देता है तो इसे ब्राण्ड कहते हैं। लेकिन जब इस ब्राण्ड का पजीकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत करा लिया गया है तो वही ब्राण्ड ट्रेडमार्क हो जाता है। इससे निर्माता या विक्रेता को लाभ होता है। अब तकइस प्रकार के ट्रेडमार्क की नकल कोई और नहीं कर सकता और इसके प्रयोग का एक मात्र अधिकार पजीकरण कराने वाले को मिल जाता है।

भारत में इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेडमार्क के पजीकरण का कार्य पेटेण्ट डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स महानिदेशक, बम्बई के द्वारा किया जाता है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेडमार्क्स रिजस्ट्रार कहलाता है। इसकी तीन शाखाए कलकत्ता, मद्रास व नई दिल्ली में है। 12

29 मई, 1995 को लोक सभा ने नया ट्रेडमार्क विधेयक-93 पारित कर दिया है जिसमे उत्पादों के अलावा सेवाओं के लिए भी ट्रेडमार्क के पजीकरण का प्रावधान किया गया है। उद्योग राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा शाही ने इस विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि यह विधेयक समय की आवश्यकता की माँग है तथा यह नया अधिनियम व्यापार एवं व्यापारिक चिह्न अधिनियम-1958 को रद्द करके लाया गया है।

इस विधेयक मे ऐसे किसी भी ट्रेडमार्क का पजीकरण नहीं किया जाय जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे अथवा जिसमें अश्लीलता नजर आती हो। श्रीमती शाही का मानना है कि गैट समझौता और विश्व में तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए 1958 का अधिनियम पुराना पड गया था।इस नये कानुन से लालफीताशाही पर अकुश लगेगा। इस विधेयक में कुल 160 धाराए है। 13

<sup>12</sup> बाजार व्यवस्था-शर्मा एव जैन, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-220

<sup>13</sup> आज-वाराणसी(इलाहाबाद),30 मई,1995,पृष्ठ सख्या-7

# एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार(एम आर टी पी )अधिनियम-1969 -

भारत के सविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य को अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रणाली के क्रियान्वयन के फलस्वरूप धन और उत्पत्ति के साधनों का जनहित के विरुद्ध केन्द्रीय करण न हो। 14 इस सवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए तथा आर्थिक प्रक्ति के केन्द्रीयकरण की सीमा एव प्रभाव का पता लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 16 अप्रैल, 1964 को उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री के सी दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग ने अपने अध्ययन में पाया कि 75 व्यापार गृहों के पास 1536 कम्पनियों का नियन्त्रण था( जैसे, बिरला के पास 151 कम्पनियों, सूरजमल नागरमल के पास 76 कम्पनियों आदि) जिसकी चुकता पूँजी 646 करोड रुपये तथा कुल सम्पत्तियों 2,600करोड रुपये थी जो समस्त कम्पनी क्षेत्र की कुल चुकता पूँजी का 44 1 प्रतिशत तथा कुल सम्पत्तियों 2,600करोड रुपये थी जो समस्त कम्पनी क्षेत्र की कुल चुकता पूँजी का 44 1 प्रतिशत तथा कुल सम्पत्तिका 46 9 प्रतिशत थी। 15

एकाधिकारी जाँच आयोग ने अपनी सिफारिशे अक्टूबर-1965 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित कानून के लिए एक प्रारूप भी प्रेषित किया था। अत सरकार ने इस प्रारूप में आवश्यक संशोधन करके एक विधेयक 'एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार विधेयक' के नाम से अगस्त 1966 में ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जो 17 दिसम्बर, 1969 को पास हो गया और जिस पर राष्ट्रपति ने 27 दिसम्बर, 1969 को अपनी स्वीकृति दे दी।

अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें 1982,84,85 तथा 1988 में व्यापक संशोधन किया गया। 24 जुलाई—1991 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति के अनुसार इस अधिनियम में पुन संशोधन का निर्णय लिया गया है, जिससे कि नई कम्पनियों को स्थापित करने, एक कम्पनी का दूसरी में विलय करने, दो कम्पनियों का आपसी मिलान, एक कम्पनी द्वारा दूसरी को खरीदने तथा कुछ परिस्थितियों में कम्पनी निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमित की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नई शिक्तयों वाले एम आर टी पी आयोग को अधिकार होगा कि वह एकाधिकार वाली प्रतिबन्धित तथा गैर—वाजिब व्यापारिक गतिविधियों अपने आप जाँच कर या उपभोक्ताओं की शिकायत पर जाँच करे।

यह अधिनियम आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण एव एकाधिकारिक प्रतिबन्धात्मक और अनुचित व्यापारिक नीतियों के नियन्त्रण हेतु एक वृहत् वैधानिक अस्त्र है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस बात

<sup>14</sup> मरकेन्टाइल लॉ-शुक्ल एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-350

<sup>15</sup> व्यावसायिक सगठन, प्रबन्ध एव प्रशासन, अष्ठाना, पद्माकर साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ सख्या-200

<sup>16</sup> सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल-अप्रैल, 1995, क्रॉनिकल पब्लिकेशन, प्रा लि नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-69

को सुनिश्चित करना है कि देश की आर्थिक प्रणाली सामान्य हितों के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं करती है और ऐसी एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियों को रोकना और नियन्त्रित करना है जो जनहित के विरुद्ध है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्निलिखित हैं—

- (अ) <u>अधिनियम का लागू होना –</u> इस अधिनियम को 1 जून, 1970 से जम्मू कश्मीर को छोडकर सम्पूर्ण देश पर लागू कर दिया गया है। धारा-3 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधन, भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम—1934, बीमा अधिनियम—1938, बैकिंग नियमन अधिनियम—1949, भारतीय स्टेट बैक अधिनियम—1955, भारतीय स्टेट बैक (सहायक बैक) अधिनियम—1959 के प्रावधानों को छोडकर अन्य सभी अधिनियमों से ऊपर होंगे। इस अधिनियम की व्यवस्थाए अग्राकित संस्थाओं पर तब तक लागू नहीं होंगी जब तक कि केन्द्र सरकार गजट में नोटीफिकेशन न दे—<sup>17</sup> सरकारी कम्पनी अथवा उसके द्वारा नियन्त्रित कम्पनी, सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में आने वाले प्रतिष्ठान, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा गठित कोई निगम, मजदूरो अथवा कर्मचारियों के स्वय के हितों की रक्षा के लिए गठित कोई—निगम, मजदूरो अथवा कर्मचारियों के स्वय के हितों की रक्षा के लिए गठित कोई—निगम, मजदूरों अथवा कर्मचारियों के स्वय के हितों की रक्षा के लिए गठित कोई सघ, सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रबन्धित कोई उद्योग, केन्द्र अथवा राज्य सरकार या राज्य सहकारी सिमीतियों के अधीन गठित सहकारी सिमीति के स्वामित्व वाले सस्थान तथा धारा—4 में वर्णित वित्तीय संस्थाए।
- (ब) एकि धिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार आयोग की स्थापना धारा—5 के अधीन अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का पालन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक आयोग स्थापित किया गया है। इस आयोग का एक अध्यक्ष होगा जिसमें सर्वोच्च न्यायलय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो तथा आयोग में कम से कम दो और अधिक से अधिक आठ सदस्य हो सकते हैं। आयोग के सदस्य व्यापार, उद्योग, विधि, अर्थशास्त्र, लेखाकन एवं सार्वजनिक प्रशासन आदि क्षेत्रों के निपुण व्यक्ति होने चाहिए। इनकी नियुक्त केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

धारा 6 के अनुसार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक का हो सकता है तथा इसे अगले पाँच वर्ष तक बढाया जा सकता है। लेकिन कोई भी सदस्य पैसठ वर्ष की उम्र तक ही आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। धारा-7 में आयोग के सदस्यों के दिवालिया हो जाने, आपराधिक कार्य में लिप्त होने या शारीरिक एव मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाने आदि की दशा में उन्हें पद से हटाने का प्रावधान दिये गये हैं।

अधिनियम की धारा-8 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह पजीकरण एव जॉन का एक महासचालक तथा आवश्यकतानुसार कितने भी अतिरिक्त, सयुक्त, उप अथवा सहायक महासचालको की नियुक्ति कर सकती है। आयोग को एकाधिकारिक निरोधात्मक एव अनुचित व्यावसायिक

<sup>17</sup> गरकेन्टाइल लॉ-शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या-351

आचरणों की जॉंच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा-10 के अनुसार यह आयोग स्वेच्छा से, सरकार के अनुरोध पर, जनता अथवा उपभोक्ता की शिकायतो पर तथा रजिस्ट्रार-प्रितबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहारों के आग्रह पर किसी भी प्रितबन्धात्मक वयापारिक कार्य की जॉंच का आदेश दे सकता है। धारा-11 के अधीन आयोग केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा अपनी स्वय की जानकारी के आधार पर एकाधिकारात्मक आचरण की जॉंच बिना किसी अन्य प्रक्रिया के आरम्भ कर सकता है।

धारा-12 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत जाँच के लिए आयोग को गवाहों को बुलाने व शपथ दिलाने, साक्ष्यों को प्रस्तुत करने, शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने एवं किसी न्यायालय अथवा कार्यालय के सार्वजनिक अभिलेखों को मँगाने के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है। धारा-13 के अधीन आयोग को प्रतिबन्धात्मक आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिबन्धात्मक आचरण के कारण हानि या क्षित होने की दशा में आयोग को वर्ष 1984 से क्षतिपूर्ति का आदेश देने के सम्बन्ध में भी अधिकार प्राप्त हो गया है। धारा 14 में देश के बाहर चले रहे एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहारों को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में ऐसी क्रियाओं के उस भाग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान दिया गया है जो कि देश के अन्दर अपना प्रभाव डालती है। धारा-15 के अनुसार- किसी एकाधिकारात्मक निरोधात्मक अथवा अनुचित व्यावसायिक आचरण की जाँच के दौरान आयोग को ऐसे आचरण से सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उपक्रम के कार्यों पर रोक लगाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त धारा—16 में आयोग के अध्यक्ष द्वारा अतिरिक्त बेच के गठन का अधिकार, धारा—17 में जनहित में सूचनाओं की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए गोपनीय सुनवाई करने का अधिकार धारा—18 में किसी व्यवसाय की प्रक्रिया निर्धारित करना, बेच की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा सदस्यों के अधिकारों के हस्तान्तरण की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार तथा धारा—19 में आयोग द्वारा दिये गये विभिन्न आदेशों की प्रतियाँ रखने एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें महासचालक को सूचित करने सम्बन्धी प्रावधान दिये गये हैं। 18

(स) <u>आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकना</u> इस अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण को रोकना है। अधिनियम के अध्याय 3 में धारा-20 से 30 तक इससे सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण एकाधिकार को बढाता है और एकाधिकार उपभोक्ता के शोषण को। उपभोक्ता का शोषण उत्पादन एव वितरण को नियन्त्रित करके तथा प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके , मूल्यों में वृद्धि के द्वारा किया जाता है। जब उपक्रम का आकार एक निर्धारित

<sup>18</sup> मर्केन्टाइल लॉ-शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या-357-358

प्रमाप से बढने लगता है तो उपक्रम के आकार को बढाने वाली प्रत्येक क्रिया का परिणाम आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण कहलाता है, इस केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए तथा ऐसे उपक्रमो को नियमित और नियन्त्रित करने के उद्देश्य से अधिनियम के अधीन जो प्रावधान दिये गये है, उनमे से कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है—

- 1 उपक्रमो का पजीकरण आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए धारा-20(अ) के अन्तर्गत आने वाले निम्न उपक्रमो का पजीकरण कराना अनिवार्य है, जिन्हे एम आर टी पी उपक्रम भी कहा जाता है-
- 1 ऐसे सभी उपक्रम जिनकी अपने सम्बद्ध इकाइयो के साथ कुल सम्पित्तयाँ 100 करोड़ रुपये से अधिक हो।
- 2 इसमे वे प्रभावी उपक्रम आते हैं जिनकी अपनी सम्बद्ध इकाइयों के साथ कुल सम्पित्तियाँ 20 करोड से अधिक हो।

सम्पित्तियों का उस वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अन्त का मूल्य लिया जायेगा जिसमें यह प्रश्न उठता है। सम्पित्तियों के मूल्य में लेखा वर्ष का द्वास समायोजित किया जायेगा ।

- 2 विवादों का निपटारा धारा—2(ए) के अनुसार सशोधन अधिनियम 1994 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम में प्रयोग की गयी विभिन्न शब्दाविलयों या उनके स्पष्टीकरणों, जैसे—विद्यमान उपक्रमों का सारपूर्ण विस्तार, उपक्रमों का सिम्मश्रण या सिक्लयन इत्यादि के सम्बन्ध में विवाद होने पर उनका निपटारा केन्द्र सरकार की ओर से कम्पानी लॉ बोर्ड द्वारा किया जायेगा। कोई भी निर्णय देने से पहले कम्पनी लॉ बोर्ड या केन्द्र सरकार, पीडित पक्षकार को अपनी बात रखने का उचित अवसर देगी।
- 3 उपक्रम का विस्तार,स्थापना, सिम्मश्रण, सिवयन या अधिग्रहण धारा—20(अ) मे वर्णित एम आर टी पी उपक्रम के विस्तार से सम्बन्धित धारा—21, इन उपक्रमों की स्थापना से सम्बन्धित धारा—22, इने सिम्मश्रण, सिवलयन एव अधिग्रहण से सम्बन्धित धारा—23, इन धाराओं के उल्लंघन के दशा में दण्ड के प्रावधान से सम्बन्धित धारा—25, एव आवेदन पत्रों पर विचार की समय सीमा से सम्बन्धित धारा—30 के प्रावधान जो उपक्रमों के विस्तार,स्थापना,सिम्मश्रण एव सिवलयन की क्रियाओं से पूर्व केन्द्र सरकार को पूर्व निर्धारित सूचनाए भेजने तथा उसका अनुमादेन प्राप्त करने से सम्बन्धित थे, अब नई औद्योगिक नीति लागू हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो गये हैं। परन्तु नई शक्तियों वाले एम आर टी पी आयोग को यह अधिकार होगा कि वह एकाधिकार वाली प्रतिबन्धित तथा गैर—वाजिब (अनैतिक) व्यापारिक गतिविधियों की उपभोक्ता की शिकायतों पर अथवा अपने आप जाँच करे।

<sup>19</sup> भारतीय अर्थशास्त्र-मामोरिया, सी बी , साहित्य भवन आगरा-1995, पृष्ठ सख्या-215

4 उपक्रम के रिजस्ट्रेशन की प्रक्रिया —धारा—26 के अनुसार एक एम आर टी पी उपक्रम के स्वामी को उसके उपक्रम के एम आर टी पी के अन्तर्गत आने के 60 दिन के अन्दर एक निर्धारित प्रारूप पर रिजस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। यह समय किसी उचित कारण के दशा में बढाया भी जा सकता है। केन्द्र सरकार ऐसी उपक्रमों के लिए एक रिजस्टर अनुरक्षित करती है। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर इस रिजस्टर में ऐसे उपक्रम का नाम प्रविष्ट कर एक निर्धारित प्रारूप पर रिजस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र निर्गत करती है।

यदि रिजस्ट्रेशन के सम्बन्ध में धारा-26 के प्रावधानों का उल्लंधन किया जाता है तो कम्पनी की दशा में एक हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है और यदि उल्लंधन आगे भी जारी रहता है तो इसके अतिरिक्त प्रतिदिन पंचास रुपये की दर से जुर्माना बढता रहेगा। फर्म के स्वामी, साझेदारी संस्था के साझेदार, कम्पनी के अधिकारी अथवा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसे उपक्रम का स्वामित्व या नियन्त्रण करता है के गलती से प्रावधानों का उल्लंधन होने की दशा में ऐसे प्रत्येक अधिकारी को दो वर्श की कैद या एक हजार रुपये का दण्ड तथा यदि अपराध आगे भी जारी रहता है तो इसके अतिरिक्त पंचास रुपये प्रतिदिन की दर से अपराध की अविध तक दण्ड को बढाया जा सकता है।

- 5 उपक्रम अथवा व्यवसाय का विभाजन धारा-27 में जनहित के विरुद्ध आर्थिक शिवत के केन्द्रीयकरण को तोड़ने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह परस्पर सम्बद्ध उपक्रमों अथवा व्यवसाय के विभाजन सम्बन्धी आदेश भी जारी कर सकती है। यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि अधिनियम के भाग'अ' में आने वाल कोई उपक्रम ऐसी एकाधिकारिक या व्यापारिक क्रियाओं में लिप्त है जो सामान्यहित के विरुद्ध है तो वह, उपक्रम की सम्पत्तियों के किसी भाग की बिक्री अथवा उपक्रम के अनेक उपक्रमों में विभाजन के आदेश जारी कर सकती है। ऐसा आदेश केन्द्र सरकार द्वारा एकाधिकार आयोग को सौंपे गये मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया जा सकता है। यदि इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कैद और एक हजार रुपये तक का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।
- 6 सरकार एव एकाधिकार आयोग द्वारा विचार किये जाने वाले मामले धारा—28 के अनुसार अधिनियम द्वारा केन्द्र सरकार एव आयोग को प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग जहाँ प्रथमत यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि अर्थिक शिक्त का जनिहत के विरुद्ध केन्द्रीयकरण न हो वहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले भी सरकार अपने विचार में ले सकती है। देश की सामान्य आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी मामले केन्द्र सरकार एव आयोग द्वारा विचार हेतु लिए जायेगे, जिनका सम्बन्ध देश की सुरक्षा आवश्यकताओं तथा देशी व विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं व सेवाओं का कुशलतम् आर्थिक ससाधनों की सहायता से, उत्पादन से हो। सरकार द्वारा देश में उपलब्ध मानवीय, भौतिक

गव औद्यागिक क्षमता के श्रेष्ठ प्रयोग को सुनिश्चित करने, विद्यमान बाजार के विस्तार तथा नये बाजारों की याज की दिशा में तकनीकी विकास का प्रयोग करने, आर्थिक शक्ति के कन्द्रीयकरण की काट के रूप में नये उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देने, सामान्य हित में देश के भौतिक साधनों के प्रयोग को नियमित व नियन्त्रित करने एव क्षेत्रीय असमानता एव असतुलन को कम करने के उद्देश्य से भी उपर्युक्त मामलों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

- 7 सुनवाई का अवसर प्रदान करना धारा-29 के अनुसार उपर्युक्त प्रावधानों के तहत् केन्द्र सरकार कोई भी आदेश जारी करने के पूर्व विचाराधीन मामले से सम्बन्धित पक्ष को अपना तथ्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेगी।
- (द) एकाधिकारात्मक व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण धारा—31 के द्वारा केन्द्र सरकार को एकाधिकारी व्यावसायिक आचरणों को भी नियन्त्रित करने के अधिकार प्राप्त है। देश की विद्यमान आर्थिक तथा अन्य दशाओं को ध्यान में रखते हुए कोई एकाधिकारात्मक वयावसायिक आचरण जनहित के लिए खतरनाक समझा जाता है यदि ऐसे आचरण का प्रभाव किसी वस्तु अथवा सेवा की उत्पादन लागतों में अवाछनीय वृद्धि, कीमतों में वृद्धि अथवा बिक्री से प्राप्त किये जाने वाले लाभों में अवाछनीय वृद्धि अथवा बस्तु की पूर्ति में रुकावट तथा प्रतियोगिता में कमी के रूप में होता है। ऐसी किसी भी स्थिति को महसूस करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सम्बद्ध मामले एकाधिकार आयोग को विस्तृत जाँच के लिए सौपे जा सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थिति को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त आवेश जारी किये जा सकते है। ऐसा कोई आदेश उपक्रम द्वारा उत्पादित, वितरित अथवा नियन्त्रित की जाने वाली वस्तु या सेवा के विक्रय या पूर्ति से सम्बन्धित शर्तों का निर्धारण कर उसके नियमन, उपक्रम द्वारा वस्तु के वितरण से सम्बन्धित प्रतियोगिता में कमी लाने वाली किसी व्यावसायिक नीति के अपनाने को प्रतिबन्धित करने, उपक्रम द्वारा उत्पादित अथवा प्रयुक्त वस्तु के स्तर निर्धारण तथा व्यावसायिक क्रियाओ अथवा किसी अनुबन्ध को अवैध घोषित करने का हो सकता है। 20

धारा-32 में उन एकाधिकारी व्यवसायिक व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जो जनहित में होते है. तथा जिन पर उपर्युक्त प्रावधान लागू नहीं होता है-

- 1 यदि उन्हें कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है,
- 2 यदि उनकी लिखित अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी है बशर्ते ऐसा व्यवहार-
- (अ) भारत वर्ष की रक्षा या राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओ को पूरा करता हो या,
- (ब) जन सामान्य के लिए आवश्यक वस्तुओ या सेवाओ के निर्माण अथवा पूर्ति को सुनिश्चित करता

<sup>20</sup> मर्केन्टाइल लॉ-शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या- 379

हो या.

(स) किसी ऐसे समझौते को कार्यरूप प्रदान करने के लिए जिसमे केन्द्र सरकार भी एक पक्षकार के रूप में है।

धारा-50 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा-31 के प्रावधानों के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश का, बिना यथोचित कारण के उल्लंघन करता है तो उसे- प्रथम अपराध की दशा में 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और पुन अपराध की दशा में 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

यदि उल्लंघन आगे भी जारी रहता है तो 500 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।

- (य) प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण धारा 2(ओ) के अनुसार ऐसा व्यापारिक व्यवहार जिसका वास्तिविक या सम्भावित परिणाम बाजार की प्रतियोगिता को बाधित करना, कम करना या नष्ट करना, प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार कहलाता है। ऐसे व्यवहार पूँजी या उत्पादन साधनो को प्रभावित कर वस्तु या सेवा की उपलब्धता में बाधा डालते हैं। सरकार ऐसे व्यवहारो पर उपभौकता उद्योग एव व्यापार के व्यापक हितो में प्रतिबन्ध लगाती है।
- 1 प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार में शामिल-क्रियाए(धारा-33) इसमें प्रतियोगिता को प्रभावित करने के उद्देश्य से वस्तु के विक्रेताओं द्वारा परस्पर समझौता करना जिसके अनुसार उत्पादन की कीमत अथवा विक्रय की शर्तें आपस में बाजार को विभाजित करने जैसी बाते तय की जाती है। अलग—अलग वर्ग के उपभोक्ताओं में वस्तु की लागत में नाम—मात्र का अन्तर होते हुए भी विभिन्न प्रभावी कीमतो पर वस्तु की बिक्री, बाजार में विद्यमान प्रतियोगिताओं को हटाने के उद्देश्य से वस्तु को थोडे समय के लिए लागत से कम कीमत पर बेचना, अधिक बिकने वाले माल के उत्पादको द्वारा अपने उत्पादन के साथ कम बिकने वाले माल को सयुक्त रूप से बेचना, किसी एक वस्तु के क्रेता को उस वस्तु समूह की सभी वस्तुए एक साथ खरीदने को बाध्य करना, उत्पादक द्वारा वितरक को केवल अपने उत्पादन बेचने को कहना, वितरक के कार्यक्षेत्र की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देना, उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन को बिक्री के लिए कीमत निश्चित कर देना जैसे आचरण शामिल किये जा सकते है।
- 2 व्यवहारों का पंजीकरण —अधिनियमानुसार ऐसे अनुबन्ध जिनका सम्बन्ध प्रतिबन्धात्मक व्यावसायिक व्यवहार से हो जाँच एव पंजीकरण के महासचालक द्वारा प्राधिकृत अनुबन्धों के रिजस्ट्रार के पास पंजीकृत कराये जाने चाहिए। निरोधात्मक व्यापारिक व्यवहारों में ऐसे व्यवहारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जब तक कि ऐसा आचरण जनहित के विरुद्ध न हो।
  - 3 **आयोग को जाँच का अधिकार(धारा-10(अ)** आयोग को किसी भी प्रतिबन्धात्मक व्यापार

व्यवहार की जॉच का अधिकार है यदि-

- (अ) प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध में तथ्यात्मक शिकायते किसी व्यापार सघ या, उपभोक्ता सघ के सदस्यो अथवा उपभोक्ता द्वारा स्वय की जाय या,
  - (ब) जॉंच का मामला केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाय, या
  - (स) मामला जाँच एव पजीकरण महासचालक द्वारा प्रेषित किया जाय या,
  - (द) आयोग के स्वय के जानकारी या सूचना प्राप्त होने पर।

एकाधिकारी आयोग को अपने आदेश को प्रभावी ढग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान बनाने और अपने आदेश को निरस्त करने सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- 4 <u>जॉच की प्रक्रिया</u> आयोग द्वारा जॉच की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए पूँजीकरण का होना आवश्यक नहीं है। प्रारम्भिक रूप में रिजिस्ट्रार को यह प्रदर्शित करना होता है कि उपक्रम द्वारा प्रतिबन्धित आचरण किया गया है और इसके बाद यह साबित करना सम्बन्धित पक्षकार का दायित्व होता है कि उपक्रम द्वारा अपनाई गयी नीतियाँ जनहित के विरुद्ध नहीं है। एक बार आयोग द्वारा यह सुनिष्टिचत कर लेने पर कि कोई निरोधात्मक व्यवहार जनहित के विरुद्ध है, उसे ऐसे व्यवहार अपनाना बन्द करने या न दुहराने, ऐसे आचरण से सम्बन्धित ठहराव को व्यर्थ घोषित करने, अथवा अनुबन्ध को उपयुक्त तरीके से परिवर्तित करने सम्बन्धी आदेश देने का अधिकार प्राप्त रहता है। ऐसा आदेश पारित करने के बजाय सम्बन्धित पक्ष के आवेदन पर आयोग उपक्रम के स्वामी या प्रबनधकों को उचित समय के अन्दर यह आश्वासन देने का अवसर प्रदान कर सकता है कि प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध नहीं है।
- 5 जनहित की मान्यताए आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए कोई प्रतिबन्धित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध समझा जाता है यदि सम्बन्धित पक्षकार प्रथमत यह साबित न कर सके कि वह अधिनियम की धारा 38(1)मे वर्णित विभिन्न निर्धारक तत्वो मे से एक या अधिक को पूरा करता है और प्रतिबन्ध अवाछनीय नहीं है एव ऐसे प्रतिबन्ध के परिणाम जनहित के लिए हानिकारक नहीं होगे। जनहित की मान्यताए अधिनियमानुसार निम्न प्रकार है—
  - 1 प्रतिबन्ध जनसाधारण को किसी प्रकार की मौलिक क्षति से बचाने के लिए आवश्यक है।
- 2 प्रतिबन्ध को हटा लेने पर जन साधारण को प्राप्त होने वाले विशिष्ट व महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो संकेगे।
- 3 व्यापार के समान स्तर पर अपनाये गये किसी प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के उपाय के रूप में प्रतिबन्ध आवश्यक है।

- 4 प्रतिबन्ध सम्बन्धित पक्षकार को वस्तु की उचित पूर्ति बनाये रखने की स्थिति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
- 5 प्रतिबन्ध को हटाने से सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में भयकर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।
- 6 देश के कुल निर्यात व्यापार अथवा उद्योग के कुल व्यवसाय को ध्यान मे रखते हुए प्रतिबन्ध को हटाने से निर्यात आय पर विरीत प्रभाव पड़ेगा।
- 7 किसी दूसरे प्रतिबन्ध को जिसे आयोग जनहित के विरुद्ध नहीं समझता एव स्थिति बनाये रखने के लिए प्रतिबन्ध आवश्यक है।
- 8 प्रतिबन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या उद्योग मे प्रतिस्पर्धा को कम नहीं करता और न ही इसे हतोत्साहित करता है।
  - 9 ऐसा प्रतिबन्ध केन्द्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत एव पुष्ट किया गया है।
- 10 प्रतिबन्ध राज्य की सुरक्षा एव देश की रक्षा की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।
  - 11 प्रतिबन्ध आवश्यक वस्तुओ या सेवाओ की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- 6 <u>दण्ड का प्रावधान(धारा-48)</u> कोई भी व्यक्ति जो धारा 33 मे वर्णित व्यवहारो से सम्बन्धित समझौता करने के 60 दिन के अन्दर ऐसे समझौते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उसे 5000 रुपये तक का आर्थिक दण्ड या 3 वर्ष तक का कैद या दोनो सजाए दी जा सकती है।
- (र) <u>अनुचित व्यापारिक व्यवहार का नियन्त्रण</u> सशोधन अधिनियम,1984 की धारा—36(ए) के अनुसार अनुचित व्यापारिक व्यवहार से आशय उस व्यवहार से हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु की पूर्ति, प्रयोग या विक्रय बढाने या सेवाओं के प्रावधान करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं से उपभोक्ता को हानि या चोट पहुँची हो, चाहे प्रतियोगिता को प्रतिबन्धित किया गया हो अथवा नही। धारा—36(ए) का विस्तृत विवरण उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम—1986 में आगे दिया गया है क्योंकि अनुचित व्यापार का आशय दोनों अधिनियमों के लिए एक ही है।
- 1 <u>आयोग द्वारा जॉन्ब का प्रावधान(धारा-36, बी सी तथा डी)</u> आयोग के समक्ष जॉन्च के लिए आये किसी अनुचित व्यापारिक व्यवहार की जॉन्च इस दिशा मे की जाती है कि सम्बद्ध व्यवहार उपभोक्ताओं अथवा सामान्य जनहित के विपरीत है। जॉन्च द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार को जनहित के विरुद्ध पाकर आयोग ऐसे व्यवहार को बन्द करने, न दोहराने तथा ऐसे आचरण से सम्बन्धित किसी अनुबन्ध को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने का आदेश पारित कर सकता है। ऐसा आदेश जारी करने के बजाय आयोग

सम्बन्धित पक्षकार को उचित समय के अन्दर ऐसे कदम उठाने का अवसर प्रदान कर सकता है जिससे अनुचित व्यापारिक व्यवहार जनहित के विरुद्ध न रह जाय। ऐसा सुनिश्चित हो जाने पर कि जनहित के विरुद्ध अनुचित व्यवहार सम्बन्धित उपक्रम द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है, आयोग इस सम्बन्ध में और आदेश न दिये जाने का निर्णय भी ले सकता है।

- 2 <u>दण्ड का प्रावधान</u> आयोग द्वारा दिये गये किसी आदेश की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा-48(सी)के अनुसार 3 वर्ष का कारावास और/ या 10000 रुपये के दण्ड का प्रावधान है। आयोग ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप क्षति उठाये किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति सम्बन्धीआदेश देने का भी अधिकार रखता है। <sup>21</sup>
- (ल) पुन विक्रय मूल्य अनुरक्षण को रोकना(धारा-39 से 41) कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रसविदा या समझौता अपने थोक या फुटकर विक्रेताओं के साथ नहीं कर सकता है, जिसमें न्यूनतम मूल्य पर पुन बिक्री को कहा गया हो। ऐसा समझौता या प्रसविदा व्यर्थ माना जायेगा। कोई भी निर्माता वस्तुओं का केवल अधिकतम मूल्य ही प्रस्तावित कर सकता है। कोइ भी पूर्तिकर्ता इस आधार पर अपनी पूर्ति उस व्यक्ति को नहीं रोकेगा जिसने पुन विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की है या उसके द्वारा पुन विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की सम्भावना है।
- 1 <u>आयोग का विश्रेषाधिकार</u> ऐसे समझौते जो र्सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम या श्रम सघो से सम्बन्धित हो, भारतीय पेटेण्ट अधिनियम के अन्तर्गत पेटेण्ड के स्वामी के अधिकारो की रक्षा के लिए अपनाये गये हो, निर्यात के उद्देश्य से वस्तु के उत्पादन, वितरण आपूर्ति अथवा नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, अथवा क्रेताओ द्वारा अन्तिम उपभोग के लिए खरीदे गये माल के सम्बन्ध मे किये गये ठहराव के कारण उत्पन्न हुए हो तो आयोग को इसमे छूट देने का अधिकार है।
- 2 <u>दण्ड का प्रावधान</u> धारा 50(2) और (3) के अनुसार धारा 39 एवं 40 के उल्लंघन करने पर उसी दण्ड का प्रावधान है जो पूर्व उल्लिखित धारा 31 के उल्लंघन पर है।
- (व) अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्याकन कुछ विपणन वेत्ताओ का मत है कि पाश्चात्य देशों की तुलना में भारतीय उद्योगों का आकार छोटा है। अत उन पर प्रतिबन्ध लगाना न्यायसगत नहीं है, क्योंकि इससे न तो राष्ट्रहित होगा और न औद्योगिक कुशलता में वृद्धि होगी। इन्हीं आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव है।यदि उद्योगों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये तो उनका समुचित विकास नहीं हो पायेगा। आधुनिक युग में देश जब औद्योगीकरण की दिशा में तीव्र गित से अग्रसर है, एकाधिकार नियन्त्रण रूपी प्रतिबन्ध से उद्योगों का समुचित

<sup>21</sup> राज्य एव व्यवसाय-जगदीश प्रकाश, प्रयाग पुस्तक भवन- इलाहाबाद-1991,पृष्ठ सख्या-106

विकास एव आधुनिकीकरण नहीं हो सकेगा। वैसे ही कम्पनी अधिनियम में सरकार को इतने व्यापक अधिकार मिल गये हैं कि वह किसी भी उद्योग पर प्रभावी नियन्त्रण रख सकती है। 22

शायद इसी भावना से प्रेरित होकर वर्तमान सरकार द्वारा 24 जुलाई-1191 को घोषित नवीन औद्योगिक नीति मे एम आर टी पी कम्पनी एव प्रभावशाली उपक्रम की सम्पत्ति सीमा को अधिनियम से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें किसी नये उपक्रम की स्थापना, उपक्रम के विस्तार, सिम्मश्रण, सिवलयन, अधिग्रहण अथवा कुछ दशाओं में सचालकों की नियुक्ति से पूर्व, केन्द्र सरकार से अनुमित प्राप्त करने की व्यवस्था को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। यद्यपि नवीन औद्योगिक नीति में इस बात पर जो दिया गया है कि अधिनियम एकाधिकारी प्रतिबन्धात्मक अनुचित व्यापार व्यवहार को नियमित और नियन्त्रित करेगा। 23

पिछले 25 वर्षों में सरकार को औद्योगिक विकास एव नियमन अधिनियम-1951 के अधीन जितने आवेदन प्राप्त हुए उसमें से केवल 10 प्रतिश्रत आवेदनों को एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग को विचारार्थ, प्रेषित किया गया जिसमें से 87 प्रतिश्रत आवेदनों को आयोग ने अनुमोदित किया। <sup>24</sup> मार्च-1990 के अन्त तक 1854 उपक्रम अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत थे जिसमें से 1787 उपक्रम एकाकी बड़े उपक्रम के रूप में धारा-20(अ) तथा 67 उपक्रम प्रभावी उपक्रम के रूप में पजीकृत थे। <sup>25</sup>

सरकार ने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से कई प्रयास किये परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उन प्रयासों के परिणामस्वरूप इसमें कोई कमी आयी है। इसके विपरीत इन घरानों या व्यवसायों की सम्पत्ति में काफी वृद्धि हुई है, जैसे— टाटा ग्रुप की सम्पत्तियाँ 1972 में 642 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 31,1990 को 8,531 करोड़ रुपये की हो गयी है। इसी प्रकार बिरला ग्रुप की सम्पत्तियाँ 1972 में 590 करोड़ रुपये की थी जो 31 मार्च—1990 को बढ़ कर 8,473 करोड़ रुपये की हो गयी है। इसी प्रकार मफतलाल 184 से 1344 करोड़ रुपये, जे के सिहानिया 121 से 2139 करोड़ रुपये, थापर 136 से 2177 करोड़ रुपये। <sup>26</sup>

यह निर्विवाद है कि जहाँ एक ओर समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए आर्थिक शिक्त के केन्द्रीयकरण पर नियन्त्रण रखना है, वही दूसरी ओर देश का तीव्र गति से औद्योगीकरण भी करना है।

<sup>22</sup> रिपोर्ट ऑन मोनोपोली इनक्वाइरी कमीशन-1965, पृष्ठ सख्या-76

<sup>23</sup> मरकेन्टाइल लॉ-शुक्ला एव गुप्ता, साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-359

<sup>24</sup> इण्डियन इकोनमी-अग्रवाल, डी सी , साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ संख्या-322

<sup>25</sup> राज्य एव व्यवसाय-जगदीश प्रकाश, कक्कड एव शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद-1991, पृष्ठ स-108

<sup>26</sup> भारतीय अर्थव्यवस्था-मामोरिया, सी बी , साहित्य भवन आगरा-1995, पृष्ठ सख्या-442

वास्तव में आकार की विशालता अथवा आर्थिक शिक्त के केन्द्रीयकरण की अधिकता स्वय में कोई सामाजिक दोष नहीं है, वरन् इस स्थित का दुरूपयोग हानिकारक है। यदि विशाल उद्योगों को सही प्रकार से सचालित किया जाए तो उनसे अनेक प्रकार की मितव्यियताए प्राप्त होती है। पूँजी निर्माण की गित तीव्र होती है और राष्ट्र का तेजी से आर्थिक विकास होता है। एकाधिकार जाँच आयोग ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा था कि," आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण ने राष्ट्र के आर्थिक सुधार में सहयोग दिया है।

सत्तर के दशक में इस अधिनियम के माध्यम से उद्योगों को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, विशेषकर बड़े औद्योगिक घरानों या बड़ी कम्पनियों में, विनियोग एवं उत्पादन के विकास में कमी आई। अस्सी के दशक में इस स्थिति पर थोड़ा अकुश लगा और यह समझा जाने लगा कि एकाधिकारी प्रावधान प्रभावी हो रहा है। वर्तमान दशक में, एकाधिकार सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन में की जाने वाली कड़ाई में उदारवादी दृष्टिकोण की झलक भी दिखाई दे रही है।

इस प्रकार यह अधिनियम अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में न तो पूर्णरूप से सफल ही रहा और न ही विफल। वर्तमान सन्दर्भों में जबिक अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रूप प्रदान करने के लिए नये— नये आर्थिक सुधार किये जा रहे है— औद्योगिक विकास का नेहरूवादी मॉडल अप्रासगिक सा हो गया है, निजीकरण बढ रहा है, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ऐसी परिस्थित में इस अधिनियम की पुन समीक्षा करने एव इसे नयारूप प्रदान करने की आवश्यकता है।

# (ज) पैकेज्ड क्स्तु नियमन आदेश-1975 -

इस तरह के आदेश का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका मे 'फेयर पैकेजिंग लेबिलग एक्ट' के नाम से प्रारम्भ हुआ जिसके अन्तर्गत िकसी पैकेट पर उसमें रखी हुई वस्तु की मात्रा, उसका वजन, उसके निर्माता का नाम आदि लिखना अनिवार्य हैं। जिससे उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं की तुलना की जा सके और वह उचित निर्णय ले सके। भारत सरकार ने भी भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार वस्नु के पैकेट पर वस्तु को पैक करते समय शुद्ध मात्रा, अधिकतम मूल्य, निर्माण की तारीख, निर्माता का नाम एव पता होना अनिवार्य हैं। सरकार ने यह आदेश 28 जुलाई, 1975 को जारी किया, जिसे 'पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश—1975' के नाम से जाना जाता है जो 1 जनवरी, 1976 से लागू हुआ। इस आदेश का उद्देश्य पैकेज्ड वस्तु का उचित मूल्य पर वितरण हैं। यह आदेश पहले 1 सितम्बर, 1975 से लागू होना था, लेकिन बाद में इसके लागू होने की तारीख दो बार बदली गयी और अन्त में यह 1 जनबरी—1976 से लागू किया जा सका। 1 अप्रैल, 1980 से यह आदेश 'बाट एव माप—मान अधिनियम'के अन्तर्गत कर दिया गया है। 27 इस आदेश की मुख्य बाते अग्र-लिखित है—

<sup>27</sup> बाजार व्यवस्था-शर्मा एव जैन, साहित्य भवन आगरा-1991, पृष्ठ सख्या-231

- (क) कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को बेचने के लिए पैक नहीं करेगा जब तक कि प्रत्येक पैकेट पर एक लेबिल अग्रलिखित बातों के सम्बन्ध में नहीं लगा देता—(1) पैकेट के अन्दर वस्तु की पहचान, (2) पैकेट में रखी हुई वस्तु की मात्रा या वजन या माप,(3) तारीख जिस दिन पैकेट तैयार किया गया है—माह एवं वर्ष सहित, (4) पैकेट का मूल्य।
- (ख) कोई भी व्यक्ति ऐसे पैकेट को न बेचेगा, न वितरित करेगा और न देगा जिस पर उपर्युकत 1 से 4 में लिखी बाते नहीं है।
- (ग) पैकेट या लेबिल पर जो मूल्य दिया गया है उससे अधिक मूल्य पर कोई भी डीलर उस वस्तु को नहीं बेचेगा।
  - (घ) प्रत्येक पैकेट पर निर्माता या पैक करने वाले का पूरा नाम एव पूरा पता होगा।
- (ड) लेबिल या पैकेट पर जो विवरण वजन, माप या नम्बर के बारे में दिया है वह किसी भी प्रकार शर्त-सिहत नहीं होगा।
  - (च) वे वस्तुए जिन पर सरकारी मूल्य नियन्त्रणलागू है, उन पर नियन्त्रित मूल्य ही दिये जायेगे।
- (छ) पैकेट पर 1 दिसम्बर, 1990 से प्रत्येक निर्माता वस्तु पर समस्त कर सिहत अधिकतम मूल्य अकित करेगे।
  - (ज) पैकेट मे वस्तु के वजन की घोषणा मे उनके पैकिंग सामान का वजन शामिल नही होगा।
- (झ) यदि किसी वस्तु को रैपर या आधानपात्र में बेचा जाता है जो उस रैपर या आधानपात्र पर सभी सूचनाए दी जायेगी।
- (ञ) यदि पैकेट पर शुद्ध वजन या मूल्य लिखना असम्भव या अव्यवहारिक हो तो पैकेट के साथ एक लेबिल या मुहर लगा दी जाय जिस पर शुद्ध वजन एव मूल्य स्पष्ट रूप से दिया हो।

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपर्युक्त आदेश उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है जो किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम आती है या थोक पैकेट के रूप में बेची जाती है या वे वस्तुए जो खाने के काम में आती है। यह आदेश बहुत छोटी वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता है। बीडी व अगरबत्ती इस सीमा से बाहर है, तथापि व्यवहारिक रूप से इन वस्तुओं की पैकिंग पर भी वस्तुओं की मात्रा या सख्या, कम्पनी अथवा उत्पादन करने वाली सस्था का नाम एव मूल्य आदि दिये होते है। वास्तव में यह आदेश उन वस्तुओं पर भी लागू होता है जो आम जनता की उपभोग की वस्तुए है, जैसे— कॉफी, चाय, खाने के तेल, वनस्पित तेल, सावुन, बिस्कुट, सीमेट, बच्चों का दूध, दवाइयों, सौन्दर्य-प्रसाधन की वस्तुए आदि।

सन्दर्भित अधिनियम मे जुलाई-1994 से दूध,चीनी, अनाज, सौन्दर्य-प्रसाधन, टूथपेस्ट, सेविगक्रीम, जैम आदि 28 वस्तुओं को इस अधिनियम से इस आशय से मुक्त कर दिया गया है कि इन वस्नुओं की कोई भी मात्रा पैकिंग की जा सकती है। <sup>28</sup> 'मानक पैक साइज व कुछ वस्तुओं को मिली छूट की जाँच के लिए स्थायी समिति भी गठित की गयी है। इन नियमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर व्यापार व उद्योग, सम्बद्ध मन्त्रालयों, उपभोक्ता सगठनों, मानक सस्थानों व अन्य सम्बद्ध लोगों से परामर्श करके सशोधन किये जाते हैं। <sup>29</sup> भारतवर्ष में यह आदेश कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। भूतपूर्व उद्योग एव नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री जार्ज फर्नाडीज के अनुसार भारतवर्ष में उपभोक्ता को करीब 32,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष(पैक किये हुए पैकेटो में कम वजन से) उगा जाता है। <sup>30</sup> वास्तव में यह आदेश उपभोक्ताओं की भलाई एव सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में एक कदम है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्माता पैकिंग के सन्दर्भ में आचार—सहिता एवं आदेश का पालन करे एवं उपभोक्ता सावधानी तथा विवेक से उपभोग की वस्तुओं का क्रय करते हुए पैकिंगों पर ध्यान दे।

जुलाई—1994 में में जो 28 क्स्तुए इस अधिनियम की व्यवस्था से, इनकी कोई भी मात्रा की पैकिंग करने के नाम से मुक्त की गयी, तो वास्तव में मात्रा का विभाजन करने वाले व्यक्तियों को यह दायित्व साैपा जा सकता था कि वस्तुओं की मात्रा के अनुपात में पैकिंग के विभाजन के बाद पुन पैकिंग पर मूल्य, मात्रा इत्यादि अकित की जाय, अन्यथा इससे गरीब उपभोक्ता के शोषण की सम्भावना बढ गयी है। इस आदेश के जारी होने से उपभोक्ताओं को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि वस्तु पर जो मूल्य लिखे जाते है, दुकानदार उससे कही अधिक मूल्य स्थानीय करों के नाम पर बसूल करता है। इसके अतिरिक्त साबुन, कापिया इत्यादि वस्तुओं पर पहले ही अधिक मूल्य अकित किया गया होता है। इस प्रकार का आदेश जनता के लिए पूर्ण उपयोगी नहीं रहा है फिर भी कम वजन या माप की शिकायतों में अवश्य कमी हुयी है।

# (झ) बाट एव माप-मान अधिनियम-1976 -

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश मे एक महत्वपूर्ण सुधार भार और माप की प्रणालियों में एकरूपता के रूप में आया है। भार एवं मानक अधिनियम—1956 के अन्तर्गत मीट्रिक टन प्रणाली पर आधारित भार और माप के एक समान मानक बनाये गये। इस अधिनियम द्वारा बनाए गये मानक, इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा बने कानूनों की व्यवस्था के अनुसार लागू किये गये। राज्यों ने इन कानूनों को लागू करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी विकसित की। नागरिक आपूर्ति विभाग में भार और माप इकाई इस विषय से सम्बन्धित सभी गतिविधियों को देखने वाली एजेन्सी है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार

<sup>28</sup> दैनिक जागरण, वाराणसी-23 जुलाई, 1994

<sup>29</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-459

<sup>30</sup> सरकार, समाज एव विपणन-मालवीय, हरिश्चन्द्र, किताब महल एजेन्सीज, इलाहाबाद-1990, पृष्ठ स0-160

भार एव माप की व्यवस्था बनाने तथा कुछ किमयों को दूर करने के लिए एक व्यापक कानून भार एव माप मानक अधिनियम-1976 लागू किया गया। 31

इस अधिनियम का उद्देश्य तोल एव माप के मान को स्थापित करना तथा तोल, माप व अन्य वस्तुए जो तोल, माप या अक से बेची या वितरित की जाती है उनके अर्न्याज्यीय व्यापार या वाणिज्य का नियमन करना एव इनसे सम्बन्धित कार्य करना है। इस अधिनियम के मुख्य तत्व निम्नलिखित है—

- 1 <u>तोल एव माप प्रमाणों की स्थापना —</u> बाट एव माप की प्रत्येक इकाई मैट्रिक प्रणाली पर आधारित होगी। इसके लिए मीटर, किलोग्राम, एम्पीयर, केलविन आदि को काम में लाया जायेगा।
- 2 <u>गैर-मान बाट, माप या अक के प्रयोग तथा उनके बनाने पर प्रतिबन्ध</u> इस अधिनियम के अधीन गैर मान के बाट व माप के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही ऐसे बाट व माप बनाने पर रोक भी लगा दी गयी है। कोई भी व्यक्ति किसी क्त्तु को बेचने के लिए मूल्य गैर मान के बाट एव माप मे नहीं बता सकता, न क्त्तुओं पर इस प्रकार का तथ्य अकित ही कर सकता है और न ही इसका कैशमेमो, बिल या बीजक आदि बना सकता है। यदि कोई परम्परा, रीति या तरीका ऐसा है जिसमें मान से कम या अधिक वस्तु की माँग की जाती है या वस्तु की सुपुर्दगी की जाती है तो इस प्रकार की माँग या सुपुर्दगी व्यर्थ होगी। यदि कोई व्यक्ति बाट, माप या अक बनाता है, बेचता है या वितरित करता है या उसकी मरम्मत करता है तो उसको इस प्रकार के वितरण, विक्रय या मरम्मत का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है।
- (3) <u>मान उपकरणो का सत्यापन</u> प्रत्येक माप पर प्रमाणित होने की मुहर लगवाना आवश्यक है। यह मुहर निर्धारित अधिकरण द्वारा निश्चित फीस लेकर लगायी जायेगी। यदि किसी मान पर मुहर नहीं लगी है तो उसका प्रयोग वर्जित है। सभी प्रयोग में आने वाले मापो व बाटो पर एक निश्चित समय के बाद मुहर लगवाना अनिवार्य है।
- 4 सरकरी अधिकारियों के अधिकार इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी ऐसे स्थान पर उचित समय में प्रवेश कर सकता है तथा तौल, माप या उससे सम्बन्धित रिकार्ड को अपने कब्जे में ले सकता है जहाँ पर इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कार्य किये जाने की सम्भावना हो इस प्रकार का यदि कोई भी अप्रमाणित तौल या माप पाये जायेगे तो उसको केन्द्रीय सरकार जब्त कर सकती है।
  - 5 दण्ड धारा-50 के अनुसार यदि कीई भी व्यक्ति निर्धारित मानको केमापो व बाटो का

<sup>31</sup> भारत-1993,सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली,पृष्ठ सख्या-459

उपयोग नहीं करता तो उसको इस प्रकार का कार्य पहली बार करने पर छ माह की सजा या एक हजार रूपये का आर्थिक दण्ड या दोनो दिया जा सकता है, परन्तु दुबारा या बाद के अपराधो पर 2 वर्ष की सजा या 5,000 रुपये का आर्थिक दण्ड या दोनो दिया जा सकता है। 32

सविधान में बयालीसवे संशोधन से माप व भार परिपालन का विषय समवर्ती सूची में आ गया था। इस परिपालन को पूरे देश में एक समान बनाने के लिए माप व भार मानक(परिपालन) अधिनियम—1985 नामक संघीय कानून लाया गया। इसमें ऐसे माप, भार तथा इनमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों एव यन्त्रों पर प्रभावी कानूनी नियन्त्रण की व्यवस्था है। जिनका उपयोग वाणिज्यिक कारोबार, औद्योगिक उत्पादन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व मानव सुरक्षा में होता है। मत्रालय द्वारा जारी समान प्रस्तावित नियमों को अधिकाश राज्यों ने अधिसूचित कर दिया है। कुछ राज्य ऐसा करने वाले हैं। 33

## (ञ) उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-1986 -

उपभोक्ता के हितों की देखभाल करना तथा उसके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना ही उपभोक्ता सरक्षण कहलाता है। प्रभावशाली उपभोक्ता सरक्षण हेतु व्यवसायी, सरकार तथा उपभोक्ता तीनों को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भारत में उपभोक्ता सरक्षण के लिए सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण प्रयास किये गये, पहला— पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजिनक क्षेत्र का विकास एव विस्तार तािक उत्पादन बढाकर, उत्पादन एव पूर्ति में समन्वय स्थापित कर, उचित मूल्य पर वस्तुए या सेवाए उपलब्ध कराकर, निजी एकािधकार को नियन्त्रित कर, वितरण व्यवस्था में सुधार लाकर उपभोक्ता के कल्याण की अभिवृद्धि की जा सके। दूसरा— सरकार ने वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, पूर्ति, वितरण, मूल्य तथा गुणवत्ता की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई अधिनियम पारित किया है। तीसरा— उपभोक्ता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने सार्वजिनक वितरण प्रणाली का विकास किया है।

उपभोक्ता सरक्षण हेतु इस अधिनियम से पूर्व सरकार द्वारा किये गये प्रयासो को निष्फल तो नहीं कहा जा सकता परन्तु इन प्रयासो का परिणाम आशानुरूप नहीं रहा है। जन उपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र लगभग एकाधिकार की स्थिति में होने के बावजूद इनका निष्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा। कुछ कानून जैसे, एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम आदि सार्वजनिक उपक्रमों की दशा में लागू नहीं होते और जो लागू भी होते हैं उनकी जटिल प्रक्रिया के कारण इनका सदुपयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए अन्य बहुत से अधिनियम उपलब्ध है, परन्तु इन

<sup>32</sup> विपणन, विक्रय कला एव विज्ञापन-जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या-161

<sup>33</sup> भारत-1993, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ सख्या-460

अधिनियमो के जटिल प्रक्रिया के कारण इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध प्रावधानो का प्रभावी क्रियान्वयन एव अनुपालन नहीं हो पाया। इससे प्रभावित होकर सरकार ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण एव प्रभावकारी अधिनियम 'उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-1986' पारित किया है।

उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-1986, 24 दिसम्बर,1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम में इस बात के लिए प्रावधान किये गये हैं कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता परिषदों का गठन किस प्रकार किया जायेगा। उपभोक्ता से सम्बन्धित विवादों के निपटारें के लिए इस अधिनियम में अधिकारयुक्त अभिकरणों के गठन की व्यवस्था भी की गई है।इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत् है-

- (अ) <u>अनुचित व्यापार व्यवहार</u> इस अधिनियम के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार का आशय वही है जो एकाधिकार एव प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम-1969 की धारा-36(ए) में वर्णित है। धारा-36(ए) के अनुसार अनुचित व्यापार व्यवहार से आशय उस व्यवहार से हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु के पूर्ति, प्रयोग या विक्रय बढाने या सेवाओं के प्रावधान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कोई भी कार्य किया गया हो तथा जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं से उपभोक्ता को हानि अथवा चोट पहुँची हो, चाहे प्रतियोगिता को प्रतिबन्धित किया गया हो अथवा अन्यथा किया गया हो—<sup>34</sup>
- (1) विवरण देने का व्यवहार चाहे वह लिखित या मौखिक रूप से दिया गया हो अथवा देखे जाने वाले प्रतिबन्धात्मक कार्य किये गये हो जिसमे—
- 1 गलत वर्णन किसी विशेष प्रकार के प्रमाप, गुण, स्तर,ढॉचे, प्रतिरूप अथवा शैली के सम्बन्ध में है।
  - 2 गलत वर्णन करके कि, सेवाए किसी विशेष प्रकार के प्रमाप गुण अथवा स्तर की है।
- 3 किसी वस्तु को पुननिर्मित, द्वितीय स्तर की, नवीनीकरण करके या पुरानी वस्तु को गलत वर्णन करके नई वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया हो।
- 4 यह वर्णन करके कि वस्तुए अथवा सेवाए प्रायोजकता, स्वीकृत निष्पादन, विशेषताए, सहायक औजार, प्रयोग अथवा लाभ से परिपूर्ण है जो कि सामान्यतया इस प्रकार की वस्तुए नही रखती है।
- 5 यह वर्णन किया जाता है कि विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता, स्वीकृति अथवा मान्यताप्राप्त है जो कि अभी तक इस प्रकार के विक्रेता अथवा पूर्तिकर्ता के पास नहीं था।
- 6 वस्तुओ या सेवाओ की उपयोगिता अथवा आवश्यकता के बारे मे गलत या भ्रामक वर्णन किया जाता है।
- 7 जनता को किसी वसतु अथवा उत्पाद के जीवन काल, प्रभाव या निष्पादन के बारे में कोई गारण्टी दी गई हो लेकिन व्यवहार में ऐसी गारण्टी बिना किसी पर्याप्त अथवा अपर्याप्त परीक्षण के दी गई हो।

  34 राज्य एवं व्यवसाय—जगदीश प्रकाश, कक्कड एवं शुक्ल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद—1991 पृ स-469

8 जब जनता को इस प्रकार गलत वर्णन करके यह गारण्टी या आश्वासन दिया जाता है कि वस्तु के एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करने से पहले किसी प्रकार के दोष आने पर उस वस्तु की मरम्मत अथवा उसको बदल दिया जायेगा जबकि व्यवहार में ऐसा कार्य न किया गया हो।

- 9 पदार्थरूप मे वस्तु के मूल्य के बारे मे जनता को भ्रमित किया गया हो।
- 10 दूसरे व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली वस्तु को घटिया बताना अथवा उसके बारे मे गलत या भ्रामक तथ्य देना।
- (2) समाचार पत्रो मे किसी क्स्तु को विक्रय अथवा पूर्ति करने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया जाता है जबिक बाजार की प्रकृति, व्यवसाय का आकार एव प्रकृति तथा विज्ञापन को देखते हुए इस बात का पता चलता है कि वस्तुओ अथवा सेवाओ को उस मूल्य पर देने का कर्तई विचार नहीं था।
  - (3) इस बात की अनुमति दी जाती है कि-
- (अ) उपहार, पुरस्कार अथवा अन्य वस्तुओं का प्रस्ताव किया जाना, जबिक ऐसा देने का कोई विचार नहीं है अथवा इस प्रकार की भावना विकसित की जा रही है कि कुछ वस्तुए नि शुल्क दी जा रही है, जबिक उनका मूल्य लेन-देन वाले मूल्य में पहले से शामिल है,
- (ब) व्यवसाय हित अथवा उत्पाद की पूर्ति, प्रयोग या बिक्री, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढाने के लिए किसी प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल या अवसर का खेल सगठित करना।
- (4) वस्तुओं के विक्रय या पूर्ति की अनुमित देना जिनकों कि उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, इस बात को जानते हुए कि जो वस्तु बेची जा रही है वह सक्षम अधिकारी द्वारा स्तर,गुण निर्माण, प्रतिरूप आदि को पूरा नहीं करती है और जिससे उपभोक्ताओं को हानि या चोट पहुँचने की आशका है।
- (5) ऐसी वस्तुओं की जमाखोरी करना अथवा विनिष्टता को बढावा देना जिन्हें कि विक्रय के लिए उपलब्ध किया जाता है इस आशय से कि उस वस्तु अथवा उसी तरह की अन्य वस्तुओं का मूल्य बढ जाना है।
- (ब) उपभोक्ता सरक्षण परिषदे इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत उपभोक्ता के हितो की रक्षा के लिए सरक्षण परिषदों के गठन का प्रायधान किया गया है। ये परिषदें निम्न दो प्रकार की होती है—
  - 1 केन्द्रीय उपभोक्ता सरक्षण परिषद धारा-4(2) के अनुसार इस परिषद मे निम्न सदस्य होगे-
- केन्द्रीय सरकार के खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रभारी मन्त्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे।
- 2 विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यो की नियुक्ति की जायेगी, जिनकी सख्या सरकार निर्धारित करेगी।

यह परिषद वर्ष मे कम से कम तीन बार अपनी बैठक बुलायेगी।

केन्द्रीय परिषद के उद्देश्य - धारा-6 के अनुसार यह परिषद उपभोक्ताओं के अग्रलिखित अधिकारों

की रक्षा एव प्रवर्तन से सम्बन्धित कार्यवाही का अनुपालन सुनिष्टिचत करेगी-

- 1 जीवन एव सम्पत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं के विपणन के विरुद्ध सरक्षित होने का अधिकार।
- 2 वस्तुओं के मूल्य, प्रमाप, शुद्धता, क्षमता, मात्रा तथा गुण आदि के बारे में सूचित होने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ता की सुरक्षा की जा सके।
- 3 प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यो पर वस्तुओ की विभिन्न किस्मो तक यथासम्भव पहुँच को सुनिश्चित करने का अधिकार।
- 4 उपयुक्त स्तरो पर उपभोक्ता हितो पर ध्यान देने को सुनिश्चित एव अपनी बात कहने का अधिकार।
- 5 अनुचित व्यापार व्यवहार या धोखाधडी से उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने का अधिकार।
  - 6 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
- 2 राज्य उपभोक्ता सरक्षण परिषद राज्य सरकारे आदेश जारी करके राज्य उपभोक्ता सरक्षण परिषद का गठन करेगी। सरकार परिषद के लिए सदस्यों की सख्या का निर्धारण समय—समय पर अपने आदेश द्वारा करेगी। धारा—7 में वर्णित राज्य में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एव प्रवर्तन का कार्य राज्य परिषदे देखेगी।
- (स) <u>उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण –</u> धारा–9 के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए निम्न अभिकरणो का गठन किया जायेगा—
- (क) उपभोक्ता विवाद निवारण मच इसकी स्थापना'जिला मच' के नाम से राज्य के प्रत्येक जिले मे राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमित लेकर की जायेगी।
- (ख) <u>उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग</u>=इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व अनमति लेकर की जायेगी जिसे 'राज्य आयोग' के नाम से जाना जायेगा।
  - (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग इसकी स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी।
- (क) जिला मच की सरचना -1 धारा-10 के अनुसार प्रत्येक जिला मच में निम्नलिखित सदस्य होगे-
- 1 एक व्यक्ति जो जिला जज हो अथवा जिला जज के योग्य हो का नामाकन राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष के रूप में किया जायेगा।
  - 2 एक व्यक्ति जो शिक्षा, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो।
  - 3 एक सामाजिक कार्यकर्ता।

- 2. जिला मच का प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष तक या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो तक पदधारण करेगा और ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं होगे।
- 3. सदस्यों का वेतन अथवा मानदेय तथा अन्य भत्तों का निर्धारण तथा सेवा शर्तों का नियमन राज्य सरकार करेगी।

जिला मच का कार्यक्षेत्र — अधिनियम के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिला मच 1 लाख रुपये तक के वस्तुओं अथवा सेवाओं नथा क्षिति पूर्नि के दावों के सम्बन्ध में शिकायतों को देखेगा। स्थानीय सीमा के अन्तर्गत आने वाली शिकायते जिला मच को प्रस्तुत होगी।

- (ख) <u>राज्य आयोग की सरचना -1</u> धारा -16 के अनुसार प्रत्येक राज्य आयोग मे निम्न व्यक्ति इसके सदस्य होगे-
- 1 एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जज हो अथवा रहा हो, की नियुक्ति राज्य सरकार अध्यक्ष के रूप मे करेगी।
- 2 दो अन्य सदस्य जो योग्य, सत्यनिष्ठ तथा प्रतिष्ठित हो तथा उन्हे अर्थशास्त्र, कानून, विषाज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, जनसम्पर्क अथवा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओ का पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव हो। इस प्रकार के सदस्यों में से एक महिला सदस्य होगी।
- 2. इस प्रकार के सदस्यों का कार्यकाल, वेतन अथवा मानदेय एवं अन्य भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

<u>राज्य आयोग का कार्यक्षेत्र</u> — अधिनियम के अन्य प्रावधानो को देखते हुए राज्य आयोग का कार्यक्षेत्र निम्न होगा—

- (अ) उन शिकायतो एव विवादो का निपटारा करना जो वस्तुओ अथवा सेवाओ के एक लाख रूपये से अधिक तथा 10 लाख रूपये तक के मूल्य से सम्बन्धित है अथवा क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित है तथा जिला मच के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना, और
- (ब) ऐसे उपभोक्ता विवादों के अभिलेख को मैंगाना तथा आवश्यक आदेश जारी करना जो जिला मच के समक्ष विलम्बित है, अथवा उनके द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है और राज्य आयोग ऐसा समझता है कि जिला मच ने कानून द्वारा दिये गये अधिकारों का अतिक्रमण किया है अथवा कार्यक्षेत्र अवैधानिक है अथवा इसमें किसी विशेष प्रकार की त्रुटि हो गयी है।
  - (ग) राष्ट्रीय आयोग की सरचना -(1) धारा-20 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग मे निम्न सदस्य होगे-
- 1 एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का जज हो अथवा रहा हो, की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष के रूप मे की जायेगी। यह महत्वपूर्ण है कि यदि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जज को आयोग

में नियुक्त किया जा रहा है तो नियुक्ति के बारे में मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सलाह लेनी आवश्यक होगी।

- 2 चार अन्य सदस्य जा योग्य, सत्यिनिष्ठ एव प्रतिष्ठित हो तथा उन्हे अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, जनसम्पर्क अथवा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओ का पर्याप्त ज्ञान अथवा अनुभव हो। इस प्रकार के सदस्यों में एक महिला सदस्य होगी।
- (2) इस प्रकार के सदस्यों का कार्यकाल, वेतन अथवा मानदेय एवं अन्य भत्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।

राष्ट्रीय आयोग का कार्यक्षेत्र —(अ) उन शिकायतो एव वादो का निपटारा करना जो शिकायते ऐसी वस्तुओ अथवा सेवाओ से सम्बन्धित है जिनका मूल्य या क्षति पूर्ति 10 लाख रुपये से अधिक हो तथा राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों को सुनना,और

(ब) ऐसे उपभोक्ता विवादों के अभिलेख को मँगाना तथा आवश्यक निर्णय अभिनिर्णीत करना जो राज्य आयोग के समक्ष विलम्बित है अथवा उसके द्वारा दिया गया निर्णय है ओर राष्ट्रीय आयोग ऐसा समझता है कि राज्य आयोग ने प्रदत्त अधिकारों अथवा कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया है अथवा निर्णय में किसी विशेष प्रकार की त्रुटि की है।

1993 के सशोधन के अनुसार रेलवे, विद्युत, डाकतार, बैंकिंग व स्वास्थ्य आदि सेवाओ को भी उसकी परिधि में ले लिया गया है। 35

- (द) शिकायतकर्ता ओर उसको प्राप्त होने वाली राहते उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निम्न में से कोई भी शिकायतकर्ता, हो सकता है—
- 1 एक उपभोक्ता या कोई ऐच्छिक उपभोक्ता सघ जो सोसाइटीज रिजस्ट्रेशन अधिनियम,1960 या कम्पनी अधिनियम-1956 या किसी लागू अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत है।
  - 2 केन्द्रीय सरकार,
  - 3 राज्य या केन्द्र शासित सरकार।

इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत से अर्थ शिकायतकर्ता द्वारा लिखित शिकायत से है जो निम्न में से किसी एक या अधिक से सम्बन्धित है—

- 1 किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने से उसे हानि या हर्जाना हुआ है,
- 2 शिकायत में जिस माल का जिक्र है उसमें एक या अधिक कमियों है,
- 3 शिकायत में जो सेवाए लिखी है उनमें कमी है,
- 4 व्यापारी ने श्रिकायतकर्ता से उस मूल्य से अधिक मूल्य लिया है जो माल पर लिखा है या माल

<sup>35</sup> विपणन विक्रय कला एव विज्ञापन-जैन, एस सी , साहित्य भवन आगरा-1994, पृष्ठ सख्या-173

के पैकेट पर लिखा है या जो कानून मे निर्धारित किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने का तरीका साधारण है। वह अपनी शिकायत बिना फीस दिये उचित स्तर पर कर सकता है अर्थात् दावा करने की कोई फीस नहीं है। शिकायत स्वय दी जा सकती है या फिर भेजी जा सकती है। शिकायत सुनने के बाद शिकायतकर्ता को निम्न राहत मिल सकती है—

- 1 प्रतिवादी को कमी दूर करने के लिए कहा जा सकता है,
- 2 माल को बदलने के लिए कहा जा सकता है,
- 3 मूल्य वापस करने के लिए कहा जा सकता है, और
- 4 हानि की क्षति पूर्ति के लिए कहा जा सकता है।

जिला स्तर के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिन के भीतर, कोई भी पक्ष राज्य स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है। राज्य स्तर के विरुद्ध अपील 30 दिन के अन्दर राष्ट्रीय स्तर पर की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

किसी भी स्तर पर अपील करने की कोई फीस नहीं लगती है। अपीलों के शीघ्र निबटारे के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है जो प्रान्तीय व राष्ट्रीय स्तरों की सुनवाई प्रारम्भ होने के पहले दिन से 90 दिन है। जिला मच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा किये गये निर्णय निश्चित समय के अन्दर अपील न होने पर अन्तिम निर्णय माने जायेगे ओर उनका क्रियान्वयन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों में होता है।

(य) अधिनियम की किमियाँ एव सुझाव — समय की माँग को देखते हुए भारत मे भी उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सरकार के सहयोग से सजग हुआ है, परन्तु उपभोक्ता सरक्षण हेतु बनाया गया यह कानून भी पूर्ण नहीं है, जैसे-कार्तिक दास बनाम मार्गन स्टेनले म्युच्युअल फण्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय इस अधिनियम की धारा-14 की व्याख्या में एक निवेशक को उपभोक्ता नहीं माना गया है जब तक कि अश/यूनिट निवेशक को आविण्टत न कर दी गयी हो। 36 अत एक निवेशक को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिल सकता।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडी एक स्थायी ससदीय सिमिति ने अगस्त-1994 में सदन में प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये हैं जिससे इस अधिनियम के अनुपालन में आ रही समस्याये स्वत उजागर होती हैं-

\* जिला उपभोक्ता अदालतो में लगभग 3 5 लाख मुकदमें लम्बित है। ये अदालते मुश्किल से औसतन 35 प्रतिशत मुदकमें निबटा सकी है।

<sup>36</sup> नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली, 18 अगस्त-1994

- 🗴 लगभग 16 प्रतिश मुकदमे तकनीकी कारणो से खारिज हो जाते है।
- $\star$  राज्य आयोग के 54 प्रतिशत मामले तथा जिला अदालतों के 41 प्रतिशत मामले फैसले की प्रतिक्षा में लिम्बत है।  $^{37}$

इस प्रकार यदि न्याय पाने में इतना विलम्ब होता है तो सामान्य न्याय प्रक्रिया एव उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम की न्याय प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा तथा उपभोक्ता कुठित जीवन—यापन के लिए बाध्य होगा।

अत इस अधिनियम के प्रावधानो को निम्नलिखित सुझावो के माध्यम से और प्रभावी बनाया जाना चाहिए-

\* अधिनियम के उपभोक्ता की परिभाषा में निवेशक को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपना धन किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोजन हेतु प्रस्तुत करता है तथा जिसे प्रतिभूति का आवण्टन नहीं किया जा सका है। अन्यथा उसे इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का लाभ अर्थात् सरल न्याय प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं होगा।

\* सदस्यों की नियुक्ति में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए केवल अनुभवी एव योग्य व्यक्ति ही सदस्य बनाये जाने चाहिए।

\* उपभोक्ता को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी समस्याओं के निदान के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित मच या आयोग का सहयोग ले अथवा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों का सहारा ले।

\* उपभोक्ताओं के लिए क्षित पूर्ति का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ मे आवश्यक प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

\* मामले तकनीकी आधार पर खारिज न हो इसके लिए सार्वजिनक वितरण प्रणाली की देख-रेख के लिए प्रत्येक जिले मे गठित किये जाने वाले प्रस्तावित नियन्त्रण कक्षो मे ही एक अनुभाग उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपील पर सुझाव हेतु बनाया जाना चाहिए जिसमे सरसरी तौर पर पीडित उपभोक्ता को इसबात की जाँच करवाने की व्यवस्था हो कि मामले तकनीकी आधार पर भविष्य मे खारिज तो नहीं होगे।इससे इन अदालतो मे एक ओर लिम्बत विवादों की सख्या में कमी लायी जा सकेगी और दूसरी ओर तकनीकी आधार पर खारिज होने वाले विवादों का प्रतिशत भी कम हो जायेगा।

\* वातावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यक उपायो की भी व्यवस्था इस अधिनियम मे की जानी चाहिए। इससे जल,वायु तथा ध्विन से सम्बन्धित प्रदूषण को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

<sup>37</sup> नवभारत टाइम्स-नई दिल्ली, 30 अगस्त-1994

\* यदि किसी भी कारणवश कोई हानिकारक उपभोक्ता सामग्री बाजार में आ जाती है तो उसे तुरन्त जब्त करने का अधिकार प्रशासनिक तन्त्र को दिया जाना चाहिए। इसके लिए अधिनियम में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

\* शहरी एव ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। इससे जनता में उपभोक्ता आन्दोलन के प्रति अपनत्व की भावना जागृति की जा सकेगी।

\* इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों को समन्वित ढग से कार्य करने की आवश्यकता है। इससे उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ आधार दिया जा सकेगा।

यद्यपि इस अधिनियम के समस्त प्रावधानों को लागू कर दिया गया है परन्तु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका कार्यान्वयन कितने प्रभावशाली ढग से किया जाता है। इसके लिए उचित वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है तथा सभी एजेन्सियों, उपभोक्ता सघो तथा सम्बद्धअन्य सघो को आगे आकर सरकार की इस दिशा में सहायता करनी होगी।

## (ट) भारतीय प्रतिभृति एव विनिमय बोर्ड अध्यादेश-1992 -

पूँजी बाजार की अनियमितताओं को दूर करके इसे एक स्वस्थ वातावरण में परिचालित होने देने एव निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 के बजट में "भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड" नामक सस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई थी जिसके अनुरूप 12 अप्रैल, 1988 में एक गैर-साविधिक निकाय के रूप में 'भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड'(एस ई बी आई- सेबी) का गठन किया गया। 30 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश जारी करके "सेबी" को पूर्ण अधिकार प्राप्त साविधिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया। 4 अप्रैल, 1992 को 'सेबी' अधिनियम-1992 पारित किया गया। इसका मुख्यालय बम्बई में हैं तथा तीन क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, दिल्ली एव मद्रास में हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष डा० एस०एस० नाडकर्णी है। 38

(अ) उद्देश्य — अधिनियम की प्रस्तावना में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढावा देना एव उसे विनियमित करना तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों व घटनाओं पर नजर रखना है।इस प्रकार सेबी के निम्न उद्देश्य वर्गीकृत किये जा सकते है—

न्यामियो, पजीयको, मर्चेन्ट बैकर्स, अभिगोपको तथा प्रतिभूति बाजार के अन्य समस्त मध्यस्थो का पजीकरण करना एव उनके कार्यकलापो को विनियमित करना।

- 2 देश के समस्त स्कन्ध विपणियो एव अश बाजारो के समस्त कार्यों को विनियमित करना,
- 3 अश बाजारो से सम्बन्धित अनुचित एव घोखाधडी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना।
- 4 सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी एव निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डो सहित अन्य सामूहिक निवेश योजनाओं के कार्यकलागे को विनियमित करना।
  - 5 प्रतिभूतियो के अन्तरग-व्यापार को नियन्त्रित एव विनियमित करना।
- 6 पूँजी बाजार में कार्यरत विभिन्न मध्यस्थों को व्यापारिक गतिविधियों में दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
- 7 कम्पनियों के अधिग्रहण एवं किसी एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा एक सीमा से अधिक अशों के खरीद को विनियमित करना।
- 8 पूँजी निर्गमन(नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 तथा प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-1956 में प्रदत्त अन्य अधिकारो का उपयोग करना।
- (ब) सेबी का सगठनात्मक ढाँचा इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए सेबी को निम्नलिखित पाँच विभागों में बाँटा गया है—
- 1 <u>प्राथमिक बाजार विभाग –</u> इसमे नीति, मध्यस्थ, स्व—विनियमनकारी सगठन, निवेशको की कठिनाइयो तथा निर्देशन सम्बन्धी कार्यो को सम्पन्न किया जाता है।
- 2 निर्गम प्रबन्धन एव मध्यस्थ विभाग अश बाजार के समस्त मध्यस्थो के पजीकरण, विनियमन, मध्यस्थो से सम्बन्धित मामलो की समीक्षा एव समय-समय पर जारी किए गए निर्गमो के अभिलेखो की जॉच सम्बन्धी कार्य इस विभाग में सम्पन्न होते है।
- 3 <u>द्वितीयक बाजार विभाग –</u> इस विभाग में नीति, सचालन एव विनिमय प्रशासन, अश मूल्य की समीक्षा, बाजार खोज, अन्तरग व्यापार से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं।
- 4 <u>छोटे स्कन्ध विपणियों से सम्बन्धित विभाग</u> देश के छोटे स्कन्ध विपणियों का प्रशासन तथा अन्य गैर-सदस्य मध्यस्थों जैसे-उप दलालों से सम्बन्धित मामलों का निबटारा इस विभाग में किया जाता है।
- 5 <u>सस्थागत निवेश विभाग</u> म्युच्युअल फण्डो तथा विदेशी सस्थागत निवेशको के सम्बन्ध मे नीति निर्माण नियन्त्रण एव विनिमय सम्बन्धी मामले तथा शोध व अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो की सदस्यता सम्बन्धी मामले इस विभाग मे आते है।
  - (स) सेबी की वित्त व्यवस्था वर्ष 1988 में एक गैर विधिक निकाय के रूप में गठित भारतीय

प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की प्रारम्भिक पूँजी 7 5 करोड रुपये थी, जो इसकी प्रवर्तक कम्पनियों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एव निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा बराबर—बराबर दी गई थी। सेबी द्वारा यह धनराशि निवेशित कर दी गयी थी। इस धनराशि से प्राप्त ब्याज की आय से 'सेबी' के दिन—प्रतिदिन के कार्य सचालन सम्बन्धी व्यय पूरे किये जाते है।

- (द) सेबी के प्रावधान सेबी ने स्वस्थ पूँजी बाजार की व्यवस्था हेतु समय-समय पर अनेक प्रावधानों की घोषणा की है जिनका अनुपालन किया जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नवत् है-
- 1 निर्मम जारी करने वाली कम्पनियो द्वारा बिना ब्याज देयताओ वाली आवेदन राशि के उपयोग
  पर नियन्त्रण इस प्रावधान के अन्तर्गत निवेशकर्ता को निर्मम के आवेदन पत्र के साथ बैंको से क्रय
  किए गए 'स्टॉक—इन्वेस्ट' को लगाना होता है। यदि निवेशकर्ता को अश/ऋणपत्र आवण्टित हो जाते हैं तो
  उतनी धनराशि स्टॉक इन्वेस्ट जारी करने वाले बैंक द्वारा सम्बन्धित कम्पनी के खाते में हस्तान्तरित कर दी
  जाती है। अन्यथा उस पूँजी पर निवेशक को एक निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। इस प्रक्रिया
  के अन्तर्गत जहाँ निवेशक को अपनी पूँजी पर अश आवण्टित होने तक ब्याज प्राप्त होता रहता है, वही
  अश आवण्टित न होने पर उसके धन की वापसी भी सुनिश्चित हो जाती है।
- 2 विवरिणका को स्पष्ट करना —अबिनर्गम जारी करने वाली कम्पनी की व्यापारिक गितिविधियों का पूरा विवरण, पूर्व के निर्गमों का विवरण, भावी वायदे व उपलब्धियों, मूल्य एव प्रीमियम निर्धारण का औचित्य तथा जोखिम तत्वों का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक कर दिया गया है। नए नियमों में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी स्तर पर यह पता चलता है कि निर्गम जारी करने वाली कम्पनी द्वारा विवरिणका में कुछ बाते छुपायी गयी है तो उन्हें निवेशकों को प्रतिभूतियों आविण्टित करते समय स्पष्ट करना होगा तथा निवेशकों को यह छूट भी प्रदान करनी होगी कि नई जानकारी के आधार पर यदि वे अपनी पूँजी वापस लेना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं।
- 3 <u>अश के मूल्य व प्रीमियम का निर्धारण</u>— सेबी के नवीन दिशा—निर्देशो के अनुसार भारतीय कम्पनियों अब अपने अश का मूल्य एव उस पर लिए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है, लेकिन शर्त यह है कि मूल्य व प्रीमियम सभी के लिए समान हो तथा इसकी सार्थकता को सिद्ध किया गया हो।
- 4 <u>मर्चेन्ट बैंकर्स के लिए आचार सिहता</u> सेबी ने मर्चेन्ट बैंकर्स के लिए एक आदर्श आचार सिहता जारी की है तािक वे अपने कार्यकलाप निष्पक्षता एव सत्यनिष्ठा के उच्च आदर्शों व मानको के अनुसार सचािलत कर सके। दिसम्बर, 1992 में जारी किए गए प्रावधानों के अधीन उनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों को जारी करने एवं उसका नवीनीकरण करने की शर्तों, पूँजी पर्याप्तता मानको, लेखों के सम्बन्ध में ,

सेबी को व्यापक अधिकार प्राप्त होगे। इसमें मर्चेन्ट बैकर्स द्वारा प्रबन्धित निर्गम के मामले में किसी भी प्रकार की गडबड़ी अथवा अनियमितता होने पर सीधे मर्चेन्ट बैकर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। इस प्रकार की त्रुटियों पर सम्बन्धित मर्चेन्ट बैकर्स के 8 विन्दु हो जाने पर उनके पजीकरण को निलम्बित किए जाने अथवा उसके अधिकार पत्र को वापस लिए जाने जैसी कार्यवाही की जा सकती है।

- 5 अभिगोपको के लिए प्रावधान अब अभिगोपक के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम परिसम्पत्ति सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके साथ—साथ सेबी ने सभी अण्डर राइटर्स को चेतावनी दी है कि निर्गम के गैर अभिदत्त भाग की खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता बरतने पर उनके पजीकरण को रदद किया जा सकता है।
- 6 अश दलालो पर नियन्त्रण यह सर्वविदित है कि 1992 का प्रतिभूति घोटाला मुख्यरूप से अश दलालो की काली करतूतो का परिणाम था। ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेबी द्वारा 1992 मे नये नियम और विनियम जारी किए गये है, जिनमे अश दलालो के पजीयन की शर्ते, सेबी को पजीयन शुल्क का भुगतान, समुचित अभिलेखो का रख—रखाव, अभिलेखो का सेबी के अधिकारियो द्वारा निरीक्षण तथा दोषी पाये जाने पर पजीयन निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रावधान दिए गए है।
- 7 <u>दलालों के लिए पूँजी पर्याप्तता मानक</u> सेबी ने अश बाजार दलालों के लिए पूँजी पर्याप्तता मानक निर्धारित किए हैं, जिनके अनुसार किसी भी स्तर पर किसी भी दलाल का सकल व्यापार उसकी आधारभूत पूँजी तथा अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकताओं के 12 5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। आधारभूत पूँजी से तात्पर्य दलालों द्वारा स्कन्ध विपणि के पास जमा कराई गई धनराशि से हैं। इस धनराशि में 25 प्रतिशत नकद, 25 प्रतिशत बैंक जमा, तथा 50 प्रतिशत स्वतन्त्र प्रतिभृतिया होती है।
- 8 लेन-देन की पारदर्शकता नये प्रावधानों की अधीन दलालों को निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियों के अनुबन्ध पत्रों में अशों का मूल्य तथा दलाली की राशि अलग—अलग दर्शायी जानी चाहिए। सेबी ने स्कन्ध विपणियों को परिपत्र जारी कर स्कन्ध विपणियों को निर्देश दिया है कि वह दलालों को इस बात के लिए बाध्य करे कि वे ग्राहकों के धन को पृथक खातों में जमा करे।
- 9 अन्तरग व्यापार भारतीय पूँजी बाजार में कम्पनियाँ स्वय या उनके कर्मचारी प्राय अन्तरग व्यापार के द्वारा नियमित रूप से अशो के मूल्यों में हेरा—फेरी करते हैं। इस व्यापार के अन्तरग व्यापार को रोकने के लिए 'सेबी' ने भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड(अन्तरग व्यापार) विनियमन, 1992 को अधिसूचित कर दिया है।
  - 10 म्यूच्युअल फण्डो पर सेबी का नियन्त्रण अस्सी एव नब्बे के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र

के बैंको, जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा कम्पनियों ने अनेक म्युच्युअल फण्डों की स्थापना की जिनमें निवेशकों को बैंक से ऊँची दर पर प्रतिफल दिये जाने का आकर्षण दिया गया। सेबी ने (म्युच्युअल फण्ड) विनियमन, 1993 जारी करके सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डों को सेबी'के नियन्त्रण में ले लिया गया है। ताकि इनके सचालन मानकों तथा कार्यविधियों में एकरूपता लायी जा सके। प्रावधान है कि म्युच्युअल फण्ड स्थापित करने वाली कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति 5 करोड रुपये होनी चाहिए जिसमें प्रायोजकों का अभिदान कम से कम 40 प्रतिशत हो।

- 11 <u>वायदा कारोबार पर रोक</u> 'सेबी' ने 14 दिसम्बर, 1993 को वायदा कारोबार पर रोक लगाते हुए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली व अहमदाबाद के स्कन्ध विपणियों को आदेश दिया है कि तात्कालिक प्रभाव से सभी सौदों में सुपुर्दगी और भुगतान की व्यवस्था लागू की जाए एव 'बदला' की सुविधा न दी जाए। यदि कोई दलाल इस आदेश को मानने से इन्कार करता है तो उसके बकाया सौदों को 'हवाला' बाजार में नीलाम कर दिया जाए।
- 12 ऋणपत्र न्यासी बनने की प्रक्रिया में सशोधन अब भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड से पजीकरण का प्रमाणपत्र लिए बिना कोई भी ऋणपत्र न्यासी का कार्य नहीं कर सकता। ऋणपत्र धारकों के हितों की सुरक्षा हेतु ऋणपत्र न्यासी पर अनेक उत्तरदायित्व डाले गये हैं। ऋणपत्रों को पूँजी बाजार में बेचने के लिए जारी करने से पूर्व ऋणपत्र न्यासी को एक कम्पनी के साथ न्यास सिन्ध करनी होगी जिसमें ऋणपत्र धारकों के शिकायतों को दूर करने के लिए स्पष्ट प्रावधान करने होगे। दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करेगे कि ऋणपत्रों के पुनर्भुगतान अथवा उनके अशों में बदले जाने में ऋणपत्र धारकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- (य) किमियाँ भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड के नये अध्यादेशों ने भारतीय पूँजी बाजार की अनेक किमयों का पता लगाकर उनके निराकरण हेतु सार्थक उपाय किए है। पूँजी बाजारों में कार्यरत सभी प्रकार के मध्यस्थों की गतिविधियों का यथासम्भव नियन्त्रण एव विनियमन किया है, फिर भी कुछ मामलों में 'सेबी' को यथोचित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है।

इसे सबसे कम सफलता निवेशको की दिन—प्रतिदिन की समस्याओ, जैसे-निर्गम जारी करने वाली कम्पिनयों से प्रमाण पत्र तथा वापसी आदेश प्राप्त न होना, लाभाश आदि का भुगतान प्राप्त न होना इत्यादि का निराकरण करने में ही मिली है। वर्ष 1993 के प्रथम 9 माह में 'सेबी' को लगभग 4 लाख शिकायते निवेशको की ओर से प्राप्त हुई जिसमें से केवल 1 6 लाख शिकायतों का निराकरण हो पाया। इस प्रकार लाखों शिकायते बोर्ड में लिम्बत है। 39 इस मामले में 'सेबी' की शिक्तयों सीमित है। निवेशक की किसी भी

<sup>39</sup> प्रतियोगिता दर्पण-अप्रैल, 1994, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा, पृष्ठ सख्या-1193

शिकायत का निराकरण न करने की दशा में दोषी कम्पनी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का अधिकार सेबी' क पास नहीं है। यह अधिकार अभी भी भारत सरकार के कम्पनी मामलों के विभाग के पास ही है।

कुछ अन्य मामलो, विशेष रूप से अश बाजार में कार्यरत विभिन्न मध्यस्थों की कार्यप्रणाली में समय— समय पर परिवर्तन करने तथा तदनुसार दिशा निर्देश जारी करने में 'सेबी' की कार्य प्रणाली की आलोचना की जाती है। अश कारोबार से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि 'सेबी' अश बाजार में कार्यरत मध्यस्थों को विश्वास में लिए बिना एक पक्षीय निर्णय लेकर नियमों में परिवर्तन करके अचानक ही सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को प्रभावित कर देती है। जब इन निर्णयों का विरोध होता है तब इसमें संशोधन कर दिये जाते हैं।

(र) सुझाव — नि सन्देह अपनी स्थापना के प्रथमतीन वर्ष मे ही 'सेबी' ने एक सुसगठित एव विनियमित पूँजी बाजार उपलब्ध कराया है। भारतीय पूँजी बाजार पर भारतीय एव विदेशी दोनों के निजी एव सस्थागत निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। 'सेबी' ने इनके अधिकारों के सुरक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई है। आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से भूमण्डलीकरण होने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी दशा में 'सेबी' की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी अत उसे सम्पूर्ण पूँजी बाजार के कारोबार पर तीक्ष्ण एव दूरगामी दृष्टि रखते हुए ऐसे उपाय करने होगे। जो निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ—साथ देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सके। इसके लिए 'सेबी' को अपने कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार लाना होगा तथा अपनी भूमिका को पर्यवेक्षण व नियन्त्रण सस्था के साथ—साथ परामर्शदात्री सस्था के रूप में विकसित करना होगा साथ ही साथ इस साविधिक सस्था को किसी भी मामले पर निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित पक्षों पर विस्तृत विचार विमर्श करना होगा। निश्चय ही इन प्रयासों से भारतीय पूँजी बाजार अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूरा कर पायेगा।

# पंचम्-सर्ग समस्यारं रवं सुझाव

## पचम-सर्ग

### समस्याए एव सुझाव

समतावादी समाज की स्थापना में प्रयासरत आज के विश्व की समस्त सरकारों के लिए, देश के सन्तुलित आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास हेतु व्यापारिक क्रियाओं में स्वयं की भागीदारी अपरिदार्य हो गयी है। विश्व के आर्थिक परिदृश्य में हो रहे तीव्र परिवर्तन, पूँजीवादी एवं समाजवादी देशों के रिश्तों में तेजी से आ रहे परिवर्तन तथा बढ रहे व्यापारिक भूमण्डलीकरण के दौरान विश्व बाजार में अपने उतपादों को प्रस्तुत करने तथा उनकी उपयोगिता को सिद्ध करने की चुनौती, विश्व के अधिकाश देशों के समक्ष खड़ी है। स्पष्ट है कि आने वाले समय में देश एवं समाज के बहुमुखी विकास तथा आर्थिक सुदृढता के लिए व्यापार की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी।

व्यापारिक क्रियाओं में उत्पादक, उपभोक्ता, समाज एवं सरकार सभी का हित विद्यमान होता है। व्यापारिक क्रियाओं से सम्बद्ध समस्त पक्षों के हित की सुरक्षा का अधिक दायित्व तुलनात्मक रूप से सरकार का ही होता है। इस पवित्र एवं कठोर उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए ही कल्याणकारी सरकार व्यापारिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार सरकार या तो स्वय व्यापारिक क्रियाओं में भाग लेती है अथवा व्यापारिक क्रियाओं में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से नियन्त्रण रखती है। किन्तु व्यापार में राजकीय हस्तक्षेप उसकी स्वतन्त्रता एवं मुक्ति हनन में खतरनाक राजनैतिक एवं सामाजिक मंशाओं की सम्भावनाए भी प्रकट करता है। कई बार राजकीय हस्तक्षेप विशिष्ट दशाओं के अन्तर्गत आर्थिक विकास में बांधा डालता है और आर्थिक गतिहीनता एवं गिरावट का कारण बन जाता है। सम्भवत इसी समायोजन हेतु भारत की वर्तमान सरकार ने आर्थिक एवं व्यापारिक उदारीकरण के अनेक पैकेंजों की घोषणा की है तथा कई व्यापारिक नियन्त्रणों में ढील दी गयी है।

नि सन्देह वर्तमान भौतिकवादी युग मे अर्थ की प्रधानता ने स्वार्थ को सर्वोपिर बना दिया है तथा नैतिक मूल्यो का हास होता जा रहा है। व्यापारी वर्ग अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्न निन्दनीय कृत्यो द्वारा उपभोक्ताओं का बहुविधि शोषण करता हुआ सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। देश के कोने—कोने में बिखरा हुआ उपभोक्ता, सगठन शक्ति के अभाव में व्यापारी वर्ग द्वारा किये जा रहे उसके शोषण को परिस्थितिजन्य मानकर एक मूक दर्शक के रूप में स्वीकार करता है। फलस्वरूप अनन्य नियमो एव नियन्त्रणों के बावजूद व्यापारी वर्ग विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्यों में लीन रहता है। उपभोक्ताओं में जागरूकता तथा उनमें व्यवस्थित सगठन के बिना उपभोक्ता के हितों की रक्षा असम्भव प्रतीत होती है। राष्ट्रीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता का सरक्षण करना है। कभी—कभी सरकार द्वारा व्यापार में अपनी भागीदारी निभाने के बाद भी उपभोक्ता सन्तुष्ट नहीं हो पाता।सरकार द्वारा व्यापार में भाग

लेने के सम्बन्ध में जो नीतियाँ निर्धारित की जाती है उनका सफल क्रियान्वयन न हो पाने के कारण राज्य की व्यापार में भागीदारी का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

भारत में ही नहीं बल्क विदेशों भी व्यापारिक समुदाय स्वतन्त्रत व्यापार का पक्ष धर रहा है। राजकीय व्यापार जनहित की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है परन्तु व्यापिर वर्ग इस मान्यता में विल्कुल विश्वास नहीं करता। सरकार ने समय—समय पर अनेक नियमों एव विनियमों के माध्यम से व्यापारिक व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया परन्तु ऐसे परिवर्तन का विरोध हमेशा किया गया। हमारे देश के व्यापारियों ने सदैव अवसर का लाभ उठाया है। अनेको बार वह जनहित की अवहेलना करने में भी नहीं चूका है। हालात् यह है कि राजकीय हस्तक्षेप और कठोर कानूनी व्यवस्था के बावजूद व्यापारी वर्ग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति में विलम्ब नहीं करता, फिर भी राजकीय हस्तक्षेप के अभाव स्वतन्त्र व्यापार की स्थित की क्या कल्पना की जा सकती है? सम्भवत इस बात से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि निजी हितों की अपेक्षा सार्वज़िनक हित कहीं अधिक महत्वपूर्ण एव आवश्यक है।

हमारे देश मे विपणन के पर्याप्त कानूनी नियमन और नियन्त्रण के बाद भी व्यापारिक वातावरण समाज के अनुकूल नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण कानूनों के सख्यात्मक विस्तार की तुलना में उनका कार्यान्वयन उपेक्षित रहना है। अनेक कानूनों में कुछ छिद्र है जिनके कारण व्यवसायों को अनैतिक व्यवहार करने का रास्ता मिल जाता है। वास्तव में व्यापार में राजकीय भागीदारी, जो कि व्यापारिक कानूनों में हस्तक्षेप के माध्यम से भी सम्पन्न होती है, का स्पष्ट उद्देश्य सामाजिक दृष्टि से हितकारी प्रवाहों को नियमित करने के लिए प्रमाप निश्चित करना तथा निर्धारित प्रमापों की व्याख्या करना और व्यापारिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करना होना चाहिए, जिससे कि सरकार व्यापारिक गतिविधियों पर बाछित नियन्त्रण कर सके।

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण प्रणाली को सुगम बनाने तथा समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता की वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा देश में सार्वजिनक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है जिससे कि जनकल्याण में वृद्धि की जा सके। परन्तु व्यावहारिक रूप में सार्वजिनक वितरण प्रणाली गरीब उपभोक्ताओं की आकाक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को न तो अच्छी वस्तुए मिल पाती है और न ही अधिकतम सन्तुष्टि। इसका कारण यह है कि वास्तव में इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को जो भी वस्तुए प्राप्त होती है उनकी गुणवत्ता इतनी कम होती है कि उसका उपभोग करना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

भारत मे गरीबी चरम सीमा पर है तथा आय की असमानता के दुष्परिणामस्वरूप समाज का बडा-

वर्ग गरीब है। न्यूनतम आय के कारण वह उचित मूल्य की दुकानों से ऐसी वस्तुए प्राप्त करता है जो कि वास्तव में उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त नहीं रहती है। अतएव सरकार द्वारा यह दावा करना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता—वस्तु वितरण की एक सफल प्रणाली है, उचित प्रतीत नहीं होता। इसके सफलता की आश्चिक कल्पना इसलिए पूरी होती है कि भारतीय उपभोक्ता खाद्यान्नों के उपभोग में लापरवाही बरतता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुए अधिकाश भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा केवल इसलिए उपभोग कर ली जात है क्योंकि उनका मूल्य कम होता है, भले ही वे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त न हो। चूँिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चालू रखने के लिए सरकार द्वारा बहुत अधिक राज सहायता दी जात है। अत इस प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य खुले बाजार के मूल्य से अधिकाश मामलों में कम तो होता है परन्तु यह मूल्य वस्तुओं की गुणवत्ता को देखते हुए अधिक ही प्रतीत होता है।

सरकार ने समता, समानता एव शोषण विहीन समाज की सकल्पना को साकार करने के लिए व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है और कानून के माध्यम से अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को नियन्त्रित करने का भी प्रयास किया है, परन्तु सरकार को इस कार्य में आशिक सफलता ही मिल पायी है। इस सफलता के बाधक तत्व तथा राजकीय व्यापार में आने वाली समस्याए इस प्रकार है—

- (क) राजकीय व्यापार में आचार सहिता का अभाव सरकार ने जिन व्यापारिक क्रियाओं में भाग लिया है उनमें उसने स्वय न तो विपणन की कोई आचार सहिता तैयार की है न ही उसने आदर्श आचार सिहता का पालन किया है। सरकार उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने में पूरी तरह सफल नहीं रही। वैकल्पिक विपणन नीतियों और व्यवहारों के प्रभावों से किसानों, उपभोक्ताओं और विपणन अभिकरणों को परिचित कराने के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण, आचार सिहता का अपनाया जाना आवश्यक है, किन्तु सरकार की नीतियों इतनी भ्रामक है कि उनका सहीं कार्यान्वयन नहीं हो पाता। अत व्यापार के क्षेत्र में पर्यान्त आचार सिहता तैयार किये बिना और उनका पूर्णतया पालन किये बिना राजकीय व्यापार में भागीदारी अथवा कानून द्वारा उस पर नियन्त्रण का वास्तिवक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता।
- (ख) <u>अधिनियमों की अधिकता एवं उनकी किमयों</u> सरकार ने व्यापारिक क्रियाओं को नियन्त्रित करने एवं जन कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्न अधिनियमों को पारित किया किन्तु ये अधिनियम अपनी जटिलता के कारण व्यापारिक वातावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभा सके। एक अधिनियम का दूसरे अधिनियम से न तो कोई सामञ्जस्य है और न ही ये स्वतन्त्र रूप से स्वचालित है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु तथा समाज में व्याप्त जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारापारित किये गये विभिन्न प्रकार के अधिनियम अधिक

प्रभावशाली नहीं रहे, जिसका मुख्य कारण कानूनों के सख्यात्मक विस्तार की तुलना में उनके अनुपालन पक्ष का उपेक्षित होना रहा है। निश्चय ही कानून बनाना महत्वपूर्ण है, परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका कठोरता से अनुपालन होता है। भारतवर्ष में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में अधिनियम बनाये गये किन्नु ये अधिनियम सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सफल नहीं हो पाये हैं। अनेक विनियमों में कुछ न कुछ किमयाँ रह गयी है जिससे व्यापारियों को अनैतिक व्यवहारों को अपनाने का अवसर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। विभिन्न अधिनियमों के पारित हो जाने के बाद भी उनमें पायी जाने वाली कुछ किमयाँ इस प्रकार है—

- उपभोक्ताओं को शुद्ध, सही एवं उचित वस्तुए उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम—1954 पारित किया गया किन्तु आज भी व्यवसायियों द्वारा तेल, ची, दूध, अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों, इत्यादि वस्तुओं में व्यापक स्तर पर अपिमश्रण का कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ता वर्तमान समय में भी शुद्ध वस्तुए प्राप्त न होने से सदैव असन्तुष्ट रहता है।
- सभी आवश्यक वस्तुओं की नियमित पूर्ति बाजार में बनी रहे इसके लिए सरकार ने कुछ वस्तुओं की सूची के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 लागू किया जिसमें जुलाई—1994 के बाद कुल 44 वस्तुए रह गयी है। जो वस्तुए इस सूची में शामिल है उनकी पूर्ति भी कभी—कभी बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं होती और व्यापारियों द्वारा विक्रय से मना कर दिया जाता है, भले ही वे गोदाम में अथवा स्टॉक में कालाबाजारी के लिए उपलब्ध हो।
- उपभोक्ताओं कोउचित तौल एव माप के आधार पर वस्तुए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बाट एव माप मान अधिनियम-1976 बनाया गया जिससे कि उपभोक्ताओं को सही माप-तौल या अक में वस्तुए मिल सके। किन्तु यथार्थ में आज भी व्यापारियों द्वारा गैर-मान बाट या माप का प्रयोग किया जाता रहा है। इनके द्वारा अधिकृत कैश मेमो,बिल या बीजक आदि आम तौर पर बनाया जाता है और इस तरह उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है।
- भारत में ट्रेंड मार्क के पजीकरण हेतु एक अधिनियम—1958 में 'व्यापार एव व्यापारिक चिह्न अधिनियम' के नाम से पारित हुआ। इसके अधीन निर्माता अपनी क्तु की पहचान एव उसका नाम याद रखने के लिए कोई चिह्न, नाम, शब्द, डिजायन या इने सिम्मश्रण से कोई चिह्न या नाम बनाकर अपनी क्तुओं पर छाप देता है, जिसे ब्राण्ड कहते हैं। ब्राण्ड का पजीकरण हो जाने पर इसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। इसकी नकल कोई दूसरा व्यापारी नहीं कर सकता। किन्तु व्यवहार में आज एक व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी के ट्रेडमार्क की नकल की जा रही है। यहाँ तक कि भारत की राजधानी दिल्ली में खुले बाजार में विभिन्न ब्राण्ड अथवा ट्रेडमार्क की डुप्लीकेट क्तुए सुगमता से मिल जाती है। इस तरह उपभोक्ता ऐसे

जालसाजी का सुगमता से शिकार हो जाता है।

- इसी प्रकार एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम—1969' का उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि देश की आर्थिक प्रणाली सामान्य हितो के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं करती है और ऐसे एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक प्रतिबन्धों को रोकना है जो कि जनहित के विरुद्ध है परन्तु इस अधिनियम का दुष्प्रभाव हमारे उद्योगों के विकास पर पड़ा है। क्योंिक नई औद्योगिक नीति—1991 घोषित होने से पूर्व नई स्थापित होने वाली कम्पनियों की सम्पत्ति सीमा 20 करोड़ रुपये तथा सम्बद्ध होने वाली कम्पनियों की सम्पत्ति सीमा 100 करोड़ रुपये होने से छोटी कम्पनियों के विस्तार का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता था। अधिनियम के प्रावधानों की कठोरता के कारण विनियोग प्रस्तावों के अनुमोदन में विलम्ब होने से औद्योगिक विकास की गित प्रभावित होती थी। इस अधिनियम के व्यवस्थाओं के कारण निर्यात सम्बर्द्धन को पर्याप्त प्रोत्साहन न मिल सका, बड़े औद्योगिक घरानों के आर्थिक सकेन्द्रण पर अनियन्त्रण भी नहीं किया जा सका। साथ ही उत्पादकता में आवश्यक सुधार, आयात, प्रतिस्थापन तथा पिछंड़ क्षेत्रों के विकास जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी वाछित सफलता नहीं मिल सकी।
- उद्योगों का सन्तुलित विकास करने के उद्देश्य से पारित किया गया औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम—1951 ने औद्योगिक समस्याओं को बढाने, राजकीय पूँजीवाद को प्रोत्साहित करने तथा बडे औद्योगिक घरानों के एकाधिकार में वृद्धि करने का ही कार्य किया है।
- उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने एवं उन्हें सरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा' उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-1986', 24 दिसम्बर, 1986 से लागू किया गया किन्तु इस अधिनियम की व्यवहारिकता भी सदिग्ध है। अभी तक आम जनता उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम की व्यवस्थाओं और मिलने वाली राहतों तथा राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया से पूर्णतया परिचित नहीं है। अतएव इस अधिनियम के द्वारा भी उसके शोषण की सम्भावना कम नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त 3 5 लाख मामलों का इन अदालतों में लिम्बत होना, 16 प्रतिशत मामलों का तकनीकी आधार पर खारिज हो जाना, एक निवेशक को उपभोक्ता न माना जाना इत्यादि ऐसे तथ्य हैं जो त्वरित न्याय व्यवस्था की किमयों को स्पष्ट करते है।
- -- पूँजी बाजार को नियमित करने के लिए लाया गया भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड अध्यादेश-1992 निवेशको की शिकायते दूर करने मे पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है जिसका कारण एक ओर तो दण्डात्मक कार्यवाही का अधिकार इसके पास न होना तथा दूसरी ओर नियमों में परिवर्तन की एक पक्षीय कार्यवाही करना रहा है।

इस प्रकार विभिन्न कानून सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा एव कल्याण के उद्देश्य से बनाये गये, किन्तु इन कानूनों में कमी एवं छिद्रता होने के कारण एक पक्ष द्वारा मनमानी की जाती है, साथ ही कानूनों का पालन न करने पर समुचित दण्ड की व्यवस्था भी नहीं है और यदि दण्ड दिये भी जाते हैं तो वह इतने कम होते हैं कि व्यवसायी को इनका कोई विशेष भय नहीं रहता है।

- (ग) <u>दोषपूर्ण राशनिग व्यवस्था</u> वर्तमान राशनिग व्यवस्था अनेक दोषो से युक्त है, जो इस प्रकार है–
- राशिनग व्यवसथा मे व्याप्त कुप्रबन्ध एव भ्रष्टाचार के कारण इसमे खाद्यान्नो की आपूर्ति नियमित नही रहती है। राशिनग की दुकाने माह मे केवल कुछ दिन खुलकर शेष दिन बन्द रहती है जिससे दुकानो के खुलने पर भीड लग जाती है और उपभोक्ताओं को एक लम्बे समय तक अपने क्रम की प्रतीक्षा करनी पडती है। इस प्रकार उपभोक्ता को वस्तु प्राप्त करने में लगने वाले समय की हानि उसके उचित मूल्य पर वस्तु की उपलब्धता से मिलने वाला लाभ, बराबर हो जाता है।
- राशिनग व्यवस्था के माध्यम से केवल सीमित सख्या में ही वस्तुए उपभोग हेतु उपलब्ध हो पाती है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता खाद्यान्नों का चयन अपनी रुचि के अनुसार नहीं कर पाता है और व्यवस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुओं का ही उपभोग करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवस्था में खाद्यान्नों के प्रतिस्थापन की सुविधा नहीं रहती।
- राशिनग व्यवस्था को निरन्तर गितशील बनाये रखने के लिए सही समय पर सही समको की उपलब्धता होनी चाहिए। जिससे राशिनग व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक उपभोग्य मात्रा का निर्धारण एव उसकी व्यवस्था की जा सके। परन्तु इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन एव खपत सम्बन्धी जो भी सख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं,वे प्राय सही न होने के कारण व्यवस्था की गितशीलता एव उपभोक्ता की सन्तुष्टि दोनों के लिए बाधक बनते हैं।
- वस्तुओं की घरेलू माँग का सही—सही अनुमान एक केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से लगाना आसान नहीं होता है। विशेषरूप से उस देश में जहाँ अधिकाश उत्पादन और वितरण का कार्य निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा हो। ऐसी दशा में एक वस्तु की अलग—अलग श्रेणियों की माँग का अनुमान लगाना तो और भी कठिन है। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में विकेन्द्रित आयातकर्ता केन्द्रीकृत एजेन्सी की तुलना में बाजार के अधिक निकट होते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न गुणों और किस्मों वाली वस्तु की माँग में परिवर्तन होने की सम्भावना और अधिक बढ जाती है। माँग का गलत अनुमान लगाने से या तो देश में वस्तुओं की कमी हो जायेगी अथवा एक वस्तु का निष्प्रयोज्य स्टॉक सचित हो जायेगा। गलत अनुमान भारत जैसे विकासशील देशों पर बुरा प्रभाव डालता है।
- -- राशन की दुकानो को विक्रेता अपनी सुविधानुसार खोलता है जहाँ वह आसानी से आ-जा सके तथा वितरित की जाने वाली वस्तुओ पर उसको परिवहन लागत तथा दुकान की अन्य लागतो का

भुगतान कम से कम करना पड़े जिसके कारण उपभोक्ता को अपने घर से बहुत दूर जाकर वस्तुए प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे विक्रेता न तो विक्रय कार्य ईमानदारी से पूरा करते हैं और न ही उपभोक्ताओं की भावनाओं का ही सम्मान करते हैं। इससे उपभोक्ता और दुकानदार के सम्बन्ध प्राय मधुर नहीं रहते।

(घ) खरीद कार्य चुनौती पूर्ण — उपभोक्ता के लिए क्स्तुओं की पूर्ति नियमित बनाये रखने हेतु उन वस्तुओं की खरीद का कार्य विभिन्न चुनौतियों से पूर्ण होता है। सरकार द्वारा खरीद का कार्य उसी दशा में आसान होता है जब उस क्स्तु का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक हुआ हो। सरकार को उन्हीं वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदना होता है जिन क्स्तुओं का उत्पादन कम हुआ है। परिणामस्वरूप सरकार अपने सवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उत्पादकों पर लेवी लगाती है। परन्तु लेवी लगाने की यह क्रिया उत्पादन प्रेरणा के लिए घातक सिद्ध होती है। लेवी को उत्पादक अपने ऊपर एक अनावश्यक रूप से थोपा गया भार समझते हैं और यह भार जैसे—जैसे बढता जाता है उत्पादक की उत्पादन प्रेरणा कम होने लगती है जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं हो सकती । खरीद कार्य ही अधिक महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण है खरीदी गई मात्रा का उचित भण्डारण एव समय— समय पर उसका निर्गमन। प्राय भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण खरीदी गई क्स्तु के सड जाने, गल जाने, अथवा गोदाम में आग लग जाने या चोरी हो जाने से वस्तु की गुणात्मक एव सख्यात्मक दोनो हानियों होती है।

खरीद कार्य राज्य सरकार एव केन्द्र सरकार दोनों के सहयोग तथा विभागों के आपसी समन्वय पर निर्भर करता है। खरीदी जाने वाली मात्रा एवं वस्तु की आवश्यक मात्रा का अनुमान भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खरीद कार्य से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियाँ स्पष्ट रूप से घोषित न होने के कारण लक्ष्यों में एकरूपता नहीं आ पाती जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। वस्तुओं की आवश्यक मात्रा एवं खरीदी गयी मात्रा में तालमेल न होने के कारण प्राय कुछ वस्तुए अनावश्यक रूप से भण्डारगृह में कई वर्षों तक अनुपयोगी पड़ी रह जाती है तथा कई आवश्यक वस्तुओं के अनुपलब्धता की स्थिति बनी रहती है।

(ड) सार्वज़िनक वितरण प्रणाली की समस्याए — भारत में सार्वजिनक वितरण प्रणाली की व्यवस्था एक 'सफेद हाथी' की तरह है जिसे न चाहते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था को ढोना पड रहा है। अग्रेजी में सफेद हाथी उस जीव या व्यवस्था को कहा जाता है जिसकी क्षुधा तो निरन्तर बढ़ती रहे किन्तु उपयोगिता न बढ़े। यह वर्णन खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार के आधार स्तम्भ—सार्वजिनक वितरण प्रणाली के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम का अनुदान निरन्तर बढ़ता रहा है, जबिक देश की कुल खाद्यान्न पूर्ति में इसका अश्वदान नहीं बढ़ा है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली की कई अन्य समस्याए इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगा रही है, जो अग्रलिखित है—

- ——यह प्रणाली भी सार्वजिनक कल्याण की अन्य योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार के चगुल में फॅसी हुई प्रतीत होती है। यह देश के ग्रामीण गरीब उपभोक्ता को उनकी आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने में वाछित सहायता नहीं कर पायी है। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि बिहार राज्य को जिसकी आबादी देश की आबादी का10 24 प्रतिशत है तथा जहाँ पर देश के 14 5 प्रतिशत गरीब व्यक्ति जीवन—यापन करते है, वर्ष 1992—93 में देश में कुल वितरित अन्न का केवल 4 प्रतिशत भाग दिया गया था जबिक दिल्ली नगर को जिसकी आबादी देश की आबादी की एक प्रतिशत भी नहीं है, और जहाँ गरीबों की सख्या भी कम है, कुल सस्ते अन्न का 5 3 प्रतिशत अन्न बाँटा गया था।
- इस प्रणाली पर केवल नगरो तक सीमित होने का आरोप भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकाने बहुत कम है जबिक भारत की दो तिहाई से अधिक आबादी गाव में रहती है साथ ही गावों में इस प्रणाली के सचालक कुछ दर्बंग लोगों को सामग्रियों उपलब्ध करा देते हैं, परन्तु निम्न आये वाले कमजोर व्यक्तियों का हक ग्राम प्रधान और इस प्रणाली के नौकरशाह तथा व्यापारी मिलकर डकार जाते हैं। गाव के 80 प्रतिशत लोग निरक्षर तथा गरीब कृषक—मजदूर के रूप में इस प्रणाली द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली वस्तुओं से विचित रह जाते हैं। इनको यह भी मालुम नहीं हो पाता कि प्रति इकाई कितनी चीनी, गेहूँ, मिट्टी—तेल आदि मिलता है। ये व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुए निकट के कस्बे अथवा बाजार से प्राप्त करना आसान समझते है क्योंकि वहाँ ये वस्तुए उन्हे ससम्मान प्राप्त होती है जबिक राशन की दुकानो पर उन्हे घण्टो प्रतिक्षा के बाद भी दुत्कार दिया जाता है।
- उचित मूल्य की दुकानो पर केवल कुछ गिनी चुनी वस्तुए ही उपलब्ध होती है जिससे उपभोक्ता को केवल उन्ही वस्तुओं का उपभोग करने के लिए बाध्य होना पडता है, जो वस्तु इस प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है उसकी स्थानापन्न वस्तुए भी दुकान पर उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इन दुकानो पर बिकने वाली वस्तुओं को सरकार को स्टॉक में रखने की आवश्यकता होती है।
- सार्वजिनक वितरण प्रणाली की एक समस्या यह भी है कि जब सामान्य बाजार में क्स्तुओं की अपर्याप्तता होती है अथवा मूल्य बहुत तेजी से बढते हैं तो उस क्स्तु का दबाव इस प्रणाली पर अधिक पडता है। जब वितरित की जाने वाली क्स्तु सामान्य बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध होती है तो आम जनता उन क्स्तुओं को बाजार से ही प्राप्त करना उचित एव आसान समझती है। ऐसी परिस्थिति में सार्वजिनक वितरण प्रणाली की क्स्तुए दुकानों में पड़ी रह जाती है और विक्रेताओं को अपनी जीविका चलाना कठिन हो जाता है।
- -- सार्वजिनिक वितरण प्रणाली मे भी वे सारे दोष पाये जाने लगे है जो निजी व्यापारियों में होते है, यथा- कम तोल, अपिमश्रण, अधिक मूल्य पर वस्तु का विक्रय, फुटकर विक्रेताओं को वस्तु का विक्रय कर देना आदि। जिन वस्तुओं की मॉम बढ़ती है वे वस्तुए इन दुकानों पर न पहुँचकर सीधे काले बाजार मे

पहुँचने लगती है। इसके अतिरिक्त फर्जी राशन कार्ड, दुकानो का प्राय बन्द रखना, गरीब कार्ड धारको को घुडकना और लौटा देना आदि निन्दनीय कार्य भी इन दुकानो पर होते है।

- ——वर्तमान समय मे यह बात प्रत्येक व्यक्ति समझने लगा है कि सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके द्वारा सम्पादित क्रियाओं में मितव्यियता का ध्यान नहीं रखा जाता और न ही इसके द्वारा उत्पादित वस्तु में पर्याप्त उपयोगिता का सृजन ही हो पाता है। यह बात कुछ हद तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को सन्देह की परिधि में डाल देती है।
- -- बहुत से डीलर अपनी दुकानों को ठेके पर दे देते हैं जिससे इस व्यवस्था में एक और मध्यस्थ शामिल हो जाता है, जो इस प्रणाली के मूल भावना से अपरिचित होता है। वह केवल लाभ की भावना से ही कार्य करता है। इसमें ठेके प्रणाली के समस्त दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
- दुकानदारों की प्रमुख समस्या योजनानुसार माल का उपलब्ध न होना है। इसके लिए दुकानदारों को आपूर्ति कार्यालय एव भण्डारगृहों का कई बार चक्कर लगाना पडता है और दुकाने बन्द रखनी पडती है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पडती है तथा वस्तु का परिवहन व्यय भी अधिक हो जाता है। गोदामों के श्रमिक, दुकानदारों को माल लादते समय परेशान भी करते है। इन्हें माप—तोल के सम्बन्ध में भी कभी—कभी असुविधा का सामना करना पडता है।
- ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों की सबसे अधिक समस्या विभागीय अधिकारियों से होती है जबिक नगर क्षेत्र के दुकानदारों की समस्याए इनकी तुलना में कम होती है। इसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा से है। कम पढ़े—लिखे होने के कारण दुकानदारों को यह अनुभव होता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है।
- उपभोक्ताओं की सबसे अधिक समस्याये कार्ड—प्राप्ति, इसके संशोधन व नवीनीकरण कराने में होती है। उपभोक्ताओं अपने राशन कार्ड का हस्तान्तरण सुविधा पूर्वक करते रहते हैं तथा निम्नवर्ग के व्यक्ति, मध्यमवर्ग या उच्चवर्ग से राशन कार्ड उधार मॉगते हैं। कुछ उपभोक्ता अपने राशन कार्ड में वास्तविक सदस्यों से अधिक संख्या अकित कराते हैं जिससे वास्तविक उपभोग की इकाई का ज्ञान नहीं हो पाता और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पडता है।
- कभी-कभी राशन की दुकान पर उपलब्ध राशन का मूल्य खुले बाजार के मूल्य के बराबर अथवा इससे अधिक हो जाता है, परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकाने बन्द होने लगती है। इसी प्रकार की समस्या फरवरी-1994 में उत्पनन हुई थी। जब राशन के एक कुन्तल गेहूँ की कीमत 427 रुपये थी जबिक बाजार में राशन की तुलना में बढिया किस्म का गेहूँ 4 से 4 50 रुपये प्रति किलो उपलब्ध था। यही स्थिति चावल की भी थी। ऐसी स्थिति में राशन की दुकानों का बन्द होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर गेहूँ के मामले में निजी व्यापारी 20-25 प्रतिशत का मुनाफा कमा कर भी राशन के गेहूँ की कीमतों के बराबर मूल्य पर गेहूँ बेच रहा था और बाजार का वहीं गेहूँ उचित मूल्य की दुकान की तुलना में बेहतर

भी था।

- (च) भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित समस्याए भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य कुछ निश्चित क्षेत्रों में निजी व्यापारियों की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करना और उत्पादक एव उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करना है। इसे भारत सरकार की एक ऐसी एजेन्सी के रूप में स्थापित किया गया है जो खाद्यान्नों के आयात, खरीद, भण्डारण, एव वितरण को सचालित करें। परन्तु यह निगम वर्तमान समय में निम्न समस्याओं से जूझ रहा है—
- भारतीय खाद्य निगम में नियोजित पूँजी की तुलना में कुल कारोबार की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। वर्तमान समय में नियोजित पूँजी से इसकी कुल खरीद एवं बिक्री केवल दो गुना है जबिक निजी सस्थाओं में यह अनुपात 6 गुना से भी अधिक होता है। इस प्रकार खाद्य निगम में नियोजित पूँजी का मदुपयोग नहीं हो पा रहा है।
- -- निगम को अधिप्राप्ति तथा उसकी लागतो की तुलना में निर्गम मूल्य में कमी की क्षतिपूर्ति हेतु उपभोक्ता सहायना राशि प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि में गत 20 वर्षों में पचास गुना वृद्धि के बावजूद निगम को वर्ष 1986-87 से निरन्तर घाटे का सामना करना पड रहा था। यह निगम के कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी तथा निगम के विभिन्न व्ययों पर अनियन्त्रण तथा उसके स्वय की अक्षमता को सिद्ध करता है।
- निगम को खाद्यान्नों को लाने, ले जाने में भारी मार्गस्थ हानि एव भण्डारण में कमी का भार उठाना पडता है। खरीदे एवं बेचे जाने वाले खाद्यान्नों का औसतन 1 5 प्रतिशत छीजन हुकों के प्रयोग, बोरों के उतारने—चढाने, गोदाम में रखने एवं निकासी तथा नमी के सूखने के कारण हो जाता है। जिसमें खाद्यान्नों के सडने या गल जाने या कीडे—मकोडे से होने वाली हानि शामिल नहीं है। वर्ष 1992—93 में यह हानि 223 3 करोड़ रुपये की थी।
- निगम को लेवी चीनी एव आयातित चीनी दोनो के सन्दर्भ मे प्रतिवर्ष घाटा उठाना पडता है। यह घाटा उसे चीनी के सम्भाल एव वितरण दोनो मामलो मे उठाना होता है। निगम चीनी की अधिप्राप्ति लेवी के निर्घारित मूल्य पर करता है उस पर भाडा, सभाल प्रभार, प्रशासनिक खर्च, चुगीप्रभार, भण्डारण प्रभार इत्यादि मदो पर भारी खर्च करता है, परन्तु उसे चीनी का निर्गमन निर्धारित मूल्यो पर करना पडता है। यद्यपि लागत मूल्य एव निर्गम मूल्य के अन्तर की भरपाई राज सहायता के माध्यम से की जाती है जो कि पर्याप्त नहीं होती।
- -- निगम की भण्डारण लागत में भी वृद्धि हुयी है। लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण बडी मात्रा में दीर्घकाल तक भण्डारों का पड़े रहना, ब्याज की दरों में वृद्धि, भण्डारण क्षमता का पूर्ण प्रयोग न होना, बोरों तथा तिरपालों का सड जाना, गोदाम से चोरी तथा आग लग जाना या वर्षा के मौसम में गोदामों का -

#### गिर जाना भी है।

- भारतीय खाद्य निगम में सम्बद्ध मन्त्रालयों में तालमेल के अभाव तथा राजनीतिक पदाधिकारियों एव नौकरशाहों के बीच अहम् का टकराव होने के कारण सम्पूर्ण राष्ट्र को परेशानी का सामना करना पडता है। छोटे—छोटे निर्णयों के लेने एव उन पर अमल करने में समय गुजर जाता है। परिणामस्वरूप निगम एव राष्ट्र दोनों को हानि होती है।
- -- जहाँ तक सरकार द्वारा किसानो के उपज का समर्थन मूल्यो पर खरीद का प्रश्न है, यह वास्तव मे दिखावा मात्र है। यद्यपि मोटे अनाजो के समर्थन मूल्यो की घोषणा प्रतिवर्ष होती रही है उसकी सरकारी खरीद नहीं के बराबर होती है। जहाँ तक चावल का सवाल है, तो खाद्य निगम इसकी आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से चावल-मिलो से लेवी की वसूली पर निर्भर करता है। इधर कुछ वर्षों से गेहूँ की खरीददारी भी सीधे किसानो से न होकर बिचौलियों के माध्यम से हो रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मोटे अनाजो धान और चावल की कुल मात्रा जो किसान बेचते है, उसका दसाश भी भारतीय खाद्य निगम सीधे किसानो से नहीं खरीदता। सरकार अपने अनाजो की आवश्यकता की आपूर्ति किसी प्रकार कर लेने के बाद किसानों को निजी व्यापारियों की कृपा पर छोड देती है।
- कभी—कभी निगम को स्थानीय एव प्रशासनिक समस्याओं से भी जुझना पडता है। स्थानीय समस्याओं मे श्रमिक समस्या, रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता, इंडताल एवं कर्पयू जैसी समस्याओं का सामना करना पडता है जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती। निगम को अन्य विभागों से भी मदद लेनी पडती है, जैसे—बन्दरगाह, रेलवे प्रशासन, राज्य प्रशासन, केन्द्र एव राज्य के भण्डारण निगम, इन पर खाद्य निगम का कोई नियन्त्रण न होने के कारण भी इन विभागों/सस्थाओं का सहयोग लेना एक कठिन कार्य होता है। निगम पर खाद्यान्तों के अधिप्राप्ति एवं निर्गमन दोनों अवसरों पर सही तोल न करने का आरोप भी लगाया जाता है। अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को शिकायत होती है कि उनकी उपज की तौल वास्तविक तौल से कम पर की जा रही है, जिससे उनके उपज का वास्तविक मृल्य न देकर उनकी उपेक्षा की जाती है। किसानों की अच्छी श्रेणी के उपज को भी 'सी'अथवा 'डी' ग्रेड देकर भी उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचायी जाती है।
- निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कार्य के प्रति बरती जा रही लापरवाही तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप, कार्य की अभिप्रेरणा में कमी, निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता में कमी के आरोप समाचार पत्रों में प्राय देखने को मिलते हैं। यद्यपि निगम द्वारा प्रति कर्मचारी किये जा रहें कारोबार में लगातार वृद्धि के समकों को प्रस्तुत किया जा रहा है, परन्तु ऐसा कर्मचारियों के स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण तथा नयी नियुक्तियों के न किये जाने के कारण है। कर्मचारियों के लापरवाही के कारण ही खाद्यान्नों का

गोदामों में सड जाने, बोरों को समय से न पलटने, समय से दवा का छिड़काव न करने, गोदामों में नमीं बने रहने कैप भण्डारण के अधीन रखे खाद्यान्नों के फट जाने अथवा उड जाने क कारण निगम को प्रतिवर्ष करोडों रुपये की हानि होती है।

- (छ) केन्द्रीय भण्डारपनिगम की समस्याए यह निगम राजकीय व्यापार में लगी एजेन्सियों के द्वारा खरीदें गये खाद्यान्न एव अन्य वस्तुओं को अपने भण्डारगृह में सुरक्षित रखने के साथ-साथ निजी व्यापारियों, सहकारी मिनितयों एवं किसानों को भी अपनी सुविधाए प्रदान करता है, परन्तु इस निगम में भी कई प्रकार की समस्याए उत्पन्न हो गयी है जो कि निम्नवत है-
- निगम का यह प्रयास तो सराहनीय है कि वह अपनी भण्डारण क्षमता में लगातार वृद्धि करता जा रहा है, परन्तु इस सराहना के साथ ही साथ इस बात के लिए उसकी निन्दा भी की जाती है कि यह अपने उपलब्ध भण्डारण क्षमता का प्रयोग करने में निरन्तर कमी की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में चाहे निगम की अपनी भण्डारण क्षमता हो अथवा किराए की, यदि वह अप्रयुक्त रह जाती है तो इससे निगम को अपूर्णनीय क्षति होती है।
- इस निगम का वित्तीय निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी है।
  मुख्य रूप से निगम की प्रित कर्मचारी सकल प्राप्ति एवं सभाली गयी क्षमता से सम्बन्धित समकों के
  अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विगत वर्षों में इन दोनों मदों में कमी आयी है। निगम के उच्चिधिकारी
  सकल प्राप्ति में कमी के लिए आर्थिक उदारीकरण को उत्तरदायी मानते हैं। उनके विचार से सकल प्राप्ति
  में कमी का कारण राजकीय व्यापार में लगी एजेन्सियों द्वारा किये गये कारोबार में कमी से निगम की सकल
  प्राप्ति कम हुयी है। लेकिन निगम तो निजी जमाकर्ताओं को भी अपनी भण्डारण की सुविधा प्रदान करता
  है और आकड़े बताते हैं कि इन निजी जमाकर्ताओं की सख्या में भी विगत वर्षों में कमी हुयी है जबिक
  आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क नियन्त्रणों में कमी करने अथवा उन्हें समाप्त करने निजी
  जमाकर्ताओं की सख्या में वृद्धि होनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट होता है कि निगम की कार्यप्रणाली में किसी
  न किसी स्तर पर कोई न कोई कमी अवश्य है। यह निगम निजी जमाकर्ताओं के साथ भी उचित व्यवहार
  और भण्डारण की उचित गुणवत्ता बनाये रखने का सही प्रयास नहीं कर पा रहा है।
- यद्यपि निगम के प्राप्ति में कुछ मदो—ऋण एव अग्रिम पर ब्याज, पोर्टफोलियो योजना के अन्तर्गत बैंको में जमा पर ब्याज, एजेन्सी कमीशन, पजाब राज्य भण्डारण निगम के सयुक्त उद्यम से उत्पन्न प्राप्ति एव महाराष्ट्र सरकार की ओर से हैंडलिंग प्रचालन से आय में वृद्धि के बावजूद निगम के लाभों में निरन्तर कमी हो रही है। वास्तव में भण्डारगृहों से उत्पन्न प्रभार में वर्ष 1990-91 से लगातार कमी होना एक चिन्ता का विषय है, जो कि निगम की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है।
  - -- इस निगम का अपने स्थापना व्यय एव परिचालन व्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इन व्ययो

में मुख्य रूप सं ग्रच्युटी, बानस, वतन भत्ने मजदूरी एव रख-रखाव के व्ययों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ये व्यय भी निगम की लाभदायकता को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहे हैं।

- केर्न्द्रीय भण्डारण निगम ने राज्य भण्डारण निगमों के समता अश्र पूँजी में जो विनियोजन किया है, उससे केर्न्द्रीय भण्डारण निगम को सन्तोषजनक प्रत्याय नहीं हो पा रही है। यद्यपि इन राज्य भण्डारण निगमों के भण्डारगृहों की सख्यात्मक एव गुणात्मक दोनों स्तरों में वृद्धि हुई है परन्तु यदि इन निगमों के निवेश से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लाभाश के रूप में प्रतिफल का अवलोकन किया जाय तो ये दरे वर्ष 1989–90 से वर्ष 1992–93 के बीच क्रमश 3 53,1 27,4 12 तथा 2 52 रही है। इन्हें किसी भी दशा में उचित प्रतिफल नहीं कहा जा सकता। वैसे तो, राज्य भण्डारण निगम 0 5 प्रतिशत से 7 0 प्रतिशत तक लाभाश घोषित करते हैं, परन्तु कई निगम समय से अपनी वार्षिक बैठके नहीं करते, कुछ लाभ होने पर भी लाभाश घोषित नहीं करते और कुछ के कारोबार में हानि हो रही है, परिणामस्वरूप केन्द्रीय भण्डारण निगम को राज्य भण्डारण निगमों में निवेशित पूँजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता।
- निगम की अपनी लाभदायकता और लाभाश वर्ष 1990—91 तक सन्तोषजनक रहा है। इसमें एक स्थिर गित से वृद्धि होती रही और नियोजित पूँजी पर प्रत्याय 12 2 प्रतिशत तक पहुँच चुका था परन्तु वर्ष 1992—93 में यह गिरकर 6 5 प्रतिशत पर आ गया। इसी प्रकार निगम की लाभाश क्रमश बढ़ते हुए वर्ष 1991—92 में 12 5 प्रतिशत पर पहुँच गयी थी, परन्तु इसे वर्ष 1992—93 में 7 प्रतिशत की दर पर भी बनाये रखने के लिए निगम ने वर्ष 1991—92 के 3317 लाख रुपये के प्रारक्षण की तुलना में वर्ष 1992—93 में केवल 486 लाख रुपये का ही प्रारक्षण किया जा सका। यद्यपि निगम के इस वर्ष में कारोबार में गिरावट कुछ तो व्यापारिक दशाओं और कुछ प्राकृतिक आपदाओं, जैसे—बाढ एव सूखा पड़ने के कारण रही परन्तु निगम को इन सम्भावनाओं और इनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को भी ध्यान में रखना चाहिए था।
- वर्तमान समय में निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी वस्तुओं के गुणवत्ता नियन्त्रण एवं उनके परिरक्षण पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं,परिणामस्वरूप भण्डारण की क्षतियों वर्ष 1990-91,91-92 एवं 1992-93 में क्रमश 0 35,0 51 और 0 43 प्रतिशत हुई। यद्यपि ये क्षतियों निगम के मार्गस्थ क्षतियों से कम है परन्तु फिर भी इन्हें और कम किया जा सकता है।
- -- भारतीय कृषको के द्वारा न तो केन्द्रीय भण्डारण निगम और न ही राज्य भण्डारण निगम के भण्डार गृहों का प्रयोग वाछित मात्रा में किया जा रहा है जबकि कृषकों से उनकी उपज खरीद कर मध्यस्थों द्वारा भण्डारण की सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है जबकि कृषकों को उनकी उपज हेतु पर्याप्त मृल्य भी नहीं चुकाया जाता।
  - -- उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त यह निगम भी राजकीय अभिकरणों में उत्पन्न दोषों एवँ

समस्याओं से परे नहीं है। इस निगम के आधिकारियों एवं कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार, नैतिकता के पतन, कार्य में अभिप्रेरणा का अभाव, कार्य के प्रति अरूचि इत्यादि समस्याओं के साथ नौकरशाही, अधिकारों के केन्द्रीयकरण, अन्य विभागों एवं अभिकरणों से समन्वय का अभाव, विभागीय अधिकारियों में तालमेल की कमी जैसे दोष विद्यमान है।

- (ज) <u>राज्य व्यापार निगम भी समस्याग्रस्त —</u> भारत के आन्तरिक व्यापार को व्यवस्थित करने तथा विदेशी व्यापार से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गयी जिसके मुख्य उद्देश्यों में कम्पनी द्वारा समय—समय पर निश्चित की गयी वस्तुओं का आयात एव निर्यात अथवा सामान्य व्यापारिक क्रियाओं को सम्पादित करना आता है परन्तु यह निगम भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने निम्न समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण सफल नहीं रहा है—
- -- राज्य व्यापार निगम का अपने व्ययो पर नियन्त्रण न होने के कारण इसकी लाभदायकता कुल बिक्री की तुलना में बहुत कम(केवल 2-3 प्रतिशत ही) रहती है जबकि निजी व्यापारियों की कुल बिक्री एवं लाभ का प्रतिशत बहुत ऊँचा होता है।
- निगम की सगठनात्मक सरचना बहुत जटिल है और इसमें उच्च पदो पर अधिकारों का केन्द्रीयकरण प्रतीत होता है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि निगम को कोई भी निर्णय लेने में काफी विलम्ब हो जाता है, जबिक आर्थिक क्षेत्र में विलम्ब से लिये गये निर्णयों का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ भी राजनीतिक पदाधिकारियों और नौकरशाहों के हितों का टकराव देखने को मिलता है।
- निगम से सम्बन्धित मन्त्रालय, यथा—खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय मे तालमेल के अभाव के कारण निगम को अपना निर्यात सस्ते दर पर करने तथा आयात महँगे दर पर करने के लिए बाध्य होना पडता है।
- -- निगम मे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् अधिकारी एव कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी एव कर्तव्य परायणता से कार्यों का निष्पादन नहीं करते क्योंकि उनमें निगम के प्रति भावनात्मक लगाव की कमी होती है। जब उनमें कार्यानुभव विकसित होता है तो उन्हें उनके मूल विभाग को वापस कर दिया जाता है।
- राज्य व्यापार निगम का विगत वर्षों में विदेशी व्यापार में योगदान घटता जा रहा है जो वर्ष 1980-81 में 9 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1992-93 में केवल 0 87 प्रतिशत रह गया है। यह इतने बड़े राजकीय व्यापार सगठन के लिए एक चिन्ता का विषय है। यद्यपि सरकार द्वारा सरणीबद्ध वस्तुओं की सूची को छोटी करने के कारण सरणीबद्ध व्यापार में कमी आयी है। परन्तु निगम ने असरणीबद्ध वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने का उचित प्रयास नहीं किया है।
- -- निगम के कर्मचारियों में अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है उनमें कुशलता लाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाती फलस्वरूप उनकी कार्यप्रणाली परम्परागत बनी रहती है एवं

कार्यक्षमता में निरन्तर कमी अती रट्ती है जिए का दुष्प्रभाव निगम की कार्यक्षमता पर भी पडता है।

- सरणीबद्ध कस्तुओं के व्यापार में ानगम को इकाधिकार प्राप्त होने के कारण स्माज का शोषण कर एक कल्याणकारी स्त्या के पुनीत उत्तरदाायत्वों का ानर्वहन यह निगम नहीं कर पाता। जहाँ इसे निजी व्यापारियों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सत्थाओं से प्रतित्पर्धा करनी होती है तो वहाँ भी इस अपनी अक्षमता के कारण हानि ही उठानी पड़ती है।
- -- निगम का अपने देश की औद्योगिक इकाइयो, अनुसन्धान एव विकास सस्थानो तथा समको का सकलन एव अनुमान लगाने वाली इकाइयो के साथ सन्तोषजनक सम्बन्ध नही है जिसके कारण उत्पादन एव उपत से सन्बन्धित सही सूचनाए नही मिल पाती और यदि मिलती भी है तो उचित समय पर नही, जिसके परिणामस्वरूप निगम के हितो के अनुरूप अनुबन्ध नहीं हो पाता।
- निगम कभी—कभी लोक कल्याण की भावना को भूलकर लाभ की भावना से प्रेरित होकर एक निजी व्यापारिक सस्थान की तरह कार्य करने लगता है। अधिकाश अवसरो पर निगम की मूल्य नीतियाँ उचित नहीं रहती है। यह पि निगम की वर्तमान समय में केवल एक अनुषगी सस्था भारतीय चाय व्यापार निगम है लेकिन उससे भी इसका समन्वय सन्तोषजनक नहीं है। वर्ष 1992—93 से पूर्व चाय व्यापार निगम की गतिविधियों को सन्तोषजनक कहा जा सकता था। परन्तु वर्ष 1992—93 में इसे 171 लाज रुपये की हानि होना एक चिन्ता का विषय है
- (ज्ञ) <u>राजकीय व्यापार की अन्य समस्याए</u> राजकीय व्यापार से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याए निम्नलिखित है-
- राजकीय अभिकरणों में ज्ञान—अनुभव और अनुबन्ध क्षमता की कमी पायी जाती है। राजकीय व्यापार विशिष्ट रूप से विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में एक विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय होता है। इसके लिए वस्तुओं का विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक होता है और इसके साथ ही साथ वृहत क्षेत्र में फैले हुए व्यापारियों से विस्तृत अनुबन्ध करने की आवश्यकता भी पड़ती है। वस्तुओं का विस्तृत ज्ञान एव अनुबन्ध की क्षमता प्राप्त करने के लिए कई वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है। राजकीय अभिकरण विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और अनुबन्ध क्षमता की कमी के कारण विदेशी व्यापार व्यवहार को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के योग्य नहीं होता ।
- -- व्यापार व्यवहार में व्यवसाय की परिवर्तनशील परिस्थितियों के कारण शीघ्र निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विलम्ब से लिये गये निर्णय व्यावसायिक क्षेत्र में निष्प्रयोज्य होते हैं। राजकीय व्यापार व्यवस्था के नौकरशाही प्रशासन में यह सम्भव नहीं है।
- --- किसी भी व्यापार के प्रभावपूर्ण एव मितव्ययी सचालन हेतु व्यक्तिगत रुचि बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजकीय व्यापार में सलग्न कर्मचारियों के व्यापार व्यवहार में कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है।व्यापार 2

की लाभ हानि सरकार के खाते में जाती है न कि व्यापार का सचालन करने वाले कर्मचारियों के। इसलिए कर्मचारी इस बात का पूर्ण प्रयास नहीं करते कि राजकीय व्यापार हेतु खरीददारी सबसे सस्ते बाजार से की जाय, तथा बिक्री सबसे महेंगे बाजार में हो।

- राजकीय व्यापार सरकारी एकाधिकार को बढ़ावा देता है। इसे राजकीय पूँजीवाद भी कहा जा सकता है इसके माध्यम से एकाधिकारी शक्ति सरकार के पास केन्द्रित हो जाती है जिससे जन साधारण को हानि होने लगती है। इसके ारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ का स्तर भी गिर जाता है, जैसे— आजकल अधिकाश राज्यों में उचित मूल्य की सरकारी दूकानों पर सेवा का स्तर गिर चुका है जिसमें उपभोक्ता को दुत्कारने, उसका अनके प्रकार से शोषण करने का प्रयास किया जाता है।
- -- राजकीय व्यापार मे भारी विनियोग की आवश्यकता होती है। अत सरकार को व्यापार व्यवहार
   मे नहीं पड़ना चाहिए बल्कि इस धनराशि का प्रयोग देश के अन्य विकास ससाधनों में करना चाहिए।
- राजकीय व्यापार में लगे अभिकरणों के क्रय-विक्रय मूल्य के अन्तराल की समाप्ति हेतु दी जाने वाली राज सहायता दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए 6000 करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुँचने वाली है। उपभोक्ता को शोषण से बचाने के नाम पर एक विकासशील देश वाला इतनी बड़ी वनराशि खर्च करना बहुत उचित नहीं है। सरकार अपने सवैधानिक अधिकारों का प्रयोग उचित ढग से करके भी उपभोक्ता को शोषण मुक्त करा सकती है।

#### सुझाव

समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर लोक-कल्याणकारी राज्य के लिए विपणन क्रियाओं में भाग लेना नि सन्देह देश के सन्तुलित व्यावसायिक तथा आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। विकसित आर्थिक मूल्यों के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि इक्कीसवी शताब्दी में देश और समाज के बहुमुखी विकास तथा आर्थिक सुदृढता के लिए राजकीय व्यापार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश की भयकर गरीबी को देखते हुए इसे न केवल समाज के कमजोरतम् वर्गों की क्रयशक्ति के पहुँच वाले मूल्यों पर जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के पूर्ति में सहयोग देना चाहिए बल्कि इसके माध्यम से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सुदृढ किया जाना चाहिए।

राजकीय व्यापार की समस्याओं की जिटलता के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि राजकीय व्यापार व्यवस्था का विघटन कर दिया जाना चाहिए। परन्तु यह एक त्रुटिपूर्ण, अदूरदर्शी और अनुचित निर्णय होगा। वास्तव मे राजकीय व्यापार की समस्याओं का समाधान अग्रलिखित राजावों के अनुपालन से किया जा सकता है—

## व्यापारिक क्रियाओं में आदर्श आचार सहिता का निर्माण एव उसका अनुपालन -

प्रत्येक व्यापार के समुचित विकास एव कुशल नियनत्रण हेतु कुछ आदर्श आचार सिंहताओं का निर्माण किया जाना तथा उनका पालन किया जाना आवश्यक हाता है। भारत के राजकीय व्यापार म इस प्रकार की कोई आचार सिंहता अभी तक नहीं बनायी गयी है। राजकीय व्यापार—क्षेत्र म पर्याप्न आचार सिंहता तैयार किये तथा उनका पालन किय बिना व्यापार में राज्य की भागीदारी अथवा कानूनो द्वारा उस पर नियन्त्रण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अत वैकिल्पिक विपणन नीतियों और व्यवहारों से किसानो उपभोक्ताओं और व्यापार एजेन्सियों का परिचत कराने के लिए अति आवश्यक है कि राजकीय व्यापार की आदर्श आचार सिंहता बनायी जाय तथा उसका पालन किया जाय।

#### भावी उत्पादन एव खपत का सही एव वैज्ञानिक अनुमान लगाना -

राजकीय व्यापार के लिए उत्पादन एव खपत का सही-सही एव वैज्ञानिक अनुमान लगाना आवश्यक होता है। इस अनुमान के लिए एक साधन के रूप में निजी इकाइयों के अनुमान को प्रयोग में तो लाया जा सकता है नरन्तु उन्हें अनुमान का आधार नहीं बनाया जा सकता। सही एव वैज्ञानिक समकों के सग्रहण हेतु नवीनतम कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था को शासकीय समक सग्रहण विभागों में उपयोग किया जाना समीचीन होगा। अत आकडों के सकलन में सलग्न सरकारी इकाइयों को और अधिक चुस्त एव दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है ताकि खपत की उत्पादन से तुलना कर आवश्यक वस्तुओं के आयात-निर्यात का निर्णय उचित समय पर लिया जा सके। इसके माध्यम से सही समय पर उचित सौदेबाजी के आधार पर अनुबन्धों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का उचित अवसर मिल सकेगा तथा तीसरे पक्षकारों से भी सम्पर्क करने की पर्याप्त अविध मिल सकेगी। इससे एक ओर न्यूनतम व्यय पर जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा दूसरी ओर राजकीय व्यापार की लाभदायकता को बढाने में भी सहायता मिलेगी।

## कानुनो की सख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर उसके अनुपालन पक्ष पर जोर -

भारत सरकार ने व्यापारिक क्रियाओ पर नियन्त्रण रखने तथा उन्हें आम जनता के लिए सुविधाजनक एव उपयोगी बनाने के लिए बहुत से अधिनियम बनाये हैं। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से प्रभावी बनाया जाय। व्यापारिक वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है कि —

- \* विभिन्न अधिनियमों के अनुपालन में सामञ्जस्य रखा जाय तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि इनके अनुपालन में एक अधिनियम दूसरे अधिनियम की व्यवस्थाओं का अतिक्रमण न करे।
  - \* भारतीय विनियम समाज मे व्याप्त व्यापारिक अनियमतताओ को दूर नही कर पाये है क्योंकि

कान्नों में कही न कही अनियमितना करने का छुद्र अवसर प्राप्त हो जाता है अत आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों का पुनरावलांकन एवं पुनरीक्षण के बाद उन्हें परिशोधित और परिष्कृत भी किया जाय।

- \* विभिन्न अधिनियमा म जो आर्थिक दण्ड निर्धारित किय गये हैं मुद्रा स्फीति को देखते हुए दोषी व्यक्तियों में किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं कर पाते। अत अधिनियमों के आर्थिक दण्डों को पुन निर्धारित किया जाय।
- \* उपभोक्ता सरक्षण अदालतो मे मामले तकनीकी आधार पर खारिज न हो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रत्येक जिले मे केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नियन्त्रण कक्षो मे ही एक अनुभाग इस आशय का खोला जाय जो उपभोक्ताओं को इन अदालतो मे जाने से पहले सरसरी तौर पर यह देखे और सुझाव दे कि मामले उपभोक्ता अदालतों में खारिज तो नहीं होंगे।
- \* उपभोक्ता अदालतो मे बढते हुए लम्बित मामलो के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला मच,राज्य आयोग एव राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की सख्या को आवश्यकतानुसार बढाया जाना चाहिए।

#### प्राथमिक एव नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता -

राजकीय व्यापार के कुशल सचालन हेतु देश के सभी नागरिकों को प्रथमत साक्षर एव द्वितीयक— नैतिक रूप से साक्षर बनाया जाना अनिवार्य हो गया है। विद्यमान सामाजिक परिवेश में स्वार्थ की जड़े काफी गहरी हो गयी है इसको उखाड फेकना नितान्त आवश्यक हो गया है। अत नागरिकों में देश भिक्त एव नैतिकता को जागृत करना अपरिहार्य है। इससे एक ओर उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति रूजग होगा तो दूसरी ओर राजकीय व्यापार में सलग्न अभिकरण एव उन्हें सचालित करने वाले व्यक्ति"कार्य ही पूजा है" की अवधारणा को समझ रूकेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर सकेंगे।

## देश मे उपभोक्ता ब्यूरो बनाने की आवश्यकता -

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एव सार्वजनिक वितरण से जुड़ी एक ससदीय समिति का सुझाव अनुपालनीय है कि देश मे एक "उपभोक्ता ब्यूरो" बनाया जाना चाहिए जो आम लोगों को समय-समय पर मार्ग दर्शन प्रदान करे। प्रस्तावित ब्यूरों के गठन से आम उपभोक्ताओं को बहुत से सुझाव और आवश्यक जानकारी मुहैया करायी जा सकेगी। इससे मात्र तकनीकी कारणों से खारिज हो जाने वाले मुकदमों की सख्या को भी घटाया जा सकेगा। वर्तमान समय में उपभोक्ता अदालतों में लिम्बत पड़े मामलों की सख्या लगभग साढ़े तीन लाख है जो चौकाने वाली है जिसमें प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। उपभोक्ता ब्यूरों बन जाने पर उपभोक्ता अदालतों में जाने से पहले उपभोक्ता इस ब्यूरों में सलाह लेगा और यदि मामले में तथ्य पूर्ण बाते हैं तभी वाद प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा नहीं। इस प्रकार यह सुझाव जिला नियन्त्रण कक्षों में मामले के सरसरी तौर पर निरीक्षण हेतु अलग बनाये जाने वाले अनुभाग के

विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

### राष्ट्रिनग व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने सम्बन्धी सुझाव -

राशनिग व्यवस्था मे आ रही वर्तमान

समस्याओं का समाधान निम्न सुझावों में मिल सकता है-

- \* राशिनग व्यवस्था में खाद्यान्ना की नियमित पूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि राशिनग के प्रबन्ध में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुव्यवस्था को समाप्त किया जाय। यदि इसे योजनाबद्ध एव व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाय, तथा अधिकारी वर्ग दुकानों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन खुलवाने की व्यवस्था करने का सकल्प ले तो खाद्यान्नों के अनियमित पूर्ति की समस्या का समाधान हो जायेगा।
- \* राशिनग व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली अभी तक की केवल छ वस्तुओं की सख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए इसके अलावा एक वस्तु की कई स्थानापन्न वस्तुए उपलब्ध कराकर अधिकाश उपभोक्ताओं की रुचि को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- \* राशिनग व्यवस्था के सुचारु रूप से सचालन हेतु खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी समकों के सकलन में अनुसन्धान कार्य में लगी इकाइयों तथा शासकीय विभागों से अनुमान लगवाया जाना चाहिए। खपत सम्बन्धी अनुमान तो राशिनग व्यवस्था स्वयं कर सकती है। इस प्रकार खाद्यान्नों के सग्रहण एवं खपत में सदैव समन्वयं बनाये रखना चाहिए।
- \* राशनिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में जनता की भ्रान्तियों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं कि राशनिंग व्यवसंथा के कारण, प्रभाव एवं प्रक्रिया का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाय।
- \* राशन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का सर्वेक्षण कर उपभोग की मात्रा का निकटतम सही अनुमान लगाया जाना चाहिए जिससे राशनिंग प्रक्रिया निरन्तर चलती रहे।
- \* उचित मूल्य की दुकानों को नगरों एव ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। इन्हें उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए न कि विक्रेता के सुविधानुसार।

इस प्रकार उपरोक्त सुझावो के अनुपालन से राशनिग व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ एव उपयोगी बनाया जा सकेगा।

## खरीद कार्य को और अधिक व्यवस्थित करने की आवश्यकता -

सरकारी खरीद को और अधिक

व्यवस्थित करने के लिए इसमें निम्न सुझावों को लागू किया जा सकता है-

\* सरकारी खरीद कार्य से सम्बन्धित नीति तय करते समय सरकार को चाहिए कि वह कृषि मूल्य आयोग की सस्तुतियो को ध्यान में रखे। खरीद सम्बन्धी लक्ष्यों के निर्धारण में केन्द्र एव राज्य सरकार समन्वित रूप से कार्य करे तथा अपनी विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप ही लक्ष्य का निर्धारण करे। \* यदि यह सम्भावना हो कि खरीदकार्य का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पायेगा तो किसानो पर न्यूनतम किन्तु उत्पादन—प्रेरक लंबी का निर्धारण कर इस सन्देह से निष्टिचन्त हुआ जा सकता है। जैसे— किसानो से खरीदे जाने वाले खाद्यान्नो का मूल्य भुगतान लंबी की चीनी, सस्ते कपडे, उपजाऊ उर्वरक, कीटनाशक दवाओं अच्छे बीजों अथवा किसान के आवश्यकता की अन्य वस्तुओं में किया जाय। इससे किसान न केवल अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए अभिप्रेरित होगे बल्कि वे अपने अतिरेक उपज को सरकारी खरीद केन्द्रों पर ही बेचना चाहेगे।

\* खरीद कार्य में केन्द्र एव राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों में कभी—कभी वाछित समन्वय न बन पाने की समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि जिस समय खरीद कार्य चल रहा हो उस समय दिन—प्रतिदिन खरीद की प्रगति अपने—अपने मुख्यालयों को प्रेषित की जाय तथा आने वाली समस्याओं की जानकारी दी जाय। राज्य एव केन्द्र सरकार के सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों की अर्द्ध मास के अन्तराल पर बैठक की जाय जिसमें खरीद कार्य की समीक्षा हो और समस्याग्रसत मामलों पर विचार—विनिमय कर जापसी समन्वय विकसित किया जाय जिससे विभागीय लक्ष्यों एव नीतियों में एकरूपता लायी जा सके।

\* खरीद कार्य राजकीय व्यापार का एक नियमित एव स्थायी उपकरण बन सके इसके लिए आवश्यक है कि राजकीय प्रशासन खरीद कार्य के लिए सस्थानात्मक एव सगठनात्मक ढाँचे की नियुक्ति के विषय मे राज्य, जिला एव खरीद केन्द्र की इकाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में, खरीद कार्य की व्यवस्था के सन्दर्भ में तथा विभिन्न स्तर पर निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सम्बन्ध में विशेष सावधानी बरती जाय। जिला स्तरीय लक्ष्य निर्धारण में आकडों की अपर्याप्तता, अनुपलब्धता एव उनके शुद्धता के स्तर का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्यानुसार वित्तीय एव खरीद के अन्य संसाधनों का बँटवारा इकाईवार किया जाता है।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावकारी बनाना -

सार्वजिनक वितरण प्रणाली को निम्न उपायो के

माध्यम से और प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए-

\* केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने के आदेश पर राज्य सरकारों को तुरन्त अमल करना चाहिए। ऐसे आदेश राज्य सिहत केन्द्र शासित प्रदेशों को भी फरवरी—1995 में जारी किये गये हैं। इनके इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार एवं प्रसार पर भी केन्द्र सरकार ने जोर दिया है जो एक सराहनीय कदम है। विभिन्न सूचना माध्यमों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता, वर्तमान व्यवस्था, प्रक्रिया एवं परिणाम की जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए। इसके द्वारा आम जनता की अनेक भ्रान्तियों को दूर किया जा सकेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगे व्यक्ति अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति संजग होंगे। इसके माध्यम से इस व्यवस्था में व्याप्त अपनिश्रण, कालाबाजारी, चोरबाजारी एवं भ्रष्टाचार में कमी की जा सकेगी।

\* किसी भी शासकीय योजना की सफलता एव विफलता के लिए सरकार एव आम जनता दोनो उत्तरदायी होती है। सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय लोग एव उच्चस्तरीय प्रशासन दोनो क सहयोग से ही सार्वजिनक वितरण तन्त्र की अष्टता को कम किया जा सकता है। जिला नियन्त्रण कक्ष के अधीन ही एक आकिस्मिक जाँच दल का गठन किया जाना चाहिए जो समय—समय पर उचित मूल्य के दुकानो की जाँच करे। खाद्यान्नों की गुणवत्ता तथा प्राप्त एव वितरित स्टॉक के सम्बन्ध में अनियमितता पाये जाने पर दोषी दुकानदारों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। जाँच कार्य में सहायता हेतु मुहल्ला या ग्राम जाँच समितियाँ भी बनायी जानी चाहिए तािक वितरण व्यवस्था की निचले स्तर पर भी जाँच की जा सके ओर इस तथ्य से सन्तुष्ट हुआ जा सके कि वस्तुओं का वितरण वािकत व्यक्तियों को ही किया जा रहा है।

\* आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में खुली बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता—वस्तु मूल्यों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति में देश के पिछडे एव ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना अपरिहार्य हो गया है।

\* सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की बिक्री न होने की समस्या का समाधान इस प्रणाली की व्यवस्था को ग्राम प्रधानों तथा ग्राम सभा सदस्यों को सौप कर किया जा सकता है।ग्राम प्रधानों की सहमित से नियुक्त किये गये कोटेदार,ग्रामवासियों की सुविधानुसार उचित स्थान पर एव उचित मूल्य पर अधिकतम सुविधाओं के साथ वस्तुओं के विक्रय का प्रयास करेगे।

\* सार्वजिनक वितरण प्रणाली पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इससे निर्धन व्यक्तियों को वाछित सहायता नहीं मिल पा रही है। इसका समाधान यह हो सकता है कि सरकार उस प्रस्ताव को मजूरी दे जो कि उसके समक्ष काफी दिनों से विचाराधीन है जिसमें उन व्यक्तियों को सार्वजिनक वितरण प्रणाली से अलग करने की बात कही गयी है जिनकी आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो। ऐसा करने से इस प्रणाली का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसा करने से इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को बढाया भी जा सकता है।

\* अधिकतम निर्धन परिवारों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए इस प्रणाली को जारी रखते हुए, प्रायोगिक तौर पर अमेरिका की तरह हमारे देश में भी निर्धन परिवारों को फूड स्टाम्प बॉटने की योजना को कार्यरूप दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले देश के अति गरीबों को परिभाषित करना होगा ओर उन्हें नकदी या कूपन के के रूप में आर्थिक सहायता देनी होगी तािक वे खुले बाजार से अपनी उदर-पूर्ति हेनु खाद्यान्न खरीद सके। यह व्यवस्था इसलिए अधिक उचित होगी कि अति गरीबों को सहायता पूरे राष्ट्र की कीमत पर की जानी चािहए न कि भारतीय गरीब कृषकों की कीमत पर। विकसित देशों के साथ ही कुछ एशियाई देशों जैसे श्रीलका ने भी अब इस अवधारणा का परित्याग किया है कि'खाद्यान्नों का

मूल्य गिरा कर रखा जाय' इसक्र स्थान पर उन्होंने नया मार्ग गरीबों की पहचान करें को अपनाया है। ऐसी व्यवस्था से सहायता उन्हें मिलेगी जिन्हें इसकी अधिक जरुरत है। इससे कम व्यय में गरीबों की अधिक मदद की जा सकेगी। किसानों को खुले बाजार में अपना अनाज बेचने से अच्छा मूल्य भी मिलेगा। परन्तु इस व्यवस्था को मार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक के रूप में अपनाना उचित होगा।

\*सार्वजिनक वितरण प्रणाली पर खाद्यान्नों की कम आपूर्ति की दशा में बढने वाले दबाव की समस्या के निराकरण हेतु खाद्यान्नों का उत्पादन एवं खपत का सही—सही अनुमान लगाया जाना आवश्यक होता है। सही—सही अनुमान के लिए समकों के सकलन हेतु दो या दो से अधिक विश्वसनीय माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए इससे न तो उचित मूल्य की दुकानों पर अनावश्यक दबाव बढने का प्रभाव पड़ेगा और न ही आपूर्ति अधिक होने की दशा में उचित मूल्य के दुकानदारों की आजीविका प्रभावित होगी। क्योंकि खाद्यान्नों की आपूर्ति के अनुसार उनके आयात अथवा निर्यात का निर्णय समय रहते लिया जा सकेगा।

- \* कमजोर वर्ग को इस प्रणाली का अनुकूलतम लाभ मिले इसके लिए आवश्यक है कि फर्जी राशन कार्डों एव जाली यूनिटो को रद्द किया जाय। अत सरकार को इस कार्य के लिए प्रभावी एव दण्डनीय अभियान चलाना चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगो को इस बात की जानकारी भी दी जानी चाहिए कि उन्हें कितनी मात्रा में, किस दर पर, किस समय वस्तुओं की आपूर्ति मिलनी चाहिए।
- \* उचित मूल्य की दुकानो पर वस्तुओं की किस्म में शुद्धता बनाये रखने तथा कम माप-तौल की समस्या के निदान हेतु उपलब्ध वस्तुओं को छोटे-छोटे पैकेटों में जिस पर"भारतीय मानक सस्थान" की मुहर लगी हो, उपलब्ध कराना चाहिए।
- \* एक दुकानदार को आविष्टित जनसंख्या व कार्डों की संख्या बढ़ाई जाय तथा वस्तुओं के कोटा में भी वृद्धि की जाय ताकि दुकाने लाभदायक बन सके इसके लिए कम कार्ड संख्या वाली दुकानों का एकीकरण भी किया जा सकता है।
- \* सरकार को राशन कार्डों को हस्तान्तरण करने वाले दोनो पक्षो को दण्डित कर इस पर पूर्ण रोक लगा देनी चाहिए तथा कार्डों की जॉंच में विवाह एवं प्रवसन का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- \* जिन दुर्गम क्षेत्रों में न तो सडके हैं न परिवहन के साधन, जहाँ अभी तक कभी कोई अधिकारी नहीं पहुँच सका है वहाँ इस प्रणाली को लागू करना उचित न होगा। ऐसे स्थलों के लिए पहले आधार भूत सुविधाए उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि इस प्रणाली के लागू करने के बाद व्यवस्था का निरीक्षण तथा नियन्त्रण किया जा सके।
- \* नई दुकानो को खोलने मे वर्तमान नियमो का कडाई से पालन किया जाना चाहिए जिसके अनुसार कम से कम दो हजार की आबादी अथवा 3 किलोमीटर की दूरी मे दूसरी दुकान का न होना आवश्यक \*

होता है।

- \* सरकार को दुकानदारो द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिये जाने वाले चन्दो पर रोक लगानी चाहिए ताकि दिन प्रतिदिन के कार्य मे राजनीतिक हम्तक्षेप न हो।
- \* उचित मूल्य की दुकानो पर वस्तुओ की आपूर्ति जिला मुख्यालय द्वारा सीघे की जानी चाहिए। इससे दुकानदारों को वस्तु की कम आपूर्ति अथवा मूल्य या मिलावट का अवसर नहीं मिल सकेगा।
- \* ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकाने खोलने के लिए ग्रामीण युवकों को प्रेरित किया जा सकता है इससे उन्हें रोजगार भी मिल सकेगा तथा वे वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने में अधिक रुचि लेंगे।
- \* नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति एव उसकी उपयोगिता से उत्सावर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे है अत उसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश पर्वतीय जिलो तथा पिछडे राज्यो के पिछडे क्षेत्रों में और अधिक बटाया जाना चाहिए।

## भारतीय खाद्य निगम को और अधिक उद्देश्यपरक बनाने सम्बन्धी सुझाव -

भारतीय खाद्य निगम

को उद्देश्यपरक एव अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है-

- \* भारतीय खाद्य निगम एक कल्याणकारी संस्था होने के कारण लाभ की भावना से अपनी सेवाए प्रदान नहीं करता। बेशक यह एक पुनीत कर्तव्य है परन्तु वर्ष 1986-87 से 1991-92 के बीच इस मावना को ढोते रहने में उसे 4455 31 करोड़ रुपये का निवल घाटा हुआ है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह अपने "न लाभ न हानि" की भावना से कार्य करना छोड़ दे। उसे "न हानि" का भी ध्यान रखना है तभी वह अपना पर्यान्त विकास एवं विस्तार करने के साथ-साथ अपना अस्तित्व भी बचा पायेगा।
- \* खाद्य निगम को अपनी कार्यक्षमता, कुशलता एव कारोबार की स्थिति में तुरन्त सुधार करने की आवश्यकता है तभी इसके विनियोजित पूँजी एव कारोबार के अनुपात को बढाया जा सकेगा जो पिछले कई वर्षों से 1 2 पर रूका हुआ है। इसके लिए आवश्यक है निगम में लगे व्यक्ति पूरी क्षमता एव स्वय के प्रेरणा से कार्यों का निष्पादन करे।
- \* निगम को लाभदायक स्थित में लाने के लिए आवश्यक है कि यह अपने कार्य में " न केवल वाणिज्यिक सिद्वान्तों का प्रयोग करें बल्कि अपने व्ययो पर नियन्त्रण भी करें। कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति—योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे यद्यपि अल्पकालीन व्यय बढेंगे परन्तु दीर्घकाल में प्रति कर्मचारी कार्यक्षमता को बढाया जा सकेगा क्योंकि रिक्त पदो पर नयी भर्ती से वेतन इत्यादि पर व्यय कम होगा तथा नये कर्मचारी अपनी अधिक कार्य, उर्जा, का प्रयोग निगम के लाभों को बढाने में कर सकेगे।
  - ≭ भारतीय खाद्य निगम को मार्गस्थ हानियो एव भण्डारण की किमयो से बहुत बडी हानि हो रही है

अत इसे कम करने का प्रयास निम्न उपायों के द्वारा करना चाहिए-

- -- खाद्यान्नो की अधिप्राप्ति के समय जारी किये गये विनिर्देशनो को कडाई से लागू किया जाय, जैसे -चावल की खरीद के सम्बन्ध मे 17-18 प्रतिशत की मान्य नमी ही स्वीकार की जाय, इससे खाद्यान्नो की सूखने से कमी को कम किया जा सकेगा।
  - -- बोरो की सिलाई केवल मशीनो से की जानी चाहिए। .
- -- निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के निर्गमन में फीफों मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे खाद्यान्न के किसी स्टॉक को गोदाम में अधिक समय तक न रोकना पड़े।
- खाद्यान्नों की परिवहन लागत कम रखने तथा अधिक सुरक्षित पहुँच को सुनिष्टिचत करने के लिए आवश्यक है कि रेल परिवहन का यथा सम्भाव प्रयोग किया। तर्राई क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा अन्य आतकवाद—प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ द्रकों द्वारा खाद्यान्न प्रेषित किया जाना अपरिहार्य हो तो वहाँ द्रकों के साथ सुरक्षा गार्डों को भी नियुक्त किया जाय साथ ही साथ द्रकों को केवल काफिलों में चलने की अनुमित दी जाय। इससे द्रकों के अपहृत कर लिये जाने से निगम को होने वाली हानि को रोका जा सकेगा।
- माल की लादने और उतारने की छीजन को रोकने के लिए यथासम्भव मशीनो का प्रयोग किया जाय। श्रिमको को हुको का प्रयोग करने की अनुमित केवल विशिष्ट बोरो और विशिष्ट परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।
- -- भण्डारण का प्रबन्ध इस तरह से किया जाय कि कैप भण्डारण में कोई खाद्यान्न रखने की आवश्यकता न पडे। यदि ऐसा करना आवश्यक ही हो तो केवल मोटे अनाजों को ही कैप भण्डारण में रखा जाय, गेहूँ या चावल नहीं।
- \* खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय विवरणो की जाँच स्वीकृत मानको को ध्यान मे
   रखकर ही स्वीकार किया जाना चाहिए।
- \* किसान भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रो पर अपनी उपज को अधिकतम मात्रा में बेचे इसके लिए आवश्यक है कि खाद्यान्नों के सरकारी मूल्यों की घोषणा फसल के बुआई के समय ही कर दी जाय। किसानों के साथ मित्रवत् व्यवहार किया जा। क्रय केन्द्रों पर किसानों और उनके बैलगाडियों के रुकने तथा खाने एव चारे की व्यवसथा यदि बड़े पैमाने पर खरीद की जाती है तो, सुनिश्चित की जाय।उन्हें इस बात से पूर्णत सन्तुष्ट किया जाय कि उनका माल अमुक ग्रेड का है जिसका सरकारी मूल्य अमुक है। अलग—अलग ग्रेडों का अनाज और उनका लिखित मूल्य कृषकों के समक्ष आदर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस व्यवहार से कृषक स्वत अपने उपजों को महाजन एवं ग्रामीण मध्यस्थों को नहीं बेचेंगे।
- \* निग को चाहिए कि वह फसलो व खाद्यान्न सरक्षण की तकनीक के बारे में अनुसन्धान करे तथा कृषकों को नवीनतम वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। उसे किसानों द्वारा लिए जाने \*

वाले ऋण की गारण्टी भी देनी चाहिए।

- \* निगम द्वारा खरींदे जान वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गुणात्मक लक्ष्य प्राप्त करन के लिए अधिकारियों को' आप ऐसा करें' के स्थान पर 'हम सब मिलकर ऐसा करें' पर अधिक जोर देना होगा।
- \* निगम को अपनी वर्तमान भण्डारण क्षमता को 197 लौख टन से बढ़ाने की आवश्यकता है। वह वर्तमान समय मे अपनी कुल भण्डारण क्षमता का एक तिहाई भाग किराये पर प्राप्त कर काम चलाता है। जिसके लिए उसे भारी किराया चुकाना पड़ता है तथा गोदामों के वाछनीय स्तर भी नहीं होते। इसके लिए एक अभियान चलाया जाय और अतिरिक्त वित्त उपलब्ध करा कर नये भण्डारगृहों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि निगम को किराये पर भण्डार क्षमता प्राप्त न करनी पड़े साथ ही मूल्यवान खाद्यान्नों को कैप भण्डारण में रखना भी न पड़े।
- \* निगम के सभी गोदामा का भौतिक सत्यापन किया जानला अपरिहार्य है, परन्तु सभी गोदामो का भौतिक सत्यापन एक साथ नहीं किया जा सकता इसके लिए लाटरी निकालकर यह तय किया जाना चाहिए कि किस डिपो का सत्यापन पहले किया जाय। इस उपाय से खाद्यान्नो का स्टॉक स्कन्ध बही के अनुसार न होना, खाद्यान्नो का सडना या गल जाना, तिरपालो एव बोरो के सडने से होने वाली हानि तथा समय से दवा न छिडके जाने से होने वाली हानि को कम किया जा सकेगा। सत्यापन करने वाले कर्मचारी भण्डारण के इस सम्बन्ध मे होने वाली हानि को रोकने का सुझाव भी अपने प्रतिवेदन मे प्रस्तुत करे, इस आशय का निर्देश भी दिया जाना चाहिए।
- \* बहुत बडे एव महत्वपूर्ण, गोदामो पर खाद्यान्नो की आवक एव निकासी के दोरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा कुल आवक एव निकासी को दर्ज करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए।

## भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम के व्यवस्थित सचालन हेतु सुझाव -

विभिन्न खाद्यान्नो एव अन्य वस्तुओं में समय एवं स्थान उपयोगिता के सृजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगा यह निगम यद्यपि अपने कर्तव्यों का कुञ्चलता से निर्वहन कर रहा है। फिर भी इस निगम के सचालन हेतु निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं—

\* इस निगम को अपने व्ययो को नियन्त्रित करने के लिए कमोबेश उन्ही उपायो का प्रयोग करना चाहिए जो कि भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्ध में दिये गये हैं। इसके लिए वास्तव में ग्रेच्युटी, बोनस, वेतन, भत्ते, मजदूरी एव अनुरक्षण व्ययो को बढ़ने से रोकना तो सम्भव नहीं है परन्तु इनकी वृद्धि दर में आकर्षक सेवानिवृत्ति—योजना के द्वारा कमी अवश्य लायी जा सकती है।

\* परिचालन व्ययों में कमी लाने के लिए भण्डारगृहों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। एक प्रिशिक्षत जन शक्ति, नवीननम तकनीको पर आधारित मशीने विवेकीकरण पर आधारिन भण्डारण व्यवस्था तथा कम्प्यूटरीकरण पर आधारित स्टॉक सगणना व्यवस्था निगम के परिचालन व्ययों में कमी लाने में सहायक होगी।

\* वृहत् पूँजी निवेश के बाद अर्जित की जाने वाली स्वनिर्मित भण्डारण क्षमता, अथवा किराया चुका कर प्राप्त की जाने वाली किराये की भण्डारण क्षमता यदि अप्रयुक्त रह जाती है तो यह निगम के हानि का माध्यम बनती है। इसलिए यह आवश्यक है कि निगम अपना विकास एव विस्तार करते हुए अपनी भण्डारण क्षमता को बढाने का कार्य जारी रखे, परन्तु किराये पर उतनी ही भण्डारण क्षमता प्राप्त करे, जितनी कि निगम के लिए आवश्यक हो। इससे एक ओर तो व्यय के रूप मे निगम द्वारा चुकाये जाने वाले किराये मे कमी होगी तो दूसरी ओर इन भण्डारगृहों के स्वामी अप्रयुक्त भण्डार गृहों का प्रयोग किन्ही अन्य कार्यों में कर सकेगे।

\* विगत वर्षों मे निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता मे आयी गिरावट को दूर करने का प्रयास करना होगा। निगम की प्रति कर्मचारी सकल प्राप्ति एव सभाली गयी क्षमता तथा कर्मचारियो पर किया गया व्यय कर्मचारियो की सख्या से प्रत्यक्ष रूप मे जुड़ा हुआ है। अत कर्मचारियो की सख्या नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। समय की मॉग यह भी है कि निगम की सकल प्राप्ति मे आयी म्मी का गहन परीक्षण एव अनुसधान कराया जाय और प्राप्त रिपॉट के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाय।

\* निगम को अपने भण्डारगृहों से होने वाली आय को बढाने के लिए निम्न सुझावों का अनुपालन करना चाहिए-

- निगम अपनी भण्डारण क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करते हुए व्ययो को नियन्त्रित करे। भण्डारण क्षमता का पूरा प्रयोग एव व्ययो पर नियन्त्रण तभी सम्भव है जब निगम के समस्त कर्मचारी अपनी पूरी लगन एव निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जमाकर्ताओं को हर सम्भव सुविधा प्रदान करे और साथ ही साथ भण्डारित वस्तुओं के गुणात्मक एव मात्रात्मक क्षति को भी न्यूनतम करे।
- -- निगम को अपना लाभ एव लाभाश बढाने के लिए परम्परागत क्षेत्र के कारोबार में वृद्धि करने के साथ ही साथ अपरम्परागत क्षेत्रों में भी अपना कारोबार बढाना है।
- -- कटेनर ढुलाई स्टेशनो से निगम को बहुत अधिक लाभ होने की सम्भावना है अत इसकी सख्या को 12 से बढाकर 20 किया जाना चाहिए। जिन ढुलाई स्टेशनो के लिए मन्त्रालय से अनुमित मिल चुकी है, उनकी स्थापना में अब विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।
  - -- इस निगम ने भी भारतीय खाद्य निगम की तरह गेहूँ की अधिप्राप्ति का जो कार्य छोटे पैमाने "

पर शुरू किया है उसमे और अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अन्य खाद्यान्नो की खरीद, भण्डारण एव खुले वाजार में कीमतो मं वृद्धि की दशा में निर्गमन का कार्य शुरू करके अपने कार्य क्षेत्र एवं लाभा में वृद्धि कर सकता है।

- -- इन प्रयासो के अतिरिक्त फलो, फूलो एव सब्जिया के भण्डारण व्यवस्था में और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है इसके लिए और अधिक कोल्ड स्टोरेज बनायें जाने चाहिए।
  - \* निगम को भण्डारण क्षतियों को न्यूनतम करने हेतु निम्न प्रयास करने चाहिए-
- स्टाक के मूल्याकन एव नियन्त्रण की नवीन विधियों को प्रयोग में लाया जाय ताकि क्षण प्रतिक्षण स्टाक में रखी गयी वस्तुओं की बिना भौतिक सत्यापन के जानकारी की जा सके साथ ही समय—समय पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टाक के मूल्याकन में तीव्रता लाने के लिए कम्प्यूटरीकृत स्टाक मूल्याकन व्यवस्था भी अपनायी जा सकती है।
- ——मार्च—1992 तक भण्डारित की जाने वाली 229 वस्तुओं के सम्बन्ध में भण्डारण प्रक्रिया सिहता का निर्धारण किया जा चुका था निगम को चाहिए कि वह भण्डारित की जानी वाली सभी वस्तुओं के समम्बन्ध में भण्डारण प्रक्रिया सिहता न केवल निर्धारण करें बल्कि उसका पालन भी करे।
- -- नमूनों के विश्लेषण एवं वस्तुओं के ग्रेड निर्धारण में विगत वर्षों में जो संख्यात्म कमी आयी है ऐसी कमी से निगम को बचना चाहिए तथा भण्डारित की जाने वाली वस्तुओं के रोग रोधी उपचार,स्टोंक का प्रधुमन, भण्डारण स्थान का प्रधुमन इत्यादि में और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए।
- माल की छीजन को रोकने अथवा कम करने के लिए बोरो को लादने एव उतारने में मशीनों का प्रयोग बढाया जाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो हुको का प्रयोग वर्जित कर दिया जाना चाहिए। निगम द्वारा कैप भण्डारण अपरिहार्य दशाओं में ही कुछ समय के लिए किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सुझावो के अनुपालन से केन्द्रीय भण्डारण निगम अपनी भण्डारण क्षतियो को न्यूनतम कर सकता है।

- \* किसानो द्वारा निगम के भण्डारगृहो का प्रयोग बढाये जाने के लिए आवश्यक है कि किसान एव कीट नाशक विस्तार सेवा योजना को और अधिक बड़े पैमाने पर लागू किया जाय, किसानो को वैज्ञानिक भण्डारण विधियों से अवगत कराया जाय, इन विधियों का प्रदर्शन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाय। यदि निगम किसानों को अपनी भण्डारण प्रक्रिया से अवगत करायेगा तो किसान स्वय अपने आधिक्यों को निगम के भण्डारगृहों में रखने के लिए उत्साहित होंगे और निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठायेगे।
- \* राज्य भण्डारण निगमो की समता अश पूँजी में किये गये विनियोजन से प्राप्त होने वाले लाभाश की स्थिरता हेतु आवश्यक है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा इन निगमों को समय से अपनी

वार्षिक साधारण सभाए बुलाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये जाये। राज्य भण्डारण निगम राज्य की स्थानीय परिस्थित, विभिन्नता एव आवश्यकता से भलीभाँति परिचित होते हैं इसलिए इन निगमों को अपनी सेवाए राज्य की निजी एव सरकार द्वारा प्रायोजित सस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करते हुए कम से कम लागत पर अधिक मात्रा में प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य भण्डारण निगमों को भी उन सुझावों का अनुपालन करना चाहिए जो कि केन्द्रीय भण्डारण निगमों को उनकी आय बढाने एव क्षमता के अधिकतम प्रयोग के सम्बन्ध में दिए गये हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावो को अपनाकर भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम खाद्यान्न एव अन्य वस्तुओं के सग्रहण भण्डारण एव वितरण में राजकीय उत्तरदायित्वों की पूर्ति में अपनी महती भूमिका और अच्छी तरह से निभा सकेगा।

## भारतीय राज्य व्यापार निगम हेतु उपयोगी सुझाव -

इस निगम को और उपयोगी बनाने के सम्बन्ध

मे कुछ सुझाव निम्नवत् है-

\* भारतीय राज्य व्यापार निगम को विगत पाँच वर्षों मे अपनी विनियोजित पूँजी पर लगभग 2 3 प्रतिशत की प्रत्याय हुई है जो कि बहुत कम है। निगम को कम से कम इसे 7-8 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। इस प्रत्याय दर को ध्यान मे रखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यापारिक अनुबन्धों में लाभ-हानि की तुलना करते हुए ही व्यापारिक अनुबन्धों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए। प्रत्याय दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि स्थापना व्यय एव अन्य खर्चों में यथा सम्भव कटौती की जाय।

\* निगम को देश के उद्योग एव व्यापार से प्रत्यक्ष व्यावहारिक सम्बन्ध लगातार बनाये रखना चाहिए तािक देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार एव वािणज्य में आ रही तात्कािलक समस्याए, उत्पादन एव खपत की सही जानकारी, परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों का निगम पर पडने वाले प्रभावों की स्थिति की वास्तिविक जानकारी मिल सक। इससे निगम को आयात—निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में अपनी सौदेबाजी की शक्ति के आधार पर लाभदायक अनुबन्धों का निर्धारण करने में आसानी होगी।

\* निगम को सदैव इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वह अपने सहायक निगम, भारतीय चाय व्यापार निगम के साथ समन्वय बनाये रखे। दोनो सस्थाओं के उद्देश्यों, लक्ष्यों एव नीतियों में एकरूपता टोनी चाहिए साथ ही दोनों में और अधिक सहयोग विकसित किया जाना चाहिए।

\* निगम को अपनी प्रशासनिक सुविधा पर अधिक ध्यान न देकर ग्राहको की सुविधा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि इस पर एकाधिकारी सस्था होने का अरोप सही नही है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सी असरणीबद्ध वस्तुओ का वयापार भी किया जाता है, फिर भी निगम को यथार्थवादी मूल्य-नीति अपनानी चाहिए तथा उचित सेवा मूल्य ही निर्धारित किया जाना चाहिए। \* वर्तमान समय में सरकार सरणीबद्ध वस्तुओं की सख्या में कमी करती जा रही है इससे निगम को स्वय अपना व्यापार क्षेत्र एवं व्यापार की वस्तु का चयन करना है। ऐसी दशा में असरणीबद्ध वस्तुओं एवं बाजार का नया क्षेत्र खोजना अपरिहार्य हो गया है। अत निगम को नये बाजार की खोज पर अधिक धन व्यय करना पड़ेगा तथा असरणीबद्ध वस्तुओं के व्यापार क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ाना होगा।

इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य व्यापार निगम को अन्य राजकीय अभिकरणों के सम्बन्ध में दिये गये यथोपयोगी सुझावों का भी अनुपालन करना चाहिए।

#### निर्णयनप्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण -

राजकीय व्यापार में शासकीय निर्णयों को विलम्ब से लेने के आरोप का निराकरण करने के लिए आवश्यक हैं कि इनके निर्णय प्रक्रिया में विकेन्द्रीकरण को लागू किया जाय। सही समय पर उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं कि राजकीय व्यापार अभिकरणों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों में अधिकारों एवं दायित्वों दोनों का साथ—साथ विकेन्द्रीकरण हो। इसके अतिरिक्त शीघ्र निर्णयन हेतु राजकीय व्यापार एजेन्सियों का गठन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया जाना चाहिए। निर्णयन प्रक्रिया में जटिलता को कम करने के लिए आवश्यक हैं कि राजनीतिक पदाधिकारियों के अधिकारों को सीमित किया जाय, जिससे वे राजकीय व्यापार अभिकरणों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न कर सके। इन पदाधिकारियों एवं शासकीय अधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। निर्णय के अधिकार को यथा सम्भव उत्तरदायित्व के साथ विकेन्द्रित किया जाना चाहिए ताकि समय एवं परिस्थिति के अनुरूप उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

#### सम्बद्ध मन्त्रालयो मे समन्वय की आवश्यकता -

यद्यपि राजकीय व्यापार से अप्रत्यक्ष रूप मे तो बहुत से मन्त्रालय सम्बद्ध होते हैं परन्तु कृषि,खाद्य एव नागरिक आपूर्ति, वित्त तथा वाणिज्य मन्त्रालय प्रमुख है। इन मन्त्रालयों के बीच सवादहीनता जैसी स्थित को समाप्त किया जाना चाहिए। इन मन्त्रालयों से सम्बन्धित अधिकारियों के बीच समन्वय तथा सचार की निरन्तरता बनाये रखने के लिए समय—समय पर विभागीय एव अन्तर्विभागीय बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।जब भी आवश्यकता समणे जाय तो मन्त्रिमण्डलीय सचिवों की समिति बनाकर अहम् मुदद्ों पर विचारों का प्रत्यक्ष आदान—प्रदान किया जाय। जिससे उत्पादन, आवश्यकता, खरीद एव निर्गमन आदि के सम्बन्ध में वास्तविक अनुमानों पर आधारित सही तथा शीघ्र निर्णय लिया जा सके तथा त्वरित कार्यान्वयन भी किया जा सके।

## राजकीय व्यापार अभिकरणो मे प्रतिनियुक्ति पर रोक -

क्योंकि थोडे समय के लिए दूसरे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों में राजकीय व्यापार के ज्ञान एवं अनुभव की कमी के कारण अनुबन्ध ैं योग्यता विकसित नहीं हो पाती है साथ ही उन्हें अपने मूल विभाग को कुछ समय बाद वापस होना होता है जिससे वे पूरे मनोवेग से निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करते। अत प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा देनी चाहिए। केवल अपरिहार्य परिस्थित में ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रति—नियुक्ति की जानी चाहिए वह भी या तो बहुत थोड़े समय के लिए, अर्थात् 1 वर्ष से कम, अथवा 5 वर्ष से अधिक। इससे राजकीय व्यापार अभिकरण अपरिहार्य परिस्थितियों से बच भी सकता है तथा यदि लम्बे समय तक प्रतिनियुक्ति जारी रहती है तो कर्मचारी या अधिकारी को अनुभव से अर्जित कार्यक्षमता का उपयोग भी हो सकेगा।

## कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता —

राजकीय

व्यापार के अभिकरणों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमें व्यापारिक क्षमता एवं योग्यता विद्यमान हो। नियुक्ति के पूर्व उनकी व्यापारिक क्षमता, योग्यता एवं रुचि का परीक्षण नवीनतम विधियों से किया जाना चाहिए। नियुक्ति का आधार केवल प्रतियोगितात्मक परीक्षण ही होना चाहिए।

यद्यपि राजकीय व्यापार अभिकरणों में कार्यरत् कर्मचारियों और अधिकारियों में ओर अधिक क्षमता, योग्यता एवं कुशलता का विकास करने के लिए समय—समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, परन्तु यह तेजी से बदल रही आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। अत प्रशिक्षण के समय अन्तराल को कम किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की नयी—नयी विधियों का प्रयोग कर कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता का पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण चरणबद्ध प्रक्रिया से पूरा किया जा सकता है। कर्मचारियों को उनके कार्य के सम्बन्ध में विदेशों में अपनायें जाने वाले अच्छे तरीकों से भी परिचित कराया जाना चाहिए।

राजकीय व्यापार अभिकरणों में कार्यरत् कर्मचारियों एवं अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भौतिकता की आपाधापी एवं मानसिक अशान्ति को कम करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण यथा—ध्यान, योग एवं नैतिक प्रशिक्षण शिविर आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। कर्मचारियों एवं अधिकारियों स्वयं के प्रेरणा से कार्य सम्पादन की इच्छा जागृत करने के लिए अभिप्रेरण के नवीनतम वित्तीय एवं अवित्तीय दोनों साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारी पूरी निष्ठा, क्षमता एवं ईमानदारी से अपने—अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे इसके लिए उन्हें यह बात समझायी जानी चाहिए कि राजकीय व्यापार अभिकरणों के हित में ही कर्मचारी का हित भी विद्यमान एवं सुरक्षित है।

## उपभोक्ता सरक्षण कानूनो को और तीव्र तथा प्रभावी बनाने की आवश्यकता -

पश्चिमी तर्ज पर

उपभोक्ताओं की अपने अधिकारों के प्रांत सजग होने की एक लहर सी देश में उठी है। परन्तु इस लहर के उठने पर यह अनुभव किया जा रहा है कि भारतीय—उपभोक्ता सरक्षण कानूनों में वह चुभन नहीं हैं, जो होनी चाहिए। कार्तिक दास बनाम मार्गन स्टेनले म्युच्युअल फण्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम—1986 के अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए कहा कि अश आविण्टत होने के पहल ही नुकसान का दावा करने जैसे मामले में कोई मुआवजा या हर्जाना दिलवाने का कोई अधिकार उपभोक्ता अदालतों को नहीं है क्योंकि एक निवेशक उपभोक्ता नहीं है। अश या यूनिट आविण्टत होने के बाद ही काई निवेशक उपभोक्ता का दर्जा हासिल करता है। लगभग इसी प्रकार मामला कलकत्ता के डां० अरविन्द गुप्ता बनाम 'सेबी' का है। अत उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम तथा उपभोक्ता हितार्थ बनाये गये अन्य समस्त कानूनों को और अधिक तींव्र एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव लागू किये जा सकते हैं—

- \* उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। जिससे उपभोक्ता के दायरे को बढाया जा सके।
- \* जिला मच, राज्य आयोग एव राष्ट्रीय आयोग मे सदस्यो की नियुक्ति मे राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए केवल अनुभवी एव योग्य व्यक्तियों को ही इनका सदस्य बनाया जाना चाहिए।
- \* उपभोक्ता के लिए क्षतिपूर्ति का आधार स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा इस सन्दर्भ में अधिनियमों में आवश्यक प्रावधान किये जाने चाहिए।
- \* शहरी एव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता आन्दोलन के प्रति अपनत्व की भावना जागृत की जा सके। उचित विज्ञापन के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं तथा उसके उपयोग की जानकारी दे। वस्तुओं के मूल्य, किस्म, वजन, पैकिंग एव पैकेजिंग के सन्दर्भ में नियमों से उपभोक्ताओं को परिचित कराया जाना चाहिए। जहाँ भी इनका उल्लंघन सिद्ध होता है, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
- \* यदि किसी कारणवश कोई हानिकारक उपभोक्ता सामग्री बाजार में आ जाती है तो उसे तुरन्त जब्त करने का अधिकार प्रशासनिक तन्त्र को दिया जाना चाहिए।
- \* तेजी से बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अधिनियमों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु विधि विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति बनाने की आवश्यकता है जो औद्योगिक( विकास एव नियमन) अधिनियम, अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम, खाद्य अपिमश्रण निवारण, आवश्यक वस्तु, व्यापार एव व्यापारिक चिन्ह, एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार, पैकेज्ड वस्तु नियमन, बाट एव माप-मान अधिनियम इत्यादि में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप परितर्वन एव परिवर्द्धन करे।

### ससदीय समिति के सुझाव का अनुपालन -

ससद की खाद्य एव नागरिक आपूर्ति सम्बन्धी स्थायी मिमिति की महत्वपूर्ण सिफारिशो का तुरन्त लागू किया जाना चाहिए जिसने अपना प्रतिवेदन गत वर्ष मे प्रस्तुत करते हुए सुझाव दिया है कि-

- \* उत्तर प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम के गोदामा में चावल उतारने के काम में लगे ठेकेदारों के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस कार्य में ठेकदारी की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा निगम द्वारा स्वय दैनिक मजदूरी पर नियुक्त शिमकों के माध्यम से इस कार्य को पूरा कराया जाना चाहिए।
- \* धान की खरीद पर लगने वाले करों में एकरूपता लाने के लिए राज्यों को राजी किया जाय जिससे लेवी के धान के खरीद मूल्यों में राज्यवार भिन्नता को समाप्त किया जा सके तथा इसके लागत नियन्त्रण में सुविधा प्राप्त हो सके।
- \* भारतीय खाद्य निगम अथवा अन्य अभिकरणों को सरकारी खरीद केन्द्र के निकट किसानों को न्यूनतम किराये पर अपनी उपज के भण्डारण हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि कृषक जब चाहे अपनी उपज इन केन्द्रों में बेच सके।
- \* भारतीय खाद्य निगम छोटे चक्की मालिको को भी कम मूल्य पर गेहूँ की आपूर्ति करे। क्योंकि शहरों में कमजोर वर्ग के उपभोक्ता राशन कार्डों के अभाव में इन्हीं आटा चिक्कियों से आटा खरीदते हैं। निगम इस समय आटा मिलो और डबलरोटी निर्माताओं को कम दर पर गेहूँ बेचता ही है जबिक ये आटा मिले अथवा डबलरोटी उत्पादक अपना आटा उत्पाद खुले बाजार में ऊँचे मूल्यों पर बेचकर लाभ प्राप्त करते हैं।

#### कुछ अन्य सुझाव -

सरकार को विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को व्यवस्थित तरीके से लागू करवाने के लिए आवश्यक है कि वह स्थानीय जिला एव राज्य स्तर पर प्रेक्षक समितियों की स्थापना करें जिससे उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित किया जा सके। इन समितियों में उपभोक्ता, व्यापार अभिकरण तथा सम्बद्ध अन्य सघों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

राजकीय व्यापार के सम्पादन से सम्बद्ध समस्त सत्ताओ यथा-केन्द्र, राज्य एव स्थानीय सत्ता के समन्वित सहयोग से ही राजकीय व्यापार की भूमिका को सकारात्मक स्वरूप दिया जा सकता है इसलिए आवश्यक है कि ये एक-दूसरे के विपरीत कार्य न करे, जब राजकीय व्यापार की सभी स्तर की एजेन्सियों में सहयोग की भावना होगी तभी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

वर्तमान समय मे विश्व का आर्थिक परिदृश्य बडी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। साम्यवादी समूह भी उन्मुक्त व्यापार व्यवस्था के लिए अपने दरवाजे खोल रहे है। पूर्वी एव पश्चिमी जर्मनी जैसे दो दिशाई का देशों का विलय हो चुका है। कई विकसित देश आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहे है। इन्ही परिस्थितियों में •

विश्व के आर्थिक मच पर कई क्षेत्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार समूहों का गठन हुआ है, तथा कई पुराने विश्व व्यापार सगठना को पुनरीक्षित, परिष्कृत एव परिवर्द्धित किया गया है। हमारा देश भारत भी इन परिवर्तनशील परिस्थितियों से अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी जून-1991 के बाद विश्व व्यापार व्यवस्था से ताल-मेल बनाये रखने हेतु आर्थिक उदारीकरण की एक नई लहर चली है जिसमें भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, अनेक वस्तुओं के आयात-निर्यात को प्रतिबन्धित सूची से हटाया गया, आयात-निर्यात के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाया गया, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए विनियमों को उदार बनाया गया, आर्थिक भूमण्डलीकरण में शामिल होने के लिए एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में अनेक संशोधन किया गया तथा नियन्त्रण के कई अन्य प्रावधानों का निरसन भी किया गया।

इस प्रकार विश्व एव भारत के नये आर्थिक परिदृश्य में राजकीय व्यापार को अपनी रचनात्मक भूमिका की खोज करनी है। हम पुरातनवादी परम्परागत आर्थिक मार्गी पर चलकर राजकीय व्यापार के समाजिक कल्याण की प्राप्ति में रचनात्मक भूमिका निर्वहन नहीं कर पायेगे। उदारीकृत व्यापार नीति के परिणामस्वरूप सरकार की प्राथमिकताए बदल चुकी है, इसिलए राजकीय व्यापार को भी अपनी प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। नि सन्देह समाजवादी सकल्पना को साकार करने में लगे नियोजित विकास—शील अर्थव्यवस्था वाले भारत में राजकीय व्यापार की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि राज्य एव लोकतन्त्र। राजकीय व्यापार आयात को अधिक मितव्ययी एव निर्यात को अधिक लाभप्रद ढग से सम्पादित कर सकता है। राज्य इसके माध्यम से कमजोर एव निर्धन उपभोक्ता के प्रति अपने पुनीत कर्तव्यों का निर्वहन भी कुशलतम ढग से करता है।

अत राजकीय व्यापार को वाणिज्यिक सिद्धान्तों के अनुसार चलाने तथा बदली हुई नयी आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप इसे अपनी नयी रचनात्मक भूमिका तय करने के लिए एक स्थायी समिति का सगठन करना चाहिए जो समय—समय पर राजकीय व्यापार की भूमिका को उपयोगी बनाने हेतु अपने सुझाव देती रहे। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता एव सामाजिक सगठनों से जुड़े योग्यता प्राप्त एव अनुभवी सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरक्त जो सुझाव राजकीय व्यापार को वर्तमान सन्दर्भों में अधिक उपयोगी बनाने हेतु दिये गये हैं उनको उपयागिता एव प्राथमिकता के क्रम में लागू किया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में ईमानदारी, निष्ठा एव नैतिकता की भावना जागृति की जाय जिससे कि वे राष्ट्रहित में कार्य कर, समाज का अधिकतम कल्याण करे, इससे राज्य एव राजकीय व्यापार से समाज जो अपेक्षाए रखता है उन्हें पूरा किया जा सकेगा और राजकीय व्यापार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

# सदर्भिका

(क) पुस्तके –	
1 अग्रवाल डी सी	इण्डियन इकोनमी साहित्य भवन आगरा-1994
2 अग्रवाल, आर सी एव ए एन	व्यावसायिन्र सगठन, प्रबन्ध एव प्रशासन, नवयुग साहित्य सदन
	आगरा-1994
3 भण्डारी एण्ड बोरा एन एन	इण्डियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रोल ऑफ प्राइवंट ट्रेड
4 भार्गव,आर एन	प्राइस कन्ट्रोल एण्ड राशनिंग, किताबिस्तान इलाहाबाद-1945
5 बजाज, आर के एव पोरवार,बी एल	सरकार समाज एव व्यवसाय,रिसर्च पिन्लिकेशन इन शोसल साइस-1979
6 चटर्जी आर एन	प्राइस कन्ट्रोल एण्ड राशनिग इन इण्डिया,कलकत्ता-1970
7 चौधरी,बी जी	लॉ ऑफ मोनोपोली एण्ड रिस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज इन इण्डिया,
	प्रेंटिस हाल आफ इण्डिया, नई दिल्ली
8 ढोलिकया एव खुराना	र्पाब्लक डिस्ट्रीब्यूश्रन सिस्टम,आक्सफोर्ड एण्ड आई वी एच ,
	पब्लिशिग कम्पनी, नई दिल्ली-1979
9 द्विवेदी, एम एल	गवर्नमेन्ट एण्ड विजनेस
10 गुप्ता,एम एल	स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया, साहित्य भवन आगरा
11 गुप्ता,अरविन्द	पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड ग्रेन इन इण्डिया,
	एग्रीकल्चर इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट, अहमदाबाद-1977
12 गुप्ता,ए पी	मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया,बोरा एण्ड कम्पनी
	पब्लिशर्स, बम्बई
13 गुप्ता,के आर	वर्किग ऑफ स्टेट ट्रेडिंग इन इण्डिया
	एस चॉॅंद एण्ड कम्पनी,नई दिल्ली-1970
14 गाबा ओ पी	राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, नेशनल पब्लिशिग हाउस,नई दिल्ली-1987
15 हजेला,टी एन	आर्थिक विचारो का इतिहास,शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी,आगरा-1986
16 हाटकिस	मिल स्टोन आफ मार्केटिंग,मैकमिलन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क-1938
17 जैन, एम पी	राजनीति के सिद्धान्त, आथर्स गिल्ड पब्लिकेशस, नई दिल्ली-1988
18 जैन, पुखराज	राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त, साहित्य भवन आगरा-1983
19 जैन, एस सी	विपणन, विक्रयकला एव विज्ञापन, साहित्य भवन आगरा-1994
20 जगदीश प्रकाश	राज्य एव व्यवसाय,प्रयाग पुस्तक सदन, इलाहाबाद-1991

21	जाडर ई टी	मार्केटिग एण्ड पब्लिक पालिसी ,सहाल
22	कुम्भट, जे जार एव	विपणन प्रबन्ध, किताब महल, इलाहाबाद
	अग्रवाल जी सी	
23	कोटलर फिलिप	मार्केटिंग मैनेजमेट, प्रेंटिस हाल आफ इण्डिया नई दिल्ली
24	युराना, राकेश	एन एनालिटिकल एप्रोच, फारम्युलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पालिसी
25	कुलशेष्ठ, आर एस	निगमो का वित्तीय प्रबन्ध, साहित्य भवन आगरा-1990
26	मजूमदार राय एव चौधरी	भारत का वृहत इतिहास,मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड,मद्रास-1990
27	मामोरिया एव जैन	भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन आगरा-1995
28	मैसन, एण्ड रथ	मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन
29	मालवीय, एच सी	सरकार,समाज एव विपणन, किताब महल, इलाहाबाद-1990
30	माथुर, एस पी	कोआपरेटिव मार्केटिंग इन यू पी
31	मोर्स, एस	दि प्रैक्टिकल एप्रोच टू मार्केटिंग मैनेजमेण्ट, माग्राहिल न्यूयार्क
32	मैगी, जे एफ	फिजिकल डिस्ट्रीब्यूश्न सिस्टम, माग्राहिल न्यूर्याक
33	मौरिस जार्ज पी एण्ड	करेट मार्केटिंग, न्यूकाउफील्ड प्रेस,
	फ्रे राबर्ट डब्ल्यू	सैन फ्रासिस्को-1973
34	ओम प्रकाश	प्राचीन भारत का आर्थिक एव सामाजिक इतिहास, वाइली ईस्टर्न लिमिटेड,
		नई दिल्ली–1986
35	सतीश चन्द्र	मध्यकालीन भारत,एन सी ई आर टी ,अक्टूबर-1990
36	सक्सेना, के के	इट्यूलेशन आफ कोआपरेटिव मूवमेण्ट,सोम्या पब्लिकेशन
		प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-1974
37	शुक्ला एव गुप्ता	मरकेन्टाइल लॉ, साहित्य भवन आगरा-1994
38	शुक्ला, आर एल	आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,
		दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-1987
39	शर्मा,टी आर एव जैन,एस सी	बाजार व्यवस्था, साहित्य भवन आगरा-1991
40	शर्मा, एल पी	मध्यकालीन भारत,लक्ष्मी नारायण अग्रवाल,आगरा-1976
41	श्रीवास्तव,के सी	प्राचीन भारत का इतिहास, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद-1989
42	सिह, वी वी	एन एव्यूलेशन आफ फेयर प्राइस शाप, आक्सफोर्ड एण्ड
		आई वी एच ,पब्लिशिग कम्पनी, नई दिल्ली
43	उपाध्याय, शर्मा एव सुधा	व्यवसाय समाज एव सरकार,रमेश बुक डिपो,जयपुर-1988-89
44	विपिन चन्द्र	आधुनिक भारत-एन सी ई आर टी -1990

45 वर्मा, हरिश्चन्द्र

मध्यकालीन भारत हिन्दी माध्यम कायोन्वय निदेशालय.

दिल्ली विभवविद्यालय दिल्ली-1986

46 वैव्विस्टम, फ्रेडरिक ई

सोशल आसपेक्ट आफ मार्केटिंग, प्रेन्टिस हाल आफ इण्डिया.

नई दिल्ली-1974

## (ख) अधिनियम -

- भारत का सिवधान राजभाषा खण्ड, विधि एव न्याय मन्त्रालय भारत सरकार,
   र्नई दिल्ली-1988
- औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम-1951
- अग्रिम अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-1952
- खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम-1954
- आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955
- प्रतिभूति अनुबन्ध(नियमन) अधिनियम-1956
- व्यापार एव व्यापारिक चिह्न अधिनियम-1958
- एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम-1969
- पैकेज्ड वस्तु नियमन आदेश-1975
- बाट एव माप मान अधिनियम-1976
- उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम-1986
- भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड अध्यादेश-1992

## (ग) पत्रिकाए -

- भारत, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- कमीशन एण्ड कॉम्पिटिशन फोरम,लक्ष्मीनगर दिल्ली
- सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, क्रॉनिकल पब्लिकेशस, दिल्ली
- इकोनांमिक सर्वे आफ इण्डिया
- इकोनॉमिकएण्ड पोलिटिकल वीकली
- फूड कोप, भारतीय खाद्य निगम, त्रैमासिक न्यूज लैटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली
- फैक्ट्स फार यू
- इण्डियन जर्नल आफ मार्कें टिंग, एसोसियेटेड मैनेजमेण्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली
- इण्डिया टुडे, कनाट प्लेस, नई दिल्ली
- कुरुक्षेत्र

- मैनेजमेण्ट कारपोरेशन नई दिल्ली
- प्रतियोगिता दर्पण, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा
- सहकारिता, यू पी कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ
- दि कामर्स जर्नल, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद
- उद्योग व्यापार पत्रिका, ट्रेड फेयर एथॉरिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली
- योजना, पिंक्लिकेशन डिवीजन, पिंटियाला हाउस्, नई दिल्ली

## (घ) प्रतिवेदन -

- वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली
- वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, 36-जनपथ, नई दिल्ली
- वार्षिक प्रतिवेदन, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलो एव सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय,
   भारत सरकार, नई दिल्ली
- वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय केन्द्रीय भण्डारण निगम, सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली
- रिपोर्ट आफ कमेटी ऑन स्टेट ट्रेडिंग,गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया नई दिल्ली
- इस्टीमेट कमेटी, रिपोर्ट ऑन दि स्टेट ट्रिडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली 196 6
- स्टेट इन फूड ग्रेन, बिरला साइटिफिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट
- इकोनॉमिक कमीशन फार एशिया एण्ड फार ईस्ट, स्टेट ट्रेडिंग इन
   कन्ट्रीज आफ इस्कैफ रीजन, जिनेवा-1964
- रिपोर्ट ऑन इनक्वाइरी कमीशन-1965

## (ड) समाचार पत्र -

- नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली
- अवर लीडर, इलाहाबाद
- दि इकोनॉमिक टाइम्स, नयी दिल्ली
- फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नयी दिल्ली
- टाइम्स आफ इण्डिया, नयी दिल्ली
- दैनिक जागरण, वाराणसी
- आज, वाराणसी,

\*\*\*\*